भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक

(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) प्रक्षेत्रों

का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		vii
अध्याय-1 प्रस्तावना		
इस अध्याय से संबंधित	1.1	1
लेखापरीक्षितों की रूपरेखा	1.2	2
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.4	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.5	4
निष्पादन लेखापरीक्षा	1.5.1	4
अनुपालन लेखापरीक्षा	1.5.4	10
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूलियाँ	1.6	12
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रिया का अभाव	1.7	13
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की अनुक्रिया	1.8	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुकरण	1.9	14
स्वायत्त निकायों के लिए अलग लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों को राज्य सदन में प्रस्तुतत करने का प्रावधान	1.10	15
अध्याय-2 निष्पादन लेखापरीक्षा		
कल्याण विभाग		
मेसो क्षेत्र में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम	2.1	17
शहरी विकास विभाग		
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	54
जल संसाधन विभाग		
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत झारखण्ड में सिंचाई क्षमता के संभाव्य का सृजन	2.3	101
पंचायती राज विभाग		
पंचायत भवनों का निर्माण	2.4	124

अध्याय-3 **जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा**		
पलामू का जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा	3.1	141
अध्याय-4 **सरकारी विभाग के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा**		
पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग की कार्यप्रणाली	4.1	191
अध्याय-5 **अनुपालन लेखापरीक्षा**		
नियमों का अनुपालन नहीं	***5.1***	227
पथ निर्माण विभाग		
मूल्य समायोजन पर परिहार्य व्यय	5.1.1	227
भवन निर्माण विभाग		
एकरारनामा का अनाधिकृत कार्यान्वयन	5.1.2	230
ग्रामीण कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग		
अग्रिमों का वसूली न होना	5.1.3	232
वित्त विभाग		
मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता का अग्राह्य भुगतान	5.1.4	234
औचित्य लेखापरीक्षा/औचित्य विरूद्ध व्यय	***5.2***	236
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग		
ठेकेदार को अदेय भुगतान	5.2.1	236
जल संसाधन विभाग		
ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ	5.2.2	238
पथ निर्माण विभाग		
बिना पहुँच पथ के पुल निर्माण पर निष्फल व्यय	5.2.3	239
ग्रामीण कार्य विभाग एवं झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण		
निष्फल व्यय एवं परिनिर्धारित क्षति की वसूली न होना	5.2.4	241

दृष्टिचूक/शासन की विफलता	***5.3***	244
पथ निर्माण विभाग		
सरकारी राशि का अवरोध	5.3.1	244
बेली पुल के निर्माण में योजना का अभाव	5.3.2	246
लगातार एवं बारंबार होने वाली अनियमितताएं	***5.4***	248
वन एवं पर्यावरण विभाग		
दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण एवं वर्तमान निवल मूल्य का कम वसूलीकरण	5.4.1	249

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी	1.7	253
2.1	प्रोटो टाईप योजनाओं का अवलोकन एवं प्रति इकाई लागत	2.1.6	254
2.2	बैच के अनुसार आ.क.आ. द्वारा स.ज.वि.अ. एवं स.ज.वि.अ. द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्गत की गई राशि की विवरणी	2.1.7	255
2.3	चाईबासा स.ज.वि.अ. में अपूर्ण योजनाओं की विवरणी	2.1.7.4	256
2.4	साहेबगंज स.ज.वि.अ. में अपूर्ण योजनाओं के असमायोजित अग्रिम की विवरणी	2.1.7.4	257
2.5	पाँच स.ज.वि.अ. में स्वीकृत एवं कार्य बल की स्थिति का ब्यौरा	2.1.12	258
2.6	जेएनएनयूआरएम के तहत झारखंड में मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं की सूची	2.2.5	260
2.7	सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति राज्य स्तरीय सुधार	2.2.6.2	261
2.8	झारखण्ड में जेएनएनयूआरएम के तहत परियोजनाओं केलिए निधि के आवंटन का स्वरूप	2.2.7.1	264
2.9	निधि के उपयोग का प्रतिशत दर्शाती विवरणी (चयनित परियोजनाएं)	2.2.7.2	265
2.10	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	2.2.7.2	266
2.11	अर्जित ब्याज, उसकी निकासी और जीआरडीए लिमिटेड के प्रशासनिक खाते में हस्तांतरित राशि को दर्शाती विवरणी	2.2.7.3	267
2.12	मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान और वसूली का विवरण	2.2.8.3	269
2.13	बी.ओ.क्यु. के अनुमोदन के बिना निविदाकर्ताओं को आवंटित किये गये आधारभूत संरचनओं के कार्य	2.2.8.10	270
2.14	सफ़ाई उपकरणों और वाहनों की अनुमोदित दर से अधिक दर पर खरीद को दर्शाती विवरणी	2.2.8.15	272
2.15	सफ़ाई वाहनों के अपर्याप्त उपयोग को दर्शाती विवरणी	2.2.8.16	273
2.16	सभी परियोजनाओं की संक्षिप्त विवरणी	2.2.10	275
2.17	त्वरित सिंचाई लाभ योजना (त्व.सिं.ल.यो.) के अन्तर्गत ली गई परियोजनाओं के स्थिति मार्च 2012	2.3.1 एवं 2.3.3.1	277

2.18	प्रगतिशील सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की स्थिति मार्च 2012 तक केन्द्रीय ऋण/अनुदान सहित	2.3.2.1 एवं 2.3.3.1	278
2.19	चयनित परियोजनाओं के अपूर्ण कार्यों की विवरणी नवम्बर/दिसम्बर 2012 तक	2.3.4	279
2.20	2007-08 तक एकरारित कार्यों जो कि अबतक अपूर्ण है, कि विवरणी	2.3.4	283
2.21	अत्यधिक भुगतित राशि के नहीं वसूली की विवरणी	2.3.4.2	286
2.22	चयनित लघु सिंचाई परियोजनाओं के दिसम्बर 2012 तक की स्थिति की विवरणी	2.3.4.4	287
2.23	आठ चयनित जिलों में जाँच किये गए पंचायत भवनों को दर्शाने वाली विवरणी	2.4.2	288
2.24	पंचायत भवनों के निर्माण एवं व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.4.3	293
2.25	आठ चयनित जिलों में अपूर्ण पंचायत भवनों पर किये गए व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.4.3	295
3.1	विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों का विवरण	3.1.5	299
3.2	महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं/ कार्यक्रमों के संबंध में निधि प्रवाह व्यवस्था	3.1.7.1	300
3.3	मार्च 2012 में डीआईएसई के आँकड़ों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात	3.1.8.2	301
3.4	विद्यालयों में मौलिक सुविधाओं का विवरण	3.1.8.4	302
3.5	मूलभूत उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा सुविधा की विवरणी	3.1.10.3	303
3.6	एनआरएचएम के अंतर्गत जिला में स्वीकृत बल (स) पदस्थापन (प) की स्थिति की विवरणी	3.1.10.4	304
3.7	आई.ए.वाई. आवास निर्माण की भौतिक उपलब्धि	3.1.13	305
3.8	अन्नपूर्णा, बीपीएल, एएवाई एवं अतिरिक्त बीपीएल योजना के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) द्वारा कम दर्शाए गये खाद्यान की विवरणी	3.1.14	306
3.9	पीएमजीएसवाई सड़क के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विवरणी	3.1.18.1	307
3.10	31 मार्च 2012 को स्वीकृत एवं कार्यरत बल की स्थिति की विवरणी	3.1.20.7	308

4.1	पशुपालन निदेशालय का संगठनात्मक ढाँचा	4.1.2	309
4.2	गव्य विकास निदेशालय का संगठनात्मक ढाँचा	4.1.2	310
4.3	प.स्वा.एवं उ.सं., कांके राँची द्वारा विभिन्न टीकाओं के उत्पादन का लक्ष्यि एवं उपलब्धि	4.1.7.1	311
4.4	स्वीकृत एवं कार्यरत बल की विवरणी	4.1.7.2	312
4.5	पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत योजनाओं का विवरण	4.1.9	313
4.6	दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम के प्राक्कलित राशि का विवरण	4.1.9.6	315
4.7	पशु वितरण योजना की स्थिति का विवरण	4.1.9.6	316
4.8	झारखण्ड डेयरी परियोजना के प्रगामी लक्ष्य एवं उपलब्धि	4.1.9.9	317
4.9	संयुक्त क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा निरीक्षण का विवरण	4.1.10	318
5.1	ग्रामीण कार्य प्रमंडल गढवा के लम्बित अस्थाई अग्रिमों की विवरणी	5.1.3	319
5.2	ग्रामीण विशेष कार्य प्रमंडल (आर.डी.एस.) गुमला के लम्बित अस्थाई अग्रिमों का ब्यौरा	5.1.3	320
5.3	मार्च 2007 से मई 2011 के दौरान लिया गया अधिक मकान किराया भत्ता की विवरणी	5.1.4	322
5.4	मार्च 2009 से मई 2011 के दौरान भुगतान किए गये अग्राहय परिवहन भत्ता का विवरणी	5.1.4	323
5.5	डी.आई.पाईपों (के-9) के गलत दर विश्लेषण के कारण अधिकाई भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी	5.2.1	324
5.6	डी.आई.पाईपों के गलत दर विश्लेषण के कारण अधिकाई भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी (के**-7)**	5.2.1	325
5.7	डी.आई.पाईपों (के-9) की भाड़ा लागत के अन्याय संगत व्यय को दर्शानेवाली विवरणी	5.2.1	326
5.8	डी.आई.पाईपों (के-7) की भाड़ा लागत के अन्याय संगत व्यय को दर्शानेवाली विवरणी	5.2.1	326

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्य सदन में राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक और आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन का प्रथम अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं विस्तार, प्रारूप कंडिकाओं एवं वार्षिक प्रतिवेदनों पर विभाग की प्रतिक्रिया एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का सारांश प्रस्तुत करता है। व्दितीय अध्याय चयनित योजनाओं/परियोजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है जबकि तृतीय अध्याय पलामू का जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा पर उठाये गये अवलोकनों से संबंधित है। चतुर्थ अध्याय में पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग की कार्यप्रणाली के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्षो को सम्मिलित किया गया है और अध्याय पाँच में विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

राज्य सरकार, राज्य वित्त से संबंधित अवलोकनों, राजस्व क्षेत्र के इकाईयों से सम्बन्धित अवलोकनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित अवलोकनों को अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले जो वर्ष 2011-12 के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये थे, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे, वैसे मामले तथा वर्ष 2011-12 के बाद की अवधि से संबंधित मामले जहाँ आवश्यक है, भी सम्मिलित किये गए हैं।

अध्याय – 1

प्रस्तावना

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 इस अध्याय से संबंधित

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) का यह प्रतिवेदन निष्पादन लेखापरीक्षा के चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर उठाये गये मामलों और सरकारी विभागों एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखा परीक्षित इकाईयों के व्यय से संबंधित लेन-देनों की जाँच द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन हुआ है या नहीं । जबकि, निष्पादन लेखापरीक्षा, में यह जाँच किया जाता है कि कार्यक्रम/गतिविधि/विभाग के उद्देश्यों को मितव्ययिता, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को राज्य विधायिका के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानदण्डों में अपेक्षित है कि प्रतिवेदन का विषयात्मक स्तर लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा और विशालता के अनुपात में होनी चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि कार्यपालक द्वारा सुधारात्मक उपायों को लागू किया जाएगा और अपने नीति निर्धारण और निर्देशों द्वारा संगठन के वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाएगा जो अच्छे प्रशासन में सहायक सिद्ध होगा।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना एवं विस्तार के साथ ही चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन, लेन-देन की लेखापरीक्षा के दौरान किया गया महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुपालन का सारांश भी प्रदत्त करता हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में चयनित कार्यक्रम/गतिविधि/विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा में उठाये गये निष्कर्ष सन्निहित है। अध्याय-3 में जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा पर हमारे निष्कर्ष सन्निहित है। अध्याय-4 में पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग के कार्यो के मुख्य नियंत्रक पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा का मुल्यांकन प्रस्तुत करता है। अध्याय-5 सरकारी विभागों में हुए अनुपालन का लेखापरीक्षा पर प्रेक्षण सन्निहित है।

1.2 लेखा परीक्षितों की रूपरेखा

सचिवों/प्रधान सचिवों द्वारा शीर्षीत, सचिवालय स्तर पर राज्य में 43 विभाग है, जिन्हें निदेशकों/आयुक्तों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त होता है, जिनका लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड द्वारा किया जाता है। 112 स्वायत निकायों का नियंत्रण सरकार के विभिन्न विभागों के अधिन होता है। इसके अतिरिक्त राज्य में 4,706 पंचायती राज्य संस्थाये (पी.आर.आई.) और 39 शहरी स्थानीय निकाये (यू.एल.बी.) हैं।

वर्ष 2011-12 और पूर्व वर्ष में सरकार द्वारा वहित व्यय का तुलनात्मक स्थिति **तालिका-1 में** दिया गया है।

तालिका-1 चालू वर्षों में राजकोषीय लेन-देन का सार

(₹ करोड़ में)

2010-11	प्राप्तियाँ	2011-12	2010-11	संवित्तरण	2011-12		
अनुभाग-अ:राजस्व					**गैर-योजना**	**योजना**	**कुल**
18781.12	राजस्व प्राप्तियाँ	**22419.45**	**17944.74**	राजस्व व्यय	**13345.30**	**7646.28**	**20991.58**
5716.63	कर राजस्व	6953.89	6990.80	सामान्य सेवायें	7399.49	446.07	7845.56
2802.89	गैर कर राजस्व	3038.22	6707.30	सामाजिक सेवायें	3728.14	3558.89	7287.03
6154.35	युनियन का कर/सेवाकर का अंश	7169.93	4246.47	आर्थिक सेवायें	2217.67	3641.32	5858.99
4107.25	भारत सरकार से अनुदान	5257.41	0.17	सहायता अनुदान एवं जमा	--	--	--
अनुभाग-ब:पूँजी							
-	विविध पूँजी प्राप्तियाँ	-	2664.30	पूँजी परिव्यय	47.88	3111.49	3159.37
24.12	ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ	23.42	307.56	वितरित ऋण एवं अग्रिम	31.21	185.89	217.11
1.39	अंतर्राजीय परिशोधन						
2446.51	लोक ऋण प्राप्तियाँ	2671.23	1299.43	लोक ऋण का भुगतान	-	-	1639.01
-	आकस्मिकता निधि का स्थानांन्तरण	-	-	आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-
7721.42	लोक लेखा प्राप्तियाँ	10813.40	7399.85	लोक लेखा संवितरण			9727.77
640.91*	प्रारंभिक नगद शेष	(-)0.41	-(-)0.41	अन्तर्राजीय परिशोधन			75.40
				नगद अंतशेष			116.85
29615.47	**कुल**	**35927.09**	**29615.47**	**कुल**	**13424.40**	**10943.66**	**35927.09**

स्रोत:- वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए वित्तीय लेखा

* अर्थोपाय अग्रिम एवं उपभुक्त ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत शुद्ध लेन-देन को छोड़कर।

1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियाँ

और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त है1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, (डी.पी.सी.) अधिनियम की परिच्छेद 13[1] के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. द्वारा सम्पादित किया जाता है। सी.ए. जी. 23 स्वायत्त निकायों जो सी.ए जी (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 के परिच्छेद 19(2)[2] एवं 20(1)[3] के अन्तर्गत लेखापरीक्षित होती है, का एक मात्र लेखापरीक्षक है। इसके अतिरिक्त, सी.ए.जी (डी.पी.सी.) अधिनियम के परिच्छेद 14[4] के अन्तर्गत 89 अन्य स्वायत्त निकायों जिन्हें सरकार द्वारा यथोचित रूप से, निधित किया जाता है, सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। लेखापरीक्षा के विभिन्न सिद्धान्त एवं पद्धतियाँ सी.ए.जी द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा एवं लेखों 2007 के विनियमनों में विहित है।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया सरकारी विभागों द्वारा किये गये खर्चों क्रियाकलापों की गहनता/जटिलता सौंपे गये वित्तीय शक्तियों और पूरा आंतरिक नियंत्रण एवं अंशधारकों से संबंधित जोखिम के आकलन के आधार पर प्रारम्भ की जाती है। इस जाँच में पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों का भी ध्यान रखा जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा के बारंबारता एवं विस्तार का निर्णय किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा के पूर्णता के पश्चात् लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का निरीक्षण प्रतिवेदन को विभागों के प्रधान को निर्गत किया जाता है। विभागों से निरीक्षण प्रतिवेदन के प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, या तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों का निपटारा हो जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में

---

1 (i) राज्य के संचित निधि से सभी लेन-देन,(ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन और (iii) सभी व्यापारिक, निर्माण, लाभ एवं हानि लेखा, तुलन पत्र एवं अन्य सहायक खातों की लेखापरीक्षा।

2 सम्बद्ध विधायिका के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य विधायिका द्वारा बनाये गये नियम के अन्तर्गत या द्वारा स्थापित निगमों (कम्पनी नहीं) के लेखों की लेखापरीक्षा।

3 कैग एवं सरकार के मध्य सहमत वैसे उपबंधों एवं शर्तो पर, राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकार के लेखों का लेखापरीक्षा।

4 राज्य सरकार के संचित निधि से अनुदान एवं ऋणों द्वारा यथोचित पूंजीगत निकाय/प्राधिकार के सभी प्राप्तियों एवं व्यय का लेखापरीक्षा और (ii) किसी निकाय या प्राधिकार के सभी प्राप्तियों एवं व्यय जहॉ राज्य के संचित निधि से अनुदान या ऋण वैसे निकाय या प्राधिकार को जो वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम नहीं हो ।

उठाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे 6 सप्ताह के अन्तर्गत जवाब देने हेतु प्रशासनिक विभागों/सरकार को अग्रसारित किया जाता है। उत्तर के अप्राप्त या विभागों/सरकार के द्वारा दिये गये उत्तर के संतोष जनक नहीं होने के मामले में प्रारूप कंडिका को प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाता है और अंतत: जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है ताकि जिसे राज्य विधायिका के पटल पर प्रस्तुत किया जा सके।

2011-12 के दौरान, सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) प्रक्षेत्रों के 527 इकाईयों का लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के छ: निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा एवं लेखापरीक्षा के लिए 5,053 पार्टी दिवसों का उपयोग कर सम्पादन किया गया। लेखापरीक्षा योजना में उन इकाईयों[5]/प्रविष्टियों को लिया गया जो हमारे निर्धारण के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिम से भरे थे।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा, जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा, मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा के द्वारा कार्यक्रमों/कार्यकलापों में अनेकों महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जो कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के कार्यकलापों को प्रभावित किया। उसी प्रकार सरकारी विभागों/संगठनों के अन्तर्गत अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया।

1.5.1 निष्पादन लेखापरीक्षा

1.5.1.1 मेसो क्षेत्र में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम

आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं बचाव के लिए, ''जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) से विशेष केंद्रीय सहायता'' (वि.के.स.), केंद्रीय योजना को 15 समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (स.ज.वि.प.) में बाँटा गया था जो 13 जिलों को पुरी तरह एवं दो जिलों का आंशिक रूप से आच्छादित किया जिसे स्थानीय स्तर पर "मेसो क्षेत्र" के नाम से जाना जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत निम्न बाते देखी गयी:

[5] आर्थिक (नन-पी.एस.यू.) और सामान्य क्षेत्रों:87,सामाजिक क्षेत्र: 440

- फरवरी 2009 में राज्य सरकार ने जिला स्तर पर विस्तृत योजना बनाने एवं टी.एस.पी. के समेकन के लिये स.ज.वि.प. को समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (स.ज.वि.अ.) में प्रभावी एवं पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। स.ज.वि.अ फरवरी 2011 में निबंधित हो पाया और प्रस्तावित पूनर्गठन दिसंबर 2012 तक पूर्ण नहीं हो पाया। फलस्वरूप, मेसो क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं हुई।
- भारत सरकार "टी.एस.पी. के लिये वि.के.स." एवं संविधान की धारा 275 (i) के अधीन अनुदान के लिये 100 *प्रतिशत्* वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। 2007-12 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 559 करोड़ निर्गत किये जिसके विरूद्ध ₹ 557 करोड़, जनजातीय कल्याण आयुक्त (ज.क.आ.) को वितरित किये गये। हमने देखा कि स ज.वि.अ.एवं कार्यान्वयन अभिकरणों में निधि के अंतिम उपयोग सुनिश्चित किये बिना ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) भेज दिये गये जो कि ज.क.आ, नमूना स.ज.वि.अ. एवं कार्यान्वयन अभिकरणों के पास बड़ी राशि अव्यवहृत पड़े रहने से परिलक्षित होती है।
- 2011-12 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर की गई निकासी के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल नहीं जमा किये जाने के कारण ₹ 19.47 करोड़ की केन्द्रीय निधि की निकासी नहीं की जा सकी, जनजातीय कल्याण आयुक्त (ज.क.आ.) ने वैयक्तिक लेजर खाते में जमा करने हेतु ₹ 91.81 करोड़ की केन्द्रीय निधि की निकासी (मार्च 2012) की थी।
- चयनित स.ज.वि.अ. में, प्राटो टाईप योजनाओं के अन्तर्गत 181 स्वीकृत योजनाओं में से 167 योजनायें (92 *प्रतिशत्*) अपूर्ण थीं।
- विभिन्न वर्गों के स्वीकृत 90 पदों के विरूद्ध 45 व्यक्ति (50 *प्रतिशत्*) कार्यरत(जुलाई 2012 को) थे। फरवरी 2009 से स.ज.वि.अ. के निर्माण के समय से ही अपर परियोजना निदेशक और सहायक परियोजना प्रबंधक के पद रिक्त थे।
- राज्य स्तर पर विभाग में अनुश्रवण एवं मुल्यांकन कोषांग कार्यरत नहीं था, हाँलाकि इसका पुनर्गठन फरवरी 2011 में किया गया था।

(कंडिका 2.1)

1.5.1.2 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार ने 3 दिसंबर 2005 को शहरों के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) लागू किया, जिसे सात साल (2005-12) की अवधि में पूर्ण किया जाना था।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा किया गया और निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

- राज्य सरकार/यूएलबी द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.ए.) के अनुसार कुल 31 सुधारों में से केवल 22 को पूर्णत: लागू किया जा सका, जबकि सात सुधार आंशिक रूप से लागू किए गए थे तथा दो सुधारों को लागू किया जाना बाकी था । सुधार के अकार्यान्वयन/आंशिक कार्यान्वयन के कारण भारत सरकार ने ₹ 39.39 करोड़ का अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.के.स.) निर्गत नहीं किया।
- जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजना के अन्तर्गत ₹ 589.20 करोड़ की उपलब्ध धनराशि के विरूद्ध केवल ₹ 326.51 करोड़ (55.42 *प्रतिशत*) का उपयोग किया जा सका।
- राँची जल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत बी.ओ.क्यु. में दर्शायी गई 900 मिमी व्यास के पाइप की आवश्यकता से अधिक की आपूर्ति/ख़रीद के कारण संवेदक को ₹ 8.21 करोड़ का अतिरिक्त /अनाधिकृत भुगतान किया गया।
- गुमला में आईएचएसडीपी के अंतर्गत नकली चालानों के माध्यम से पथ प्रकाश सामग्री की ख़रीद में ₹ 22.48 लाख का गबन किया गया।

(कंडिका 2.2)

1.5.1.3 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत झारखण्ड में सिंचाई संभाव्य का सृजन

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत झारखण्ड में सिचाई संभाव्य का सृजन के लेखापरीक्षा में निम्न उद्घटित हुआ:

- पूर्व से चले आ रहे सिंचाई योजनाओं को त्वरित रूप से पूरा करने के लक्षित उद्देश्य में कार्यक्रम के असफल रहने के फलस्वरूप किसानों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा जबकि इन योजनाओं को शुरू हुए पाँच से 12 वर्ष बीत चुके थे।

- सरकार द्वारा 1.20 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के विरूद्ध, सिर्फ 0.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता मार्च 2012 तक सृजित हो सका।
- भूमि अधिग्रहण एवं आवश्यक सर्वे के कार्य प्रगति में विलम्ब के कारण वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा। निविदा प्रक्रिया के विलम्ब एवं कार्य की मंद गति के कारण लघु सिंचाई योजनाओं की प्रगति भी वाधित हुई।
- नमूना जाँचित प्रमण्डलों ने 33 *प्रतिशत्* आंवटित राशि का उपयोग नहीं कर सका। पूर्ण हो चुके मध्यम सिंचाई योजनाओं के रख-रखाव नहीं होने और लघु सिंचाई परियोजनाओं में माइक्रोलिफ्ट्स स्थापित नहीं होने के कारण ए.आई.बी.पी के परियोजनाओं के अन्तर्गत सृजित सिंचाई क्षमताओं का भी पुरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा था ।
- योजनाओं का अनुश्रवण प्रभावोत्पादक नहीं था।

(कंडिका 2.3)

1.5.1.4 पंचायत भवनों का निर्माण

पंचायत भवनों के निर्माण के लेखापरीक्षा से निम्नलिखित कमियाँ पाई गई: जून 2012 तक 4,423 पंचायत भवन (पं.भ.) के विरूद्ध, 2,694 (पं.भ.) का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया/शुरू नहीं किया गया। विभिन्न स्तरों पर अप्रभावोत्पदाक योजना, वित्तीय अव्यवस्था और नियमित पर्यवेक्षण की कमी के दृष्टान्तों को पाया गया। इसके अलावे, कुछ पं.भ. यद्यपि पूर्ण हो चुके थे किन्तु न तो हस्तांतरित किये गए और न उस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हुए जिसके लिए निर्माण किया गया था। अत: सभी ग्राम पंचायतों में सुविधा केन्द्रों के रूप में पंचायत भवनों को स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य अप्राप्त रह गया।

(कंडिका 2.4)

1.5.2 पलामू का जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा

पलामू का जिला केंद्रित लेखापरीक्षा, जिले में वित्तीय मामलों में एवं महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति को मुख्य रूप से उजागर करती है। प्रतिवेदन में संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एन.आर.एच.एम.), समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.)

आपदा प्रबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता, राज्य सड़क और पुलिस आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं को सन्निहित कर तैयार की गई है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे विमर्शित है:

- किसी खास समय में सम्पूर्ण प्रक्षेत्रवार जिला में निधि का प्रवाह को दर्शाने की कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। जिला योजना समिति की बैठक सिर्फ एक ही बार हुई और इसकी कार्यप्रणाली दिखावटी एवं अपूर्ण रही। जिले का पंचवर्षीय विस्तृत योजना एवं वार्षिक कार्य योजना भी नहीं तैयार किया गया। अधिनियम के अंतर्गत निधि, कार्य एवं कार्यान्वयन का हस्तांतरण पंचायती राज इकाई (पी.आर.आई.) को भी नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)।
- एस.एस.ए. के अस्तित्व के बावजूद काफी संख्या में बच्चे स्कूल में नामांकित नहीं थे और छात्र-शिक्षक का अनुपात (पी.टी.आर.) निर्धारित मापदण्ड से नीचे था ।
- एम.डी.एम. योजना के क्रियान्वयन के क्रम में 1974.79 एम.टी. चावल जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़ था विद्यालयों के भण्डार पंजी में नहीं लिया गया जब की उसे एस.एफ.सी. गोदामों से निर्गत दिखाया गया था। एम.डी.एम. के अंतर्गत चावल की दूसरी योजनाओं में विचलन एवं कुकिंग फंड का दुरूपयोग भी पाया गया।
- एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन के बाद भी जिला, प्रखण्ड एवं गाँव स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या एन.आर.एच.एम. मानक की तुलना में कम पाया गया। स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए मूलभूत संरचना सुविधाएं अनुपयुक्त थी। 2009-12 के दौरान कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं मे संस्थागत प्रसव सिर्फ 40 *प्रतिशत्* पंजीकृत महिलाओं का ही हो पाया।
- आई.सी.डी एस. के अन्तर्गत अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी) में लागू ज्यादातर आंगनबाडी केन्द्रों में शौचालय, पेयजल इत्यादि की मुलभूत सुविधा नहीं थी।
- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल में 75 हजार आबादी के लिए दो पाईप जलापूर्ति योजना बीच में ही रोक दी गई जिसके फलस्वरूप पाईप के खरीद में खर्च किये गए ₹ 19.17 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। फ्लोराइड निस्तरण यंत्र के अक्रियाशील रहने के कारण उस पर हुए ₹ 7.01 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 1,457 लक्षित गाँवों के विरूद्ध सिर्फ 668 गांवों का विद्युतीकरण किया गया।
- पलामू जिला के पुलिस बल में पुराने एवं अप्रचलित हथियारों को चरणबद्ध तरीके से बाहर नहीं किया गया।

(कंडिका 3.1)

1.5.3 पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग का कार्यकलाप

पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग, झारखण्ड सरकार पशुओं के उपचार, टीकाकरण, बन्ध्याकरण, कृत्रिम गर्भाधान के साथ-साथ राज्य में दूध, मांस, अण्डा एवं ऊन के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है। पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग एवं गव्य विकास निदेशालय का मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में निम्नलिखित निष्कर्ष उद्घटित हुआ:

- नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के प्रावधान के तहत् राज्य में आवश्यक 1,756 पशु अस्पतालों के विरूद्ध केवल 451 अस्पताल थे। पशु अस्पतालों/चिकित्सालयों में पर्याप्त सरंचनायें नहीं थीं। इसके अलावे पशु चिकित्सकों की कमी (32 *प्रतिशत*) थी।
- राशि के आवंटन में विलंब के कारण योजना मद में राशि की भारी बचत हुई और मार्च के महीने में व्यय का वेग हुआ।
- बकरा विकास योजना के तहत सरकार ने बकरा शेड के निर्माण एवं बकरा खरीद को समक्रमित नहीं किया। बकरा खरीद हेतु निधि को विचलित किया गया।
- दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम के तहत 2007-11 के दौरान नमूना जाँचित जिलों में गायों के कम क्रय किये जाने के कारण 3,670 इकाईयाँ के विरूद्ध केवल 2,611 इकाईयाँ (71 *प्रतिशत*) ही स्थापित हुई।
- नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा प्रबंधित (एक एम.ओ.यू. के अन्तर्गत) झारखण्ड डेयरी प्रोजेक्ट (जे.डी.पी.) 2008-12 की अवधि में ₹ 11.10 करोड़ व्यय करने के पश्चात् कुल 12 में से 3 जिला ही दूध प्रापण एवं संसाधन हेतु आच्छादित कर सका।

(कंडिका 4.1)

1.5.4 अनुपालन लेखापरीक्षा

1.5.4.1 नियमों का अनुपालन नहीं

सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, विनियमों और आदेशों के तहत् व्यय किया जाता हो। यह न तो केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग एवं धोखेबाजी को रोकता है वरन् अच्छे वित्तीय अनुशासन के संधारण में भी मदद करता है। इस प्रतिवेदन में नियमों के अनुपालन न होने से संबंधित ₹ 55.20 करोड़ के उदाहरण समाहित है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार है:

- सरकारी आदेश के खिलाफ सड़क निर्माण के लिए कार्य संपादन हेतु अतिरिक्त समय दिए जाने के कारण अनुबंध में मूल्य समायोजन का क्लॉज शामिल करना पड़ा जिसके फलस्वरूप ₹ 6.25 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ ।

(कंडिका 5.1.1)

- संवेदक के निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त्तों के अधीन किए गए करार जिसमें मूल्यवृद्धि एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम अनुमान्य नहीं था के विरूद्ध विभाग ने ₹ 47.53 करोड़ रूपये मूल्य का कार्य जिसमें मूल्यवृद्धि एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम सन्निहित था का कार्य कराया। यह सभी निविदादाताओं को समान अवसर प्रदान करने का सरकार के आदेश का उल्लंघन था।

(कंडिका 5.1.2)

- अस्थाई-अग्रिम प्रदान करने एवं उनके समायोजन में संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 48.34 लाख के सरकारी धन की वसूली न होना।

(कंडिका 5.1.3)

- हकदार सीमा से अधिक मकान किराया भत्ता की स्वीकृति के कारण ₹ 23.18 लाख परिवहन भत्ता के साथ कुल ₹ 70.87 लाख रूपये का अग्राह्य भुगतान ।

(कंडिका 5.1.4)

1.5.4.2 औचित्य/बिना तर्कसंगत व्यय के विरूद्ध लेखापरीक्षा

लोक निधि से होने वाले व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धांत से मार्गदर्शीत किया जाना है। प्राधिकारियों, जिनमें व्यय करने की शक्ति निहित है से आशा की जाती है कि व्यय करते समय वे वैसा ही सतर्कता बरतें जैसा कि सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति स्वयं के पैसे को खर्च करते समय बरतता है तथा उन्हें प्रत्येक कदम पर वित्तीय आदेश व सशक्त मितव्ययिता को लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा में औचित्यहीन और अतिरिक्त व्यय के ₹ 10.47 करोड़ के दृष्टांतों का पता चला, जिसमें से कुछ निम्नवत है:

- संविदा के नियम एवं शर्तों में सरकार के निर्देशों को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 6.77 करोड़ की राशि का अदेय भुगतान द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया ।

(कंडिका 5.2.1)

- भैरवा और केसो जलाशय योजनाओं के बचे हुए कार्यों के संरचना और आलेख हेतु भुगतान में उच्चतर अधिकारी के आदेशों तथा अनुबंध के प्रावधानों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.08 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया।

(कंडिका 5.2.2)

- पहुँच पथ के लिए भूमि अधिग्रहण किए बिना कार्य प्रारंभ करने के कारण उच्च स्तरीय पुल के निर्माण पर ₹ 1.02 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

(कंडिका 5.2.3)

- कार्यपालक अभियंता द्वारा समय पर कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण ₹ 1.34 करोड़ का निष्फल व्यय के अलावे ₹ 25.50 लाख की परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 5.2.4)

1.5.4.3 दृष्टिचूक/शासन की विफलता

सरकार को लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का दायित्व है जिसके लिए यह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और बुनियादी संरचना के उन्नयन और जनसेवा आदि के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के तहत् कार्य करती है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में उदाहरण पाये गये, जहाँ सरकार द्वारा सामुदायिक

लाभ हेतु लोक संपदा की सृष्टि हेतु विमुक्त की गयी ₹ 15.76 करोड़ की राशि विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में असमर्थता एवं योजनाबद्ध तरीके का आभाव, प्रशासनिक दृष्टिचूक का अभाव, के कारण अनुपयोगित/अवरोधित और/या निष्फलसिद्ध/अ-उत्पादक रही। वैसे मामलों को नीचे विमर्शित किया गया है:

- लागत हिस्सेदारी के आधार पर प्रस्तावित पार पथ के प्राक्कलन के अनुमान्यता/स्वीकार्यता के बिना संहिता प्रावधानों/सरकारी आदेश के विरोध में दक्षिण पूर्वी रेलवे को अग्रिम दिया गया, फलस्वरूप सरकारी राशि ₹ 7.37 करोड़ का अवरोध हुआ तथा ₹ 2.30 करोड़ के सूद की हानि हुई।

(कंडिका 5.3.1)

- आपदा की स्थिति में बेली पुल के अधिष्ठापन एवं संयोजन हेतु तैयारी एवं योजना के अभाव में विभाग ₹ 6.09 करोड़ व्यय करने के बावजूद बेली पुल के द्वारा यातायात सम्बद्धता उपलब्ध कराने में असफल रहा।

(कंडिका 5.3.2)

1.5.4.4 सतत् एवं व्यापक होने वाली अनियमिताएं

एक अनियमितता को लगातार कहा जाता है जब वह निरंतर प्रत्येक वर्ष होता है। यह बारंबार हो जाता है जब यह पूरे प्रणाली में व्याप्त हो जाता है। पूर्व के लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बावजूद अनियमितताओं का पुन: होना कार्यपालिका के पक्ष में न केवल अगंभीरता को दर्शाता है बल्कि प्रभावी अनुश्रवण की कमी को भी दर्शाता है। बदले में यह नियम/विनियम का जानबूझ कर अनदेखी करने को प्रोत्साहित करता है तथा प्रशासनिक ढाँचा को कमजोर करने के परिणाम के रूप में आता है। लेखापरीक्षा में निम्न पता चला:

- दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण एवं वर्तमान निवल मूल्य का कम निर्धारण के परिणामस्वरूप **₹** 65.34 लाख क्षतिपूरक वनरोपण एवं **₹** 80 लाख वर्तमान निवल मूल्य का कम वसूली हुआ ।

(कंडिका 5.4.1)

1.6 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूलियाँ

2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर 26 मामलों में ₹ 20.64 लाख की राशि वसूली की गयी। इसके अतिरिक्त, प्रमंडलीय वन पदाधिकारी, सारंडा

वन प्रमंडल, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वर्त्तमान निवल मूल्य ₹ 17.20 करोड़ की राशि का संग्रहण किया गया (सितम्बर 2012)।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रिया का अभाव

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सरकारी विभागों का आवधिक लेखापरीक्षा निरीक्षण करने की व्यवस्था करता है जिसमें नमूना जाँच द्वारा लेन-देन और महत्वर्पूण लेखा और अन्य अभिलेखों का संधारण, नियमों एवं कार्यपद्धति के अनुसार किया जा रहा है या नहीं, को सत्यापित किया जाता है। ये निरीक्षणें, निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा अनुगमन की जाती है। लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन संबंद्ध विभाग के सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के अनुश्रवण एवं निपटारा के लिए भेजा जाता है। कार्यालयों के प्रधान एवं उनके उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट निष्कर्षों का अनुपालन और दोषों को शीघ्रातिशीघ्र सुधार करने और अपने अनुपालन को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रतिवेदित करना अपेक्षित है।

30 जून 2012 तक, 2002-12 की अवधि से सम्बन्धित 2,819 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का 17,857 कंडिकाएं लम्बित थीं। वर्षवार निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विवरण ***परिशिष्ट-1.1*** में अंकित है। इनमें से 921 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 6,682 कंडिकाओं पर प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ था।

जून 2010, जून 2011 एवं जून 2012 तक लम्बित नि.प्र./कंडिकाओं की स्थिति **तालिका-2** में दर्शित है

तालिका-2

लंम्बित नि.प्र./कंडिकाओं की स्थिति

विवरण	अंत तक लंबित		
	जून 2010	जून 2011	जून 2012
निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3658[6]	3286	2819
कंडिकाओं की संख्या	20047	18962	17857

लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं पर कार्रवाई में कमी, प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, शासन की आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया की कमजोरी, अक्षम और अप्रभावी सार्वजनिक सामग्री का विवरण,

[6] लम्बित नि.प्र. एवं कंडिकाओं की संख्या में ह्रास।

कपट, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक राजकोष की हानि जैसी वित्तीय खतरे से निरंतर प्रभावित है।

सचिवों, जिन्हे अर्द्धवार्षिकीय प्रतिवेदनों के तहत् स्थिति की जानकारी दी गयी थी, सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा शीघ्र एवं सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

1.8 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की अनुक्रिया

2012-13 के दौरान, 11 प्रारूप कंडिकायें एवं छः प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा/जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा/मुख्य नियंत्री आधारित लेखापरीक्षा/ लम्बी प्रारूप कंडिकायें, संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के भीतर अपना मन्तव्य भेजने के लिए अग्रसारित किया गया था। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले इन कंडिकाओं को उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया ताकि राज्य के विधानसभा में उपस्थापित करने से पहले इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनके संभावित मन्तव्य/जवाब शामिल किये जा सकें। इसके बावजूद, पाँच प्रारूप कंडिकाओं एवं तीन समीक्षा/लम्बी प्रारूप कंडिकाओं पर सरकार का जवाब अप्राप्त रहा। विभागों से प्राप्त जवाब यथोचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर ली गयी है ।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुकरण

व्याख्यात्मक (की गई कार्रवाई) टिप्पणी का अप्रस्तुतीकरण

बिहार सराकर के वित्त विभाग के निर्देशन नियमावली (1998) (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) में समाविष्ट था कि सम्बद्ध विभागों के सरकार के सचिवों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ए.आर.) में सम्मिलित की गई कंडिकाओं एवं समीक्षाओं का पुनरीक्षण कर लोक लेखा समिति के किसी टिप्पणी या निर्देश की प्रतिक्षा के बिना विधायिका के समक्ष ए.आर.के प्रस्तुतीकरण की तिथि से दो माह के अन्दर विधान सभा सचिवालय को निर्धारित मानकों से वैसे विचलनों/अनियमितताओं के घटित होने की परिस्थितियों एवं कारणों और प्रस्तावित कार्रवाई/की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन (नवम्बर 2007) के नियम 213 में समाविष्ट है कि केन्द्र, राज्य एवं केन्द्रशासित क्षेत्र जहाँ विधान सभा है एवं विधायिका संचालित हैं जहाँ सरकार चाहती है कि नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक की गई कार्रवाई की टिप्पणियों (ए.टी.एन.) की जाँच करें, सम्बद्ध विभागों के सरकार के सचिवों को प्रारूप कार्रवाई स्वव्याख्यात्मक टिप्पणियों को दो प्रतियों में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सम्बद्ध संचिकाओं एवं दस्तावेजों को जिसके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियों को प्रतिपादित किया गया है, उपयुक्त ढंग से उल्लिखित एवं जुड़ाव किया गया है, को भेजना चाहिए। इसको वैसे समयावधि में करना है जो पीएसी द्वारा स्वयं व्याख्यात्मक टिप्पणी के प्रस्तुतीकरण के लिए निर्णय किया गया हो।

यह पाया गया कि दिसम्बर 2012 तक वर्ष 2000-01 से 2010-11 और दिसम्बर 2012 तक विधान सभा में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 271 कंडिकाओं/समीक्षाओं में से, 128 के सम्बन्ध में 13 विभागों[7] द्वारा कोई अनुपालन या व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई।

लोक लेखा समिति के अनुशंसाओं पर कार्रवाई का ना होना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शित कंडिकाओं के निपटारा के लिए निर्देशित नियमावली के अनुसार, लोक लेखा समिति के अनुशंसाओं पर, विभागों को पीएसी को अपने प्रतिवेदन द्वारा किये गये अनुशंसाओं की तिथि से दो माह के अंदर पीएसी को की गई कार्रवाई टिप्पणी (ए.टी.एन.) को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

यह देखा गया कि दिसम्बर 2012 तक पीएसी द्वारा 201 कंडिकाओं का विमर्शित किया गया एवं नवम्बर 2000 और फरवरी 2013 के मध्य 31 कंडिकाओं के विरूद्ध अनुशंसायें की गयी। इनमें से दिसम्बर 2012 तक केवल 11 मामलों में ए.टी.एन. प्राप्त किया गया था।

1.10 स्वायत्त निकायों के लिए अलग लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों को राज्य सदन में प्रस्तुत करने का प्रावधान

2011-12 के दौरान, राज्य सदन में स्वायत्त निकायों के लिए अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपस्थापित नहीं किया गया था।

[7] पशुपालन एवं मत्स्य पालन, कला संस्कृति एवं युवा मामले. मंत्रिमंडल (निर्वाचन), मंत्रिमंडल (निगरानी), आपदा प्रबन्धन, ऊर्जा, खाद्य, सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले, आवास, गृह (जेल),श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण,लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण,राज्य भाषा एवं पर्यटन विभाग

अध्याय -2

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-2

कल्याण विभाग

2.1 मेसो क्षेत्र में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

कार्यकारी सारांश

आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं शोषण से बचाव के लिए, केंद्रीय योजना "जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) को विशेष केंद्रीय सहायता (वि.के.स.)" को 15 समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (स.ज.वि.अ.) में बाँटा गया था जो 13 जिलों को पूरी तरह एवं दो जिलों में आंशिक रूप से आच्छादित किया जिसे स्थानीय स्तर पर "मेसो क्षेत्र" के नाम से जाना जाता है।

समेकित जनजातीय विकास अभिकरणों (स.ज.वि.अ.) के द्वारा चलाये जाने वाले जनजातीय कल्याण योजनाओं को भारत सरकार द्वारा जनजातीय उपयोजना के लिये वि.के.स. के अंतर्गत प्रोटो टाईप योजनाओं के द्वारा स्थायी आजीविका के साथ आय अर्जन के लिये तथा आधारभूत ढाँचे की कमी को पाटने हेतु संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत वित्त-पोषण किया जाता है।

हमनें 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिये "मेसो क्षेत्र में जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों" के कार्यांवयन के लिये निष्पादन लेखापरीक्षा की। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

- फरवरी 2009 में राज्य सरकार ने जिला स्तर पर विस्तृत योजना बनाने एवं टी एस पी के समेकन के लिये स.ज.वि.प. को स.ज.वि.अ. में मजबूत एवं पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। स.ज.वि.अ. फरवरी 2011 में निबंधित हो पाया और प्रस्तावित पुनर्गठन दिसंबर 2012 तक पूर्ण नहीं हो पाया। फलस्वरूप मेसो क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं हो पायी। आगे राज्य सरकार ने केन्द्र सहायत हेतू स.ज.वि.अ. से सूचना प्राप्त किये बिना ही वार्षिक योजना तैयार की। हमनें पाया कि वर्ष 2005 में प्रदान नामक एक एन.जी.ओ. के द्वारा गाँवों के आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाओं का आँकड़ा तैयार किया गया था परंतु उसे विगत सात वर्षो के दौरान अद्यतन नहीं किया गया। अत: सरकार द्वारा वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के दौरान मेसो क्षेत्र के वास्तविक जरूरतों को सुनिश्चित नहीं किया गया।

सरकार को मेसो क्षेत्र में विस्तृत योजना के लिये स.ज.वि.प. का प्रस्तावित पूनर्गठन एवं टी.एस.पी. का समेकन पूर्ण करना चाहिये। प्रदान द्वारा तैयार किये गये आँकड़ो को अद्यतन करना चाहिये और योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लक्षित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त होने के बाद ही योजना का अंतिमिकरण किया जाना चाहिये।

- भारत सरकार 100 *प्रतिशत्* वित्तीय सहायता "टी.एस.पी. के लिये वि.के.स." एवं सविधान की धारा 275 (1) के अधीन अनुदान मुहैया कराती है। 2007-12 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 559 करोड़ विमुक्त किये जिसके विरूद्ध ₹ 557 करोड़ आदिवासी कल्याण आयुक्त (आ.क.आ.) को संवितरित किये गये। हमने देखा कि स.ज.वि.अ. एवं कार्यान्वयन अभिकरणों में निधि के अंतिम उपयोग सुनिश्चित किये बिना ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) भेज दिये गये जो कि आ.क.आ., स.ज.वि.अ. एवं कार्यान्वयन अभिकरणों के पास में अव्यवहृत पड़ी बड़ी राशि से परिलक्षित हुई। फलस्वरूप, बड़ी संख्या में योजनायें अपूर्ण रही।
- 2011-12 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर की गई निकासी के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल नहीं जमा किये जाने के कारण ₹ 19.47 करोड़ के केन्द्रीय निधि की निकासी नहीं की जा सकी, आ.क.आ. ने ₹ 91.81 करोड़ के केन्द्रीय निधि की निकासी (मार्च 2012) कर वैयक्तिक बही खाते में जमा किया।

  सरकार को निधियों का समय पर उपयोगिता सुनिश्चित करना चाहिये और निधियों के अंतिम उपयोग के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किये जाने चाहिये।

- दिसंबर 2012 तक मेसो क्षेत्र में 353 स्वीकृत योजनाओं (2006-12) में से 271 अपूर्ण योजनाओं (77 *प्रतिशत्*) के मामले थे। नमूना स.ज.वि.अ. में प्रोटो टाइप के अंतर्गत 181 स्वीकृत योजनाओं में से 167 योजनायें (92 *प्रतिशत्*) अपूर्ण थीं। हमने वैसी योजनाओं पर भी व्यय देखा जो निरर्थक, अलाभप्रद, निष्फल और योजना के दायरे से बाहर के थे।
- हमने आधारभूत संरचना के निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने के दृष्टांत देखे। नमूना स.ज.वि.अ. में स्वीकृत 193 आंगनबाड़ी केन्द्रों (आं.के.) में से 96 आ.के. अपूर्ण थे जबकि 54 का कार्य प्रारंभ नहीं किये थे। चार जनजातीय आवासीय विद्यालयों के लिये 2005 में स्वीकृत छात्रावास जनवरी 2013

तक पूर्ण नहीं थे। पुन: 2003 में प्राथमिक रेफरल इकाई के रूप में प्रस्तावित 14 मेसो ग्रामीण अस्पतालों का निर्माण देर से हुआ और उनमें से पाँच अभी तक चालू नहीं हो पाये।

सरकार को योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से करनी चाहिये एवं परियोजनाओं को तय समय में पूर्ण होना सुनिश्चित करना चाहिये।

- नमूना स.ज.वि.अ. के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में मानव संसाधन की कमी एक रूकावट थी। विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत 90 पदों के विरूद्ध 45 पदों पर कर्मी (50 *प्रतिशत*) कार्यरत (1 जुलाई 2012) थे। फरवरी 2009 में स.ज.वि.अ. के गठन के समय से ही अपर परियोजना निदेशक और सहायक परियोजना प्रबंधक के पद खाली थे।

  सरकार को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त मानव संसाधन मुहैया कराना सुनिश्चित करना चाहिये।

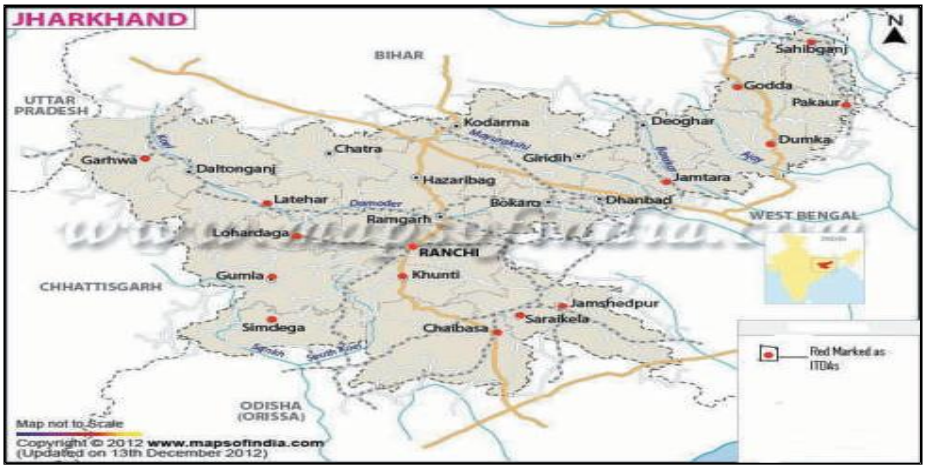
- राज्य स्तर पर विभाग में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग कार्यरत नहीं था जबकि इसका पुनर्गठन फरवरी 2011 में किया गया था। इसी प्रकार योजनाओं के प्रगति की समीक्षा परियोजना कार्यान्वयन समिति एवं परियोजना निदेशकों द्वारा नियमित अंतराल पर नहीं किया गया था। परियोजना निदेशक (प.नि.) के द्वारा कार्य स्थल के निरीक्षण के लिये सरकार ने कोई अनुसूचि नहीं तय की थी। प्रभावी अनुश्रवण तंत्र के अभाव ने योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन को प्रभावित किया।

  योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक स्तर पर निर्धारित एवं सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

2.1.1 प्रस्तावना

देश में अनुसूचित जनजातियों की छठी बड़ी आबादी झारखण्ड में है। 2001 के जनगणना के अनुसार झारखण्ड की कुल आबादी 2.69 करोड़ में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) की आबादी 70.87 लाख थी जो 26 *प्रतिशत* थी। अ.ज.जा. के बीच शिक्षा दर 40.7 *प्रतिशत* (2001) थी जो अ.ज.जा. की आबादी के राष्ट्रीय औसत (47.1 *प्रतिशत*) से काफी कम थी। आदिवासियों के विकास के लिये राज्य सरकार की कोशिशों की सहायता के लिये, भारत सरकार ने जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.) के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (वि.के.स.) प्रारंभ (1977-78) की। तदनुसार टी.एस.पी. को राज्य में 15 समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (स.ज.वि.प.) में बाँटा (फरवरी

2009) गया जो 13 जिलों[1] में पूर्ण रूप से एवं दो जिलों[2] को आंशिक रूप से आच्छादित किया। अ.ज.जा. आबादी के लिये विस्तृत विकास कार्यक्रम बनाने हेतु इन स.ज.वि.प. द्वारा आच्छादित क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था जो स्थानीय स्तर पर मेसो के नाम से जाना जाता है। नीचे झारखण्ड के नक्शे में मेसो क्षेत्रों को दर्शाया गया है।



भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं[3] के क्रियान्वयन के लिये और जनजातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं शोषण से बचाव के साथ ही साथ अनुसुचित जाति, अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्प संख्यकों के कल्याण के लिये कल्याण विभाग उत्तरदायी है। राज्य सरकार आय उत्पादक योजनाओं एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिये 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में भारत सरकार से वि.के.स प्राप्त करती है। राज्य के जनजातीय परामर्शी परिषद की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने मेसो क्षेत्रों, जिसके प्रमुख, परियोजना पदाधिकारी हैं जो टी.एस.पी. के लिये वि.के.स. एवं संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, को मजबूत करने एवं पुनर्गठन करने के लिये एवं जनजातीय विकास के लिये निधियों के बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करने के क्रम में स.ज.वि.आ. जिसके प्रमुख एक परियोजना निदेशक है बनाने का संकल्प (फरवरी 2009) लिया जिसे समिति निबंधन अधिनियम 1860 के अंतर्गत समिति के रूप में निबंधित होना था। स.ज.वि.अ. फरवरी 2011 में ही

---

1 दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामतारा, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, राँची, साहेबगँज, सरायकेला, सिमडेगा एवं प0 सिहंभूम (चाईबासा एवं चक्रधरपुर)।

2 गढ़वा जिला में एक प्रखण्ड और गोडडा जिला में दो प्रखण्ड।

3 जनजातीय उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता और संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत योजनायें (यथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और मेसो ग्रामीण अस्पताल इत्यादि) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

समिति निबंधन अधिनियम के अंतर्गत निबंधित हुए और प्रस्तावित पुनर्गठन दिसंबर 2012 तक पूर्ण नहीं हो पाया क्योंकि टी.एस.पी. के समेकन के लिये जिला कल्याण पदाधिकारियों क.स.ज.वि.अ. में विलय नहीं हो पाया था।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

कल्याण विभाग मेसो क्षेत्र में जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये प्रशासनिक विभाग है और प्रधान सचिव इसके प्रमुख है जिनकी सहायता के लिये एक विशेष सचिव, एक संयुक्त सचिव और तीन उप सचिव हैं। राज्य स्तर पर आदिवासी कल्याण आयुक्त क्रियान्वयन अभिकरण हैं। मेसो क्षेत्र स्तर पर एक परियोजना क्रियान्वयन समिति (प.कि.स.) होती है जिसमें उपायुक्त पदेन अध्यक्ष, परियोजना निदेशक (स.ज.वि.अ.) उपाध्यक्ष सह सदस्य सचिव एवं जिला योजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के उप विकास आयुक्त, तकनीकी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी और लोक प्रतिनिधि[4] सदस्य होते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये लाभुकों के चयन एवं स.ज.वि.अ. के शासी निकाय से स्वीकृति के लिये प.कि.स. उत्तरदायी है। प्रखण्ड स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन अन्य लाइन विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से होता है। पुनर्गठित संरचना के अंतर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.प.) को स.ज.वि.अ. के अधीन ले आना था। हाँलाकि प्रस्तावित विलय दिसंबर 2012 तक नहीं हो पाया।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- कल्याण कार्यक्रमों के पहचान के लिये योजना पर्याप्त और विश्वसनीय आँकड़ों पर आधारित थी;
- निधियों का आवंटन, विमुक्ति एवं उपयोग मितव्ययी, दक्षता पूर्ण और प्रभावी था;
- मेसो क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन दक्षता पूर्ण एवं प्रभावी था;
- स.ज.वि. अभिकरणों में उपलब्ध मानव संसाधन प्रयाप्त थे;
- मेसो क्षेत्र में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली गई थी और
- अनुश्रवण प्रणाली प्रभावी था।

[4] संबंधित मेसो क्षेत्र के संसद सदस्य एवं राज्य विधान सभा के सदस्य गण।

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पहुँचने के लिये निम्नलिखित श्रोतों को लेखा परीक्षा मापदण्ड के रूप में अपनाया गया

- विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत अनुदानों के उपयोग के लिये दिशा निर्देश;
- प्रोटो टाइप योजनाओं[5] के क्रियान्वयन के लिये दिशा निर्देश;
- लोक-निजी भागीदारी के परियोजनाओं के समझौते की शर्तें और
- विभाग की निर्धारित अनुश्रवण प्रणाली।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

हमने "मेसो क्षेत्र में "जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों" की निष्पादन लेखा परीक्षा," अप्रैल से जुलाई 2012 के दौरान, राज्य स्तर पर सचिवालय, कल्याण विभाग और आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, 15 स.ज.वि.अ./मेसो कार्यालयों में से छ:[6] जिसमें 54 प्रखण्ड है के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा की गई। चयनित स.ज.वि.अ. में, छ: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (इ.एम.आर.एस/आश्रम विद्यालयों) में से तीन[7] विद्यालय और नौ मेसो ग्रामीण अस्पतालों में से दो[8] अस्पतालों की जाँच 2007-12 की अवधि के लिए की गई। सिंचाई योजनाओं एवं बागवानी योजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। 20 अप्रैल 2012 को हुए प्रवेश सम्मेलन में सचिव, कल्याण विभाग के साथ लेखा परीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड और पद्धति पर चर्चा की गई। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिये एक निकास सम्मेलन सचिव, कल्याण विभाग के साथ 12 दिसंबर 2012 को आयोजित की गई। सरकार के जवाबों को समुचित जगहों पर शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

2.1.6 योजना

मेसो क्षेत्र के परियोजना पदाधिकारीगण, विभाग/आ.क.आ. को प्रस्तुत करने के लिये ग्राम स्तर पर स्थायी आय उत्पादन के लिये आर्थिक क्रियाकलाप और

---

[5] जन जातीय आबादी के लिये स्थायी आय उत्पादक कार्यकलाप के विषय में है। इसे 2005-06 में प्रस्तुत किया गया और यह क्षेत्र के भौगोलिक, मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों, व्यवसाय/व्यापार, बाजार इत्यादि पर आधारित था। राज्य सरकार द्वारा दस प्रकार के प्रोटो टाइप योजनायें चिन्हित की गई थी।

[6] गुमला, राँची, साहेबगंज, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा एवं चक्रधरपुर)

[7] भोगनाडीह (साहेबगंज), तमाड़ (राँची) और तोरसुंदरी (चाईबासा)

[8] जोन्हा (राँची), कैंदुआ (साहिबगंज)

इन क्रियाकलापों के लिए आधारभूत संरचना में कमियों के लिये क्रियाकलापों के निर्धारण को चिन्हित करने सहित, विस्तृत योजना तैयार करने के लिये उत्तरदायी थे।

विभाग ने 'टी.एस.पी. के लिये वि.के.स.' के अंतर्गत योजनाओं को चिन्हित करने एवं स्वीकृति हेतु दिशा निर्देश जारी (नवंबर 2005) किये। ये दिशा निर्देश एक गैर-सरकारी संस्था (एन.जी.ओ.) 'प्रदान' जिसने राज्य के मेसो क्षेत्रों के सभी गाँवों में जनजातियों के विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक मामलों[9] का सर्वेक्षण किया था के प्रतिवेदन पर आधारित थे। इस प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार ने वि.के.स. के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्रोटो टाइप के नाम से 10[10] प्रकार के क्रियाकलाप चिन्हित किये।

प्रतिवेदन में प्रत्येक प्रोटो टाइप योजना के लिये मानक प्राक्कलन भी शामिल था, जिसमें क्रियाकलापों एवं होने वाले आर्थिक लाभ की गणना थी (***परिशिष्ट-2.1***)। इस प्रतिवेदन में प्रत्येक गाँव में क्रियान्वित होने वाले प्रोटो टाईप योजना के प्रकार का भी सुझाव था। इसलिये, यह प्रतिवेदन वार्षिक योजना को तैयार करने के लिये मेसो क्षेत्रों की जरूरतों के निर्धारण का आधार बनाना था।

आगे, अगले वर्ष की योजना व्यय के लिये राज्य सरकार के टी.एस.पी. के लिये वि.के.स. और संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक स.ज.वि.अ. के लिये भारत सरकार को अलग से योजना प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष मार्च महिने में भेजना था। हमने देखा कि 2007-12[11] के दौरान राज्य सरकार ने भारत सरकार को योजना प्रस्ताव देरी से प्रस्तुत किये। भारत सरकार ने टी.एस.पी. के लिये वि.के.स. एवं संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार के लिए उद्दिष्ट निधियों एवं अनुदान का आवंटन किये और राज्य सरकार ने आवंटित निधियों के अंदर ही योजना तैयार की।

---

9 मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पारंपरिक व्यवसाय, भूमि का चित्रण, वर्तमान आधारभूत संरचना, नजदीकी शहरी व्यवसायिक केन्द्र इत्यादि।

10 जल संग्रहक, सिंचाई योजना एवं भूमि सुधार योजना, वर्षा जल संग्रहण कृषि पद्धति, बागवानी एवं ईमारती लकड़ियों का वृक्षरोपण (बहुस्तरीय रोपण), दुग्ध उत्पादन, गृहीत कुक्कुट पालन, बकरी पालन, तसर (प्री कोकून), तसर (पोस्ट कोकून), रंगीनी लाह पालन और शहतुल वृक्षरोपण एवं रेशम कीड़ा पालन।

11 2007-08:अक्टूबर 2007, 2008-09:दिसम्बर 2008, 2009-10: अक्टूबर 2009, 2010-11: जुलाई 2010 और 2011-12:जुलाई 2011।

परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। सरकार ने वार्षिक योजना प्रस्ताव स.ज.वि.अ. से प्रस्ताव प्राप्त किये बिना ही तैयार किये ।

2007-12 के दौरान सरकार ने वार्षिक योजना प्रस्ताव[12] स.ज.वि.अ. से प्रस्ताव प्राप्त किये बिना ही तैयार किये और उन्हें निधियों का आवंटन किया। हमने देखा कि 'प्रदान' के प्रतिवेदन को विगत सात वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया था जो कि मेसो क्षेत्रों की जरूरतों के निर्धारण करने के लिये एकमात्र श्रोत था यह देखा गया कि स.ज.वि.अ. ने प्रदान के पुराने आँकड़ों के आधार पर, प्रोटो टाइप योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये। दो स.ज.वि.अ. (गुमला एवं सिमडेगा) के नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि दो योजनायें यथा जल संग्रहण और शहतूत वृक्षरोपण और रेशम कीड़ा पालन क्रमश: बैच III (2007-10) एवं बैच IV (2010-13) के लिये स्वीकृत किये गये एवं निधियाँ (₹ 83.23 लाख) स.ज.वि.अ. को निर्गत की गई। ये योजनायें क्रियान्वित नहीं किये गये और निधियाँ (₹ 54.14 लाख) व्ययगत हो गई क्योंकि संबंधित प.का.स. ने बताया कि ये योजनायें उस क्षेत्र के लिये अव्यवहार्य अनुपयुक्त थी। अत: मेसो क्षेत्र की जरूरतों के निर्धारण किये बिना ही प्रस्तावित वार्षिक योजना/कार्य योजनायें तैयार किये गये।

आगे, स.ज.वि.अ. के प्रस्तावित पुनर्गठन के अनुसार परियोजना निदेशक को संबंधित स.ज.वि.अ. के लिये टी एस पी के समेकन के लिये गाँवों का आँकड़ा अद्यतन करना एवं परिप्रेक्ष्य योजनायें तैयार करना था।

संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि किसी भी नमूना जाँच किये गये स.ज.वि.अ. में टी.एस.पी. का प्रस्तावित समेकन एवं स.ज.वि.अ. के लिये परिप्रेक्ष्य योजना दिसंबर 2012 तक तैयार नहीं की गई थी।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2012) कि स.ज.वि.अ. के मजबूत करने के प्रयास किये जा रहे थे और उन्हें कार्यकारी बनाया जा रहा है ताकि जरूरत आधारित योजनायें बन सके।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

जनजातीय आबादी के लिये आय उत्पादक गतिविधियों एवं आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रमों के लिये टी.एस.पी. के लिये वि.के.स. एवं संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार राज्य को 100 *प्रतिशत्* वित्तीय सहायता एवं अनुदान मुहैया कराती है। 2007-08 से 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों और उसे आ.क.आ. को निर्गत करने का विवरण **तालिका-1** में है।

[12] निधियों के स ज वि अ एवं योजनावार प्रस्ताव।

तालिका-1:केन्द्रीय निधियों की प्राप्तियों एवं विमुक्तियों की विवरणी

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता से जनजातीय उप योजना				अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान			
	प्रारम्भिक राशि	प्राप्तियाँ	आदिवासी कल्याण आयुक्त को आबंटित राशि	अंत शेष	प्रारम्भिक राशि	प्राप्तियाँ	आदिवासी कल्याण आयुक्त को आबंटित राशि	अंत शेष
2007-08	शून्य	77.11	77.11	शून्य	शून्य	30.60	30.60	शून्य
2008-09	शून्य	21.98	21.98	शून्य	शून्य	18.52	18.52	शून्य
2009-10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	37.30	2.53	34.77
2010-11	शून्य	94.82	85.92	8.90	34.77	80.04	78.72	36.09
2011-12	8.9	107.04	115.94	शून्य	36.09	91.81	125.40	2.50
कुल		**300.95**	**300.95**			**258.27**	**255.77**	

(स्त्रौत- कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार)

उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय की विवरणी के अभाव में भारत सरकार द्वारा 2009-10 का केन्द्रीय निध निर्गत नहीं हुआ।

2007-12 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को प्रोटो टाईप योजनाओं और धारा 275 (1) के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ₹ 300.95 करोड़ एवं ₹ 258.27 करोड़ क्रमश: टी.एस.पी. के लिये वि.के.स. एवं धारा 275(1) के लिये निर्गत किया। इनमें से वि.के.स. के अंतर्गत ₹ 300.95 करोड़ एवं धारा 275 (1) के अंतर्गत ₹ 255.77 करोड़ आ.क.आ. को से वितरित किये गये। हमने देखा कि सरकार ने योजना निधियों के वास्तविक उपयोग निश्चित किये बिना ही आ.क.आ. को राशि निर्गत करने के आधार पर ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत किये थे। हमने यह भी देखा कि इसके अलावे नमूना जाँच किये गये स.ज.वि.अ. के पास ₹ 57.14 करोड़ 31 जुलाई 2012 तक अव्यवहृत था। आ.क.आ. के पास ₹ 57.75 करोड़ 31 मार्च 2012 को अव्यवहृत शेष के रूप में था। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार को सभी बकाया उ.प्र.प., पिछले वर्ष प्राप्त निधि के व्यय विवरणी और पिछले वर्ष के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन, जिनके गतिविधियों के लिये प्रस्ताव दिये गये थे, के साथ वि.के.स. के लिये निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि यद्यपि भारत सरकार ने 2009-10 के दौरान राज्य को ₹ 74.61 करोड़ (जून 2009) उद्दिष्ट किया था किंतु विभाग ने वि.के.स. के लिये प्रगति प्रतिवेदन एवं 2008-09 के लिये उ.प्र.प./व्यय विवरणी नहीं जमा किये थे जिसके फलस्वरूप 2009-10 के दौरान भारत सरकार ने वि.के.स. के अंतर्गत

निधि निर्गत नहीं की। वि.के.स. के अंतर्गत प्रोटो टाइप योजनाओं के बैच I (2005-08), बैच II (2006-08), बैच III (2007-10) एवं बैच IV (2010-13) तथा 2007-12 की अवधि के लिये और धारा 275 (1) आ.क.आ. द्वारा अनुदान वार निधियों की प्राप्ति एवं नमूना स.ज.वि.अ. द्वारा उनके उपयोग का विवरण **तालिका-2** में है:

तालिका-2:नमूना समेकित जनजातीय विकास अभिकरण को प्राप्त निधि एवम् उसके उपयोगिता का विवरण

(करोड़ रूपये में)

समेकित जनजातीय विकास अभिकरण का नाम	उपलब्ध राशि		कार्यकारी अभिकरणों को विमुक्त राशि		व्यय		31 जुलाई 2012 तक अव्ययित शेष	
	वि0 के0 स0	275 (1)	वि0 के0 स0	275(1)	वि0 के0 स0	275 (1)	वि0 के0 स0	275(1)
चाईबासा	19.59	9.48	14.56	6.60	14.08	2.66	5.03	2.88
चक्रधरपुर	13.33	7.89	10.64	5.41	9.9	5.18	2.69	2.48
गुमला	25.10	9.36	18.31	6.07	17.18	3.21	6.79	3.29
सिमडेगा	16.04	2.83	8.65	1.70	6.57	1.45	7.39	1.13
राँची	30.69	14.43	23.89	3.21	20.55	3.97	6.8	8.97[13]
साहेबगंज	14.85	15.49	11.12	11.78	8.28	10.65	3.73	3.71
कुल योग	**119.60**	**59.48**	**87.17**	**34.77**	**76.56**	**27.12**	**32.43**	**24.71**

(श्रोत- आदिवासी कल्याण आयुक्त, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार)

वि.के.स. और धारा 275(1) के अंतर्गत नमूना स.ज.वि.अ. द्वारा प्राप्त कुल आवंटन के विरूद्ध क्रमश: 46 एवं 64 *प्रतिशत्* ही व्यय किया जा सका

तालिका-2 से ज्ञात हुआ कि नमूना स.ज.वि.अ. धारा 275 (1) एवं वि.के.स. के अंतर्गत प्राप्त आबंटन में से क्रमश: केवल 46 एवं 64 *प्रतिशत्* व्यय कर पाये थे। आगे यह देखा गया कि स.ज.वि.अ. द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को वि.के.स. निधियों को निर्गत करने में 12 और 36 महिने की देरी हुई (***परिशिष्ट 2.2***)। फलस्वरूप बड़ी संख्या में वि.के.स. की योजनाये दिसंबर 2012 तक अपूर्ण थी जिसकी कंडिकाएं 2.1.8, 2.1.8.1, 2.1.8.3, 2.1.8.4 और 2.1.8.5 में चर्चा की गई है। संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत योजना/कार्यों के पूर्ण होने में देरी का कारण कार्यकारी अभिकरणों के चयन में देरी, स्थल परिवर्तन, संवेदक के चयन में देरी और बिजली का अभाव था, जैसा कि कंडिकाएं 2.1.9.1 एवं 2.1.9.2 में चर्चा की गई है।

सरकार ने लेखा परीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (दिसंबर 2012)।

[13] 2011-12 के दौरान स ज वि अ, राँची द्वारा ₹ 2.25 करोड़ की निकासी नहीं की जा सकी

2.1.7.1 निधियों का लेखापित नहीं किया जाना

आ.क.आ. के कार्यालय के रोकड़ बही में ₹ 11.14 करोड़ का हिसाब नहीं था।

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 86 के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मी को जो सरकार के निमित्त धन प्राप्त करता है को कोषागार चालान प्रपत्र 6 में एक रोकड़ पुस्त संधारण करना चाहिये। हमने पाया कि आ.क.आ. के पास 01 जुलाई 2009 से पहले के रोकड़ पुस्त नहीं थे। आ.क.आ. द्वारा 1 जुलाई 2009 से ₹ 50,48,05,407.02 के प्रारंभिक शेष के साथ एक नया रोकड़ पुस्त खोला गया। रोकड़ के विश्लेषण में दर्शाया गया कि बैंक में शेष ₹ 39,36,29,610.40, ₹ 2,70,000 के बिना भुनाये चेक एवं ₹ 11,14,45,796.62 सेवानिवृत रोकड़पाल के नाम पर थे। आगे, संवीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2012 को अवशेष राशि ₹ 57,75,49,194.02 थी जिसमें से ₹ 11,14,45,796.62 तत्कालीन रोकड़पाल के नाम पर बनी हुई थी। आ.के.आ. ने सेवा निवृत रोकड़ पाल को रोकड़ पुस्त जमा करने का निर्देश दिया (सितंबर 2010) रोकड़ पुस्त जमा करने में विफल रहने पर एक फौजदारी मुकदमा दायर किया जायेगा और सेवानिवृति रोक दी। हाँलाकि कोई फौजदारी मुकदमा नहीं किया गया (दिसंबर 2012)। अत: तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक ₹ 11.14 करोड़ की राशि का लेखापित नहीं किया जाना सरकारी धन के दुर्विनियोग की संभावना से भरा है।

2.1.7.2 वैयक्तिक खाता लेखा में अनियमित जमा

झारखण्ड कोषागार संहिता के भाग-1 के नियम 300 के अनुसार यदि तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो तो कोषागार से धन की निकासी नहीं की जानी चाहिये। कार्यों के क्रियान्वयन या विनियोग के व्ययगत होने से बचाने के माँग की प्रत्याशा में अग्रिम निकासी की अनुमति नहीं है।

योजना निधि ₹ 91.81 करोड़ वैयक्तिक लेखा खाते में जमा कर दिया

भारत सरकार ने कल्याण विभाग को धारा 275 (1) के अंतर्गत योजनाओं के लिये ₹ 91.81 करोड़ विमुक्त किये (सितंबर 2011)। राज्य सरकार ने योजना निधि के अग्रिम निकासी की अनुमति दी (मार्च 2012) राशि की निकासी मार्च 2012 में की गई एवं अगले वर्ष के आबंटन में कमी से बचने के लिये अनुसूचित जाति विकास निगम (एस.सी.डी.सी.) राँची के वैयक्तिक लेखा (पी.एल.) खाता में जमा कर दिया गया।

सरकार ने कहा (दिसंबर 2012) कि भारत सरकार को उक्त राशि का उ.प्र.प. निर्गत नहीं किया गया है।

बिना किसी तत्काल आवश्यकता के निधियों की निकासी एवं एस.सी.डी.सी. के पी.एल. खाता में जमा करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

2.1.7.3 योजना निधि का प्रत्यर्पण

पहले के ए.सी. बिलों की निकासी के विरूद्ध डी.सी. बिल जमा नहीं करने के कारण ₹ 19.47 करोड़ की केन्द्रीय निधि की निकासी नहीं कि जा सकी।

2011-12 के दौरान सरकार ने चार[14] स.ज.वि.अ. को योजना निधि के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिल पर अग्रिम निकासी की अनुमति दी। हमने देखा कि 2001-12 के दौरान उनके द्वारा पूर्व में निकासी की गई ए.सी. बिल की राशि (₹ 48.06 करोड़) के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को जमा नहीं करने के कारण कोषागार पदाधिकारियों ने ए.सी. बिलों पर आगे निकासी करने पर रोक लगा दी। फलस्वरूप उनके द्वारा ₹ 19.47 करोड़[15] की योजना निधि की निकासी नहीं की जा सकी एवं प्रत्यर्पित हो गई।

पहले निकासी की गई निधियों से संबंधित डी.सी. बिल के जमा न करने के कारण सरकार योजना निधि के निकासी करने एवं उसके उपयोग करने में असमर्थ रही जिससे इन चार जिलों की अ.ज.जा. आबादी योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित रही।

सरकार ने कहा (दिसंबर 2012) कि मार्च 2013 तक डी.सी. बिल जमा करने के प्रयास किये जा रहे थे।

2.1.7.4 कार्यों पर व्यय के लिये दिये गये अग्रिम के समायोजन में अनियमिततायें

चाईबासा और साहेबगंज स.ज.वि.अ. में ₹ 2.96 करोड़ के कार्य बिल को विभागीय अभियंताओं के अग्रिम के विरूद्ध मापी पुस्त, एम.आर. एवं अभिश्रव के बिना समायोजित किया गया।

कोई भी कार्य जो विभाग द्वारा क्रियान्वित होते है के अंतिम व्यय का लेखा करने के लिये मस्टर रौल (एम.आर.), अभिश्रवों एवं मापी पुस्त का होना आवश्यक है। चाईबासा और साहेबगंज स.ज.वि.अ. में 2005-10 के दौरान विभाग द्वारा छात्रावास आंगनबाड़ी केन्द्र (आ.के.), पक्का चेक डैम तथा सरना स्थल की चहारदिवारी का निर्माण कार्य 12 महीने में पूरा करने के लिये शुरू की गई। हमने देखा कि कार्य प्रारंभ होने के तीन से चार वर्ष बीत जाने के बाद भी 42 निर्माण कार्य जुलाई 2012 तक अपूर्ण थे। इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिये स.ज.वि.अ ने विभागीय अभियंताओं को 2005-11 के दौरान ₹ 9.30 करोड़[16] अग्रिम (***परिशिष्ट 2.3 एवं 2.4***) दिये थे एवं उन्हें अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया था। हमने देखा (जून-जुलाई 2012) कि ₹ 2.96 करोड़ के व्यय को चल लेखा बिल के आधार पर समायोजित (जुलाई 2012) किया गया। हाँलाकि अभियंताओं द्वारा संबंधित मापीपुस्त, एम.आर. एवं अभिश्रव लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। हमारे आगे पृच्छा पर प्र.नि. ने कहा कि अपेक्षित दस्तावेज अभियंताओं से जमा कराये जायेंगे। इस

---

[14] चाईबासा, चक्रधरपुर, गुमला और राँची

[15] चाईबासा:₹ 3.60 करोड़, चक्रधरपुर:₹ 1.64 करोड़, गुमला:₹ 6.22 करोड़ और राँची:₹ 8.01 करोड़

[16] चाईबासा: ₹ 4.10 करोड़ (***परिशिष्ट 2.3***) और साहेबगंज:₹ 5.20 करोड़ (***परिशिष्ट 2.4***)

प्रकार लेखापरीक्षा में व्यय की सत्यता सुनिश्चित नहीं हो पाई। इसके अलावे संबंधित अभियंताओं को दिये गये अग्रिमों ₹ 6.34 करोड़ का समायोजन दिसंबर 2012 तक नहीं हो पाया था।

सरकार ने कहा (दिसंबर 2012) कि योजनायें लगभग पूर्ण होने वाले हैं और एम.आर. और अभिश्रव कनीय अभियंता द्वारा जमा किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि क्रियान्वित कार्य के लिये मापी पुस्त, एम.आर. एवं अभिश्रव कार्य बिल के साथ ही अभियंताओं द्वारा जमा करना चाहिये था।

मेसो क्षेत्र में क्रियान्वित वृहत योजनायें

2.1.8 विशेष केन्द्रीय सहायता (वि.के.स.)

विशेष केन्द्रीय सहायता (वि.के.स.) भारत सरकार द्वारा राज्यों को परिवार केन्द्रित आय उत्पादक योजनाओं और गरीबी रेखा से नीचे के जनजातीय आबादी को केन्द्रीत करने के साथ सहायक आधारभूत संरचना के विकास के लिये 100 *प्रतिशत्* अनुदान के रूप में दिया जाता है। विभाग ने स्थायी आजीविका के लिये प्रोटोटाइप योजनाओं जिसमें 10 कार्य-कलाप हैं के लिये दिशा निर्देश (नवंबर 2005) जारी किया। प्रोटो टाईप योजनायें या तो एन.जी.ओ. द्वारा तैयार किये गये गाँवों के समूह में लाभार्थियों के स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) यथा लाभुक समिति (ला.स.) या लाइन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। एस.एच.जी. को उनके बैंक खाते के द्वारा निधि विमुक्ति की जाती है। परियोजना की लागत[17] 'प्रदान' द्वारा तैयार किये गये मानक परियोजना के प्राक्कलन पर आधारित था। प्रोटो टाईप योजनायें बैच[18] के अनुसार (बैच I,III और IV तीन वर्ष के लिये और बैच II दो वर्ष के लिये) लिये जाने थे और दूसरे वर्ष में पूर्ण होने थे। हाँलाकि परियोजना फेसिलिटेटर को क्षमता निर्माण और नेट वर्किंग हेतू तीसरे वर्ष भी जारी रखना था।

राज्य में 2005-12 के दौरान ली गई और पूर्ण की गई प्रोटो टाइप इकाईयाँ[19] के दिसंबर 2012 तक के विवरण **तालिका-3** में उल्लेखित हैं। ये इकाईयों चयनित एन.जी.ओ/लाइन विभागों द्वारा मेसो क्षेत्रों/स.ज.वि.अ में क्रियान्वित होना था।

---

17 वर्त्तमान सूचि दर के अनुसार विभिन्न मदों के दर पुनरीक्षित हो गये थे किंतु प्रदान के प्रतिवेदन में दर्शाया गया प्रत्येक परियोजना की कुल लागत नहीं बदली गई थी। परियोजना के कुल लागत को समायोजित करने के लिये कार्य एवं लाभुकों की संख्या में कमी की गई

18 बैच 1 (2005-08):146 इकाई; बैच 2 (2006-08):70 इकाई;बैच 3 (2007-10):183 इकाई और बैच 4 (2010-13):83 इकाई स्वीकृत किये गये

19 एक प्रोटो टाईप क्रियाकलाप में योजना/कार्यों का समूह

तालिका 3:राज्य में शुरू किये गये प्रोटो टाईप इकाईयाँ एवं उनकी पूर्णता (दिसंबर 2012)

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	प्रोटो टाईप इकाईयाँ	बैच I (2005-08), बैच II (2006-08), बैच III (2007-10) और बैच IV (2010-13)						
		शुरू की गई इकाईयाँ	कार्यकारी अभिकर्ताओं की संख्या	स्वीकृत राशि	कार्यकारी अभिकर्त्ताओं को विमुक्त राशि	व्यय	पूर्ण की गई इकाईयों की संख्या	अपूर्ण इकाईयों की संख्या
1	जल संग्रहक, सिंचाई एवं भूमि विकास योजना	182	139	151.26	116.64	107.05	45	137
2	बागवानी एवं ईमारती लकड़ियों (आम) का उच्च भूमि पर वृक्षारोपण (बहुस्तरीय रोपण)	56	56	35.51	25.38	24.39	17	39
3	गव्य विकास	10	10	9.42	6.04	5.47	1	9
4	पेड़ों पर रंगीन लाह पालन	25	17	5.85	3.78	3.56	7	18
5	बकरीपालन	21	23	8.17	6.74	6.08	3	18
6	वर्षा जल संग्रहण उन्नत कृषि सह -पैकेज	26	25	17.07	13.18	11.31	6	20
7	गृहीत कुक्कुट पालन	9	9	8.93	6.39	6.01	3	6
8	शहतूत वृक्षारोपण एवं रेशम कीड़ा पालन	4	2	2.69	1.73	1.73	0	4
9	तसर (प्री कोकून)	18	15	11.72	5.45	5.18	0	18
10	तसर (प्रोस्ट कोकून)	2	2	4.38	2.45	2.45	0	2
कुल योग		**353**	**298**	**255.00**	**187.78**	**173.23**	**82**	**271**

(स्त्रोत: जनजातीय कल्याण आयुक्त, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार)

353 स्वीकृत योजनाओं में से केवल 82 इकाइयाँ पूर्ण हो पायी थीं।

तालिका-3 से यह स्पष्ट होता है कि विभाग ने सभी स.ज.वि.अ को 353 प्रोटो टाईप इकाइयों के क्रियान्वयन के लिये ₹ 255.00 करोड़ स्वीकृत किया था। स.ज.वि.अ. ने क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 187.78 करोड़ विमुक्त किये जिसमें से ₹ 173.23 करोड़ व्यय किये गये थे। अत: स.ज.वि.अ द्वारा प्रोटो टाईप योजनाओं के शुरू करने में देरी के साथ-साथ ₹ 67.22 करोड़ के कम विमुक्ति के कारण 353 स्वीकृत योजनाओं में से केवल 82 इकाइयाँ (23 *प्रतिशत*) पूर्ण हो पायी थीं।

2005-12 के दौरान नमूना जाँच किये गये स.ज.वि.अ. में शुरू किये गये और पूर्ण किये गये प्रोटो टाईप योजनाओं का विवरण **तालिका-4** में नीचे दिया गया है।

तालिका-4: नमूनाकृत समेकित जनजातीय विकास अभिकरणों मे लिये गये प्रोटो टाईप इकाईयाँ एवं उनकी पूर्णता की स्थिति (दिसम्बर 2012)

क्रम संख्या	प्रोटो टाईप इकाई	नमूनाकृत समेकित जनजातीय विकास अभिकरणों में प्रोटो टाईप के अंतर्गत लिये गये योजनाएं एवं उनकी पूर्णता की स्थिति बैच I (2005-08), बैच II (2006-08), बैच III (2007-10) और बैच IV (2010-11)											
		चाईबासा		चक्रधरपुर		गुमला		राँची		साहेबगंज		सिमडेगा	
		शुरू की गई इकाईयाँ	पूर्ण	शुरू की गई इकाईयाँ	पूर्ण	शुरू की गई इकाईयाँ	पूर्ण	शुरू की गई इकाईयाँ	पूर्ण	शुरू की गई इकाईयाँ	पूर्ण	शुरू की गई इकाईयाँ	पूर्ण
1	जल संग्रहक, सिंचाई एवं भूमि विकास	15	0	9	5	20	0	23	0	11	0	15	0
2	बागवानी एवं ईमारती लकड़ियों (आम) का उच्च भूमि पर वृक्षारोपण (बहुस्तरीय रोपण)	04	0	04	0	08	0	11	6	01	0	02	0
3	गव्य विकास	0	0	0	0	0	0	03	0	0	0	0	0
4	रंगीनी लाह पालन	04	0	04	0	0	0	06	0	0	0	03	0
5	बकरीपालन	01	0	0	0	05	0	0	0	01	0	04	01
6	वर्षा जल संग्रहण उन्नत कृषि सह पैकेज	03	0	01	0	0	0	04	2	0	0	0	0
7	गृहीत कुक्कुट पालन	0	0	0	0	01	0	01	0	0	0	01	0
8	शहतूत वृक्षारोपण एवं रेशम कीड़ा पालन	0	0	0	0	03	0	0	0	0	0	01	0
9	तसर (प्री कोकून)	06	0	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	तसर (प्रोस्ट कोकून)	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0
कुल योग		**33**	**0**	**23**	**5**	**37**	**0**	**48**	**8**	**14**	**0**	**26**	**1**

(स्त्रोत: जनजातीय कल्याण आयुक्त, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार)

181 इकाइयों में से केवल 14 ही पूर्ण हो पाये थे

तालिका-4 से यह देखा जा सकता है कि दिसंबर 2012 तक ₹ 10.54 करोड़ की लागत से 181 इकाइयों में से केवल 14 (8 *प्रतिशत*) ही पूर्ण हो पाये थे।

छः नमूना स.ज.वि.अ में प्रोटो टाईप योजनाओं के क्रियान्वयन पर लेखा परीक्षा निष्कर्षो पर नीचे चर्चा की गई है।

2.1.8.1 जल संग्रहण, सिंचाई एवं भूमि विकास योजना

जल संग्रहण, सिंचाई और भूमि विकास योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार लिये छः[20] प्रकार के क्रियाकलाप योजनाओं के समूह के रूप में निर्धारित थे। योजनाओं के समूह में जल के लिये आधारभूत संरचना का निर्माण, पम्प घर का निर्माण, लाभार्थियों के खेतों तक संवितरण पाइप बिछाना, नियंत्रण क्षेत्र का विकास (खेतों में नाली बनाना, बाड़ लगाना, खेतों में खाद का प्रयोग, चूने का प्रयोग, बीज और खाद आदि भी जोड़े गए घटक थे। जैसा कि **तालिका-3** में दिखाया गया है राज्य में चार बैचों की अवधि में ली गई जल संग्रहक, सिंचाई और भूमि विकास के 182 इकाईयों में से योजनाओं के समूह के रूप 45 इकाईयाँ (24 प्रतिशत) ही पूर्ण हो पाई थी। हाँलाकि नमूना स.ज.वि.अ. में ₹ 48.25 करोड़ व्यय होने के बाद शुरू की गई 93 इकाईयों में से पाँच ही पूर्ण हो पाई थी (**तालिका-4**) ।

मेसो क्षेत्र में जल संग्रहण योजनाएं सिर्फ 24 *प्रतिशत* ही पूर्ण हो पाई थी।

नमूना जाँच की गई योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई खामियों की चर्चा नीचे की गई हैं।

- हमने देखा कि दो एन जी ओ यथा अराउज और सोशल वेल्फेयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट आरगेनाइजेशन क्रमशः सिमडेगा और चक्रधरपुर में, 3,590 जनजातीय परिवारों को जिनकी खेती योग्य भूमि 5,122 एकड़ तक फैली थी, को ₹ 5.16 करोड़ की लागत पर बैच 1 और बैच II (चार इकाई सिमडेगा में और एक इकाई चक्रधरपुर में) 116 सुक्ष्म उद्वह सिंचाई 104 उथला कुआँ और 23 जल संग्रहण तालाब का निर्माण सौंपा (जुलाई 2006 से अक्टुबर- 2008) गया। जल के आधारभूत संरचना के पूर्ण करने का नियत समय कार्य के प्रारंभ से दो वर्ष का था।

₹ 4.71 करोड़ के खर्च के बावजूद 113 योजनाएँ अपूर्ण रहीं

हमने देखा कि दिसंबर 2012 को योजनाओं के क्रियान्वयन पर ₹ 4.71 करोड़ व्यय किये गये थे। एन जी ओ के प्रतिवेदन के अनुसार जो कि मेसो पदाधिकारियों द्वारा जाँचे गये थे, 91 सूक्ष्म उद्वह सिंचाई, 20 उथला कुआँ और दो जल संग्रहक तालाब अपूर्ण थे क्योंकि 31 पंप घर और 7 कुओं के पारापेट नहीं बने थे, 27 पंप की पूर्ति नहीं की गई थी, लाभान्वितों के खेतों में पाईप नहीं बिछाया गया था और कमांड क्षेत्र (1,599 एकड़ में) विकसित नहीं किया गया था। स.ज.वि.अ. ने हाँलाकि विभाग को अपने मासिक प्रगति प्रतिवेदन में योजनाओं के पूर्णता का प्रतिवेदन दिया था, चूँकि योजनायें पूर्ण नहीं हो पाई थी इसलिए 3,365

[20] (1) सूक्ष्म उद्वह सिंचाई (2) बारी कुआँ (3) उथला कुआँ (4) मृदा बाँध (5) जल संग्रहक तालाब और (6) भूमि समतली करण

एकड़ में इच्छित सिंचाई सुविधा नहीं बन पाई और 2,040 जनजातीय परिवार वंचित रहे।

सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को माना (दिसंबर 2012) और कहा कि लंबित योजनायें पूरी की जायेगी।

- साहेबगंज में समाज कल्याण सेवा सदन (एन.जी.ओ.) को ₹ 87.60 लाख की लागत पर जो 475 परिवारों के 590.50 एकड़ भूमि (1 इकाई) के लिये 38 योजनाओं[21] का निर्माण कार्य सौंपा गया (मई 2007) जिसके विरूद्ध एन.जी.ओ. को ₹ 74.30 लाख (मई 2007 एवं सितंबर 2011 के बीच) अग्रिम दिये गये थे।

18 योजनाएँ अपूर्ण रहीं और एन.जी.ओ. के पास ₹ 19.46 लाख चार वर्षों के अधिक से असमायोजित थी

हमने देखा कि एन.जी.ओ. ने 30 योजनाओं की पूर्णता को प्रतिवेदित (सितंबर 2011) किया और ₹ 54.84 लाख का लेखा प्रस्तुत किया एवं आठ योजनाओं को अपूर्ण रखा (दिसम्बर 2012), जिसके लिये राशि के निर्गत होने के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी ₹ 19.46 लाख असमायोजित थे। आगे, हमने देखा कि 245 परिवारों के लिये अच्छादित 289.50 एकड़ के सिंचित भूमि पर 20 योजनायें ही वास्तवित रूप से पूर्ण थे। मापी पुस्त, अभिश्रवों इत्यादि की हमारी संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 10 जल संग्रहक तालाब में आउटलेट नहीं बने थे और कमांड क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था यद्यपि स.ज.वि.अ. साहेबगंज द्वारा इन्हें पूर्ण दिखाया गया था। अत: 18 योजनाओं[22] के अपूर्ण रहने के कारण 220 परिवारों के 301 एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा की सृष्टि नहीं हो सकी।

आगे में यह देखा गया कि साहेबगंज 2008-12 के दौरान बैच III एवं IV के जल संग्रहक, सिंचाई और भूमि सुधार की सात इकाईयाँ शुरू की गई हाँलाकि निर्गत राशि ₹ 5.38 करोड़ के विरूद्ध ₹ 3.05 करोड़ व्यय हो जाने के बाद भी उनमें से कोई भी पूर्ण नहीं हो सकी।

- भूमि संरक्षण पदाधिकारी (भू सं प), सिमडेगा को बैच III (2007-10 के लिये ₹ 2.60 करोड़ की लागत पर 257 जल संग्रहक और सिंचाई योजनायें सौंपी गई थी (अगस्त 2009)। इन योजनाओं को 1,680 जनजातीय परिवारों के 1,632 एकड़ भूमि के लिये मार्च 2011 में पूरा करना था। हमने देखा कि स.ज.वि.अ., सिमडेगा ने मार्च 2010 से जनवरी 2012 के दौरान भू.स.प. को धन निर्गत किये थे। स.ज.वि.अ. ने विभाग

पी.भी. सी. पाईप की कमी के कारण 49 योजनाएँ अपूर्ण रहीं

[21] एक बारी कुआँ, 10 उद्वह सिंचाई, 16 उथला कुआँ और 11 जल संग्रहक तालाब

[22] पाँच उद्वह सिंचाई, 2 उथला कुआँ और 11 जल संग्रहक तालाब

को पूरी राशि को खर्च हो गया (जुन 2012) बताया था। हमने देखा कि पूर्ण होने के निर्धारित तिथि के 20 माह बाद अक्टूबर 2012 को 208 योजनायें (तीन इकाईयाँ) ही पूर्ण थी और 49 योजनायें अपूर्ण थी अत: स.ज.वि.अ. द्वारा राशि के देर से निर्गत करने के कारण 234 लक्षित जनजातीय परिवारों के 306 एकड़ भूमि पर इच्छित सिंचाई लाभ नहीं मिल पाया था।

उत्तर में विभाग ने कहा (दिसंबर 2012) कि स.ज.वि.अ. सिमडेगा द्वारा पी.वी.सी. पाइप के क्रय का अंतीमीकरण नहीं करने के कारण सूक्ष्म उद्वह योजनायें पूर्ण नहीं हो सकी थी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि क्रियान्वयन अभिकरणों को पाइप का क्रय सुनिश्चित करना चाहिये था।

- लघु सिंचाई (ल.सि.) प्रमंडल, राँची को 65 सूक्ष्म उद्वह सिंचाई योजनाये, 19 जल संग्रहक तालाब, 93 उथला कुआँ और 192 बाड़ी कुआँ प.का.स. के अनुमोदन के पश्चात ₹ 6.96 करोड़ की लागत स.ज.वि.अ. राँची द्वारा सौंपा (दिसंबर 2006) गया था। यह राशि दिसंबर 2006 और जून 2012 के बीच निर्गत की गई थी जिसके विरूद्ध दिसंबर 2012 तक ₹ 5.32 करोड़ व्यय किये गये थे। ये कार्य राँची के नौ प्रखंडों[23] में किये जाने थे

  योजना के प्राक्कलन के अनुसार 2,380 जनजातीय परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिये 3,689 एकड़ में सिंचाई क्षमता बनानी थी। ये योजनायें प्रारंभ की तिथि से दूसरे वर्ष के अंत तक (दिसंबर 2008) पूर्ण होनी थी और परियोजना संचालन इकाई (ल.सि. प्रमंडल) को समुदाय यथा लाभुक समिति के साथ क्षमता वर्द्धन और नेटवर्किंग के लिये तीसरे वर्ष कार्य जारी रखना था।

भौतिक सत्यापन के दौरान 20 उद्वह सिंचाई योजनायें जिन्हें पूर्ण बताया गया था अपूर्ण पायी

स.ज.वि.अ., राँची के अभिलेखों की संविक्षा से उद्घटित हुआ कि ल.सि. प्रमंडल, राँची के प्रतिवेदन के अनुसार दिसंबर 2012 तक 369 में से 318 योजनायें पूर्ण थी जबकि 39 अपूर्ण थी और 12 में संवेदक के साथ करार नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। मासिक प्रतिवेदन से हमने देखा कि बैच I और II की 20 योजनायें जो ल. सि. प्रमंडल द्वारा पूर्ण बताई गई थी वास्तविकता में पूर्ण नहीं थी। हमने यह भी देखा कि लाभुकों की शिकायत के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.प.) बेड़ो द्वारा इन योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया था। प्र.वि.प्र. ने प्रतिवेदित किया कि ये 20 योजनायें वास्तविकता में क्रियान्वित नहीं की

[23] बेड़ो, बुढ़मु, चान्हो, कांके, लापुंग, मांडर, ओरमांझी, रातु और सिल्ली

गई थी। ल.सि. प्रमंडल, राँची ने प्र.वि.प. द्वारा बताई गई अनियमितताओं के आधार पर ₹ 17.28 लाख वापस किये।

अत: दिसंबर 2012 तक 59 सिंचाई योजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण जनजातीय परिवारों तक लक्षित लाभ नहीं पहुँच सका था। अवर प्रमंडल पदाधिकारी ल.सिं. प्रमंडल राँची के साथ चान्हो प्रखण्ड में संयुक्त क्षेत्र भ्रमण (फरवरी 2013) के दौरान हमने देखा कि सिविल कार्य नहीं किये जाने के कारण तीन सूक्ष्म उद्वह सिंचाई (एम.ए.आई.) योजनायें और पंप सेट की पूर्ति नहीं होने के कारण एक बाड़ी कुआँ अपूर्ण[24] था यद्यपि स.ज.वि.अ. राँची को ल.सि. प्रमंडल राँची ने इन चार योजनाओं के पूर्ण होने का प्रतिवेदन दिया था। अत: ल.सि. प्रमंडल राँची द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन का असत्य प्रतिवेदन दिया था। क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों के दूर्विनियोग की संभावना से इंकार नहीं किया सकता है।

सरकार ने कहा (दिसंबर 2012) कि योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है।

- स.ज.वि.अ. गुमला द्वारा 11 एम.एल.आई. का निर्माण कार्य ₹ 30.25 लाख (प्रत्येक ₹ 2.75 लाख पर) की लागत पर ल.सि. प्रमंडल गुमला को सौंपा (फरवरी 2010) और अप्रैल और अगस्त 2010 के बीच राशि निर्गत की गई थी। प्रमंडल ने मई 2012 तक ₹ 25.28 लाख व्यय किये थे। ये कार्य ल.सि. प्रमंडल के परियोजना फेशिलिटेटर होने के साथ-साथ लाभुक समिति के द्वारा किये जाने थे।

  स.ज.वि.अ. गुमला के अभिलेखो के हमारी संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि ल.सि. प्रमंडल के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (दिसंबर 2012) में ल.सि. प्रमंडल, गुमला द्वारा कमांड क्षेत्र का विकास साथ ही साथ नालियों, बाड़, जैविक खाद, चूने का प्रयोग, बीज और खाद शामिल था के बिना ही इन कार्यों को पूर्ण (मई 2012) दर्शाया गया था। मई 2012 तक स.ज.वि.अ., गुमला द्वारा इन कार्यों को पूर्ण करने के लिये कोई कारवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा ल सि प्रमंडल द्वारा तीसरे वर्ष में क्षमता वर्द्धन और लाभुकों के प्रशिक्षण कार्य, जैसा कि योजना दिशा निर्देशों में उद्धृत है, नहीं किया गया ।

11 सूक्ष्म उद्वह सिंचाई योजनाओं पर ₹ 25.28 लाख का व्यय अलाभप्रद रहा

अत: कमांड क्षेत्र विकसित नहीं किये जाने के कारण 11 सूक्ष्म उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर किया गया व्यय ₹ 25.28 लाख अलाभप्रद सिद्ध हुआ।

[24] तीन एम एल आई (पटुक सरना टोली, सरना टोली और ओपा 2) और एक बाड़ी कुआँ (हुटार)

- प्रोटो टाईप योजना दिशा निर्देशों के अनुसार आधारभूत संरचना में शामिल अवयव यथा पाईप बिछाना, पंप स्थापित करना, कमांड क्षेत्र विकसित करना ताकि जल स्त्रोत से सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग हेतु लाभुकों के खेत तक ले जाया जा सके। ये कार्य क्रियान्वयन अभिकरणों (आई.ए.) की सहायता से लाभुक समिति (ला.स.) द्वारा किये जाने थे।

  स.ज.वि.अ. गुमला ने कामडारा और चैनपुर प्रखण्ड में 1,412 किसानों के 809 एकड़ के कमांड क्षेत्र को आच्छादित करने के लिये जल संग्रहक, सिंचाई और भूमि सुधार के 128 योजनायें (दो इकाईयाँ) ₹ 1.75 करोड़ के स्वीकार्य लागत पर झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कारपोरेशन (झालको) को सौंपा और कार्यादेश (फरवरी 2007) निर्गत किया। फरवरी से सितंबर 2007 के दौरान राशि निर्गत की गई थी। कार्यों को प्रारंभ की तिथि (फरवरी 2007) से तीन वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था।

अग्राह्य कार्यों पर ₹ 1.36 करोड़ का व्यय

  स.ज.वि.अ., गुमला के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में उद्घटित हुआ (फरवरी 2010) कि झालकों ने योजना दिशा निर्देशों के परे जाकर 18 पक्का चेक डैम के निर्माण पर ₹ 1.36 करोड़ का उपयोग किया था। विचलन के कारण अभिलेखों में नहीं था। संवीक्षा में यह भी उद्घटित हुआ कि प.प., स.ज.वि.अ., गुमला ने पहले ही क्षेत्रीय प्रबंधक, झालको को चेक डैम निर्माण नहीं करने का निर्देश (जून 2007) दे दिया था। अत: आवश्यक आधारभूत संरचना यथा पाईप लाइन, पंप सेट की स्थापना इत्यादि के पूर्ण नहीं होने और दिशा निर्देशों, कार्यादेश एवं निर्देशों की अवहेलना कर चेक डैम के निर्माण के कारण लाभुक अपनी भूमि पर सिंचाई के लाभ से वंचित रहे।

  प.नि., स.ज.वि.अ. गुमला ने लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2012) कि क्रियान्वयन अभिकरणों से कारण पृच्छा की जायेगी।

2.1.8.2 उच्च भूमि पर बागवानी (आम) और ईमारती लकड़ियों का वृक्षारोपण (बहुस्तरीय रोपण) योजनायें

उच्च भूमि पर बागवानी (आम) और ईमारती लकड़ियों का वृक्षरोपण (बहुस्तरीय रोपण) योजनाओं में उचित ऊपरी मिट्टी और जल स्रोत वाले उच्च भूमि पर फलों के फसलों के पैधारोपण उद्धृत थी और उनकी अवधि तीन वर्ष

की है। इस योजना के अंतर्गत आम के पौधों के चारो ओर ईमारती लकड़ी के पेड़ यथा गम्हार, शीशम, सागवान इत्यादि लगाये जाने थे।

नमूना जाँच किये गये पाँच[25] में से तीन[26] स.ज.वि.अ. में से क्रियान्वित इस योजना की कमियों की चर्चा नीचे की गई है।

- चाईबासा एवं चक्रधरपुर में उच्च भूमि पर बागवानी (आम) और ईमारती लकड़ियों (बहुस्तरीय रोपण 1,05,999 पौधों के साथ) 267 एकड़ भूमि पर की चार योजनायें ₹ 2.44 करोड़ की स्वीकार्य लागत पर चार[27] एन.जी.ओ. को सात[28] प्रखण्डो के 642 जनजातीय परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिये सौंपा (2005-08) गया।

  हमने देखा कि पौधा रोपण कार्यों पर ₹ 1.94 करोड़ व्यय (दिसंबर 2009) किये गये थे। हाँलाकि चाईबासा मेसो क्षेत्र में 126 एकड़ में सूखे की वजह से और चक्रधरपुर में अज्ञात लोगों द्वारा जला दिये जाने के कारण जैसा कि लाभुकों ने बताया था, 38 एकड़ में पौधे जीवित नहीं रह पाये थे। संबंधित स.ज.वि.अ. ने दूसरे वर्ष के बाद तीसरे वर्ष की गतिविधियों यथा मैन्युरिंग एवं टहनियों की छँटाई के लिये ₹ 50 लाख निर्गत नहीं किये थे। सहायक अभियंता, मेसो क्षेत्र, चाईबासा के साथ तांत नगर प्रखण्ड के तुईबाना गाँव में संयुक्त क्षेत्र भ्रमण (फरवरी 2013) किया गया जिसमें उद्घटित हुआ कि दिशा (एन.जी.ओ.) द्वारा किये गये पौधा रोपण कार्य असफल हो गये क्योंकि वहाँ पर कोई जल स्त्रोत उपलब्ध नहीं था, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शित है।





चाईबासा के तांत नगर प्रखण्ड के तुईबना गाँव में सुखाड़ से विफल पौधा रोपण का चित्र

---

25 चाईबासा, चक्रधरपुर, गुमला, राँची और सिमडेगा

26 चाईबासा, चक्रधरपुर और सिमडेगा

27 (1) दिशा, (2) समेकित जन विकास केन्द्र (3) सिंहभूम ग्रामोंद्योग विकास संस्थान और (4) सृजन महिला विकास मंच

28 चाईबासा मेसो क्षेत्र में टोंटो, झिकपानी, तांतनगर, मझगाँव, खुंटपानी, जगरनाथपुर और चक्रधरपुर मेसो क्षेत्र में चक्रधरपुर सदर

पौधों के जीवित नहीं रहने के कारण बागवानी योजना पर ₹ 1.48 करोड़ का व्यय व्यर्थ साबित हुआ

स.ज.वि.अ./मेसो क्षेत्र के पदाधिकारियों ने पौधो के जीवित रहने के लिये जल स्त्रोतो का निर्माण सुनिश्चित नहीं किये जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक थे। फल्स्वरूप पौधा रोपण असफल रहे। अत: असफल पौधा रोपण पर ₹ 1.48 करोड़[29] का व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ, जिससे 541 लाभुक आर्थिक लाभ से वंचित रहे।

परियोजना निदेशक, स.ज.वि.अ., चाईबासा और परियोजना पदाधिकारी, मेसो क्षेत्र चक्रधरपुर ने कहा (जून 2012) कि पौधा रोपण के असफल होने से बचाने के लिये सुधार कदम लिये जायेंगे।

सरकार ने कहा (दिसंबर 2012) कि संबंधित एन जी ओ को नये पौधे लगाने का निर्देश दिया गया है।

स्थल के गलत चुनाव के कारण ₹ 8.80 लाख का व्यय व्यर्थ

- स.ज.वि.अ. सिमडेगा ने एक एन जी ओ (पर्वतीय दुर्गम शिक्षा विकास संस्थान) की (परियोजना फेशिलिटेटर के तौर पर) सहायता से बागवानी पौधारोपण करने के लिये प्र.वि.प. ठेठईटांगर को ₹ 18.23 लाख निर्गत (जनवरी 2008) किये। योजना को लाभुक समिति के द्वारा क्रियान्वित करना था। तदनुसार प्र.वि.प. ने ₹ 1.10 लाख प्रत्येक को प्र.श.क. किस्त के तौर पर आठ लाभुक समितियों को ₹ 8.80 लाख उनके बैंक खाते में अंतरित किये थे। स.ज.वि.अ. सिमडेगा ने उपायुक्त सिमडेगा (प.का.स. के अध्यक्ष) को सूचित किया कि प.का.स. के द्वारा गलत स्थल का चयन एवं संबंधित एन जी ओ द्वारा निदेशों की कमी के कारण लाभुक समिति द्वारा लगाये गये पौधे जीवित नहीं रह पाये। फलस्वरूप ₹ 8.80 लाख के व्यय व्यर्थ सिद्ध हुए।

  परियोजना निदेशक ने कहा (जून 2012) कि मामले की जाँच की जायेगी।

[29] ₹ 1.30 करोड़ चाईबासा में जहाँ कोई पौधें जीवित नहीं थे और ₹ 0.18 करोड़ जहाँ पौधा रोपण कुछ (15086 पौधे) जीवित थे

2.1.8.3 बकरी पालन योजना

इस योजना में अ.ज.जा. आबादी के लिये आय उत्पादन कार्य बकरी पालन द्वारा करना था। योजना में बकरी की आपूर्ति (चार बकरी और एक बकरा), जानवरों का बीमा, शेड की लागत, लाभुकों का प्रशिक्षण, दवा का प्रावधान और संवर्धन लागत (क्षेत्र कार्यकर्ता और पशु चिकित्सक का पारिश्रमिक उनका यात्रा व्यय और फेशिलिटेटिंग अभिकरण का प्रशासनिक लागत) का प्रावधान था। छः में से तीन[30] स.ज.वि.अ. में बकरी पालन योजना क्रियान्वित थी। योजना के क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितताओं पर चर्चा नीचे की गई है।

- स.ज.वि.अ., साहेबगंज ने 240 लाभुको के लिये योजना का क्रियान्वयन ₹ 45.29 लाख की स्वीकार्य लागत पर सोना संथाल समाज (एन.जी.ओ.) को सौंपा (मार्च 2010)। स.ज.वि.अ. के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि दिसंबर 2012 तक 80 लाभुकों को 388 बकरियाँ वितरित की गई थी। हाँलाकि शेड का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया था, बकरियाँ बिमीत नहीं थी और अभिकरण द्वारा पशुचिकित्सक के भ्रमण की व्यवस्था नहीं की गई थी फलस्वरूप बिमारी से ग्रसित होकर 54 बकरियाँ मर गई थी।

  सरकार ने कहा (दिसंबर 2012) कि लाभुकों को तत्काल चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित कराने के लिये एन.जी.ओ. को आदेश दिये गये थे। उत्तर सही नहीं था क्योंकि यह योजना के क्रियान्वयन के दौरान ही सुनिश्चित किया जाना चाहिये था।

- सिमडेगा में 2005-06 और 2007-08 के बीच दो एन.जी.ओ. (अराउज और निदान) को 685 अ.ज.जा. के लिये, 3,425 बकरियों के वितरण, शेड का निर्माण, प्रशिक्षण की व्यवस्था इत्यादि के लिये ₹ 1.27 करोड़ निर्गत किये गये थे। स.ज.वि.अ. सिमडेगा को एन.जी.ओ. द्वारा प्रस्तुत किये प्रतिवेदनों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 315 अ.ज.जा. के बीच अराउज द्वारा वितरित की जाने वाली 1,575 बकरियों में से एन.जी.ओ. ने 125 अ.ज.जा. के बीच 625 बकरियाँ वितरित नहीं की गई। उसी प्रकार निदान द्वारा 370 अ.ज.जा. के बीच 1,850 बकरियॉ वितरित किये जाने थे जिसमें से 161 अ.ज.जा. के बीच 270 बकरियों वितरित नहीं की गई (सात अ.ज.जा. को बकरियाँ नहीं मिली)। हाँलाकि एन.जी.ओ. द्वारा 370

[30] गुमला, साहेबगंज और सिमडेगा

अ.ज.जा. के लिये योजना के क्रियान्वयन पर संपूर्ण राशि व्यय दिखा दी गई। इसके अलावा अराउज द्वारा बकरियाँ के रहने के लिये 125 शेड का निर्माण किया गया और बकरी पालन का प्रशिक्षण, ₹ 14.12 लाख की लागत पर उन अ.ज.जा. को दिया गया जिन्हें बकरी वितरीत नहीं किये गये थे। व्यय अलाभप्रद रहा (जून 2012) और 132 लाभुक योजना के लाभ से वंचित रहे।

सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार (दिसंबर 2012) किया और कहा कि योजना को पूर्णता में क्रियान्वित किया जायेगा।

- गुमला जिले में बैच I (2005-08) और बैच III (2007-10) के दौरान बकरी पालन की पाँच इकाईयॉ ली गई। हाँलाकि इनमें से कोई भी योजना जून 2012 तक पूर्ण नहीं थी क्योंकि स्वीकृत ₹ 2.27 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 1.82 करोड़ ही निर्गत किये गये और जिसके विरूद्ध ₹ 1.74 करोड़ ही व्यय किये गये थे। संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि प.प. ने दो बकरी पालन इकाई को दो एन.जी.ओ. (निदान गुमला और ग्रामीण उत्थान संस्थान, सिसई) को सौंपा (मार्च 2006) और ₹ 40 लाख (मार्च 2006 से अप्रील 2007) निर्गत किया था। हाँलाकि प.का.स. ने असंतोष जनक कार्य के कारण कार्यादेश को समाप्त (अक्टुबर 2008) कर दिया था। अत: प्रस्तावित लक्षित जन जातियों को योजना के अंतर्गत लाभ नहीं प्रदान किया गया।

2.1.8.4 शहतूत वृक्षारोपण एवं रेशम कीट पालन की योजना

180 एकड़ में लगाये गये शहतूत के पौधों में से 120 एकड़ के पौधे जीवित नहीं रहे

इस योजना में जनजातीय लोगों के लिये आय उत्पादन का कार्य शहतूत वृक्षारोपण एवं रेशम कीट पालन से करना था। इस योजना में पौधा रोपण और उनका अनुरक्षण, रियरिंग के उपकरण का क्रय, पालन घर, कार्यशील पूंजी का प्रावधान, प्रशिक्षण लागत और संबर्धन लागत शामिल था। यह कार्यक्रम केवल एक चयनित स.ज.वि.अ., गुमला में क्रियान्वित था 360 लाभुकों को लाभ देने के लिये 180 एकड़ के क्षेत्र पर शहतूत वृक्षारोपण एवं रेशम कीट पालन का कार्य एक एन.जी.ओ. अराउज को सौंपा गया और मार्च 2006 से मार्च 2008 के दौरान ₹ 1.73 करोड़ निर्गत किये गये। हमने देखा कि स.ज.वि.अ., गुमला ने 2005-08 के दौरान शहतूत वृक्षारोपण हेतू कम जीवन दर[31] (20 से 50 *प्रतिशत*) रहने पर भी नियमित अंतराल पर राशि

[31] 2005-06 तक की अवधि में पौधा रोपण:60 एकड़, 2006-07:60 एक्ड़, 2007-08:60 एकड़ (कुल पौधा रोपण:180 एकड़) और वास्तविक जीवित पौधें 2008-09 में केवल 60 एकड़ में था

निर्गत की थी। 2008-09 के दौरान कुल 180 एकड़ के पौधा रोपण में से 60 एकड़ का पौधा रोपण ही जीवित रहा था।

आगे योजना दिशा निर्देश में पौधों की सिंचाई के लिये जल स्रोत की सृष्टि का प्रावधान नहीं था क्योंकि शहतूत के पौधे रेन फेड होते है। एन.जी.ओ. ने कम वृष्टि एवं सिंचाई सुविधा की कमी को पौधों के कम जीवित रहने का कारण बताया। 360 में से 62 लाभुकों ने उप विकास आयुक्त, गुमला से पौधो का जीवन बढ़ाने के लिये सिंचाई सुविधा का प्रावधान करने का अनुरोध किया (2007)। अत: योजना की कमी और प.प. द्वारा अनुवर्ती कारवाई नहीं करने के फलस्वरूप शहतूत के पौधों की मृत्यु हुई।

2.1.8.5 गव्य विकास योजना

योजना में प्रत्येक आदिवासी को दो गाय का वितरण, प्रशिक्षण की व्यवस्था, बीमा, दवायें, शेड का निर्माण और दुग्ध उत्पादन केन्द्र की स्थापना शामिल थी। यह कार्यक्रम केवल एक चयनित स.ज.वि.अ. राँची में क्रियान्वित थी। जिला गव्य विकास पदाधिकारी (जि.ग.वि.प.), राँची को 100 आदिवासियों को लाभ पहुँचाने के लिये गव्य विकास योजना की एक इकाई का क्रियान्वयन ₹ 98.82 लाख के स्वीकार्य लागत पर सौंपा (मार्च 2007) गया जिसके विरूद्ध स.ज.वि;अ. द्वारा अक्टूबर 2007 (₹ 49.82 लाख) और जनवरी 2008 में (₹ 26.54 लाख) कुल ₹ 76.36 लाख प.का.स. द्वारा अनुमोदित लाभुकों की सूची के साथ क्रियान्वयन अभिकरण (जि.ग.वि.प.) को निर्गत किया था। जि.ग.वि.प. को मापी पुस्त, अभिश्रव इत्यादि दस्तावेज संधारित करने थे और मांगे जाने पर प्रस्तुत करना था। योजना को दो वर्ष में पूर्ण करना था और कार्य की प्रगति मासिक रूप से प्रस्तुत करना था।

जि.ग.वि.प., राँची के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि क्रियान्वयन अभिकरण ने (जनवरी 2012 तक) दो दुग्ध संग्रहण केन्द्रों, 100 शेड का निर्माण, मिनरल का प्रावधान, अनुपुरक भोजन, मिल्क एनालाइजर के क्रय, गायों के क्रय एवं गायों के लिये बीमा पर ₹ 49.36 लाख व्यय किया।

हाँलाकि, प.नि., स.ज.वि.अ., राँची के निरीक्षण टिप्पणी (अगस्त 2011) और जिला पशुपालन पदाधिकारी, राँची (जि.प.पा.प.) द्वारा भौतिक सत्यापन के प्रतिवेदन (मार्च 2012) की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि जि.ग.वि.प. ने 97 प्रस्तावित लाभुकों में से 88 लाभुकों को दो गायों के प्रावधान के विरूद्ध एक गाय वितरित किया था। वितरित 88 गायों में से 46 की मृत्यु हो गई, गाय के लिये शेड का निर्माण नहीं किया गया और दुग्ध संग्रहण केन्द्र उपयोग में नहीं था। यद्यपि गायों का बीमा किया गया था परंतु जि.ग.वि.प. एवं

स.ज.वि.अ. राँची द्वारा अनुवर्ती कारवाई के अभाव में मृत गायों के बीमा का दावा नहीं किया गया था। यह प.नि. एवं स.ज.वि.अ., राँची द्वारा वांछित अनुश्रवण के अभाव एवं जि.ग.वि.प. द्वारा योजना का अपूर्ण क्रियान्वयन इंगित किया।

जि.ग.वि.प. के योजना के क्रियान्वयन में असफलता को देखते हुए प.का.स. की अनुशंसा पर, स.ज.वि.अ. ने योजना को जि.प.पा.प. को पुन: आवंटित (मई 2012) किया। स.ज.वि.अ. ने जि.प.पा.प. को ₹ 27.35 लाख योजना को पूर्ण करने के लिये निर्गत किया। हाँलाकि नवंबर 2012 तक योजना अपूर्ण थी।

गायों की मृत्यु के कारण ₹ 11.50 लाख का व्यय व्यर्थ हुआ

अत: योजना लाभुकों के लिये लक्षित आय उत्पादन कराने में असफल रही। इसके अलावा 46 गायों के जीवित नहीं रहने के कारण ₹ 11.50 लाख का व्यय व्यर्थ साबित हुआ।

सचिव, कल्याण ने कहा (दिसंबर 2012) कि प्रोटो टाईप योजनाओं को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

2.1.9 भारत के संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत योजनायें

भारत के संविधान की धारा 275 (1) अनुसूचित जाति के कल्याण को बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि से अनुदान प्रदान करता है। तदनुसार जनजातीय मामलों का मंत्रालय, राज्यों को निधि मुहैया कराता है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा और जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना है।

राज्य द्वारा संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत अनुदान का उपयोग योजनाओं जैसे आंगनबाड़ी केन्द्र (आ.के.) का निर्माण, छात्रावास का निर्माण और उनमें बिजली का प्रावधान, आवासीय विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कमरा का निर्माण, ग्रामीण अस्पतालों की स्थापना, आवर्ती व्यय की पूर्ति, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की लागत इत्यादि पर किया गया। योजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.1.9.1 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

निधि के उपलब्धता के बावजूद 150 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण अपूर्ण रहा

सचिव, कल्याण विभाग ने 387 आ.के. ₹ 16.72 करोड़ के स्वीकार्य लागत पर 12 मेसो क्षेत्र के लिये ₹ 4.32 लाख की दर पर स्वीकृत (मई 2010) किये थे। निर्माण कार्य 12 महीने में पूर्ण करना था। पाँच नमूना जाँच किये गये स.ज.वि.अ. में दिसंबर 2012 तक आ.के. के निर्माण की स्थिति **तालिका-5** में दिया गया है।

तालिका 5:चयनित समेकित जनजाति विकास अभिकरण में आंगनवाड़ी निर्माण की अवस्था (दिसम्बर 2012)

(₹ लाख में)

स्वीकृत 193 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 43 केन्द्र ही पूर्ण हुए, ₹ 2.57 करोड़ की राशि अव्यवहृत रही।

चयनित समेकित जनजाति विकास अभिकरण्	स्वीकृत आंगन वाड़ी	विमुक्त राशि	पूर्ण की गई आंगनवाड़ी	नहीं ली गई आंगन वाड़ी	अपूर्ण आंगन वाड़ी	उपयोग की गई राशि	अकलित शेष राशि जो अभिकर्ताओं के पास
चाईबासा	50	216.00	10	32	08	60.83	155.17
गुमला	30	129.60	0	05	25	48.48	शुन्य
राँची	50	216.00	12	0	38	183.94	32.06
साहेबगंज्	40	129.60	0	17	23	70.13	59.47
सिमडेगा	23	99.36	21	0	2	88.64	10.72
कुल	**193**	**790.56**	**43**	**54**	**96**	**452.02**	**257.42**

(दिसम्बर 2012 की स्थिति)

योजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे है।

- चाईबासा में प.नि., स.ज.वि.अ., चाईबासा ने स्वीकृत 50 आ.के. में से 16 का निर्माण कार्य आ.के. कार्यपालक अभियंता (का.अ.), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) चाईबासा को सौंपा (मार्च 2011) और 34 आ.के. का निर्माण का कार्य ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (आर.डी.एस.डी.) को सौंपा। प.नि. ने का.अ.एन.आर.ई.पी. और आर.डी.एस.डी. को क्रमश: ₹ 69.12 लाख और ₹ 1.47 करोड़ अग्रिम (मार्च 2011), साथ ही मार्च 2012 तक कार्य पूर्ण करना नियत किया।

  स.ज.वि.अ., चाईबासा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि एन.आर.ई.पी. को सौंपे गये 16 आ.के. में से 12 आ.के. का कार्य, का.अ. एन.आर.ई.पी. के द्वारा निविदा पर संवेदक के नहीं आने के कारण, प्रारंभ नहीं हो पाया। चार में से दो आ.के. ही दिसंबर 2012 तक पूर्ण हो पाये थे। आर.डी.एस.डी. को सौंपे गये 34 आ.के. में से संवेदक के साथ करार न होने के कारण (10 आ.के.) और जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण (10 आ.के.) कुल 20 का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। दिसंबर 2012 तक शुरू की गई 14 आ.के. में से आठ ही पूर्ण हो पाये थे।

  सरकार ने तथ्य को स्वीकार (दिसंबर 2012) किया और कहा कि जमीन उपलब्ध कराने और कार्यों के लिये पुन: निविदा के प्रयास किये जा रहे थे।

- गुमला में 30 आ.के. के निर्माण के लिये ₹ 1.30 करोड़ स्वीकृत और आवंटित किया गया (मई 2010) जिसे 12 महीने में स.ज.वि.अ. द्वारा

पूर्ण किया जाना था। हाँलाकि स.ज.वि.अ. द्वारा सात माह की देरी से (जनवरी 2011) दो महीने (मार्च 2011 तक) में पूरा करने के लिये कनीय अभियंता को कार्यादेश सौंपा। संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि स.ज.वि.अ. गुमला द्वारा स्थल चयन में देरी के कारण पाँच आ.के. का निर्माण दिसंबर 2012 तक शुरू हो पाये जून 2012 तक शेष 25 अपूर्ण आ.के. पर व्यय ₹ 48.48 लाख था और शेष राशि ₹ 81.12 लाख व्ययगत हो गई। आ.के. भवनों के लिये निधि मुहैया कराना और जमीन की उपलब्धता में ताल मेल की कमी थी। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (दिसंबर 2012) किया और कहा कि कार्य प्रारंभ करने के लिये निधि का आवंटन किया जायेगा।

- साहेबगंज में, 40 आ.के. के निर्माण के लिये परियोजना निदेशक स.ज.वि.अ., साहेबगंज को ₹ 1.30 करोड़ की स्वीकृति (मई 2010) दी गई थी। यह कार्य स.ज.वि.अ. के कनीय अभियंता द्वारा किया जाना था। संवीक्षा से उदघटित हुआ कि 40 में से 23 आ.के. 12 महीने में पूर्ण करने हेतु शुरू किये गये (नवंबर 2010)। जून 2012 तक सभी 23 आ.के. के निर्माण पर ₹ 70.13 लाख व्यय प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाया गया था। हाँलाकि, स.ज.वि.अ., साहेबगंज के जनवरी 2013 के प्रतिवेदन में देखा गया कि क.अ. को दिये गये अग्रिम ₹ 43.50 लाख (जुलाई 2011) के विरूद्ध ₹ 20.66 लाख का समायोजन लंबित (जनवरी 2013) था।

  सरकार ने कहा (दिसंबर 2012) कि अभिकरण को संबंधित मापी पुस्त/अभिश्रव/बिल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

- स.ज.वि.अ. सिमडेगा ने स्वीकृत (अगस्त 2010) सभी 23 आ.के. का निर्माण शुरू किया गया था जिसमें से जन सेवक (विलेज लेवल वर्कर) के द्वारा दिसंबर 2012 तक 21 आ.के. पूर्ण किया गया था।

- स.ज.वि.अ., राँची द्वारा ₹ 2.16 करोड़ के स्वीकार्य लागत पर जिला परिषद, राँची को 50 आ.के. का निर्माण सौंपा (नवंबर 2010) गया था। संवीक्षा मे उद्घटित हुआ कि केवल 12 आ.के. (24 *प्रतिशत*) ही पूर्ण हुए और शेष 38 आ.के. अपूर्ण रहे (अगस्त 2012) यद्यपि प्रगति प्रतिवेदन में ₹ 1.84 करोड़ (85 *प्रतिशत*) का व्यय दर्शाया गया था।

  अत: कार्यादेश निर्गत करने के 17 महीने बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका यद्यपि क्रियान्वयन अभिकरण के पास निधि उपलब्ध थी।

2.1.9.2 अ.ज.जा. आवासीय विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान

विभाग द्वारा 89 अ.ज.जा. आवासीय विद्यालय (अ.ज.आ.वि.) (35 उच्च विद्यालय, 45 मध्य विद्यालय और 9 प्राथमिक विद्यालय) चलाये जाते हैं। छात्रावास के निर्माण और छात्रावास में बिजली के प्रावधान में पाई गई कमियाँ नीचे विमर्शित है:

- **अ.ज.जा. आवासीय विद्यालय में छात्रावास के निर्माण में विलंब:**

निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलंब के कारण ₹ 11.61 की मूल्य वृद्धि हुई।

आ.क.आ. द्वारा मेसो कार्यालय, साहेबगंज को अ.ज.आ.वि. में चार[32] 50 बेड के छात्रावास का निर्माण कार्य ₹ 34.49 लाख प्रत्येक के प्राक्कलित लागत पर आवंटित (सितंबर 2005) किया था। तीन कार्य विभागीय कनीय अभियंता (क.अ.) को और एक कार्य कनीय सांख्यिकी सहायक (क.सा.स.) को आवंटित (जनवरी 2006) किया गया था। कार्य की धीमी प्रगति के कारण ये कार्य कार्यपालक अभियंता, एन.आर.इ.पी. साहेबगंज और आर.डी.एस.डी. गोड्डा को पुन: आवंटित किये गये तथा उन्हें ₹ 99.65 लाख निर्गत किये गये (जुलाई 2006) थे। क्रियान्वयन अभिकर्ता ने अपर्याप्त राशि और जमीन की अनुपलब्धता के कारण कार्य कर पाने में अपनी असमर्थता जताई और राशि वापस (मई 2007) कर दी। ये कार्य पुन: विभागीय क.अ. को और क.सा.स. को कार्य प्रारंभ की तिथि से एक वर्ष में पूरा करने के लिये सौंपे (जुलाई 2007) गये। छात्रावासों के प्रारंभ/ निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलंब के कारण विभाग द्वारा उनका प्राक्कलन दोबारा सितंबर 2007 में ₹ 39.08 लाख और मार्च 2010 में ₹ 46.10 लाख पर पुनरीक्षित किया गया। इन छात्रावासों का निर्माण जनवरी 2013 तक पूर्ण नहीं हो पाया था।

- **₹ 14.40 लाख का अधिक भुगतान**

स.ज.वि.अ. साहेबगंज के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि स.ज.वि.अ. साहेबगंज ने जनवरी 2006 और जून 2008 के बीच क.अ. और क.सा.स. को छ:[33] कार्यों (लागत ₹ 1.63 करोड़) के कार्यादेश जारी किये थे। इन कार्यों को इनके प्रारंभ से एक वर्ष के अंदर पूर्ण करना था।

---

[32] धमधमियाँ, कार्तिकभीठा, कुर्तिका और रतनपुर।

[33] अ.ज.जा. आवासीय विद्यालय, धमधमियाँ, कर्तिकभीठा और रतनपुर (तीन योजनाओं); आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय, अदरो में पाँच अतिरिक्त वर्ग कमरा (एक योजना); आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय, बाँझी में आठ अतिरिक्त वर्ग कमरा (एक योजना) और मेसो ग्रामीण अस्पताल पठना में चिकित्सक आवास।

निर्माण में विलंब होने के कारण प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया (मार्च 2010) गया। यह देखा गया कि कार्य के विभिन्न मदों के दर के पुनरीक्षण से पूर्व ही कार्य (84 और 90 *प्रतिशत* के बीच) पूर्ण (जून 2008 और सितंबर 2009) हो गये थे और चलंत लेखा बिल (च.ले.) पर भुगतान (जून 2008 और सितंबर 2009) किया गया था। हाँलाकि दरों के पुनरीक्षण के बाद (मार्च 2010) क.अ. और क.सा.स. ने बाद के च.ले. बिल में पुराने और नये दर का अंतर उन कार्यों के लिये दावा किया जो पहले ही क्रियान्वित किये गये, मापी किये गये और भुगतान किये गये थे। इन च.ले. बिलों का भुगतान (जून 2011) किया गया।

परियोजना निदेशक ने कहा (जुलाई 2012) कि मामले की जाँच की जायेगी।

क.अ. और क.सा.स. को ₹ 14.40 लाख का अधिक भुगतान किया

अत: स.ज.वि.अ. ने क.अ. और क.सा.स. को, उन मदों के लिये जो पुनरीक्षण से पहले क्रियान्वित किये जा चुके थे, के लिये पुनरीक्षित दर पर च.ले. लेखा बिल स्वीकार कर तथा अग्रिम का समायोजन कर ₹ 14.40 लाख का अधिक भुगतान किया।

- **अ.ज.जा. आवासीय विद्यालय में बिजली का प्रावधान**

2007-08 के दौरान छ: नमूना स.ज.वि.अ. में अ.ज.जा.आ.वि. में 15 ट्रांसफारमर स्थापित करने थे। स.ज.वि.अ. गुमला के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि आ.क.आ. ने 63 के.वी.ए. के दो ट्रांसफारमर दो अ.ज.जा., आ.वि. में (चापा टोली ₹ 0.77 लाख और घाघरा ₹ 0.77 लाख) स्थापित करने के लिये ₹ 1.54 लाख आवंटित किया तथा ₹ 5.94 लाख 63 के.वी.ए. ट्रांसफॉरमर और एक के.वी.ए. एच.टी. लाइन अ.ज.जा.आ.वि. सखुआपानी, के लिये आवंटित किये थे। हाँलाकि यह देखा गया कि केवल अ.ज.जा.आ.वि. चापा टोली में ₹ 8.79 लाख के व्यय पर एक ट्रांसफारमर स्थापित (2011-12) किया गया। विद्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि विद्यालय में आंतरिक विद्युत वायरिंग नहीं थी। अत: ₹ 8.79 लाख व्यय करने के बाद भी विद्यालय बिना बिजली के चल रहा था।

अ.ज.जा.आ.वि. चापा टोली के लिये ट्रांसफारमर की स्थापना के लिये स्वीकृत राशि ₹ 0.77 लाख के विरूद्ध स.ज.वि.अ. ने ₹ 8.79 लाख व्यय किये जो इंगित करता है कि व्यय का प्राक्कलन सही ढंग से नहीं हुआ था

तथा दो अन्य विद्यालयों में जिनके लिये निधि आवंटित हुई थी में ट्रांसफॉरमर नहीं लगे थे।

2.1.10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने, नवोदय विद्यालय के तर्ज पर धारा 275 (1) के अंतर्गत अनुदान से राज्यों के लिये वर्ग VI से XII में पढ़ने वाले अ.ज.जा. छात्रों के लिये छ:[34] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ए.मॉ.आ.वि.) स्वीकृत (मार्च 2004) किये। ए.मॉ.आ.वि. का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों के अ.ज.जा. के छात्रों में उत्तम शिक्षा मुहैया करना था ताकि वे सामान्य छात्रों के समान ही सबसे अच्छे अवसर पाने योग्य हो सके।

इन विद्यालयों के निर्माण, संधारण और प्रबंधन के लिये एक निबंधित समिति[35] गठित करना था। हाँलाकि दिसंबर 2012 तक कोई समिति गठित नहीं की गई थी।

संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि प्रत्येक विद्यालय में 300 से 420 छात्रों (60 छात्र प्रति वर्ग) के लिये कल्याण विभाग द्वारा छ: ए.मॉ.आ.वि. स्थापित किये गये थे (जनवरी 2006)।

ए.मॉ.आ.वि. के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रधानाध्यापक और शैक्षणिक कर्मियों के लिये समान सरकारी विद्यालयों से अधिक वेतन, सभी शैक्षणिक कर्मियों के लिये आवास, पढ़ाने हेतु उचित समय व्यवसायिक शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं पाठ्येत्तर कार्य के प्रावधान थे।

छ: में से तीन[36] ए.मॉ.आ.वि. के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुई कमियों की चर्चा नीचे है:

- मार्गदर्शिका में वर्णित निबंधित समिति स्थापित करने के बजाय विद्यालय निजी क्षेत्र/एन.जी.ओ. द्वारा चलाये जा रहें थे।
- एन.जी.ओ. के साथ हुए एम.ओ.यु. के अनुसार विद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन के लिये एक स्थानीय प्रबंधन समिति गठित किया जाना था जिसमें झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि, उपायुक्त, शिक्षाविद्, माता पिता और शिक्षकों के प्रतिनिधि और प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव के रूप में रहने थे। यह नहीं हो पाया था।

---

[34] भोगनाडीह, कुचाई, काठीजोरिया, सलगाडीह्, सिसाई और तोरसुन्दरी

[35] विभागीय प्रतिनिधि, प्रख्यात शिक्षाविद् चयनित प्रतिनिधि और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि

[36] भोगनाडीह (साहेबगंज), सलगाडीह् (राँची) और तोरसुन्दरी (पश्चिम सिंहभूम)

- ए.मॉ.आ.वि. में शिक्षा का माध्यम हिन्दी था जबकि कल्याण विभाग और एन.जी.ओ. के बीच किये गये (अक्टूबर 2007) एम.ओ.यू. के अनुसार शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना था। साथ ही विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के साथ संबंद्ध होना था जो नहीं हो पाया। हाँलाकि ए.मॉ.आ.वि. झारखण्ड, अधिविध परिषद के साथ संबंद्ध हुए थे।
- हमने देखा कि 2010-12 के दौरान विज्ञान के अंतर्गत वर्ग XII के लिये 291 में से 125 छात्र (43 *प्रतिशत*) झारखण्ड अधिविध परिषद् की परीक्षा पास करने में असफल रहे। परीक्षाफल बताये गये उद्देश्यों से मेल नहीं खाया।

2.1.11 मेसो ग्रामीण अस्पताल

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं की पहुँच और उपलब्धता में सुधार के लिये सरकार ने (जुलाई 2003) चौदह, 50 शैय्या वाले मेसो ग्रामीण अस्पतालों को लोक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के तर्ज पर स्थापित करने का निर्णय लिया। इनमें से नौ (फरवरी 2009) कार्यशील थे और शेष पाँच कार्यशील होना शेष था (दिसंबर 2012)। इस योजना को केन्द्रीय निधि, संविधान की धारा 275 (1) से क्रियान्वित होना था।

अस्पताल को प्रथम रेफरल इकाई (एफ.आर.यू.) के रूप में काम करना था ताकि सबसे अधिक वंचितों तक पहुँचा जा सके तथा गरीबों से गरीब का प्रबंधन किया जा सके।

आ.क.आ., राँची में एम.आर.एच.के. अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुआ।

- एन.पी.सी.सी. ने 14 में से नौ अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा किया था और दिसंबर 2004 और मार्च 2008 के बीच सौंप दिया। विभाग द्वारा प्रतिष्ठित एन.जी.ओ. से व्यापारिक घरानों से, धर्म आधारित संगठनो से इन अस्पतालों के संचालन के लिये इच्छा की अभिव्यक्ति (मार्च 2006) मँगाये गये। आ.क.आ. की अध्यक्षता वाली चयन समिति[37] ने चार[38] एन जी ओ का चयन किया और उनसे नौ एम.आर.एच. के संचालन के लिये

---

[37] आ.क.आ.- अध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, रिनपास के निदेशक, एच.ई.सी. अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डॉ सुधीर कुमार- अस्थि रोग विभाग के सहायक प्रधायपक और केयर के प्रतिनिधि

[38] (1) इंस्टीट्युट ऑफ कंटिन्युईंग एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग (आई.सी.ई.आर.टी) (1) कुचाई, (2) पारसडीह (2) रिसर्च इंस्टीट्युट फॉर सिविल हेल्थ इंटिग्रेशन ट्रष्ट होस्पीटल(रिन्ची) (1) जोन्हा (2) अड़की, (3)लिट्टीपाड़ा (4)काठिकुंड (3) विकास भारती- बहरागोड़ा (4) डायनेमिक तरंग (1) केंदुआ (2) नाला

एम.आर.एच. की स्थापना में विलंब के कारण भवनों की मरम्मत पर ₹ 47.76 लाख व्यय करने पड़े

एम.ओ.यु. हस्ताक्षरित किये थे (फरवरी 2009)। यह देखा गया कि अस्पतालों को सौंपने के समय (फरवरी 2009) आठ[39] अस्पतालों की अवस्था जीर्ण शीर्ण थी और एन.जी.ओ. को भवनों की मरम्मत पर ₹ 47.76 लाख व्यय करने पड़े।

- हमने देखा कि शेष पाँच एम.आर.एच. का निर्माण पूरा हो गया था और तीन[40] एन.जी.ओ. को अगस्त 2012 में आवंटित कर दिया गया था। हाँलाकि एम.आर.एच. कार्यशील नहीं हो पाये क्योंकि फरवरी 2013 तक एन.जी.ओ. के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित नहीं हो पाये थे।

2.1.12 मानव संसाधन प्रबंधन

योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण में कर्मियों की पर्याप्तता ही सर्वोत्तम होती है। राज्य में जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये झारखण्ड सरकार ने विभिन्न संवर्गों में प्रत्येक स.ज.वि.अ. के लिये 18[41] पद स्वीकृत (फरवरी 2009) किये। हमने देखा कि पाँच[42] नमूना जाँच स.ज.वि.अ. में मुख्य पदों में बड़ी रिक्तियाँ थी।

- नमूना जाँच जिलो में विभिन्न संवर्गों के 90 स्वीकृत पदों के विरूद्ध वास्तविक कार्यरत बल (जुलाई 2012) 45 थी जो कि 50 *प्रतिशत्* थी। ***(परिशिष्ट-2.5)***
- फरवरी 2009 में स.ज.वि.अ. के गठन से ही सहायक परियोजना निदेशक और सहायक परियोजना प्रबंधक के पद नमूना जिलों में रिक्त थे।
- चार[43] नमूना जाँच किये गये स.ज.वि.अ. में परियोजना पदाधिकारी परियोजना निदेशक के बदले कार्य कर रहे थे।

अत: मानव संसाधन में 50 *प्रतिशत्* की कमी ने मेसो क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन और अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था जैसा कि पूर्व के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

---

39 दुमका पाकुड़, खुँटी, राँची, लोहरदगा, सरायकेला, साहेबगंज और जामताड़ा के एम.आर.एच.।

40 बड़ाचिरू, पश्चिम सिंहभूम और मनानचुटांग, लातेहार आई.सी.ई.आर.टी. को; बानो, सिमडेगा और लोधोडीह, चक्रधरपुर डायनेमिक तरंग को और नागफेनी, गुमला विकास भारती को।

41 एक परियोजना निदेशक, दो सहायक परियोजना निदेशक, दो सहायक परियोजना प्रबंधक, एक सहायक अभियंता, एक कार्यालय अधीक्षक, एक लेखापाल, दो लिपिक, एक निजी सहायक, चार आदेशपाल और तीन चालक।

42 चक्रधरपुर के लिये मानव संसाधन स.ज.वि.अ. चाईबासा में सम्मिलित है।

43 चक्रधरपुर, गुमला, सिमडेगा और साहेबगंज।

विभागीय सचिव ने कहा (दिसंबर 2012) कि मानव संसाधन की कमी को न्युन किया जायेगा।

2.1.13 अनुश्रवण

क्रियान्वयन प्रक्रिया को सहज बनाने, योजनाओं/परियोजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकण करने, कार्यकारी भागीदारों एवं अन्य हितधारको का क्षमता वर्द्धन करने तथा सभी स.ज.वि.अ. का डाटा बेस का प्रंबधन करने के उद्देश्य से जनजातीय कल्याण आयुक्त के कार्यालय में एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकण प्रकोष्ठ[44] का गठन (फरवरी 2008) किया गया था। प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी चल रही परियोजनाओं की योजना, बजट, कार्यान्वयन तथा समीक्षा के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) का सृजन करना था।

प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कभी नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप अनुश्रवण मूल्यांकण एवं प्रकोष्ठ कार्यरत नहीं हो सका। एक प्रशिक्षित अधिकारी और दो अनुबंधित सहायकों (जुलाई 2008) से कार्यरत थे जो केवल विभाग के डाटा बेस का प्रबंधन किया। यहाँ तक कि एम.आई.एस. अधिकारी का पद जो मई 2009 से खाली था फरवरी 2011 तक नहीं भरा गया था। चुंकि प्रकोष्ठ तीन साल तक में भी कार्य शुरू नहीं कर पाया, प्रकोष्ठ को पुनर्गठित (फरवरी 2011) किया गया जिसमें सचिव, कल्याण विभाग अध्यक्ष के रूप में, आदिवासी कल्याण आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में तथा उप सचिव/अवर सचिव, कल्याण विभाग, सदस्य के साथ पाँच तकनीकि सलाहकार एवं पाँच कार्यालय कार्यपालक सम्मिलित थे। लेकिन यह देखा गया कि दिसंबर 2012 तक सलाहकार एवं कार्यालय कार्यपालकों की नियुक्ति नहीं की गई थी।

मेसो क्षेत्र स्तर पर, राज्य सरकार के आदेश (नवम्बर 2005) के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए प.का.स. द्वारा 60 दिनों के अंतराल पर अर्थात सलाना छः समीक्षा बैठक करना था।

तीन प.का.स. के अनुश्रवण संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच से यह उद्घाटित हुआ कि केवल 24 समीक्षा बैठक[45] योजनाओं के प्रगति अनुश्रवण 2007 से 2012 के बीच किया गया था जबकि प्रत्येक प.का.स. को 30 बैठकें

---

[44] एक प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण पदाधिकारी, एम.आई.एस. पदाधिकारी और दो सहायक को मिलाकर

[45] 2007-12 के दौरान प क स, राँची: 7 बैठके; प क स, सिमडेगा: 11 बैठके और प क स, साहेबगंज:6 बैठके।

करनी थी। इसके अलावा सरकार ने परियोजना निदेशक स्तर के पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु अनुसूचि निर्धारित नहीं किया गया था।

एक प्रभावी अनुश्रवण तंत्र का अभाव योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी के कारणों में से एक कारण था।

सरकार ने कहा (दिसंबर 2012) कि योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जायेगा तथा इस दिशा में अनुश्रवण प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया जा रहा है जो कि जन जातीय सहकारी विकास निगम, राँची के कार्यालय से कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

2.1.14 योजना के प्रभाव का मूल्यांकण

झारखण्ड अनुसूचित जनजाति कल्याण अनुसंधान संस्थान, राँची (जून 2008) द्वारा मेसो क्षेत्रों में एस.सी.ए. और संविधान की धारा अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकण अध्यन किया गया। अध्यन का निष्कर्ष निकला कि अनुसूचित जन जातियों के लिए आय सृजन तथा मेसो क्षेत्रों में बुनियादि ढाँचे में कमी को भरने का प्रयास असंतोषप्रद था क्योंकि जनजातियों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं थी एवं सिंचाई सुविधाएं अप्रर्याप्त थे, योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियाँ थी, लाभुकों के बीच जागरूकता की कमी थी और दूरदराज के क्षेत्रों में जनजतियों को वांछित लाभ नहीं पहुँचा था। अध्ययन यह भी दर्शाया कि केवल 46 *प्रतिशत्* जनजातियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था।

विभाग के सचिव (दिसंबर 2012) ने कहा कि आय सृजन योजनाओं के प्रभाव का अध्यन नाबार्ड कंसल्टेसी सर्विसेस (पी) लिमिटेड (नेबकोन्स) द्वारा जारी था और उसके अध्ययन और आकलन के आधार पर सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे।

2.1.15 निष्कर्ष

हाँलाकि राज्य सरकार ने 2007-2012 के दौरान मेसो क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम के लिये टी.एस.पी. के लिये वि.के.स. एवं संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत अनेक योजनायें शुरू की जिन पर योजना, वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण में कमी के कारण विपरित असर पड़ा।

- फरवरी 2009 में राज्य सरकार ने जिला स्तर पर विस्तृत योजना बनाने एवं टी.एस.पी. के समेकन के लिये स.ज.वि.प. को समेकित जनजातीय

विकास अभिकरण में प्रभावी एवं पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। स.ज.वि.अ. फरवरी 2011 में निबंधित हो पाया और प्रस्तावित पुनर्गठन दिसंबर-2012 तक पूर्ण नहीं हो पाया। फलस्वरूप मेसो क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई। आगे राज्य सरकार ने स.ज.वि.अ. से सूचना प्राप्त किये बिना ही वार्षिक योजना तैयार की। हमनें पाया कि वर्ष 2005 में 'प्रदान' एक एन.जी.ओ. के द्वारा गाँवों के आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाओं का डाटा तैयार किया गया परंतु उसे विगत सात वर्षो के दौरान अद्यतन नहीं किया गया। अत: सरकार द्वारा वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के दौरान मेसो क्षेत्र के लिये वास्तविक जरूरतों को सुनिश्चित नहीं किया गया।

- भारत सरकार 100 *प्रतिशत्* वित्तीय सहायता टी.एस.पी. के लिये वि.के.स. एवं सविधान की धारा 275 (1) के अधीन अनुदान के लिये मुहैया कराती है। 2007-12 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 559 करोड़ निर्गत किये जिसके विरूद्ध ₹ 557 करोड़ आ.क.आ. को वितरित किये गये। हमने देखा कि स.ज.वि.अ. एवं कार्यान्वयन अभिकरणों में निधि के अंतिम उपयोग सुनिश्चित किये बिना ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) भेज दिये गये जो कि आ.क.आ., नमूना स.ज.वि.अ. एवं कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ में बड़ी राशि अव्यवहृत पड़े रहने से परिलक्षित होती है। फलस्वरूप, बड़ी संख्या में योजनायें अपूर्ण रही।
- 2011-12 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर की गई निकासी के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल नहीं जमा किये जाने के कारण ₹ 19.47 करोड़ के केन्द्रीय निधि की निकासी नहीं की जा सकी, आ.क.आ. ने ₹ 91.81 करोड़ का केन्द्रीय निधि की निकासी (मार्च 2012) कर वैयक्तिक लेजर खाते में जमा किया।
- दिसंबर 2012 को मेसो क्षेत्र में 353 स्वीकृत योजनाओं (2006-12) में से 271 अपूर्ण योजनाओं (77 *प्रतिशत्*) के उदाहरण थे। नमूना स.ज.वि.अ. में प्रोटो टाईप के अंतर्गत 181 स्वीकृत योजनाओं में से 167 योजनायें (92 *प्रतिशत्*) अपूर्ण थी। हमने वैसी योजनाओं पर व्यय देखा जो निरर्थक, अलाभप्रद, निष्फल और योजना के दायरे से बाहर के थे।
- हमने आधारभुत संरचना के निर्माण कार्य के अपूर्ण रहने के दृष्टांत देखे। नमूना स.ज.वि.अ. में स्वीकृत 193 आंगनबाड़ी केन्द्रों (आ.के.) में से 96 आ.के. अपूर्ण थे जबकि 54 का कार्य प्रारंभ नहीं किये गये थे। आगे 2003 में प्राथमिक रेफरल इकाई के रूप में प्रस्तावित 14 मेसो ग्रामीण

अस्पतालों का निर्माण विलंब से हुआ और उनमें से पाँच अभी तक चालू नहीं हो पाये। चार जनजातीय आवासीय विद्यालयों के लिये 2005 में स्वीकृत छात्रावास जनवरी 2013 तक पूर्ण नहीं थे।

- नमूना स.ज.वि.अ. के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में मानव संसाधन की कमी एक रूकावट थी। विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत 90 पदों के विरूद्ध 45 पदों पर कर्मी (50 *प्रतिशत*) कार्यरत थे (जुलाई 2012)। फरवरी 2009 में स.ज.वि.अ. के गठन के समय से ही अपर परियोजना निदेशक और सहायक परियोजना प्रबंधक के पद खाली थे।
- राज्य स्तर पर विभाग में अनुश्रवण एवं मुल्यांकन कोषांग कार्यरत नहीं था जबकि इसका पुनर्गठन फरवरी 2011 में किया गया था। इसी प्रकार परियोजना कार्यान्वयन समिति की प्रगति की समीक्षा नियमित अंतराल पर नहीं की गयी थी। सरकार ने परियोजना निदेशक (प.नि.) के द्वारा कार्य स्थल के निरीक्षण के लिये कोई अनुसूचि तय नहीं की थी। प्रभावी अनुश्रवण तंत्र के अभाव ने योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन को प्रभावित किया।

2.1.16 अनुशंसाए

हम निम्नलिखित अनुशंसा करते हैं

- *सरकार को स.ज.वि.प. का प्रस्तावित पुनर्गठन एवं मेसो क्षेत्र में विस्तृत योजना के लिये टी.एस.पी. का समेकन पूर्ण करना चाहिये। 'प्रदान' द्वारा तैयार किये गये डाटा को अद्यतन करना चाहिये और योजनाओं के अंतर्गत लाभ पानेवाले लक्षित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त होने के बाद ही योजना का अंतिमिकरण किया जाना चाहिये।*
- *सरकार को निधियों का समय पर उपयोगिता सुनिश्चित करना चाहिये और निधियों के अंतिम उपयोग पर आधार के उ.प्र.प. जमा किये जाने चाहिये।*
- *सरकार को योजनाओं का क्रियान्वयन तेज करना चाहिये एवं परियोजनाओं को तय समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिये।*
- *सरकार को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त मानव संसाधन मुहैया कराना सुनिश्चित करना चाहिये।*
- *योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक स्तर पर निर्धारित एवं सुनिश्चित किया जाना चाहिये।*

राज्य सरकार ने अनुशंसाओं को स्वीकार (दिसम्बर 2012) किया।

नगर विकास विभाग

2.2 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने 3 दिसंबर 2005 को शहरों के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम) लागू किया जिसे सात साल (2005-12) की अवधि में पूर्ण किया जाना था। इस मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा, जनवरी 2008 से मार्च 2011 के दौरान, 27 परियोजनाओं को झारखण्ड में अनुमोदित किया गया। इस मिशन को शहरी प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन में सुधार तथा स्थानीय शासन में हितधारक की भागीदारी के माध्यम से प्रभावशाली शहरी सेवा वितरण और परिष्कृत नागरिक बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि के द्वारा प्राप्त किया जाना था।

'जेएनएनयूआरएम' के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा जो वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक की अवधि को कवर कर रही थी, सात शहरी स्थानीय निकायों (यु.एल.बी.) द्वारा कार्यान्वित 15 परीयोजनाओं में से 12 परियोजनाओं के संबंध में की गयी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे वर्णित हैं:

- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गइ जानकारी के अनुसार राज्य सरकार/यूएलबी द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.ए.) (दिसम्बर 2007 से जुलाई 2011) के अनुसार कुल 31 सुधारों में से केवल 22 को पूर्णत: लागू किया जा सका जबकि सात सुधार आंशिक रूप से लागू किए गए थे तथा दो सुधारों को लागू किया जाना बाकी था ।

- 12 चयनित परियोजनाओं के डी. पी. आर. में हमने पाया की बिना स्पष्ट और भारमुक्त भूमि की उपलब्ध्ता के परियोजनाएं ली गई थी, परिणामत: परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

  परियोजनाओं को विलम्ब से पुर्ण होने तथा सरकारी निधि अवरुद्ध होने की स्थिति से बचने के लिए सरकार को परियोजनाओं के शुरू होने से पहले ही भार मुक्त भूमि की पहचान और अधिग्रहण सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।

- ₹ 589.20 करोड़ उपलब्ध धनराशि के विरूद्ध केवल ₹ 326.51 करोड़ (55.42 *प्रतिशत*) का उपयोग किया जा सका, शेष ₹ 262.69 करोड़ की राशि अप्रयुक्त

पड़ी रही। बीएसयूपी के मामले में स्थिति विशेष रूप से गम्भीर थी जहां उपलब्ध राशि का केवल 6.13 *प्रतिशत्* का ही उपयोग किया जा सका था ।

शहरी आबादी को आधारभूत सेवाएं तथा शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए चिन्हित परियोजनाओं पर निधियों का समयबद्ध तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

- राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) को जे.एन.एन.यू.आर.एम के क्रियान्वन हेतु केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों को संवितरित की जानी थीं तथा इन निधियों/जमाओं पर अर्जित ब्याज की राशि जीआरडीए लिमिटेड की आय नहीं थी फ़िर भी हमारी जांच में पता चला कि मार्च 2012 तक कुल ₹ 8.00 करोड़ इन निधियों/जमा पर ब्याज के रूप में अर्जित किया गया था जिसमें से ₹ 4.02 करोड़ का उपयोग प्रशासनिक व्यय (₹ 85.50 लाख) पर और आय कर (₹ 3.17 करोड़) भुगतान के लिए किया गया था ।

- राँची जल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत यह देखा गया कि प्रधान कार्य (हेडवर्क्स) प्रमंडल राँची में मात्रा विपत्र (बी.ओ.क्यु.) के अनुसार 900 मिमी व्यास के पाइप की आवश्यकता केवल 100 मीटर की थी परंतु उत्पाद शुल्क छूट प्रमाणपत्र 7,550 मीटर के लिए निर्गत किया गया तथा इसके विरुद्ध 7,050 मीटर डी.आइ. पाईप की खरीद/आपूर्ति की गयी। बी.ओ.क्यु में दर्शायी गई 900 मिमी व्यास के पाईप की आवश्यकता से अधिक की आपूर्ति/ख़रीद के कारण संवेदक को ₹ 8.21 करोड़ का अतिरिक्त /अनाधिकृत भुगतान किया गया।

अतिरिक्त लागत से बचने के साथ ही परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ससमय पूर्ण करने के लिए सरकार को योजनाओं का निष्पादन, मितव्ययीता, कुशलता और प्रभावी ढ़ग से सुनिश्चित करना चाहिए।

- तीन शहरी स्थानीय निकायों के डीपीआर के अनुसार प्रस्तावित लाभार्थियों की पहचान राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड और स्लम बस्तियों के प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से की गई थी। लाभार्थी सूची तैयार किये जाने के समय विधवा, एकल महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाना था। हाँलाकि, नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित (अक्टूबर 2009) समिति द्वारा, डीपीआर में निहित सूचियों के सत्यापन के बाद तैयार की गई सूची की जाँच से पता चला कि डीपीआर में सही जानकारी का अभाव था क्योंकि इनमें मृतक, लापता, भूमिहीन, संदिग्ध लाभार्थियों के अलावा वैसे लाभार्थी भी शामिल थे जिनके पास पक्का मकान थे, जो सरकारी सेवा में होने के कारण अयोग्य थे तथा जिनको वाम्बे के तहत पहले से ही आवास आवंटित था।

- गुमला में आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत नकली चालानों के माध्यम से पथ प्रकाश सामग्री की ख़रीद दर्शाकर ₹ 22.48 लाख का गबन किया गया।

- आईएचएसडीपी के दिशा निर्देशों के अनुसार, एसएलसीसी को चल रहे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और नए परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बैठक करना आवश्यक था। लेकिन गठन के उपरांत, 23 बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध एस.एल.सी.सी. की केवल तीन बैठकें हुईं। इसी प्रकार यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के दिशा निर्देशों के अनुसार, एस.एल.एस.सी. को चल रहे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और नए परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक साल में कम से कम तीन बैठक करना आवश्यक था। लेकिन जून 2006 में गठन के उपरांत, कम से कम 18 बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध मार्च 2012 तक एस.एल.एस.सी. की केवल दो बैठकें हुईं।

- एम.ओ.एच.यु.पी.ए द्वारा भी बी.एस.यू.पी और आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी हेतु तीसरी पार्टी निरीक्षण और अनुश्रवन एजेंसियों (टी.पी.आइ.एम.ए.) की नियुक्ति के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है। मेसर्स सृष्टि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली का चयन (मई 2011) में टी.पी.आइ.एम.ए के रूप में उक्त प्रयोजन हेतु गठित निविदा समिति द्वारा किया गया था। हाँलाकि चयनित एजेंसी को सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन (फरवरी 2012) दी गई है, परंतु चयनित फर्म के साथ एमओए का निष्पादन नहीं किया जा सका था।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावशाली और समयबद्ध तरीके से किये जाने के लिये अनुश्रवन तंत्र को मजबूत करना सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.1. परिचय

भारत सरकार ने 3 दिसंबर 2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल नगरों में आधारभूत सेवाओं के समेकित विकास पर केन्द्रीभूत ध्यान देने, परिसम्पत्ति निर्माण तथा परिसम्पत्ति प्रबन्धन के बीच प्रभावी संबंध सुनिश्चित करने ताकि शहरों में आधारभूत सेवाओं का सृजन न केवल दक्षतापूर्ण तरीके से संरक्षित की जा सके बल्कि दीर्घकालीन अवधि के लिये स्वपोषित हो सके, शहरी आधारभूत सेवाओं में कमियों को पूरा करने के लिये पर्याप्त निधि का निवेश सुनिश्चित करने, चयनित शहरों के साथ शहरी सीमा से सटे क्षेत्रों, बाहर के क्षेत्रों तथा शहरी गलियारों का सुनियोजित विकास करने ताकि विस्तरित रूप से शहरीकरण हो सके, शहरी गरीबों के

लिए सार्वभौमिक पहुँच पर बल देने के साथ नागरिक सुविधाओं का वितरण और उपयोगिताओं के प्रावधान को बढ़ाने, भीड़-भाड़ को कम करने के लिये शहरी नवीकरण यानि पुराने नगरीय क्षेत्रों के पुनर्विकास के कार्यक्रम लेने, के उद्देश्यों से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का शुभारंभ किया। मिशन की अवधि सात साल अर्थात 2005-12 थी।

इस मिशन के चार संघटक थे:(i) शहरी बुनियादी ढाँचा और प्रशासन (यु.आई.जी), (ii) छोटे और मध्यम शहर के लिए शहरी बुनियादी ढाँचा विकास योजना(यु.आइ.डी.एस.एस.एम.टी.), (iii) शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं (बी.एस.यु.पी.), और (iv) समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आइ.एच.डी.एस.पी)| भारत सरकार ने जनवरी 2008 से मार्च 2011 के दौरान इन 4 संधटकों के अधीन झारखण्ड राज्य में ₹ 1691.88 करोड़ की 27 परियोजनाओं (तीन मिशन शहरों-राँची धनबाद तथा जमशेदपूर में 11 परियोंजनाए तथा 12 गैर-मिशन शहरों में 16 परियोजनओं) को स्वीकृति दी। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा मार्च 2012 तक कुल ₹ 590.20 करोड़ प्राप्त किया गया। इनमें से ₹ 589.20 करोड़ कार्यकारी एजेंसियों को विमुक्त किए गए, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा कुल ₹ 326.51 करोड़ की राशि तक खर्च की गई (मार्च 2012)। जहां तक परियोजनाओं की बात है सभी 27 परियोजनाएं 31 मार्च 2012 तक अपूर्ण रहीं।

2.2.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देश के अनुसार मिशन के तहत परियोजनाओं पर निर्णय तथा प्राथमिकता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, संबंधित विभागों/अधिकारियों[1] से सदस्यों के साथ, राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस.एल.एस.सी.), का गठन किया जाना था। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल एजेंसी को एस.एल.एस.सी. की सहायता करनी थी। झारखण्ड राज्य के लिए ग्रेटर राँची डेवेलपमेंट एजेंसी (जी.आर.डी.ए.) लिमिटेड, नोडल एजेंसी थी। एस.एल.एन.ए. की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करने एवं लागू करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पी.एम.यू) को एस.एल.एन.ए में स्थापित किया

[1] नगर विकास विभाग, आवास विभाग, सांसद/विधायक, वित्त विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, महापौर/प्रशासक/विशेष पदधिकारी

जाना था। जे.एन.एन.यू.आर.एम के तहत परियोजनाओं और सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए मिशन शहरों के स्थानीय निकायों में परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आइ.यु.) का गठन उनके नगर निकायों द्वारा किया जाना था ।

2.2.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि

- क्या राज्य तथा नगर निकायों के स्तर पर योजना पर्याप्त तथा सक्षम थी;
- क्या वित्तीय प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली सही ढंग से काम कर रही थी;
- क्या शहरी गरीबो को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने तथा आधारभूत सुविधाओं के समेकित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओ का कार्यान्वयन कुशलता, मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता के साथ किया जा रहा था; और
- क्या पर्याप्त एवं प्रभावकारी मूल्यांकन तथा अनुश्रवण के लिए तंत्र मौजूद थे।

2.2.4 लेखापरीक्षा के मापदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए अपनाए गए लेखा परीक्षा मापदंड निम्नलिखित साधनों में से लिए गए है-

- शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यु.डी), आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एम.ओ.एच.यु.पी.ए), वित्त मंत्रालय(एम.ओ.एफ) तथा नगर विकास विभाग (न.वि.वि), झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश, निर्देश एवं परिपत्र;
- चयनित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा समझौता ज्ञापन पत्र;
- जे.एन.एन.आर.यू.एम के विभिन्न मुद्दों पर शहरी विकास मंत्रालय, आवास शहरी एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए टूल किट; और
- केंद्रीय संस्तुति एवं केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सी.एस.एम.सी) की बैठकों के कार्यवृत्त।

2.2.5 लेखापरीक्षा विस्तार एवं कार्यविधि

जे.एन.एन.आर.यू.एम. के अधीन झारखण्ड में मार्च 2012 तक स्वीकृत की गई 27 परियोजनाओं ***(परिशिष्ट-2.6)*** में हमने सात[2] जिलो में चलाई जा रही 12[3] परियेाजनाओं को क्रम रहित आधार पर निष्पादन लेखा परीक्षा के लिए चुना। 2005-12 तक की अवधि के लिए अप्रैल 2012 से जून 2012 के दौरान नगर विकास विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड सरकार तथा कार्यकारी एजेंसियों[4] के दस्तावेंजों तथा फाइलों की नमूना जाँच तथा परियोजनाओं की संयुक्त भौतिक जाँच के द्वारा लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, विस्तार तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की कार्याविधि की चर्चा 20 अप्रैल 2012 को सचिव नगर विकास विभाग के साथ 15 नवम्बर 2012 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में की गई ।

चर्चा के परिणामों को उपयुक्त ढंग से निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है ।

2.2.6 योजना

2.2.6.1 राज्य और नगर विकास स्तर पर प्रारंभिक संरचना

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए)

जे.एन.एन.आर.यू.एम. की परियोजनाओं को प्राथमिकता देने एवं लागू करने के लिए ग्रेटर राँची डेवेलपमेंट एजेंसी (जी.आर.डी.ए.) लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित (अप्रैल 2006[5] तथा जून 2006[6]) किया गया। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के मुख्य कार्य विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का आकलन करना, मिशन के तहत केन्द्र सरकार की सहायता प्राप्त करने के लिये राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की अनुशंसा प्राप्त करना, राज्य तथा केन्द्र सरकार के अनुदानों का प्रबंधन, कार्यकारी अभिकरणों के लिए निधियों की विमुक्ति, परियोजनओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण आदि थे। नगर निकायों द्वारा समर्पित त्रैमासिक

---

2 मिशन शहर- राँची और धनबाद गैर मिशन शहर देवघर हजारीबाग लोहरदगा गुमला चास(बोकारो)

3 राँची जलापूर्ति और बीएसयूपी (फेज 2), धनबाद जलापूर्ति और बीएसयूपी (फेज 2), देवघर जलापूर्ति, हजारीबाग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आईएचएसडीपी, लोहरदगा एसडब्ल्यूएम और आईएचएसडीपी गुमला आईएचएसडीपी, चास एसडब्ल्यूएम और जलापूर्ति

4 नगर निकायों

5 यूआईजी और बीएसयूपी परियोजनाओ के लिए

6 यूआईडीएसएसएमटी और आईएचएसडीपी परियोजनाओं के लिए

प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की निगहबानी करना था। हाँलाकि एस.एल.एन.ए. द्वारा बताया गया (जून 2012) कि केंद्र सरकार को अप्रैल 2008 से मार्च 2012 के दौरान 266 त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजे जाने थे जिसके विरुद्ध मात्र 201 त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन ही भेजे जा सके ।

कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.)

पी.एम.यू. के गठ्न में विलंब हुआ तथा कार्यबल आवश्यकता से कम थी

राज्य स्तर पर मिशन से सबंधित कार्यो के कार्यान्वयन तथा प्रबंधन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू) द्वारा एस.एल.एन.ए. को सहयोग प्रदान किया जाना था जिसमे खुले बाजार से निश्चित अवधि अनुबंध के आधार पर तथा यथा सम्भव एकल अनुबंध के तहत नियुक्ति की जानी थी ताकि पी.एम.यू. दल में समन्वयता तथा एस.एल.एन.ए के प्रति पूर्ण रुप से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। यह देखा गया कि एस.एल.एन.ए में पी.एम.यू. के गठन के लिए भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय (ए.एस.सी.आई), हैदराबाद को (अगस्त 2009) परामर्शी मनोनीत किया गया। हाँलाकि महाविद्यालय द्वारा इस संबंध में कोई कार्य नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा यह मनोनयन फरवरी 2010 में निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात विशेषज्ञों के 11 चिन्हित पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए। केवल 6 विशेषज्ञ नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए जिसमें से 5 ने पी.एम.यू. में योगदान दिया (मार्च/ अप्रैल 2010)।

यद्यपि एस.एल.एन.ए. के गठन के 4 वर्षो के बाद पाँच[7] विशेषज्ञों के साथ पी.एम.यू. वास्तविक रूप से अस्तित्व में आया (मार्च 2010), दो विशेषज्ञों ने बाद में इस्तीफा दे दिया (जुलाई 10 तथा अप्रैल 2011) तथा 11[8] विशेषज्ञों की आवश्यकता के विरूद्ध केवल तीन[9] विशेषज्ञ ही पी.एम.यू. में कार्य कर रहे थे (मार्च 2012)। स्पष्टत: पी.एम.यू. में नगर निकायों को आवश्यक अभियांत्रिकी/तकनीकी सहायता देने के लिए कार्यबल की कमी थी ।

---

[7] एमआईएस विशेषज्ञ सामाजिक विकास विशेषज्ञ(समान एवं विकास) विशेषज्ञ, कम्यूनिटी मोविलाईजेशन और एमआईएस नगरीय गरीबी प्रबंधन विशेषज्ञशोध एवं प्रशिक्षण समन्वयन

[8] सामाजिक विकास विशेषज्ञ, शहरी गरीबी प्रबंधन विशेषज्ञ, शोध एवं प्रशिक्षण समन्वयक, परियोजना प्रबंधन और खरीद विशेषज्ञ, परियोजना विशेषज्ञ (आवास एवं गन्दी बस्ती विकास), कार्यकम प्रबंधक/टीम लीडर लोक कार्य, कार्य एवंम् लोक स्वास्थ्य अभियन्ता, नगर वित्त विशेषज्ञ, एमआईएस विशेषज्ञ, विशेषज्ञ कम्यूनिती मोविलाईजेशन और एमआईएस तथा विशेषज्ञ(समाजिक एवं विकास)

[9] सामाजिक विकास विशेषज्ञ (यूआईडी/एमआईयूडी), शहरी गरीबी प्रबंधन विशेषज्ञ (बीएसयूपी/ एमओएचयूपीए) और शोध एवं प्रशिक्षण समन्वयक (बीएसयूपी/एमओएचयूपीए)

सचिव, नगर विकास विभाग के द्वारा समापन सम्मेलन के दौरान यह आश्वासन दिया गया कि पी.एम.यू. को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ।

कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)

रां.न.नि. तथा ध.न.नि. में गठित पी.आई.यू. में कार्यबल की कमी थी जिससे पी.आई.यू. की कामकाज प्रभावित हुई

नगर निकायों की दक्षता एवं अनूपूरकता बढ़ाने के लिए पी.आई.यू. का गठन एक परिचालन इकाई के रुप में किया जाना था। इसे मात्र पर्यवेक्षण निकाय बने रहने के बजाय मिशन के क्रियान्वयन को सशक्त बनाने के लिए पूर्व से काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद की जा रही थी। पी.आई.यू. का मुख्य उद्देश्य मिशन के क्रिया कलापों की गति तथा तथा उत्कृष्टता को बढ़ाना था। पी.आई.यू. सदस्यों का चयन और नियुक्ति नगर निकायों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना था।

पी.आई.यू. के 13[10] सदस्यों (यू.आई.जी के लिए 8 तथा बीएसयूपी के लिए पाँच) की आवयश्कता के विरुद्ध राँची नगर निगम (रां.न.नि.) के द्वारा समान संख्या में (मई 2009 तथा फरवरी 2010 के बीच) जबकि धनबाद नगर निगम (ध.न.नि.) द्वारा केवल सात पी.आई.यू. सदस्यों को खुली भर्ती प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त (सितम्बर 2009) किया गया। हाँलाकि रां.न.नि. तथा ध.न.नि. में गठित पी.आई.यू. से 4-4 अधिकारियों ने कालांतर (दिसम्बर 2009 तथा मई 2012 के बीच) में इस्तीफा दे दिया और दोनों निकायों में क्रमश: नौ और तीन कर्मचारी ही रह गए। आगे यह देखा गया कि न.वि.वि. द्वारा मांगे जाने पर पी.आई.यू./रां.न.नि. के सूचना तकनीकी पदाधिकारी तथा पी.आई.यू./ध.न.नि. के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वयक, न.वि.वि. में प्रतिनियुक्त (दिसम्बर 2010) थे। इस प्रकार, प्रारम्भ में नियुक्त क्रमश:13 तथा 7 पी.आई.यू. कर्मियों के विरुद्ध रां.न.नि. में केवल आठ तथा ध.न.नि. में दो कर्मी कार्य कर रहे थे। यह स्पष्ट है ध.न.नि. के पी.आई.यू. में स्थिति अधिक गम्भीर थी जहां केवल दो यू.आई.जी. कर्मी ही वास्तविक रूप में कार्य कर रहे थे जबकि बी.एस.यू.पी. संघटक के देखभाल के लिए कोई भी कर्मी नहीं था क्योंकि इस प्रयोजन हेतु भर्ती किया गया व्यक्ति जून 2012 की स्थिति के अनुसार न.वि.वि. में प्रतिनियुक्त था।

---

[10] 12 परियोजना समन्वयक (आवास एवं गरीबस्ती विकास), सामाजिक विकास पदाधिकारी, आजीविका विकास विशेषज्ञ शोध पदाधिकारी, शोध एवं प्रशिक्षण समन्वयक, सूचना तकनीकी पदाधिकारी, नगर वित्त पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंता, सामाजिक विकास पदाधिकारी, नगर योजना पदाधिकारी,प्रोक्योरमेंत पदाधिकारी, पर्यावरन पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास पदाधिकारी

रां.न.नि. के द्वारा पी.आई.यू. कर्मियों को उनके परिभाषित कार्य क्षेत्र के अलावा अन्य कार्य जैसे वाल्मिकी अम्बेदकर मलीन बस्ती आवास योजना (वाम्बे), जनगणना 2011 तथा निर्धनता रेखा सर्वेक्षण से संबंधित कार्यो में भी व्यस्त रखा गया था ।

इस तरह रां.न.नि. की पी.आई.यू. में दिसम्बर 2009 के बाद से कर्मियों की कमी थी जबकि धं.न.नि. में प्रारंभ से ही कर्मियों की कमी थी । इस प्रकार 13 लोगों के द्वारा किये जाने वाला कार्यों को रां.न.नि. तथा ध.न.नि. में क्रमश:आठ और दो कर्मियों द्वारा ही किया जा रहा था जिससे पी.आई.यू. का कुशल संचालन समग्र रुप से प्रभावित था।

सचिव, न.वि.वि. के द्वारा समापनसम्मेलन में यह आश्वासन दिया गया कि पी.आई.यू. को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

2.2.6.2 सुधारों का क्रियान्वयन

शहरी अभिशासन की उन्नति के उद्देश्य को पाने के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के तहत राज्य सरकार तथा स्थानीय नगर निकायों को सुधारों[11] के क्रियान्वयन की एक कार्यसूची को स्वीकार करना था एवं चिन्हित सुधारों के क्रियान्वयन की वचनबद्धता दर्शाते हुए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन[12] (एम.ओ.ए.) हस्ताक्षरित करना था ताकि नीयत अवधि (2005-12) में नगर निकाय वित्तीय रुप से मजबूत हो सकें तथा निर्मित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण सही ढंग से हो सके। अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए.) पाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना एक आवश्यक पूर्व-शर्त थी।

वचनबद्ध 31 सुधारो में से केवल 22 सुधार पूर्ण रूप से लागू किए जा सके थे

सुधारों के क्रियान्वयन के संबंध में एस.एल.एन.ए द्वारा दी गई स्थिति के अवलोकन से पता चला कि भारत सरकार के साथ राज्य/स्थानीय नगर निकायों (स्था.न.नि.) द्वारा हस्ताक्षरित एमओए (दिसम्बर 2007 से जुलाई 2011) में प्रतिबद्ध 31 सुधारो में से केवल 22 सुधार पूर्ण रुप से लागू किए गए जबकि सात सुधार आंशिक रुप से लागू किए गए थे और दो सुधारों का लागू किया जाना अभी बाकी था। ***(परिशिष्ट-2.7)***

---

[11] 21 अनिवार्य सुधार (13 राज्य-स्तरीय तथा आठ नगर निकाय स्तर पर) और 10 नगर निकाय-स्तरीय ऐछिक सुधार-राज्य तथा नगर निकय द्वारा प्रत्येक वर्ष कोई दो सुधार एक साथ किये जाने थे

[12] राज्य सरकार/एसएलएनए तथा भारत सरकार के बीच, यूआईडीएसएसएमटी तथा आईएचएसडीपी परियोजनाओ के मामले में एसएलएनए तथा नगर निकाय के बीच सब्सीडियरी एग्रीमेन्ट होना था

जमशेदपुर, जुगसलाई तथा मानगो नगर निकायों में चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश (जून 2006) के कारण नहीं होने के अलावा राज्य स्तर पर अनिवार्य सभी सुधार लागू कर दिए गए थे जबकि नगर निकाय स्तर पर अनिवार्य सुधार जैसे ई-गर्वनेंस स्थापना, लेखा नियमावली आरेखन, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन शुल्क की लाभुकों/घरो से पूर्ण वसूली आदि सरीखे सुधार अभी भी प्रक्रियाधीन थे। इस प्रकार नियत अवधि अर्थात मार्च 2012 तक राज्य सरकार/स्था.न.नि द्वारा स्वीकृत सुधारों की क्रियान्वयन नहीं की जा सकी थी।

सुधारों का क्रियान्वयन नहीं किए जाने/आंशिक रुप से क्रियान्वित किए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा ए.सी.ए. की दूसरी किश्त के रूप में ₹ 39.39 करोड़ की राशि की विमुक्त प्रभावित हुइ जिसके कारण क्षेत्र के लोग योजना के लाभों से वंचित रहे।

समापनसम्मेलन के दौरान सचिव न.वि.वि द्वारा बताया गया कि बाकी बचे सुधारों को लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।

2.2.6.3 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डी.पी.आर.) का निर्माण

एम.ओ.यु.डी. द्वारा जारी किए गए डी.पी.आर. निर्माण टूलकिट के अनुसार आधारभूत संरचना निर्माण तथा गुणवत्तायुक्त सतत् सेवा प्रदान करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जे.एन.एन.यू.आर.एम. का एक आवश्यक अंग था। परियेाजना की अनुशंसा, स्वीकृति तथा कुशलता पूर्वक एवं ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसे सावधानीपूर्वक तथा पर्याप्त विवरणों के साथ तैयार किया जाना था। अन्य बातों के अलावा, डी.पी.आर. में परियेाजना के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा तथा उसके विरुद्ध उपलब्धता के बारे में जानकारी जरूरी थी तथा आवश्यक भूमि नगर निकाय के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा खरीद ली गई है, इसकी भी पुष्टि जरूरी थी। दूसरे शब्दो में जमीन की मिल्कियत स्पष्ट और भारमुक्त होनी चाहिए थी। झारखण्ड लोक कार्य लेखा (जे.पी.डब्ल्यू.ए.) संहिता के अनुसार भी कार्य के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के बाद ही निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ होनी चाहिए।

12 चयनित परियोजनाओं[13] के डी.पी.आर में हमने पाया की बिना स्पष्ट और भारमुक्त भूमि की उपलब्धता के परियोजनाएं ले ली गईं थीं या निविदाओं[14] का निष्पादन किया गया था जिसके कारण परियोजनाओं[15] के **कार्यान्वयन** में विलम्ब हुआ, जिसकी चर्चा कंडिका 2.2.8 के अंतर्गत की गई है।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 आंवटन एवं व्यय

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत झारखण्ड में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में लागू होने वाले निधि-प्रणाली को ***परिशिष्ट-2.8*** में दिखाया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सराकर को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (केन्द्रीय अनुदान) विमुक्त किया गया था। राज्य सरकार द्वारा इस केंद्रीय निधि को अपने तथा नगर-निकायों के अंशदान के साथ एस.एल.एन.ए को आवंटित किया जिसने तत्पश्चात् प्राप्त निधियों को कार्यकारी एजेंसियो को विमुक्त किया।

मिशन के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नगर-निकायों द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त की गई कुल निधियों तथा उसके विरुद्ध मार्च 2012 तक किए गए कुल व्यय को **तालिका-1** में दर्शाया गया है।

तालिका-1: जे.एन.एन.यू.आर.एम से संबंधित परियोजनाओ में आंवटन तथा व्यय को दर्शाती विवरणी

उपसंघटक	स्वीकृत परियोजना लागत	प्राप्तियाँ				व्यय	प्राप्तियों के विरुद्ध कुल उपयोगिता *प्रतिशत*
		केन्द्रांश	राज्यांश	नगर निकाय अंश	कुल		
		(*प्रतिशत* में)					
बी.एस.यू.पी.	504.44	40.26 (30.15)	27.42 (20.53)	65.89 (49.32)	133.57	8.19	6.13
यू.आ.ई.जी.	832.15	132.62 (48.96)	47.33 (21.52)	90.91 (41.33)	270.86	219.97	81.21
आइ.एच.एस.डी.पी.	225.64	56.35 (71.79)	19.86 (25.30)	2.29 (2.92)	78.50	31.94	40.69

[13] राची जलापूर्ति तथा बीएसयूपी (फेज 2), धनबाद जलापूर्ति तथा बीएसयूपी (फेज 2) देवघर जलापूर्ति, हजारीबाग (एसडब्ल्यूएम और आईएचएसडीपी), लोहरदगा (एसडब्ल्यूएम और आईएचएसडीपी), गुमला आईएचएसडीपी, चास (एसडब्ल्यूएम और जलापूर्ति)

[14] राँची और धनबाद जलापूर्ति परियोजनाएं

[15] राँची और धनबाद बीएसयूपी परियोजनाएं, चास एवं हजारीबाग एसडब्ल्यूएम परियोजनाएं

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी	129.65	71.34 (67.13)	30.93 (29.10)	4.00 (3.76%)	106.27	66.41	62.49
योग	**1691.88**	**300.57 (51.02)**	**125.54 (21.31)**	**163.09 (27.68)**	**589.20**	**326.51**	**55.42**

स्रोत- आँकडे रोकड़ पुस्तिकाओं तथा एस.एल.एन.ए द्वारा उपलब्ध कराये गये । कोष्ठक में अंकित आँकडे प्रतिशत् दर्शाते हैं।

तालिका-1 से यह स्पष्ट होगा कि

(i) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के मामले में कुल प्राप्ति स्वीकृत परियोजना लागत की 81.96 *प्रतिशत्* थी जबकि बी.एस.यू.पी., यू.आई.जी., और आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाओ के मामले में यह क्रमशः 26.48 *प्रतिशत्,* 32.55 *प्रतिशत* और 34.79 *प्रतिशत्* थी।

(ii) कुल ₹ 589.20 करोड़ की उपलब्ध निधि के विरुद्ध मात्र ₹ 326.51 करोड़ (55.41 *प्रतिशत*) की राशि का उपयोग किया जा सका, ₹ 262.69 करोड़ की राशि अप्रयुक्त पड़ी रही।

बी.एस.यू.पी के मामले में स्थिति विशेष रुप से गंभीर थी जिसमें उपलब्ध निधियों का केवल 6.13 *प्रतिशत* का ही उपयोग किया जा सका।

राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति तथा व्यय में कमी का कारण सुधारों के क्रियान्वयन में देरी तथा परियोजनाओं का विलम्ब से प्रारंभ होना बतलाया गया।

2.2.7.2 निधियों का अनियमित उपयोग एवं भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अनियमित सम्प्रेषण

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. दिशानिर्देश के अनुसार केंद्रांश का 50 *प्रतिशत* समझौता ज्ञापन[16] (एम.ओ.ए.) हस्ताक्षरित करने के उपरांत राज्यांश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद एस.एल.एन.ए. को विमुक्त की जानी थी तथा शेष 50 *प्रतिशत* पूर्व में विमुक्त की गई निधियों (राज्य तथा केंद्र अनुदान) के 70 *प्रतिशत* का उपयोगिता प्रमाण पत्र एस.एल.एन.ए. द्वारा प्रेषित किये जाने के बाद विमुक्त किया जाना था। एस.एल.एन.ए को राज्यांश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद केंद्रीय अनुदान का 25 *प्रतिशत* भाग तथा केंद्रांश की शेष निधि को राज्य अनुदान विमुक्त किये जाने तथा सुधारों के क्रियान्वयन की प्रगति सुनिश्चित करते हुए विमुक्त करना था।

[16] राज्य सरकार/एसएलएनए तथा भारत सरकार के बीच

हमने देखा कि अप्रैल 2011 में 4 नगर निकायों की पाँच[17] (तीन एस.डब्ल्यू.एम तथा दो जलापूर्ति) परियोजनाओं[18] के संदर्भ में एस.एल.एन.ए द्वारा पत्र भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण प्रेषित करते हुए ए.सी.ए की दूसरी और अंतिम किश्त विमुक्त करने का अनुरोध किया गया। चुंकि सुधारों का क्रियान्वयन विलंबित था और अंतिम वित्तीय स्थिति प्रमाण पत्र/स्थानीय निकायों के संकल्प/2011-12 में यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के अन्तर्गत राज्य बजट आवंटन की प्रति, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ समर्पित नहीं किये गए थे, इसलिए इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

एस.डब्ल्यू.एम की सारी परियोजनाओं के मामले में ए.सी.ए की दूसरी और अंतिम किश्त विमुक्त करने के अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि केंद्रांश और राज्यांश की कुल उपलब्ध राशि के 70 *प्रतिशत्* से कम राशि का व्यय प्रतिवेदित किया गया था। हालांकि यह पाया गया कि एस.डब्ल्यू.एम लोहरदगा के मामले में कुल व्यय 72 *प्रतिशत्* से अधिक था लेकिन एस.एल.एन.ए नें भारत सरकार को एसीए की दूसरी किश्त के लिए अनुरोध करते समय स्थानीय नगर निकाय अंश की उस राशि को भी विमुक्त दर्शा दिया जो कि उस समय तक (अप्रैल 2011) नगर निकाय को विमुक्त नहीं की गई थी जिसके कारण भारत सरकार द्वारा उपयोगिता का *प्रतिशत्* 70 से कम आंका गया और परिणामस्वरूप ए.सी.ए की दूसरी किश्त विमुक्त नहीं की गई।

मार्च 2012 तक निधियों का उपयोग तथा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने संबंधित विवरण क्रमश:***परिशिष्ट-2.9*** तथा ***2.10*** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार निधियों का अपर्याप्त उपयोग, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक कागजात नहीं प्रेषित किये जाने तथा सुधारों की कार्यसूची का विलंबित क्रियान्वयन के साथ साथ एस.एल.एन.ए द्वारा गलत सूचना समर्पित करने के कारणों से ए.सी.ए की दूसरी किश्त के रूप में ₹ 39.39 करोड़[19] रुपये की विमुक्ति प्रभावित हुई जिसमें से ₹ 31.83 करोड़ रुपये की राशि झारखण्ड

---

[17] चास (जलापूर्ति परियोजना और एस.डब्ल्यू.एम. परियोजनाएं), देवघर (जलापूर्ति परियोजनाएं), हजारीबाग (एस. डब्ल्यू. एम. परियोजनाएं), लोहरदगा (एसडब्ल्यूएम परियोजनाएं)

[18] चास नगर पर्षद, हजारीबाग नगर पर्षद एवं लोहरदगा नगर पर्षद

[19] चास नगर पर्षद: जलापूर्तिपरियोजना (एसीए बाकी ₹ 14.09 करोड), एसडब्ल्यूएम परियोजना (एसीए बाकी ₹ 2.27 करोड़), देवघर नगर पर्षद: जलापूर्ति परियोजना (एसीए बाकी ₹ 18.95 करोड़), हजारीबाग नगर पर्षद: एस.डब्ल्यू.एम. परियेजना (एसीए बाकी ₹ 2.29 करोड़), लोहरदगा नगर पर्षद: एस.डब्ल्यू.एम. परियेजना (एसीए बाकी ₹ 1.79 करोड़)

सरकार द्वारा चास तथा देवधर जलापूर्ति परियोजनाओ के लिए राज्य बजट से जनवरी 2012 में विमुक्त की गई क्योंकि निधि की कमी से परियोजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हो रहा था।

2.2.7.3 जमाओ पर प्राप्त ब्याज की राशि का अनियमित उपयोग

एसएलएनए द्वारा जेएनएनयूआरएम निधियों पर अर्जित ब्याज को प्रशासनिक खर्चे एवं आयकर भुगतान में खर्च किया गया

भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत झारखण्ड सरकार का एक उपक्रम-जी.आर.डी.ए लिमिटेड को अन्य बातों के अलावा जे.एन.एन.आर.यू.एम के तहत केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधियों को स्थानीय नगर निकायों का हस्तान्तरित करने तथा अनिवार्य सुधारो एवं जे.एन.एन.आर.यू.एम परियोजनाओ के प्रभावकारी क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए एस.एल.एन.ए नामित किया गया। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (20) के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की आय आयकर से मुक्त रखी गई है। जे.एन.एन.आर.यू.एम के दिशानिर्देश जे.एन.एन.आर.यू.एम निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि के उपयोग किये जाने के तरीकों पर मौन हैं।

एस.एल.एन.ए को जे.एन.एन.यू.आर.एम के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों को संवितरित की जानी थीं तथा इन निधियों/जमाओं पर अर्जित ब्याज की राशि जी.आर.डी.ए. लिमिटेड की आय नहीं थी फ़िर भी हमारी जांच में पता चला कि मार्च 2012 तक कुल ₹ 8.00 करोड़ ***(परिशिष्ट-2.11)*** इन निधियों/जमा पर ब्याज के रूप में अर्जित किया गया था जिसमें से ₹ 4.02 करोड़ का उपयोग प्रशासनिक व्यय (₹ 85.50 लाख) पर और आय कर (₹ 3.17 करोड़) भुगतान के लिए किया गया, जैसा कि **तालिका-2** में दर्शाया गया है।

तालिका-2 जी.आर.डी.ए लिमिटेड द्वारा किये गये आयकर भुगतान को दर्शाती विवरणी

निर्धारण वर्ष	आयकर भुगतान (₹)					कुल (₹)
	टीडीएस	स्व-निर्धारण	दिनांक	अग्रिम कर	दिनांक	
2010-11	37,71,584	36,94,705	30.10.2010	-	-	74,66,289
2011-12	27,48,000	-	-	1,00,00,000	15.03.2011	1,27,48,000
2012-13	34,84,426	-	-	80,00,000	12.12.2011	1,14,84,426
योग						**3,16,98,715**

स्रोत: एस.एल.एन.ए द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

यह सुस्पष्ट किए जाने पर एस.एल.एन.ए ने जवाब दिया (जुलाई 2012) कि जी.आर.डी.ए लिमिटेड झारखण्ड सरकार की एक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है तथा जमाओं पर प्राप्त ब्याज की राशि

स्वाभाविक रूप से जी.आर.डी.ए लिमिटेड की आय का भाग है अतःउस पर कर भुगतान उसकी जिम्मेवारी है।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जी.आर.डी.ए., न कि एस.एल.एन.ए, अपनी आय पर कर भुगतान के लिए जिम्मेवार थी तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम जमाओं/निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि जी.आर.डी.ए. लिमिटेड की आय नहीं मानी जानी चाहिए थी क्योंकि वह इन निधियों की अभिरक्षक मात्र थी ।

हाँलाकि, नगरविकास विभाग के सचिव ने समापनसम्मेलन के दौरान नवम्बर 2012 में कहा कि आयकर अधिकारियों से, भुगतान की गई आयकर की राशि की वापसी हेतु प्रयास किया जाएगा एवं केंद्र से प्रशासनिक तथा अन्य खर्चो के लिए कर्नाकित चार *प्रतिशत्* आवंटन प्राप्त होते ही जी.आर.डी.ए लिमिटेड द्वारा खर्च की गई प्रशासनिक व्यय की राशि वापस कर दी जाएगी।

2.2.8. परियोजनाओं का कार्यान्वयन

जलापूर्ति परियोजनाएं

नगर विकास विभाग चयनित शहरों में क्रियान्वित की जा रही सभी जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए नगर विकास विभाग, झारखण्ड ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पे.स्व.वि) झारखण्ड को कार्यकारी एजेंसी बनाया । नीचे **तालिका-3** में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को सारांक्षित किया गया है।

तालिका-3 जलापूर्ति परियोजनाओं के संदर्भ में स्थिति दर्शाती विवरणी

(₹ करोड में)

परियोजना का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	सीएसएमसी/ एसएलएससी द्वारा स्वीकृति की तिथि	संविदा जारी करने की तिथि	संविदा मुल्य	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	31.03.12 को भौतिक स्थिति	संवेदक का नाम
राँची जलापूर्ति परियोजना	288.39	13.08.2008	12.03.2010	234.71	12.03.2010	12.09.2012	प्रगति में	मेसर्स आईवीआरसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस लिमिटेड हैदराबाद
धनबाद जलापूर्ति परियोजना	365.85	21.11.2008	30.04.2011	298.00	07.05.2011	29.05.2013	प्रगति में	मेसर्स एल एण्ड टी. लि. चेन्नई
देवघर जलापूर्ति परियोजना	47.38[20]	14.02.2008	14.12.2007	49.56	14.12.2007	13.12.2009	प्रगति में	मेसर्स आईवीआरसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस लिमिटेड हैदराबाद

[20] संशोधित स्वीकृत परियोजना लागत-₹ 48.07 करोड़

चास जलापूर्ति परियोजना	34.24[21]	14.02.2008	22.12.2008	50.02	22.12.2008	21.06.2010	प्रगति में	मेसर्स विश्वा इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज प्रा.लि. हैदराबाद

स्रोत - प्रक्षेत्रों से संग्रहित सूचनाएं

ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि चास तथा देवधर की परियोजनाएं, पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के क्रमशः 21 तथा 27 माह बीत जाने के बाद भी मार्च 2012 तक भी, अपूर्ण थी। डी.डब्ल्यू.एस.डी. प्रक्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए भौतिक प्रगति प्रतिवेदन बताते हैं कि राँची तथा धनबाद में परियोजनाओं की गति धीमी है। परियोजनाओं के विलम्ब तथा अपूर्ण रहने के कारणों पर आगे की कंडिकाओं में विस्तार से चर्चा की गई है ।

2.2.8.1 विलम्बित तथा अपूर्ण परियोजनाएं

- ***राँची जलापूर्ति परियोजना***

केंद्रीय मंजूरी तथा निगरानी समिति[22] द्वारा (अगस्त 2008) परियोजना स्वीकृत की गई थी। प्रारंभ में कार्य राँची नगर निगम द्वारा क्रियान्वित कराया जाना था और तदनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं (नवम्बर 2008) परन्तु नगर विकास विभाग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार (फरवरी 2009) डी.डब्ल्यू.एस.डी. को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया और फिर से अक्तूबर 2009 में डी.डब्ल्यू.एस.डी. द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई, जिसे फरवरी 2010 में अंतिम रुप दिया गया ।

मेसर्स आई.भी.आर.सी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्टस् लि. हैदराबाद को कार्यादेश जारी होने से पूर्व कुसई में जलमीनार (इ.एस.आर.) के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण नहीं हो पाया था। साथ ही, विभिन्न विभागों[23] द्वारा प्रयोग की अनुमति नहीं मिल पाने के कारण रूक्का के जलशोधण संयंत्र से भूमिगत जलाशय-3, कांके के भूमिगत जलाशय-1 से ललगूटवा में भूमिगत जलाशय-2, भूमिगत जलाशय 2 से 6 जलमीनार[24] तक पाईप लाइन संरेखण का कार्य और वितरण संजाल तथा रामपुर में भूमिगत जलाशय-3 का निर्माण प्रारंभ भी नहीं हो पाया था ।

---

21 संशोधित स्वीकृत परियोजना लागत-₹ 50.26 करोड़

22 एमओयूडी तथा एमओएचयूपीए में क्रमश यूआईजी तथा बीएसयूपी परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सीएसएमसी स्थापना की गई थी

23 राष्ट्रीय/राज्य उच्चपथ, रेलवे, रिंग रोड आदि

24 हरमु, कुसई, डिबडीह, पुनदाग, हटिया एवं तुपुदाना

उपर बताएं गए मुददों का समाधान लंबित रहने के कारण समय सीमा-रेखा (सितंबर 2012) पहले ही पार कर चुकी है जो कि नागरिकों को लक्षित लाभ देने में विलम्ब तथा परियोजना की लागत वृद्धि का कारण भी बन सकती है।

- ***धनबाद जलापूर्ति परियोजना***

  सी.एस.एम.सी. द्वारा परियोजना के लिए ₹ 365.85 करोड़ की राशि को मंजूरी (नवम्बर 2008) दी गई। डी.पी.आर. की तकनीकी स्वीकृति के समय केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियंत्रण संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) द्वारा जनसंख्या के आँकड़ों में परिवर्तन की संभावना को देखते हुए योजना का आधार वर्ष 2009 से बदलकर 2011 कर देने की सलाह दी गई थी जिसके चलते परियोजना के अवयवों में तदनुसार ढांचागत परिवर्तन करने पडे। उसी अनुसार परामर्शी[25] को कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया जिसके लिए उसने ₹ 30 लाख की अतिरिक्त राशि की मांग की। काफी पत्राचार तथा पूछताछ के बाद परामर्शी द्वारा अंतिम अद्यतन डीपीआर (नवम्बर 2010) जमा किया गया जिसकी तकनीकी स्वीकृति नवम्बर 2010 में दी जा सकी। कार्य मेंसर्स एल. एंड टी.लि. को आवंटित किया गया (मई 2011) और यह जून 2012 तक प्रगति में था।

16 इ.एस.आर. और सी.डब्ल्यू.आर. इत्यादि का स्थल निर्धारण न होने के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई

हाँलाकि स्थल निर्धारण नहीं हो पाने के कारण 36 में से 16 जलमीनारों (इ.एस.आर.) का कार्य प्रारम्भ भी नहीं हो पाया था (मई 2012)। साथ ही, करकेंद में स्वच्छ जल भंडार (सी.डब्ल्यू.आर-1) तथा कंट्रोलरूम और पम्पहाउस का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका था क्योंकि चयनित स्थल भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) के अधिकार क्षेत्र में पड़े रहे, आगे प्रभावित क्षेत्र में था। बी.सी.सी.एल. इस स्थल क्षेत्र का मलिकाना हक धनबाद नगर निगम को सौंपने के लिए इच्छुक नहीं था। उसी प्रकार, सिंदरी में इएसआर-1 का निर्माण तथा 19.6 किमी की लंबाई में पाईप बिछाने का कार्य भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) द्वारा रोका गया था क्योंकि यहां भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के द्वारा एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का तथा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड द्वारा एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

इस प्रकार परामर्शी द्वारा संशोधित डीपीआर जमा करने में लगे समय अंतराल तथा इ.एस.आर., सी.डब्ल्यू.आर., और पम्प हाउस के लिए स्थल

[25] इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन लि. आईआईडीसी - (आई एल एंड एफ एस), नई दिल्ली

निर्धारण किए बगैर संविदा सौंपने का परिणाम परियोजनाओं की विलम्बित शुरूआत तथा क्रियान्वयन की धीमी गति के रूप में सामने आया।

अंतिम आयोजित बैठक के दौरान (नवम्बर 2012) सचिव न.वि.वि. के सचिव द्वारा बताया गया कि भूमि तथा स्थल संबंधी सारे मुद्दे सुलझा लिए गए थे तथा परियोजना में अच्छी प्रगति है।

- ***देवघर जलापूर्ति योजना***

निधियों की कमी के कारण कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ

योजना पूर्ण होने के लिए निर्धारित तिथि (दिसम्बर 2009) के 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि बीत जाने के बावजूद परियोजना (लागत राशि ₹ 47.38 करोड़) अपूर्ण थी (जून 2012)। हमने पाया कि प्रारंभ में देवधर नगर निगम को ₹ 30.36 करोड़ की राशि (अप्रैल 2008 तक) विमुक्त की गई थी जिसे फरवरी 2010 तक डी.डब्ल्यू.एस. डिवीजन, देवधर को हस्तांतरित कर दिया गया और मार्च 2010 तक सारी राशि खर्च कर ली गई। उसके बाद मार्च 2012 तक कोई निधि प्राप्त नहीं हुई। निधि की प्राप्ति तथा विमुक्ति में विलंब के कारण संविदाकार द्वारा कार्य दो वर्षों तक रोक दिया गया (अप्रैल 2010)। 31 मार्च 2012 को संवेदक को ₹ 3.35 करोड़ की राशि देय थी जो कि जून 2012 में तभी विमुक्त की जा सकी जब मार्च 2012 में ₹ 17.71 करोड़[26] का आवंटन प्राप्त हो गया। इस प्रकार निधियों की मुक्ति में अतिशय विलंब के परिणाम स्वरूप परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

- ***चास जलापूर्ति योजना***

संविदाकार को कार्यादेश जारी होने के समय अभियन्ता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रभाग, चास को दिए गए निर्देशों (दिसंबर 2008) के अनुसार परियोजना (लागत राशि ₹ 34.24 करोड़) का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना था कि सभी बडे अवयवों[27] का निर्माण पहले हो। जाँच से पता चला कि प्रभाग को जून 2010 तक उपलब्ध संपूर्ण आवंटन का ₹ 20.64 करोड़[28] की राशि सिर्फ

---

[26] राज्य सरकार के द्वारा विमुक्त बकाया केन्द्रांश तथा पुनिरीक्षित संशोधित लागत के चलते अंतर की राशि

[27] इनटेक वेल, एनफिलट्रेशन गैलरी, एप्रोच व्रिज, जल शोधन संयंत्र, एलिवेटेड तथा ग्राउण्ड सर्विस रिजर्वायर

[28] केन्द्रांश प्रथम किस्त: ₹ 13.80 करोड़, राज्यांश: ₹ 3.42 करोड़, निकाय अंश: रु .3.42 करोड़

पाइपों की खरीद में लगा दी गई। परियोजना के अन्य अवयवों के क्रियान्वयन के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं थी क्योंकि सुधारों के लागू नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा एसीए की दूसरी तथा अंतिम किश्त की ₹ 13.60 करोड़ की राशि विमुक्त नहीं की गई थी। संविदाकार को भुगतान किए जाने के लिए ₹ 6.40 करोड़ की राशि बकाया थी जो कि तभी विमुक्त की जा सकी जब राज्य सरकार से ₹ 29.62 करोड़ की राशि प्राप्त हो गई (मार्च 2012)। गैर-अनुपातिक रूप से तथा अविवेकपूर्ण तरीके से केवल एक ही अवयव पर खर्च करने के कारण तथा निधियों की विमुक्ति में विलंब के कारण परियोजना अपने पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के दो वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रही।

2.2.8.2 राँची जलापूर्ति परियोजना के डीपीआर में गलत प्रावधान के कारण परियोजना लागत में ₹ 60.33 करोड़ की अनुमानित वृद्धि

राँची जलापूर्ति परियोजना पर विचार करते समय केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनियंत्रण संगठन द्वारा अगस्त 2008 में की गई टिप्पणियों के अनुसार परियोजना की क्रियान्वयन अवधि के बीच में कोई लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी और यदि कोई लागत वृद्धि स्वीकार भी की जाती तो इसे झारखण्ड सरकार/रां.न.नि. द्वारा पूरा किया जाना था।

नैनो सिस्टम कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लि. द्वारा राँची जलापूर्ति परियोजना का तैयार किया गया डीपीआर तकनीकी रूप से ₹ 288.39 करोड़ के लिए प्रमुख अभियता, तकनीकी कोषांग न.वि.वि. द्वारा स्वीकार किया गया तथा सीएसएमसी द्वारा मंजूर (अगस्त 2008) किया गया। कार्यकारी एजेंसी होने के नाते रां.न.नि. ने निविदाएं आमंत्रित (नवम्बर 2008) कीं तथा एनआईटी के प्रकाशन पर ₹ 18.01 लाख खर्च किए। हाँलाकि न.वि.वि. ने रां.न.नि. के बदले डी.डब्ल्यू.एस.डी. को (फरवरी 2009) कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी बनाया। इससे रां.न.नि. द्वारा एनआईटी प्रकाशन पर किया गया ₹ 18.01 लाख का खर्च बेकार साबित हो गया। संचिका पर कार्यकारी एजेंसी में परिवर्तन का कोई कारण उपलब्ध नहीं था। अभियंता प्रमुख, डी.डब्ल्यू.एस.डी द्वारा उसी राशि के लिए तकनीकी मंजूरी (मई 2009 में) दी गई जिसके लिए मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, न.वि.वि. द्वारा तकनीकी स्वीक्रति दी गई थी। मेंसर्स आई.भी.आर.सी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्रोजेक्ट्स लि., हैदराबाद को ₹ 234.71 करोड़ के लिए संविदा (मार्च 2010) सौपी गई।

योजना के क्रियान्वयन के दौरान अभियंता प्रमुख, डी.डब्ल्यू.एस.डी. द्वारा रां.न.नि./न.वि.वि. को सूचना दी गई (अगस्त 2010) कि संवेदक द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण के बाद सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार डीपीआर में निम्नलिखित त्रुटियां थी:-

- तीन में से किसी भी यूजीआर के लिए पम्पहाउस तथा चहारदीवारी तथा आठ जलमीनारों में चहारदीवारी का प्रावधान नहीं था।
- जलशोधन संयंत्र से यूजीआर-1 तथा यूजीआर 3 की राइजिंग मेन पाइपों की लंबाई तथा डिस्ट्रब्यूशन मेन पाइपों की लंबाई गलत आंकी[29] गई थी।
- इनटेक वेल का स्थान उपयुक्त नहीं था।
- वर्तमान फीडर से प्रस्तावित तीनों यूजीआर केन्द्रों तक उच्च प्रवाही संयोजन का कोई प्रावधान नहीं था।
- यह स्पष्ट नहीं था कि कुसई कॉलोनी की जलमीनार को किस यूजीआर से जल की आपूर्ति की जाएगी।
- रेलवे क्रासिंग, एनएच क्रासिंग तथा नदी क्रासिंग के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए थे।
- जलमीनारों तथा यूजीआर के लिए प्रस्तावित भूमि क्षेत्र की भौतिक स्थिति के अनुरुप नहीं थी।

डी.पी.आर में गलती के कारण लागत में ₹ 60.33 करोड़ की वृद्धि आंकी गई है

यह न.वि.वि. तथा डी.डब्ल्यू.एस.डी. की तकनीकी तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी थी कि वे कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व, परियोजना क्रियान्वयन से सम्बंधित प्रत्येक व्यावहारिक पहलू की गहराई से पड़ताल करते जो कि सही से नहीं निभाई गई तथा कार्य के स्कोप के परीक्षण के बिना तथा आने वाली सही लागत का निर्धारण किए बिना ही कार्य का आवंटन कर प्रारम्भ कर दिया गया।

डी.पी.आर. की कमियों के कारण ₹ 60.33 करोड़ का लागत विचलन डी.डब्ल्यू.एस.डी. द्वारा अपेक्षित/निर्धारित किया गया (फरवरी 2011)। यदि न.वि.वि के तकनीकी कोषांग द्वारा या फिर डी.डब्ल्यू.एस.डी. द्वारा तकनीकी मंजूरी देने तथा निविदा आमंत्रण से पूर्व प्राक्कलन की सत्यता परखी गई होती तो कमियों को समय पर दूर किया जा सकता था तथा स्वीकृत परियोजना

[29] जल शोधन संयंत्र से यूजीआर-1 के राइजिंग मेन का लबाई 13.1 किमी से बदकर 23.5 किमी हो गई तथा जल शोधन संयंत्र से यूजीआर-3 के राइजिंग मेन का लबाई 23.81 किमी से बदकर 34.20 किमी हो गई

लागत के उपर लागत वृद्धि के भार को राज्य सरकार को वहन नहीं करना पड़ता।

न.वि.वि. के द्वारा कार्य के क्रियान्वयन को रा.न.नि. के बदले डी.डब्ल्यू.एस.डी. द्वारा कराए जाने के निर्णय में देरी के कारण परियोजना क्रियान्वयन में देरी के अलावा रा.न.नि. द्वारा एन.आई.टी. प्रकाशन में किया गया ₹ 18.01 लाख का खर्च भी निष्फल हो गया।

समापन सम्मेलन के दौरान सचिव, न.वि.वि. द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया। यह कहा गया कि उन लोगों की जिम्मेवारी तय की जाएगी जो तकनीकी स्वीकृति तथा मंजूरी के समय सारे पहलुओं को देखने में असफल रहे।

2.2.8.3 मोबिलाइजेशन एडवांस का कम समायोजन

मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार ब्याज रहित मोबिलाईजेशन एडवांस की वसूली उस विपत्र भुगतान के अगले विपत्र से प्रारम्भ की जानी थी जिसके द्वारा संवेदकों को किए गए कुल भुगतान की राशि संविदा मूल्य का 20 *प्रतिशत्* हो जाए अथवा एडवांस के प्रथम किस्त के भुगतान की तिथि के बाद छः माह की अवधि बीत जाए इनमें से जो भी अवधि पहले खत्म हो जाए तथा वसूली किए जाने वाले प्रत्येक अंतरिम भुगतानों से 20 *प्रतिशत्* की दर से एडवांस की पूरी वसूली हो जाने तक की जानी थी बशर्ते कि अग्रिम का पूरी तरह से समायोजन, योजना की अवधि पूरी हो जाने के मौलिक/तय तिथि तक, हर हाल में हो जाए।

राँची और धनबाद के डी.डब्ल्यू.एस.डी. के कागजातों की पड़ताल से पता चला कि ₹ 53.27 करोड़ की ब्याजमुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस का भुगतान[30], जो कि कुल एग्रीमेंट राशि[31] का 10 *प्रतिशत्* थी, संवेदकों को अप्रैल 2010 से जून 2011 के बीच बिना शर्त एग्रीमेंट राशि के 10 *प्रतिशत्* के बराबर राशि की जमा की गई बैंक गारंटी के विरूद्ध, किया गया।

₹ 53.27 करोड़[32] की मोविलाईजेशन एडवांस में से केवल ₹ 15.85 करोड़ की वसूली मार्च 2012 तक हो पाई ***(परिशिष्ट 2.12)***। आगे पड़ताल से पता चला

---

[30] राँची जलापूर्ति परियोजना-आईभीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एडं प्रोजेक्ट्स लि हैदराबाद, धनबाद जलापूर्ति परियोजना-एलएडंटी लि.चेन्नई

[31] राँची: ₹ 234.71 करोड़, धनबाद: ₹.298 करोड़

[32] राँची अप्रैल 2010 से फरवरी 2011 के बीच ₹.23.47 करोड़ और धनबाद जुन 2011 मे ₹ 29.80 करोड़

₹ 13.09 करोड़ के मोबिलाईजेशन एडवांस का कम समायोजन हुआ

कि संवेदकों को कुल ₹ 144.70 करोड़ (राँची ₹ 79.93 करोड़ तथा धनबाद ₹ 64.77 करोड़) का भुगतान किया गया जबकि प्रावधान के अनुसार ₹ 28.94 करोड़ (₹ 144.70 करोड़ का 20 *प्रतिशत*) की राशि वसूल की जानी चाहिए थी अर्थात् ₹ 13.09 करोड़ की कम वसूली की गई।

समापन सम्मेलन के दौरान डी.डब्ल्यू.एस.डी. द्वारा कहा गया कि मोबिलाईजेशन एडवांस की त्वरित वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

2.2.8.4 डीआई पाईपों की अतिशय खरीद पर अनाधिकृत भुगतान

राजस्व विभाग वित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 दिसम्बर 2009 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 26/2009/केन्द्रीय उत्पाद के अनुसार सभी व्यास के तथा सभी प्रकार के राईजिंग तथा डिस्ट्रिब्युशन के डीआई पाईपों को केन्द्रीय उत्पाद कर से मुक्त कर दिया गया था। आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति किए जाने वाले पाईपों पर उत्पाद कर की छूट पाने के लिए संबंधित उपायुक्त (डीसी) से उत्पाद कर-छूट का प्रमाण पत्र जारी करवाना था।

नीचे **तालिका-4** में राँची जलापूर्ति परियोजना के लिए हेडवर्क्स डिवीजन, राँची को परिमाण विपत्रों के अनुसार आवश्यक पाईपों की मात्रा, वह परिमाण जिस पर उत्पाद कर-छूट प्रमाण पत्र उपायुक्त द्वारा निर्गत किया गया तथा 31 मार्च 2012 तक आपूर्तित पाईपों जिसके लिए भुगतान किया गया का परिमाण दिखाया गया है ।

तालिका-4: 900 मिमी व्यास के पाईपों की आवष्यकता तथा खरीद को दिखाता प्राक्कथन

(परिमाण मीटर में)

पाईप का व्यास	परिमाण विपत्र के अनुसार आवश्यक मात्रा	वह मात्रा जिस पर उपायुक्त द्वारा उत्पाद कर छूट के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया	वह मात्रा जिसके लिए 31.3.12 तक आपूर्ति/भुगतान किया गया
900 मिमी	100	7550	7050

स्रोत: डिवीजन से संग्रहित सूचनाएं

डी.आई पाईपों की अतिशय खरीद के कारण ₹ 8.21 करोड़ का अतिरिक्त/अनाधिकृत भुगतान हुआ

परिमाण विपत्र (बीओक्यू) के अनुसार मात्र 100 मी. 900 मिमी व्यास के पाईप की जरुरत थी लेकिन 7,550 मी. लंबाई के लिए उत्पाद कर छूट प्रमाण पत्र जारी किए गए जिसके विरुद्ध) 7,050 मी डीआई पाईपों की आपूर्ति की गई। परिमाण विपत्र में बताई गई आवश्यकता से अधिक 900 मिमी व्यास के पाईपों की खरीद के कारण ₹ 8.21 करोड की अतिरिक्त/अनाधिकृत राशि का भुगतान किया गया जैसा कि **तालिका-5** में दिया गया है।

तालिका-5:डीआई पाईपों के लिए अतिरेक भुगतान को दर्शाता प्राक्कथन

पाईपों का व्यास	31.3.12 तक लेखांमित पाइप की लंबाई	किया गया भुगतान (₹)			परिमाण विपत्र के अनुसार आवश्यक मात्रा	प्रिमाण विपत्रक अनुसार आवश्यक पाईपों का मूल्य	स्वीकार्य भुगतान (₹) (75% आपूर्ति के लिए + 15% बिछार्ने के लिए)	अतिरिक्त/अनधिकृत भुगतान (₹) (6-9)
		पाईपों की आपूर्ति के लिए (आपूर्ति किए गए पाईपों के मूल्य के 75 *प्रतिशत्* की दर से)	पाईपों को बिछार्ने के लिए (बिछाए गए पाईपों के मूल्य के 15 *प्रतिशत्* की दर से)	पाइप आपूर्ति तथा बिछाने के कार्य के लिए किया गया कुल भुगतान (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900 मिमी	7,050 मी.	9,76,91,850 का 75 *प्रतिशत्*=7,32,68,888	4856 मी के मूल्य का 15 *प्रतिशत*=1,00,93,439	8,33,62,327	100 मी	13,85,700 (₹ 13,857 प्रति मी)	13,85,700 का 90 *प्रतिशत्*=12,47,130	8,21,15,197

स्त्रोतः डिविजन से प्राप्त सूचनाएं

समापन सम्मेलन के दौरान डी.डब्ल्यू.एस.डी. द्वारा कहा गया कि चूंकि संवेदक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आवश्यक राइजिंग मेंन्स पाईपों की लंबाई डी.पी.आर. में आंकी गई लंबाई से अधिक थी अतः प्रारुप में परिवर्तन करना पड़ा जिसके चलते अतिरिक्त पाईपों की खरीद करनी पड़ी। सचिव, न.वि.वि. ने स्वीकारा कि परियोजना के प्रारुप (डिजाइन)/स्कोप में परिवर्तन पर सी.पी.एच.ई.ई.ओ. की पूर्व स्वीकृति के बिना भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था।

2.2.8.5 उत्खनित पत्थरों की नीलामी नहीं किए जाने के कारण ₹ 43.51 लाख की क्षति

देवघर जलापूर्ति परियोजना की माप पुस्तिका की पड़ताल में देखा गया कि नन्दन पहाड़ की योजना के क्रियान्वयन के दौरान 82,878.75 घनमीटर[33] कठोर पत्थर उत्खनित किए गए। हाँलाकि उक्त मात्रा मेटेरियल एट साइट खाते में नहीं लिया गया और न ही उत्खनित कठोर पत्थरों के प्रयोग को दर्शाता कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध था। आगे यह भी देखा गया कि उत्खनित कठोर पत्थरों की उक्त मात्रा में से जिला खनन पदाधिकारी, (डीएमओ) देवधर द्वारा केवल 1,417.23 घनमीटर की नीलामी ₹ 75,700 की राशि के लिए की गई। हाँलाकि अंतिम मापन (सितम्बर 2010) के बाद शेष बची 81,461.52 घनमीटर की मात्रा की नीलामी डीएमओ देवघर द्वारा नहीं किया गया। समापन सम्मेलन के दौरान (नवम्बर 2012) राज्य सरकार ने

[33] ब्लास्टिंग तथा ढुलाई के लिए 10 *प्रतिशत्* की क्षति को लेखांकित करने के बाद

कहा कि उत्खनित पत्थरों की स्टैकिंग नहीं किए जाने के कारण पत्थरों का मापन नहीं लिया गया तथा नीलामी की व्यवस्था भी नहीं की जा सकी। स्टैकिंग का कार्य प्रगति पर है और इसके बाद नीलामी की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह, कम से कम ₹ 43.51 लाख[34] के पत्थरों की क्षति अथवा चोरी से इंकार नहीं किया जा सकता।

2.2.8.6 समझौते का उल्लंघन करते हुए डीआई पाईपों के लिए अतिरेक भुगतान

निविदाधारियों को जारी की गई टिप्पणियाँ, जो कि संवेदक के साथ किए गए समझौते का एक भाग होती हैं, के उपबंध 2.32 के अनुसार संयंत्रों, उपष्करों, एशेसरीज, स्पेशल्स[35], वाल्व्स तथा पाईपों की आपूर्ति के लिए 80 *प्रतिशत्* का भुगतान प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित किए जाने और अच्छी स्थिति में साइट पर माल की प्राप्ति के बाद तथा शेष राशि संतोषजनक संस्थापन तथा चालू करने के बाद किया जाना था।

डी.डब्ल्यू.एस. डिवीजन, चास के मापन पुस्तिकाओं/चालू खाता विपत्रों/परिमाण विपत्रों की पड़ताल से पता चला कि परिमाण विपत्र में विभिन्न व्यास के कुल 92,227 मीटर पाईपों के उपबंध के विरुद्ध ₹ 24.17 करोड़ मूल्य के 91,958 मीटर पाईप की आपूर्ति की गई जिसके विरुद्ध 93 *प्रतिशत्* की दर से कुल ₹ 22.48 करोड़, का भुगतान किया गया जब कि निविदा दस्तावेजों के अनुसार केवल ₹ 19.34 करोड़ (80 *प्रतिशत्*) का ही भुगतान किया जाना चाहिए था। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संवेदक को भेजे गए (दिसम्बर 2008) स्वीकृति पत्र (लेटर आफ एक्सेप्टेन्स) के उपबंध 10 में यह प्रावधान किया गया था कि प्रभारी अभियन्ता द्वारा उचित रुप से प्रमाणित किए जाने तथा माल की अच्छी स्थिति में प्राप्ति के बाद डीआई पाईपों के मूल्य का 93 *प्रतिशत्* भुगतान किया जाएगा।

एकरारनामा में वर्णित प्रावधानों से अलग एलओए जारी करने के कारण संवेदक को ₹ 3.14 करोड की राशि का अनुचित लाभ

डिवीजन ने जवाब दिया (जुलाई 2012) कि 500 मिमी व्यास के कुल 2,450 मीटर के 9 पाईपों के विरूद्ध केवल 2,447.50 मीटर पाईप ही आपूर्ति किया गया तथा 93 *प्रतिशत्* का भुगतान किया गया। उसने संवेदक को किसी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान से इंकार किया। जबाव निविदा कागजातों में किए गए उपबंधों के अनुरुप नहीं है क्योंकि स्वीकृति पत्र (एलओए) में जोडी गई शर्त

---

[34] 75,700/1,417.23 = 53.41, 81461.52* 53.41 = 43.51 लाख

[35] पाईप फिटिग एसेसरीज

समझौते के विरूद्ध थी तथा इससे संवेदक को ₹ 3.14 करोड़[36] के बराबर का लाभ अनुचित रुप से पहुँचाया गया।

हाँलाकि राज्य सरकार ने समापन सम्मेलन के दौरान अंकेक्षण प्रेक्षण को स्वीकार किया।

बी.एस.यू.पी/आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाएं

बी.एस.यू.पी. दिशानिर्देशों की कंडिका संख्या 4.1 के अनुसार बी.एस.यू.पी. का मिशन उद्देश्य मिशन के अन्तर्गत आ रहे शहरों में शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सुविधाओं के एकीकृत विकास पर केन्द्रीभूत घ्यान देना, (वहनीय मूल्यों पर अवधि की सुरक्षा, बेहतर आवास, जलापूर्ति तथा स्वच्छता आदि) है। आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों की कंडिका 2, चिन्हित शहरों की गंदी बस्तियों के वासियों को पर्याप्त आश्रय तथा मूल आधारभूत सुविधाओं के द्वारा एक स्वस्थ तथा योग्य नगरीय वातावरण के साथ गंदी बस्तियों के पवित्र विकास की बात करती है। केन्द्रीय मंजूरी तथा निगरानी समिति (सी.एस.एम.सी) की 26$^{वीं}$ बैठक के अनुसार लक्ष्य निर्धनों में से उन निर्धनों को आवास उपलब्घ करना था जो अपना आवास खुद से नहीं बना सकते थे। अंतिम उद्देश्य सबसे पहले उन जरुरतमंद लोगों को घेरे में लेना था जिन्हें आश्रय की आवश्यकता थी ताकि मिशन का अधिकाधिक लाभ गरीब पा सकें। सही लाभुकों की पहचान करने को सबसे ज्यादा महत्व देना था।

तलिका-6 में बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी. की विस्तृत पड़ताल के लिए चयनित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-6: बीएसयूपी/आईएचएसडीपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का विवरण दिखाता प्राक्कथन

क्रम संख्या	नगर निकाय का नाम	डी.पी.आर के अनुसार पूर्ण होने की निर्घारित तिथि	परियोजना प्रारम्भ[37] होने की तिथि	निर्माण की जाने वाली आवासीय इकाईयों की संख्या	मार्च 2012 तक स्थिति		
					लाभुकों की वह संख्या जिन्हें किष्तें मुक्त की गई	निर्मित आवासीय इकाईयों की संख्या	आधारभूत सुविधावों को विकास
1	रांची	15 माह बाद	17.3.08	2358	276[38]	शून्य	प्रारंम्भ नहीं हुआ था
2	धनबाद	15 माह बाद	17.3.08	1090	31	शून्य	प्रारंम्भ नहीं हुआ था
3	हजारीबाग	15 माह बाद	06.3.09	1230	738[39]	शून्य	प्रारंम्भ नहीं हुआ था

[36] ₹ 22.46 करोड-₹.19.32 करोड=₹ 3 14 करोड

[37] एसीए कि प्रथम किश्त मुक्त करने कि तिथि

[38] 1259 अंतिम रुप से चयनित लोगो में से

[39] 1096 अंतिम रुप से चयनित लोगो में से

4	लोहरदगा	18 माह बाद	06.3.09	1623	1014	48	प्रगति में
5	गुमला	18 माह बाद	05.3.08	1292	शून्य	शून्य (लाभूकों की सूची तय नहीं हो पाई थी)	प्रगति में

स्त्रोतः नगर निकायों से संग्रहीत सुचनाएं

2.2.8.7 बीएसयूपी (चरण-II) परियोजनाओं[40] के क्रियान्वयन में विलम्ब

डी.पी.आर. में बस्तियों में स्थित सरकारी/नगरीय/निजी भूमि पर जी+1/जी+2 ढाँच में आवासीय इकाईयों (आवासीय इकाईयों) के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। शुरुआत में बस्तियों में आवासीय इकाईयों का निर्माण तथा आधारभूत ढाँचा विकास का कार्य खुली प्रतियोगी निविदा पद्धति द्वारा किया जाना था। हाँलाकि इस कार्य के लिए आमंत्रित की गई निविदा[41] निस्तारित नहीं की जा सकी क्योंकि बस्तियों में निजी भूमि पर रह रहे लाभुक अपनी निजी भूमि पर इस प्रकार के आवासीय इकाईयों के निर्माण को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए न.वि.वि (फरवरी 2011) द्वारा बस्तियों में निजी भूमियों पर सी.एस.एम.सी. की 85वीं बैठक के निर्देश के आलोक में, डी.पी.आर में चयनित लाभुकों की जाँच के बाद खुद लाभुकों द्वारा उनके लिए एकतलीय आवासों का निर्माण करवाने का निर्देश दिया गया। नगर अधिकारियों द्वारा जाँच के दौरान परामर्शी द्वारा चिन्हित लाभुकों में कई भूमिहीन/किराएदार/मृतक/गुमनाम लोगों के नाम सामने आए जिन्हें जाँच के बाद हटा दिया गया था। राँची बीएसयूपी परियोजना के डी.पी.आर. के अनुसार चरण 2 के लिए चिन्हित तथा 2,358 प्रस्तावित लाभुकों में से केवल 1,259 लक्षित लाभुक ही जाँच के बाद अतिम रुप से मार्च 2012 तक चयनित हो पाए और ₹ 132.37 लाख की निधि 276 लाभुकों को चार किश्तों में (मार्च 2012 तक) विमुक्त की जा सकी। धनबाद बीएसयूपी परियोजना चरण 2 के डी.पी.आर के अनुसार चिन्हित 1,090 लाभुकों में से 31 लाभुकों को कुल ₹ 30.14 लाख की राशि दो किश्तों में मुक्त की गई, अन्य लाभुकों की भूमि जाँच का कार्य प्रगति पर था (जून 2012)।

यद्यपि परियोजना 15 माह में पूरी की जानी थी फिर भी अपनी भूमि पर आवासीय इकाईयों का जी+1/जी+2 ढांचे में निर्माण तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होने देने में लाभुकों की अनिच्छुक की वजह से निविदा निस्तारण नहीं हो पाने (रा.न.नि. के मामले में) से फाइनल की गई निविदाओं को रद्द करने में नष्ट हुए समय (फरवरी 2009 से दिसम्बर 2009) तथा लाभुकों की सूची की

[40] रांची और धनबाद

[41] रांची-जुलाई और अक्तूबर 2010, धनबाद-अक्तूबर 2009

जाँच में लगे समय के कारण एक भी इकाई का निर्माण नहीं हो सका था, और इंन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास भी नहीं हो सका था। डी.पी.आर. बनाते समय ही प्रस्तावित निर्माण के तरीके पर यदि लाभुकों की इच्छा जान ली गई होती तो समय की कुछ बचत होती।

अतः डी.पी.आर. में आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए प्रस्तावित तरीका जिस पर बाद में प्रस्तावित लाभुक सहमत नहीं हुए राँची और धनबाद में बी.एस.यू.पी. परियोजना के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब का मुख्य कारण था।

समापन सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार ने इस सच्चाई को, कि आवासीय इकाईयो के निर्माण के प्रस्तावित तरीके पर शुरुआत में लाभुकों की सहमति नहीं ली गई थी जिसके कारण निविदाएं निस्तारित नहीं की जा सकीं फलस्वरुप परियोजना के प्रारम्भ/क्रियान्वयन में देर हुई, स्वीकार किया।

2.2.8.8 आईएचएसडीपी परियोजनाओं[42] के क्रियान्वयन में देर

- ***प्रस्तावित लाभुकों का गलत चयन***

तीन नगर निकायों[43] के डी.पी.आर. के अनुसार प्रस्तावित लाभुकों का चयन राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड तथा बस्तियों के प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था। लाभुक सूची की तैयारी में विधवाओं, अकेली महिलाओं तथा वृद्ध व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाना था। हाँलाकि न.वि.वि. द्वारा निर्धारित (अक्टूबर 2009) समिति[44] द्वारा डी.पी.आर. में मौजूद सूचियों की जाँच के बाद बनाई गई सूची की पड़ताल से पता चला कि डी.पी.आर में सही सूचनाओं की कमी थी क्योंकि उसमें मृतकों/गुमनाम व्यक्तियों/भूमिहीनों तथा संदेहास्पद लाभुकों के अलावा पक्के पकानों में रह रहे लाभुक, सरकारी नौकरी वाले अयोग्य लाभुक तथा वाम्बे योजना में आवंटित मकान पा चुके अन्य लाभुक आदि भी शामिल थे, जैसा कि **तालिका-7** में दर्शाया गया है।

---

42 हजारीबाग, लोहरदगा और गुमला

43 गुमला, लोहरदगा और हजारीबाग

44 समिति का सन्योजन-सम्बन्धित वार्ड के वार्ड पार्षद, पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अधिकृत एक पदाधिकारी/कर्मी तथा उपायुक्त द्वारा अधिकृत एक पदाधिकारी

तालिका-7 लाभुकों के गलत चयन के विवरणों को दर्शाती विवरणी

नगर निकाय का नाम	डी.पी.आर में शामिल लाभुकों की संख्या	पक्का मकान/एस्बेस्टस छत के नीचे रह रहे लाभुकों की संख्या	नामों में दोहरी करण के मामलों की संख्या	मृतक लाभुकों की संख्या	बाहरी किराएदारों की संख्या	भूमिहीन/अपर्याप्त भूमि वाले लाभुक/जनजातीय भूमि में रह रहे/लापता/खुद अपना परिवार में शामिल सरकारी नौकर वाले मामलों की संख्या	वाम्बे में आवास पा चुके लाभुकों की संख्या	संदेहास्पद
लोहरदगा	1623	38	52	12	16	169	3	3
हजारीबाग	1230	37	-	12	-	68	11	44
गुमला	1282	-	-	-	-	666	-	-
योग		**75**	**52**	**24**	**16**	**903**	**14**	**47**

स्रोत: नगर निकायों द्वारा प्राप्त सूचियाँ

राज्य सरकार ने समापन सम्मेलन के दौरान कहा कि शुरुआत में आवासीय इकाईयों का निर्माण निविदा द्वारा कराया जाना था परन्तु केरल तथा तमिलनाडु में अपनाए गए तरीकों के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि आवासीय इकाईयों का निर्माण खुद लाभुकों द्वारा ही करवाया जाय। इसलिए परामर्शी द्वारा शुरुआत में बनाई गई लाभुक-सूचियों की न.वि.वि. द्वारा गठित की गई समितियों से जाँच कराई गई जिसमें पाया गया था कि कुछ अयोग्य लाभुक भी योजना में शामिल कर लिए गए थे। उन लाभुकों के नाम लाभुकों की अंतिम सूची से हटा दिए गए थे।

इस प्रकार नगर निकायों द्वारा लाभुकों के गलत चिन्हीकरण के कारण परियोजनाओं का क्रियान्वयन लम्बित रहा।

- ***आवासीय इकाईयों के निर्माण में विलंब***

  आइ.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के मामले में शुरुआत में बस्तियों में आवासीय इकाईयों का निर्माण तथा आधारभूत संरचना का विकास खुली प्रतियोगिता के आधार पर बोली के द्वारा कराया जाना था। उसी अनुसार गुमला नगर पंचायत, द्वारा तीन बार[45] निविदाएं निकाली गई लेकिन जहां आधारभूत संरचना विकास की निविदाएं निस्तारित कर दी गई अक्टूबर 2008 तथा जनवरी 2009 वहीं आवासीय इकाईयों के निर्माण की निविदा ₹ 1.49 लाख प्रति आवासीय इकाईयों[46] के संशोधित प्राक्कलन पर न.वि.वि. द्वारा स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण निष्पादित नहीं की जा

[45] डीयू के निर्माण के लिए जुलाई 2008 में, आधारभूत ढाँचागत विकास के लिये अक्तूबर 2008 में, डीयू के निर्माण तथा आधारभूत ढांचागत विकास के लिये नवम्बर 2008 में

[46] सीएससी द्वारा स्वीकृति डीपीआर मे अन्य बातो के अलावा प्रति डीयू ₹ 80,000/-कि दर से 1,292 डीयू का प्रावधान था

सकीं। उसी बीच न.वि.वि. ने (सितम्बर/अक्टूबर 2009) आईएचएसडीपी परियोजनाओं के मामले में डी.पी.आर. में बनाई गई लाभुकों की सूची इस हेतु प्रस्तावित समिति[47] द्वारा सत्यापन/जाँच के बाद खुद लाभुकों द्वारा ही एकतलीय आवासीय इकाईयों के निर्माण करवाने का निर्देश दिया। हजारीबाग में लाभुकों को किश्तें/अक्टूबर 2009 से जाँच के पूर्व ही मुक्त की जाने लगी जबकि लोहरदगा में उक्त समिति द्वारा उचित जाँच[48] के बाद जनवरी 2011 से लाभुकों को किश्तें मुक्त की गई। मार्च 2012 तक हजारीबाग में लाभुकों को ₹ 8.13 करोड़ मुक्त किए गए जिसमें कि 544 लाभुकों को तीन किश्तें[49] जारी की गई। हाँलाकि एक भी आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। जबकि लोहरदगा में 1,014 लाभुकों को 4 किश्तों तक विवि, राँची द्वारा निर्धारित 3 किश्तों के विरुद्ध ₹ 9.17 करोड़ मुक्त करके 48 इकाईयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था।

हजारीबाग तथा लोहरदगा में आवासीय इकाईयों का निर्माण, लाभुकों की जाँच तथा लाभुकों द्वारा कार्य के धीमे कार्यान्वयन के कारण लगे समय के कारण, 2 वर्ष की देर से प्रारंभ हो पाया। लोहरदगा नगर पर्षद के मामले में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निधियों की कमी भी एक कारण थी क्योंकि वहां सम्पूर्ण आवंटन की उपलब्ध राशि मार्च 2012 तक खत्म हो चुकी थी गुमला में आवासीय इकाईयों का निर्माण शुरु भी नहीं हो सका था क्योंकि नगर न.वि.वि. ₹ 1.49 लाख प्रति आवासीय इकाईयों का संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हो पाने के कारण निविदाएं निस्तारित नहीं की जा सकी थी तथा लाभुकों की सूची भी मार्च 2012 तक स्वीकृत/फाइनलाइज नहीं हो पायी थी ।

समापन सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार ने अंकेक्षण प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा कि गुमला के लि आवासीय इकाईयों की आंकलित लागत जल्द ही पूर्ण कर ली जाएगी।

---

47 समिति का सन्योजन-सम्बन्धित वार्ड के वार्ड पार्षद, पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अधिक्रित एक पदाधिकारी/कर्मी तथा उपायुक्त द्वारा अधिक्रित एक पदाधिकारी

48 हजारीबाग-मई 2010 और अगस्त 2010, लोहरदगा-फरवरी 2010

49 एग्रीमेंट साईन होने पर-25 *प्रतिशत्*, बुनियादी स्तर तक काम हो जाने पर-40 *प्रतिशत्*, छत तक का काम हो जाने पर-35 *प्रतिशत्* (प्रथम किश्त-737 लाभुको को ₹ 2.72 करोड़, व्दितीय किश्त-587 लाभुको को ₹ 2.89 करोड़ तथा त्रितीय किश्त - 544 लाभुको को ₹ 2.52 करोड़)

- ***आधारभूत संरचना कार्य में विलम्ब***

  आइ.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशो की कंडिका संख्या 4.1 के अनुसार बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं जैसे कि जलापूर्ति तथा सीवरेज आदि भी उपलब्ध कराई जानी थी। मार्च 2012 तक हजारीबाग में ढाँचागत परियोजनाएं नगर पर्षद द्वारा परिमाण विपत्र के न.वि.वि. को समर्पण में तथा उसकी स्वीकृति में देरी[50] तथा निधियों की कमी के कारण प्रारम्भ नहीं की जा सकी थी। लोहरदगा नगर पर्षद द्वारा निधियों के आवंटन की कमी/कम प्राप्ति को ढाँचागत कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण बताया गया।

समापन सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया कि हजारीबाग में आधारभूत कार्य परिमाण विपत्रों की स्वीकृति में देरी के कारण लम्बित हो गया। अब सभी औपचारिकताएं पूरी हो गईं है, राज्य सरकार द्वारा आगे की निधियाँ आवंटित कर दी गई है तथा जल्द ही कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। निधियों की कमी नहीं मुक्त किए जाने के संबंध में कहा गया कि सुधारों के लागू नहीं होने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के विलम्बित प्रतिस्थापन के कारण केन्द्र से निधि प्राप्त नहीं हो पाई थी।

इस प्रकार, बीएसयूपी/आईएचएसडीपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कमी के कारण चिन्हित शहरों की बस्तियों के वासियों को पर्याप्त आश्रय तथा मूल आधारभूत सुविधाओं द्वारा एक स्वस्थ तथा योग्य नगरीय वातावरण बनाते हुए गंदी बस्तियों के पवित्र विकास का उद्देश्य, ₹ 27.86 करोड़[51] के खर्च के बावजूद अभी भी पूरा किया जाना बाकी था।

2.2.8.9 ठेकेदार लाभ (सीपी) की कटौती नहीं किये जाने के कारण आवासीय इकाइयों के प्राक्कलन बढ़े हुए थे

प्रारंभ में बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी. के अधीन आवासीय इकाइयों का निर्माण निविदा के माध्यम से किया जाना था। हाँलाकि, नगर विकास विभाग के निर्देश/निर्णय (सितम्बर 2009/फरवरी 2011) के अनुसार, आवासीय इकाई का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं करना था। बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी. के दिशानिर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को आवास नि:शुल्क प्रदान

---

[50] तकनीकी स्वीकृति दिसम्बर 2010 में तथा प्रशासनिक स्वीकृति जून 2011 में

[51] राँची बी.एस.यू.पी.-₹.132.37 लाख लाभुकों को दिए गए, धनबाद बी.एस.यू.पी-₹.30.14 लाख लाभुकों को दिए गए, लोहरदगा आई.एच.एस.डी.पी.-₹ 1,186.94 लाख लाभुकों को दिए गए, गुमला आई.एच.एस.डी.पी.-₹.622.60 लाख लाभुकों को दिए गए, हजारीबाग आई.एच.एस.डी.पी.-₹ 251.95 लाख लाभुकों को दिए गए

प्राक्कलनों में सीपी की कटौती नहीं किये जाने के कारण आवासीय इकाईयों के प्राक्कलन बढ़े हुए थे जिसके कारण ₹ 2.97 करोड़ की देयता बनी

नहीं करना था। लाभार्थियों को अंशदान के रुप में आवासीय इकाई के लागत मूल्य का 12 *प्रतिशत्* वहन करना था, एस.सी./एस.टी./पिछडी जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पी.एच. और किसी भी अन्य कमजोर वर्ग के द्वारा 10 *प्रतिशत्* अंशदान के रुप में वहन किय जाना था। तदनुसार, चयनित लाभार्थियों के साथ प्राक्कलित मूल्य पर एकरारनामा किया गया जिसमें 9.1 *प्रतिशत्* ठेकेदार का लाभ सम्मिलित था जिसके कारण ₹ 2.97 करोड़ की देयता बनी, जिसका विस्तृत विवरण नीचे **तालिका-8** में दर्शायी गई है:

तालिका-8: अतिरिक्त देयता दर्शाती विवरणी

शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बीएसयूपी/आईएचएसडीपी	लाभार्थियों की संख्या जिनके साथ समझौते किये गये	प्रति आवासीय इकाई सहमत मूल्य (लाख ₹ में)	कुल व्यय शामिल (करोड़ ₹ में)	सी.पी. की कटौती के बाद प्रति आवासीय इकाइ की अनुमानित लागत (लाख ₹ में)	सी.पी. की कटौती के बाद कुल व्यय (करोड़ ₹ में)	अतिरिक्त दायित्व (करोड़ ₹ में)
राँची	बी.एस.यू.पी. (चरण II)	276	1.72	4.75	1.57	4.32	0.43
धनबाद	बी.एस.यू.पी. (चरण II)	31	1.70	0.53	1.64	0.51	0.02
हजारीबाग	आईएचएसडीपी	738	1.48	10.92	1.34	9.89	1.03
लोहरदगा	आईएचएसडीपी	992	1.64	16.27	1.49	14.78	1.49
योग		**2037**		**32.47**		**29.50**	**2.97**

स्रोत- प्राक्कलन तथा लाभूकों के साथ किये गये एकरारनामा

राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन को समापन सम्मेलन में स्वीकार किया गया और यह कहा गया कि सी.पी. की कटौती लाभार्थियों को की जाने वाली अंतिम किस्त के भुगतान से की जाएगी।

2.2.8.10 मात्रा विपत्र (बी.ओ.क्यु.) के अनुमोदन के बिना अनियमित कार्य निष्पादन

जेपीडब्लुडी संहिता के कंडिका 126 के अनुसार हर कार्य के शुरु होने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत एक विस्तृत अनुमान तैयार किया जाना चाहिए।

कार्यों का निष्पादन प्रतिरूप प्राक्कलन के आधार पर बगैर मात्रा विपत्र के अनुमोदन के ही किये गये

गुमला नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि आई.एच.एस.डी.पी. के तहत् ₹ 6.23 करोड़ लागत मूल्य (***परिशिष्ट 2.13***) के आधारभूत संरचनाओं के कार्य (सड़क, नाली आदि) बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा मात्रा विपत्र के अनुमोदन के ही सफल निविदाकर्ताओं को आवंटित कर दिया गया। कार्य का निष्पादन प्रतिरुप प्राक्कलन के आधार पर किया गया, जिसकी स्वीकृति अभिलेख में नहीं थी। इसके

अलावा, कार्य का पूर्ण विवरण (यथा सटीक स्थान और लंबाई/क्षेत्र) एन.आई.टी., निविदा दस्तावेज, कार्य आदेश और ठेकेदारों के साथ किये गये समझौतों में उपलब्ध नहीं था। अत: मापी पुस्तिका के अनुसार किये गये कार्य का सत्यापन तथा आवश्यक लेखापरीक्षा जाँच नहीं की जा सकी।

अभिलेखों में सटीक स्थान जहां इन कार्यों को क्रियान्वित किया गया था से संबंधित पूर्ण जानकारी के अभाव में कार्यों का भौतिक सत्यापन मुश्किल था। हाँलाकि, लेखापरीक्षा दल ने नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ कुछ इलाकों का दौरा किया जहां आई.एच.एस.डी.पी. के अधीन कार्य शुरु किया गया था। निर्माण की गुणवत्ता नीचे के चित्र से स्पष्ट है:




टुकु टोली, गुमला में निर्मित पीसीसी सड़क और पुलिया की खराब गुणवत्ता दर्शाती दिनांक 18.05.12 को ली गई तस्वीरें




पंडित और बड़ाइक मुहल्ला, गुमला में सड़क और नाली का निर्माण दर्शाती दिनांक 18.05.12 को ली गई तस्वीरें

लेखापरीक्षा में यह सुस्पष्ट किये जाने पर शहरी स्थानीय निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ठेकेदारों को कार्यों का आवंटन निविदा समिति के निर्णयानुसार किया गया था तथा उनके द्वारा उक्त निर्णय के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अनुचित होगा। कार्यपालक पदाधिकारी का जवाब टालमटोल था क्योंकि योजनओं का कार्यान्वयन/निष्पादन नियमसंगत नहीं था तथा व्यय की वास्तविकता और उपलब्धि का आंकलन एनआईटी, निविदा दस्तावेज और कार्य आदेश में पूर्ण जानकारी के अभाव में नहीं किया जा सका।

समापनसम्मेलन के दौरान राज्य सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रक्रिया गलत थी और इसकी जाँच कर जिम्मेवार लोगों के विरूद्ध कारवाई की जाएगी।

2.2.8.11 *पथ प्रकाश सामग्री की ख़रीद पर ₹ 22.48 लाख की संदेहात्मक गबन*

केतकी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा गुमला नगर पंचायत के लिए आई.एच.एस.डी.पी. हेतु तैयार किये गए डी.पी.आर. को केन्द्रीय मंजूरी समिति (सी.एस.सी.) द्वारा ₹ 19.67 करोड़ की स्वीकृति (जनवरी 2008) दी गई थी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मलिन बस्तियों में ₹ 73.91 लाख की विद्युतीकरण (सड़क प्रकाश व्यवस्था) का भी प्रावधान था।

छ:[52] फर्मों से प्राप्त कोटेशन (जून/जुलाई 2008) के आधार पर मेसर्स सुपर सेल्स कॉरपोरेशन[53] राँची, जिन्होंने सबसे कम दर उद्धृत किये थे, को निविदा समिति के निर्णय (अगस्त 2008) के अनुसार अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए चयनित किया गया था।

फ़र्जी बीजकों के विरूद्ध भुगतान कर ₹ 22.48 लाख का गबन किया गया

संवीक्षा (मई 2012) से पता चला कि मेसर्स सुपर सेल्स कॉरपोरेशन राँची को ₹ 22.48 लाख की राशि का भुगतान सड़क प्रकाश सामग्री की आपूर्ति के विरुद्ध, **तालिका-9** में दर्शाए गये विवरणी के अनुसार, किया गया था।

तालिका-9: सड़क प्रकाश सामग्री की ख़रीद के विरुद्ध की गयी भुगतान की विवरणी

ख़रीद आदेश संख्या/तिथि	ब्यौरे	चालान संख्या/तिथि	बीजक संख्या/तिथि	बीजक की सकल राशि (₹ में)	कटौतियां (₹ में)	भुगतान की गई राशि (₹लाख में)	चेक[54] संख्या/तिथि
अगस्त 2008	500 सीएफएल लैंप (85 वाट), पूरी फिटिंग के साथ	03/08-09/102 दिनांक 06.09.2008	120 दिनांक 08.09.2008	14,76,562	आय कर- 33, 075 रोक कर रखी गई राशि[55] - 2,95,312[56]	11.48	44526 दिनांक 12.09. 2008
उप्लब्ध नहीं	एल्यूमीनियम केबल, कॉपर वायर, 5 एम्पेयर स्विच श्रम लागत सहित	03/08-09/102 दिनांक 15.09.2008	121 दिनांक 17.09.2008	2,69,800	आय कर-- 4, 252	2.66	44530 दिनांक 01.10.2008
सितम्बर 2008	200 सीएफएल लैंप (85 वाट) तार, स्विच, बोर्ड	03/08-09/102 दिनांक 31.09.2008	125 दिनांक 02.10.2008	6,50,175	आय कर- 12,981, 15% निष्पादन	5.39	18602 दिनांक 12.12.2008

---

[52] राँची केबल, राँची, सुपर सेल्स निगम, राँची, इंटेक सिस्टम्स, राँची, श्री संतोष कुमार सिंह, श्री दीपक कुमार, और श्री सुनील कुमार गुप्ता

[53] मालिक श्री उमेश चंद्र मिश्र

[54] बैंक ऑफ इंडिया, गुमला पर आहरित

[55] रोक कर रखी गई राशि

[56] चेक संख्या 44531 दिनांक 01 अक्टुबर 2008 द्वारा विमुक्त

	आदि के साथ				गारंटी, ₹ 1125 अधिक भुगतान की वसूली		
कुल भुगतान की गई राशि (रोक कर रखी गई 2.95 लाख की राशि की विमुक्ति सहित)						**22.48**	

स्रोत: संबंधित ख़रीद संचिका से संकलित डाटा

यह ऊपर दिये गये विवरणी से स्पष्ट होगा कि सभी आपूर्ति एक ही चालान संख्या अर्थात 03/08-09/102 द्वारा किया गया था। सामग्रियों की आपूर्ति, चालान तिथि 31.09.2008 द्वारा भी संदिग्ध था। छानबीन से पता चला कि गुमला नगर पंचायत का खाता बैंक ऑफ इंडिया, गुमला में था। चुँकि सभी चेक बैंक ऑफ इंडिया, गुमला पर आहरित थे, अत: लेखापरीक्षा दल द्वारा उक्त बैंक के मुख्य प्रबंधक से संपर्क (मई 2012) कर मेसर्स सुपर सेल्स कॉरपोरेशन को किए गए भुगतानों से संबंधित विवरणी प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया। बैंक के मुख्य प्रबंधक ने सूचित किया कि सभी चेक गुमला सिमडेगा केंद्रीय सहकारी बैंक (जीएससीसीबी), गुमला से क्लीयरेंस हेतु प्राप्त किये गये थे। अत: प्रबंध निदेशक, जीएससीसीबी, गुमला से मेसर्स सुपर सेल्स कॉरपोरेशन को किए गए भुगतानों/ बैंक ऑफ इंडिया, गुमला द्वारा जीएससीसीबी, गुमला को की गई हस्तांतरणों से संबंधित विवरणी प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया। जीएससीसीबी, गुमला द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों से निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

- 09 सितम्बर 2008 को मेसर्स सुपर सेल्स कॉरपोरेशन के नाम से एक फ़र्जी खाता (चालू खाता सं 381) जी.एस.सी.सी.बी., गुमला में खोला गया था जिसे फर्म के मालिक श्री मनोज कुमार सिंह के द्वारा संचालित किया जा रहा था। वर्तमान खाता लेजर के प्रासंगिक पृष्ठ संख्या 204 पर पता डी.टी.पी.ओ. गुमला दर्शाया गया था।
- बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चेकों को क्लीयरेंस (सितंबर और दिसंबर 2008 के बीच) दिये जाने के पश्चात, श्री मनोज कुमार सिंह, जिनका खाता जी.एस.सी.सी.बी, गुमला में था, ने जी.एस.सी.सी.बी, गुमला के चार[57] चेक किसी श्री संजय सिन्हा के नाम तथा एक चेक खुद के नाम पर निर्गत किए। जी.एस.सी.सी.बी, गुमला का खाता भी बैंक ऑफ इंडिया, गुमला (वर्तमान खाता संख्या सी.डी.-49) में

[57] (क) चेक सं 52452 दिनांक 12.09.08 ₹ 11,45,000 के लिए, श्री संजय सिन्हा के नाम
(ख) चेक सं 52451 दिनांक 03.10.08 ₹ 5,50,000 के लिए, श्री संजय सिन्हा के नाम
(ग)चेक सं 52457 दिनांक 12.05.09 ₹ 2,00,000 के लिए , श्री संजय सिन्हा के नाम
(घ) चेक सं 52456 दिनांक 27.05.09 ₹ 5,000 के लिए, श्री संजय सिन्हा के नाम
(ड.) चेक सं 52455 दिनांक 13.12.08 ₹ 5,40,000 के लिए, स्वयं के नाम

था, इसी कारण श्री मनोज कुमार सिंह से प्राप्त चेक के विरुद्ध जी.एस.सी.सी.बी, गुमला ने बैंक ऑफ इंडिया के चेक[58] निर्गत किये।

दो चेकों के संबंध में जी.एस.सी.सी.बी, गुमला द्वारा वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये थे। अत: यह वर्णित नहीं किया जा सका कि श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा निर्गत किए गए इन चेकों के विरुद्ध उपरोक्त तीन चेकों की तरह ही बैंक ऑफ इंडिया, गुमला के चेक श्री संजय सिन्हा के पक्ष में जी.एस.सी.सी.बी., गुमला द्वारा निर्गत किये गये थे या किसी को नकद भुगतान किया गया था।

- मेसर्स सुपर सेल्स कॉरपोरेशन , जिसके मालिक श्री मिश्रा थे और जिसे अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए चयनित किया गया था, द्वारा गुमला नगर पंचायत से लिखित ख़रीद आदेश प्राप्त नहीं किया गया था।

इन्होंने दूरभाष पर लिये गये आदेश के आधार पर 500 सी.एफ.एल. लैंप (85 वॉट) और एक्रीलीक कवर की आपूर्ति की और तदनुसार ₹ 7.28 लाख का बीजक समर्पित किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी बीजक संख्या के विरुद्ध ₹ 11.48 लाख की राशि का भुगतान श्री मनोज कुमार सिंह के स्वामित्व वाले फर्म को किया गया, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में विस्तृत है। जिन बीजकों के विरुद्ध श्री मनोज कुमार सिंह के स्वामित्व वाले फ़र्म को गुमला नगर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया था, उनका मिलान श्री मिश्रा के स्वामित्व वाले फ़र्म द्वारा समर्पित बीजकों से करने पर यह प्रकाश में आया कि पहले वाले फ़र्म के बीजकों में अक्षर कंप्युटर द्वारा भरे गये थे जबकि दूसरे वाले फ़र्म के बीजकों में अक्षर टाइपराइटर द्वारा भरे गये थे। इसके अलावा, जिन बीजक संख्याओं के विरुद्ध श्री मनोज कुमार सिंह के स्वामित्व को श्री मिश्रा के स्वामित्व वाले फ़र्म द्वारा अन्य संस्थानों/संगठनों को निर्गत पाये गये।

- हमारे पूछे जाने पर श्री मिश्रा के स्वामित्व वाले मेसर्स सुपर सेल्स कॉरपोरेशन ने बताया कि उनके द्वारा की गई आपूर्ति के विरुद्ध उन्होंने कोई भी पैसा, नकद या चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, प्राप्त नहीं किया था तथा जिन बीजकों के विरुद्ध भुगतान किया गया था वो उनकी फर्म का नहीं थीं बल्कि नकली थीं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि न तो उनकी फर्म की और न ही उनकी, गुमला

---

[58] (क) श्री संजय सिन्हा के पक्ष में चेक सं 011459 दिनांक 13.09.08 ₹ 11,45,000 के लिए, चेक सं 52452 दिनांक 12.09.08, इतनी ही राशि के विरुद्ध,
(ख) श्री संजय सिन्हा के पक्ष में चेक सं 011466 दिनांक 03.10.08 ₹ 5,50,000 के लिए, चेक सं 52451 दिनांक 03.10.08, इतनी ही राशि के विरुद्ध
(ग) श्री संजय सिन्हा के पक्ष में चेक सं 011499 दिनांक 13.12.08 ₹ 5,40,000 के लिए, चेक सं 52455 दिनांक 13.12.08, इतनी ही राशि के विरुद्ध

के किसी भी बैंक में कभी भी कोई भी खाता था। श्री मनोज कुमार सिंह के स्वामित्व वाले फ़र्म के द्वारा किये गये लेन-देन से भी यह स्पष्ट है कि कोइ भी भुगतान उस फ़र्म को नहीं किया गया था जिस के मालिक श्री उमेश चंद्र मिश्र थे एवं जिसे एल-वन फ़र्म के रुप में चयनित किया गया था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा दल को ख़रीद की स्टॉक प्रविष्टि तथा मलिन बस्तियाँ /स्थान जहाँ सी.एफ.एल. लैम्पस लगाये गये, की सूची नहीं दिखायी गयी। स्थानीय निकाय द्वारा यह बतलाया गया कि स्टॉक रजिस्टर गुम था।

ऊपर वर्णित तथ्यों से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि पथ प्रकाश सामग्री की ख़रीदगी की भुगतान एक फर्जी फर्म को कर ₹ 22.48 लाख का गबन किया गया है। मामले की सरकार के स्तर पर विस्तृत जाँच की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा के नतीजों को राज्य सरकार द्वारा समापन सम्मेलन में स्वीकार किया गया तथा यह कहा गया कि जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

2.2.8.12 आई.एच.एस.डी.पी. - लोहरदगा के तहत योजनाओं का अनियमित चयन/अनुमोदन

आई.एच.एस.डी.पी. के दिशा निर्देशों के कंडिका संख्या 2 के अनुसार चिन्हित शहरी क्षेत्रों के गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों को पर्याप्त आश्रय और बुनियादी ढाँचागत सुविधा मुहैय्या कराकर समग्र गंदी बस्ती विकास के साथ एक स्वस्थ और सक्षम शहरी वातावरण के लिये प्रयास करना, आई.एच.एस.डी.पी. का बुनियादी उद्देश्य था।

दिशा निर्देशों के विरूद्ध ₹ 2.13 करोड़ लागत की योजनायें ली गईं

छानबीन से पता चला कि शहरी स्थानीय निकाय, लोहरदगा ने, अन्य बातों के साथ–साथ, मलिन बस्तियों में ढाँचागत कार्यों के अलावा नगर परिषद क्षेत्र के गैर स्लम क्षेत्रों में ₹ 2.13 करोड़ लागत की पी.सी.सी. सड़कों और नालियों (पी.सी.सी. सड़क ₹ 1.05 करोड़ और नालियों ₹ 1.08 करोड़) के निर्माण के लिए प्रस्तावना तैयार किया (सितम्बर 2010)। न.वि.वि.द्वारा इसपर तकनीकी स्वीकृति जुलाई 2010 में दी गई और बी.ओ.क्यु. अक्टूबर 2010 में अनुमोदित किया गया। मार्च 2012 तक इन कार्यों पर कुल ₹ 38.57 लाख की राशि (पीसीसी सड़कों पर ₹ 10.59 लाख, नालियों पर ₹ 27.98 लाख) खर्च किये गये थे।

चुँकि परियोजना का उद्देश्य मलिन बस्तियों का एकीकृत विकास था ना कि नगर परिषद के गैर स्लम क्षेत्रों का विकास अत: नगर परिषद क्षेत्र के गैर स्लम क्षेत्रों में पीसीसी सड़कों एवं नालियों के निर्माण पर खर्च उचित नहीं था।

इस प्रकार, उक्त योजनाओं का चयन/न.वि.वि. द्वारा तकनीकी स्वीकृति, दिशा निर्देशों के अनूरुप नहीं था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को समापन सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और यह कहा गया कि स्लम क्षेत्रों के बाहर योजनाओं पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए था, फिर भी इस मामले की जाँच तथा समुचित कार्रवाई की जाएगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

एम.ओ.यु.डी द्वारा जारी किया गया डी.पी.आर टूलकिट में उल्लेखित परियोजना के घटक **तालिका-10** में दर्शाये गए हैं:

तालिका-10: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्लुएम) परियोजना के घटकों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	प्रमुख घटक	उप घटक
1.	कचरे का प्राथमिक संग्रह	(i) संग्रह की प्रणाली (दरवाजे से दरवाजा संग्रह, कचरे का अलगाव) (ii) अपशिष्ट भंडारण और संग्रह डिब्बे (घरेलू डिब्बे, सामुदायिक डिब्बे) (iii) प्राथमिक संग्रह वाहन (संग्रह और हस्तांतरण स्टेशन पर हस्तांतरण के लिए)
2.	हस्तांतरण स्टेशन	(i) हस्तांतरण स्टेशनों का विकास (ii) उपकरण
3.	परिवहन	(i) वाहन (हस्तांतरण स्टेशनों से निपटान स्थल को हस्तांतरण के लिए)
4.	कचरे का निपटान	(i)निपटान साइट के विकास (लैंडफिल साइट, खाद संयंत्र, वाहन डिपो) (ii) निपटान स्थल पर उपकरण

स्रोत: एम.ओ.यु.डी. द्वारा जारी किया गया डी.पी.आर टूलकिट

एस.डब्लु.एम. परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

2.2.8.13 एस.डब्लु.एम. परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब

एस.डब्लु.एम. परियोजनाओं की डी.पी.आर. राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तर स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.) के द्वारा फरवरी 2008 में अनुमोदित किया गया।

लैंडफिल साइट/खाद संयंत्र हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण एसडब्लुएम परियोजनाएं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ

हमारी जाँच में पता चला कि तीन[59] शहरी स्थानीय निकायों की अनुमोदित डी.पी.आर. में न तो क्वांटम और न ही लैंडफिल साइट/हस्तांतरण स्टेशन/खाद संयंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता उल्लेखित थी। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लैंडफिल साइट/खाद संयंत्र/हस्तांतरण स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि की पहचान/हस्तांतरण/अधिग्रहण के संबंध में स्थिति निम्न थी:

- **चास नगर परिषद:** माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 12 दिसंबर 1996 के आदेश अनुसार लैंडफिल के निर्माण के लिए गाँव सुमटा में चिन्हित भूमि के गैर वन उपयोग के लिए वन विभाग की मंजूरी लिया जाना था चुँकि भूमि की प्रकृति

[59] चास, हजारीबाग और लोहरदगा

"*जंगल-झाड़ी*" थी। हाँलाकि, नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया और चयनित भूमि स्थानांतरित/अधिग्रहित नहीं किया जा सका(अप्रैल 2012)।

- **लोहरदगा नगरपालिका परिषद:** गांव चित्रि (थाना सेन्हा) में लैंडफिल के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डी.एल.ए.ओ.) लोहरदगा को अनुरोध (दिसंबर 2010) किया गया था। जवाब में, डीएलएओ द्वारा शीघ्र कार्रवाई हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव न.वि.वि. के माध्यम से भेजने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को अनुरोध (फरवरी 2011) किया गया। तदनुसार, डी.एल.ए.ओ. को अधिग्रहण प्रस्ताव भेजने हेतु न.वि.वि. को अनुरोध (मई 2011) किया गया । न.वि.वि. ने अधिग्रहण प्रस्ताव डी.एल.ए.ओ. को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित (अगस्त 2011) किया। इस संबंध में आगे कोई विकास दस्तावेजों पर नहीं देखा गया (मई 2012) ।
- **हजारीबाग नगर परिषद:** अपेक्षित भूमि ग्राम मंडई खुर्द में चिन्हित (जून 2010) की गई थी जिसे मई 2012 तक अधिग्रहित नहीं किया जा सका था हाँलाकि, प्रक्रिया जारी थी।

परियोजना के अनुमोदन (फरवरी 2008) के चार से अधिक वर्षों के बाद भी लैंडफिल साइट/खाद संयंत्र/ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि नहीं अधिग्रहित किये जाने के कारण, सफाई उपकरण/परियोजना के तहत खरीदे गए वाहन या तो अप्रयुक्त पड़े हुए थे या डी.पी.आर. में परिकल्पित रुप में उपयोग नहीं किये जा रहे थे। परिणाम स्वरुप शहरों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को गैर वैज्ञानिक ढंग से निपटाया जा रहा था।

राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को समापन सम्मेलन में स्वीकार किया गया और यह बताया गया कि लोहरदगा में लैंडफिल के लिये तथा हजारीबाग में लैंडफिल/हस्तांतरण स्टेशनों/खाद संयंत्र के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है परंतु चास में भूमि की मुद्दा सुलझ नही पाई थी।

2.2.8.14 एस.डब्लु.एम. के तहत खादगरहा, लोहरदगा में खाद संयंत्र और हस्तांतरण स्टेशन के निर्माण पर निष्फल व्यय

जेपीडब्लुडी संहिता के कंडिका 126 के अनुसार हर कार्य शुरु होने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत एक विस्तृत अनुमान तैयार किया जाना चाहिए।

हमारी जाँच में पता चला कि खादगरहा में खाद संयंत्र और हस्तांतरण स्टेशन का निर्माण कार्य बिना टीएस/बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा बी.ओ.क्यु. के अनुमोदन, के शुरु किये गये थे। इसके अलावा, निविदा कागजात और ठेकेदारों के साथ समझौते के कागज़ात भी उपलब्ध नहीं थे।

बगैर टी.एस. और बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा बी.ओ.क्यु. के अनुमोदन के खाद संयंत्र और हस्तांतरण स्टेशन के निर्माण पर ₹ 30.49 लाख का व्यय किया गया

खाद संयंत्र के निर्माण का काम श्री बलबीर कुमार देव को ₹ 33.89 लाख समझौता मूल्य पर सौंपा (जुलाई 2008) गया था और अक्टूबर 2009 तक कुल ₹ 27.14 लाख का भुगतान भी उक्त ठेकेदार को किया जा चुका था परंतु स्थानीय बाधा के कारण कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया। हस्तांतरण स्टेशन का निर्माण कार्य श्री उमर शाह को सौंपा गया था परंतु ₹ 3.35 लाख के भुगतान (नवंबर 2008) के साढे तीन वर्ष से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य प्रारंभिक अवस्था में था।

लेखापरीक्षा में यह सुस्पष्ट किये जाने पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा बताया गया कि चुँकि न.वि.वि. द्वारा डी.पी.आर./परियोजना को टीएस नहीं प्रदान की गई थी अत: बी.ओ.क्यु. पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त नहीं किये जा सके तथा उक्त कार्यों को आवश्यकता के अनुरुप शुरु किये गये। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह निर्णय प्रावधानों के खिलाफ था तथा कार्य अपूर्ण रहने के कारण संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

राज्य सरकार ने समापन सम्मेलन के दौरान कहा कि मामले की जाँच की जाएगी तथा जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



खादगरहा में अधूरा खाद संयंत्र दिखाता 3 मई 2012 को लिया गया तस्वीर



खादगरहा में अधूरा ट्रांसफर स्टेशन दिखाता 9 मई 2012 को लिया गया तस्वीर

2.2.8.15 सफाई उपकरणों/ वाहनों की ख़रीद पर ₹ 68.91 लाख का अतिरिक्त व्यय

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 11 के अनुसार, एक नियंत्रण अधिकारी को न केवल यह देखना है कि कुल व्यय अधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर है बल्कि यह भी देखना है कि इकाईयों को आवंटित धन जनता के हित में तथा उस प्रयोजन पर खर्च किये जा रहे हैं जिसके लिए धन उपलब्ध कराया गया था।

सफाई उपकरणों/वाहनों की ख़रीद एसएलएससी द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक दरों पर किये जाने के कारण ₹ 68.91 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ

जाँच में पता चला कि तीन[60] शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एस.डब्लु.एम. परियोजना के तहत सफाई उपकरणों/वाहनों[61] की ख़रीद (***परिशिष्ट 2.14*** में विस्तृत), एस.एल.एस.सी. द्वारा स्वीकृत दरों से 5.06 *प्रतिशत्* से लेकर 200 *प्रतिशत्* तक अधिक दरों पर की गयी थी जिसके परिणामस्वरुप ₹ 68.91 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। ख़रीद समिति के निर्णय को न तो विभाग[62] को सूचित किया गया था और न ही उच्च दरों पर उपकरणों/वाहनों की ख़रीद की घटनोत्तर स्वीकृति विभाग से प्राप्त की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा समापन सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया गया और यह बताया गया कि उक्त मामले में हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त तथा लोहरदगा के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ सतर्कता मुक़दमा पहले से ही चल रहे थे। यह भी कहा गया कि सफाई उपकरणों/वाहनों की ख़रीदगी लैंडफ़िल साइट/स्थानांतरण स्टेशन/खाद संयंत्र के निर्माण के बाद की जानी चाहिए थी।

2.2.8.16 घरेलू डिब्बे और ट्विन डिब्बे अप्रयुक्त रहने के कारण ₹ 1.06 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध थी

एस.डब्लु.एम. परियोजना के तहत क्रमशः ₹ 1.64 करोड़ और ₹ 6.80 लाख मूल्य के 50,013 घरेलू डिब्बे और 50 ट्विन डिब्बे, तीन[63] शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सितम्बर 2008 और सितम्बर 2010 के दौरान खरीदे गए थे । घरेलू डिब्बों को स्रोत पर सूखे और गीले कचरे के अलगाव हेतु परिवारों को वितरित किया जाना था, खाद संयंत्र में आगे के उपचार के लिए, ट्विन डिब्बों को नगरपालिका क्षेत्र में सुविधाजनक जगहों पर स्रोत पर बायोडीग्रेडेबल और गैर-बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट के अलगाव के लिए स्थापित किये जाने थे ।

₹ 1.06 करोड़ मूल्य के घरेलू एवं ट्विन डिब्बे अप्रयुक्त पडे हुए थे

स्टॉक/वितरण पंजिका के अवलोकन से पता चला कि नगर परिषदों द्वारा ख़रीदे गये कुल 50,013 घरेलू डिब्बों में से केवल 22,243 केवल डिब्बे वितरित (अप्रैल 2012) किये गये थे और ₹ 98.90 लाख के मूल्य के 27,770 डिब्बे भंडार में अप्रयुक्त पडे हुए थे। लोहरदगा नगरपालिका परिषद द्वारा ख़रीदे गये ₹ 6.80 लाख मूल्य के 50 ट्विन डिब्बे स्थापित नहीं किये गये और भंडार में अप्रयुक्त पड़े हुए

---

60 नगर परिषद लोहरदगा, नगर परिषद हजारीबाग, नगर परिषद चास

61 कन्टेनराइज़ड रिक्शा ट्रॉली, सीमलेस हाथ गाड़ी, सामुदायिक धूल डिब्बे, ट्विन डिब्बे, डम्पर प्लेसर, हाइड्रोलिक ट्रेलर आदि

62 नगर विकास विभाग

63 नगर परिषद लोहरदगा, नगर परिषद हजारीबाग, नगर परिषद चास

थे। इस प्रकार, कुल ₹ 1.06 करोड़ मूल्य के डिब्बे अप्रयुक्त पड़े हुए थे (**तालिका-11** में विस्तृत)।

तालिका-11: अप्रयुक्त घरेलू/ट्विन डिब्बे दर्शाती विवरणी

मद	ख़रीद् की तारीख	मात्रा	मूल्य (लाख ₹ में)	अप्रैल / मई 2012 तक निर्गत	भंडार में पड़ी शेष	मूल्य (लाख ₹ में)
लोहरदगा नगर परिषद						
घरेलू डिब्बे	सितम्बर 2008	10000	38.50	शून्य	10000	38.50
ट्विन डिब्बे	सितम्बर 2008	50	6.80	शून्य	50	6.80
चास नगर परिषद						
घरेलू डिब्बे	सितम्बर 2008	10080	71.64	5563	14617	51.89
	दिसंबर 2009 और सितंबर 2010	10100				
हजारीबाग नगर परिषद						
घरेलू डिब्बे	जनवरी 2010	19833	53.55	16680	3153	8.51
योग			**170.49**			**105.70**

स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों से डाटा संकलित

इसके अलावा चास और हजारीबाग नगरपालिका परिषदों द्वारा घरों में डिब्बों का वितरण व्यावहारिक रुप कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा था क्योंकि खाद संयंत्रों, जहाँ कचरे का उपचार किया जाना था, का निर्माण नहीं किया जा सका था। तीनों शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ख़रीदे गये ₹ 2.03 करोड़[64] मूल्य के सफ़ाई वाहन भी लैंडफ़िल साइट/स्थानांतरण स्टेशन/खाद संयंत्र के निर्माण ना होने तथा ड्राइवरों और स्वच्छता कर्मचारियों की कमी की वजह से पर्याप्त रुप से उपयोग नहीं किये जा रहे थे (***परिशिष्ट-2.15*** में विस्तृत)।

इस प्रकार, जरुरत और कार्यबल का आकलन किये बगैर सफ़ाई उपकरणों और वाहनों की ख़रीद की गई जिसके परिणामस्वरुप निधि अवरुद्ध होने के अलावा उनका उचित/पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा था।

राज्य सरकार ने समापन सम्मेलन के दौरान बताया कि उक्त मामले में हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त तथा लोहरदगा के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ सतर्कता मुक़दमा पहले से ही चल रहे थे। यह भी कहा गया कि सफाई उपकरणों/वाहनों की ख़रीदगी लैंडफ़िल साइट/स्थानांतरण स्टेशन/खाद संयंत्र के निर्माण के बाद की जानी चाहिए थी।

---

[64] चास नगर परिषद-₹ 0.62 करोड़, हजारीबाग नगर परिषद-₹ 0.83 करोड़, लोहरदगा नगरपालिका परिषद-₹ 0.58 करोड़





लोहरदगा नगर परिषद के भंडार में अप्रयुक्त पड़े हुए घरेलू डिब्बों और ट्विन डिब्बों को दर्शाती हुई 4 मई 2012 को ली गई तस्वीर



हजारीबाग नगर परिषद के भंडार में अप्रयुक्त पड़े हुए घरेलू डिब्बों को दर्शाती हुई 31 मई 2012 को ली गई तस्वीर



चास् नगर परिषद के भंडार में अप्रयुक्त पड़े हुए घरेलू डिब्बों को दर्शाती हुई 26 अप्रैल 2012 को ली गई तस्वीर

2.2.9 निगरानी और मूल्यांकन

राज्य स्तर पर निगरानी

2.2.9.1 निगरानी के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस.एल.एस.सी.) या किसी अन्य राज्य स्तरीय समिति की भूमिका

- जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशा निर्देशों के कंडिका संख्या 16 के अनुसार जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत चिन्हित परियोजनाओं को छांटने और प्राथमिकता देने में एस.एल.एस.सी. की प्राथमिक भूमिका थी। इसे परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी तथा शहरी सुधारों की प्रगति की समीक्षा भी करना था। हमने देखा कि एस.एल.एस.सी. ने युआइजी/बीएसयूपी परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु केवल चार बार (जनवरी 2008, अप्रैल 2008, अक्टूबर 2009 और जुलाई 2010) बैठक की।
- आई.एच.एस.डी.पी. के दिशा निर्देशों के कंडिका संख्या 10.2 एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. दिशा निर्देशों के कंडिका संख्या 12.2 के अनुसार, राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) और राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.) का गठन क्रमश: आईएचएसडीपी और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. परियोजनाओं की जाँच, अनुमोदन और समय - समय पर निगरानी के लिए किया गया था।

आई.एच.एस.डी.पी. के दिशा निर्देशों के कंडिका संख्या 10.3 के अनुसार, एस.एल.सी.सी. को चल रहे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और नए परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार मिलना आवश्यक था। लेकिन अपने गठन (जून 2006) के उपरांत, 23 बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध एस.एल.सी.सी. की केवल तीन[65] बैठकें हुई (मार्च 2012)।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के दिशा निर्देशों के कंडिका संख्या 12.3 के अनुसार, एस.एल.एस.सी. को चल रहे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और नए परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक साल में कम से कम तीन बार मिलना आवश्यक था. लेकिन जून 2006 में अपने गठन के उपरांत, कम से कम 18 बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध मार्च 2012 तक एस.एल.एस.सी. की केवल दो[66] बैठकें हुईं।

इसके अलावा, दोनों राज्य स्तरीय समितियां (एस.एल.एस.सी. और एस.एल.एस.सी) की बैठकें केवल ई.एच.एस.डी.पी./यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी परियोजनाओं की जाँच और अनुमोदन करने के लिए आयोजित की गईं। कोई भी बैठक परियोजनाओं की निगरानी के लिए आयोजित नहीं की गई। अत:जिन उद्देश्यों से इन समितियों का गठन किया गया था उन उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में ये विफल रहीं।

- राँची और धनबाद में चल रहे जल आपूर्ति परियोजनाओं की निगरानी के लिए न.वि.वि. द्वारा प्रधान सचिव, पे.स्व.वि./न.वि.वि. की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन (फरवरी 2009) किया गया था। गठन के उपरांत उक्त समिति ने छ:[67] बैठकें कीं।

अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता, पे.स्व.वि की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकों का भी आयोजन (जनवरी 2011 और दिसम्बर 2011) किया गया।

इस प्रकार, हालाँकि जल आपूर्ति परियोजनाओं की निगरानी राज्य/विभाग स्तर पर किया जा रहा था, फिर भी परियोजनाओं की प्रगति भूमि अधिग्रहण/आर.ओ.यु. मंजूरी और निधि से संबंधित बाधाओं की वजह से धीमा था।

---

65 अगस्त 2007, मार्च 2009 एवं फरवरी 2010

66 फरवरी 2008 एवं मार्च 2011

67 जनवरी 2011, फरवरी 2011, अप्रैल 2011, सितम्बर 2011, फरवरी 2012 एवं जून 2012

2.2.9.2 *निगरानी में एस.एल.एन.ए. की भूमिका*

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशा निर्देशों के कंडिका संख्या 17 के अनुसार, एस.एल.एन.ए. यानी जी.आर.डी.ए. लिमिटेड को स्वीकृत परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति और एम.ओ.ए. में प्रतिबद्ध सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करना आवश्यक था।

योजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी.ई.ए.) और स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी (आई.आर.एम.ए.) के द्वारा वर्णित जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति पहलुओं के प्रग्रहण के लिये मिशन निदेशालय द्वारा लागू वेब आधारित परियोजना निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली (पी.एम.ई.एस.), पी.एम.यू. में एमआईएस विशेषज्ञ के महत्वपूर्ण पद रिक्त (जुलाई 2010 के बाद से) होने के कारण अमल में नहीं था।

2.2.9.3 *यू.एल.बी. स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था*

मिशन शहरों की शहरी स्थानीय निकायों में स्थापित पी.आइ.यु. को अन्य कार्यों के अलावा, अन्य विभागों के समन्वय के साथ शहरी स्थानीय निकायों को उनके द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने में सहायता प्रदान करना था। हालांकि, पी.आइ.यु. में कर्मचारियों की कमी के कारण निर्दिष्ट विशेषज्ञों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को मौजूदा कर्मियों द्वारा किया जा रहा था जिसके चलते समग्र रुप में पी.आई.यू. का कुशल कामकाज प्रभावित था।

मिशन और गैर मिशन शहरों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख विभाग के कनीय/सहायक/कार्यपालक अभियंता इंजीनियर के द्वारा किया जा रहा था जो परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने में विफल रहे।

2.2.9.4 *तीसरे पक्ष की निगरानी*

शहरी विकास मंत्रालय ने यु.आइ.जी. और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. परियोजनाओं का तीसरा पक्ष निगरानी और समीक्षा, स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आई.र.एम.ए.) द्वारा, कराये जाने हेतु एक राज्य स्तरीय तंत्र का गठन किया था। इसी तरह एम.ओ.एच.यु.पी.ए. ने भी बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी हेतु तीसरी पार्टी निरीक्षण और निगरानी एजेंसियों (टी.पी.आइ.एम.ए.) की नियुक्ति के लिए एक तंत्र विकसित किया है. *अन्य बातों के साथ-साथ,* एसीए के आगे की किश्तों की विमुक्ति तीसरी पार्टी के निरीक्षण और निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट पर निर्भर करता है।

- ***तीसरी पार्टी के निरीक्षण और निगरानी एजेंसी (टीपीआइएमए)***

मेसर्स सृष्टि अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली का चयन (मई 2011) में टी.पी.आइ.एम.ए. के रुप में उक्त प्रयोजन हेतु गठित निविदा समिति[68] द्वारा किया गया था। हालाँकि चयनित एजेंसी को सी.एस.एम.सी. द्वारा अनुमोदन (फरवरी 2012) प्राप्त है, परंतु चयनित फर्म के साथ एमओए निष्पादित नहीं किया जा सका था। उक्त फर्म को एमओए पर हस्ताक्षर करने और हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद काम शुरु करने हेतु सूचित (दिसंबर 2012) किया गया था।

अत:टी.पी.आइ.एम.ए. के अस्तित्व मे नहीं आ पाने के कारण झारखंड में बी.एस.यू.पी. और आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी नहीं की जा रही थी।

- ***स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी***

सी.एस.एम.सी. ने झारखंड राज्य में कार्यान्वित किया जा रहे यु.आइ.जी. और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करने के लिए नेशनल कंसल्टेंसी फौर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग (एन.सी.पी.इ.), हैदराबाद की इरमा के रुप में नियुक्ति को मंजूरी (अक्टूबर 2009) दी। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुबंध समझौते के अनुमोदन में देरी के कारण, सी.एस.एम.सी. की स्वीकृति के 19 महीनों के पश्चात एस.एल.एन.ए. और एन.सी.पी.इ. के बीच समझौता (मई 2011) हुआ।

प्रारंभिक चरण में, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आई.आर.एम.ए. को अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे उसके कामकाज में बाधा आया। जून 2012 की स्थिति के अनुसार, राँची और धनबाद जल आपूर्ति परियोजनाओं के संबंध में पूर्व निर्माण और निर्माण स्टेज-I रिपोर्ट तथा राँची जल आपूर्ति परियोजना के संबंध में निर्माण स्टेज-II रिपोर्ट एजेंसी द्वारा समर्पित किया गया था। एस.एल.एन.ए. द्वारा उक्त रिपोर्टों को समीक्षा के पश्चात भारत सरकार को अपने सिफारिशों के साथ आगे की किश्तों को विमुक्त करने के लिए प्रेषित (दिसम्बर 2011) किया गया। तदनुसार, राँची और धनबाद जल आपूर्ति परियोजनाओं के संबंध में एसीए की दूसरी किस्त जनवरी 2012 विमुक्त किया गया। हाँलाकि, अन्य बातों के साथ – साथ, अन्य युआइजी और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्ट नहीं समर्पित किये जाने के कारण एसीए की दूसरी किस्त की विमुक्ति प्रभावित थी।

---

[68] तकनिकी समिति अध्यक्ष-ओ.एस.डी,जी.आर.डी.ए. लिमिटेड, सदस्यगण-प्रमुख अभियंता, तकनीकी कोषांग, न.वि.वि, जी.एम, जीआरडीए लिमिटेड, अधीक्षण अभियंता, तकनीकी कोषांग, न.वि.वि, श्रीमती रीता सिंघ एवं श्री विनय कुमार, पीएमयू, जी.आर.डी.ए लिमिटेड

2.2.9.5 सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी की आउटसोर्सिंग

सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए विशेष / तकनीकी एजेंसियों को आउटसोर्स किया जाना था। एम.ओ.यु.डी., भारत सरकार द्वारा क्रिसिल रिस्क एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड (सी.आर.आइ.एस.) को बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में सुधारों की समीक्षा के लिए एजेंसी के रुप में नियुक्त किया गया था। जुलाई 2010 से अगस्त 2012 के दौरान एजेंसी ने झारखण्ड में सुधारों की समीक्षा के लिए छः दौरे[69] आयोजित किये।

एजेंसी द्वारा समर्पित (सितम्बर 2012) आखिरी (छठा) समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से, झारखंड राज्य में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन में समग्र प्रगति धीमी थी, लेकिन पिछले दो वर्षों में प्रगति अच्छी थी।

2.2.10 निष्कर्ष

हाँलाकि मिशन अवधि 2005-12 था, परंतु झारखंड राज्य में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन वास्तव में मार्च 2008 में शुरु हुआ।

हाँलाकि, शहरी बुनियादी ढाँचा में दक्षता, सेवा वितरण तंत्र, समुदाय की भागीदारी एवं नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों की जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जे.एन.एन.यू.आर.एम. सुधार संचालित तथा देश भर के शहरों का तेजी से विकास का उद्देश्य मिशन अवधि (2005-12) मे प्राप्त नहीं किया जा सका। ऐसा मुख्यतः दोषपूर्ण डी.पी.आर, बगैर भूमि चिन्हित किये कार्यों का आवंटन तथा निधि की विमुक्ति में देरी की वजह से हुआ। इसके अलावा, जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजनाओं की निगरानी भी प्रभावी ढंग से नहीं किया जा रहा था क्योकि एस.एल.एन.ए. में पी.एम.यू. तथा शहरी स्थानीय निकायों में पी.आइ.यु. में कार्यबल कम थी, आई.आर.एम.ए. ने हाल ही में कामकाज शुरु किया था जबकि टी.पी.आइ.एम.ए. ने अभी तक काम शुरु नहीं किया था।

हाँलाकि, अनिवार्य मिशन अवधि 2005-12 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण किये जाने के लिए मिशन अवधि (2005-12) को और दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। परंतु त्रुटियां और जिस गति से परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है। कुल उपलब्ध करायी निधि में से केवल 55.42 *प्रतिशत* का ही उपयोग किया जा सका और पिछले चार वर्षों के दौरान लिये गये 27 परियोजनाओं में से कोई भी मार्च

[69] जुलाई 2010, दिसंबर 2010, मई 2011, नवंबर 2011, फरवरी 2012, अगस्त 2012

2012 तक पुर्ण नहीं हो सका। बी.एस.यू.पी. के मामले में स्थिति विशेष रुप से चौंकाने वाली थी जहां केवल 6.13 *प्रतिशत* राशि का ही उपयोग किया जा सका था (***परिशिष्ट 2.16***)। अत: शहरी स्थानीय निकाय शहरी प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और हितधारक की भागीदारी में सुधार के माध्यम से प्रभावशाली शहरी सेवा वितरण और परिष्कृत नागरिक बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने में विफल रहीं। इसलिए यह जरुपयेरी है कि सभी संबद्ध संस्थायें परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के लिए और सुधारों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध और ठोस कदम उठाएं अन्यथा मिशन के उद्देश्यों को विफल होना पडेगा।

2.2.11.अनुशंसाएँ

- *शहरी आबादी को आधारभूत सेवाएं तथा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं उप्लब्ध कराने के लिये चिन्हित परियोजनाओं पर निधि का उपयोग समयबद्ध तरीके से करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जायें।*
- *परियोजनाओं को विलम्ब से पूर्ण होने तथा सरकारी निधि अवरुद्ध होने की स्थिति से बचने के लिये परियोजनाओं को शुरु करने से पहले बाधा मुक्त भूमि की शिनाख्त कर अधिगृहित कर ली जाए।*
- *अतिरिक्त लागत से बचने तथा परियोजनाओं का ससमय एवं गुणवत्ता के साथ समापन सुनिश्चित करने के लिये परियोजनाओं का कार्यान्वयन मितव्ययिता, कुशलता एवं प्रभावशाली तरीके से किया जाय।*
- *निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावशाली और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।*

जल संसाधन विभाग

2.3 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत झारखण्ड में सिंचाई क्षमता के संभाव्य का सृजन

2.3.1 परिचात्मक

झारखण्ड के जनसंख्या का 60 *प्रतिशत्* से अधिक के जीविक का मुख्य स्रोत कृषि है। कृषि उत्पादन और उत्पादक में वृद्धि के लिए सिंचाई अतिमहत्वपूर्ण घटक है। झारखण्ड में लगभग 29.74 लाख हेक्टेयर के कुल कृषियोग्य क्षेत्र में से 24.25 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सका था। यद्यपि मार्च 2012 के अंत तक, राज्य में सृजित सिंचाई क्षमता 7.46 लाख हेक्टेयर[1] थी जो कि कृषि योग्य भूमि का 31 *प्रतिशत्* था। इसमें एआईबीपी के अंतर्गत सृजित 0.45 लाख हेक्टेयर (6 *प्रतिशत्*) की सिंचाई क्षमता सन्निहित है।

चालू सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूर्णता के अभिप्राय से, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) कल्पित किया गया जिसमें सिंचाई क्षमता को सृजित करना और अधिकतर क्षेत्रों में सिंचाई को विस्तारित करना था।

वर्ष 1997-98 और 2011-12 के मध्य ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत राज्य के दो वृहत[2], आठ मध्यम[3] और 456 लघु सिंचाई परियोजनाओं[4] को 4.07 लाख हेक्टेयर सिंचाई अनुमोदित किया गया था। विस्तृत ब्यौरा ***परिशिष्ट-2.17*** में दिया गया है। इनमें से दो मध्यम परियोजनाएं 2002-03 में पूर्ण हो गई थी एवं एक परियोजना वर्ष 1999-2000 से लंबित था। इनमें से एक वृहत परियोजना (सुवर्ण रेखा बहुदेश्यीय परियोजना एवं 171 लघु सिंचाई परियोजनाएं को 2011-12 में एआईबीपी के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया जिसे 2012-13 और 2014-15 तक पूर्ण किया जाना है।

चलन्त परियोजनाओं जिन्हे 2011-12 तक पूर्ण होना था में से एक वृहत परियोजना (गुमानी बराज) एवं दो मध्यम परियोजनाओं (पंचखेरो एवं अपरशंख जलाशय योजना) को सिम्पल रैन्डैम सैम्पलिंग बिदाउट रिप्लेसमेंट प्रणाली

---

1 जल संसाधन विभाग का 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन

2 गुमानी बराज परियोजना एवं सुवर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना

3 कांसजोर, लतरातू , पंचखेरो, सोनुआ, सुरंगी, तपकरा, तोराई एवं अपरशंख जलाशय योजना

4 सुकरी जलाशय कार्ययोजना एवं 455 ऋंखलाबद्ध चेकडैम (ऋंखलाबद्ध का मतलब है कि वैसे परियोजनाएं जिसमें एक से अधिक चेकडैम बराबर अंतराल पर मिट्टी के प्राकृति एवं ढाल के अनुसार बनाया गया हो)।

द्वारा चयनित किया गया। इन चयनित वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का पाँच जिलों[5] में से इन जिलों से संबंधित 62 लघु सिंचाई परियोजनाओं[6] का भी लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया। अतिरिक्त में, दो जिलों (पूर्वी सिंहभूम एवं रामगढ़) का भी इन जिलों से संबंधित 30 अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं[7] को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया।

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार एआईबीपी के अंतर्गत लिये गये परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है, लेखापरीक्षा जलसंसाधन विभाग के दो मुख्य अभियंताओं[8], दो अधीक्षण अभियंताओं[9] एवं 14 कार्यपालक अभियंताओं[10] के अभिलेखों, निदेशक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, केन्द्रीय जल आयोग राँची से संकलित सूचनाओं के नमूना जाँच द्वारा संचालित (अप्रैल 2012 एवं जनवरी 2013) के मध्य किया गया।चयनित परियोजनाओं में 44,079 हेक्टयर लक्ष्य के विरूद्ध 11,053 हेक्टयर सिंचाई क्षमता का सृजन 2007-12 के अवधि में किया गया। चयनित परियोजनाओं का संपूर्ण प्रदर्शन 2007-12 के दौरान उनके निष्पादन पर जोर देते हुए लेखापरीक्षा में निर्धारित किया गया। इसके अलावे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में चूकों जिसका सिंचाई क्षमता के सृजन पर प्रभाव पड़ा को भी परीक्षित किया गया।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

2.3.2 वित्तीय प्रबंधन

2.3.2.1 निधि की पर्याप्तता

ए.आइ.बी.पी. के अन्तर्गत निधि को केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में प्रारंभ (1996-97) किया गया। अप्रैल 2005 से, भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 90 *प्रतिशत्* अनुदान सूखा पीड़ित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, में प्रदान किया गया।

पंचखेरो जलाशय योजना के अलावे, ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत अनुमोदित राज्य की सभी परियोजनायें, जनजातिय एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लाभान्वित करने के लिए और 90 *प्रतिशत्* अनुदान प्राप्त करने के लिये योग्य थी।

---

5 गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड और साहेबगंज

6 गुमला-26, हजारीबाग-06, कोडरमा-18, पाकुड-04 और साहेबगंज-08

7 पूर्वी सिंहभूम-16 और रामगढ़-14

8 मुख्य अभियंता, जलपथ हजारीबाग और मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), रॉची

9 अधीक्षण अभियंता जलपथ अंचल, हजारीबाग एवं गुमला

10 सिंचाई प्रमंडल, बरहेट, बरहरवा और पाकुड़, जलपथ प्रमंडल, गुमला, नं-I चैनपुर, नं.II चैनपुर और बरही और लघु सिंचाई प्रमंडल पूर्वी सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़ और साहेबगंज

पंचखेरो जलाशय योजना सूखाग्रस्त क्षेत्रों को आंशिक सिंचाई सुविधा प्रदान की गई थी और इसके लिए 38 *प्रतिशत* अनुदान अनुमोदित थी।

यह देखा गया कि यद्यपि, राज्य सरकार (जल संसाधन विभाग) द्वारा परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाले नियत रूपरेखा में अनुदान विमुक्त करने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, भारत सरकार द्वारा राज्य को अनुदान का केन्द्रीय अंश विमुक्त नहीं किया गया। स्वीकृत परियोजनाओं (1997-98 एवं 2010-11 के मध्य) के **₹** 1,029.31 करोड़ के प्राक्कलित लागत के विरूद्ध, जलसंसाधन मंत्रालय द्वारा मार्च 2012 तक पूर्णता के लिए नियत परियोजनाओं[11] के लिए मार्च 2012 तक मात्र ₹ 444.11 करोड़ (43 *प्रतिशत*) ऋण/अनुदान विमुक्त किया गया था, जिसमें से मार्च 2012 तक ₹ 326.07 करोड़ का उपयोग किया गया था। जबकि, राज्य निधि सहित इन परियोजनाओं पर कुल व्यय ₹ 783.37 करोड़ था (***परिशिष्ट-2.18***)।

2.3.2.2 निधि की उपयोगिता

2007-12 के दौरान राज्य में एआईबीपी पर वहित व्यय एवं भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा विमुक्तियों का विस्तृत ब्यौरा **तालिका-1** में दिया गया है।

तालिका-1: 2007-12 के दौरान आवंटन एवं व्यय की विवरणी

(**₹** करोड़ों में)

वर्ष	केन्द्र अंश	राज्य अंश	कुल	व्यय	शेष
2007-08	9.22	42.19	51.41	49.64	1.77
2008-09	3.72	51.63	55.35	42.97	12.38
2009-10	0.00	30.46	30.46	20.64	9.82
2010-11	231.64	35.65	267.29	72.22	195.07
2011-12	114.15	29.93	144.08	200.97*	(-) 56.89
कुल	**358.73**	**189.86**	**548.59**	**386.44**	**162.15**

(स्रोत: जल संसाधन विभाग) आवंटन से अधिक व्यय का कारण केन्द्रीय अनुदान की उपयोगिता थी जो वर्ष 2010-11 में व्यय नहीं किया जा सका था

कुल अनुदान के ₹ 358.73 करोड़ में 2010-12 के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए निर्गत ₹ 334.55 करोड़ शामिल था। विभाग द्वारा कुल आवंटित निधि का ₹ 162.16 करोड़ (30 *प्रतिशत*) का उपयोग नहीं किया जा सका था।

2007-12 के दौरान चयनित परियोजनाओं से संबंधित आवंटन एवं व्यय **तालिका-2** में दिया गया है।

[11] लतरातू, तपकारा और तोराई जलाशय(पूर्ण/स्थगित) योजना को छोड़कर।

तालिका-2: 2007-12 के दौरान चयनित परियोजनाओं पर आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़)

क्र.सं.	चयनित परयिोजना का नाम	आवंटन	व्यय	बचत	
				राशि	*प्रतिशत*
1	गुमानी बराज परयिोजना	69.57	46.53	23.04	33
2	पंचखेरो जलाशय परियोजना	34.65	23.27	11.38	33
3	अपरशंख जलाशय परियोजना	64.51	37.87	26.64	41
4	ऋंखलाबद्ध चेक डैम	76.22	56.79	19.43	25
कुल		**244.95**	**164.46**	**80.49**	**33**

(स्रोत- सम्बद्धित प्रमंडलें)

जैसा कि **तालिका-2** में दिया गया है, कि चयनित प्रमंडलों के द्वारा कुल आवंटित निधि से ₹ 80.49 करोड़ (33 *प्रतिशत*) का उपयोग नहीं किया जा सका था। कम उपयोगिता का कारण कार्यों के धीमी प्रगति था क्योंकि भूमि अधिग्रहण के बिना, निविदा के अंतिमीकरण में विलम्ब, संवेदकों द्वारा कार्यों का धीमा/अक्रियान्वयन और लघु परियोजनाओं (चेक डैमों) में माइक्रो लिफ्ट का अ-क्रियान्वयन के बिना कार्य आरंभ करा दिया जाना जैसा कि कंडिका 2.3.4 में विमर्शित है।

2.3.3 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में चूक

परियोजनाओं की पूर्णता/प्रगति

ए.आई.बी.पी. के मार्गदर्शनों के अनुसार, ए.आई.बी.पी. में उनके शामिल होने के बाद वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं को चार वर्षों और लघु सिंचाई परियोजनाओं को दो वर्षों के भीतर पूर्ण होना है। अतिरिक्त में, परियोजना को चरणबद्ध ढंग से पूर्ण होना चाहिए जिससे कि अन्तर्विष्ट लाभ शीघ्र प्रवाहित हो सके।

वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनायें मुख्यत: दो घटकों संग्रहण[12] एवं वितरण[13] प्रणाली से बनी थी। परियोजनाओं के सभी घटकों को पूर्ण होना है जिससे अन्तर्विष्ट सिंचाई क्षमता सृजित हो सके। लघु सिंचाई परियोजनाओं में चेक डैम जल संग्रहण और माइक्रो लिफ्ट[14] क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करते हैं।

---

[12] संग्रहण प्रणाली में डैम, बराज, जलाशय, स्पीलवे, स्पील चैनल और निकास सन्निहित है। डैम, बराज एवं जलाशय जलसंग्रह करते हैं, स्पीलवे एवं स्पील चैनल जलाशय से आधक्यि जल को प्रवाहित करते हैं और निकास नहर में जल को ले जते हैं।

[13] वितरण प्रणाली में मुख्य नहर, शाखा नहर एवं वितरणी सन्निलित है जो जलाशय से अधिकृत सिंचित क्षेत्रों में जल ले जाती हैं। लघु वितरणी एवं जलवाहा नहरों की सहायक हैं जो जलप्रवाह को खेतों तक ले जाती हैं।

[14] पम्प घर में लगाया हुआ मशीन जो कि जलाशय से जल को उठाकर पाईपों के नेटवर्क के द्वारा खेतों में पानी पहुँचाता है।

2.3.3.1 राज्य में ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं की स्थिति

- विस्तृत परियोजनाओं प्रतिवेदनों के अनुसार 2007-12 के दौरान एक वृहत, छह मध्यम एवं 285[15] लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए 1.08 लाख[16] हेक्टेयर का सिंचाई क्षमता सृजित करना था। यद्यपि, राज्य द्वारा 2007-12 के दौरान एक मध्यम (अपरशंख), 284 में से 148 श्रृंखलाबद्ध अवरोधक बाँधों द्वारा मात्र 27,344 हेक्टेयर (25 *प्रतिशत*) के सिंचाई क्षमता का ही सृजन किया जा सका था। (***परिशिष्ट -2.17***)

- हमने पाया कि ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत 1997-98 एवं 2004-05 में स्वीकृत छः[17] चलन्त वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एक स्थगित को छोड़कर) जिसमें 0.43 लाख हेक्टेयर का सिंचाई क्षमता का सृजन, मार्च 2012 तक लक्ष्यित था जिसे ₹ 533.24 करोड़ का व्यय वहन करने के बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका था जबकि परियोजनाओं का प्रारंभिक अनुमान मात्र ₹ 44.76 करोड़ पर आंकलित था। (***परिशिष्ट-2.18***) राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के पूर्णता की तिथि को आवर्ती रूप में संशोधित किया गया और अब उनको 2012-13 में पूर्ण करना नियत है।

- 2010-11 के दौरान स्वीकृत 284 श्रृंखलाबद्ध चेक डैमों में से, मार्च 2012 तक मात्र 148 श्रृंखलाबद्ध को पूर्ण किया गया एवं 26944 हेक्टेयर का सिंचाई क्षमता सृजित किया गया। शेष 136 श्रृंखलाबद्ध चेक डैम जिनसे 29,291 हेक्टेयर का सिंचाई क्षमता का सृजन लक्ष्यित था मार्च 2012 तक अपूर्ण थी। सुकरी लघु परियोजना (लक्षित सिंचाई क्षमता 440 हेक्टेयर के साथ) वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया और उसे ए.आई.बी.पी. में वर्ष 2010-11 में सम्मिलित किया गया, मार्च 2012 तक अपूर्ण थी और इसके द्वारा कोई भी सृजन क्षमता प्राप्त नहीं किया गया (***परिशिष्ट-2.17, 2.18***)। इसके अतिरिक्त, पूर्ण लघु सिंचाई परियोजनाओं, (चेक डैमों) से खेतों को सिंचाई प्रदान करने के लिए माइक्रो लिफ्ट की स्वीकृति प्रत्येक डैम को दिया गया था। यद्यपि, जल संसाधन विभाग के निर्णयानुसार (सितंबर-2011) माइक्रो लिफ्टों को उनके विद्यमान रूपरेखा पर आधारित संदिग्ध उपयोगिता के आधार पर निर्माण नहीं करने का आदेश दिया गया। दिसम्बर 2012 तक माइक्रो लिफ्ट के स्थान पर जल उठाव के

---

[15] 284 श्रृखलाबद्ध अवरोधक बाँध एवं सुक्री जलाशय परियोजना (लघु सिचाई)।

[16] 0.12 लाख हेक्टेयर जो कि लातरातू और तपकरा परियोजना द्वारा 2002-03 में सृजित किया गया था को छोड़कर।

[17] तोराई (स्थागित योजना) को छोड़कर गुमानी, कंसजोर, पंचखेरो, सोनुवा, सुरंगी और अपरशंख।

प्रबंधन का निर्णय नहीं लिया गया था। माइक्रो लिफ्टों के अभाव में, चेक डैमों द्वारा कंडिका 2.3.5 में विमर्शित अन्तर्विष्ट सिंचाई प्रदान नहीं की गयी।

2.3.3.2 चयनित एआईबीपी परियोजनाओं की प्रगति

लक्ष्यित सिंचाई क्षमता 0.44 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध, 2007-12 की अवधि के दौरान जाँच परीक्षित परियोजनाओं के द्वारा मात्र 0.11 लाख हेक्टेयर का ही सिंचाई क्षमता सृजित किया गया था जैसा कि **तालिका-3** में दिया गया है

तालिका-3: चयनित परियोजना में सिंचाई क्षमता का सृजन एवं भौतिक अवस्था

परियोजना का नाम	मार्च 2012 तक सृजित सिंचाई क्षमता	2007-12 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता	भौतिक अवस्था
गुमानी बराज परियोजना	16190	शून्य	ए.आई.बी.पी. में परियोजना को 1997-98 में शामिल किया गया और चार वर्षों में पूर्ण करना था। परियोजना की संग्रहण प्रणाली को पूर्ण किया गया परन्तु आवश्यक जलप्लावन क्षेत्र के अभाव के कारण परियोजना नवम्बर 2012 तक जल संग्रहण करने की अवस्था में नहीं थी। परियोजना का वितरण नेटवर्क पूर्ण नहीं किया गया था
पंचखेरो जलाशय परियोजना	3085	शून्य	2005-06 तक पूर्ण करने के लिए परियोजना को 2004-05 में ए.आई.बी.पी. में शामिल किया गया। नवम्बर 2012 तक परियोजना का संग्रहण प्रणाली के साथ-साथ वितरण प्रणाली भी अपूर्ण था।
अपरशंख जलाशय परियोजना	7070	400	2005-06 तक पूर्ण करने के लिए परियोजना 2004-05 में ए.आई.बी.पी. में शामिल किया गया। नवबंर 2012 तक संग्रहण प्रणाली पूर्ण था परन्तु वितरण प्रणाली अपूर्ण था।
92 श्रृंखलाबद्ध चेक डैम	17734	10653	2010-11 में एआईबीपी में श्रृंखलाबद्ध चेक डैम को शामिल किया गया और उन्हें मार्च 2012 तक पूर्ण करना था। 92 क्रंखलाओं (304 चेक डैमों) के विरूद्ध मात्र 63 श्रृंखलाओं (220 चेक डैमों) को पूर्ण किया गया। अतिरिक्त में, मात्र 2 श्रृंखलाओं[18] 8 चेक डैमों में माइक्रो लिफ्ट लगाया गया और शेष 61 श्रृंखलाओं (212 चेक डैमें) बिना माइक्रो लिफ्ट के थी (दिसंबर 2012)।
कुल	**44079**	**11053**	

(स्रोत: जल संसाधन विभाग एवं सबंद्वित प्रमंडल)

- जैसाकि **तालिका-3** में वर्णित है, सेनेगरहा एवं मरमगहा नाला परियोजनाओं के अलावे कोई भी परियोजना पूर्ण नहीं किया गया। परियोजनाओं की अपूर्णता, भूमि की अनुपलब्धतता, क्षतिपूर्ति का अ-भुगतान, संवेदकों द्वारा कार्यों का धीमा करना/अ-क्रियाशीलता के कारण

[18] रामगढ़ जिला में सेनेगरहा एवं मरमगरहा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम

थी जैसा कि कंडिका 2.3.4 में विमर्शित है।

2.3.4 कार्य की अपूर्णता

झारखण्ड लोक कार्य नियमावली के नियम-146 और उसके तहत् जारी निर्देशों (जुलाई 1986) के अनुसार भूमि-अधिग्रहण के बिना किसी कार्य की तकनीकी स्वीकृति और निविदा नहीं किया जाना चाहिए। अतिरिक्त में, संविदा दस्तावेजों में आवंटित कार्य को पूर्ण करने में विफल रहने पर चूककर्त्ता संवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की शुरूआत करना नियत है।

भूमि अधिग्रहण के बिना कार्य का आबंटन एवं क्षतिपूर्ति भूगतान न करने के कारण ₹ 26.18 करोड़ को व्यय वहन करने बाद भी 80 अनुबंधों का अपूर्ण रहना।

तीन चयनित वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं के संग्रहण और वितरण प्रणाली को पूर्ण करने लिए, ₹ 27.58 करोड़ की एकरारित लागत पर 2007-12 के दौरान 53 अनुबंधों[19] को क्रियान्वित किया गया। इन कार्यों को अक्टूबर 2007 और अप्रैल 2012 (***परिशिष्ट-2.19***) के मध्य पूर्ण करना था। यद्यपि, ये कार्य ₹ 27.58 करोड़ के एकरारित लागत के विरूद्ध ₹ 17.72[20] करोड़ (एकरारित लागत का 64 *प्रतिशत*) के व्यय वहन करने बाद भी पूर्णता के नियत तिथि से सात से 61 महीने बीत जाने के बाद भी अपूर्ण पड़े रहे। अतिरिक्त संवीक्षा से पता चला कि ₹ 10.94 करोड़ के मूल्य वाली 27 अनुबंधों को 2002-03 और 2006-07 के मध्य शुरू किया गया और ₹ 8.46 करोड़ (एकरारित मूल्य का 77 *प्रतिशत*) (***परिशिष्ट-2.20***) का व्यय वहन करने के बाद भी पाँच से नौ वर्षों से अधिक से अपूर्ण थी।

हमने पाया कि इन कार्यों के अपूर्ण रहने का कारण, कार्य को बिना भूमि अधिग्रहण एवं क्षतिपूर्ति[21] के भुगतान के प्रारंभ कराया जाना जिसके कारण भू-स्वामियों द्वारा कार्य के क्रियान्वयन को बाधित किया जाना, विस्थापित व्यक्तियों[22] क्योंकि इन्हें समुचित रूप में पुर्नस्थापित नहीं किया गया, द्वारा बाधित किये जाने और संवेदकों द्वारा कार्यों[23] का धीमा/अक्रियान्यन मुख्य कारण थे। अतिरिक्त में, 2007 से पूर्व में शुरू किये गये 27 अनुबंधें अभी भी चल रही थी और अभिलेखों में यह दर्शित नहीं था कि संवेदकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू किया गया या नहीं या इन अनुबंधों को स्थगित किया

---

19 गुमानी बराज परियोजना, ₹ 8.79 करोड़ के लिए 13 अनुबंध, अपरशंख जलाशय योजना, ₹ 8.36 करोड़ के लिए 32 अनुबंध एवं पंचखेरों जलाशय योजना: ₹ 10.43 करोड़ के लिए 8 अनुबंध ।

20 गुमानी ₹ 7.15 करोड़, अपरशंख, ₹ 5.77 करोड़ एवं पंचखेरो : ₹ 4.80 करोड़ ।

21 गुमानी बराज की शाखा नहर, पंचखेरों जलाशय की मुख्य नहर एवं गुमानी बराज और अपरशंख जलाशय की वितरणी

22 पंचखेरों का मुख्य कार्य

23 पंचखेरो जलाशय मुख्य कार्य, अपर शंख, पंचखेरों जलाशय का नहर नेटवर्क, तथा गुमानी

गया था जिससे कि शेष कार्य को पुन: क्रियान्वित किया जा सके। संबद्ध कार्यपालक अभियंताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया।

परिणामस्वरूप, उपरांकित त्रुटियों के कारण चयनित परियोजनाओं के पूर्णता और सिंचाई क्षमता के सृजन, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में विमर्शित है पर प्रभाव पड़ा।

2.3.4.1 गुमानी बराज परियोजना

परियोजना, जिसे 1976 में प्रारंभ किया गया था, बरहेट प्रखण्ड के पेटरवासा ग्राम के पास गुमानी नदी पर आठ फाटकों, एक एफलक्स बाँध, एक बिना फाटक के स्पीलवे, एक स्पील चैनल और एक बाहरी निकास जो गुमानी मुख्य नहर को प्रवाहित करने से बनी है। इसके अतिरिक्त में, एक शाखा नहर (बरहरवा), 10 वितरणीयों[24] और साहेबगंज के तीन प्रखण्डों (बरहेट, बरहरवा और पथना) और पाकुड़ जिला के तीन प्रखंडों (लिट्टीपाड़ा, हिरनपुर और पाकुड़) में 16,190 हेक्टेयर के क्षेत्र की सिंचाई प्रदान करने के लिए लघु एवं जल साधनों के नेटवर्क बनाया गया था। जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2012) सूचनाओं के अनुसार, हेड कार्य का 99 *प्रतिशत्,* नहर कार्यों का 100 *प्रतिशत्* एवं विवरणियों का 80 *प्रतिशत्* मार्च 2012 तक पूर्ण हो गया था। यद्यपि, नवम्बर 2012 तक परियोजना का भौतिक अवस्था प्रतिवेदन प्रगति से मेल नहीं खाता था, जिसे नीचे विमर्शित किया गया है:

संग्रहण तंत्र

- अंतिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) 2009 के अनुसार, जलप्लावित क्षेत्र के लिए 16.19 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी जिसे पहले ही अधिग्रहित कर लिया गया था। यद्यपि, परियोजना के जाँच परीक्षण (अगस्त 2011) के दौरान, जब लक्षित सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए आवश्यक 50 मीटर (नहर के पूरे आपूर्ति स्तर तक) जल संग्रहित किया गया तो निर्धारित जलाप्लावित क्षेत्र से छ: और अधिक ग्रामों की भूमि जलप्लावित हो गयी। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा अधीक्षण अभियंता, साहेबगंज को आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए हिदायत दिया (अगस्त 2011)। इस प्रयोजन के लिए, प्रमंडल द्वारा सर्वेक्षण संचालन के लिए प्रयास किया गया (फरवरी और मई 2012) लेकिन ग्रामीण जो अपने भूमि का अधिग्रहण नहीं चाहते थे के पुरजोर विरोध के कारण इसे स्थगित कर

जलप्लावन क्षेत्र के अ-निर्धारण के कारण छ: अधिक ग्राम की भूमि जलप्लावित हो गयी।

[24] बरमसिया, विशुनपुर, चुटिया, दरियापुर, फतेहपुर, झिकटिया, मयूरकोला, पतना, शहरीडोमपारा एवं सत्यगाछी।

दिया गया। परिणामस्वरूप, प्रारंभ में परियोजना के जलप्लावित क्षेत्र का सही रूप से निर्धारित नहीं किया गया और इसलिए अन्तर्विहित सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए अतिरिक्त जलप्लावित क्षेत्र के अधिग्रहण में देरी हुई।

वितरण प्रणाली

- गुमानी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 33 किमी (1083 चेन) है। मुख्य नहर के कार्य को 14.93 किमी (490 चेन) पर निर्मित नहीं किया जा सका है क्योंकि 1989-90 से पुल का निर्माण नहीं हुआ है। अतिरिक्त में, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ द्वारा वर्ष 2010 में भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जल ले जाने के लिए 19.17 किमी से आगे मुख्य नहर के सम्पूर्ण मरम्मति की जरूरत थी, जो 2005 से पूर्व निर्मित किया गया था और नहर के किनारों पर क्षरण, नहर के सतह पर मृदा जमाव ओर ढाँचा क्षतिग्रस्त था। यद्यपि 2010-13 के वार्षिक योजना में इस हिस्से का सर्वेक्षण अनुमोदित था, लेकिन नवम्बर 2012 तक कार्यपालक अभियंता द्वारा संचालित नहीं किया जा सका था। परिणामस्वरूप, 19.17 किमी के आगे मुख्य नहर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था ओर जीर्णोद्धार कार्य को प्रारंभ करने के लिए सर्वेक्षण की जरूरत थी।

एन.एच एवं रेल से वांछित अनुमति प्राप्त न हाने के कारण बरहरवा शाखा नहर के तीन बिन्दुओं पर शाखा नहर का निर्माण नहीं किया गया।

- बरहरवा शाखा नहर 24.63 किमी में से केवल 16.66 किमी में पूर्ण था (नवम्बर 2012 तक)। 1.83 किमी से 18.49 किमी नहर पूर्ण था, यद्यपि नवम्बर 2012 तक तीन बिन्दुओं[25] में 17वें और 19वें किमी जहाँ रेल पथ और राष्ट्रीय उच्च पथ सं. 80 गुजर रहे थे पर शाखा नहर निर्मित नहीं किया गया था। इन बिन्दुओं पर, तीन पुलों के निर्मित नहीं किया गया था क्योंकि विभाग, 2007-08 से मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ संवर्ग झारखण्ड और पूर्वी रेल से वांछित अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा। इसी वजह से इन बिन्दुओं से आगे शाखा नहर में जल का प्रवाह सम्भव नहीं था।

- गुमानी मुख्य नहर और बरहरवा शाखा नहर के दस वितरणियों (85.25 किमी) में से, चार वितरणियों[26] (45.38 किमी) नवम्बर 2012 तक पूर्ण हो गयी थी। तीन वितरणियों[27] मुख्यत: प्रभावित भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति भुगतान में विलम्ब के कारण 25.02 किमी में से केवल 3.96

---

[25] 554 (16.88 किमी), 606 (18.47 कि.मी.) और 618 (18.84 कि.मी.) चेन पर।

[26] बरमसिया-19.87 किमी, दरियापुर-10.36 किमी, फतेहपुर-10.06 किमी और पथना-5.09 किमी।

[27] विशुनपुर-6.40 किमी, चुटिया-12.22 किमी और शहरी डोमपाड़ा-6.40 किमी।

किमी (नवम्बर 2012 तक) की लम्बाई में पूर्ण हुई थी। शेष तीन[28] (14.84 किमी) वितरणीयों का कार्य 18.21 हेक्टेयर भूमि (सभी तीन वितरणियों के लिए) के अधिग्रहण नहीं होने और सम्बद्ध प्रमण्डलों द्वारा दो वितरणियों (झिकटिया एवं सत्यागाछी) के जाँच प्रतिवेदन के तैयार नहीं करने के कारण अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप दस में से छः वितरणियों जिसकी लंबाई 35.90 किमी थी अपूर्ण रह गयी और कोई सिंचाई क्षमता सृजित नहीं कर रही थी।

- अतिरिक्त में, खेतों तक जल ले जाने के लिए आवश्यक गुमानी मुख्य नहर, बरहरवा शाखा नहर और आठ[29] वितरणियों से शाखाकृत लघु और जलवाहों को नवम्बर 2012 तक भूमि के वास्तविक आवश्यकता के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ प्रमंडलों (बरहेट एवं पाकुड़) द्वारा नहीं निर्धारित करने के कारण अभी तक निर्मित करना था। तीन में से, केवल एक प्रमंडल (बरहरवा) द्वारा गुमानी मुख्य नहर, बरहरवा शाखा नहर और चार वितरणियों के 94.03 किमी के लम्बाई में लघु एवं जल वाहा[30] के निर्माण के लिए 100.04 हेक्टेयर के आवश्यकता का आकलन किया गया। शेष दो प्रमंडल (बरहेट एवं पाकुड) गुमानी मुख्य नहर और दरियापुर विवरणियों से लघु एवं जलवाहों के लिए भूमि की आवश्यकता का निर्धारण करने में असफल रहे।

  अतिरिक्त में, दो वितरणियों (बरमसिया एवं पाकुड़ प्रमंडल के अन्तर्गत फतेहपुर) का मुख्य नहर से 19.17 किमी आगे के निर्माण दिसम्बर 2004 और मार्च 2006 में प्रारंभ किया गया और ये नवम्बर 2012 तक अपूर्ण पड़े थे। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रंडल, पाकुड़ द्वारा बताया गया (मई 2012) कि जलवाहा पूर्णतया क्षतिग्रस्त थे और शेष कार्य को पूर्ण करने तथा निर्धारण के लिए वर्तमान में सर्वेक्षण की जरूरत थी। परिणामस्वरूप, कृषि योग्य खेतों में जल ले जाने के लिए अधिकतर लघु वितरक नहरों और जलवाहों का निर्माण अभी भी करना था जिससे सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सके।

परिणामस्वरूप, परियोजना जिनका 1976 में प्रारंभ किया गया नहरों को जब तक अतिरिक्त जलप्लावन क्षेत्र के लिए आवश्यक था, भंडारित जल से पूर्ण

---

[28] झिकटिया, मयुरकोला और सत्यागाछी

[29] विशुनपुर, चुटिया, दरियापुर, झिकटिया, मयुरकोला, पतना, शहरी डोमपारा और सत्यगाछी

[30] जी.एम.सी.14.16 हैक्टेयर (33.35 कि. मी.) बी.बी.सी.33.14 हैक्टेयर (22.65 कि. मी.) विशुनपुर 8.70 हैक्टेयर(6.80 कि.मी.) चुटिया 24.54 हैक्टेयर (15.69 कि.मी.) पतना, 10.01 हैक्टेयर (7.31 कि.मी.) एवं शहरी डोमपारा 9.49 हैक्टेयर (8.23 कि. मी.)

आपूर्ति करने की अवस्था में नहीं थे। मुख्य नहर 14.93 किमी एवं निम्नतर पहुँचों से आगे तक जल ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। यद्यपि मुख्य नहर 14.93 किमी तक निर्मित थे, जिनसे खेतों तक जल नहीं ले जा सकते थे क्योंकि लघु वितरक नहरों एवं जलवाहों को बिछाया नहीं गया था। इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2012 तक परियोजना पर ₹ 150.84 करोड़ का व्यय वहन करने के बाद भी चरणबद्ध क्रियान्वयन द्वारा लक्ष्यित सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं हुआ।

2.3.4.2 अपरशंख जलाशय योजना

योजना में, चैनपुर प्रखंड के नवगेन ग्राम के नजदीक शंख नदी पर मृदा बाँध, फाटक रहित स्पीलवे, उर्जा वितरण करने वाले सहित स्पील चैनल, दो मुख्य नहर (दाहिना और बाँया) को आपूर्ति करता दो आउटलेट, आठ वितरक नहरें और छः लघु नहरों का निर्माण सन्निहित था। योजना गुमला जिले के चैनपुर प्रखण्ड के 7,070 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 1987 में प्रारंभ किया गया था। नवम्बर 2012 तक योजना का भौतिक स्थिति नीचे दिया गया है :-

संग्रहण प्रणाली

- योजना की संग्रहण प्रणाली पूर्ण थी। यद्यपि, केन्द्रीय जल आयोग ने 2011-12 के अपने अनुश्रवण प्रतिवेदन में पाया कि मुख्य नियंत्रक का फाटक त्रुटिपूर्ण और असंचालनीय थे और फाटक से जल स्राव था। परिणामस्वरूप, यद्यपि जलाशय का संग्रहण प्रणाली 2006-07 में पूर्ण था, इसलिए नहर से जल के आपूर्ति के लिए फाटकों में सुधार कि जरूरत थी।

वितरण प्रणाली

- जलाशय की बायीं मुख्य नहर 14.04 किमी के कुल लम्बाई में से मात्र 9 किमी में पूर्ण थी। अपने उद्गम स्थल शुरू होकर नियमित विस्तार में नहर पूर्ण नहीं थी और दुसरे और 6$^{वें}$ किमी में अपूर्ण पड़ी थी। संवेदक द्वारा अनुबंधित कार्य के धीमा/अक्रियान्वयन के कारण में 7$^{वें}$ और 14$^{वें}$ किमी में कुछ विस्तार में भी नहर अपूर्ण थी। प्रमंडल द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए स्मारित किया गया (नवम्बर 2011) था, परन्तु नवम्बर 2012 तक कार्य अपूर्ण पड़ी थी। परिणामस्वरूप, खंडित निर्माण के कारण, नहर की सिंचाई प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता था।

बाँयी मुख्य नहर के मुहाने पर सायफन में गाद भर जाने से सायफन नहर में जल प्रवाह गमन करने में सक्षम नहीं था।

- मुख्य अभियंता, रूपांकन, अग्रिम योजना एवं जल विषयक जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा अनुमोदित रूपांकण पर आधारित बाँयी मुख्य नहर के मुहाने पर 150 मीटर लम्बा ह्युम पाईप साइफन[31] का निर्माण नवम्बर 2002 में प्रारंभ किया गया। क्रियान्वयन के दौरान संवेदक द्वारा प्रमंडल को सूचित (जून 2005) किया गया कि नहर का जल स्तर सायफन के स्तर से 9 मीटर नीचा था और परिणामस्वरूप सायफन का भविष्य में गाद से भर जाने और अवरूद्ध होने का खतरा था। यद्यपि कोई सुधारात्मक उपाय नवम्बर 2012 तक विभाग द्वारा नहीं किया गया था और कार्यपालक अभियंता तथा सी.डब्लू.सी द्वारा पाया गया कि सायफन गाद से भर गया था जिससे नहर में जल स्थानान्तरण में सक्षम नहीं था।

- बाँयी मुख्य नहर (एलएमसी) में मृदा कार्य और ढाँचा[32] के क्रियान्वन के लिए अनुबंध ₹ 88.36 लाख[33] के अनुबंध को कार्यान्वित किया गया, जिसे अप्रैल 2006 तक पूर्ण होना था। संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया एवं ढाँचा के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण अनुबंध को समाप्त करने के लिए आग्रह किया गया (जुलाई 2008)।

  मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा प्रारंभ में भूमि के अधिग्रहण के आधार पर संवदेक पर बिना कोई जुर्माना अरोपित किये अनुबंध की समाप्ति का आदेश (अगस्त 2008) में दिया गया। बाद में, मुख्य अभियंता द्वारा अनुबंध की समाप्ति से संबंधित पूर्ववर्ती आदेश रद्द (दिसम्बर 2008) कर दिया क्योंकि कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन प्रमंडल-II चैनपुर, द्वारा जैसा कि सूचित किया गया (नवम्बर 2008) कि भूमि अधिग्रहण कोई समस्या नहीं था। मुख्य अभियंता द्वारा कार्यपालक अभियंता से कार्य के स्थगन का वास्तविक कारण प्रस्तुत करने को कहा गया था। यद्यपि कार्यपालक अभियंता द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया और कार्य की अन्तिम मापी ले लिया गया (मई 2009)। अन्तिम मापी में, नहर कार्य के संबंध में सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता द्वारा ₹ 4.47 लाख रूपये का त्रुटिपूर्ण मापी अभिलिखित किया गया, जिसके वसूली के लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को सूचित किया गया (अप्रैल 2010)। तथापि, कार्यपालक अभियंता द्वारा 7वैं और

---

[31] नहर में स्पील चैनल के नीचे जल आवागमन का ढाँचा ।

[32] 5.22 से 5.31 किमी तक मृदा कार्य, 6.53 किमी पर एकल मार्ग रोड पुल, 5.225 किमी पर त्रियक नाली और 6.13/6.21 किमी पर पथ पुल।

[33] नहर: ₹ 18.45 लाख और ढाँचा : ₹ 69.91 लाख।

अन्तिम विपत्र[34] में संवेदक से राशि की वसूली नहीं किया गया। अन्तिम विपत्र को भी अनुबंध की समाप्ति से संबंधित मुख्य अभियंता के आदेश (अगस्त 2008) के आधार पर बिना किसी क्षतिपूर्ति आरोपित किये पारित कर दिया गया (अगस्त 2011)। अन्तिम विपत्र तक, संवेदक को ₹ 83.65 लाख का भुगतान कर दिया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को ₹ 8.38 लाख के जमानत को भी वापस कर दिया गया (सितम्बर 2011)। परिणामस्वरूप, कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता के आदेश (दिसंबर 2008) की उपेक्षा करते हुए बिना जुर्माना आरोपित किये हुए क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 8.84 लाख की राशि की हानि हुई। इसके अलावे, संवेदक को ₹ 4.47 लाख का अधिक भुगतान भी किया गया।

- इसी तरह, दाँयी मुख्य नहर (आर.एम.सी.) का 13.11 किमी में से 10.92 किमी पूर्ण था। तथापि, संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण पहले किमी से 11वें किमी के विभिन्न विस्तार अपूर्ण पड़ी थी। आर.एम.सी. में मृदा कार्य, त्रियक नालियों और पुलों के लिए कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन प्रमंडल, चैनपुर, गुमला द्वारा जनवरी 2004 ओर अप्रैल 2010 के मध्य ₹ 3.43 करोड़ के लिए सात अनुबंध क्रियान्वित किये गये। इन कार्यों को जुलाई 2004 और जुलाई 2010 के मध्य पूर्ण होना था। यद्यपि, कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत किये गये बहुत सारे स्मारों के बावजूद संवेदक ने कार्य पूर्ण नहीं किया। प्रमंडल द्वारा संवेदक को चलन्त लेखा विपत्र के माध्यम से ₹ 3.07 करोड़ का भुगतान किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा सभी अनुबंधों को विखंडित कर दिया गया (जून 2011) और ₹ 2.59 करोड़ कार्य मूल्य का अंतिम मापी ले लिया गया। अत: कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता द्वारा त्रुटिपूर्ण मापी स्वीकार करने और अभिलिखित करने के कारण चलन्त लेखा विपत्रों के माध्यम से संवेदक को पहले ही ₹ 47.69 लाख के अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया। अतिरिक्त में, कार्यपालक अभियंता द्वारा नियत समय के अन्दर कार्य के पूर्ण नहीं करने के लिये संवेदक पर ₹ 34.28 लाख का जुर्माना आरोपित किया गया। यद्यपि, ₹ 81.97 लाख (₹ 47.69 लाख और ₹ 34.28 लाख) प्रमंडल द्वारा ₹17.26 लाख की जमानत राशि एवं क्षतिपूर्ति चलन्त लेखा विपत्रों से रोक रखने के बावजूद चूककर्त्ता संवेदक से ₹ 64.71 लाख (अप्रैल 2012) की वसूली नहीं हो पायी ***(परिशिष्ट-2.21)*** अलावे आरएमसी अपूर्ण पड़ा रहा।

[34] कार्य मुल्य ₹ 83.65 लाख (नहर ₹ 17.95 लाख एवं ढाँचा ₹ 65.70 लाख)

- मुख्य नहर (30.04 किमी की प्रस्तावित लम्बाई) के सभी आठ वृहत वितरणियों को निर्मित नहीं किया गया क्योंकि 80.98 हेक्टेयर की आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नवम्बर 2012 तक प्रगति में था। आठ वितरक नहरों में से, पाँच वितरक नहरों (12.54 किमी) पर कार्य जुलाई 2008 ओर जून 2011 के मध्य पूर्णता के लिये मार्च 2008 और सितम्बर 2010 के मध्य शुरू किया गया। यद्यपि, कार्य अपूर्ण पड़े रहें क्योंकि वांछित भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ, क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया और भू-स्वामियों द्वारा आपत्ति उठाया गया। भौतिक प्रगति तीन और 87 *प्रतिशत्* के मध्य सीमा तक थी (नवम्बर 2012)। तीन वितरक नहरों पर कार्य नवम्बर 2012 तक शुरू नहीं किया जा सकता था।
- 9.88 किमी की लम्बाई वाली एलएमसी के छः लघु नहरों का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि नवम्बर 2012 तक 33.02 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रगति के अन्तर्गत था। छः में से एक लघु नहर (लम्बाई 3.50 किमी) पर कार्य बिना भूमि अधिग्रहण के सितम्बर 2009 तक पूर्णता के लिए मार्च 2009 में शुरू किया गया। कार्य प्रगति पर था ओर शेष पाँच वितरक नहरों पर कार्य नवम्बर 2012 तक शुरू नहीं हुआ था।

  अत: नहरों, वितरक नहरों एवं लघु नहरों के समकालिक रूप से अपूर्णता के कारण संग्रहण प्रणाली की पूर्णता और नवम्बर 2012 तक ₹ 136.82 करोड़ के व्यय वहन करने के बावजूद लक्ष्यित सिंचाई का चरणबद्ध कार्यान्वयन प्राप्त नहीं हुआ।

2.3.4.3 पंचखेरो जलाशय योजना

योजना, जो 1986 में प्रारंभ किया गया जो कोडरमा जिला में मरकच्चो प्रखंड के अरकोसा ग्राम एवं गिरिडीह जिला में राजधनवार प्रखण्ड के ग्राम जोरहन के नजदीक पंचखेरों नदी पर एक मृदा बाँध (बायाँ डाइक[35] सहित), फाटक रहित स्पीलवे, एक स्पील चैलन, दो मुख्य नहरों (दायाँ और बायाँ) में आपूर्ति हेतु दो आउट लेट, दो शाखा नहर ओर पाँच वितरक नहरों का निर्माण सन्निहित है। योजना की कुल प्रस्तावित वार्षिक सिंचाई हजारीबाग, गिरिडीह एवं कोडरमा जिलों का 3,085 भूमि क्षेत्र हेक्टेयर है। दिसम्बर 2012 तक योजना की भौतिक अवस्था यथा नीचे विमर्शित है :-

[35] मुख्य बांध के हिस्से द्वारा जल फैलाव को रोकने के लिए निर्मित कम ऊँचाई के साथ छोटा बांध

संग्रहण प्रणाली

कम मशीन एवं यंत्र और व्यक्तियों के उपयोग के कारण नदी के बंदी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका।

- जल संग्रहण के लिए आवश्यक 170 मीटर के नदी बंद के कार्य के अलावे मृदा बाँध (प्रस्तावित लंबाई 2,310 मी., स्पील वे सहित) लगभग पूर्ण था। नदी बंदी का कार्य जून 2012 तक पूर्णता के लिए अप्रैल 2011 में प्रारंभ किया गया था। यद्यपि, कार्य संवेदक द्वारा वांछित संयत्र एवं मशीनरी और मानव शक्ति के कम तैनाती के कारण अपूर्ण था जैसा कि अधीक्षण अभियंता ओर कार्यपालक अभियंता द्वारा अवलोकित किया गया (फरवरी एवं मार्च 2012)। दिसम्बर 2012 तक, नदी बंदी का भौतिक प्रगति केवल 40 *प्रतिशत* था। अग्रेतर बाँध पर स्पील चैनल, बायाँ निकास एवं ढलान/बर्म नाली का निर्माण जनवरी 2006 एवं फरवरी 2008 के मध्य पूर्णता के लिए अप्रैल 2005 एवं मई 2007 के मध्य प्रारंभ किया गया था। इन कार्यों को भी संवेदक द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। तीन में से दो अनुबंधों (बायाँ निकास एवं ढलान/बर्म नाली) को कार्यपालक अभियंता जल पथ प्रमंडल, बरही द्वारा फरवरी 2012 में विखंडित कर दिया गया लेकिन शेष कार्य भी दिसम्बर 2012 तक प्रारंभ नहीं किया गया। स्पील चैनल (तीसरे अनुबंध) को पूर्ण करने के लिए संशोधित प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को प्रस्तुत किया गया (जनवरी 2013)।

  अंत: संग्रहण प्रणाली के अपूर्णता के कारण सिंचाई क्षमता का सृजन वंचित हुआ।

वितरण प्रणाली

- बायाँ मुख्य नहर में मृदा कार्य के लिए ₹ 1.18 करोड़ के अनुबंधीय लागत पर फरवरी 2006 एवं जुलाई 2009 के मध्य सात अनुबंध क्रियान्वित किये गये। इन कार्यों को अगस्त 2006 एवं अक्टूबर 2009 के मध्य पूर्ण होना था। यद्यपि, संवेदक द्वारा कार्य का अ-क्रियान्वयन, भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति का अ-भुगतान जिन्होंने कार्य के क्रियान्वयन (चेन 141 एंव चेन 241 तक) में आपति किया तथा अनुबंधित परिमाण (चेन 172 से चेन 185 तक) से अधिक मृदा कार्य की जरूरत जिसके लिए संशोधित प्रक्कलन को स्वीकृत करना था के कारण 1.02 करोड़ का व्यय वहन करने के बाद भी कार्य अपूर्ण पड़ा था। दो अनुबंधो (चेन 109 से चेन 138 तक एवं चेन 185 से 241 तक) को कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक द्वारा कार्य के अ-क्रियान्वयन लेकिन दिसम्बर 2012 तक शेष कार्यों का पूर्न निविदित होने के कारण विखंडित कर दिया गया (दिसम्बर 2010)।

शेष पाँच अनुबंध अभी भी चल रही थी, यद्यपि, दिसम्बर 2012 तक क्षतिपूर्ति एवं प्राक्कलन के संशोधन की कठिनाईयों को निपटारा करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया गया हो कि वैधता का कोई अभिलेख नहीं पाया गया। अत: एलएमसी अपने सम्पूर्ण लम्बाई 7.35 किमी (चेन 0 से चेन 241 तक) में पूर्ण नहीं थी।

- एल.एम.सी. के मुहाने पर स्पील चैनल के उपर एक्वाडक्ट[36] का निर्माण फरवरी 2008 में प्रारंभ किया गया जिसे ₹ 67.93 लाख के अनुबंधित लागत पर नवम्बर 2008 तक पूर्ण होना था। संवेदक द्वारा कार्य बंद कर दिया गया (मार्च 2011) ओर ₹ 18.07 लाख के व्यय वहन करने के बाद फरवरी 2012 में अनुबंध को विखंडित कर दिया गया। जनवरी 2013 में नौ महीनों में पूर्णता के लिए ₹ 71.96 लाख के अनुबंधित लागत पर कार्य को पुन: आवंटित किया गया। एक्वाडक्ट के अभाव में नहर में जल का प्रवाह सम्भव नहीं था।
- दिसम्बर 2012 तक दायाँ मुख्य नहर अपने कुल लम्बाई 3.25 किमी में पूर्ण नहीं था। नहर (चेन 0 से 20.5 एवं चेन 45 से चेन 106.5 तक) के निर्माण के लिए, ₹ 19.83 लाख के अनुबंधित लागत पर फरवरी, 2008 में क्रियान्वित किया गया जिसे अगस्त 2008 तक पूर्ण होना था। यद्यपि संवेदक द्वारा कार्य के अक्रियान्वयन के कारण दिसम्बर 2012 अपूर्ण पड़ा था। इसके अतिरिक्त, स्थल अवस्था के अनुसार प्राक्कलन के संशोधन की आवश्यकता थी। शेष बचे कार्यों के लिए प्रमंडल द्वारा अधीक्षण अभियंता को संशोधित प्राक्कलन (चेन 0 से 20.5 तक) प्रस्तुत किया गया (जनवरी 2013) विस्तार (चेन 45 से चेन 106.5 तक) का प्राक्कलन संशोधन विचाराधीन पड़ा था।
- दो शाखा नहरों और मुख्य नहरों के पाँच लघु नहरों जिनकी प्रस्तावित लम्बाई 19.33 किमी थी का निर्माण दिसम्बर 2012 तक पूर्ण नहीं हुआ था। इस प्रयोजन के लिए भूमि के 58.15 हेक्टेयर के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रमंडल द्वारा विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, तेनुधाट परियोजना, हजारीबाग का सितम्बर 2010 में प्रस्तुत किया गया। दिसम्बर 2012 तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रगति पर था।

पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना

- योजना आयोग, भारत सरकार, (जुलाई 2010) के निर्देश के अनुसार पंचखेरो जलाशय योजना के जलप्लावन के प्रारंभ से पहले पुनर्वास एवं

[36] नहर से स्पील चैनल के उपर जल ले जाने का एक ढाँचा

पुर्नवास का कार्य पूर्ण कर लेना था।

संवीक्षा से पता चला कि विभाग द्वारा पंचखेरों परियोजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित किया गया (1989 एवं 2008 के मध्य) कि 107 परिवारों को पुर्नवासित करना था। यद्यपि, विस्थापित व्यक्तियों का मांग था (2006 से) कि परिवारों की संख्या का पुन: निर्धारण, उनके नाम से बंदोबस्त सरकारी जमीन के लिए मुआवजा[37] और पूर्ण पुनर्वास हो। सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा इन मांगों को पूरा करना सुनिश्चित किया गया (फरवरी 2011) एवं उप आयुक्त कोडरमा और गिरिडीह को सरकारी भूमि के बंदोबस्ती की समस्या सुलझारने का एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग को पुनर्वास पूर्ण करने का निर्देश दिया गया (फरवरी 2011)। यद्यपि, दिसम्बर 2012 तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था एवं विस्थापित व्यक्तियों द्वारा नदी बंदी के क्रियान्वयन पर आपत्ति किया जा रहा था।

- अतिरिक्त में मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं जैसे रोड, स्वस्थ्य उप केन्द्र, स्कूल, पेयजल सुविधा, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि को प्रदान करने के लिए, पुनर्वास पदाधिकारी, पंचखेरो द्वारा 2007-10 के दौरान ₹ 2.64 करोड़ मूल्य की 22 अनुबंधों को क्रियान्वित किया गया। कार्य अप्रैल 2007 एवं नवम्बर 2010 के मध्य पूर्ण करना नियत था। 22 अनुबंधों में से 11 अनुबंध (₹ 92.04 लाख) जो स्कूल, पेयजल सुविधा, प्रशिक्षण केन्द्र, मन्दिर, बच्चों का पार्क आदि के निर्माण के लिए क्रियान्वित किये गये थे संवेदकों द्वारा कार्य के धीमी क्रियान्वयन के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। पुनर्वास पदाधिकारी ने नवम्बर 2011 में संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया। जबकि संवेदक ने कार्य पूर्ण नहीं किया और पुनर्वास पदाधिकारी ने सितम्बर 2012 में 11 में से पाँच एकरारनामा का विखंडित कर दिया। ₹ 67.27 लाख का व्यय वहन के बावजूद दिसम्बर 2012 तक अपूर्ण पड़े थे जबकि प्रमंडल के पास भूमि और निधि उपलब्ध था।

पुनर्वास पदाधिकारी पंचखेरों द्वारा पुनर्स्थापित व्यक्तियों के लिए आधारभूत सुविधाएं नहीं प्रदान की गयी

अत: परियोजना जो 1986 में प्रारंभ किया गया था नदी बंदी और बाँध के शेष कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपने जलाशय में जल संग्रह करने की अवस्था में नहीं था। मुख्य नहर भी पूर्ण नहीं था एवं शाख नहर, वितरक नहरों एवं लघु नहरों का निर्माण अभी भी प्रारंभ किया जाना था। बाँध के आपत्ति रहित कार्य के लिए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास अभी तक पूर्ण

[37] गैर मजरूआ (सरकारी) भूमि को रैयती (व्यक्तिगत) भूमि के कानूनी अधिकार के परिवर्तन के तहत

नहीं था। दिसम्बर 2012 तक ₹ 71.66 करोड़ का व्यय वहन करने के बावजूद योजना के अन्तर्विष्ट सिंचाई लाभों को नहीं प्राप्त किया गया था।

2.3.4.4 लघु सिंचाई योजना (चेक बाँध)

जाँच परीक्षित सात जिलों में ए.आई.बी.पी. में फेज-I से III के अन्तर्गत ₹ 130.64 करोड़ पर श्रृंखला चेक बाँधों का बनाने योजनाओं को स्वीकृत किया गया था। इन योजनाओं को मार्च 2012 तक पूर्ण करने का योजना था। इन योजनाओं के अन्तर्गत, 92 श्रृंखला/304 चेक बाँधों को 17.734 हेक्टयर के सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए निर्मित करना था। (***परिशिष्ट-2.22***)। संवीक्षा (अप्रैल 2012 से जनवरी 2013) से निम्नलिखित पता चला :

- 92 श्रृंखला (304 चेक डैम) योजनाओं में से, दिसम्बर 2012 तक ₹ 62.31 करोड़ व्यय वहन करने के बाद केवल 63 श्रृंखला (202 चेक डैम) योजनाएं ही पूर्ण हुई। 10,653 हेक्टयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ। एक योजना (गौरी नाला चेक बाँध, कोडरमा) लोक आपत्ति के कारण छोड़ दिया गया। शेष 28 योजनायें ₹ 8.78 करोड़ के व्यय वहन करने के बाद भी प्रगति के अन्तर्गत थी। इन्हें दिसम्बर 2012 तक पूर्ण नहीं किया जा सका था निविदा निपटारे में विलम्ब हुआ एवं संवेदकों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति किया गया।
- सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए प्रत्येक चेक बाँध में दो माइक्रो लिफ्ट संस्थापित करने की आवश्यकता थी। 220 चेक डैमों में 440 माइक्रो लिफ्टो संस्थापित करने थे जिसमें रामगढ़ जिला के आठ चेक डैमों (दो श्रृंखलाओं) में केवल 12 माइक्रो लिफ्टों को ही संस्थापित किया गया था। विभाग द्वारा यथा आदेशित (सितम्बर 2011) शेष चेक डैमों में माइक्रो लिफ्टों को संस्थापित नहीं किया जा सका था।

2.3.5 सृजित सिंचाई क्षमता का कम उपयोग

ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत पूर्ण एवं चलन्त परियोजना के जरिये से 2002-03 एवं 2011-12 के मध्य, 45,344 हेक्टेयर के सिंचाई क्षमता को सृजित किया गया था। यद्यपि, सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका-**4 में दिया गया है:

तालिका-4 सृजित सिंचाई क्षमता की विवरणी

(सिंचाई क्षमता (सि.क्ष) हैक्टेयर में)

प्रयोजनाओं के नाम	*लक्षित सि.क्ष.*	सृजित *सि.* क्षमता	*उपयोगित सि. क्ष.* (वार्षिक औसत 2007-12 दौरान) (*प्रतिशत* में)
तपकारा	1860	1840	294 (16)
लतरातू	9900	9900	1057 (11)
कंसजोर	6260	6260	875 (14)
अपरशंख	7070	400	20 (5)
योग	**25090**	**18400**	**2246**
148 **लघु सिंचाई योजनाएं**	26944	26944	लागू नहीं[38]
कुल योग	**52034**	**45344**	**2246**

(स्रोत : जल संसाधन विभाग)

तालिका-4 से यह देखा जा सकता है कि चार मध्यम परियोजनाओं से औसत वार्षिक सिंचाई मात्र 2,246 हेक्टेयर था जो सृजित सिंचाई क्षमता के पाँच और सोलह *प्रतिशत* के मध्य सीमा में था। सृजित सिंचाई क्षमता के कम उपयोग के पीछे के कारणों को नीचे विमर्शित किया गया है:-

- तपकरा (2002) एवं कंसजोर परियोजना के फेज-**I** (2006) के पूर्णता के बाद, विभाग द्वारा वितरण प्रणाली जो 1988 के पहले से निर्मित थी के नियमित अनुरक्षण के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, ये गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थे और अन्तर्विष्ठ सिंचाई प्रदान करने के लिए जल ले जाने में सक्षम नहीं थे। कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल सं.I, सिमडेगा द्वारा बताया गया (सितम्बर 2012) कि सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए इन परियोजनाओं का जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी और परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया था।
- अपरशंख परियोजना में सृजित सिंचाई क्षमता (400 हेक्टेयर) का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि नहर में जल नहीं प्रवाहित किया गया था क्योंकि वितरण प्रणाली अपूर्ण थी।
- दिसम्बर 2012 तक विभाग द्वारा लघु सिंचाई परियोजनाओं (चेक बांधों) से संबंधित राज स्तरीय आँकड़ों को संकलित नहीं किया गया था। यद्यपि, चयनित जिलों में दिसम्बर 2012 तक का सिंचाई क्षमता से संबंधित उपयोगिता को **तालिका-5** में दिया गया है:

[38] प्रियोजनाएं 2011-12 में पूर्ण हो गई थी परन्तु उपयोगिता का आकलन 2012-13 में सिंचाई उपलब्ध कराने के बाद किया जाना था

तालिका-5: उपयोगित सृजित सिचाई क्षमता की विवरणी

(सिंचाई क्षमता (सि क्ष.) हैक्टेयर में)

क्र.सं	जिलों का नाम	पूर्व चेक डेमों की संख्या	सृजित सि. क्ष.	उपयोगित सि. क्ष. (प्रतिशत में)
1	कोडरमा	47	1564	553
2	हजारीबाग	19	855	445
3	पाकुर	17	905	9
4	रामगढ़	51	2012	384
5	गुमला	25	1442	95
6	साहेबगंज	22	634	482
7	पूर्वी सिंहभूम	39	3241	444
योग		**220**	**10653**	**2412 (23)**

(स्रोत: प्रमंडलों के प्रगति प्रतिवेदन)

तालिका-5 में जैसा कि वर्णित है, के सृजित सिंचाई क्षमता का केवल 23 *प्रतिशत* का उपयोग किया था। पूर्ण चेक बाँधों में 154 चेक बाँध सम्मिलित थे जिन्हें अप्रैल 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य निर्मित किया गया था परन्तु, उनके साथ माइक्रो लिफ्टों के अ-निर्माण के कारण अन्तर्विष्ट सिंचाई प्रदान नहीं कर रहे थे।

2.3.6 परियोजनाओं का अनुश्रवण

ए.आई.बी.पी. मार्गदर्शिका के अनुसार, केन्द्रीय जल कमीशन द्वारा वृहत/मध्यम परियोजनाओं का व्यापक भौतिक एवं वित्तीय अनुश्रवण करना था। लघु सिंचाई योजनाओं का अनुश्रवण राज्य सरकार द्वारा अपने आप निर्माण अभिकरणों से स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करना था। सीडब्लूसी को भी एमओडब्लूआर द्वारा तय पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध नमूना आधार पर इन योजनाओं का अनुश्रवण करना था।

संवीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला:

- केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्लू.सी.) वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संतुष्ट नहीं था। सीडब्लूसी द्वारा गुमानी परियोजना में जल मार्ग का अभी भी निर्माण करना, पंचखेरों जलाशय के संग्रहण एवं वितरण प्रणाली का अपूर्ण रहना, अपरखंश परियोजना का वितरणी प्रणाली का अपूर्ण रहना और निर्मित नहरों में कटाव एवं दरारों का रहना जैसे कार्यक्रम कियान्वयन में त्रृटियों का अवलोकन किया गया (अक्टूबर 2011 एवं मार्च 2012)। सीडबलूसी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं वितरक नहरों, लघु और जल मार्गों के सर्वेक्षण में विलम्ब अवलोकित किया गया।

सीडब्लूसी द्वारा सुझाव दिया गया कि फेजवार कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि कृषकों को सिंचाई जल मिलना प्रारंभ हो। यद्यपि दिसम्बर 2012 तक सीडब्लूसी द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था।

- परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए राजस्तरीय अनुश्रवण समिति[39] का गठन (फरवरी 2011) करना था। समिति को परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का समीक्षा करता था और नियत समय के अन्दर परियोजनाओं को पूर्णता के लिए नीति बनाना था। समिति द्वारा समीक्षा बैठकों (मार्च 2011 एवं दिसम्बर 2012 हुई) के जरिये से परियोजनाओं के प्रगति को अनुश्रवित किया गया परन्तु उनका अनुश्रवण 2010-12 के दौरान स्वीकृत लघु सिंचाई परियोजनाओं के समीक्षा तक ही सीमित था। यह निर्णय (दिसम्बर 2012) लिया गया कि चालू सिंचाई योजनाएं जनवरी 2013 तक पूर्ण हो जाए।
- लघु सिंचाई योजनाओं के अनुश्रवण के लिए, विभाग द्वारा एक तीसरे अभिकरण जल एवं ऊर्जा सलाहकार सेवाओं लिमिटेड को रखा गया (मई 2012) जिसे अपना प्रतिवेदन अक्टूबर 2012 तक प्रस्तुत करना था। यद्यपि, अभिकरण द्वारा दिसम्बर 2012 तक अनुश्रवण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- क्षेत्र स्तर पर मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा योजनाओं (वृहत एवं मध्यम) को अनुश्रवित किया जाता था, यद्यपि, सुधारात्मक उपायों जैसे सामयिक पर्यवेक्षण और भूमि अधिग्रहण, अनुबंधों की समाप्ति, प्राक्कलनों का संशोधन आदि यथा वार्षिक योजनाओं में आवर्ती रूप से वे कार्य सम्मिलित थे जिनकों संवेदकों द्वारा भूमि अधिग्रहण समस्याओं, अनुबंधित परिमाणों से विचलन दरों का पुराना हो जाना और कार्य जहाँ प्राक्कलन के संशोधन की आवश्यकता थी, को कार्य बंद कर दिया गया था।

[39] विशेष सचिव द्वरा, जल संसाधन विभाग के अन्य सदस्य गण प्रमुख्य अभियंता । एवं ॥, मुख्य अभियंता, योजना, अनुश्रवण एवं मुल्यांकन, अधिक्षण अभियंता, योजना एवं अनुश्रवण अंचल 1,2 एवं 3 तथा निदेशक, अनुश्रवण एवं अंकन केन्द्रीय जल आयोग्य

अत: परियोजनाओं का अनुश्रवण अनुपयुक्त था एवं कार्य समकालिक रीति से क्रियान्वित नहीं हो रहे थे। खेतों में जल पहुँचाने में कठोर कार्रवाई के अभाव के परिणामत: इन परयिोजनाओं में व्यापक निधियों को निवेशित करने के बावजूद बिना कोई लाभ दिये ये परियोजना निष्क्रिय पड़े थे।

2.3.7 निष्कर्ष

ए.आई.बी.पी. अपने शुरूआत से पाँच से बारह वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी चलन्त सिंचाई परियोजना के त्वरित पूर्णता एवं कृषकों को सिंचाई के जल के लाभ देने के लक्ष्यित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही। 1.20 लाख हेक्टेयर के सिंचाई क्षमता सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध मार्च 2012 तक राज्य द्वारा मात्र 0.45 लाख हेक्टेयर के सिंचाई क्षमता ही सृजित किया जा सका था। सभी तीन चयनित वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वयन की धीमी गति के कारण भारी रूप से भुगतना पड़ा। गुमानी बराज परियोजना का जलप्लावन क्षेत्र, पंचखेरों जलाशय का संग्रहण प्रणाली एवं सभी तीन परियोजनाओं का वितरण प्रणाली भूमि अधिग्रहण एवं वांछित सर्वेक्षण में विलम्ब के कारण अपूर्ण थे। लघु सिंचाई परियोजना का प्रगति भी निविदा प्रक्रिया में विलम्ब एवं कार्य की धीमी गति के कारण बाधित रहा। परियोजना (बाँध एवं मुख्य कार्य, मुख्य एवं शाखा नहर, वितरक एवं जल मार्गों) के विभिन्न अवयवों के समकालिक क्रियान्वयन के अभाव एवं बिना भूमि अधिग्रहण के कार्य के शुरूआत के कारण परियोजना क्रियान्वयन भी अपर्याप्त रहा। चयनित प्रमंडलों द्वारा आवंटित निधि को 33 *प्रतिशत्* उपयोग नहीं किया जा सका। एआईबीपी परियोजना के अन्तर्गत सृजित सिंचाई क्षमता का भी पूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अ-रखरखाव एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं में माइक्रो लिफ्ट के अ-संस्थापन के कारण पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया। परियोजना का अनुश्रवण भी भूमि अधिग्रहण, धीमी प्रगति, सर्वेक्षण आदि जैसे बाधाओं को हल करने में बहुत प्रभावशाली नहीं था।

2.3.8 अनुशंसायें

- *भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में शीघ्रता करनी चाहिए एवं वितरकों, लघु नहरों एवं जल मार्गों का सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को फेज वार पूर्ण किया जाना चाहिए जिससे कि सिंचाई का लाभ शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि किया जा सके। वार्षिक योजना स्थल की अवस्था एवं वास्तविक कार्य प्रगतिके निर्धारण के बाद तैयार किया जाना चाहिए।*

- *आवंटित निधि का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *माइक्रो लिफ्ट के संस्थापन्न संबंधी निर्णय प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए जिससे अन्तर्विष्ट सिंचाई क्षमता का पूर्ण चेक बाँधों से उपयोग किया जा सके।*
- *परियोजना की प्रगति के नियमित रूप से अनुश्रवित किया जाना चाहिए जिससे कि परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके।*

मामला सरकार को (सितम्बर 2012 एवं जनवरी 2013 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2013)।

पंचायती राज विभाग

2.4 पंचायत भवनों का निर्माण

2.4.1 परिचय

संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा देश में अधिक भागीदारी वाली शासन संरचना सुनिश्चित करने के लिये ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर एक त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई) को आर्थिक विकास के लिए सूक्ष्म योजना तैयार करने, सामाजिक-आर्थिक विकास पर लक्षित योजनाओं का कार्यान्वयन और भारत के संविधान की 11$^{वीं}$ अनुसूची में निर्धारित 29 विकास मदों के संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। इसके लिये राज्यों के पंचायतों को निधि, कार्यों एवं कार्यबलों को सौंपना था ताकि वे स्वशासित संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम हो सकें।

इसी उद्देश्य को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन (पं.भ.) बनाने का निर्णय लिया (मार्च 2002)। तदनुसार, पंचायत भवन निर्माण हेतु निधि का आवंटन राज्य निधि (2004-08), राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस. भी. वाई.) (2007-09), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ) (2008-12) से और भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (बी.एन.आर.जी.एस.के) सह पंचायत सचिवालय (2010-12) का निर्माण हेतु निधि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा) और बी.आर.जी.एफ के अभिसरण के तहत उपलब्ध कराई गई ।

पंचायत भवन का निर्माण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया था:

- सामाजिक-आर्थिक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करने के लिए;
- ग्राम सभा बैठकों, सभाओं और ग्रामीण विकास योजनाओं के चयन एवं कार्यान्वयन तथा श्रम बजट प्रस्तावों के लिए बैठक करने हेतु;
- मनरेगा के संबंध में ग्रामीण स्तर पर जानकारी प्रदान करने के लिए नागरिक उपयोग केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए;

- ग्राम पंचायत और प्रखण्ड कार्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी) सुविधा संचालित करने के लिए और पंचायत स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस) डाटा प्रवेश के लिए, और
- ग्रामीण जनता की शिकायतों के निवारण के लिए बैठक हेतु एक स्थल के रूप में इस्तेमाल के लिए।

इस प्रकार, स्थानीय स्वशासन के लिए सुविधा केन्द्र के रुप में पंचायत भवनों की योजना बनाई गई थी।

2.4.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली

2007-12 की अवधि से संबंधित पंचायत भवनों के निर्माण की लेखापरीक्षा यह देखने के लिए की गई कि पंचायत भवनों का निर्माण अनुमोदित लक्ष्य के अनुसार समय पर किया गया था तथा उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा था जिसके लिए परिकल्पना की गई थी एवं इसके लिए निर्गत राशि का प्रबंधन कुशलता पूर्वक किया गया और परियोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण सुचारु रुप से किया गया था। अप्रैल और जुलाई 2012 के दौरान पंचायती राज विभाग एवं आठ[1] जिलों के 18[2] प्रखण्डों के अंतर्गत 175 पंचायतों (***परिशिष्ट-2.23***) के कार्यान्वयन एजेंसियों[3] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच लेखा परीक्षा के दौरान की गई। हमने कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से 31 पंचायत भवनों का भौतिक निरीक्षण भी किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.3 योजना

ससमय और प्रभावी लागत पर कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक उचित योजना जरूरी है। झारखण्ड सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण का निर्णय किया (मार्च 2002) ताकि पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के चुनाव के पश्चात् निर्वाचित निकाय अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सके। तदनुसार, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा सभी 4,423 ग्राम पंचायत में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए निर्देश जारी किये गये (अगस्त 2002) ताकि ग्रामीणों के लाभ के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर

---

1 चतरा, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा

2 चंदवा, चतरा, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, घाटशिला, गोविंदपुर, इट्खोरि, जामताड़ा, काड़ा, कोलेबिरा, कुरु, लातेहार, लोहरदगा, मधुपुर, नारायणपुर, पलजोरि और सिमडेगा

3 प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), जिला योजना कार्यालय (DPO), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार विकास कार्यक्रम), ग्रामीण विकास विशेष.प्रभाग, ग्रामीण निर्माण प्रभागों और जिला परिषदों

पदस्थापित राज्य सरकार कर्मचारी, एक ही छत के नीचे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार, ने प्रारंभ में ₹ 17.48 लाख की लागत पर प्रत्येक पंचायत भवन के निर्माण के लिए एक मॉडल प्राक्कलन (मार्च 2003) तैयार किया गया। हाँलाकि, अनूसूचित दर 2005 के अनुसार प्राक्कलन संशोधित कर ₹ 19.00 लाख किया गया (जुलाई 2005) । 2003-04 से 2006-07 तक राज्य योजना निधि से 188 पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई ।

मॉडल प्राक्कलन को पुन: संशोधित (मई 2007) कर ₹ 16.24 लाख किया गया था और राज्य योजना से 479 पंचायत भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार ने उपायुक्तों/उप विकास आयुक्तों को बी.आर.जी.एफ के वार्षिक कार्ययोजना में पंचायत भवन के निर्माण को सम्मिलित करने का निर्देश जारी किया (जून 2007)।

पंचायती राज विभाग से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर, हमने पाया कि राज्य निधि, राष्ट्रीय सम विकास योजना, बी.आर.जी.एफ एवं मनरेगा एवं बी.आर.जी.एफ के अभिसरण से मार्च 2012 तक 4072 पंचायत भवनों के निर्माण की योजना बनाई गई, जैसा कि **तालिका-1** में दर्ज है:

तालिका-1: पंचायत भवनों का योजना वार निर्माण

क्र.संख्या	वर्ष	राज्य योजना	आरएसवी वाई	बीआर जीएफ	मनरेगा और बीआरजीएफ की अभिसरण	कुल	पंचायत भवनों की संख्या।	
							पूर्ण	अपूर्ण
1	2007-08 से पहले	188	-	--	--	188	1729	2343
2	2007-08	479	135	--	--	614		
3	2008-09	–	71	1023	--	1094		
4	2009-10	–	-	507	73	580		
5	2010-11	–	-	323	1273	1596		
6	2011-12	–	-	--	--	0		
कूल		**667**	**206**	**1853**	**1346**	**4072**	**1729**	**2343**

(स्रोत: पंचायती राज विभाग)

इस प्रकार, अगस्त 2002 में झारखण्ड सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में 4,423 पंचायत भवनों के निर्माण के विरुद्ध केवल 4,072 पंचायत भवनों का

निर्माण स्वीकृत एवं आरंभ किया गया जबकि 351 पंचायत भवनों के निर्माण की योजना नहीं बनाई गई (मार्च 2012)। इस प्रकार, सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्णय लेने के 10 वर्षों के बाद भी पूरा नहीं हो सका है।

- कुल 4,072 ग्राम पंचायतों में केवल 1,729 (42.46 *प्रतिशत*) ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्ण थे (मार्च 2012) एवं 2,343 (57.54 *प्रतिशत*) पंचायत भवन अभी भी निर्माणाधीन थे (जुलाई 2012)। पंचायती राज विभाग के पास योजनावार पूर्ण पंचायत भवनों की सूची उपलब्ध नहीं थी।
- नमूना जाँच हेतु चयनित आठ जिलों में 169[4] पंचायत भवनों के अभिलेखों की विस्तृत जाँच से यह पता चला कि केवल 61 पंचायत भवन ₹ 12.13 करोड़ (***परिशिष्ट-2.24***) के व्यय से पूर्ण हुए, जिनके पूर्ण होने में 02 से 40 माह तक का विलम्ब हुआ जबकि 108 पंचायत भवन ₹ 11.63 करोड़ (***परिशिष्ट-2.25***) के व्यय के उपरान्त अभी भी अपूर्ण थे।

इसके अलावा, 61 पूर्ण पंचायत भवनों में से, केवल 27 पंचायत भवनों को उनके पूर्ण होने की तिथि से 14 माह तक विलम्ब से 2010-11 के दौरान ग्राम पंचायतों को सौंपा गया । इन पंचायत भवनों का उपयोग सभाओं और बैठकों के आयोजन, योजनाओं का चयन एवं निष्पादन से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया, लेकिन बिजली संयोजन के अभाव में, अभिलेखों के आँकडों एवं एम.आई.एस. की प्रविष्टि नहीं की जा रही थी। वर्तमान में, इन कार्यों को प्रखण्ड कार्यालयों में संपादित किया जा रहा था। शेष 34 पंचायत भवनों को पंचायत प्राधिकारियों को नहीं सौंपा गया है जबकि इन्हें 42 माह पूर्व तक पूरा कर लिया गया है (मार्च 2012), जैसा कि कार्यान्वयन एजेंसियों की प्रगति प्रतिवेदन में परिलक्षित होता है। यद्धपि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम अधिकारी की यह जिम्मेदारी थी कि पूर्ण पंचायत भवनों को ग्राम पंचायतों को हस्तगत करें किन्तु ऐसा नहीं करने के लिए न ही कोई कारण अभिलेखों में दर्ज था और न ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा को बताया गया।

इस प्रकार, ₹ 11.63 करोड़ व्यय करने के बाद भी 108 पंचायत भवन अपूर्ण रहे। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों द्वारा बिजली और पानी संयोजन आदि प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण पूर्ण पंचायत भवन भी

[4] चार पंचायत भवनों का निर्माण किसी भी योजना से शुरू नहीं हुआ था ।

पूर्ण रुप से परिचालित नहीं थे। अत: इन पंचायत भवनों पर किया गया व्यय ₹ 12.13 करोड़ आंशिक रूप से ही उपयोगी था।

2.4.4 वित्तीय प्रबंधन

2.4.4.1 निधि का आवंटन एवं व्यय

जिलों ने राज्य योजना निधि, आर.एस.भी.वाई, बी.आर.जी.एफ. और मनरेगा से निधि प्राप्त किया। इसके बाद, पंचायत भवन के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी किए गए। चयनित आठ जिलों में वर्ष 2007-12 के दौरान निधि का आवंटन और उपयोग का विवरण **तालिका-2** में दिया गया है-

तालिका-2: वर्ष 2007-12 के दौरान चयनित आठ जिलों में पंचायत भवन के निर्माण पर व्यय एवं आवंटन

(₹ करोड़ में)

जिलों का नाम।	निर्माण किये जाने वाले पंचायत भवनों की संख्या	अनुमानित लागत	निर्गत राशि	व्यय	अव्ययित शेष	पंचायत भवन की स्थिति		
						पूर्ण	अपूर्ण	परित्यक्त/ निलंबित
चतरा	156	30.34	21.32	14.91	6.41	27	129	0
लातेहार	115	24.21	16.89	15.65	1.24	34	81	0
सिमडेगा	94	17.21	14.41	13.76	0.65	71	22	1
धनबाद	263	40.48	36.38	27.83	8.55	89	174	0
जामताड़ा	113	23.75	45.42	19.61	25.81	71	41	1
लोहरदगा	59	11.60	10.56	8.98	1.58	28	29	2
देवघर	201	27.79	27.75	24.2	3.55	95	106	0
पूर्वी सिंहभूम	199	43.63	28.36	26.84	1.52	57	142	0
कुल	**1200**	**219.01**	**201.09**	**151.78**	**49.31**	**472**	**724**	**4**

(स्रोत: पंचायती राज विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

निर्गत ₹ 201.09 करोड़ में से ₹ 151.78 करोड़ (75.48 *प्रतिशत*) चयनित जिलों में खर्च किया गया था

जैसा कि **तालिका-2** से स्पष्ट है ₹ 219.01 करोड़ के प्राक्कलित लागत के विरुद्ध 2007-12 के दौरान 1200 पंचायत भवनों के लिये ₹ 201.09 करोड़ निर्गत (91.84 *प्रतिशत*) किया गया, जिसमें से ₹ 151.78 करोड़ (75.48 *प्रतिशत*) व्यय किया गया तथा शेष ₹ 49.31 करोड़ अनुपयुक्त रहा। 1,200 पंचायत भवनों में से, 472 पंचायत भवन पूर्ण थे, 724 पंचायत भवन अपूर्ण थे जबकि 4 पंचायत भवन परित्यक्त/निलंबित थे।

इस प्रकार, जहाँ एक तरफ निधि अव्यहृत रहा दूसरी ओर पंचायत भवन अपूर्ण थे जिससे योजना का लक्षित उददेश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.4.4.2 निधि का अनियमित प्रतिधारण

झारखण्ड कोषागार संहिता, खंड-I का नियम 611 निर्धारित करता है कि विभागीय या संबद्ध प्रयोजनों के लिए सरकारी कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी के विशेष आदेश के तहत दिये गये अग्रिम, जिस सरकारी कर्मचारी, के लिए स्वीकृत किया गया है, की प्राप्ति एवं उत्तरदायित्व पर, को आहरित किया जा सकता है यदि प्रमाणक द्वारा समर्थित विस्तृत लेखा प्रस्तुत कर समायोजन किया जाए या वापस किया जाए, जैसा आवश्यक हो। इसके अलावा, लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 100 में प्रावधान है कि अग्रिम, पारित किए गए प्रमाणक पर सरकारी कर्मचारियों को, प्रदान किया जाता है जिसे जितनी जल्दी हो सके आहरित अग्रिम के लिए विपत्र जमा करना आवश्यक है। आगे कोई अग्रिम पिछले अग्रिम के समायोजन वसूली के बिना सरकारी कर्मचारी को नहीं दी जा सकती है। अग्रिम के समायोजन के अभिश्रवण हेतु अग्रिम पंजी संधारित किया जाना था।

जिला परिषद, चतरा के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि जिला अभियंता द्वारा सहायक अभियंता को राज्य निधि से मोकतमा पंचायत भवन के निर्माण के लिए प्राक्कलित राशि ₹ 19 लाख के विरुद्ध ₹ 16 लाख का अग्रिम दिया गया था(अगस्त 2007 एवं अप्रैल 2008)। योजना संचिका, मापी-पुस्तिका, अभिश्रव एवं अन्य संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरुप यह पता नहीं लगाया जा सका कि पंचायत भवन का निर्माण पूरा हो चुका है या आरंभ भी हुआ या नहीं। अग्रिम असमायोजित रहा (जून 2012)।

अंकेक्षण पृच्छा पर जिला अभियंता, जिला परिषद, चतरा द्वारा बताया गया (सितम्बर 2012) कि दोषी के खिलाफ नीलामपत्र वाद मामला दायर करने के लिए जिला नीलाम वाद पदाधिकारी, चतरा को एक पत्र भेजा गया है ।

2.4.4.3 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से गबन

उपायुक्त,चतरा द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से ₹ 19.91 लाख प्रति पंचायत भवन की दर से ₹ 3.38 करोड़ के प्राक्कलित लागत का 17 पंचायत भवन[5] जिला परिषद को आवंटित किया गया (दिसम्बर 2008)। इसमें से जनवरी 2009 में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 1.70 करोड़ जिला अभियंता को उपलब्ध कराया गया था। पूरी राशि श्री ललन चौधरी, सहायक

[5] कोयद, कल्यानपुर, टण्ड्वा प्रखण्ड में बेन्टिचुरि(उत्तर), कुंदा प्रखण्ड में मर्गाडा बभ्ने, राम्पुर, प्रतापपुर प्रखण्ड में सिड्की, गिद्धोर में गिद्धोर प्रखण्ड , टरवागडा, काटिया, टिल्हेट, करैलिबार, जाब्डा, हण्टरगंज प्रखण्ड में उरैलि और चतरा प्रखण्ड में जम्मरिबक्स्पुरा, डम्डोइया

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष में से ₹ 1.70 करोड़ की राशि का गबन था

अभियंता को पंचायत भवन के निर्माण के लिए अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराई गई थी (जनवरी 2009)। हाँलाकि उन्होंने न तो पिछले अग्रिम का समायोजन विपत्र और अभिश्रव प्रस्तुत किया और न ही मोकतमा पंचायत भवन के निर्माण हेतु उपलब्घ कराई गई राशि वापस किया। जुलाई 2007 और अप्रैल 2008 में उन्हें दिया गया अग्रिम संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। 17 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए समायोजन अभिश्रव 42 महीने (जून 2012) के समाप्त होने के बाद भी नहीं प्रस्तुत किया गया।

अभिलेखों की जाँच से पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, चतरा द्वारा 17 जून 2009 को सहायक अभियंता और अन्य व्यक्तियों (छह सेवा निवृत्त जिला अभियंता, एक सेवा निवृत्त कनीय अभियंता व एक जिला अभियंता) के विरुद्ध सरकारी राशि के गबन हेतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर सं.134/09) दर्ज किया गया है, लेकिन ₹ 1.70 करोड़ का अग्रिम समायोजित/वसूल किया जाना अभी भी बाकी है (जून 2012)।

अग्रिम का समायोजन नहीं हुआ था क्योंकि अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया जाता था जिससे असमायोजित अग्रिम की वसूली पर नजर रख सके एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया जा सके। इस तरह, उपविकास आयुक्त द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को दिए गए अग्रिमों के समायोजन/वसूली के संबंघ में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतते हुए संबंधित सहायक अभियंता को पूर्व के अग्रिम असमायोजित रहते हुए भी लगातार अग्रिम दिया गया ।

2.4.4.4 फर्जी अभिश्रव पर भुगतान

नियम 34 के साथ पठित झारखण्ड वितीय नियमावली के नियम-12 के अनुसार प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि जनता के पैसे की हानि खिलाफ निर्धारित जाँच को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण सरकार को हुई नुकसान के लिए सरकारी कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

₹ 7.38 लाख का भुगतान नकली टिन वाले वाउचर पर किया गया था

बाघुरिया, माहुलिया और उल्दा पंचायत भवनों के पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला प्रखण्ड के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाटशिला द्वारा मेसर्स आमला मटेरियल्स, घाटशिला को (ईंट, स्टील, सिमेंन्ट, गिट्टी और बालू) के क्रय के विरूद्ध ₹ 7.38 लाख का भुगतान अगस्त 2011 और फरवरी 2012 के मध्य किया गया। विपत्र के अनुसार डीलर का कर पहचान संख्या (TIN) 20562405243 था। अभिश्रव का विवरण **तालिका-3** पर है ।

तालिका-3: फर्जी अभिश्रव पर भुगतान की विवरणी

क्रम.सख्या	विपत्र संख्या/दिनांक	राशि (₹ में)
1.	08/3.9.11	39446
2.	48/8.2.12	93250
3.	66/14.9.11	33448
4.	69/11.8.11	81295
5.	70/12.8.11	84154
6.	71/17.10.11	109505
7.	87/2.12.11	165742
8.	88/23.11.11	64190
9.	89/22.11.11	57966
10.	156/28.1.12	9302
कुल		**738298**

(स्रोतः प्रखण्ड का योजना संचिकाएं)

जैसा कि **तालिका-3** से स्पष्ट है कि बिल सं.69 और 70, अगस्त 2011 में जारी किये गये थे जबकि बिल सं.08 और 66 सितम्बर 2011 में बिल सं. 88 एंव 89 नवम्बर 2011 में, 87 दिसम्बर 2011 में, 156 जनवरी 2012 में औऱ 48 फरवरी 2012 में जारी किए गए थे जो कि क्रमागत संख्या के अनुसार अनियमित है। इसके अलावा, वाणिज्यिक कर विभाग के वेबसाइट पर दुकान के कर पहचान संख्या के सत्यापन पर पाया गया कि वह कर पहचान संख्या किसी भी फर्म को जारी नहीं किया गया है, जिसे वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा भी सम्पुष्ट किया गया है।

इस प्रकार विपत्र के असली होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है और ₹ 7.38 लाख के भुगतान फर्जी बिल पर होने को नकारा नहीं जा सकता है।

लेखापरीक्षा पृच्छा करने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा विपत्र के असलियत के बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया।

2.4.4.5 असमायोजित अग्रिम

लोहरदगा जिला के सलगी पंचायत भवन निर्माण से संबंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडु द्वारा प्राक्कलित राशि ₹ 16.24 लाख के विरुद्ध ₹ 13.72 लाख का अग्रिम (अक्टुबर 2007 से मई 2009 के मध्य) सदस्य सचिव, कैरो लैम्पस को पंचायत भवन निर्माण के लिये दिया गया। कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि मार्च 2008 थी। चतुर्थ

चलन्त लेखा विपत्र (मार्च 2009) के समय ₹ 10.68 लाख का कार्य मापी किया गया था। कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा नौ महीने के पश्चात (दिसम्बर 2009) ₹ 14.29 लाख का पांचवाँ चलन्त लेखा विपत्र बिना के ₹ 3.61 लाख (₹ 14.29 लाख-₹ 10.68 लाख) के अभिश्रव व मस्टर रोल को प्रस्तुत किया गया। पूर्ण होने की निधारित तिथि से 4 चार साल बीत जाने के बाद भी कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है (अप्रैल 2012)।

इस प्रकार पूर्ण करने की निधारित तिथि के पश्चात सितम्बर 2008 और मई 2009 के बीच पांचवाँ और उसके बाद दिये गये अग्रिम ₹ 3.04 लाख (₹ 13.72 लाख-₹ 10.68 लाख) जिसका समायोजन अभिश्रव कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जमा नहीं किया गया, सरकारी राशि दुर्विनियोजित/गबन का जोखिम भरा मामला हो सकता है।

पृच्छा करने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडु द्वारा कहा गया कि (अप्रैल 2012) सदस्य सचिव, लैम्पस को मस्टर रोल एंव अभिश्रव जमा करने के लिए कहा गया है जिससे अग्रिम का समायोजन हो सके।

तथ्य यह है कि तीन साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुडु द्वारा दोषी के खिलाफ न तो अग्रिम के समायोजन हेतु और न ही कार्य पूर्ण करने हेतु कोई कार्रवाई की गई।

2.4.4.6 निधि का अवरोधन

पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देशों (जुलाई 2007) के अनुसार, उप विकास आयुक्त (जिला परिषद के प्रशासनिक प्रमुख) पंचायत भवन के निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग से प्राप्त अनुदान को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को हस्तांतरित करेगें। उप विकास आयुक्त के स्वीकृति आदेश के जारी होने की तारीख से छः से सात महीनों के भीतर पंचायत भवनों का पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगे और विभाग को मासिक भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करेंगें।

आठ जिलों के अभिलेखों के नमूना जाँच से तीन[6] जिलों में ज्ञात हुआ कि

पंचायती राज विभाग द्वारा 2007 से 2011 के बीच तीन जिलों[7] के उप विकास आयुक्तों को 40 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु ₹ 6.50 करोड़ दिया

[6] चतरा, पूर्वी सिंहभूम और लातेहार

[7] चतरा (18), पूर्वी सिंहभूम (13) और लातेहार (9)

गया जिसके विरुद्ध ₹ 4.62 करोड़ प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों[8] एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया गया तथा शेष ₹ 1.88 करोड़ उप विकास आयुक्त के पास मार्च 2011 से बचे रहे जो कि विभाग के आदेश का उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट रुप से निर्देश दिया गया था कि आवंटित राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाए।

लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा करने पर (अप्रैल से जूलाई 2012 तक) जिला अभियंता, चतरा द्वारा कहा गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को योजना की अद्यतन स्थिति बताने के लिए कहा गया है जिससे कि कार्य के मूल्यांकन के पश्चात राशि/शेष आवंटन निर्गत किया जा सके।

जिला अभियंता, चतरा का उत्तर यह पुष्टि करता है कि उप विकास आयुक्त कार्य की प्रगति की निगरानी नहीं कर रहे थे।

- पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जिला परिषद चतरा को छ:[9] पंचायत भवनों के निर्माण के लिये 2004-07 के मध्य ₹ 1.11 करोड़ निर्गत किए गए। कार्य छ: (06) माह में पूरा करना था।

सात कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्गत ₹ 69.50 लाख अप्रयुक्त रहा

अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि निर्गत ₹ 1.11 करोड़ के विरूध्द ₹ 90 लाख (मार्च 2012) खर्च करने के वावजूद सभी छ: पंचायत भवन अपूर्ण थे एवं शेष ₹ 21 लाख अप्रयुक्त/अव्ययित रहा।

- देवघर में 21 भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र व लोहरदगा में एक पंचायत भवन का निर्माण करने हेतु सात[10] कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 69.50 लाख (2010-11) निर्गत किया गया जो कि फरवरी 2011 से अप्रयुक्त था तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पड़ा हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा करने पर, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद देवघर द्वारा आदेश की एक प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार जिला अभियंता/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास (विशेष प्रमण्डल) एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर 21 सेवा केन्द्र (देवघर) का निर्माण रद्द कर दिया गया है (दिसम्बर 2011) क्योंकि निर्माण संभव नहीं था। हालांकि इसका कारण अभिलेख में उल्लेखित नहीं था। लोहरदगा जिला में

---

8 चतरा-प्रखण्ड चतरा, गिद्दौर, हटरगंज, ईटखोरी,लावालौंग,मयूरहंड, पत्थलगडा, प्रतापपुर, सिमरिया औरर टंडवा, लातेहार प्रखण्ड बरवाडीह, बालुमाथ, चंदवा, लातेहार और महुआताड़ और पूर्वी सिंहभूम प्रखण्ड बहरागोड़ा, धालभूमगढ, घाटशिला, जमशेदपुर, मुसावनी और पटमदा।

9 चतरा जिला में बगरा, गाडिलौग, जोरी, कान्हाचट्टी, मोकतमा और पितिज(प.)

10 जिला परिषद देवघर(13) ग्रामीण विकास (विशेष) डिवीजन(2) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी देवघर(1) मोहनपूर(2) सरवन(2) सारठ(1) और जिला परिषद लोहरदगा(1)

एक पंचायत भवन का निर्माण रद्द होने के बारे में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सेन्हा ने कहा कि दुर्गम एवं पहाड़ी जगह होने के कारण निर्माण शुरू नहीं किया जा सका।

इसका मतलब यह है कि पंचायत भवन के निर्माण हेतु स्थल का चयन उचित प्रक्रिया द्वारा नहीं किया गया जिससे पंचायत भवन का निर्माण पूरा नहीं हो सका। इस प्रकार, इन भवनों को पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग करने का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका।

2.4.4.7 भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना पंचायत भवन का निर्माण

उपायुक्त द्वारा जारी आदेश (मार्च 2009) के अनुसार पंचायत भवन का निर्माण सरकारी भूमि पर करना था और सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में पंचायत भवन का निर्माण रैयती[11] भूमि पर उसके वास्तविक स्वामी द्वारा निबंधित अधिकारपत्र (डीड) द्वारा उक्त भूमि का दान महामहिम राज्यपाल के नाम करने के उपरांत ही योजना पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा अन्यथा कार्यारंभ के पश्चात किसी प्रकार के भूमि संबंधी विवाद होने पर इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित कार्यान्वयन अभिकरणों की होगी।

स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना 11 पंचायत भवन के निर्माण रैयती भूमि पर किया गया

तीन जिलों[12] के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ऊपरोक्त प्रावधान के विपरीत वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक ₹ 1.97 करोड़ खर्च भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना रैयती भूमि पर 11[13] पंचायत भवन के निर्माण पर किया गया इसके बदले में जमीन मालिकों से नोटरी हलफनामों द्वारा स्थल प्राप्त किया गया जो कि अनियमित और नियमों का विचलन कर कुल ₹ 1.33 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा (अप्रैल 12 से जूलाई 12 तक) करने पर इसका कोई कारण कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा नहीं बताया गया कि क्यों भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण किए बिना निर्माण कार्य शुरू किया गया था ।

2.4.4.8 मनरेगा निधि से अनियमित व्यय

भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र सह पंचायत सचिवालय के निर्माण हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देश के कंडिका '6' के अनुसार मनरेगा निधि से

---

[11] निजी भूमि (रैयती)

[12] चतरा सिमडेगा और लातेहार

[13] चंदवा पूर्वी प भ (चंदवा) करनी मलकपुर (ईटखोरी) बंगरू कूल्लूकेरा अधरमा डोमटोली (कोलेबिरा) नवाटोली रैसिया शाहपूर बेंदी (लातेहार)

अधिकतम अनुमत्य व्यय की राशि ₹ 10 लाख है। हमने पाया कि ₹ 10 लाख की अधिकतम सीमा का लातेहार में 33 पंचायत भवनों एवं जामताड़ा जिला में 03 पंचायत भवनों के निर्माण में उल्लंघन किया गया।

- उपायुक्त, लातेहार द्वारा 2010-11 में अभिसरण योजना के तहत 33 पंचायत भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक भवन के लिए प्राक्कलित राशि ₹ 24.50 लाख रू0 थी। ₹ 24.50 लाख में से मनरेगा निधि से स्वीकार्य सीमा ₹ 10 लाख के विरूद्ध ₹ 13.50 लाख आवंटित किया गया एवं बी.आर.जी.एफ. से ₹ 11 लाख आवंटित किया गया। इसके फलस्वरूप मनरेगा निधि से प्रत्येक योजना के लिए ₹ 3.50 लाख का अतिरिक्त आवंटन हुआ।

  मनरेगा निधि से ₹ 1.16 करोड़ की राशि का अनियमित विचलन

  इस प्रकार 33 पंचायत भवनों के निर्माण में मनरेगा निधि से ₹ 1.16 करोड़ की राशि का अनियमित विचलन किया गया।

- जामताड़ा जिले में अभिसरण योजनाओं के तहत तीन[14] पंचायत भवनों के निर्माण (2010-11) के अभिलेखों की जाँच से पता चलता है कि सम्पूर्ण राशि ₹ 59.80 लाख मनरेगा निधि से व्यय की गई जिसके फलस्वरूप ₹ 29.80 लाख (₹ 59.80-₹ 30 लाख) की राशि का व्यय मनरेगा निधि के तय सीमा से अधिक की गई थी।

  प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा कहा गया (जूलाई 2012) कि बी.आर.जी.एफ. निधि से आवंटन की प्रत्याशा में मनरेगा निधि का उपयोग किया गया।

  जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किया गया व्यय बी.एन.आर.जी.एस.के दिशा निर्देश के विरूद्ध था।

2.4.4.9 पंचायत भवनों का अनियमित उपयोग

राज्य एवं बी.एन.आर.जी.एस.के. के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत भवनों का निर्माण का उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं के चयन एवं कार्यान्वयन हेतु ग्राम सभा की बैठकों/सभा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत कार्यालय के रूप में उपयोग करने, मनरेगा से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु नागरिक सुविधा केन्द्र एवं ग्राम स्तर पर आई.सी.टी. सुविधाओं का संचालन करने के लिए किया गया था ।

[14] जामताडा में बेवा लाधमा और सूपाईडीह

हालांकि, योजना अभिलेखों की जाँच एवं चयनित जिलों में 31 पंचायत भवनों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि छः पूर्ण पंचायत भवनों का (केवल सोनबाद पंचायत भवन को सौंपा गया था) का अनियमित उपयोग अयोग्य कब्जादारों द्वारा किया जा रहा था। जो निम्न प्रकार है:

- नारायणपुर (जामताड़ा जिला) एवं चंदवा (लातेहार जिला) में निर्मित दो पंचायत भवनों[15] को पुलिस विभाग द्वारा क्रमशः जनवरी 2011 एव जून 2011 से कब्जा कर लिया गया था।





(पुलिस विभाग द्वारा देवलबारी पंचायत भवन कब्जा कर लिया गया था।)
(फोटो 4 जुलाई 2012 को लिया गया)

- उदलबानी (जामताड़ा जिला) में एक पंचायत भवन पर अग्निशमन विभाग द्वारा जूलाई 2010 से कब्जा था।
- घाटशिला प्रखण्ड (पूर्वी सिंहभूम जिला) एवं चतरा प्रखण्ड (चतरा जिला) के दो पंचायत भवनों का, प्रखण्ड कार्यालय के रूप में, उपयोग किया जा रहा था।
- जामताड़ा जिले में एक पंचायत भवन (सोनबाद जिसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया था) को गोदाम में परिवर्तित कर राज्य खाद्य निगम (रा.खा.नि.) द्वारा अनाजों का भंडारण किया जा रहा था। जैसा कि नीचे दिये गये चित्र में दर्शाया गया है:



जामताड़ा में सोनबाद पंचायत भवन

[15] नारायणपुर में देवलबारी पंचायत भवन एवं चंदवा प्रखण्ड में बोदा

इसे बताये जाने पर उपविकास आयुक्त, जामताड़ा ने कहा (जुलाई 2012) की देवलबारी पंचायत भवन का निर्माण दूरदराज जगह पर अर्थात जामताड़ा एवं गिरिडीह जिलों की सीमा पर किया गया था एवं कानून व्यवस्था की समस्या के कारण एक पुलिस शिविर अस्थायी रूप से तैनात किया गया था। हालांकि पुलिस अधीक्षक से शिविर हटाने के लिए अनुरोध किया गया है। उदलबानी पंचायत भवन के संबंध में उप विकास आयुक्त ने कहा (जुलाई 2012) कि अग्निशमन विभाग के लिए एक भवन का निर्माण कर लिया गया है एवं जिला उपायुक्त, जामताड़ा से पंचायत भवन खाली कराने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन जून 2012 तक खाली नहीं किया गया था।

घाटशिला में धरमबहाल पंचायत के लिए बनाये गये पंचायत भवन का उपयोग प्रखण्ड कार्यालय के लिए किया जा रहा था, इसलिए मुखिया ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाटशिला से अनुरोध (अपैल 2011) किया था कि दूसरे स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जाय परंतु जून 2012 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाटशिला ने जवाब दिया (सितम्बर 2012) कि मौजूदा भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था इसलिए प्रखण्ड कार्यालय पंचायत भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार सभी छः पंचायत भवनों में अनाधिकृत कब्जे के कारण पंचायत भवनों का निर्माण के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

2.4.5. अनुश्रवण

निगरानी एवं पर्यवेक्षण प्रभावी नहीं था

पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों (सितम्बर 2007) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करने के लिए ग्राम सभा द्वारा एक निगरानी समिति गठित किया जाना चाहिए। जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा भी ऐसे निगरानी समिति के लिए दिशा निर्देश (जून 2007 में) जारी किये गये। निगरानी का उद्देश्य योजनाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं क्रियान्वयन दक्षता में सुधार और ससमय पूरा करना था।

हमने देखा कि हाँलाकि सभी नमूना जाँच किए गए ग्राम पंचायतों में इन समितियों का गठन किया गया था पर निरीक्षण के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन, यदि किया गया हो तो, उपलब्ध नहीं था।

विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश (जूलाई 2007) में भी उपविकास आयुक्त को कार्यों की स्थिति दर्शाते हुए मासिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को भेजने का निर्देश था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण राजीव गाँधी

सेवा केन्द्र के संबंध में जारी दिशा निर्देशों (जनवरी 2010) के अनुसार भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र सह पंचायत सचिवालय भवनों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ससमय पूरा करने की जिम्मेदारी उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी) की थी।

हमने देखा कि बीआरजीएफ/मनरेगा के साथ बीआरजीएफ के अभिसरण के तहत् निर्मित पंचायत भवनों के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए एवं उपायुक्त को समर्पित किये गये जबकि राज्य योजना से निर्मित पंचायत भवनों के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा उप विकास आयुक्तों को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसका तात्पर्य था कि पंचायती राज विभाग राज्य योजना से निर्मित पंचायत भवन के निर्माण की स्थिति से अनभिज्ञ था.

पंचायत भवन के गुणात्मक और समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए अभिश्रवण तंत्र के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में, केवल उपविकास आयुक्त, जामताड़ा (जुलाई 2012) ने कहा कि समय-समय पर स्थल निरीक्षण किया गया था और मौखिक निर्देश जारी किए गए थे, जबकि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास (विशेष प्रमण्डल), चतरा ने कहा (सितम्बर 2012) कि कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा समय-समय पर कार्य का निरीक्षण किया गया था.

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभिश्रवण व्यवस्था प्रभावी नहीं थी, क्योंकि 108 पंचायत भवन पूरा होने की निर्धारित तिथि के काफी समय बाद भी (3 से 58 महीने तक) अपूर्ण रहे।

2.4.6 निष्कर्ष

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन प्रदान करने का उद्देश्य अधूरा रहा चूंकि जून 2012 तक कुल 4,423 ग्राम पंचायतों के विरूध्द, 2,694 पंचायत भवन अभी भी अपूर्ण/आरंभ नहीं किए गए थे। हमने विभिन्न स्तरों पर अप्रभावी योजना, वितीय कुप्रबंधन एवं योजनाओं का नियमित पर्यवेक्षण एवं अभिश्रवण के अभाव का दृष्टान्त देखा। इसके अलावा, कुछ पंचायत भवन यद्यपि पूर्ण कर लिए गए थे लेकिन या तो वे सौंपे नहीं गये थे या जिस उद्देश्य के लिए बनाये गए थे उसके लिए उपयोग नहीं किए जा रहे थे।

परिणाम स्वरूप, स्थानीय स्वशासन की सहायता हेतु पंचायत भवनों को सुविधाकेन्द्र के रूप में विकसित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

2.4.7 अनुशंसाएं

- *योजना के दिशानिर्देश एवं आदेशों के अनुरूप निर्गत निधियों की उपयोगिता एवं कार्य की ससमय पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण एवं अभिश्रवण किया जाना चाहिए।*
- *भविष्य में वाद विवाद से बचने के लिए निर्माण शुरू करने से पूर्व स्थल चयन में सतर्कता एवं निजी भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *पंचायत भवनों के पूर्ण होने पर तुरंत ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि उनके निर्माण में निहित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।*

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2012) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2013) ।

अध्याय -3
जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा

अध्याय-3

3.1 पलामू का जिला केंद्रित लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

पलामू का जिला केंद्रित लेखा परीक्षा जिला में वित्तीय मामलों में एवं महत्वपूर्ण समाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति को मुख्य रूप से उजागर करती है। प्रतिवेदन में संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), मध्याहन भोजन (एम.डी.एम.) कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एन.आर.एच.एम.), समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.), आपदा प्रबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता, राज्य सड़क और पुलिस आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं को सन्निहित कर तैयार की गई है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा बिन्दु नीचे उद्धित है:

- किसी खास समय में सम्पूर्ण प्रक्षेत्रवार जिला में निधि का प्रवाह को दर्शाने की कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। पलामू में जिला योजना समिति का गठन संविधान के 74$^{वें}$ संशोधन के 18 वर्ष बाद दिसम्बर 2011 में किया गया। जिला योजना समिति की बैठक सिर्फ एक ही बार हुई और इसकी कार्यप्रणाली दिखावटी एवं अपूर्ण रही। जिले का पंचवर्षीय विस्तृत योजना एवं वार्षिक कार्य योजना भी नहीं तैयार किया गया। अधिनियम के अंतर्गत निधि, कार्य एवं कार्यन्वयन का हस्तांतरण पंचायती राज संस्था (पी.आर.आई.) को भी नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)

  सरकार को योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पी.आर.आई. की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए।

- एस.एस.ए. के अस्तित्व के बावजूद काफी संख्या में बच्चे स्कूल में नामांकित नहीं थे, निर्धारित मापदण्ड के विरूद्ध छात्र-शिक्षक का अनुपात (पी.टी.आर.) नीचे था और पी.टी.आर. जिला मुख्यालय से दूर प्रखण्डों में काफी खराब था। काफी संख्या में भवनों एवं कक्षा का निमार्ण या तो अपूर्ण था या बीच में ही जमीन के अभाव में रोक दिया गया था। बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति भी कम थी। विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था।

सरकार को विद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत संरचनाएं एवं मूलभुत सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

- एम.डी.एम. योजना के क्रियान्वयन के क्रम में 1974.79 एम.टी. चावल जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़ था, विद्यालयों के भंडार पंजी में नहीं लिया गया जब की उसे एस.एफ.सी. गोदामों से निर्गत दिखाया गया था। एम.डी.एम. के अंतर्गत चावल की दूसरी योजनाओं में विचलन एवं कुकिंग फंड का दुरूपयोग भी पाया गया। कुछ विद्यालयों में एम.डी.एम. कुछ दिनों के लिए अनाज आपूर्ति कम होने के कारण अवरूद्ध पाया गया।

- एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन के क्रम में जिला, प्रखण्ड एवं गाँव स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या मानक की तुलना में कम पाया गया। मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें यथा रक्त भण्डारण, शिशु सेवा, अल्ट्रासाउण्ड, ई.सी.जी. सेवायें, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवायें इत्यादि भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्द्ध नही थी। सदर अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन, धुलाई मशीन एवं इन्सीनेरेटर अक्रियाशील थे। जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के बावजूद सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान जरूरी तीन जाँच नहीं किया गया एवं 2009-12 के दौरान संस्थागत प्रसव सिर्फ 40 *प्रतिशत* पंजीकृत महिलाओं का ही हो पाया।

सरकार को मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर/स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

- वर्ष 2009-12 के दौरान आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) में पाया गया की 2,583 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विरूद्ध 2,484 केंद्रों में शौचालय एवं 2,026 केन्द्रों में चापाकल नहीं थे। एस.एन.पी. में 36 से 38 *प्रतिशत* की कमी पाई गई।

- ₹ 44.96 करोड़ मूल्य का बी.पी.एल., अन्तोदय, अन्नपूर्णा एवं अतिरिक्त बी.पी.एल. योजना का अनाज सरकारी राशन दुकानो में प्राप्ति नहीं दर्शाया गया जब की एस.एफ.सी. द्वारा इसे निर्गत दिखाया गया था। इस अंतर का मिलान नहीं किया गया।

- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल में 75 हजार आबादी के लिए दो पाईप जलापूर्ति योजना बीच में ही रोक दी गई जिसके फलस्वरूप पाईप के खरीद में खर्च किये गए ₹ 19.17 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

- पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वर्ष 2007-12 के बीच ₹ 27.86 करोड़ के लागत से पूर्ण किये गए 31 सड़कों का रखरखाव नहीं किया गया एवं 181 ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने वाले 86 सड़कें ₹ 42.60 करोड़ के खर्च के बावजूद भी अपूर्ण रहे।

  पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सरकार को सभी मौसम के लायक सड़क द्वारा सभी ग्रामीण बस्तियों को जोड़ना सुनिश्चित करना चाहिए।

- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत 1,457 लक्षित गाँवों के विरूद्ध सिर्फ 668 गाँवों का विद्युतिकरण किया गया। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निश्चित दर से बिलिंग करने के फलस्वरूप मीटर लगाने में ₹ 3.86 करोड़ का खर्च निष्फल हुआ।

- एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 861 स्वरोजगारियों को भवन के अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका जिसके फलस्वरूप वे बैक वित्तीय पोषण से वंचित रहे।

- पलामू में पुलिस बल के लिए आधारभूत सुविधाएं यथा थाना, आउटपोस्ट भवन पुलिसकर्मी के लिए आवास, बैरक, वाहन आदि की कमी थी। पुराने हथियारों का जिला में निस्तारण नहीं किया गया।

- जिला योजना समिति को योजनाओं की प्रगति की समीक्षा अपनी बैठक में करनी थी। समिति ने अपने एकमात्र बैठक में समीक्षा नहीं की। इसके अलावे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अन्तर्गत समितियों का संगठन उनके अंतर्गत आने वाले कार्यों के देखरेख के लिए करना था परंतु इन समितियों के गठन न होने के कारण विकास योजनाओं का अनुश्रवण नहीं हो सका।

  सरकार को अनुश्रवण प्रणाली को सुद्धढ़ करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

3.1.1 प्रस्तावना

पलामू की संपूर्ण जनसंख्या 19.36 लाख है जो प्रथमत: कृषि, जंगल और पशुओं के पालन पर जिविका चलाते है। यह जिला उत्तर में औरंगाबाद (बिहार), पूर्व में चतरा जिला, दक्षिण में लातेहार जिला एवं पश्चिम में गढ़वा जिला से घिरा हुआ है।



5,043.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पलामू जिला तीन अनुमण्डलों[1] एवं 20 प्रखण्डों मे विभक्त है। इस जिले के अंतर्गत 283 ग्राम पंचायत, 20 पंचायत समितियों, एक नगर परिषद और एक जिला परिषद शामिल है।

जिले में सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंद्धित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नांकित है:

प्रशासनिक विभाग	पलामू प्रमण्डल
जिला मुख्यालय	डाल्टनगंज (मेदिनीनगर)
थाना	21
जनसंख्या घनत्व	381 प्रति वर्ग कि.मी.
अनुसूचित जाति	4.24 लाख (27.55 *प्रतिशत*)
अनुसूचित जनजाति	1.39 लाख(9.03 *प्रतिशत*)
लिंग अनुपात	947 महिला प्रति हजार पुरूष
साक्षरता दर	65.50 *प्रतिशत*
गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का प्रतिशत	सम्पूर्ण परिवारों का 79 *प्रतिशत*
कुल परिवारों की संख्या	2,52,319
ग्रामीण परिवार	2,37,337
शहरी परिवार	14,982
कुल गाँवों की संख्या	1,918
विद्युतीकृत गाँव	34.50 *प्रतिशत*
जलापूर्ति योजना से सम्बद्ध जनसंख्या	99.83 *प्रतिशत*
उचित मूल्य की दुकान	1,434
विद्यालयों की संख्या	2,818
स्वास्थ्य केंद्र	220 निजि स्वास्थ्य सुविधाओं सहित
शिशु मृत्यु दर(प्रति 1000)	38
मातृ मृत्यु दर(प्रति एक लाख)	208

[1] छत्तरपुर, हुसैनाबाद एवं मेदिनीनगर।

कुल प्रजनन दर	3.2 *प्रतिशत*
बैक शाखाओं की संख्या	60 वाणिज्यिक एवं 33 सहकारी वाणिज्यिक बैक
संड़क संबंद्धता	23.57 *प्रतिशत* गाँव

स्त्रोत:जिला योजना पदाधिकारी द्वारा तैयार की गयी जिला प्रोफाइल तथा 2001 की जनगणना

पलामू के जिला केंद्रित लेखापरीक्षा में सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों में वित्तीय प्रबंध, निधियों की उपयोगिता एवं योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए रचनात्मक निक्षेपण पर केन्द्रीभूत लक्ष्यों से संबंधित शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, पेय जल एवं स्वच्छता, सड़क, आपदा प्रबंधन, विद्युत एवं कानून व्यवस्था को लक्ष्य में रखा गया।

3.1.2 प्रशासनिक संरचना

उपायुक्त जिला का प्रशासनिक एवं सभी कार्यक्रमों की स्वीकृति अधिकारी हैं। उपायुक्त जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) के अध्यक्ष भी है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचायती राज संस्थान (पी.आर.आई.), प्रखंड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) एवं जिले में अवस्थित सभी सरकारी लाइन विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने की सुनिश्चित व्यवस्था करते हैं।

जिला स्तर के विभिन्न पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्त, उपायुक्त की सहायता करते हैं। वे जिला में कार्यान्वित होने वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमों की योजना एवं निरीक्षण के साथ सम्पूर्ण प्रगति एवं समयानुसार कार्यों के निश्चित सम्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। पुलिस अधीक्षक एवं उनके चार उपाधीक्षक भी उपायुक्त की सहायता करते हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की धारा 243 जेड.डी. में निर्दिष्ट प्रावधान है कि जिले में योजना समिति प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में रहेगी।

जिले में जिला योजना समिति का गठन दिसम्बर 2011 में हुआ। झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 में चिन्हित 29 मामलों से संबंधित 75 कार्य ग्राम पंचायतों (जी.पी.), 114 कार्य[2] पंचायत समितियों (पी.एस.) एवं 124 कार्य जिला परिषद (जेड.पी.) को करना था। परंतु उपरोक्त चिन्हित कार्यो का हस्तान्तरण दिसम्बर 2012 तक नहीं किया गया।

[2] चिन्हित मामलों के अंतर्गत विस्तृत रूप से किये जाने वाले कार्य यथा भूमि विकास, कृषि एवं बागवानी, दुग्ध उत्पादन फार्म का विकास, पेय जलापूर्ति इत्यादि।

लेखापरीक्षा कार्य संरचना

3.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा विषय में जाँच करना था कि क्या:

- जिले में योजनाओं का स्थानीय प्रबंधकीय अधिकार प्रभावोत्पादक था,
- वित्तीय प्रबंधन कुशल था,
- योजना लक्ष्य प्राप्त हुआ था और
- एक प्रभावी अनुश्रवण तंत्र स्थापित था।

3.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड में लेखापरीक्षा संरचना हेतु व्याख्याओं को सूचित किया गया था:

- झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001,
- वार्षिक कार्य योजना और परियोजना के कार्यान्वयन की योजना,
- संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं की मार्गदर्शिका,
- झारखंड वित्तीय नियम, झारखण्ड लोक कार्य लेखे/विभागीय संहिता एवं आरक्षी नियम पुस्तिका इत्यादि तथा
- चयनित कार्यक्रमों एवम् योजनाओं का अनुमोदित अनुश्रवण तंत्र।

3.1.5 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं विधि

पलामू जिले का जिला केंद्रित लेखापरीक्षा जिला में वर्ष 2009-12 के दौरान महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों [3] के कार्यन्वयन संबंधित मूल्यांकनों को लेखापरीक्षा में सन्निहित किया गया।

उपायुक्त पलामू के साथ मार्च 2012 में लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदंड एवं इच्छित परिणामों के संबंध में विचार विमर्श के लिए एक आगमन बैठक किया गया। लेखापरीक्षा अप्रैल-जून 2012 के बीच विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (***परिशिष्ट 3.1***) का जिला स्तरीय कार्यालयों में लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच के द्वारा किया गया। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को एक अलग निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। उपायुक्त के

[3] सामाजिक क्षेत्र: स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति एवं स्वच्छता। आर्थिक क्षेत्र: आधारभूत संरचना, सड़क ग्रामीण विद्युतीकरण, रोजगार सृजन इत्यादि तथा सामान्य क्षेत्र: कानून व्यवस्था।

साथ 13 दिसम्बर 2012 को लेखापरीक्षा के परिणामों के संबंध में एक समापन बैठक मे विचार विर्मश किया गया एवं लेखापरीक्षा में अनवेशित प्रत्युक्तरो को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

3.1.6 योजनाकरण

3.1.6.1 जिला योजना समिति

जिला में पंचवर्षीय योजना के साथ वार्षिक योजनाएं भी तैयार नहीं थी

झारखण्ड पंचायति राज्य अधिनियम (झा.पं.रा.आ.) के खण्ड 127 के अनुसार जिला योजना समिति सम्पूर्ण जिले के लिए पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा, सभी प्राकृतिक एवं मानव संसाधन का एक डाटा बेस के आधार पर प्रत्येक गाँव, प्रखण्ड एवं जिला में उपलब्ध सुविधाओं की एक सूची बनाएगा तथा लिए गए सभी कार्यों की एक सूची तैयार करेगा, उसे संशोधित करेगा एवं पंचायती राज्य संस्थाओं एवं यू.एल.बी. द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करेगा, जिला योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आहुत करेगा एवं कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में सरकार को सूचित करेगा। झा.पं.रा.आ. 2001 के खंड 130 के अनुसार जिला योजना समिति प्रत्येक दो माह के अंतराल पर कम से कम एक बार बैठक करेगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2009.-12 के दौरान जिला के लिए पंचवर्षीय योजना के साथ एक वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गयी थी। यद्यपि, अधिनियम के नियमों के अंतर्गत जि.यो.स. कार्यान्वित चालू योजनाओं की प्रगति का आवश्यकता अनुसार अनुश्रवण नहीं किया गया था। हालांकि, झा.पं.रा.आ. कि कार्यान्वयन के पूर्व एवं जि.यो.स. के गठन के उपरांत भी योजनाओं का मूल्यांकन/परीक्षण उपायुक्त द्वारा लगातार प्रत्येक माह की गयी थी।

पुनश्च: लेखापरीक्षा में देखा गया कि पंचायती राज संस्थान के चुनाव के एक वर्ष बाद जिला योजना समिति का गठन 22 दिसम्बर 2011 को हुआ और इसकी बैठक जून 2012 तक सिर्फ एक बार (27 दिसम्बर 2011) को हो सकी। जिला योजना समिति ने अपनी पहली बैठक में मनरेगा का वर्ष 2012-13 के लिए कार्य योजना का अनुमोदन किया एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान का वर्ष 2011-12 के वार्षिक कार्य योजना का भुतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन किया।

अत: जिला योजना समिति के गठन में विलम्ब के फलस्वरूप जिला में सम्पूर्ण एवं तृणमूल स्तरीय योजनाकरण का लक्ष्य अप्राप्त रहा।

3.1.6.2 कार्य, कार्यक्रम एवं निधियों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरण

झा.पं.रा.आ. 2001 के खण्ड 69 के अनुसार विगत बैठकों में कार्यान्वयन प्रगति पर लिये गए निर्णयों एवं पिछले माह में किये गए विकास कार्यो का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर विचार विमर्श करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रत्येक माह बैठक करनी थी। इसके अलावा झा.पं.रा.आ. के खण्ड 71 एवं 72 में यह भी अवसर प्रदान किया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में कार्यों[4] की देखभाल के लिए ग्राम पंचायतों में सात[5] एवं प्रत्येक पंचायत समिति एव जिला परिषद में आठ[6] स्थायी समिति का गठन कर सकता है। इसके साथ ही झा.पं.रा.आ. के 77 बी के अनुसार वर्त्तमान जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को जिला परिषद में मिला दिया गया था।

शक्तियों का हस्तांतरण पंचायती राज संस्थानों को नही होने के कारण ग्राम पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर की स्थायी समितियों का गठन जून 2012 तक नहीं किया जा सका। जैसा की झा.पं.रा.आ. में प्रावधानित है उस अनुरूप जमीनी स्तरीय योजनाकरण एवं अनुश्रवण पंचायती राज संस्थानों को कार्यों के हस्तांतरण नहीं होने के कारण नहीं हो सका। इस बावत जिला योजना पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि निधि, कार्यकलापों एवं कर्मियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी।

3.1.7 वित्तीय प्रबंधन

3.1.7.1 निधि प्रवाह की व्यवस्था

- जिले के ज्यादातर ग्रामीण सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं विशेषकर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निधि सरकारी खाते से बाहर सीधे कार्यकारी ऐजेंसियों को उपलब्ध करायी जाती है। विभिन्न विभाग विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कार्यकारी ऐजेंसियों यथा जिला ग्रामीण विकास अधिकरण,

---

[4] सामान्य कार्य, विकास कार्य, कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन एवं पर्यावरण, लोक संपदा इत्यादि।

[5] सामान्य प्रशासनिक समिति, विकास समिति, महिला, बाल एवं समाज कल्याण समिति, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण समिति, सरकारी संपदा समिति, बुनियादी संगठन समिति एवं ग्राम शिक्षा समिति।

[6] सामान्य प्रशासनिक समिति, कृषि एवं उद्योग समिति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति, वित्त एवं अंकेक्षण समिति, योजना एवं विकास समिति सहकारी समिति, महिला, बाल एवं समाज कल्याण समिति, वन एवं पर्यावरण समिति एवं संचार एवं कार्य समिति।

जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि से जिले में कराती है।

- योजनाओं के लिए उपलब्ध निधियों एवं उनके विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत ऐजेंसियों यथा जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, जिला स्वास्थ्य समिति इत्यादि द्वारा किये गए व्यय का केंद्रीकृत आँकड़ा जिला योजना पदाधिकारी के पास उपलब्ध नहीं था। भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों से महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए जिला को दिये गए निधि के प्रवाह की व्यवस्था को ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है।

वर्ष 2009-12 में पलामू जिला के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के विकासशील योजनाओं के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं अन्य ऐजेंसियों को राज्य सरकार एवं भारत सरकार के मंत्रालयों से प्राप्त निधियों एवं उनके विरूद्ध किये गए व्यय[7] का समेकित विवरण **तालिका-1** में दिया गया है।

तालिका-1: पलामू जिले के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास योजनाओं से संबंधित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	योजना	नि. एवं व्य.पदा. ऐजेंसि	2009-10		2010-11		2011-12		व्यय नही की गई शेष की प्रगति
			उपलब्ध निधि	व्यय	उपलब्ध निधि	व्यय	उपलब्ध निधि	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)
सामाजिक	रा.ग्रा.स्वा.मि.	जि.स्वा.स.	11.36	8.13	23.21	19.06	23.44	12.75	10.69
सामाजिक	स.बा.वि.का.	जि.स.का.प.	17.89	16.17	31.69	30.39	32.29	30.50	1.79 प्रत्यार्पित
सामाजिक	एस.जी.एस. वाई.	जि.ग्रा.बी.ए.	12.57	8.23	12.33	5.41	14.42	2.92	11.50
सामाजिक	इं.आ.यो.	जि.ग्रा.बी.ए.	23.18	13.17	60.62	26.11	52.98	34.80	18.18
सामाजिक	सा.शि.आ.	जि.का.पदा.	120.94	119.03	109.83	91.15	93.39	62.90	30.49
सामाजिक	म.यो.	जि.शि.पदा.	23.94	23.04	26.08	18.73	40.93	27.10	13.83
सामाजिक	आपात प्रबंधन कार्यक्रम	उपायुक्त	10.55	10.38	19.35	19.35	0.70	0.70	-
सामाजिक	एन.आर. डी.डब्लू. पी.	कार्य.अभि., डी.डब्लू एवं एस. डी.	46.78	8.09	45.76	25.46	26.24	5.27	20.97
आर्थिक	राज्य सड़क	कार्य. अभि., सडक नि. प्र.	43.65	42.94	20.37	18.30	11.91	10.75	1.16 व्यपगत
आर्थिक	आर.जी.जी. वी. वाई.	कार्य.अभि., जे.एस.इ.बी.	18.57	1.61	16.96	-	16.96	-	16.96

स्रोत : पदनामित नि. एवं व्य. पदा. एवं कार्यकारी ऐजेंसियों

नोट: 1. निधि की उपलब्धता- इसमें योजनाओं से संबंधित विगत वर्ष के अ-व्यपगत निधियों का शेष सन्निहित है।

2. पुलिस आधुनिकिकरण के लिए पूरे राज्य के लिए समेकित बजट बनाया गया न कि केंद्रीकृत जिला के लिए, इसलिए पुलिस अधीक्षक पलामू से उपलब्ध निधियों एवं उनके विरूद्ध किए गए व्यय से संबंधित सूचना नहीं पाई गई।

तालिका-1 में दिखाए गए निधियों का कम उपयोग प्रधानत: भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं होना, कार्य की धीमी प्रगति, वित्तीय वर्ष के अंत में निधि की विमुक्ति आदि थे जिन्हें अगले कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

[7] व्यय में कार्यकारी ऐजेंसियों को वितरित राशि सन्निहित है।

कार्यक्रमों का कार्यन्वयन

सामाजिक प्रक्षेत्र

सामाजिक प्रक्षेत्र के अधीन जैसे सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.आ.), मध्याह्न भोजन (म.भो.) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.), समेकित बाल विकास कार्यक्रम (स.बा.वि.का.) एवं पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन मानव संसाधन विकास विभाग, स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं पेयजल एवं स्वच्छता के अधीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यन्वयनों के विभिन्न कमियों को आगामी कंडिकाओं में विमर्शित किया गया।

3.1.8 प्राथमिक शिक्षा - सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

सर्व शिक्षा अभियान, एक केंद्र प्रायोजित योजना, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2001 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा के वर्ष 2010 तक सर्वव्यापीकरण करने के लिए शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान सहिंता के पारा 9.1 के प्रावधानानुसार हॉउस होल्ड सर्वेक्षण करना था एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित नामांकित या अनामांकित, विद्यालय से बाहर अथवा व्यवस्थाधीन, निजी विद्यालयों अथवा स्वायत/ सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत इत्यादि सूचनाओं पर आधारित सूक्ष्म स्तरीय योजना तैयार करनी थी।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (जे.ई.पी.सी.) राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के लिए कार्यकारी एजेंसी है। राज्य परियोजना निदेशक राज्य स्तर पर कार्यन्वयन प्रभारी है। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति योजनाकरण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2009-12 के दौरान कुल उपलब्ध राशि ₹ 303.59 करोड़ प्रारंभिक शेष ₹ 9.22 करोड़ सहित के विरूद्ध ₹ 273.10 करोड़ योजना पर व्यय की गई। अव्यवहारित राशि ₹ 30.49 करोड़ था।

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में पायी गई कमियाँ नीचे वर्णित है:

3.1.8.1 नामांकित, अनामांकित और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चें

वर्ष 2009-12 में, 6 से 14 आयु वर्ग के नामांकित, अनामांकित एवं विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की जिले में स्थिति नीचे **तालिका-2** में वर्णित है:

तालिका-2: नामांकित, अनामांकित एवं विद्यालय छोड़ चुके बच्चों का विवरण

वर्ष	नामांकित			अनामांकित			विद्यालय छोड़ चुके			विद्यालय से बाहर रहने वाले कुल बच्चे (7+10)
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009-10	262739	242875	505614	641	954	1595	940	1399	2339	3934
2010-11	260983	251191	512174	351	523	874	583	871	1454	2328
2011-12	250162	243002	493164	1163	1218	2381	1927	2019	3946	6327

स्त्रोत: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पलामू द्वारा संधारित नामांकन आँकड़ा

तालिका-2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 में नामांकन पूर्व की वर्ष की तुलना में तनिक रूप से बढ़ा था जबकि वर्ष 2011-12 में घट गया। इसी तरह से अनामांकित एवं विद्यालय छोड़ चुके बच्चों की संख्या 2010-11 में घट गया परंतु 2011-12 में इसमें तेजी से बढोत्तरी हुई।

3.1.8.2 छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षकों का नियोजन

जिला मुख्यालय से दूर के प्रखण्डों में विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात (पीटीआर) 48:1 और 60:1 के बीच रहा

सर्वशिक्षा अभियान संहिता के पारा 21.3 के प्रावधानानुसार छात्र शिक्षकों का अनुपात (पी.टी.आर.) 40:1 होना चाहिए। लेखा परीक्षा में पाया गया की प्रावधान के विरूद्ध पी.टी.आर. वर्ष 2011-12 के दौरान हुसैनाबाद, पांकी तथा टिपरा प्रखंडों में अधिकतम 60:1 था। जिला शिक्षा सुचना तंत्र (डाइस)[8] के 2011-12 के आँकड़ा के विशलेषण से उजागर हुआ कि कुल छात्र संख्या के विरूद्ध शिक्षकों[9] का नियोजन विभिन्न प्रखण्डों मे अलग-अलग रूप से था। सदर प्रखण्ड मेदिनीनगर में पी.टी.आर. 38:1 था जबकि जिला मुख्यालय से दूर प्रखण्डों में पी.टी.आर. 48:1 एवं 60:1 के बीच था (***परिशिष्ट -3.3***)। ऐसा पाया गया कि दूरदारज के क्षेत्र ज्यादातर पारा शिक्षकों पर ही आश्रित थे जिनकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पर होती है और जिन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

समापन बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सरकारी शिक्षकों के उचित नियोजन के द्वारा पी.टी.आर. के अनुपात में सुधारात्मक कारवाई की जाएगी।

---

[8] विद्यालय स्तर से जनित मूल आँकड़ा जिसे जिला स्तर पर संकलित किया जाता है और जो शिक्षा सूचना प्रणाली का एक भाग है।

[9] सरकारी एवं पारा शिक्षक सम्मिलित रूप में।

3.1.8.3 विद्यालय आधारभूत संरचना

सर्वशिक्षा अभियान संहिता के पारा 26 के अनुसार वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में असैनिक कार्यों के अंतर्गत नया विद्यालय भवन (एन.एस.बी.) अतिरिक्त कक्षा (ए.सी.आर.) प्रखण्ड संसाधन केंद्र (बी.आर.सी.), संकुल संसाधन केंद्र (सी.आर.सी.) इत्यादि का निमार्ण अनुमोदित/स्वीकृत लक्ष्यों के आधार पर की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत एन.एस.बी. एवं अतिरिक्त दो/तीन कमरों की कक्षाओं के निर्माण की स्वीकृत 2009-12 के दौरान दी गई जिन्हें निधि विमुक्ति से छः माह के भीतर पूर्ण करना था। यह देखा गया की 34 एन.एस.बी. जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 2.72 करोड़ थी की स्वीकृति वर्ष 2010-11 में दी गई भूमि की अनुपलब्धता के कारण दिसम्बर 2012 तक शुरू नहीं किया जा सका।

आगे, 2009-11 के दौरान मंजूर किये गए 4,858 योजना (9,721 ए. सी. आर.) जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 19.95 करोड़ थी उनमें से 688 योजनाएं (1,381 ए. सी. आर.) का निर्माण कार्य दिसम्बर 2012 तक शुरू नहीं कि जा सकी जिसे **तालिका-3** में दर्शाया गया है।

तालिका-3: स्वीकृत, पूर्ण, नहीं लिए गए एवं अपूर्ण योजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	राशि	पूर्ण योजनाओं की संख्या	राशि	नहीं ली गई योजनाओं की संख्या	राशि	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	राशि
2010-11	एन.एस.बी.	34	2.72	शून्य	शून्य	34	2.72	शून्य	शून्य
2009-10	2ए.सी.आर.	1800	58.48	1462	47.50	शून्य	शून्य	338	10.98
2010-11	2ए.सी.आर.	2253	63.08	967	27.08	285	7.98	1001	28.03
2011-12	2ए.सी.आ.	800	23.28	39	1.14	398	11.58	363	10.56
2010-11	3ए.सी.आर.	05	0.39	शून्य	शून्य	05	0.39	शून्य	शून्य
कुल		**4892**	**147.95**	**2468**	**75.72**	**722**	**22.67**	**1702**	**49.57**

स्रोत :जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिये गए सूचना के अधार पर झारखण्ड शिक्षा परियोजना द्वारा संकलित

नोट: वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 में कोई भी एन.एस.बी. एवं तीन कमरों वाले ए.सी.आर. स्वीकृत नही थें।

नियत तिथि की समाप्ति के बाद ₹ 49.57 करोड़ व्यय होने पर भी 1,702 योजनाएं लंबित थे

जैसा कि **तालिका-3** में देखा जा सकता है कि 4,170 ली गई ए.सी.आर. निर्माण योजनाओं के विरूद्ध 1,702 (41 *प्रतिशत*) योजनाएं ₹ 49.57 करोड़ के व्यय के बाद भी लंबित थी जबकि पूर्ण होने की नियत तिथि समाप्त हो चुकी थी। जैसा कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के मासिक प्रगति प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त योजनाएं मुख्यत: ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच विवाद, भूमि के अनुपलब्धता के कारण लंबित थी।

इस तरह 1,702 ए.सी.आर. के पूर्ण न होने के कारण आधारभूत संरचना तैयार करने का वांछित उद्देश्य की पूर्ति पूर्णत: नहीं हो सकी। यह भी पाया गया कि 312 उतक्रमित प्राथमिक विद्यालयों के 936 कमरों के जरूरत (एस.एस.ए. के अनुसार प्रति विद्यालय 3 कमरे) के विरूद्ध 1,532 कमरों (मार्च 2012 इाइस आंकड़ा के मुताबिक) का निर्माण कराया गया जो कि 596 कमरे अधिक थे कमरों के निर्माण की स्वीकृति जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दी गई। इन कमरों के निर्माण में न्यूनतम लागत मूल्य ₹ 1.25 लाख प्रति कमरा (मुख्य अभियंता, झारखण्ड शिक्षा परियोजना द्वारा प्रतिवेदित) के आधार पर ₹ 7.45 करोड़ संगणित किया गया।

समापन बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि योजनाओं को पूर्ण करने की कारवाई की जाएगी। अधिक कक्षाओं के निर्माण के विषय में कहा गया कि मामले की जाँच की जाएगी।

3.1.8.4 मूलभूत सुविधाएं

सर्व शिक्षा अभियान संहिता के पारा 26.10 के अनुसार, एस.एस.ए. और पेय जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के साथ मिलकर सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेय जल , सामान्य शौचालय और अलग से बालिका शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरा के अनुसार 2,656 विद्यालयों में अप्रैल 2012 तक उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति ***परिशिष्ट-3.4*** में दी गई है। यह देखा गया कि जिले के 84 *प्रतिशत्* विद्यालयों में सामान्य शौचालय नहीं थे, एवं 60 *प्रतिशत्* विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी और 98 *प्रतिशत्* विद्यालयों में बिजली नही थी। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं।

समापन बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा (दिसंबर 2012) कि मूलभूत सुविधाओं के अद्यतन आँकड़े उपलब्ध कराया जाएगा।

3.1.8.5 मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण

सर्व शिक्षा अभियान संहिता की कंडिका 25 के अनुसार कक्षा I से VIII तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना था। विद्यालयों में वास्तविक नामांकन के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पाठ्य पुस्तकों की संख्या का आकलन कर राज्य परियोजना निदेशक (एस.पी.डी.) को आपूर्ति मांग प्रस्तुत करना था। सत्र के शुरूआत में (अप्रैल) पुस्तक प्राप्ति के बाद प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को विद्यालयों के प्रधानाद्यापक के माध्यम से छात्रों के बीच वितरण कराना था।

हमने यह देखा कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा गलत माँग प्रस्तुत किये जाने और आगे राज्य परियोजना निदेशक द्वारा उसमे भी कटौती किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2009-10 से 2011-12 के बीच छात्रों में 24 से 34 *प्रतिशत* तक कम पुस्तकें वितरित की गई।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने मध्याह्न भोजन में औसत उपस्थिति के आधार पर पुस्तकों की आपूर्ति किये जाने के कारण छात्रों के बीच कम पुस्तकों का वितरण होना को इसके लिए मुख्य कारण बताया। जवाब तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि मध्याह्न भोजन की औसत उपस्थिति पर पुस्तकों की आवश्यकता का गणना सहीं नहीं था जिसके परिणाम स्वरूप मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की सुविधा से छात्रों को वंचित होना पड़ा।

समापन बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) की मध्याह्न भोजन की औसत उपस्थिति के आधार पर पुस्तकों की आपूर्ति गलत थी।

3.1.9 मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन

भारत सरकार ने कक्षा I -V तक के छात्रों के बीच नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव को बढाकर शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु नवम्बर 2003 में मध्यान्ह भोजन योजना शुरू की। जिले के सभी 20 शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों में यह योजना अक्टूबर 2007 से कक्षा VI -VIII तक बढाई गई। इस योजना के अंतर्गत कक्षा I-V तक के छात्रों को 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस एवं कक्षा VI -VIII तक के छात्रों को 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस के दर से पका हुआ खाना देना था। सरस्वती वाहिनी संचालन समिति जो एक ग्राम शिक्षा समिति की उप समिति है को खाना पकाने पर होनेवाले व्यय को उपलब्ध कराना था। जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर क्रमश: जिला शिक्षा अधीक्षक और प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

हमने यह पाया कि कुल ₹ 82.71 करोड़ उपलब्ध राशि के विरूद्ध ₹ 68.87 करोड़ मध्यान्ह भोजन पर वर्ष 2009-12 कि बीच व्यय हुआ और ₹ 13.84 करोड़ (17 *प्रतिशत*) शेष रहा। शेष राशि का वृहत भाग (₹ 13.84 करोड़ के विरूद्ध ₹ 13.53 करोड़) विद्यालयों को खाना पकाने का खर्च की राशि डी.एस.इ. जनवरी 2012 से मार्च 2012 के दौरान नहीं दिया गया क्योंकि विद्यालयों ने विगत खर्च का व्यौरा नहीं दिया था।

3.1.9.1 खाद्यान का आवंटन, उठाव एवं उपयोग

छात्रों के नामांकन के आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग जो कि नोडल विभाग नामांकित था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को जिलावार खाद्यान की आवश्यकता संसूचित करता है। भारत सरकार का मंत्रालय खाद्यान के आबंटन की सूचना राज्य सरकार को देती है। विभाग आबंटन की सूचना जिला के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य निगम को देती है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान का आवंटन और उसके विरूद्ध राज्य खाद्य निगम द्वारा उठाव **तालिका-4** में निर्दिष्ट है:

तालिका-4: खाद्यान के कम उठाव का विवरण

(मात्रा मिट्रीक टन में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा आवंटित	राज्य खाद्य निगम द्वारा उठाई गयी मात्रा	कम उठाव (प्रतिशत)
2009-10	7706.27	6036.27	1670.00(22)
2010-11	7616.25	6484.04	1132.21(15)
2011-12	5970.78	5382.44	588.34(10)

स्रोत: मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, जिला प्रबंधक खाद्य निगम, पलामू

जैसा की उपरोक्त **तालिका-4** में देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष खाद्यान का कम उठाव हुआ। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा की भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य खाद्य निगम को खाद्यान की आपूर्ति नहीं की गई जिसके कारण आवंटन व्यपगत हुआ और कम उठाव हुआ। यह जिला प्रशासन एवं राज्य खाद्य निगम के बीच समन्वय की कमी दर्शाता है।

जिला शिक्षा अधीक्षक के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया की जनवरी और फरवरी 2012 के बीच सात प्रखण्डों[10] के 1,133 विद्यालयों में से 167 विद्यालयों में पॉच से 24 दिनों तक मध्याहन योजना खाद्यान आपूर्ति न होने के कारण बाधित रहा। राज्य खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान की आपूर्ति न होने के कारण उपरोक्त वर्णित विद्यालयों के 41,126 नामांकित बच्चे मध्याहन भोजन योजना के लाभ से वंचित रहे।

3.1.9.2 राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत एवं विद्यालयों द्वारा खाद्यान उठाव की मात्रा में विसंगति

भारत सरकार द्वारा आवंटित चावल का उठाव राज्य खाद्यय निगम द्वारा भारतीय राज्य खाद्य निगम से किया जाता है और उसे राज्य खाद्य निगम अपने गोदामों में रखता है। प्रखण्डों में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी खाद्यान वितरण हेतु विद्यालयों को राज्य खाद्य निगम से चावल उठाव के

[10] छतरपुर, हरिहरगंज, हुसैनाबाद, लेस्लीगंज, नौडीहाबाजार, पाटन तथा सतबरवा।

लिए परमिट निर्गत करते है तथा खाद्यान उठाव संबंधित एक रिर्पोट का संकलन करते है।

दस राज्य खाद्य निगम गोदामों के ग्रेन स्टेटमेंट/परिवहन रजिस्टर फार्म-बी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारीयों के खाद्यान उठाव रिर्पोट (जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये) के जाँच से पता चला कि वर्ष 2010-12 के दौरान राज्य खाद्य निगम ने विद्यालयों को कुल 12,900.73 मिट्रिक टन चावल निर्गत किया परंतु जिला शिक्षा अधीक्षक के रिर्पोट के मुताबिक (जो कि प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारीयों के रिर्पोटो के संकलन के आधार पर था) विद्यालयों द्वारा इस दौरान उठाव की कुल मात्रा 10,925.94 मिट्रिक टन था। इस तरह 1,974.79 मिट्रिक टन (12,900.73 मि.ट.-10,925.94 मि.ट.) चावल जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़[11] की विसंगति थी। अभिलेखों में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जिसे यह पता चले की जिला शिक्षा अधीक्षक ने राज्य खाद्य निगम के लेखाओं से मिलान किया था।

1,974.79 लाख टन चावल जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़ था की विसंगतियों का मिलान नहीं किया गया था

समापन बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा (दिसम्बर 2012) की विसंगति का मिलान कर लिया जाएगा।

3.1.9.3 मध्याह्न भोजन चावल के अस्थायी विचलन का समायोजन नहीं किया जाना

राज्य खाद्य निगम के गोदामों के ग्रेन स्टेटमेंट के जाँच से पता चला कि सात राज्य निगम गोदामों[12] के सहायक गोदाम प्रबंधकों ने 6,840.28 क्विंटल मध्यान्ह भोजन चावल जिसका मूल्य ₹ 38.65 लाख (खरीद मूल्य ₹ 565 प्रति क्विंटल के दर के अधार पर) था का विचलन गरीबी रेखा से नीचे के लाभुक (बी.पी.एल.), अंततोदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) और अतिरिक्त बी.पी.एल. योजनाओं में किया गया जिसका समायोजन मार्च 2012 तक नहीं हुआ था। मध्याह्न भोजन योजना दिशानिर्देश में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि चावल का विचलन कहीं और योजनाओं में विचलन किया जा सके अत: किया गया विचलन अनियमित था।

मध्याह्न भोजन की 6,840.28 क्विंटल चावल जिसका मूल्य ₹ 38.65 लाख था को अन्य योजनाओं में विचलित कर दिया गया

डी.एस.इ. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि विसंगतियों का मिलान किया जाएगा।

3.1.9.4 कुकिंग फंड का संवितरण

कुकिंग फंड ₹ 3.17 प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिवस कक्षा I-V एवं ₹ 4.75 प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिवस कक्षा VI-VIII के लिए सरस्वती वाहिनी संचालन समिति को खाना बनाने हेतु देय था। जिला शिक्षा अधीक्षक को बैंकर

---

[11] भारत सरकार द्वारा प्रावधानित मितव्ययी दर ₹ 20880 प्रति मिट्रिक टन के आधार पर।

[12] विश्रामपूर, चैनपुर, छतरपुर, हरिहरगंज, ओवरब्रिज(मेदिनीनगर), पदमा और पांकी।

चैक द्वारा जो बैक एडवाइस से समर्थित थे के द्वारा कुकिंग फंड का संवितरण करना था जो सीधे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा होना था। चूकिं कुकिंग फंड का कक्षा I-V एवं कक्षा VI-VIII के लिए अलग-अलग थे अत: इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवंटन प्राप्त था।

कुकिंग फंड के उपयोगिता से संबंधित अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुई:

- जिला शिक्षा अधीक्षक के अभिलेखों के जाँच से पता चला कि अप्रैल से अक्टूबर 2011 के बीच ₹ 16.29 लाख कुकिंग फंड का संवितरण 53 उतक्रमित प्राथमिक विद्यालयों एवं सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बीच कक्षा I-V के लिए किया गया था। इसके अलावे उन्हीं विद्यालयों को ₹ 10.33 लाख का आवंटन उसी बैंक एडवाइस के द्वारा कक्षा VI-VIII के छात्रों के लिए दिया गया। परंतु विद्यालयों के डाइस रिर्पोट से उद् घटित हुआ कि इन विद्यालयों में कक्षा VI-VIII नहीं चल रहे थे इस तरह इन विद्यालयों में कक्षा VI-VIII में कोई छात्र नहीं थें। इस तरह वैसे कक्षाएं जो नहीं चल रही थी और जिनमें छात्र नहीं थे के लिए कुकिंग फंड दिये जाने से उसकी उपयोगिता के बारे में गंभीर शंका उत्पन्न होती है।
- प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मध्याह्न भोजन से संबंधित विद्यालय वार एक मासिक रिर्पोट संकलित करता है जिसमें नामांकित एवं लाभान्वित छात्रों की संख्या, महीने में विद्यालय दिवसों की संख्या चावल एवं कुकिंग फंड का प्रारंभिक एवं अंत शेष तथा दोनों की महीने के दौरान प्राप्ति और खर्च की सूचना होती है जिसे वह जिला शिक्षा अधीक्षक को संसूचित करता है। प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, हुसैनाबाद के माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर 2011 तथा मार्च 2012 के मासिक रिर्पोट के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि कुकिंग फंड एवं अनाज के मद में अगस्त एवं अक्टूबर 2011 के दौरान 23 विद्यालयों में ₹ 6.29 लाख का नकारात्मक अंतशेष था जो यह दर्शाता है कि दोनो कारक विद्यालय में उपलब्ध नहीं थी और विद्यालय कर्मी अपने स्तर से खाना बना कर राशि प्राप्त होने के उपरांत उसका समायोजन कर रहे थे। मध्याह्न भोजन मार्ग दर्शिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण कुकिंग फंड एवं अनाज के मद में नकारात्मक अंतशेष का समायोजन करना अनियमित था।

समापन बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा (दिसम्बर 2012) कि उपरोक्त विसंगति का मिलान किया जाएगा।

3.1.9.5 परिवहन व्यय

भारत सरकार से प्राप्त परिवहन व्यय के उपयुक्त उपयोग के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक उतरदायी है। भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों के मध्य खाद्यान का परिवहन राज्य खाद्य निगम द्वारा ₹ 37.प्रति क्विंटल (₹55 प्रति क्विंटल की दर से अप्रैल 2011 से) की दर से किया जाता था। माँग के प्रस्तुत किये जाने के बाद, जिला शिक्षा अधीक्षक परिवहन व्यय का भुगतान माँग की जाँच विद्यालयों द्वारा किये गये कुल खाद्यान का उठाव से करने के बाद करते है।

एसएफसी द्वारा खाद्यान्नों की वास्तविक परिवहन व्यय का दावा पुष्टि के बिना भुगतान किया गया था

यह पाया गया कि राज्य खाद्य निगम ने वर्ष 2009-12 के दौरान 1.81 लाख क्विंटल अनाज उठाव के विरूद्ध कुल ₹77.26 लाख का माँग प्रस्तुत किये। परंतु सभी 20 प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत भंडारण/उपयोगिता रिर्पोट की जाँच से ज्ञात हुआ कि माध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत उस दौरान कुल उठाव मात्र 1.78 लाख क्विंटल ही हुआ जिसके लिए ₹ 73.87 लाख परिवहन व्यय राज्य खाद्य निगम को देय था। परंतु जिला शिक्षा अधीक्षक ने राज्य खाद्य निगम के माँग को बिना जाँचे ही ₹ 92.03 लाख परिवहन व्यय मद में भुगतान कर दिया। इस तरह परिवहन व्यय मद में राज्य खाद्य निगम को कुल ₹ 18.16 लाख का अधिक भुगतान कर दिया गया जो दिसम्बर 2012 तक असमायोजित था।

समापन बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा (दिसम्बर 2012) की मामले की जाँच की जाएगी।

3.1.10 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.)

भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में रा.ग्रा.स्वा.मि. इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विशेषता गरीब एवं सुभेदय लोगों तक पहुँचात्मक, क्षमतात्मक, प्रभावपूर्ण एवं विश्वसनीय चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। यह कार्यक्रम राज्य में अक्टूबर 2007 को समाविष्ट किया गया था।

स्वास्थ्य, चिकित्सीय शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत जिला स्वास्थ समिति (जि.स्वा.स.) रा.ग्रा.स्वा.मि., पलामू के सचिव सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मेदिनीनगर दो अनुमण्डलीय अस्पताल, दस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (स.स्वा.के.), 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रा.स्वा.के.) 171 स्वास्थ्य उप केंद्र (स्वा.उ.के.) एवं 32 रोगी कल्याण समिति के माध्यम से लोगो की स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

2009-12 की अवधि के दौरान रा.ग्रा.स्वा.मि. के विभिन्न घटकों के लिए उपलब्ध ₹ 19.31 करोड़ में सन्निहित ₹ 4.14 करोड़ की प्रारंभिक शेष में से ₹ 12.75 करोड़ व्यय किया गया था और ₹ 10.69 करोड़ अव्ययित अवशेष था।

3.1.10.1 योजना

रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में त्रुटियों को चिन्हित करने के लिए मकानों और सुविधाओं का एक सर्वेक्षण किया जाना था। जिला स्तर पर रा.ग्रा.स्वा.मि. के कार्यान्वयन एजेंसी उपायुक्त की शीर्षता में जिला स्वास्थ्य समिति को जिला के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करना अपेक्षित था। निचले स्तर के कार्यकारियों से प्राप्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत योजना को तैयार करना था।

रा.ग्रा.स्वा.मि. मार्गदर्शिका के अनुसार जिला स्तर पर (मई 2009) अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक जि.स्वा.मि., जिला परिषद एवं एक समेकित जि.स्वा.मि. का गठन करना था। जि.स्वा.स. का शासकीय निकाय का प्रमुख उपायुक्त एवं कार्यकारी समिति का प्रमुख जि.वि.आ./मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी है सबसे निचले स्तर से योजना, परिक्षण मूल्यांकन, लेखांकन एवं डाटा बेस प्रबंधन के लिए जि.स्वा.स. उत्तरदायी है।

वार्षिक योजना के लिए मकानों और सुविधाओं का सर्वेक्षण नहीं हुआ था

हमने यह पाया कि 2009-10 के दौरान विलम्ब से जि.स्वा.स. का गठन होने के कारण वार्षिक योजना तैयार नहीं हो पायी थी। दिसम्बर 2012 तक जि.स्वा.स. का गठन होने के उपरांत भी मकानों और सुविधाओं का सर्वेक्षण नहीं हुआ था। प्रखण्डों एवं गाँव से कोई इनपुट के बिना ही 2010-11 एवं 2011-12 के लिए वार्षिक योजना तैयार किया गया था।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) की प्रा.स्वा.के. एवं सा.स्वा.के. से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के उपरांत अभिवार्षिक योजना को तैयार किया जा रहा है।

3.1.10.2 संगठनात्मक ढ़ाचा

स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की महत्वपूर्ण कमी थी

रा.ग्रा.स्वा.मि. के मार्गदर्शिका के अनुसार 80,000, 20,000 एवं 3,000 से ऊपर की जनसंख्या के लिए क्रमश: एक स.स्वा.के., प्रा.स्वा.के. एवं स्वा.उ.के. होना था। तदनुसार जिले के लिए अवश्यक 26 सा.स्वा.के., 104 प्रा.स्वा.के. एवं 699 स्वा.उ.के. होना था। दिसम्बर 2012 तक इसके विरूद्ध 10 सा.स्वा.के., 21 प्रा.स्वा.के. एवं 171 स्वा.उ.के. था। हमने यह पाया कि, भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त

सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गयी थी जिसके संबंध में अगले कंडिकाओं में विमर्श किया गया है।

यह भी पाया गया कि पूर्वोत्तर प्रा.स्वा. केंद्रों, अतिरिक्त प्रा.स्वा. केंद्रों एवं उप केंद्रों को प्रोन्नत करने के उपरांत भी अवश्यक सुविधाओं[13] को तैयार नहीं किया गया था एवं 10 सा.स्वा.के., 21 प्रा.स्वा.के. एवं 171 स्वा.उ.के. उन्ही भवनों में चलाया जा रहा था। हालांकि पाँच सा.स्वा.के., पाँच प्रा.स्वा.के; एवं 12 स्वा.उ.के. का भवन निर्माण प्रगति पर था (जून 2012)।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति विभाग को प्रतिवेदित किया गया है।

स्वास्थ्य केंद्रों की कमी के परिणामस्वरूप जिले के ग्रामीण गरीबों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की सेवाएं प्राप्त नहीं हो पायी थी।

3.1.10.3 स्वास्थ्य केंद्रो में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं

बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केन्द्रों में से अधिकांश में उपलब्ध नहीं थे

भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (भा.लो.स्वा.मा.) के नियमों के अनुसार उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सा.स्वा. केंद्रों को खून भंडारण, नवजात शिशुओं की देखभाल की सुविधाएं, एक्स-रे, इलेक्ट्रो-कार्डियोंग्राम (इ.का.ग्रा.) शल्य चिकित्सागृह, गर्भमोचन सुविधा, प्रसव गृह, जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति इत्यादि से सुसज्जित करना था। प्रा.स्वा.के./सा.स्वा. केंद्रो में प्रसव गृहों की सुविधा भी रखनी थी।

हमने यह पाया (जून 2012) की किसी भी सा.स्वा. केंद्रों में खून संग्रहण, गर्भमोचन सुविधा, एक्स-रे सुविधा, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, ई.सी.जी. एवं स्त्री रोग की सुविधाओं की आधारभूत सेवाओं की सुविधाएं नहीं थीं। भा.लो.स्वा.मा. के 30 शय्या के मानकों के विरूद्ध सभी सा.स्वा. केंद्रो मे केवल छः शय्या थे। 171 स्वा.उ. केंद्रों में से 99 किराये के भवन में चलाये जा रहे थे एवं 11 प्रा.स्वा. केंद्रों एवं सभी 171 स्वा.उ. केंद्रों में निरंतर जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। 11 प्रा.स्वा. केंद्रों एवं 136 स्वा.उ. केंद्रो में प्रसव गृह उपलब्ध नहीं थे ***(परिशिष्ट 3.5)***। इस प्रकार जिले में भा.लो.स्वा.मा. के मानकों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया गया था।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) की आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा नीति का निर्णय किया जा रहा है।

[13] रक्त भंडारण, शिशु चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, इ.सी.जी. आदि।

3.1.10.4 मानव संसाधन

चिकित्सकों और पारा चिकित्सकों की भारी कमी थी

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की निपुणता और गुणवता मुख्यत: योग्य चिकित्सकों, नर्सों एवं अन्य चिकित्सीय कर्मचारीयों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जिले में 430 चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सीय कर्मचारियों के पद के स्वीकृत बल के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा केवल 214 पदों में पदास्थापित किया गया जिससे 216 पद (50 *प्रतिशत*) में से चिकित्सक श्रेणी में (34 *प्रतिशत*), अक्सिलरी नर्स मिडवाईफ (ए.एन.एम.) (49 *प्रतिशत*) प्रयोगशाला तकनिशियन (94 *प्रतिशत*), स्टाफ नर्स (20 *प्रतिशत*), फार्माशिस्ट (91 *प्रतिशत*) एवं महिला स्वास्थ्य निरिक्षिका (म.स्वा.नि.) (65 *प्रतिशत*) का पद रिक्त था (***परिशिष्ट-3.6***)।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि मानव संसाधन की वृद्धि के लिए सरकार के पास नीति निर्णय विचाराधीन था।

रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत, एक 'सहिया'[14] की नियुक्ति प्रति हजार जनसंख्या पर करना था एवं कम से कम एक प्रति राजस्व गाँव के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में गाँवों के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए समुदाय के मध्य परस्पर स्वास्थ्य प्रणाली की जानकारी देगी।

रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत जि.स्वा.स. द्वारा जनसंख्या के आधार पर 'सहिया' की आवश्यकता का निर्धारण करना था जिसमे 2,700 में से 1,992 सहियाओं को दिसम्बर 2012 तक नियुक्त किया गया था।

इसके अलावे जिला में सहियाओं को छ: मड्यूल्स[15] में प्रशिक्षित किया जाना था। यद्यपि हमनें यह भी पाया कि दिसम्बर 2012 तक 1,992 सहियाओं में से 148, 5वीं एवं 6ठीं मड्यूल्स में अप्रिशिक्षित रहीं। पहले चार मड्यूल्स में प्रशिक्षण निजी संस्थाओं द्वारा दिए गए। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पास संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि मानव संसाधन की वृद्धि के लिए सराकार के पास नीति निर्धारण विचाराधीन था।

---

[14] महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता।

[15] प्रथम मड्यूल्स: सहिया संदेश परिचय, द्वितीय मड्यूलस: सहिया संदेश स्वस्थ शिशु उज्जवल भविष्य तृतीय मड्यूल्स: भोजन, पानी और सफाई, चतुर्थ मड्यूल्स: सुरक्षित मातृत्व पंचम मड्यूल्स: नेतृत्व क्षमता विकास तथा षष्ठ मड्यूल्स: बीमारी और पोषण।

3.1.10.5 जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना (ज.सु.यो.) का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी और गृह प्रसव के बदले संसथागत (अस्पताल में) प्रसव में वृद्धि करना था। शिशु जन्म से पूर्व देखभाल ज.सु.यो. का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके लिए सभी निबंधित गर्भवती महिलाओं को तीन पूर्ण जाँच और अन्य चिकित्सीय सुझाव देना था।

जिले में पंजीकृत 1,12,363 गर्भवती महिलाओं में से केवल 45,310 (40 *प्रतिशत*) महिलाओं का ही संस्थागत प्रसव किया गया

यह पाया गया कि 2009-12 की अवधि के दौरान ₹ 14.24 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि में से इस योजना में ₹ 11.33 करोड़ व्यय किया गया था। हमने यह पाया कि 2009-12 की अवधि में 83,213 (74 *प्रतिशत*) गर्भवती महिलाओं को सभी तीन पूर्ण जाँच (पू.जाँ.) की प्राप्ति हुई थी। 1,12,363 निबंधित गर्भवती महिलाओं में से केवल 45,310 (40 *प्रतिशत*) का संस्थागत प्रसव किया गया था। विस्तृत विवरण **तालिका-5** में दिया गया है।

तालिका-5: जननी सुरक्षा योजना का वर्षवार विवरण

वर्ष	निबंधित महिलाएं	तीन पूर्ण जॉच	संस्थागत प्रसव (*प्रतिशत*)
2009-10	40059	28083	10759(26.85)
2010-11	42028	32894	17649(41.99)
2011-12	30276	22236	16902(55.82)
कुल	**112363**	**83213**	**45310(40.32)**

स्रोत: जिला स्वास्थ्य समिति पलामू

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि जागरूकता का विस्तार एवं सुचना शिक्षा एवं संचार के लिए अतिरिक्त पदक्षेप उठाया जायगा।

3.1.10.6 अंधापन नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम

अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (रा.अ.नि.आ.) का लक्ष्य मोतियाबिन्द ऑपरेशन में वृद्धि, स्कूली बच्चों की आखों की जाँच तथा उसे मुफ्त चश्मा प्रदान करना, नेत्रदान को बढ़ावा एवं दान केंद्रों एवं नेत्र बैंकों की स्थापना के द्वारा अंधापन की घटनाओं में कमी लाना था।

4,962 अपवर्तक त्रुटि मामलों के खिलाफ केवल 2,219 चश्मे स्कूली बच्चों के लिए प्रदान किया गया

2009-12 की अवधि के दौरान, कार्यक्रम के लिए ₹ 1.20 करोड़ उपलब्ध था जिसमें से मार्च 2012 तक ₹ 1.07 करोड़ का व्यय किया गया था। अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि मोतियाबिन्द ऑपरेशन में जिले की उपलब्धता अच्छी थी, 2009-10 में 5,664 (6,600 की लक्ष्य में से 86 *प्रतिशत*) 2010-11 में 6,013 (93 *प्रतिशत*) एवं 2011-12 में 6,083 (87 *प्रतिशत*) था। यद्यपि, अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन कमियों के मामलों में स्कूली बच्चों को

4,962 के विरूद्ध केवल 2,219 (45 *प्रतिशत*) चश्मा प्रदान किया गया था। इसके अलावे, नेत्रदान की सुविधाएं एवं नेत्र बैंक की स्थापना नहीं की गई थीं।

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि निधि की कमी के कारण चश्मों की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। हम यह मानने के लिए राजी नहीं हैं क्योंकि अभिलेखों में ऐसा नहीं पाया गया कि निधि प्राप्ति के लिए मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कोई प्रयास किया गया था।

3.1.10.7 अक्रियाशील उपस्कर

हमारी जाँच में पाये गये बेकार अक्रियाशील उपस्करों का विमर्श निम्नांकित है:

वर्ष 2008-09 के दौरान खरीदे गये मूल्य ₹ 1.69 करोड़ के सीटी स्कैन मशीन रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में बेकार पड़ा है।

- 2008-09 के दौरान ₹ 1.69 करोड़ मूल्य के सि.टी. स्कैन मशीन का क्रय किया गया था जिसे सदर अस्पताल, पलामू में मार्च 2009 को अधिष्ठापित किया गया था। राज्य सरकार एवं आपूर्तिकर्ता के मध्य किये गये आपसी करार (जनवरी 2008) के अनुसार, उपयोगकर्त्ता (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) तीन फेज की ट्रास्फरमर की व्यवस्था करेगा एवं विक्रेता द्वारा वारंटी अवधि के एक वर्ष के दौरान रखरखाव के लिए भुगतान के आधार पर मानव संसाधन की व्यवस्था करनी थी।

  हमने यह पाया कि अगस्त 2012 में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा रेडियोलोजिस्ट की नियुक्ति की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई थी परंतु दिसम्बर 2012 तक न तो रेडियोलोजिस्ट की नियुक्ति की गई थी और न ही ट्रांसफर्मर का अधिष्ठापन किया गया था। इस प्रकार ₹ 1.69 करोड़ व्यय के उपरांत भी उपस्कर अक्रियाशील रहा एवं रोगियों को सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा।

  समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) की मशीन को क्रियाशील करने के लिए प्रभावपूर्ण पदक्षेप उठाया जा रहा है एवं मामले को उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित किया गया है।

- उपायुक्त, पलामू की अध्यक्षता में क्रय समिति द्वारा निर्णय लिया गया (मार्च 2006) की सदर अस्पताल में ₹ 19.59 लाख की मूल्य का मशीनी लौन्ड्री का अधिष्ठापन करना था। मशीनी लौन्ड्री को दिसम्बर 2010 में अधिष्ठापित किया गया था। आपूर्तिकर्ता (मेसर्स फॅन्ट सिस्टम प्रा0 लिमिटेड, राँची) के साथ हुई करार के अनुसार समझौता की गई दर पर इसका अधिष्ठापन एवं ₹ 1.50 प्रति कपड़े तथा ₹ 5.00 प्रति कम्बल धोने एवं चलाने के लिये उत्तरदायी था। आपूर्तिकर्ता को अधिष्ठापन की तिथि

से आगामी पाँच वर्ष तक मशीन का रख-रखाव करना था। जबकि, मशीनी लौन्ड्री की अधिष्ठापन (दिसम्बर 2010) के बाद से यह अक्रियाशील था। आपूर्तिकर्ता के साथ कई पत्राचार के बाद भी आपूर्तिकर्ता नहीं आया था। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दिसम्बर 2012 तक आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया था। इस प्रकार, मशीनी लौन्ड्री अधिष्ठापन में ₹ 19.59 लाख का निष्फल व्यय प्रमाणित हुआ था।

- अगस्त 2009 को सदर अस्पताल में ₹ 27.45 लाख मूल्य के एक इनसिनेटर अन्य उपकरणों के साथ क्रय किया गया था एवं अधिष्ठापित किया गया था। आपूर्तिकर्ता के साथ किये गये करार के अनुसार इनसिनेटर को चलाने के लिये एक प्रशिक्षित व्यक्ति की व्यवस्था की जानी थी। जबकि, जिला पदाधिकारियों द्वारा स्मार निर्गत करने के बावजूद आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति का प्रबंध नहीं करने के कारण इनसिनेटर अब तक अक्रियाशील था, इस प्रकार, ₹ 27.45 लाख व्यय किये जाने का बाद भी जिस उद्देश्य से, यानी चिकित्सीय अपशिष्टों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किये जाने के लिये इनसिनेटर अधिष्ठापन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था। एवं यह पाया गया कि चिकित्सीय अपशिष्ट खुले में पड़े हुये थे जिससे स्वास्थ्य संबंधित गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो रही थी।



सदर अस्पताल,मेदिनीनगर के परिसर में खुले पड़े जैव चिकित्सा अपशिष्ट

समापन बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि मशीनी लौन्ड्री एवं इनसिनेटर को चालू करने के लिये पदक्षेप उठाये जा रहें हैं।

3.1.11 समेंकित बाल विकास सेवा (स.बा.वि.से.) योजना

समेंकित बाल विकास सेवा (स.बा.वि.से.) योजना, एक केंद्र प्रायोजित योजना, का उद्देश्य है कि बच्चों का पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने और समूचित पोषण एवं स्वस्थ्य शिक्षा के माध्यम से माताओं में बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के आवश्यकताओं को समझाने की क्षमता को बढ़ाना था। इन सेवाओं में अनुपूरक पोषण कार्यक्रम(अ.पो.का.), टीकाकरण, विद्यालय

पूर्व शिक्षा(वि.पू.शि.), स्वास्थ्य जाँच एवं पोषण एवं महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा आदि कार्यक्रम सनिहित था। इस योजना के लाभुकों में छः माह से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिला, दुग्धवती माताएं एवं किशोरी बालिकाएं (11 से 18 आयु के मध्य) सनिंहित है। ये सेवाएं लाभुकों को वितरित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता (आं.का.) एवं आंगनबाड़ी सहायक (आं.स.) के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गाँव स्तर के लिए योजना को केंद्रीकृत किया गया था। इस योजना का पर्यवेक्षण जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (जि.स.का.पदा.) एवं प्रखण्ड स्तर पर महिला पर्यवेक्षकों की सहायता से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा किया जाना था। जिले में 2,583 आंगनबाड़ी केंद्रों एवं 20 प्रखण्ड़ों को 11 बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा पूर्ण किया जाना था।

2009-12 की अवधि के दौरान, स.बा.वि.यो. के सभी घटकों के अंतर्गत इस योजना मे ₹ 148.40 करोड़ की निधि जि.स.क.पदा. के पास उपलब्ध थी। इनमे से ₹ 139.55 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 8.85 करोड़ अव्ययित शेष था।

3.1.11.1 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया

भूमि के अभाव में 36 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण नहीं किया गया था

भारत सरकार के निर्देशानुसार (अप्रैल 2007), 400 से 800 की जनसंख्या के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना करना था। यद्यपि, जि.स.क.पदा. द्वारा कहा गया (फरवरी 2013) की जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकताओं का निर्धारण नही किया गया था। जिले के जनसंख्या के आधार पर 750 की औसत जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र था। हमने यह पाया कि, 2009-11 के दौरान स.बा.वि.यो. के अधीन समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड ने 38 आं.के. निर्माण के लिए ₹ 1.64 करोड़ आवंटित किया था। यह निधि दो कार्यकारी एजेंसियों[16] को विमुक्त किया गया था। दिसम्बर 2012 तक भवन प्रमण्डल द्वारा ₹ 7.53 लाख पर दो आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया था। अंचल अधिकारियों (अं.अ.) द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं किये जाने के कारण कार्यकारी एजेंसियों द्वारा बाकी 36 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2012 तक कार्यकारी एजेंसियों के पास ₹ 1.57 करोड़ पड़े हुए थे।

[16] 2009-10 में भवन प्रमण्डल, मेदिनीनगर को तीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ₹ 12.96 लाख और 2010-11 में ग्रामीण विकास विषेश प्रमण्डल, मेदिनीनगर को 35 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ₹ 1.51 करोड़।

समापन बैठक के दौरान जि.स.का.पदा. ने कहा दिसम्बर 2012 की कार्यकारी एजेंसियों को चालू वित्तीय वर्ष में कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश निर्गत किया जा रहा है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में अपर्याप्त सुविधाएं

कुल 2,583 आंगनबाड़ी केंद्रों से 2,484 में कोई शौचालय की सुविधा नही थी और 2,026 में कोई नलकूप की सुविधा नहीं थी

यह पाया गया कि जिले में कुल 2,583 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 2,484 (96 *प्रतिशत*) में शौचालय नहीं थे एवं 2,026 में नलकूप (पानी की सुविधा) नहीं थीं। 11 बा.वि.प.पदा. कार्यालय में से आठ के पास निजी भवन नहीं था एवं 2,167 आंगनवाड़ी केंद्र किराये के भवनों में थी इस प्रकार अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 15 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 10 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन जर्जर अवस्था में थे।



चियांकि आंगनवाड़ी केंद्र की जर्जर स्थिति को प्रदर्शित करती छायाचित्र (19.6.2012)

मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कार्यक्रम की पहुँच पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जबकि योजना की सभी सेवा सुविधाएं समेंकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आते है।

3.1.11.2 अनुपूरक पोषण कार्यक्रम में कमी

अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) का लक्ष्य शून्य से छः वर्ष के आयु के बच्चे, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाएं तथा धात्री माताओं का सम्पूर्ण विकास करना था। यह बच्चों में कुपोषण के रोकथाम के लिए एक प्रभावकारी साधन था। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के लिए जिले में जनसंख्या के आधार पर की गई थी। अनुपूरक पोषण सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को वर्ष में 300 दिन या महीने में 25 दिन देना था।

एस.एन.पी. में छः माह से छः वर्ष के आयु के बीच के बच्चे और उसी कोटि के कुपोषित बच्चे को दोहरे मात्रा में प्रतिदिन 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन देना था। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, दुग्धवती माताएं और किशोरी बालिकाएं को सुखा खाद्यान टेक होम राशन देना था। 2009-12 के दौरान 11 योजनाओं में से 10 के नमुना जाँच में लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी, जैसा की **तालिका-6** में निर्दिष्ट है।

तालिका-6: संचयित लक्ष्य, प्राप्ति और कमी

वर्ष	एस0एन0पी के अंतर्गत लाभान्वित लाभुकों की संख्या		
	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी *(प्रतिशत)*
2009-10	229300	142333	86967(38)
2010-11	233200	148813	84387(36)
2011-12	232829	148682	84147(36)
कुल	**695329**	**439828**	**255501(36.74)**

स्रोत : जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय, पलामू

तालिका-6 से प्रकट होता है कि लक्ष्य के विरूद्ध 36 से 38 प्रतिशत् से कम प्राप्ति हुआ था जिसके कारण 1.92 लाख बच्चे, 0.26 लाख दुग्धवती महिलाएं, 0.25 लाख गर्भवती महिलाएं और 0.13 लाख किशोरी बालिकाएं इस योजना में शामिल नहीं किये गये थे। यद्यपि, जि.स.क.पदा. ने इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए जनसमूह में कोई कदम नहीं उठाए।

3.1.11.3 मानव बल प्रबंधन

समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) की दक्षता एवं गुणवत्ता मुख्य रूप से पर्याप्त संख्या में उपलब्ध दक्ष पर्यवेक्षक श्रेणी जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) तथा महिला पर्यवेक्षिका (एल.एस.) के साथ-साथ भूस्तरीय कार्यकर्ता (आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका) पर निर्भर है। सी.डी.पी.ओ. एवं एल.एस. की मुख्य जिम्मेवारी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना था जो कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। डी.एस.डब्लू.ओ. के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि आई.सी.डी.एस. कर्मियों के सभी श्रेणियों में जुलाई 2012 तक काफी रिक्तियाँ थी जिसे **तालिका-7** में दर्शाया गया है:

तालिका-7: कार्यरत बल की विवरणी (जुलाई 2012)

श्रेणी	स्वीकृत बल	कार्यरतबल	रिक्ति (प्रतिशत)
सी0डी0पी0ओ0	11	03	08 *(73)*
महिला पर्यवेक्षिका	69	20	49 *(71)*
संख्यिकी सहायक	12	03	09 *(75)*
लिपिक	13	08	05 *(38)*
कुल	**105**	**34**	**71 *(68)***

आंगनवाड़ी सेविका	2583	2428	155 *(6)*
आंगनवाड़ी सहायिका	2276	2081	195*(9)*
कुल	**4859**	**4509**	**350** *(7)*

स्रोत: जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय, पलामू

तालिका-7 से सुस्पष्ट है कि जिले में सभी श्रेणियों में कुल रिक्ति 68 *प्रतिशत्* थी। इसके अलावे आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों मे क्रमश: 155 और 195 पद रिक्त पड़े थे परिणामस्वरूप 350 आंगनबाड़ी केंद्र एकल कर्मी द्वारा निकटवर्ती आंगनबाड़ी केंद्र के सेविकाओं के सहयोग से संचालित हो रहे थे। पर्याप्त मानव बल की कमी और सी.डी.पी.ओ. एवं एल.एस. द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के कम पर्यवेक्षण के कारण आई.सी.डी.एस. सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

हमने यह पाया कि 2009-12 की अवधि के दौरान, नौ सी.डी.पी.ओ. ने लक्षित 9,720 दौरो के विरूद्ध केवल 4,703 दौरे और दस एल.एस. ने केवल 16,833 दौरे कुल लक्षित 29,220 दौरो के विरूद्ध किया।

जॉब आरिएन्टेशन प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और रिर्फेसर कोर्स का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कमी थी

3.1.11.4 प्रशिक्षण

योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार पूरी सेवा अवधि में एक बार जॉब आरिएन्टेशन प्रशिक्षण और प्रत्येक दो वर्षों मे एक बार रिर्फेसर कोर्स का प्रशिक्षण सभी सेविका, सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका और सी.डी.पी.ओ. को देना था। डी.एस.डब्लू.ओ. को सभी अप्रशिक्षित कर्मीयों की सूची निदेशालय को प्रशिक्षण हेतू उपलब्ध करानी थी।

डी.एस.डब्लू.ओ. के अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि जॉब आरिएन्टेशन और रिर्फेसर कोर्स का प्रशिक्षण अपर्याप्त थे जैसा कि **तालिका-8** में वर्णित है:

तालिका-8: प्रशिक्षण में कमी का विवरण (जुलाई 2012)

कोर्स	लक्ष्य			प्राप्ति			कमी		
	आ.से.	आं.स.	एल.एस.	आ.से.	आं.स.	एल.एस.	आ.से.	आं.स.	एल.एस.
जॉब आरिएन्टेशन	2428	2081	20	2057(85)	1426(69)	10 (50)	371(15)	655(31)	10(50)
रिर्फेसर	2428	2081	20	804(33)	343(14)	00(00)	1624(67)	1738(86)	20(100)

स्रोत: डी. एस. डब्लू. ओ. पलामू (कोष्टक की संख्या प्रतिशत दर्शाती है)

आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पर्यवेक्षिका के प्रशिक्षण में कमी आइ.सी.डी.एस. के विभिन्न घटकों की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था।

डी.एस.डब्ल्यू.ओ. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सभी अप्रशिक्षित सेविका, सहायिका और पर्यवेक्षिका के प्रशिक्षण हेतु कारवाई की जायेगी।

3.1.11.5 रोकड़ में पायी गई कमी

झारखण्ड कोषागार संहिता खंड-I के नियम 86(II) के अनुसार प्रत्येक माह की समाप्ति पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है ताकि रोकड़ बही में दर्शाये गये रोकड़ शेष को भौतिक शेष के साथ मिलान सुनिश्चित किया जा सके।

₹ 2.48 लाख की कमी की वसूली पूर्व नाजिर से की जानी थी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2012 को रोकड़ बही में अंतशेष ₹ 6,93,23,558 था जबकि अग्रिम पंजी, अभिप्रव पंजी एवं बैंक पास बुक/विवरणी के आधार वास्तविक शेष 31 मार्च 2012 को ₹ 6,06,84,887 पर पाया गया। इस प्रकार ₹ 86,38,671 की अंतर राशि सरकारी धन के गबन की ओर इंगित करता था जो कि डी.एस.डब्ल्यू.ओ. द्वारा लेखों का बैंक विवरणी के साथ मिलान नहीं किए जाने के कारण संभव हुआ।

डी.एस.डब्ल्यू.ओ. ने लेखों के मिलान करने के उपरान्त ₹ 2.48 लाख की कमी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) जो भूतपूर्व नाजिर से वसूलनीय था।

समापन बैठक के दौरान डी.एस.डब्ल्यू.ओ. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि भूतपूर्व नाजिर से राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीण विकास

3.1.12 सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना

सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना (स.ग्रा.स्व.यो.) का लक्ष्य है कि परिवारों में (स्वरोजगारी) सतत् आय की वृद्धि करके उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीबों को सामाजिक जुटाव, प्रशिक्षण एवं सामर्थ्यावान करने के साथ आय वृद्धि हेतु संपति का अर्जन करने की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाए। स्व.स.स. कि आय वृद्धि हेतु सम्पति अर्जित करने के लिए जिला के प्रमुख बैकों के माध्यम से ऋण एवं आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाए। सम्पूर्ण योजना का कार्यन्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जाना था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग दर्शिका (अक्टूबर 2009) के अनुसार जिला के प्रमुख बैंक द्वारा चयनित स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण

संस्थान (ग्रा.स्वा.प्र.सं.) की स्थापना की जानी थी। वर्ष 2008-12 की अवधि के दौरान जि.ग्रा.वि.आ., पलामू के पास ₹ 28.06 करोड़ की निधि उपलब्ध थी जिसमें से ₹ 16.56 करोड़ व्यय किया गया था, मार्च 2012 तक ₹ 11.50 करोड़ अव्ययित था।

जि.ग्रा.वि.आ., पलामू के अभिलेखों की लेखा जाँच (जून2012) में पाया गया कि वर्ष 2009-12 की अवधि के दौरान 1631 स्वा.स.स. गठित की गई थी (2009-10 के दौरान 430, 2010-11 के दौरान 730 एवं 2011-12 के दौरान 471)

स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण बैंक के वित्तीय सुविधा से वंचित होना पड़ा

- स्वा.स.स. के स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रमुख बैंक (भारतीय स्टेट बैक) के अधीन मार्च 2010 में ग्रा.स्वा.प्र.सं. की सृष्टि की गई थी। हमने यह पाया की ग्रा.स्वा.प्र.सं. की सृष्टि के उपरांत भवन की अनुपलब्धता के कारण 861 स्वा.स.स. को प्रशिक्षण प्रदान नही किया गया था। फलस्वरूप, प्रमुख बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने से अस्वीकार किया गया था। मार्च 2012 में भवन की व्यवस्था की गई एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रमुख बैक को ₹ 4.44 लाख (मार्च 2012) का भुगतान किया गया इस प्रकार 2010-12 के दौरान 861 स्वरोजगारियों को निर्दिष्ट लाभ से वंचित होना पड़ा।

  इस संबंध में कहे जाने पर,निदेशक लेखा, जि.ग्रा.बी.अ., पलामू ने माना कि (जुलाई 2012) मार्च 2010 से मार्च 2012 के दौरान स्व.स.स. को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

- इसके अलावे, कार्यपालक अभियंता, लधुसिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर को आठ प्रखण्डों[17] में बहुउद्देशीय सदभावना भवन जहाँ स्वा.स.सं. का प्रशिक्षण केंद्र एवं बैठके करना, कृषि उत्पादो का प्रदर्शनी एवं बिक्री स्थल का कार्य किया जायगा, के निर्माण हेतु ₹ 16लाख प्रति भवन की प्राक्कलित लागत पर ₹ 1.48 करोड़ अग्रिम (अप्रैल 2008) दिया गया था। इन भवनों को जुलाई 2008 तक पूर्ण करना था जो जून 2012 तक पूर्ण नहीं किया गया था, जबकि जुलाई 2011 तक ₹ 67.29 लाख का व्यय हो चुका था।

उप विकास आयुक्त पलामू द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2012) की भवन पूर्ण हो गये है एवं कार्यपालक अभियंता के साथ भवनों के हस्तान्तरण के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

[17] चैनपुर,छतरपुर, हरिहरगंज, लेसलीगंज, मनातु, मेदिनीनगर, सतबरवा एवं विश्रामपुर।

इस प्रकार ₹ 1.48 करोड़ व्यय होने के बावजूद सदभावना भवन निमार्ण के लिए निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायी।

3.1.13 इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जि.ग्रा.वि.अ. के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए कार्यान्वित होगा। इस योजना के अधीन, पलामू के लाभुकों को स्वयं गृह निर्माण हेतु ₹ 48,500 प्रति ईकाई की दर से दो किस्तों में भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

यह पाया गया कि, जि.ग्रा.वि.अ., पलामू के पास इं.आ.यो. के अंतर्गत ₹ 92.26 करोड़, 2009-12 की अवधि के दौरान उपलब्ध था, जिनमें से ₹ 74.08 करोड़ इस योजना में व्यय किया गया था।

निर्माण के लिए लिये गये गृहों में 33 से 79 *प्रतिशत्* अधूरे पड़े थे

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि 2009-12 के दौरान 25,136 गृह[18] निर्माण के लिए लिया गया था। जिनमें से कथित अवधि जून 2012 तक 20,356 गृह (81 *प्रतिशत*) पूर्ण हो गया था एवं 4,780 गृह (19 *प्रतिशत*) अपूर्ण था, इन गृहों को स्वीकृत तिथि से तीन माह के अंदर पूर्ण करना था। वर्ष 2009-12 के दौरान विभिन्न श्रेणी के अधीन निर्माणों (नई निर्माण, उच्च कोटि आदि) की भौतिक स्थिति को ***परिशिष्ट-3.7*** में दिखाया गया है। हमने यह पाया कि वर्ष 2011-12 के अंत तक 33 *प्रतिशत* गृह नये निर्माण के लिए लिये गये थे। यद्यपि, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इं.अ.यो. के अधीन गृहों का निर्माण/उन्नयन[19] कार्य का अनुपालन संतोषप्रद दिखाई दिया।

समापन बैठक के दौरान, लेखानिदेशक, जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2012) कि अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए त्वरित कारवाई की जाएगी।

3.1.14 आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा

वर्ष 2009-11 की अवधि के दौरान पलामू जिले को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। सूखा के डर के प्रतिकूलता के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया (अगस्त 2009 एवं अगस्त 2010) की बी.पी.एल. लोगों को

---

[18] 2009-10 से पूर्व के अनिर्मित गृह 4070 एवं 2009-10 के दौरान स्वीकृत 21066 गृह।

[19] नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अधीन 7533 गृहों को लिया गया था। समान्य श्रेणी 7176 (95 *प्रतिशत्*) गृह पूर्ण हो गये थे जब कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अधीन थे-2009-12 के दौरान उच्च कोटि के 4406 गृहो में से 4252 (97 *प्रतिशत्*) पूर्ण हो गये थे।

अतिरिक्त अनाज की व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा का संवर्धन के लिए मनरेगा। इसमें 1.27[20] लाख गृहस्थों को चालू योजनाओं जैसे अन्तोदय अन्न योजना (अ.अ.यो.), लक्षित जनवितरण प्रणाली (ल.ज.वि.प्र.) एवं अन्नपूर्णा इत्यादि के माध्यम से रोजगार दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, 1.43 लाख बी.पी.एल. के अतिरिक्त बी.पी.एल. के गृहस्थो का पहचान किया गया था परंतु जिन्हें उपरोक्त योजनाओं के अधीन शामिल नहीं किया गया था, को भी लेने का (नवम्बर 2010) निर्णय लिया गया था। संबंधित आपूर्ति निरीक्षकों/विपणन पदाधिकारियों के समग्र पर्यवेक्षण के तहत लाभार्थियों के बीच वितरित आवंटन के अनुसार उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) में खाद्यान एसएफसी द्वारा निर्गत किए जाते हैं.। जिला में लाभार्थियों के बीच एफपीएस के माध्यम से उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिम्मेदार था। विपणन पदाधिकारी (वि.पदा.) एफपीएस द्वारा उठाये गए रिपोर्ट को संकलित कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समेकित करता है। इस तरह, एसएफसी द्वारा जारी किए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा विपणन पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी की रिपोर्ट से मिलना चाहिए।

योजनाओं के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गई:

एसएफसी द्वारा जारी किये गये खाद्यान्न की मात्रा से एफपीएस नेटवर्क द्वारा रसीद में कम दिखाये गए

- एसएफसी के अनाज प्रतिवेदन एवं जि.आ.पदा. द्वारा उठाये गये चावलों के समेकित प्रतिवेदनों की जाँच में पाए गए कि एसएफसी द्वारा निर्गत परिमाण एवं उच्च मूल्य दुकान द्वारा प्राप्ति के माध्यम पाई गई विसंगतियों को ***परिशिष्ट-3.8*** में दिया गया है। 2009-12 अवधि के दौरान एसएफसी द्वारा उचित मूल्य दुकान को चावल का कुल परिमाण 14,13,426.46 क्विंटल निर्गत किये गए थे (गोदाम के अनाज प्रतिवेदन के अनुसार) जब कि उचित मूल्य की दुकानों में 12,12,778.46 क्विंटल की प्राप्ति दिखाया गया था (बि.प. द्वारा प्रतिवेदित जि.आ.प. द्वारा समेकित प्रतिवेदन के अनुसार)। इस प्रकार, अन्नपूर्णा, बी.पी.एल., अ.अ.यो. एवं अतिरिक्त बी.पी.एल. योजनाओं के अधीन ₹ 41.89[21] करोड़ मूल्य के 2,00,648 क्विंटल उचित मूल्य दुकान में कम प्राप्ति दिखाई गई थी। जि.आ.प. द्वारा विसंगतियों का समाधान नहीं किया गया था।
- इसके समरूप, 2009-11 के दौरान एसएफसी द्वारा उचित मूल्य दुकान को निर्गत गेंहू की कुल परिमाण 2,05,788.14 क्विंटल था जबकि

[20] बी.पी.एल. (0.64 लाख गृहस्थ), अ0अ0यो0 (0.50 लाख गृहस्थ) एवं अन्नपूर्णा (0.13लाख लाभुक)।

[21] किफायती मूल्य के अनुसार ₹ 2,088 प्रति क्विंटल।

बी.पी.एल. एवं अ.अ.यो. के अधीन 1,85,674.87 क्विंटल उचित मूल्य दुकान में प्राप्ति दिखाया गया था। जि.आ.प. द्वारा 20,113.27 क्विंटल गेंहू (₹ 3.07 करोड़ मूल्य[22]) के विसंगतियों का समाधान नहीं किया गया था।

समापन बैठक के दौरान जि.आ.प. के द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2012) कि समाधान किया जाएगा।

3.1.15 शहरी विकास

शहरी विकास विभाग का समग्र उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र के नागरिको को नगरिय सुख-सुविधायों की व्यवस्था की जाय। शहरी नागरिकों को सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए विभाग विभिन्न तरह के कार्यक्रम करता है। जिला स्तर पर, नगर परिषद (नगरपालिका परिषद) द्वारा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है। नगर परिषद द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों की विवेचना निम्नांकित है:

3.1.15.1 समेकित गृह एवं बस्ती विकास कार्यक्रम (स.गृ.ब.वि.का.) के कार्यान्वयन में बिलम्ब

स.गृ.ब.वि.का. एक केंद्र प्रायोजित योजना जो जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अधीन लाभुकों द्वारा स्वयं गृह निर्माण एवं बस्ती क्षेत्र के निवासी को आधारभूत सुख-सुविधाएं प्रदान करने के लिए नगरपालिका परिषद, पलामू द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नगरपालिका परिषद को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.प.प्र.) तैयार करने की जिम्मेवारी है। बस्ती निवासियों की पहचान करना वि.प.प्र. का एक घटक था। वि.प.प्र. के आधार पर चयनित लाभुकों को तीन किस्तों में ₹ 1.81 लाख प्रतिनिवास ईकाई वितरित किया जाना था। इन गृहों को 18 महीने में पूर्ण करना था। इस योजना कि अवधि मार्च 2012 तक था।

हम लोगों ने यह पाया कि वि.प.प्र. में 969 लाभुकों का चयन (सितम्बर 2008) किया गया था एवं इनके नाम सितम्बर 2008 में विभाग को अग्रसारित किया गया था। विभाग द्वारा ₹ 11.36 करोड़ (फरवरी 2010 एवं मई 2012 के मध्य) विमुक्त किया गया था। हमने यह भी पाया कि केवल 420 लाभुकों का चयन किया गया था, चूंकि इनके पास निवासी इकाई निमार्ण के लिए भूमि थी। योजना के अनुसार शेष 549 लाभुक, भूमि का मालिकाना प्रमाण नहीं दिखा सके।

[22] किफायती मूल्य के अनुसार ₹ 1,526 प्रति क्विंटल।

2010-11 के दौरान 420 निवासी इकाई निमार्ण के लिए लिया गया था जिसके लिए लाभुको को ₹ 4.42 करोड़ वितरित किया गया था। यद्यपि, नगरपालिका परिषद के प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, दिसम्बर 2012 तक सभी 420 निवासी इकाई अपूर्ण थे।

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2012) कि योजना को पूर्ण करने को लिये त्वरित कारवाई की जायगी। उत्तर उपयुक्त नहीं था क्योंकि कार्यों को समय पर पूर्ण करने का उत्तरदायित्व नगरपालिका परिषद का था।

इस प्रकार, ₹ 4.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था, इसके अलावे वि.प.प्र. तैयारी के प्रक्रम में लाभुकों के दोषपूर्ण चयन के कारण नगरपालिका परिषद के पास ₹ 6.94 करोड़ अवरूद्ध पड़ हुए थे।

3.1.15.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत जमीन भराव निर्माण के लिए निधि का अनुपयोगी रहना

मेदिनीनगर में प्रस्तावित जमीन भराव निर्माण नहीं होने के कारण व्यक्तिगत लेजर खाते में अक्टूबर 2006 से निधि पड़ी हुई थी

नगरपालिका परिषद क्षेत्र, मेदिनीनगर के ठोस अपशिष्ट के निपटान के उद्देश्य से, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा (सितम्बर 2006) मेदिनीनगर में भूमि भराव निमार्ण के लिए शहर के समीप ₹ 4.50 करोड़ के प्रकलित राशि पर 30 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए विभाग को अनुरोध किया गया था। तदनुसार, 10 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए ₹ 1.50 करोड़ विमुक्त किया गया था (अक्टूबर 2006)। भूमि का प्रबंध करने के लिए नगरपालिका परिषद द्वारा उपायुक्त को (अप्रैल 2008) अनुरोध किया गया था। यद्यपि, दिसम्बर 2012 तक जिला प्रशासन द्वारा भूमि भराव के उद्देश्य से भूमि का चयन नहीं हो पाने के कारण नगरपालिका परिषद, मेदिनीनगर को भूमि का प्रबंध नहीं किया गया था। अक्टूबर 2006 से अब तक नगरपालिका परिषद के व्यक्तिगत लेजर लेखे में राशि रखा हुआ था।

इस प्रकार, भूमि की अनुपलब्धता के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना दिसम्बर 2012 तक कार्यान्वित नहीं हो सका था एवं योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी।

समापन बैठक के दौरान, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2012) कि त्वरित कारवाई की जाएगी।

3.1.16 पेयजल और स्वच्छता

भारत सरकार ने 1972 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू की जिसका नाम राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (1991-92) का नाम दिया गया था। यह सभी ग्रामीण बस्तियों के लिए हर 250 व्यक्तियों के लिए एक

पीने के पानी के स्त्रोत की स्थापना के द्वारा सुरक्षित पीने के पानी की निर्धारित मात्रा (40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ लागू किया गया था। पलामू जिला में ग्रामीण बस्तियों में (संख्या 6,806) ग्रामीण आबादी (17.10 लाख) जो पहले से ही 18,319 नलकूपों (मार्च 2012) के माध्यम से पेयजल प्रदान की जा रही थी।

इसके आलावा राष्ट्रीय गामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) के दिशा निर्देशों के अनुसार, सुरक्षित पेयजल सम्पूर्ण आबादी को स्थायी रूप से प्रदान किया जाना था जो कि ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना (आर.पी. डब्लू. एस. एस.) की स्थापना के माध्यम से संभव किया जाना था। पलामू जिले में, कुल 353 आर.पी.डब्लू एस.एस. योजना स्वीकृति किया गया जिसमें केवल 153 योजनाओं को 2009-12 की अवधि के दौरान पूरा किया जा सका।

लेखापरीक्षा में पाई गई प्रमुख निष्कर्ष की नीचे चर्चा की जा रही है।

पाइप जल आपूर्ति योजनाएं

अधूरी पाईप जल आपूर्ति योजना पर कुल ₹ 19.17 करोड़ का निष्फल व्यय

25,000 निवासियों के आबादी के लिए, विश्रामपुर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना[23] कार्यपालक अभियन्ता, डी.डब्लू. एण्ड एस. प्रमण्डल, पलामू के द्वारा फरवरी 2008 में एक ठेकेदार को ₹ 7.54 करोड़ की सहमति से दिया गया जिसे फरवरी 2009 तक पूरे किये जाने थे। यद्यपि कार्य को विवाद मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण रद्ध (दिसम्बर 2008) कर दिया गया था। यह कार्य भूमि विवाद को हल किये बिना दूसरे ठेकेदार को ₹ 9.70 करोड़ की लागत पर जुलाई 2011 तक पूर्ण करने हेतु दिया गया (जनवरी 2010)। परिणामस्वरूप, दिसम्बर 2012 तक ₹ 6.90 करोड़ मुल्य की पाईप खरीद को छोड़कर कोई भी कार्य नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता (का.अ.) द्वारा पाइप की लागत ₹ 6.90 करोड़ ठेकेदार को भूगतान (फरवरी 2012) तक कर दिया गया। इस वजह से विभाग द्वारा बाधाओं को बिना हल किये ₹ 6.90 करोड़ के व्यय के रूप में नवम्बर 2012 तक अधुरे कार्य पर निष्फल व्यय बने रहे फलस्वरूप पानी की आपूर्ति के लाभ से विश्रामपुर के निवासी वंचित रहे।

50,000 लोगों की आबादी के लिए बारालोटा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना निविदा के बाद लिया गया था जिसे एक ठेकेदार को सहमति लागत ₹ 16.38 करोड़ पर आवंटित किया गया (अक्टुबर 2009) जिसे जनवरी 2011 तक पूरा किया जाना था।

[23] वाटर ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट, पाइप की खरीद एवं विछाव, मिट्टी कार्य इत्यादि।

हमने पाया कि कोई भी काम (दिसम्बर 2012) नहीं किया गया सिवाय ₹ 12.27 करोड़ मूल्य की पाईप की खरीद के जिसका भुगतान कार्यपालक अभियंता द्वारा फरवरी 2012 में भुगतान कर दिया गया। यह देखा गया कि, हार्ड रॉक निमार्ण स्थल पर पाये जाने के कारण ठेकेदार द्वारा काम शुरू नहीं किया गया और ब्लास्ट करने के लिए अनुमति की मांग (मई 2010) में की गई जिसे पलामू डी.सी. द्वारा मार्च 2012 में अनुमति दी थी। इसके फलस्वरूप ₹ 12.27 करोड़ का निष्फल व्यय के अलावे बारालोटा के निवासियों को लाभ से वंचित रखा गया।

समापन बैठक के दौरान (दिसम्बर 2012) कार्यपालक अभियंता ने कहा कि दोनों कार्य को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

3.1.16.1 फ्लोराइड मिटिगेसन योजनाओं का कार्यान्वयन

वर्ष 2005-06 में, डी. डब्लू एण्ड एस. प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत भूमिगत जल में फ्लोराइड प्रदूषण का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के आधार पर विभाग 1,679 फ्लोराइड रिमुभल एटैचमेन्ट युनिट ₹ 7.26 करोड़ की लागत से वर्ष 2008-09 के दौरान पहले से ही गाड़े गए नलकूपों के लिए मंजूरी दी। यह कार्य कलकत्ता आधारित आपूर्तिकर्ता को (जून 2008) दिया गया जिसे कार्य आदेश की तारीख से तीन महीने में चालू करना था। एग्रीमेन्ट के नियम एवं शर्त्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को दो साल तक इन यूनिटों का सफल रख-रखाव किया जाना था जिसके विरूद्ध प्रमण्डल द्वारा कुल लागत का दस *प्रतिशत्* रखा जाना था एवं सफल रख रखाव के उपरान्त वापस करना था। हम लोगों ने देखा कि आपूर्तिकर्ता द्वारा काम नवम्बर 2008 एवं अगस्त 2009 के बीच कार्य सम्पन्न किया गया एवं ₹ 7.01 करोड़ बिना दस *प्रतिशत्* रख-रखाव की गारंटी को रोके भुगतान कर दिया गया। यद्यपि आपूर्तिकर्ता फलोराइड रिमुभल एटैचमेन्ट यूनिटों को समझौते की शर्तो के अनुसार नहीं बनाए रखा था। फलस्वरूप, सभी स्थापित इकाइयाँ मई 2011 एवं मई 2012 के दौरान अकार्यशील हो गया एवं ₹ 7.01 करोड़ का कुल व्यय निष्फल हुआ।

समापन बैठक के दौरान कार्यपालक अभियन्ता, डी.डब्लू. एण्ड एस. (दिसम्बर 2012) ने कहा कि इस मामले की अच्छी तरह से जाँच की जाएगी।

आर्थिक क्षेत्र

3.1.17 राज्य पथ

जिला सड़क संचार पर अधिक निर्भर है चूँकि यहाँ केवल 29 रेल हेड दो प्रखण्ड एवं एक शहर से गुजरती है। राज्य सड़के दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों को अर्थव्यवथा के समस्त विकास के लिए जिला मुख्यालय के करीब लाता है।

सड़क निमार्ण विभाग (आर.सी.डी.) प्रशासनिक विभाग है जो नई सड़के, मौजूदा सड़कों की सुधार एवं चौड़ी करण, रख रखाव एवं निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ग्रामीण कार्य विभाग (आर.डब्लू.डी.) ग्रामीण कार्य प्रमण्डलों के द्वारा ग्रामीण कालीकृत सड़कों के निमार्ण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार थे। जिले में दिसम्बर 2012 तक 241.14 कि.मी.राज्यमार्ग, 124 कि.मी. राष्ट्रीय मार्ग एवं 550.135 कि.मी. ग्रामीण कालीकृत सड़के थे। 16 राज्य सड़कों[24] में से छ:[25] सड़के (111.99 कि. मी.) को 2009-12 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु लिया गया था, जिसमें से दो[26] सड़के (68.375 कि.मी.) पूर्ण थे, तीन[27] सड़के (39.54 कि.मी.) प्रगति में थे एवं एक सड़क (4.075 कि.मी.) निविदा के अंतिम चरण में थे।

यद्यपि सडकों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य लिये गये थे। लेकिन 2009-12 के दौरान जिलों में राज्य पथों की लम्बाई अपरिवर्तित रहे।

3.1.17.1 कार्यों की अपूर्णता

झारखण्ड लोक निमार्ण लेखा संहिता [28] (जे.पी.डब्लू.ए.) के अनुसार किसी कार्य का प्राकलन बनाने के पूर्व किसी भी परियोजना हेतु फोरेस्ट भूमि की मंजूरी निश्चित किया जाना चाहिए। आगे, इंडियन रोड कांग्रेस (आई.आर.सी.) के अनुसार, यातायात की आवागमन की मंजूरी के पहले पूर्ण रूप से वाटर बाउन्ड मेकाडम (डब्लू.बी.एम.) के ऊपर कालीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- विश्रामपुर महुआगाँव इटको रोड (18.90 कि.मी.) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु जून 2009 में सहमति राशि ₹ 10.23 करोड़ पर लिया गया था जिसे जुलाई 2010 (जून 2012 तक विस्तारित) तक पूर्ण किया

---

[24] एकल: छ: (71.70 कि.मी.), मध्यवत्ता लेन (124.27 कि.मी.) दोहरा लेन एक (45.17 कि.मी.)

[25] छत्तरपुर-डुमरिया, मेदिनीनगर-लेस्लीगंज-पँकीपथ, विश्रामपुर-महुआगाँव-इटको पथ, मेदिनीनगर-चैनपुर पथ, मेदिनीनगर हरिहरगंज पथ एवं कजरी-पाटन-मनातू पथ।

[26] मेदिनीनगर-लेसलीगंज-पाकी पथ एवं छत्तरपुर-डुमरिया पथ

[27] विश्रामपुर-महुआगाँव-इटको पथ, मेदिनीनगर-चैनपुर पथ, मेदिनीनगर-हरिहरगंज पथ एवं कजरी-पाटन-मनातू पथ।

[28] एनेक्जर-ए-कैबिनेट एवं कोओरडिनेशन विभाग (निगरानी सेल) रिजोलुसन संख्या-948 दिनांक 16 जुलाई 1986-पैरा-4.5 एवं 6.3

जाना था। कार्य के मद में डब्लू.बी.एम. एवं कालीकरण कार्य निहित थे। मजबूतीकरण के काम के लिए फारेस्ट क्लियरेंस (मई 2008) सशर्त दिया गया था कि कोई पेड़ की कटाई न हो एवं कोई भी सड़कों का चौड़ीकरण न किया जाय।

अपूर्ण कार्यो पर ₹ 6.03 करोड़ की निष्फल व्यय

हमने पाया कि ठेकेदार फरवरी 2012 तक केवल डब्लू.बी.एम. स्तर तक ही कार्य निष्पादित किया था एवं ₹ 6.03 करोड़ का भुगतान (मई 2012) इस मद में किया गया। इसके बाद, वन विभाग के शर्तो के उल्लंघन के कारण वन विभाग द्वारा कार्य बन्द करवा दिया गया था। फलस्वरूप कालीकरण कार्य ठेकेदार द्वारा (मई 2012) नहीं किया गया। आई.आर.सी के पारा 4.8.2 में निहित प्रावधान के अनुसार बिना कालीकरण कार्य के यातायात आवागमन हेतु उपयुक्त नहीं था। इस प्रकार पूरे डब्लू.वी.एम. कार्य लागत ₹ 6.03 करोड़ निष्फल हुआ।

समापन बैठक (दिसम्बर 2012) में का.अ. ने कहा कि भविष्य में इस तरह के कार्य में पूर्व में ही फारेस्ट क्लियरेंस लिया जायगा ।

3.1.18 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़क की स्थिति

निमार्ण, उन्नयन और जिले में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव प्रधान मंत्री सड़क योजना और राज्य योजना दोनों के तहत लिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007) के अंत तक 500 से अधिक आवादी के साथ सभी ग्रामीण वस्तियों को सभी मौसम सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए दिसम्बर 2000 में किया गया था। आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के साथ बस्तियाँ कनेक्टिविटि के लिए पात्र थे। गाँवों से गुजरती सड़के को एक ठोस पेभमेन्ट, डस्टप्रुफ एवं कम रखरखाव वाले सड़क उपलब्ध कराए जाने थे।

3.1.18.1 योजना

योजना प्रायोजनार्थ 2001-2002 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसके आधार पर एक जिला कोर नेटवर्क पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के चयन के लिए तैयार किया गया था।

सर्वेक्षण के अनुसार जिला के ग्रामीण निवासों का करीब 53 *प्रतिशत* (1,754 में से 924) सभी मौसम सड़कों से असंबद्ध पाया गया। तदनुसार, पीएमजी-एसवाई के अन्तर्गत सभी असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को संबद्धता प्रदान करने के लिए सड़कों का संशोधित कोर नेटवर्क एवं नयी संबद्धता प्राथमिकता सूची

का कोर नेटवर्क (सी.एन. सी.पी.एल.) तैयार किया गया था (2005)। सी.एन.सी.पी.एल. में 221 सड़के 912.15 कि. मी. लम्बाई में सम्मिलित थे। जिसे प्राथमिकता के आधार[29] पर 518 ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने थे। 518 ग्रामीण बस्तियों में से, 222 ग्रामीण बस्तियों को 2008-09 तक (VI चरण) तक जोड़ दिया गया था।

296 असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों में से 269 ग्रामीण बस्तियों को 125 सड़के (440 कि. मी.) सी.एन.सी.पी.एल में से 2009-12 (VII चरण) के दौरान स्वीकृत किया गया।

दिसम्बर 2012 तक इन सड़कों (125) की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति ***परिशिष्ट-3.9*** में दिया गया है।

लक्षित 181 ग्रामीण बस्तियों असंबद्ध रहे।

हमने पाया कि 125 सड़कों में से 39 सड़के (31 *प्रतिशत*) दिसम्बर 2012 तक पूर्ण कर दिये गये थे एवं 86 सड़के ₹ 42.60 करोड़ का व्यय उपरान्त अधूरे रह गये। ई.ई. ने (अगस्त 2012) में कहा कि ठेकेदार द्वारा प्रगति में देरी, नक्सल समस्याऐं, कोलतार के अभाव एवं फारेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही। अत: लक्षित 181 ग्रामीण बस्तियों सभी मौसम सड़कें से असंबद्ध रह गये।

3.1.18.2 गुणवत्ता नियंत्रण

पी.एम.जी.एस.वाई के तहत, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सभी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेवार हैं। परीक्षण करने के लिए योग्य कर्मचारियों के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में किये जाने हैं। ठेकेदारों द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए एक गुण नियंत्रण पुस्तिका संसाधारण किया जाना जरूरी है। राज्य गुणवत्ता मोनीटर (एस.क्यू.एम.) को कमसे कम दो बार सड़कों की निरीक्षण करना चाहिए। पहला निरीक्षण कार्य के दौरान एवं अन्तिम निरीक्षण कार्य के पूरा होने के एक महीने के भीतर एस.क्यू.एम. के द्वारा किया जाना चाहिए।

सभी इंगित कार्य ''असंतोषजनक'' या पुनरूद्वार हेतु आवश्यक'' को राज्य गुणवत्ता कोओडिनेटर द्वारा प्राप्त सुधारात्मक रिर्पोट को नेशनल गुणवता मोनीटर (एन.क्यू.एम.) या एस.क्यू.एम. द्वारा पून: निरीक्षण करना आवश्यक है।

---

[29] प्रथम प्राथमिकता 1000+ ग्रामीण बस्तियॉ: द्वितीय प्राथमिकता:500+ ग्रामीण बस्तियों एवं सबसे कम प्राथमिकता: 250+ ग्रामीण बस्तियों।

एस.क्यू.एम. द्वारा मार्च 2012 तक 82 सड़कों का निरीक्षण किया गया जिसमें छः सड़कों को 'पुनरूद्वार हेतु आवश्यक' बताया गया।

एस.क्यू.एम. के निरीक्षण रिपोर्ट की जाँच से पता चला कि 2009-12 के अवधि दौरान 20 पूर्ण सड़को में से 15 सड़के का निरीक्षण एस क्यू.एम. द्वारा दो बार एवं पॉच सड़कों का केवल एक बार किया गया। मार्च 2012 तक एस क्यू.एम. द्वारा 82 निरीक्षित सड़कों में से छः सड़कें ''सुधार की आवश्यकता'' इंगित किया गया। इन सड़कों पर की गई कारवाई का कोई अभिलेख नहीं था। अतः इन सड़कों की गुणवत्ता का द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण मोनीटर द्वारा सत्यापित नहीं किया गया यथा एस क्यू.एम. एवं एन. क्यू. एम/गुणवत्ता नियंत्रण पुस्तिका भी पी.आई.यू. द्वारा नहीं संधारित किया गया। इस प्रकार पी.आई.यू. ने गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण ठेकेदार के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया एवं एस.क्यू.एम. द्वारा गुणवत्ता परीक्षण भी अपर्याप्त थी। अतः निम्न गुणवत्ता सड़कों के निर्माण से इंकार नहीं किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता (जून 2012) लेखापरीक्षा मार्ग दर्शन को भविष्य के लिए अवलोकन हेतु इंगित किया ।

3.1.18.3 पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों का असंधारण

पीएमजीएसवाई के दिशा निर्देश अनुच्छेद 17.2 के अनुसार, पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के संधारण की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। अतिरिक्त, अनुबंध के संधारण अनुच्छेद में सड़कों की पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षों तक का दोषदायित्व अवधि समाविष्ट था। इस अवधि के दौरान, संवेदक द्वारा हर महीने सड़कों का निरीक्षण अपेक्षित था और सामान्य संधारण एवं आवश्यक सुधारों द्वारा सड़क को यातायात के लायक प्रशस्त रखना था। पी.आई.यू. द्वारा भी प्रत्येक माह सड़कों का निरीक्षण आवश्यक था।

2007-12 के दौरान 31 पूर्ण रोड़ (123.77 किमी) का मरम्मत नहीं किया गया

प्रोग्राम कार्यान्वयन यूनिट (पी.आई.यू.) पलामू के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ की 31 सड़कें (123.77 कि.मी.) ₹ 27.86 करोड़ की लागत से 2007-12 में पूर्ण किये गये। ठेकेदार द्वारा इन सड़कों का संधारण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा पर झारखण्ड ग्रामीण राज्य विकास अभिकरण (जे.आर.एस.आर.डी.ए.) सितम्बर 2012 में कहा कि पी.आई.यू. द्वारा न तो रख-रखाव का बिल प्रस्तुत किया न ही धन की मांग की गई।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (10 जून 2012) के दौरान हमने पाया कि एक सड़क बुधीवीर से चोट्टासा (5.10 कि. मी.) पूर्ण स्ट्रेच् पर पौट हौल पूरे खंड पर थे एवं पी.सी.सी. सतह भी टूटे एवं क्षतिग्रस्त थे। (छायाचित्र नीचे),

हाँलाकि संधारण का अनुबंध भी मई 2008 में किया गया। यह भी पाया गया कि एस.क्यू.एम. दल भी इस सड़क का निरीक्षण कार्य के दौरान किया था लेकिन इसे समाप्ति के बाद निरीक्षण नहीं किया। यद्यपि, संधारण अनुबंध ठेकेदार के साथ था। संधारण न तो ठेकेदार द्वारा किया गया न ही का.अ. ने ठेकेदार को संधारण हेतु अनुदेशित किया। इस प्रकार पी.एम.जी.एस.वाई. का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण वस्तियों को सभी मौसम की सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।



(बुद्धिवीर से चोट्टासा तक बिटुमिनस सड़क की जर्जर स्थिति को प्रदिर्शित करती छायाचित्र)



(बुद्धिवीर से चोट्टासा तक पीसीसी सड़क की जर्जर स्थिति को प्रदिर्शित करती छायाचित्र)

कार्यपालक अभियंता ने (जून 2012) कहा कि अनुबंध के अनुसार कार्रवाई की जायगी।

3.1.19 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.भी.वाई)

सभी ग्रामीण गृहस्थों को विद्युत उपलब्ध कराने तथा 2009 तक वैद्युतिक आधारभुत संरचना के संवर्धन के उद्देश्य के साथ भारत सरकार (जी.ओ.आई) नें मार्च 2005 में आर.जी.जी.भी.वाई. की शुरूआत की।

पलामू जिला में योजना को झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.इ.बी.) लागू कर रहा था। आर.जी.जी.भी.वाई. के निरीक्षण हेतू जे.एस.इ.बी. ने टेलीकम्युनिकेशन कनसल्टेन्टस इंडिया लिमिटेड (टि.सी.आई.एल) को तृतीय पक्ष निरीक्षण अधिकरण के रूप में नियुक्त किया। जिला स्तर पर विद्युत अधीक्षण अभियन्ता (वि.अ.अ.) योजना के तहत कार्यों के क्रियान्वयण हेतू नोडल अधिकारी था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (ग्रा.वि.नि.) योजना के वित्तपोषण तथा क्रियान्वयण के लिए नोडल अभिकरण था।

1,457 गाँवों में से मात्र 668 गॉव विद्युतीकृत हुए।

आर.जी.जी.भी.वाई. के तहत दिसम्बर 2006 से जून 2008 के दौरान पलामू जिले के 1,457 गाँवों को ₹ 185.33 करोड़ के लागत से विद्युतीकरण नियोजित था। पलामू जिला में विद्युतीकरण (पैकेज जी) का कार्य हैदराबाद अवस्थित एक संवेदक को टर्नकी आधार पर दिसम्बर 2006 में दिया गया था। कार्य की लागत को पुनर्रिक्षित करते हुए ₹ 214 करोड़ करने का एक प्रस्ताव किया गया (अगस्त 2009) परन्तु ग्रा.वि.नि. ने अनुमोदित नहीं

किया। योजना के अन्तर्गत 1,15,068 निर्धनता रेखा के अधीन (बी.पी.एल.) गृहस्थों को एकल बिन्दु विधुत क्नेक्शन दिया जाना था। झारखण्ड सरकार तथा जे.एस.इ.बी. दोनों को परियोजना पूर्ण होने तथा गाँवों को विद्युतिकृत घोषित करने के पूर्व यह सुनिश्चत करना था कि ग्रामीण विद्युत वितरण स्तंभ[30] (ग्रा.वि.वि.स.) की व्यवस्था, ग्रामीण वितरण के प्रबंध हेतु फ्रेचाइजी की नियुक्ति तथा 100 *प्रतिशत्* पुंजीगत सहाय्य के साथ अविद्युतिकृत बी.पी.एल. गृहस्थों को विद्युतीकरण[31] हो। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत निम्न बिन्दु उजागर हुए।

- जून 2008 तक जिले में 1457 गाँवों में निहित 1.15 लाख बी.पी.एल. गृहस्थों का विद्युतीकरण लक्षित था। जबकि मार्च 2012 तक 668 गॉवों का विद्युतीकरण पूर्ण हो सका था तथा 789 गाँवों में कार्य प्रगति पर था। 668 विद्युतिकृत गाँवों में से मात्र 214 गाँवों को आवेशित किया जा सका था अर्थात विद्युत उप-केन्द्रो (पी.एस.एस.) से जोड़ा गया था। हमने पाया कि चार पी.एस.एस. जो पूर्ण करने थे, में से तीन का निर्माण पूर्ण हो गया था। इन पूर्ण पी. एस. एस. में भी कमियाँ थी, जैसे कि नियंत्रण कक्ष तल निर्माण, स्ट्रिंगिंग कार्य, अर्थिंग तथा ग्रेवलिंग, ट्रेन्च कभर, वैद्युतिक कार्य, नहीं हुए थे, जैसा कि टेलीकम्युनिकेशन कन्सल्टेन्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा उनकी निरीक्षण में उजागर हुआ। अत: इन गाँवों के विद्युतीकरण में खर्च किये गए ₹ 57.75[32] करोड़ अधिकांशत: अलाभकारी हो गया, क्योकि 454 गाँव विधुत से वंचित रह गए।
- जे.एस.इ.बी. के द्वारा मात्र 415 आवेशित गाँवों को अधिग्रहित किया गया। परिणामत: जुलाई 2012 तक 668 गाँवों में 44,535 विद्युतीकृत बी.पी.एल. कनेक्शनों में से मात्र 17,056 बी.पी.एल कनेक्शन का विपत्रीकरण हो पाया। इसका परिणाम हुआ कि ₹ 9.62[33] लाख प्रतिमाह

---

[30] ग्रा. वि. वि. स्. का अर्थ विद्युत वितरण हेतु पर्याप्त क्षमता के उप-केन्द्रों तथा लाइनो का प्रावधान है।

[31] एक गाँव तभी विद्युतीकृत घोषित किया जा सकता है, जब

(i) मुल आधारभुत संरचना जैसे कि वितरण ट्रान्सफॉमर तथा वितरण लाइन दलित वस्तियों/छोटा गाँव सहित सभी बसाहटों में व्यवस्था।

(ii) विधालयों, पंचायत, स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि लोक स्थानों को विद्युत उपलब्ध कराना, तथा

(iii) विधुतीकृत गृहस्थों की संख्या, गाँव के कुल गृहस्थों की संख्या का कम-से-कम 10 *प्रतिशत्* हो।

[32] एक गाँव के विधुतीकरण की औसत लागत (कुल समझौता लागत ₹ 1853254319/1457 गॉव= ₹ 12,71,966) x अनावेशित गाँवों की संख्या (454)= ₹ 57,74,72,564

[33] टैरिफ के अनुसार दर (₹35)xअविपतिकृत क्नेक्शनों की संख्या (27479)

की निरन्तर राजस्व हानि 27,479 संबंधों के विपत्रीकरण नहीं होने के कारण हुआ।

- पुन: 668 गाँवों में से 305 गाँवों को विद्युतिकृत घोषित करते हुए विद्युतीकरण प्रमाण पत्र निर्गत हुआ तथा शेष गाँवों में प्रमाण पत्र निगर्मन प्रक्रियाधीन है। अत: 363 गाँवों का विद्युतीकरण विद्युतिकृत घोषित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार पुर्ण नहीं था क्योकि प्रखण्ड विकास प्रदाधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुए थे।
- सदर प्रखण्ड के जमुनई गाँव में 63 के. वी.ए. का एक ट्रान्सफॉरमर दिसम्बर 2004 में जला हुआ बताया गया, जिसे प्रतिस्थापित करना था। ट्रान्सफॉरमर को प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा जे.एस.इ.बी. ने उक्त गाँव को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में सम्मिलित कर लिया। एक 63 के.वी.ए. के ट्रान्सफॉरमर की लागत (₹ 36,727) का ध्यान में रखते हुए इस गाँव के विद्युतीकरण में खर्च हुए ₹12.35[34] लाख परिहार्य था।
- आर.जी.जी.भी.वाई. के अन्तर्गत विधुत क्नेक्शन कुटिर ज्योति योजना (के.जे.पी.)[35] के मानको के अनुरूप दिया जाना था। 44,535 विधुतीकृत बी.पी.एल. क्नेक्शनों को मीटर लगाने में ₹3.86[36] करोड़ का खर्च निष्फल रहा। क्योकि इन बी.पी.एल. कनेक्शन का मीटर पाठन नहीं लिया जा रहा था तथा उन्हे निर्धारित राशि से विपत्र दिया जा रहा था।
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा गाँव को विद्युतीकृत घोषित करने के लिए निर्गत प्रमाणपत्रों की नमुना जाँच में यह देखा गया कि किसी भी गाँव में लोक स्थानों को विद्युत क्नेक्शन नहीं दिया गया था। 305 गाँवों में से 28 गाँवों में योजना की आवश्यकता के अनुरूप कुल गृहस्थों का न्युनतम 10 प्रतिशत को विद्युतीकृत कियें बिना, विद्युतकृत घोषित कर दिये गया। हमने यह पाया कि 39 गाँवों में विद्युतीकृत बी.पी.एल. गृहस्थों की संख्या गाँव के कुल विद्युतीकृत गृहस्थों की संख्या से अधिक दिखाई गई थी, जो आँकड़ों की विश्वसनीयता पर शंका उत्पन्न करता है।

---

[34] एक गाँव के विद्युतीकरण की औसत लागत (₹ 12.72 लाख)-63 के.वी.ए. के ट्रान्सफॉरमर की लागत (₹ 36727) = ₹12.35 लाख

[35] के.जे.पी. मानकों के अनुसार कनेक्शन 100 *प्रतिशत्* पुंजीगत सहास्य के साथ निशुल्क उपलब्ध कराना थ। पलामू में के.जे.पी तथा आर.जी.जी.भी.वाई. के अनतर्गत मीटर उपलब्ध कराने की लागत क्रमश: ₹ 750 तथा ₹ 1616 थी।

[36] मीटर को सम्मिलित करने के कारण लागत मे वृद्धि (₹ 866) x कुल निर्गत कनेक्शनों की संख्या (44,535) =₹ 3,85,67,310

समापन बैठक के दौरान वि.अ.अ. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि कारवाई की जाएगी।

सामान्य प्रक्षेत्र

3.1.20 कानून व्यवस्था

पलामू नक्सल प्रभावित जिला है। जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक जो कि जिले की आंतरिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी हैं के प्रशासनिक अधिकार के अधीन 21 थाना एवं तीन पुलिस आउटपोस्ट कार्यरत थे। पुलिस को आधुनिक हथियार, वाहन एवम् आवासीय व्यवस्था मुहैया कराने हेतु एक केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना राज्य में लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत योजनाकरण, निधि की व्यवस्था, आधुनिक हथियारों, वाहनों इत्यादि का क्रय पूरे राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाना था।

इस योजना के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन में पायी गई त्रुटियाँ आगे की कंडिकाओं में वर्णित है:

3.1.20.1 आधारभूत संरचनायें एवं सुरक्षा व्यवस्था

सभी आरक्षियों को अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने हेतु सभी थानों एवम् आउटपोस्ट में पर्याप्त आधारभूत संरचना और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना जरूरी है। यह पाया गया कि थानों और आउटपोस्ट के मूल आधारभूत सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त थे। 21 में से पाँच थानों तथा तीन में से दो आउटपास्ट के पास अपना भवन नहीं था। पाँच पुलिस थानों में बैरक की व्यवस्था नहीं थी और केवल हुसैनाबाद थाना में एक वाच टावर उपलब्ध था।

इस तरह से नक्सल प्रभावित जिला में पर्याप्त आधारभूत संरचना सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण थाना/आउपोस्ट को उग्रवादी हमलों का काफी जोखिम था।

3.1.20.2 पुलिसकर्मियों के आवासीय भवन

राष्ट्रीय पुलिस कमीशन (एन.पी.सी.) ने विशेषकर सभी उच्च और निम्न वर्गीय[37] सबआर्डिनेट पुलिसकमिर्यों के लिए आवास की व्यवस्था की संस्तुति की है। परंतु पलामू जिला इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे था जैसा कि **तालिका-9** में दर्शाया गया है:

[37] उच्च वर्गीय: सहायक सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तथा निम्नवर्गीय: हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल

तालिका-9: आवश्यकता के विरूद्ध उपलब्ध आवासीय सुविधा

भवनों के प्रकार	कुल आवश्यकता	31 मार्च 2012 की स्थिति	कमी (*प्रतिशत*)
निम्न सबआर्डिनेट के लिए आवास	786	115	671(85))
उच्च सबआर्डिनेट के लिए आवास	369	82	287(78)
बैरक	65	38	27(42)
गैराज	218	24	194(89)

स्रोत: पुलिस अधीक्षक, पलामू

इस तरह जिले में मूल आधारभूत संरचना की कमी 42 और 89 *प्रतिशत* के बीच था जिसके कारण पुलिसकर्मियों की कार्यदक्षता स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी था।

3.1.20.3 पुलिसकर्मियों की गतिशीलता

जिले में पुलिस बल द्वारा अंतरिक सुरक्षा के लिए दक्षता पूर्वक काम करने एवं प्रतिक्रिया समय को कम करने हेतु पुलिस आधुनिकीकरण में पुलिस की क्रियाशीलता को बढाना एक मूख्य ध्येय था। वर्ष 2009-12 में जिला पुलिस बल के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वाहनों की स्थिति **तालिका-12** में दी गयी है:

तालिका-10: जिला में विभिन्न प्रकार के वाहनों की उपलब्धता की स्थिति

	हल्के वाहन	मध्यम प्रकार के वाहन	भारी वाहन	मोटर साईकिल	कुल
कुल आवश्यकता	178	91	24	306	599
उपलब्ध	101	37	13	106	257
कमी	77	54	11	200	342
प्रतिशत कमी	43	59	46	65	57

स्रोत: पुलिस अधीक्षक, पलामू

जिले मे वाहनों की कमी 57 *प्रतिशत* थी

इस प्रकार देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2012 को सभी प्रकार के वाहनों में 57 *प्रतिशत* की कमी थी। यह भी देखा गया कि 76 विशेष वाहनों[38] की आवश्यकता के विरूद्ध सिर्फ 15 वाहन ही उपलब्ध थे। इस प्रकार विशेष वाहन की श्रेणी में आवश्यकता के अनुरूप 80 प्रतिशत की कमी थी।

3.1.20.4 अस्त्र-शस्त्र

पुराने एवं प्रचलन से बाहर हथियारों को चरणबद्ध रूप से बदला नहीं गया

राज्य में सबसे पुराना नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण पलामू जिले को पुलिस आधुनिकीकरण के तहत एक मुख्य घटक के तौर पर पर्याप्त हथियार चाहिए था। पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण) झारखण्ड ने बताया (मई 2007) की पुराने एवं प्रचलन से बाहर हो चुके हथियार यथा .303 एवं एसएलआर राईफल को नए शस्त्रों जैसे एके-47 एवं इंसास राईफल से चरणबद्ध रूप से निस्तारण का निर्णय लिया गया था।

[38] रोगी वाहन, मध्यम बारूदी सुरंग निरोधक वाहन, बुलेटप्रुफ वाहन।

प्रति पुलिसकर्मी के हिसाब से हथियारों का पैमाना एक-एक आधुनिक या मुख्य मारक हथियार[39] निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जुलाई 2012) कि 489 (7.52 एमएम एसएलआर) एवम् 453 (.303 रायफल) 31 मार्च 2012 तक जिला पुलिस के पास पड़े हुए थे। यह भी देखा गया कि 157 एसएलआर (489 के विरूद्ध) एवं 346 .303 रायफल (453 के विरूद्ध) जिला शस्त्रागार में अक्रिय पड़े हुए थे। जिला में मार्च 2012 को 2,070 स्वीकृत पुलिस बल के विरूद्ध कुल 2,194 हथियार[40] उपलब्ध थे। इसके अलावे 163 हथियार मार्च 2012 तक खराब पड़े थे। यही स्थिति दिसम्बर 2012 तक बनी हूई थी। छः वर्ष पूर्व लिए गए निर्णय (मई 2007) के बावजूद पुराने हथियारों के नहीं बदले जाने से पुलिस बल की तैयारी में विपरीत असर पड़ सकता था।

3.1.20.5 सुरक्षा उपकरण

उग्रवादी विरोधी अभियान में पुलिस बल की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपकरण यथा बुलेटप्रुफ (बीपी) जैकेट एवम् बीपी हेलमेट आवश्यक हैं। प्रत्येक मारक बल के लिए ऊपर वर्णित एक जोड़ी सुरक्षा उपकरण होना था। यह पाया गया कि 2,070 स्वीकृत मारक बल के विरूद्ध में केवल 482 बीपी जैकेट एवम् हेलमेट (23 *प्रतिशत*) उपलब्ध थे जिसमें से 19 बीपी जैकेट और छः बीपी हेलमेट, बारूदी सुरंग विस्फोट में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। सुरक्षा उपकरणों की कमी से मारक बल के जीवन को या गंभीर रूप से घायल होने का खतरा उत्पन्न हो गया था।

बुलेटप्रुफ जैकेट एवं बुलेटप्रुफ हेलमेट में भारी कमी थी

3.1.20.6 चलंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाहन

पुलिस शोध एवं विकास व्यूरो ने प्रत्येक जिले को एक चलंत विधि-विज्ञान प्रयोगशाला वहन देने का सुझाव दिया था। पुलिस मुख्यालय ने मार्च 2004 में पलामू जिला पुलिस को अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक चलंत विधि-विज्ञान प्रयोगशाला वाहन दिया था। इस वाहन से संबंधित लोग बुक जनवरी 2012 के बाद की अवधि का उपलब्ध कराया गया जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सिर्फ जनवरी 2012 में दो अज्ञात उद्देश्य के दौरे विश्रामपुर के लिए किए गए थे। इसके बाद वाहन निष्क्रिय पड़ा हुआ पाया गया। लेखापरीक्षा के द्वारा पूछे जाने पर परिचारी प्रवर, पलामू ने कहा

---

[39] मुख्य मारक हथियार: 5.56 एमएम इंसास राईफल, एके-47, 9-एमएम स्टेनगन, 9-एमएम पिस्टल, .38 रिवाल्वर और भीएल पिस्टल।

[40] 5.56 एमएम इंसास रायफल, 7.62 एमएमएसएलआर, एके-47, 9 एमएम स्टेनगन, 9-एमएम कार्बाइन, 9- एमएम पिस्टल, .38 रिवाल्वर और.303 रायफल।

(जुलाई 2012) कि दो प्रशिक्षित पुलिसकर्मी जो इस वाहन में पदस्थापित थे उनका तबादला मई 2012 में राँची और देवघर कर दिया गया था और उनके स्थान पर कोई भी प्रशिक्षित पुलिसकर्मी की प्रतिस्थापना नहीं हुई थी। इस तरह प्रशिक्षितकर्मी के अभाव में वाहन निष्क्रिय पड़ा हुआ था। इस तरह से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी के अभाव में अनुसंधानकर्त्ता पदाधिकारी[41] द्वारा प्रदर्शो का सुरक्षित संग्रहण किया जा रहा था।

3.1.20.7 मानव बल प्रबंधन

अधिकारी संवर्ग में 10 से 100 *प्रतिशत्* और कांस्टेबल संवर्ग में 10 से 43 *प्रतिशत्* की कमी देखी गई

पुलिस सेवा की दक्षता एवं गुणवत्ता पर्याप्त संख्या प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह पाया गया कि मार्च 2012 को आरक्षी उपाधीक्षक श्रेणी में 50 *प्रतिशत्,* अवर निरीक्षक में 44 *प्रतिशत्,* सहायक अवर निरीक्षक में 10 *प्रतिशत्* एवं पुलिसबल में 10 से 43 *प्रतिशत्* की कमी थी ***(परिशिष्ट-3.10)***। परिचारी के दो स्वीकृत पद भी खाली थे। पलामू जिला जो कि घनघोर रूप से नक्सल प्रभावित है बड़ी मात्रा में रिक्ति पुलिस बल की तैयारी में विपरीत प्रभाव डाल सकता है।

3.1.21 अनुश्रवण

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, जिला योजना समिति (डीपीसी) को अपनी बैठक के दौरान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करनी थी। डीपीसी ने दिसम्बर 2011 में सिर्फ एक बैठक की थी। डीपीसी के इस एकल बैठक में योजनाओं की समीक्षा नहीं की गयी।

जिला योजना समिति चालू योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी नहीं किया

इसके अलावा अधिनियम के धारा 71 एवं 72 के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए सात एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद के लिए आठ-आठ स्थायी समितियों का गठन उनके क्षेत्राधीन कार्यो के देखरेख के लिए किया जाना था। उपरोक्त समितियों का गठन दिसम्बर 2012 तक कार्यों का हस्तांतरण पंचायतीराज संस्थाओं को न होने के कारण नहीं हो सका जबकी पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन दिसम्बर 2010 में ही हो चुका था जैसा कि कंडिका 3.1.6.2 में वर्णित है। इस तरह जैसा कि झारखण्ड पंचायतीराज अधिनियम में प्रावधानित है, स्थायी समितियों के गठन नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर से विकास कार्यों का अनुश्रवण नहीं हो सका।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के पूर्व योजनाओं का अनुश्रवण उपायुक्त द्वारा मासिक बैठक के द्वारा किया जाता था।

---

[41] सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक, आरक्षी निरीक्षक और आरक्षी उपाधीक्षक।

समापन बैठक के दौरान जिला योजना पदाधिकारी ने कहा (दिसम्बर 2012) कि स्थायी समितियों के गठन की प्रक्रिया जारी थीं।

इस तरह सुदढ़ अनुश्रवण तंत्र का अभाव योजनाओं के क्रियान्वयन में पायी गयी त्रुटियों का भी एक कारण था।

3.1.22 निष्कर्ष

पलामू का जिला केंद्रित लेखा परीक्षा जिला में वित्तीय मामलों में एवं महत्वपूर्ण समाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति को मुख्य रूप से उजागर करती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा बिन्दु नीचे विमर्शित है:

- किसी खास समय में सम्पूर्ण प्रक्षेत्रवार जिला में निधि का प्रवाह को दर्शाने की कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। पलामू में जिला योजना समिति का गठन संविधान के 74$^{वें}$ संशोधन के 18 वर्ष बाद (दिसम्बर 2011) में किया गया। जिला योजना समिति की बैठक सिर्फ एक ही बार हुई और इसकी कार्यप्रणाली दिखावटी एवं अपूर्ण रही। जिले का पंचवर्षीय विस्तृत योजना एवं वार्षिक कार्य योजना भी नहीं तैयार किया गया। अधिनियम के अंतर्गत निधि, कार्य एवं कार्यन्वयन का हस्तांतरण पंचायती राज ईकाई (पी.आर.आई.) को भी नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)

- एस.एस.ए. के अस्तित्व के बावजूद काफी संख्या में बच्चे स्कूल में नामांकित नहीं थे, निर्धारित मापदण्ड के विरूद्ध छात्र-शिक्षक का अनुपात (पी.टी.आर.) नीचे था और पी.टी.आर. जिला मुख्यालय से दूर प्रखण्डों में काफी खराब था। काफी संख्या में भवनों एवं कक्षा का निमार्ण या तो अपूर्ण था या बीच में ही जमीन के अभाव में रोक दिया गया था। बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति भी कम थी। विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था।

- एमडीएम योजना के क्रियान्वयन के क्रम में 1,974.79 एम.टी. चावल जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़ था विद्यालयों के भंड़ार पंजी में नहीं लिया गया जब की उसे एस.एफ.सी. गोदामों से निर्गत दिखाया गया था। एमडीएम के अंतर्गत चावल की दूसरी योजनाओं में विचलन एवं कुकिंग फंड का दुरूपयोग भी पाया गया। कुछ विद्यालयों में एमडीएम कुछ दिनों के लिए अनाज आपूर्ति कम होने के कारण अवरूद्ध पाया गया।

- एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन के क्रम में जिला, प्रखण्ड एवं गाँव स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या मानक की तुलना में कम पाया गया। मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं यथा रक्त भण्डारण, शिशु सेवा, अल्ट्रासाउण्ड,

ई.सी.जी. सेवाएं, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं इत्यादि भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थीं। सदर अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन, धुलाई मशीन एवं इन्सीनेरेटर अक्रियाशील थे। जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के बावजूद सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान जरूरी तीन जाँच नहीं किया गया एवं 2009-12 के दौरान संस्थागत प्रसव सिर्फ 40 *प्रतिशत्* पंजीकृत महिलाओं का ही हो पाया।

- वर्ष 2009-12 के दौरान आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) में पाया गया की 2,583 आंगनबाड़ी केंद्रों के विरूद्ध 2,484 केंद्रों में शौचालय एवं 2,026 केंद्रों में चापाकल नहीं थे। एस.एन.पी. में 36 से 38 *प्रतिशत्* की कमी पाई गई।
- ₹ 44.96 करोड़ मूल्य का बी.पी.एल., अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं अतिरिक्त बी.पी.एल. योजना का अनाज सरकारी राशन दुकानो में प्राप्ति नहीं दर्शाया गया जब की एस.एफ.सी. द्वारा इसे निर्गत दिखया गया था। इस अंतर का मिलान नहीं किया गया।
- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल में 75 हजार आबादी के लिए दो पाईप जलापूर्ति योजना बीच में ही रोक दी गई जिसके फलस्वरूप पाईप के खरीद में खर्च किये गए ₹ 19.17 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। अक्रियाशील फ्लोराइड निस्तरण यंत्र के खर्च पर ₹ 7.01 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2007-12 के बीच ₹ 27.86 करोड़ के लागत से पूर्ण किये गए 31 सड़को का रखरखाव नहीं किया गया एवं 181 ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने वाले 86 सड़कों पर ₹ 42.60 करोड़ के खर्च के बावजूद भी अपूर्ण रहे।
- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत 1,457 लक्षित गाँवों के विरूद्ध सिर्फ 668 गाँवों का विद्युतिकरण किया गया। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निश्चित दर से बिलींग करने के फलस्वरूप मीटर लगाने में ₹ 3.86 करोड़ का खर्च निष्फल हुआ।
- एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 861 स्वरोजगारियों को भवन के अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका जिसके फलस्वरूप वे बैंक वित्तीय पोषण से वंचित रहे।

- पलामू में पुलिस बल के लिए आधारभूत सुविधाएं यथा थाना तथा आउटपोस्ट भवन, पुलिसकर्मी के लिए आवास, बैरक एवं वाहन की कमी थी। पुराने हथियारों का चरणबद्ध रूप से जिला में निस्तारण नहीं किया गया।
- जिला योजना समिति को योजनाओं की समीक्षा अपनी बैठक में करनी थी। समिति ने अपने एकमात्र बैठक में कोई समीक्षा नहीं की। इसके अलावे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अन्तर्गत समितियों का संगठन उनके अंतर्गत आने वाले कार्यों के देखरेख के लिए करना था परंतु इन समितियों के गठन न होने के कारण विकास योजनाओं का अनुश्रवण नहीं हो सका।

3.1.23 अनुशंसाएं

सरकार को योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पी.आर.आई. की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए।

सरकार को विद्यालयों में पर्याप्त आधारभूत संरचनाएं एवं मूलभुत सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

सरकार को मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर/स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य क्रेंदों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सरकार को सभी मौसम के लायक सड़कों द्वारा सभी ग्रामीण बस्तियों को जोड़ना सुनिश्चित करना चाहिए।

सरकार को अनुश्रवण प्रणाली को सुद्धढ़ करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्य की पूर्ति हो सके

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया है(फरवरी 2013)। उत्तर अप्राप्त है (मार्च 2013)।

अध्याय -4

मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

अध्याय-4

सरकारी विभाग का मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

4.1 पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग की कार्यप्रणाली

कार्यकारी सारांश

पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग, झारखण्ड सरकार पशुओं के उपचार, टीकाकरण, बन्ध्याकरण कृत्रिम गर्भाधान के साथ-साथ राज्य में दूध, मांस, अण्डा आदि के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग विभिन्न योजनाओं यथा बकरा विकास योजनायें, कुक्कुट विकास योजनायें, सूकर विकास योजनायें, दुधारू पशु वितरण योजनायें इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा में विभाग के दो निदेशालयों (पशुपालन एवं गव्य विकास) के 2007-12 के दौरान किये गये कार्यों की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष नीचे उल्लेखित हैं:

- नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर (1976) के प्रावधान के तहत् राज्य में आवश्यक 1,756 पशु अस्पतालों के विरूद्ध केवल 451 अस्पताल थे। पशु अस्पतालों/चिकित्सालयों में पर्याप्त आधारभूत सरंचनायें नहीं थे। राज्य में विभाग के अन्तर्गत केवल आठ दुग्ध शीतक केन्द्र चालू अवस्था में थे जिससे दुग्ध उत्पादकों के लिए उत्पादित दुग्ध के फायदेमन्द निष्पादन हेतु सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि जगह के अभाव में दुग्ध केन्द्रों की स्थापना भी नहीं हो सकी। इसके अलावे पशु चिकित्सकों की कमी (32 *प्रतिशत*) थी।

  सरकार को पर्याप्त संख्या में पशु अस्पतालों, दुग्ध शीतक केन्द्रों, दुग्ध केन्द्रों और पशु चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।

- राशि के आवंटन में विलंब के कारण योजना मद में राशि की भारी बचत हुई और मार्च के महीने में व्यय का वेग हुआ। जिला पशुपालन पदाधिकारियों (जि.प.पदा.)/बैंकों के पास अनुदान की बड़ी राशि पड़ी रहीं और जि.प.पदा. द्वारा लाभुकों के बैंक खाते में अनुदान की राशि के जमा किए जाने का अनुश्रवण नहीं किया गया।

  सरकार को मार्च महीने में खर्च के वेग के परिहार्य हेतु योजना मद की राशि का अधिकतम उपयोग एवं समायानुसार राशि का आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए ।

सरकार को इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बैंकों के पास अनुदान की राशि का अनुश्रवण किया जाना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

- बकरा विकास योजना के तहत सरकार ने बकरा शेड के निर्माण एवं बकरा खरीद को समक्रमित नहीं किया। बकरा खरीद हेतु निधि को पुनर्विनियोजित कर अन्य कार्यों में लगाया गया। अनुश्रवण की कमी के कारण योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। लाभुकों से साक्षात्कार में पता चला कि बकरियाँ मर गई थीं, जिसकी जानकारी जि.प.पदा. को नहीं थी।

  सरकार को बकरों की खरीद और योजनाओं के अनुश्रवण को सुनिश्चित करना चाहिए।

- कुक्कुट विकास योजनाओं में लाभुकों के चयन में विलंब के कारण लक्ष्य प्राप्ति में कमी रही। जि.प.पदा. मुर्गियों के मर जाने से वाकिफ नहीं थे।

  विभाग को मुर्गियों के स्वास्थ की समुचित देखभाल एवं नियमित अनुकरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि योजना का इच्छित लाभ प्राप्त किया जा सके।

- पाँच नमूना-जाँचित जिलों के 38 लाभुकों के संयुक्त साक्षात्कार से पता चला कि 2009-12 के दौरान 17 लाभुकों के 223 सुकरों में से 46 सूकरों की मौत हो गई पर लाभुकों द्वारा बीमा का दावा पेश नहीं किया गया था क्योंकि सूकरों का बीमा नहीं था। ऐसा जि.प.पदा. द्वारा लाभुकों में जागरूकता उत्पन्न नहीं किये जाने के कारण हुआ जबकि इसके लिए निधि उपलब्ध थी।

  विभाग के लाभुकों में सूकरों के बीमा सम्बन्धी जागरूकता के उत्पन्न होने को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लाभुकों को हानि से बचाया जा सके।

- पशु रोगों की रोकथाम के लिए राज्यों को सहायता (एस्काड) के तहत 2007-12 के दौरान टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्तियों में खुरहा चपका (एफएमडी) रोग में 7 *प्रतिशत्*, बकरी प्लेग (पीपीआर) में 89 *प्रतिशत्*, लँगड़ा ज्वर (बीक्यू) एवं गलघोंटू (एच.एस.) में 40 *प्रतिशत्* एवं रानीखेत बीमारी में 88 *प्रतिशत्* की कमी टीकों के विलंब से/अल्प मात्रा में प्राप्ति के कारण हुई।

  विभाग को टीकाकरण द्वारा पशु रोगों के नियंत्रण हेतु ससमय एवं पर्याप्त टीके प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

- दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम के तहत 2007-11 के दौरान नमूना-जाँचित जिलों में गायों के आंशिक खरीद किये जाने के कारण 3,670 इकाईयों के विरूद्ध केवल 2,611 इकाईयाँ (71 *प्रतिशत*) ही स्थापित हुई।

  विभाग को कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गायों की खरीद सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इच्छित लाभ को प्राप्त किया जा सके।

- झारखण्ड डेयरी परियोजना (जे.डी.पी.) जो राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा संचालित (एम.ओ.यु.के तहत) है, 2008-12 के दौरान दुग्ध संग्रहण एवं उसके परिष्करण हेतु निर्धारित 12 जिलों के लक्ष्य के विरूद्ध ₹ 11.10 करोड़ खर्च कर केवल तीन जिलों को आच्छादित कर सका। विभाग ने एम.ओ.यु. की अवधि की समाप्ति के पश्चात ही जे.डी.पी. के प्रबंधन का भार उठाया (दिसम्बर 2012)।

4.1.1 भूमिका

पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग (ए.एच. और एफ.डी.) पशु सम्बन्धी बीमारियों के रोक थाम, दूध, अंडा, मांस इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि और दुधारू मवेशी वितरण, नस्ल सुधार, बछिया पालन, बकरा, कुक्कुट एवं सूकर विकास कार्यक्रमों के सघन कार्यान्वयन द्वारा पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। विभाग कृषि श्रमिकों और छोटे/सीमांत किसानों को रोजगारोन्मुख अवसर प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका भी निभाता है।

लेखापरीक्षा कार्य संरचना

4.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग (ए.एच. और एफ.डी.) के शीर्ष में सचिव/प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार हैं जिन्हें राज्य स्तर पर तीन निदेशकों (पशुपालन, गव्य विकास एवं मत्स्यपालन) सहायता प्रदान करते हैं। पशुपालन प्रक्षेत्र में जिला पशुपालन पदाधिकारी (डी.ए.एच.ओ.) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें पशु शल्य चिकित्सकों, (भी.एस.), भ्रमणशील पशु चिकित्सकों और प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। गव्य विकास प्रक्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी (डी.डी.डी.ओ.) उत्तरदायी हैं। इसके अलावे विभाग का अपना टीका उत्पादन संस्थान, मवेशी, सूकर एवं कुक्कुट फार्म एवं किसान प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो योजनाओं में सहयोग प्रदान कर उद्देश्यों की प्राप्ति कराते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट 4.1*** *एवं* ***4.2*** में दिया गया है।

4.1.3 विभाग के उद्देश्य

पशुपालन निदेशालय के उद्देश्य हैं:

- राज्य में पशु विकास हेतु वर्त्तमान आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का सशक्तिकरण एवं समेकित करना;
- पशु उत्पाद जैसे दूध, अंडा, मांस इत्यादि में वृद्धि करना; और
- संकर नस्ल, आहार, समुचित प्रबंधन एवं पशु स्वास्थ्य आच्छादन हेतु विकसित सुविधाओं द्वारा ग्रामीण जनता के अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में पशुपालन को बढ़ावा देना है।

गव्य विकास (डी.डी.) निदेशालय के उद्देश्य हैं:

- दूध एवं दूध उत्पादों का संग्रहण, परिवहन और बिक्री हेतु दक्ष विपणन प्रणाली विकसित करना;
- दूध उत्पादकों के नजदीक पशु आहार, चारा, मिनरल एवं अन्य पूरक आहार एवं पशुओं के नस्ल सुधार का प्रबंधन; एवं
- राज्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूध उत्पादन में वृद्धि एवं स्थिर रोजगार का सृजन करना।

4.1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि विभाग:

- के पास योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचनाएं, मानव शक्ति और बजटीय संसाधन उपलब्ध थे;
- द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ससमय एवं प्रभावपूर्ण तरीकों से किया गया;
- ने दूध, अंडा एवं मांस के उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति की;और
- में पर्याप्त अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र थे।

4.1.5 लेखापरीक्षा के मापदण्ड स्तरीकरण

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के मानक हेतु अपनाये गये मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- झारखण्ड वित्त नियमावली, बजट मैन्यूअल और झारखण्ड कोषागार संहिता;
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरे केन्द्रीय योजनाओं का मार्ग दर्शिका;

- विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी आदेशों एवं अनुदेशों; और
- राज्य सरकार एवं कार्यान्वयन ऐजेन्सी (एन.जी.ओ.) के बीच किये गये एम.ओ.यु.।

4.1.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में विभाग के 2007-12 के अवधि के क्रियाकलापों को आच्छादित किया गया और इसका क्षेत्र विभाग के पशुपालन एवं गव्य विकास निदेशालयों तक सीमित रहा। राज्य के 24 जिलों में सिम्पल रैन्डम सैम्पलिंग विदाउट रीपलेसमेन्ट तरीके से चुने गये आठ[1] जिलों के 16 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) के लेखा का लेखापरीक्षा (अप्रैल से जुलाई 2012) किया गया। सचिवालय, निदेशालयों एवं उनके जिला इकाईयों के अभिलेखों एवं संचिकाओं की जाँच की गई। प्रखण्ड सम्बन्धी सूचनायें जिला कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त की गई।

इसके अलावा प्रश्नावली निर्गत कर दूसरे सह कार्यालयों[2] से सूचनायें एकत्रित की गई। विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में 282 लाभुकों (6,278 में से) का साक्षात्कार लिया गया एवं प्रश्नावली के माध्यम से सूचनायें प्राप्त की गई।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं क्षेत्र संबंधी विचार-विमर्श विभाग के सचिव के साथ प्रवेश सभा (एन्ट्री कन्फ्रेंस) में 30 मार्च 2012 को की गई। कई अनुरोधों के बावजूद भी सचिव/प्रधान सचिव समय नहीं दे पाये फलस्वरूप निकास सभा (एक्जीट कन्फ्रेंस) नहीं किया जा सका। यद्यपि विभाग के उत्तर प्राप्त हुए (नवम्बर 2012 और जनवरी 2013) और इस प्रतिवेदन में समुचित जगहों पर शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.7 संस्थागत प्रबंधन

प्रत्येक संस्था को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं प्रबंधन हेतु सुदृढ़ योजना, पर्याप्त संरचना एवं मानव शक्ति एवं निधि की आवश्यकता होती है। ये सभी संस्थागत कार्यकलापों के मुख्य क्षेत्रों में आंतरिक प्रणाली एवं नियंत्रण की सुदृढ़ता एवं उपयुक्तता को सुनिश्चित करता है और संस्था को मितव्यय, दक्षतापूर्ण और प्रभावशाली तरीके से उद्देश्यों को प्राप्ति की ओर अग्रसर कराता है।

---

1 बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, लातेहार और राँची ।

2 विभाग के अन्तर्गत सूकर फार्म कांके, पॉलटरी फार्म, होटवार एवं बोकारो, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान (ए.एच.पी.आई), कांके, कृत्रिम गर्भाधान पदाधिकारी का कार्यालय, किसान प्रशिक्षण केन्द्र, कांके और पशु अस्पतालों।

हमने पाया कि विभाग ने 2007-12 अवधि में पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना तैयार किया। यद्यपि लक्षित लाभुकों के जरूरतों का पता नहीं किया गया क्योंकि अधीनस्थ कार्यालयों से कोई इनपुट नहीं लिया गया। कुछ क्षेत्रों में जहाँ कार्यकलापों का प्रबंधन कमजोर पाया गया आगे के कंडिकाओं में चर्चित है।

4.1.7.1 पशुपालन (ए.एच.) में आधारभूत संरचना की कमी

दक्ष टीकाकरण और पशुओं के चिकित्सा के लिए टीका उत्पादन संस्थान एवं उपयुक्त संख्या में तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना युक्त पशु चिकित्सालयों का होना आवश्यक है। हमने पाया कि टीका उत्पादन संस्थान एवं पशु अस्पतालों/पशु चिकित्सालयों में निम्नलिखित कमियाँ थीं:

- ***टीका उत्पादन हेतु आधारभूत संरचना***

सरकारी पशु अस्पतालों में आपूर्ति एवं उपयोग हेतु पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान (ए.एच.पी.आई.) काँके राँची 1986 से बैक्टेरीयल एवं भाईरल बीमारियों का टीका[3] बना रहा था। संस्थान ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) के तहत, आवश्यक उत्पादन लाइसेन्स के बिना जनवरी 2013 तक कार्यरत था क्योंकि लाइसेंस 31 दिसम्बर 2000 को ही कालातीत हो गया था। यह एक अपराध था जो उक्त अधिनियम की धारा 27(ए) के अन्तर्गत दण्ड के प्रावधान को आकर्षित करता है।

ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक नियमावली 1945 के शेड्युल एफ (1), भाग 1(ए) के अनुसार जिस प्रतिष्ठान में भाइरल/बैक्टेरीयल टीके बनाये जाते हैं वह एक ऐसे व्यक्ति के दिशा-निर्देश एवं नियंत्रण में रहेगा जो योग्य एवं बैक्टेरीओलोजी का विशेषज्ञ तथा भीरोलोजी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ हो, साथ ही टीकों के उत्पादन एवं उनके गुणवता का पर्याप्त अनुभव रखता हो।

ए.एच.पी.आई. राँची द्वारा 2007-12 के दौरान उत्पादित टीकों की लक्ष्य प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य का छः से 46 *प्रतिशत* के बीच रहा

ए.एच.पी.आई. द्वारा प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से उद्घटित हुआ कि संस्थान टीकों के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में पीछे रहा एवं 2007-12 के दौरान लक्ष्य प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य का छः *प्रतिशत्* एवं 46 *प्रतिशत्* के बीच रहा ***(परिशिष्ट-4.3)*** जिसके परिणामस्वरूप 2007-12 में पशुओं का कम टीकाकरण हुआ (जैसा ***कंडिका 4.1.9.4*** में चर्चित है) और पशु संक्रमक बीमारियों के लिए खुले रहे।

आगे, संस्थान 2007-12 के दौरान भाइरल टीका नहीं बना सका क्योंकि भाइरल टीके उत्पादन के विशेष साज-समान यथा लियोफलाइजर और एग इक्यूबेटर नहीं

[3] हेमरहैजिक सेप्टेसेमिया, ब्लैक क्वार्टर, रानीखेत और स्वाईन फीवर रोग।

खरीदे गये थे (अगस्त 2012) और प्रयोगशाला का गुड मैनुफैक्चरींग प्रैक्टिस[4] (जी.एम.पी.) मानक के अनुरूप आधुनिकीकरण किया जा रहा था।

हमने यह पाया कि जुलाई 2007 के बाद संस्थान के सर्वोच्च पद पर किसी भी माइक्रो बायोलोजिस्ट[5] की नियुक्ति नहीं हुई। अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति नहीं होना टीकों के कम उत्पादन का एक कारण रहा जैसा कि ए.एच.पी.आई. के निदेशक का कहना था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (नवम्बर 2012) और कहा कि ड्रग लाइसेन्स के पुनर्नवीकरण हेतु आवश्यक कागजातों के साथ फीस की राशि जमा की गई थी (मई 2008)। विभाग ने यह भी कहा कि संस्थान के निदेशक को निदेशित किया गया था कि वे टीकों के उत्पादन में कार्यरत लोगों के योग्यता के बारे में ध्यान दें। यद्यपि विभाग संस्थान के सर्वोच्च पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किये जाने के बारे में चुप रहा।

- ***पशु अस्पतालों (भी.एच.)/पशु चिकित्सालयों (भी.डी.) की प्रर्याप्तता***

विभाग के पास 451 भी.एच/ भी.डी. थे 5,000 पशुओं पर एक के मानक के विरूद्ध 19,470 पशुओं पर एक अस्पताल था

नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, 1976 (एन.सी.ए.) पर आधारित झारखण्ड सरकार के संकल्प के अनुसार पशु चिक्त्सिा सेवा प्रदान करने के लिए 5,000 पशुओं पर एक पशु अस्पताल की आवश्यकता थी। राज्य में 87.81 लाख पशु[6] थे और तदनुसार 1,756 पशु अस्पतालों की आवश्यकता थी। मार्च 2008 तक राज्य में केवल 451 अस्पताल[7] थे (अर्थात 19,470 गौ जाति पर एक) और मार्च 2012 तक अस्पतालों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकी थी। दो चरणों में विभाग ने राज्य योजना के तहत 2007-09 के दौरान (2007-08:115, 2008-09:185) 300[8] पशु अस्पतालों के भवन निर्माण की योजना बनायी। विभाग ने प्रथम चरण में 115 भी.एच. निर्माण हेतु पाँच क्षेत्रीय निदेशकों (आर.डी.) को कुल ₹ 6.99 करोड़[9] की मंजूरी एवं आवंटन (मार्च 2008) प्रदान किया। आगे, 2010-12 के दौरान विभाग ने ₹ 38.32[10] करोड़ 250 अस्पतालों (नव निर्माण

---

4 ड्रग्स और कॉस्मेटिक नियम 1945 में वर्णित शेडयूल 'एम' के अनुसार सभी उत्पादन इकाई/जाँच प्रयोगशालाओं में जी.एम.पी. मानक होना चाहिए। भारत सरकार ने इसे जुलाई 2005 से अनिवार्य कर दिया है।

5 माइक्रोंबायोलोजी जिसमें वीषाणुविज्ञान, माइकोलोजी, पारासीटोलोजी, बैकट्रीयोलोजी, आदि सम्मलित है।

6 18 वें पशु जनगणना 2007 के अनुसार।

7 भी.एच: 424, भी.डी: 23 एवं चलन्त अस्पाताल: 4।

8 153 भवनहीन, 61 अस्त-व्यस्त स्थिति में और 86 मरम्म्त योग्य।

9 प्रत्येक भी.एच. के लिए प्राक्कलित राशि `₹ 6.08 लाख थी।

10 प्राक्कलित राशि: भी एच. के नवनिर्माण हेतु ₹ 15 लाख और पुनर्स्थापन हेतु ₹ 10 लाख; और भी.डी. के नवनिर्माण हेतु ₹ 11.60 लाख और पुनर्स्थापन हेतु ₹ 6 लाख।

194 भी.एच. एवं 4 भी.डी. और पुनरूद्धार 46 भी.एच. एवं 6 भी.डी.) के लिए मंजूर किया।

2007-12 के दौरान स्वीकृत 365 के विरूध मात्र 130 भी.एच./भी.डी. का निर्माण पूरा किया गया

अभिलेखों एवं एकत्रित सूचनाओं की संवीक्षा से पता चला कि 2007-08 के दौरान शुरू किए गए 90 पशु अस्पतालों में से 84 अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा हुआ जबकि छः अस्पताल उनके निर्माण की धीमी प्रगति के कारण दिसम्बर 2012 तक अपूर्ण रहे। भूमि की अनुपलब्धता एवं दर अनुसूची में वृद्धि (मई 2008) के बावजूद लागत मूल्य के संशोधन न होने के कारण 25 अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। विभाग के दिशा निर्देश (दिसम्बर 2009) के अनुसार कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा ₹ 1.52 करोड़ (दिसम्बर 2009; ₹ 1.46 करोड़ एवं मई 2010; ₹ 0.06 करोड़) संबंधित आर.डी. को लौटा दिया गया। आगे 2010-11 में मंजूर किये गये आठ पशु अस्पतालों में केवल एक[11] एवं 2011-12 में मंजूर किये गये 242 में से 45 भी.एच./भी.डी. जनवरी 2013 तक पूरे किये जा सके।

इस प्रकार 2007-12 के दौरान मंजूर किये गए 365 भी.एच./भी.डी. में से केवल 130 भी.एच./भी.डी. ही जनवरी 2013 तक पूर्ण किये जा सके।

विभाग ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

- ***अस्पतालों/चिकित्सालयों में आधारभूत संरचना सुविधा***

कई भी.एच./भी.डी. के पास जल, विधुत आपूर्ति, रेफ्रिजेरेटर, भण्डारण आदि सुविधा नहीं थे

पशुओं के सेवा प्रतिपादन में भी एच.[12]/भी.डी.[13] की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। भारत सरकार के मार्ग-दर्शिका के अनुसार भी.एच/भी.डी. के लिए अच्छी हालत में एक अस्पताल भवन का होना स्वच्छ जल की उपलब्धता, सामान रखने की सुविधा, रेफ्रिजेरेटर और आधुनिक मशीन/औजार होना चाहिए।

आठ नमूना-जाँचित जिलों के 173 टी.भी.एस./10 भी.एस. में से 128 अस्पतालों/चिकित्सालयों के भ्रमणशील चिकित्सकों और 9 पशु शल्य चिकित्सकों से प्राप्त सूचनाओं की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 137 भी.एच./भी.डी. में से 39 के पास अपना भवन नहीं था। 47 भी.एच./भी.डी.में स्वच्छ जल की और 31 भी.एच./भी.डी. में सामान रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 60 भी.एच./भी;डी. के पास रेफ्रिजेरेटर नहीं थे। बिजली की आपूर्ति नहीं रहने के कारण 73 भी.एच./भी.डी. में रेफ्रिजेरेटर का चलना संदेहात्मक था। आभारभूत सुविधाओं की कमी ने पशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रतिपादन को बुरी तरह प्रभावित किया।

---

[11] कोलेबीरा (सिमडेगा)।

[12] प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर टी.भी.ओ. के अधीन।

[13] जिला स्तर पर भी.एस. के अधीन।

विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि भी.एच./भी.डी. में मूलभत संरचनाओं हेतु निधि चालू वित्तीय वर्ष में मुहैया कराये जा रहे थे।

गव्य विकास

- ***दुग्ध शीतलता हेतु संरचना***

ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों द्वारा उत्पादित दूध के लाभदायक बिक्री हेतु दुग्ध शीतक केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/पुनरूद्धार एवं नये दुग्ध शीतक केन्द्रों की स्थापना किया जाना 2007-08 के वार्षिक योजना में समाहित किये गए। फरवरी 2013 तक राज्य में स्थित दुग्ध शीतक केन्द्रों की वस्तुस्थिति **तालिका -1** में दिए गये हैं।

तालिका-1: राज्य में दुग्ध शीतक केन्द्रों की वस्तुस्थिति

कुल जिले	राज्य में दुग्ध शीतक केन्द्रों की संख्या			नमूना-जाँचित जिले	
	कार्यशील	अकार्यशील	स्वीकृत एवं निर्माणाधीन	कार्यशील	अकार्यशील
24	8[14]	6[15]	6[16]	4[17]	3

(स्रोत: गव्य विकास निदेशालय)

नमूना-जाँचित जिलों में अवस्थित दुग्ध शीतक केन्द्रों के दुग्ध बिक्री पंजी एवं अन्य सम्बधित अभिलेखों से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ।

24 जिलों में केवल आठ दुग्ध शीतक केन्द्र कार्यशील थे। छः शीतक केन्द्र अकार्यशील पड़े रहे

- डी.डी.डी.ओ. के कथनानुसार दो दुग्ध शीतक केन्द्र दुमका एवं गुमला जिलों प्रत्येक में एक-एक क्रमश: 2006 एवं मार्च 2012 से खराब साधनों के कारण बन्द थे। उपकरणों के पुनरूद्धार करने की जरूरत थी। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में दुग्ध शीतक केन्द्र के निर्माण हेतु विभाग ने ₹ 2.25 करोड़ (मार्च 2010 ₹ 0.25 करोड़ और मार्च 2011 ₹ 2 करोड़) की राशि डी.डी.डी.ओ. को निर्गत किया। डी.डी.डी.ओ. पूर्वी सिंहभूम ने ₹ 0.25 करोड़ की राशि चहारदीवारी, समतलीकरण एवं डीप टयूब वेल के अधिष्ठापन पर खर्च किया। उसने ₹ 0.75 करोड़ की राशि दुग्ध शीतक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता (ई.ई.) भवन निर्माण विभाग जमशेदपुर (कार्यकारी एजेंसी) को हस्तांतरित किया (मार्च 2011) और ₹ 1.25 करोड़ की राशि अपने बैंक बचत खाते में रखा (अप्रैल 2011)। जूलाई 2012 तक ई.ई. निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सका क्योंकि उसे उक्त शीतक केन्द्र में विद्युत खपत के अनुमानित आवश्यकता को नहीं बताया गया जो भवन में विधुत साज-सज्जा की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक था।

शीतक केन्द्र के लिए आवंटित ₹ 1.25 करोड़ बचत खाता में रखा गया

[14] देवघर, धनबाद, हजारीबाग, गिरीड़ीह, कोडरमा, लातेहार, लोहरदागा एवं राँची।.

[15] दुमका, गुमला, खूँटी, राँची, सराईकेला एवं साहेबगंज ।

[16] गोड्डा, जामताड़ा, जमशेदपुर, सिमडेगा एवं रॉची (2)।

[17] देवघर, धनबाद, लातेहार एवं राँची ।.

इस प्रकार निधि की उपलब्धता के बावजूद शीतक केन्द्र का निर्माण शुरू नहीं हो सका।

- देवघर एवं लातेहार जिलों में अवस्थित शीतक केन्द्रों में दूध की आपूर्ति में कमी के कारण सितम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के बीच ₹ 18.51 लाख[18] की लागत से अधिष्ठापित दही, घी, पनीर और खोवा बनाने के मशीने का उपयोग नहीं हो सका। इस प्रकार ₹ 18.51 लाख का खर्च निष्फल रहा।

इस प्रकार दूध उत्पादकों द्वारा उत्पादित दूध के लाभदायक बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य की पूर्ति पूरी तरह नहीं हो पाई।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि बंद पड़े शीतक केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एवं सभी जिलों में चरणबद्ध तरीकों से कुछ दुग्ध शीतक केन्द्रों के निर्माण हेतु योग्य निजी सहभागी का चयन की प्रक्रिया जारी थी। जवाब मानने योग्य नहीं था क्योंकि दुमका में बंद पड़े शीतक केन्द्र को चालू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, वस्तुत: गुमला अवस्थित शीतक केन्द्र मार्च 2012 से कार्य करना बंद कर दिया और जमशेदपुर के शीतक केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

- ***मिल्क बूथ पर अकार्यशील विनियोग***

शहरी उपभोक्ताओं के बीच दुग्ध एवं दुग्ध जनित पदार्थों की समुचित एवं अचल बिक्री सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने नौ जिलों (आठ नमूना-जाँचित जिलों में से चार[19] जिले शामिल) में 108 पोर्टेबल मिल्क बूथ (मिल्क पारलर) (2010-11: 28 और 2011-12:80) के अधिष्ठापन के लिए ₹ 2.63 करोड़[20] (अगस्त 2010 और जुलाई 2011) की मंजूरी दी। डी.डी.डी.ओ. को मिल्क बूथों के लिए जगह का चुनाव कर विभाग को निधि उपलब्ध कराने हेतु सूचित करना था।

जगह के अभाव में 18 मिल्क बूथ का अधिष्ठापन नहीं हुआ

अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि 2010-12 में मंजूर किये गये 18 मिल्क बूथों (देवघर, 13 एवं गुमला, 5) जगह की अनुलब्धता के कारण अधिष्ठापित नहीं किये गये। यद्यपि, आवंटित ₹ 44.25 लाख की राशि में से ₹ 42.33 लाख की राशि 18 मिल्क बूथों के सामग्री[21] की खरीद पर खर्च कर दिये गए जो जुलाई 2012 तक अकार्यशील रहे। आगे, गुमला का दुग्ध शीतक केन्द्र मार्च 2012 से बन्द हो गया। परिणामस्वरूप अधिष्ठापन होने के बावजूद

---

18 देवघर: रू 16.33 लाख और लातेहार: रू 2.18 लाख।

19 धनबाद:14, देवघर:13, गुमला:5, और रॉची: 44।

20 2010-11: मिल्क बूथ की सामग्री- ₹ 1.85 लाख और फर्निचर- ₹ 0.40 लाख और 2011-12:मिल्क बूथ की सामग्री- ₹ 2 लाख और फर्निचर- ₹ 0.50 लाख।

21 मूल्य ₹ 42.33 लाख (देवघर:₹ 30.47 लाख और गुमला ₹ 11.86 लाख) ।

देवघर एवं गुमला के मिल्क बुथों के अधिष्ठापन नहीं होने के कारण ₹ 42.33 लाख की सामग्री अकार्यशील रहे

मिल्क बूथ का उपयोग नहीं हो सकता है। राँची और धनबाद में मिल्क बूथों का अधिष्ठापन प्रगति पर था।

इस प्रकार ₹ 42.33 लाख के खर्च के बावजूद योजना के उद्देश्यों की लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि बाकी बचे मिल्क बूथों के अधिष्ठापन के लिए योग्य भूमि को चिन्हित किया जा रहा था। उत्तर ठीक नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा योग्य भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना निधि निर्गत किया गया था।

4.1.7.2 मानव बल की पर्याप्तता

पशुपालन प्रक्षेत्र में बी.ए.एच.ओ., टी.भी.ओ. और एल.ए. एवं गव्य विकास प्रक्षेत्र में डी.डी.डी.ओ., सहायक डेयरी एक्सटेंशन आफिसर और इनपुट सुपरवाइजर विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लिए मुख्य कार्यपालक थे।

पशुचिकित्सकों की 32 *प्रतिशत* कमी थी

हमने पाया कि राज्य में स्वीकृत बलों की तुलना में 249 पशु चिकित्सकों की कमी (32 *प्रतिशत*) एवं नमूना-जाँचित जिलों में 78 चिकित्सकों की कमी (26 *प्रतिशत*) थी। अराजपत्रित कर्मचारियों की राज्य एवं नमूना-जाँचित जिलों में कमी क्रमश: 37 एवं 38 *प्रतिशत* थी। आगे गव्य विकास प्रक्षेत्र में राज्य स्तर पर तकनीकी पदाधिकारी/स्टाफ और गैर-तकनीकी पदाधिकारी/स्टाफ की कमी क्रमश: 48 एवं 27 *प्रतिशत* थी। नमूना-जाँचित जिलों में स्वीकृत बलों की तुलना में यह कमी 53 और 45 *प्रतिशत* थी। मार्च 2012 तक दोनों निदेशालयों में मानव बल की कमी का विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिए गए हैं।

मानव बल की कमी से सेवा प्रतिपादन प्रभावित हुआ जो ***कंडिका 4.1.9*** में चर्चित है। हमने यह भी अवलोकन किया कि पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत बी.ए.एच.ओ. विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, परीक्षा एवं चुनाव आदि कार्यों में लगे रहे जिससे उनके द्वारा किए जाने वाले योजनाओं का अनुश्रवण/सहायता बाधित हुआ। डी.ए.एच.ओ. एवं डी.डी.डी.ओ. ने इस तथ्य को स्वीकार किया।

4.1.8 वित्तीय नियम, आदेश इत्यादि का अनुपालन

दृढ़ वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि व्यय वित्तीय नियमों, विधानों और योग्य प्राधिकारों द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किए जाते हों। नियम एवं विधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के उदाहरण नीचे विमर्शित हैं:

4.1.8.1 वित्तीय नियंत्रण, बजट आवंटन एवं व्यय

योजना मद के निधि का भारी बचत हुआ

विभाग का वित्त पोषण प्रधानतया राज्य बजट के द्वारा मुख्य शीर्ष 2403-पशुपालन ओर 2404-गव्य विकास के अन्तर्गत किया गया था। इसके अलावा, केन्द्र संपोषित योजनाओं हेतु निधि भी राज्य बजट के द्वारा राज्यांश और केन्द्रांश के हद तक दिया गया था। 2007-12 के दौरान पूरे बजट आवंटन एवं किए गए व्यय को **तालिका-2** में दर्शाया गया है।

तालिका-2: बजटीय प्रावधान एवं व्यय

पशुपालन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना			गैर- योजना		
	प्रावधान	व्यय	बचत	प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	32.14	23.20	8.94 (28)	44.60	41.81	3.16 (7)
2008-09	32.89	26.89	6.01 (18)	56.46	53.02	3.43(6)
2009-10	26.05	21.89	4.16 (16)	77.02	61.69	15.33(20)
2010-11	42.45	26.97	15.48 (36)	67.67	63.43	4.24(6)
2011-12	59.21	37.60	21.61 (36)	75.42	71.86	3.56(5)
कुल	**192.74**	**136.55**	**56.20 (29)**	**321.17**	**291.81**	**29.72 (9)**

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग। कोष्ठक में अंक उपबंध का प्रतिशत बतलाता है।

गव्य विकास

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना			गैर-योजना		
	प्रावधान	व्यय	बचत	आबंटन	व्यय	बचत
2007-08	39.65	34.53	5.12 (13)	3.93	3.67	0.26 (7)
2008-09	46.00	44.15	1.85 (4)	4.69	4.48	0.21 (4)
2009-10	47.10	46.09	1.01 (2)	5.87	5.59	0.28 (5)
2010-11	55.00	46.74	8.26 (15)	6.05	5.83	0.22 (4)
2011-12	66.00	53.64	12.36 (19)	6.84	6.54	0.30 (4)
कुल	**253.75**	**225.15**	**28.60 (11)**	**27.38**	**26.11**	**1.27 (5)**

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग। कोष्ठक में अंक उपबंध का प्रतिशत बतलाता है।

2007-12 के दौरान पशुपालन (ए.एच.) निदेशालय का योजना व्यय उपबंध की निधि का 64 और 84 *प्रतिशत्* के बीच था जबकि गव्य विकास निदेशालय में यह 81 एवं 98 *प्रतिशत्* के बीच रहा।

पशुपालन के अन्तर्गत निधियों का प्रावधान पशुओं की संख्या में वृद्धि के साथ समक्रमित नहीं था

पशुपालन के अन्तर्गत निधि का उपबंध पशुओं की वास्तविक संख्या[22] के साथ नहीं बढ़ाया गया। यद्यपि 2008-09 में 2007-08 की तुलना में पशुधन की संख्या 1.02 *प्रतिशत्* बढ़ी पर 2009-10 में पशुपालन के उपबंध एवं व्यय पिछले वर्ष से ₹ 6.84 करोड़ (20.80 *प्रतिशत्*) एवं ₹ 5.00 करोड़ (18.60 *प्रतिशत्*) क्रमश: कम हुआ।

[22] 2007-08:159.37 लाख; 2008-09:161.01 लाख 2009.10:161.76 लाख; 2010-11:152.52 लाख और 2011-12:166.05 लाख।

अत: कम उपबंध के कारण पशुओं के स्वास्थ्य एवं पशुधन उत्पाद पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

वित्त विभाग के 17 अप्रैल 1998 के कार्यकारी स्थायी अनुदेश के अनुसार कोषागार से अग्रिम की निकासी जे.टी.सी. के नियम 300 के तहत ही किया जा सकता है। संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि सरकार ने 2011-12 के बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ₹ 1.10 करोड़ की राशि राँची में 11 पशु अस्पतालों के निर्माण हेतु आवंटित (मार्च 2012) किया। कोषागार पदाधिकारी डोरंडा राँची ने यद्यपि अग्रिम की निकासी स्थायी कार्यकारी अनुदेश (अप्रैल 1998) का उलंघन करार देते हुए निकासी पर आपत्ति जताया था। अत: निधि की निकासी नहीं हो पायी और फलस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ की राशि व्ययगत हो गई।

4.1.8.2 मार्च महीने में व्यय का वेग

झारखण्ड बजट मन्युअल के नियम 113 के अनुसार व्यय का वेग खास कर वित्तिय वर्ष के अंतिम महीने में होना वित्तिय नियम का उल्लंघन है, जिसे परिहार्य किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान पशुपालन में मार्च महीने में योजना व्यय कुल व्यय का 55 और 66 *प्रतिशत* के बीच एवं गव्य विकास में 56 और 85 *प्रतिशत* के बीच रहा। इसी तरह की बात[23] नमूना-जाँचित जिलों में भी देखा गया। मार्च महीने में व्यय का वेग का होना विभाग द्वारा व्यय का अपर्याप्त अनुश्रवण के खतरे से भरा था।

2007-12 के दौरान लिए गये तीन विभिन्न योजनाओं के 10 मामलों[24] में सभी डी.ए.एच.ओ. को राज्यादेश के निर्गत होने की तारीख से 53 से 180 दिनों के विलंब से आवंटन पत्र जारी किए गए।

मार्च में व्यय के वेग को परिहार्य किया जा सकता था अगर विभाग राज्यादेश निर्गत होने के तुरंत बाद निधि का आवंटन करता। यह मुख्य नियंत्री पदाधिकारी के कमजोर वित्तीय प्रबंधन को भी इंगित किया।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि यह लाभुकों के चुनाव में विलंब के फलस्वरूप हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आवंटन पत्र राज्यादेश के निर्गत होने के तुरंत बाद निर्गत नहीं किया गया।

---

[23] पशुपालन: 44 से 78 *प्रतिशत*; गव्य विकास: 43 से 86 *प्रतिशत*।

[24] बकरा विकास: 2007-08; 154 दिनों का प्रत्येक तीन आवंटन आदेशो में, 2009-10; 103 दिन एवं 158 दिन 2010-11; 164 दिन और 2011-12; 53 दिन, 80 दिन और 180 दिन, सूकर विकास: 2009-10; 103 दिन एवं अस्पताल एवं औषधालय भवन का निर्माण 2011-12; 170 दिन।

4.1.8.3 अनुदान प्रबंध

पशुपालन

स्वीकृति आदेशों के अनुसार जि.प.पदा. द्वारा अनुदान राशि लाभुकों के बैंक खातों में विमुक्त किया जाना था। विहित तंत्र के अभाव में प्रस्तावित लक्षित लाभुकों को ऋण स्वीकृति या ऋण स्वीकृत होने की प्रक्रिया से संबंधित सूचना सहित दावा विपत्र प्राप्त होने के बाद जि.प.पदा. ने अनुदान की राशि बैंक शाखाओं में विमुक्त किया। 2009-12 के दौरान नमूना-जाँचित जिलों के 2051 लाभुकों का ₹ 3.47[25] करोड़ अनुदान उनके खातें में जमा करने हेतु विभिन्न बैंक शाखाओं को विमुक्त करने के लिए कोषागार से आहरित किया गया।

जिला पशुपालन पदाधिकारियों को लाभूकों के खातें में अनुदान की राशि जमा होने की सूचना नहीं थी

नमूना-जाँचित जिलों के जि.प.पदा. द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि यद्यपि 2009-12 के दौरान 1,676 लाभुकों का ₹ 2.65 करोड़ अनुदान विभिन्न बैंकों को विमुक्त किया गया था लेकिन जि.प.पदा. को इस बात की सूचना नहीं थी कि बैंक से ऋण स्वीकृत हुआ या प्रस्तावित लाभुकों के खाते में वास्तव में राशि जमा की गई थी और उनका अपना अंशदान दिया गया था।

हमने पाया कि 375 चयनित लाभुकों का ₹ 0.82 करोड़ का अनुदान बैंकों के दावा विपत्र के अभाव में जि.प.पदा. के पास पड़े हुए थे। पूछे जाने पर, जि.प.पदा. ने बताया कि 1,676 लाभुकों के खाते में अनुदान जमा करने संबंधी सूचना सम्बंधित बैंकों से प्राप्त कर उपलब्ध करायेंगे। यह विभाग में अनुदान उपयोग पर नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

गव्य विकास

दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम[26] के अन्तर्गत ऋण प्रक्रिया हेतु लाभुकों की सूची बैंकों को भेजी जानी थी। बैंक द्वारा आवेदन एवं पात्रता की आवश्यक सत्यापन के बाद अनुदान का दावा जि.ग.वि.पदा. को प्रस्तुत किया जाना था। झा.स. के आदेशानुसार छः महीने के अन्तराल पर पशुओं का क्रय दो चरणों में किया जाना था। तदनुसार बैंकों को अनुदान विमुक्त किया जाना था।

गाय खरीद पंजी एवं सात[27] नमूना-जाँचित जिलों के जि.ग.वि.पदा. द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि लाभुकों द्वारा गाय की खरीद नहीं

---

[25] पूर्वी सिंहभूम में कुक्कुट एवं सूकर विकास योजनाओं को छोड़कर क्योंकि जि.प.पदा. द्वारा सूचना नहीं दिया गया।

[26] एक कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा अनुदान (20 और 50 प्रतिशत के बीच) पर संकर नस्ल की गाय एवं भैंस प्रस्तावित लाभुकों के बीच वितरित किया जाता था।

[27] जि.ग.वि.पदा. देवघर द्वारा सूचना नहीं दिया गया।

₹ 3.04 करोड़ की अनुदान की राशि बैंकों में अव्यवहृत पड़े थे

किये जाने के कारण 2007-12 के दौरान ₹ 3.04 करोड़[28] (राज्य योजना: ₹ 26.84 लाख एवं रा. कृ. वि. यो.: ₹ 2.77 करोड़) की अनुदान की राशि बैंकों में अव्यवहृत पड़े थे। जि.ग.वि.पदा. द्वारा बताया कि प्रथम चरण के गाय क्रय के बाद लाभुकों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया इसलिए द्वितीय चरण हेतु ऋण एवं अनुदान राशि बैंकों द्वारा जमा नहीं किया गया और अनुदान राशि अव्यवहृत पड़ी रही।

जवाब पूरी तरह से सही नहीं था क्योंकि 2007-11 के दौरान 3,670 मामलों में से 332 मामलों में प्रथम चरण की गायें भी क्रय नहीं की गई थी। आगे, बैंकों को विमुक्त राशि जो अव्यवहृत थी, को जि.गा.वि.पदा. के लेखा में अनियमित रूप से व्यय दिखाया गया। बैंकों द्वारा अवितरित राशि को कोषागार में प्रेषित करने संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2012) कि अनुदान उपयोग में शत् प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

4.1.9 सेवा प्रदान

अंडा, दूध एवं मांस के उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामीण जनता के लिए रोजगार सृजित करने तथा उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा कुक्कुट विकास, सूकर विकास, बैकयार्ड पाल्ट्री, बकरा विकास, मवेशी वितरण तथा चारागाह विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया और टीकाकरण, पशुधन का उपचार, कृत्रिम गर्भाधन इत्यादि सेवाएं प्रदान की गई।

पशुपालन

वर्ष 2007-12 के दौरान विभाग द्वारा राज्य योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के अंतर्गत बकरा, कुक्कुट तथा सूअर विकास की योजनाओं को लिया गया। योजनाओं के उद्देश्यों/लक्ष्यों, निधि तथा व्यय को ***परिशिष्ट 4.5*** में वर्णित किया गया है।

[28] 2007-08: ₹ 26.62 लाख, 2008-09 ₹ 64.79 लाख, 2009-10 ₹ 29.60 लाख, 2010-11 ₹ 46.90 लाख और 2011-12 ₹135.87 लाख।

4.1.9.1 बकरा विकास योजना

(अ) बकरे के लिये आधारभूत संरचना का निर्माण

बकरी क्रय की राशि को विचलित किये जाने के कारण बकरियों के लिए सिर्फ सेड का निर्माण किया गया

बकरा विकास योजना के तहत् सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत बकरों की खरीद तथा आधारभूत संरचना (बकरा शेड) के निर्माण इत्यादि के लिए ₹ 6.49 करोड़ की स्वीकृति (सितम्बर 2007) प्रदान की गई। जिसमें से ₹ 5.47 करोड़ को पशु अस्पताल के निर्माण में पुनर्विनियोजित (मार्च 2008) में कर दिया गया। सरकार के आदेश (फरवरी 2008) के तहत् विभाग द्वारा ₹ 1.02 करोड़ की निकासी (मार्च 2008) में की गई तथा बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से दो जिला पशुपालन पदाधिकारियों[29] राँची (150 इकाई) तथा दुमका जिले (225 इकाई) में पशुपालकों को बकरा शेड निर्माण करवाने के लिये उपलब्ध कराई गई (मई 2008)। प्रति इकाई की कीमत ₹ 27,130 (शेड निर्माण- ₹ 24,000, खिलाने के उपकरण ₹ 2,650 तथा अनुश्रवण एवं परिवहन- ₹ 480 थी। जि.प.पदा. ने (सितंबर 2008 तथा मार्च 2010 के बीच) लाभुकों को 356 शेडों के निर्माण के लिये ₹ 81.97[30] लाख अग्रिम के रूप में भुगतान किया। उन्होंने खिलाने के उपकरण खरीद तथा परिवहन पर ₹ 7.03 लाख[31] खर्च किये। बचे हुए 19 शेडों[32] का निर्माण पूरा नहीं हुआ। अव्यवहृत राशि में से जि.प.पदा. राँची के पास ₹ 8.07 लाख थे जबकि जि.प.पदा., दुमका ने ₹ 4.67 लाख कोषागार में प्रेषित कर दिया (जून 2010)। विभाग के पास वास्तव में पशुपालकों द्वारा पूर्ण शेडों की संख्या की जानकारी नहीं थी। यद्यपि योजना की स्वीकृति (सितंबर 2007) में शेडों तथा बकरियों दोनों के वितरण का प्रावधान था पर हमने यह पाया कि सरकार के आदेश (फरवरी 2008) में बकरियों की खरीद का प्रावधान नहीं था। जिसके फलस्वरूप शेडों के निर्माण एवं सामग्री पर ₹ 89.00 लाख का व्यय लाभुकों के लिए कोई आमदनी का जरिया नहीं बन सका।

विभाग द्वारा बताया गया कि योजना का मकसद वैसे लाभुकों के लिये था जिनके पास बकरियाँ थी पर आधारभूत संरचना नहीं थी। विभाग का जवाब सही नहीं था क्योंकि स्वीकृति पत्र के अनुसार विभाग को बकरियाँ खरीदकर वितरित करनी थी।

---

[29] जि. प. पदा. दुमका: रू 61.04 लाख और जि. प. पदा. रॉची रू 40.70 लाख।

[30] दुमका: 209 इकाइयों के लिए ₹ 50.07 लाख और रॉची: 147 इकाइयों के लिए ₹ 31.90 लाख।

[31] दुमका: ₹ 6.30 लाख और रॉची ₹ 0.73 लाख।

[32] दुमका: 16 और रॉची:3।

(ब) उन्नत नस्ल की बकरी/बकरा वितरण

बकरी पालन हेतु आवश्यक सामग्री, दवाईयाँ टीका एवं 50 *प्रतिशत्* अनुदान पर तीन साल के लिए बीमा के साथ बकरी वितरण इकाई (पाँच बकरी एवं एक बकरा प्रत्येक इकाई में) विभाग द्वारा स्वीकृत (अगस्त 2011) किया गया। प्रत्येक इकाई का लागत ₹ 22,500 था। इसके अलावे, जि.प.पदा. द्वारा प्रत्येक इकाई के लिए ₹ 800 प्रचार पर व्यय किया जाना था। लाभुकों से यह वचन लिया जाना था कि उनके पास बकरियों के लिए शेड़ है और वे अपना अंशदान बैंक ऋण या बचत के द्वारा अपने बैंक खाते में जमा करेंगे। विभागीय पदाधिकारियों को योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए प्रेरित, सूत्रित एवं सहायता करना था। राज्य में 1,949 इकाईयों की स्थापना विभाग द्वारा स्वीकृत (अगस्त 2011) किया गया एवं ₹ 2.35 करोड़ आबंटित किया गया।

आठ नमूना-जाँचित जिलों में 761 इकाई के लक्ष्य के विरूद्ध 652 इकाई स्थापित किये गये थे। विभाग द्वारा 2011-12 के दौरान आवंटित ₹ 89.81 लाख में से ₹ 84.13 लाख व्यय किये गये। 46 इकाईयों के लिए शेष निधि ₹ 5.68 लाख 2011-12 में अभ्यर्पित किये गये।

नमूना-जाँचित जिलों में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

लाभुकों के खाते में बैंक द्वारा ₹ 3.15 लाख अनुदान जमा नहीं किया गया।

- जि.प.पदा. देवघर द्वारा 28 लाभुकों के लिए ₹ 3.15 लाख का अनुदान सिन्डीकेट बैंक को विमुक्त किया गया (मार्च 2012) यह सुनिश्चित किये बिना कि वे बैंक से ऋण प्राप्त करेंगे अथवा नहीं। बैंक द्वारा सिर्फ पाँच योग्य लाभुकों को ऋण स्वीकृत किया गया (अप्रैल एवं मई 2012) लेकिन जून 2012 तक अनुदान जमा नहीं किया गया। इस प्रकार, ₹. 3.15 लाख बैंक में अव्यवहृत पड़े रहे।

  साक्षात्कार (जून 2012) के दौरान पाँच में से चार लाभुकों द्वारा बताया गया कि उन्होने विहित 20 बकरी और चार बकरा के विरूद्ध 14 बकरी एवं एक बकरा का क्रय किया। कम एवं गैर-अनुपातिक संख्या में की गई क्रय उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है।

- धनबाद में 52 में से तीन लाभुकों के साक्षत्कार में उद्घटित हुआ कि उनके पास शेड नहीं थे।

- गुमला में ₹ 13.28 लाख की लागत पर 118 इकाई के निर्माण के विरूद्ध मात्र ₹ 5.85 लाख की लागत पर 52 इकाई स्थापित हुए थे। 66 इकाई के लिए ₹ 7.43 लाख जुलाई 2012 तक बैंकों/डाकघरों में पड़े थे।

- जि.प.पदा. राँची द्वारा स्वीकृति आदेशों (अगस्त 2011) का उल्लंघन करके 211 इकाई के लिए 211 लाभुकों का ₹ 23.74 लाख की अनुदान राशि लाभुकों के बैंक खाते में जमा करने के बजाय बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से उन्हें सीधे भुगतान किया गया। इस प्रकार, राशि के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विभाग सृजित परिसम्पतियों पर नियंत्रण खो सकता है।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया गया (जनवरी 2013)।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)

राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प (मई 2007) के अनुपालन में कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य योजना बजट के अतिरिक्त 100 *प्रतिशत्* केन्द्रीय सहायता वाली एक योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई। योजना के अन्तर्गत, स्पष्ट उद्देश्यों एवं सुनिश्चित समय सीमा के साथ विशिष्ट परियोजना चलाये जाने थे जो क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप हो ताकि रा.कृ.वि.यो. के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों के बराबर परिणाम हो। उपायुक्त नोडल पदाधिकारी थे और योजना का क्रियान्वयन उनके मार्गदर्शन में होना था। निम्नलिखित तीन योजनाओं के लिए 2008-12 में स्वीकृत ₹ 24.75 करोड़ में से ₹ 21.76 करोड़ व्यय किये गये।

(स) बकरा विकास योजना

राज्य सरकार द्वारा 2008-10 के दौरान 1,143 इकाईयों के वितरण के लिए ₹ 4.06 करोड़ स्वीकृत (फरवरी और अक्टूबर 2009 के बीच) किया गया जिनमें से ₹ 3.96 करोड़ व्यय के बाद 1,054 इकाई स्थापित किये गये। योजनाओं का विवरण **तालिका-3** में दिया गया है।

तालिका-3: बकरा विकास योजना के अन्तर्गत प्रावधान का विस्तृत विवरण

वर्ष	योजना	इकाई-लागत (₹)	अनुदान (₹)		लाभुक अंशदान (₹)		वार्षिक आय सृजन (₹)
			अ.जा./अ.ज.जा.	अन्य	अ.जा./अ.ज.जा.	अन्य	
2008-09 (सभी जिलों के लिए)	एक बकरा इकाई (10 मादा ब्लैक बंगाल नस्ल का एवं एक उन्नत नस्ल का नर)	60000[33]	54000	51000	6000	9000	आकलन नहीं किया गया

[33] परिवहन सहित बकरा क्रय: ₹26,000, बीमा: ₹ 1,600, बाड़ा निर्माण (150 वर्ग फीट) : ₹ 30,000, बर्तन एवं अन्य सामग्री का क्रय: ₹1,200, दवाई और टीका : ₹ 700 और अनुश्रवण एवं साइनबोर्ड : 500।

2009-10 (नमूना-जाँचित देवघर एवं दुमका सहित 11 जिले)	एक बकरा इकाई (देशी नस्ल के 10 मादा एवं ब्लैक बंगाल नस्ल का एक नर)	18000[34]	9000	7200	9000	10800	18600

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग

2008-09 के दौरान राज्य में 687 इकाईयों के लक्ष्य के अंतर्गत नमूना-जाँचित जिलों में 251 इकाईयाँ स्थापित किये जाने थे। इसके विरूद्ध 243 इकाईयाँ (97 *प्रतिशत*) ₹ 1.31 करोड़ की लागत से नमूना-जाँचित जिलों में स्थापित किये गये। 2009-10 के दौरान दुमका में 45 इकाई के लक्ष्य के विरूद्ध ₹ 3.91 लाख की लागत पर 43 इकाईयाँ (96 *प्रतिशत*) स्थापित किये गये। देवघर में 40 इकाई के लक्ष्य के विरूद्ध एक भी इकाई स्थापित नहीं की गयी जिसके लिए कोई कारण अभिलेखित नहीं था और ₹ 3.68 लाख का आवंटन अभ्यर्पित कर दिया गया।

निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:-

- फरवरी और अक्टूबर 2009 के राज्यादेशों में यह विहित नहीं था कि बकरी का क्रय, सामग्री, बीमा और शेड निर्माण की व्यवस्था, लाभुक या विभाग, किसे करना था। हमने पाया कि नमूना-जाँचित जिले में जि.प.पदा. द्वारा सीधे लाभुकों को राशि अग्रिम में दी गई। उनके पास शेड निर्माण से संबंधित कोई सूचना नहीं थी क्योंकि योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण नहीं किया गया था। इस प्रकार योजना की राशि के दुरूपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता।

- चार नमूना-जाँचित जिला[35] में 126 लाभुकों (2008-09) में से 27 के साथ साक्षात्कार में उद्घाटित हुआ कि विभिन्न बीमारियों के कारण 297 में से 156 बकरियाँ मर गई थी। जि.प.पदा. दुमका ने बताया (जुलाई 2012) कि शव परीक्षण एवं बीमा के पुनर्नवीकरण के अभाव में इन बकरियों के बीमा का दावा पेश नहीं किया जा सका।

- दुमका में 43 (2009-10) में से सात लाभुकों के साक्षात्कार में उद्घाटित हुआ कि वे 70 बकरी और सात बकरा के विरूद्ध मात्र 28 बकरी क्रय किये थे जबकि पूरा अनुदान राशि ₹ 63,000 का भुगतान उन्हें किया जा चुका था। जि.प.पदा. के अभिलेखों में यद्यपि 77 बकरियों का क्रय दिखाया गया था। इस प्रकार, 49 बकरियों के संदेहपूर्ण क्रय से इनकार नहीं किया जा

---

[34] परिवहन सहित बकरा क्रय: ₹ 15,000, बीमा: ₹ 1,100, बतर्न एवं अन्य सामग्री का क्रय: ₹ 1,200 तथा दवाई और टीका : ₹ 700।

[35] बोकारो, दुमका पूर्वी सिंहभूम और लातेहार ।

सकता। उपर्युक्त स्थिति जि.प.पदा. द्वारा अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया गया (जनवरी 2013)।

4.1.9.2 कुक्कुट विकास योजना (कु.वि.यो.)

रा.कृ.वि.यो. के अधीन वर्ष 2008-09 के दौरान विभाग ने बैकयार्ड कुक्कुट की स्वीकृत 4,793 (60 चूजे की एक इकाई) इकाईयों के विरूद्ध 4,775 इकाईयाँ स्थापित की। नमूना-जाँचित जिलों में 2010-12 के दौरान 1,010 इकाईयों की स्थापना के लक्ष्य (2010-11: 250 एवं 2011-12: 760) (400 ब्रायलर चूजे प्रति इकाई) के विरूद्ध 948 ईकाईयों (2010-11: 238 तथा 2011-12: 710) की स्थापना चयनित जिलों[36] में की गई।

(अ) बैकयार्ड कुक्कुट (साठ चूजे की योजना)

सरकार के राज्यादेश (फरवरी 2009), जो वर्ष 2008-09 के लिए निर्गत था, के अनुसार प्रत्येक कुक्कुट इकाई की लागत ₹ 8,000 थी। इसमें से, सहायक निदेशकों (एडी), क्षेत्रीय/राज्य कुक्कुट प्रक्षेत्र, बोकारो एवं राँची को जि.प.पदा. को चूजों की आपूर्ति हेतु ₹ 1,800 प्रति इकाई की दर से निधि का आवंटन प्राप्त था तथा अवशेष लागत राशि ₹ 6,200 प्रति इकाई की दर से योजना के कार्यान्वयन के लिए जि.प.पदा. को आवंटित किया गया। योजना लागू होने के प्रथम वर्ष में प्रति इकाई ₹ 17,000 तथा ₹ 16,600 का निवल लाभ क्रमश: अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य के लिए जो कि उन्हें दिये गये अनुदान[37] पर निर्भर था, का अनुमान विभाग ने लगाया।

लातेहार छोड़कर शेष सात चयनित जाँचित जिलों में लक्षित 1,585 कुक्कुट इकाईयों के विरूद्ध 1,547 कुक्कुट इकाईयाँ स्थापित किये गये

नमूना-जाँचित जि.प.पदा. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं तथा अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि विभाग ने राज्य में 4,793 इकाईयों को लागू करने के लिए ₹ 3.40 करोड़ आवंटित (फरवरी 2009) किया था। आठ नमूना-जाँचित जिलों में 1,785 इकाईयों हेतु चूजे आपूर्ति करने के लिए दो ए. डी.[38] को ₹ 32.13 लाख आवंटित था (फरवरी 2009)। इसमें से स्थापित 1,547[39] इकाईयों (लक्ष्य 1,585 इकाई) हेतु, लातेहार छोड़कर शेष सात नमूना-जाँचित जिलों में ए. डी. ने चूजों की आपूर्ति की।

---

[36] 2010-11 के दौरान पाँच और 2011-12 में 21 जिलों।

[37] अ. जा./अ. ज. जा.: 90 *प्रतिशत* और अन्य : 85 *प्रतिशत*।

[38] क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, राँची: 885 इकाईयों के लिए ₹ 15.93 लाख और राज्य कुक्कुट प्रक्षेत्र, बोकारो : 900 इकाईयों के लिए ₹ 16.20 लाख।

[39] राँची: 657 इकाईयाँ (₹ 12.39 लाख) तथा बोकारों: 890 इकाईयाँ (₹ 15.27 लाख)

लातेहार में लाभुकों का चयन समय से नहीं होने के कारण योजना लागू नहीं हो सकी जबकि इसके लिए 200 इकाईयों का लक्ष्य था।

पुनश्च, चयनित लाभुकों के बीच वितरण के लिए सामग्रियों यथा; कुक्कुट गृह का निर्माण हेतु, बाँस, तार आदि तथा खाद्य पदार्थ, दवाईयाँ आदि की खरीद हेतु आठ नमूना-जाँचित जिलों के जि.प.पदा. को ₹ 94.12 लाख का आवंटन (फरवरी 2009) प्राप्त था। जि.प.पदा. ने उक्त मद में ₹ 93.89 लाख का व्यय किया तथा लाभुकों के बीच सामग्रियों का वितरण किया

52 लाभुकों के सभी चूजे बीमारी से मर गये थे। यह जि.प.पदा. के जानकारी में नहीं था

विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में 1,306 (राँची छोड़कर) लाभुकों में से 61 से हुए साक्षात्कार (मई एवं जुलाई 2012) के दौरान प्रकट हुआ कि 52 लाभुकों के सभी चूजे बीमारी से मर गये थे। हालाँकि यह जि.प.पदा. के जानकारी में नहीं था जैसा कि जि.प.पदा.(बोकारो, पूर्वी सिंहभूम एवं गुमला) ने बताया (जून एवं जुलाई 2012)। उक्त में से शेष नौ में पूर्वी सिंहभूम के दो लाभुकों ने बताया (जुलाई 2012) कि उन्होंने अनुमानित आय से अधिक का अर्जन (₹ 24,000 तथा ₹ 50,000) किया जबकि सात ने अनुमानित आय से कम (₹ 100 से ₹ 10,000 के बीच) अर्जित किया।

लाभुकों के विलम्बित चयन के कारण लातेहार में चूजे की आपूर्ति नहीं की गयी। परन्तु, जि.प.पदा. ने कुक्कुट सामग्रियों का वितरण कर दिया। लातेहार में 16 लाभुकों से साक्षत्कार में पता चला कि कुक्कुट खाद्य पदार्थ (₹ 1.37 लाख), बाँस-तार की जाली आदि (₹ 4.73 लाख) जो उन्हें वितरित की गई थी, बरबाद हो गये थे। उनकी ताकत समाप्त हो गई थी तथा समय के बितने के साथ-साथ ₹ 1.30 लाख मूल्य की दवाईयाँ कालातीत हो गई थी। इस प्रकार ₹ 7.40 लाख का व्यय निष्फल साबित हुआ।

अत: योजना के लागू करने में उचित व्यवस्था तथा अनुश्रवण का अभाव था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2013)।

(ब) कुक्कुट पालन इकाईयों (प्रति इकाई 400 ब्रायलर चूजे) की स्थापना

राज्य में वर्ष 2010-12 के लिए विभाग ने कुक्कुट विकास योजना (400 ब्रायलर प्रति इकाई) के अन्तर्गत 1,010 इकाईयों (दिसम्बर 2010; 250 इकाईयाँ तथा जुलाई 2011; 760 इकाईयाँ) की स्वीकृति दी। कुल अनुमानित राशि ₹ 86,000[40] प्रति इकाई में से 50 *प्रतिशत्* सरकारी अनुदान था तथा शेष लागत राशि की व्यवस्था प्रस्तावित लाभुकों द्वारा बैंक ऋण से किया जाना था। विभाग

[40] चूजे, खाद्य सामग्री, दवाईयॉ: ₹ 32,000; शेड की लागत: ₹ 47,600 तथा कुक्कुट उपकरण: ₹ 6,400 ।

ने प्रतिवर्ष सात चक्रों में ₹ 42,700 प्रति इकाई की दर से आय का अनुमान लगाया।

चयनित जिलों में 370 कुक्कुट इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्ध 232 इकाईयाँ स्थापित की गई

राज्य के 948 लाभुकों के 948 इकाईयों पर कुल आवंटित राशि ₹ 4.35 करोड़ (दिसम्बर 2010 एवं जुलाई 2011) में से ₹ 4.06 करोड़ व्यय किये गये। सात[41] नमूना-जाँचित जिलों के जि.प.पदा. को 370 इकाईयों के लिए ₹ 1.59 करोड़[42] आवंटित था। जि.प.पदा. ने 321 इकाईयों के लिए ₹ 1.38 करोड़ की निकासी दिसम्बर 2012 तक किया था एवं ₹ 0.21 करोड़ प्रत्यार्पित कर दिया। यद्यपि, उसमें से ₹ 1.06 करोड़ का अनुदान 248 इकाईयों के लिए निर्गत किया गया तथा 73[43] इकाईयों की ₹ 0.32 करोड़ का अनुदान उनके बैंक खाते में जुलाई 2012 तक रखे हुए थे। जनवरी 2013 तक 232 इकाईयों स्थापित की गई तथा देवघर में 16 इकाईयों की स्थापना, बैंक ऋण स्वीकृत नहीं होने के कारण, नहीं हो सकी।

योजना के लागू किये जाने में हमने निम्नांकित त्रुटियाँ पाई:

- बोकारो के 30 लाभुकों में से चार को मात्र ₹ 0.63 लाख का अनुदान (₹ 13,000 से ₹ 20,000 के बीच) दिया गया जबकि अनुमान्य राशि ₹ 1.72 लाख (₹ 43,000 प्रति लाभुक) थी। भुगतान किया गया अनुदान वांछित लाभ के लिए पर्याप्त नहीं था।
- चार[44] नमूना-जाँचित जिलों के 136 लाभुकों में से 15[45] के साक्षात्कार के दौरान पता चला कि बोकारो तथा धनबाद में चूजे का उत्पादन प्रगति में था तथा लातेहार में कुक्कुट गृह निर्माणाधीन था। देवघर में चार लाभुकों ने बताया कि उन्हें बैंक से न तो ऋण और न ही अनुदान राशि प्राप्त हुई।

अत: नमूना-जाँचित जिलों में योजना की प्रगति समरूप नहीं थी तथा बैंक द्वारा निधि का ससमय निर्गत करने हेतु किये गये कार्रवाई का उचित अनुश्रवण न तो विभाग और न ही जि.प.पदा. द्वारा किया गया। फलस्वरूप योजना के अन्तर्गत वाँछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

---

41 बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार तथा राँची। गुमला के लिए कोई योजना नहीं थी।

42 2010-11: ₹ 43.40 लाख और 2011-12: ₹ 116.10 लाख।

43 बोकारो: ₹ 1.09 लाख, दुमका: ₹ 2.58 लाख,पूर्वी सिंहभूम: ₹ 7.31 लाख वर्ष 2010-11 में तथा ₹ 20.21 लाख वर्ष 2011-12 में एवं लातेहार: ₹ 1.29 लाख।

44 बोकारो, देवघर, धनबाद तथा लातेहार।

45 बोकारो: दो, धनबाद: छ:, देवघर: चार तथा लातेहार: तीन।

विभाग ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार (जनवरी 2013) किया तथा कहा कि सम्बधित जिलों का उचित अनुश्रवण किया जायगा।

4.1.9.3 सूकर विकास योजना (प्रजनन इकाई)

रा.कृ.वि. योजना के अधीन सरकार ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए राज्य के 14[46] जिलों में सूकर विकास योजना लागू करने की स्वीकृति दी। वर्ष 2011-12 में सरकार ने इसे 24 जिलों तक विस्तारित किया। योजना के अन्तर्गत चयनित लाभुकों के बीच सूकर प्रजनन इकाई[47] के लिए उन्नत नस्ल के सूकरों का वितरण करना था। राज्यादेश में विहित मार्ग दर्शन के अनुसार, बैंक से ऋण राशि या लाभुकों द्वारा स्वयं का अंशदान की राशि उनके खाते में जमा होना सुनिश्चित होने के बाद अनुदान की राशि लाभुकों के खाते में स्थानान्तरित किया जाना था। सूकरों को बिमित किया जाना था जिसके लिए इकाई के लागत राशि में ही निधि सम्मिलित थी। विभागीय पदाधिकारी को प्रोत्साहक के रूप में कार्य करना था और उनके द्वारा तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण, अनुश्रवण तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना था। योजनाओं का विवरण **तालिका-4** में दिया गया है:-

तालिका-4: सूकर विकास योजना में प्रावधानों को दर्शाने वाली सारणी

वर्ष	योजना	इकाई लागत (₹)	अनुदान (₹)		लाभुक अंशदान / बैंक ऋण (₹)		प्रति इकाई अनुमानित औसत वार्षिक आय (₹)
			अ.जा./अ.ज.जा.	अन्य	अ.जा./अ.ज.जा.	अन्य	
2009-10	छः सूकर (चार मादा और दो नर)	30000	15000	12000	15000	18000	23000
2010-11	छः सूकर (चार मादा और दो नर)	40000	13200	13200	26800	26800	26900
	13 सूकर (आठ मादा और पॉच नर)	71000	23430	23430	47570	47570	66000
	प्रति इकाई तीन सूकर-शेडों का निमार्ण	40000	13200	13200	26800	26800	--
2011-12	छः सूकर (चार मादा और दो नर)	27500	13750	13750	13750	13750	20 शवक

स्रोत :- पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग

जि.प.पदा. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं तथा अभिलेखों की जाँच के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

[46] इसमें से छः जिले यथा बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, लातेहार एवं राँची, वर्ष 2009-11 के दौरान शामिल थे।

[47] प्रत्येक इकाई में दो नर तथा चार मादा सूकरें।

चयनित जिलों में 1,241 के लक्ष्य के विरूद्ध 1,102 इकाईयॉ (89 *प्रतिशत*) स्थापित की गई

- वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान नमूना-जाँचित जिलों में 1,241 इकाईयों[48] के लक्ष्य के विरूद्ध 1,102 इकाईयों[49] की उपलब्धि रही। वर्ष 2010-11 के दौरान जि.प.पदा. लातेहार योजना को लागू करने में असफल रहे और ₹ 18.42 लाख की आवंटित राशि का प्रत्यार्पण किया गया।
- पूर्वी सिंहभूम एवं धनबाद में वर्ष 2009-12 के दौरान प्रशिक्षण, अनुक्षवण प्रसार तथा योजना के प्रति जागरूकता लाने के लिए निधि की उपलब्धता (धनबाद ₹ 1.17 लाख, तथा पूर्वी सिंहभूम ₹ 1.25 लाख) के बावजूद इन पर व्यय नहीं किये गये ओर निधि प्रत्यार्पित कर दी गई।
- वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 20.03 लाख (गुमला: ₹ 11.03 लाख एवं पूर्वी सिंहभूम: ₹ 9.00 लाख) का समस्त अनुदान 139 (गुमला 75, एवं पूर्वी सिंहभूम: 64) चयनित लाभुको के खाते में स्थानान्तरित (अप्रैल एवं जुलाई 2010 के बीच) कर दिया गया। गुमला के 75 में से पाँच लाभुकों का अनुदान कोषागार में जमा कर दिया गया क्योकि उन्होंने इच्छुक नहीं होंने के कारण योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया। पूर्वी सिंहभूम में बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति नहीं हाने के कारण चार लाभुक सूकर का क्रय नहीं कर सके।
- किसी भी नमूना-जाँचित जिलों में योजना के अधीन कोई भी सूकर बीमित नहीं पाया गया जिसे जि.प.पदा. द्वारा स्वीकार किया गया। पाँच नमूना-जाँचित जिलों में योजना (2009-12) के 1,102 लाभुकों में से 38 से साक्षात्कार के क्रम में पाया गया कि 17 लाभुकों के 46 सूकर (मूल्य ₹ 0.67 लाख) मर गये थे और लाभुक बीमा का लाभ नहीं ले सके क्योंकि सूकरें बीमित नहीं थी।

लाभुकों के द्वारा नर एवं मादा सूकरों का गैर-अनुपातिक क्रय किया गया

- हमने पाया कि चार नमूना-जाँचित जिलों के 21 इकाईयों[50] के लिए जि. प.पदा. ने 42 नर और 84 मादा सूकर की आवश्यकता के विरूद्व 28 नर, 90 मादा तथा चार नपुंसक सूकर का क्रय किया। अत: कम संख्या में सूकरों का क्रय योजना के उदेश्य (लाभुकों का अनुमानित आमदनी) को प्रभावित करेगा।
- पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों के 134 में से नौ लाभुकों से साक्षात्कार में प्रकट हुआ कि 2009-10 की योजना के सात लाभुकों ने औसत वार्षिक प्रक्षेपित लाभ से कम आमदनी (₹ 3,000 से ₹ 20,000) अर्जित की, दो

---

[48] 2009-10 : 380 इकाईयाँ, 2010-11 :433 इकाईयाँ एवं 2011-12: 428 इकाईयाँ।

[49] 2009-10: 344 इकाईयाँ, 2010-11 :368 इकाईयाँ एवं 2011-12: 390 इकाईयाँ।

[50] पूर्वी सिंहभूम: दो, गुमला: चार, बोकारो- दो तथा राँची:13।

लाभुको ने अधिक आमदनी (₹ 50,000) जुलाई 2012 तक अर्जित की। धनबाद के 11 लाभुकों के साक्षात्कार में प्रकट हुआ कि वर्ष 2010-11 में सूकरों के लिए शेडों का निर्माण नहीं किया गया था, एक लाभुक ने सूकरों का क्रय नहीं किया जबकि एक अन्य लाभुक द्वारा कम संख्या में सूकरों का क्रय किया गया।

विभाग द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित जिलों में उचित अनुश्रवण किया जायगा तथा आवश्यक कारवाई की जायगी।

अन्य योजनाएं

4.1.9.4 पशुरोग नियंत्रण हेतु राज्य को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.)

पशुरोग नियंत्रण हेतु राज्य को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.) एक केन्द्र प्रायोजित योजना का लक्ष्य संक्रामक रोगों यथा सूकर ज्वर, खुरहा चपका[51] एवं अन्य पशुरोगों का नियंत्रण था। सिवाय प्रशिक्षण अवयव के जो शत् प्रतिशत् भारत सरकार द्वारा निधित थी, यह योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में निधित थी। भारत सरकार ने ए.एस.सी.ए.डी. परियोजनाओं के लिए वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के लिए ₹ 16.53 करोड़ (राज्यांश ₹ 3.85 करोड़ सहित) की स्वीकृति प्रदान की थी। फिर भी भारत सरकार ने केन्द्रांश ₹ 12.68 करोड़ में से ₹ 8.14 करोड़ ही निर्गत की थी। केन्द्रांश की राशि कम उपयोग किये जाने के कारण कम राशि निर्गत की गई थी। योजना के अधीन पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग को टीके का उत्पादन अपने टीका उत्पादन संस्थान से या इसकी आपूर्ति किसी अन्य फर्म से करनी थी। वर्ष 2007-12 की अवधि में विभाग ने ₹ 5.95 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 4.49 करोड़ तथा राज्यांश: ₹ 1.46 करोड़) का उपयोग किया। कम उपयोग का कारण राज्य के उत्पादन संस्थान में टीके का कम उत्पादन तथा अन्य फर्म से कम आपूर्ति योजना के अन्तर्गत लिया जाना था। यह भी टीका करण की उपलब्धि को प्रभावित किया जैसा कि **तालिका-5** में चर्चित है।

तालिका-:5 टीकाकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	खुरहा चपका (एफ. एम डी.)		बकरी प्लेग (पी.पी.आर)		लँगड़ा ज्वर (बी. क्यू.)		गलघोंटू (एच.एस.)		सूकर ज्वर (स्वाइन फीवर)		रानीखेत बीमारी	
	लक्ष्य	उपलब्धि.	लक्ष्य	उपलब्धि.	लक्ष्य	उपलब्धि.	लक्ष्य	उपलब्धि.	लक्ष्य	उपलब्धि.	लक्ष्य	उपलब्धि.
2007-08	2	0.89	3	0	10	3.19	10	4.37	0.50	0.05	5	0
2008-09	2	0.11	3	0	10	8.79	10	9.21	0.50	0.05	0	0
2009-10	2	0.77	3	1.00	10	6.54	10	5.09	0.50	0.01	5	1.39
2010-11	2	0.29	3	1.47	10	4.64	10	7.64	0.50	0	5	0.54
2011-12	5	10.00	10	0.05	10	6.59	15	6.51	0.50	0	5	1.00
कुल	**13**	**12.06**	**22**	**2.52**	**50**	**29.75**	**55**	**32.82**	**2.50**	**0.11**	**20**	**2.93**

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग

[51] फुट एण्ड माउथ डिजीज।

टीकाकरण में उपलब्धि कम रही

- वर्ष 2007-12 की अवधि में टीकाकरण के लक्ष्य के विरूद्व खुरहा चपका में सात *प्रतिशत्*, बकरी प्लेग में 89 *प्रतिशत्* लँगड़ा ज्वर और गलघोंटू में 40 *प्रतिशत्*, सूकर ज्वर में 96 *प्रतिशत्* तथा रानीखेत में 88 *प्रतिशत्* की कम उपलब्धि रही।
- जि.प.पदा. बोकारो तथा गुमला मे टीकाकरण के लक्ष्य के विरूद्व कम उपलब्धि का कारण पशु स्वा. एवं उ.सं. द्वारा टीके का कम तथा विलंबित आपूर्ति किया जाना बताया गया (जून एवं जुलाई 2012)। जि.प.पदा. दुमका एवं धनबाद मे लक्षित पशुओं का टीकाकरण नहीं किये जाने का कारण तकनीकी कर्मचारी तथा पारा पशुचिकित्सक (पारा-भेट) का कमी बताया गया (जून तथा जुलाई 2012) चार[52] जि.प.पदा. ने कोई उत्तर नहीं दिया (अगस्त 2012)।

अत: निधि[53] की उपलब्धता के बावजूद टीके के अभाव में पशुओं को संक्रामक रोग होने के जोखिम में रखा गया। पशु.स्वा. एवं उ. सं. के आधार भूत संरचना को सुदृढ़ करने तथा संस्थान द्वारा टीके के उत्पादन/आपूर्ति प्राप्त करने का अनुश्रवण में विभाग असफल रहा।

संस्थान में सभी प्रकार के टीके के नहीं बनने, अपर्याप्त मात्रा में निजी संस्थान/अन्य प्रदेशों के संस्थानों से आपूर्ति प्राप्त करने तथा पारा-पशु चिकित्सकों (पारा-भेट) की कमी के कारण को विभाग ने स्वीकारा (जनवरी 2013)। उत्तर पूर्णतया सही नहीं थे क्योंकि एस्काड के लिए योजना बनाने तथा अन्य फर्मों से टीके के क्रय में दर की स्वीकृति विलम्बितथी।

4.1.9.5 पशु स्वास्थ्य सावधानी एवम् पशुचिकित्सा सेवाएं

विभाग ने राज्य में पशुओं के रोगों के नियंत्रण तथा स्वास्थ आच्छादान हेतु टीकाकरण, चिकित्सा एवं बन्ध्याकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। परन्तु, जिलों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारत नहीं थे। वर्ष 2007-08 से 2011-12 अवधि के लक्ष्य एवं उपलब्धि की विवरणी निम्नांकित **तालिका-6** में है।

---

[52] देवघर, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार तथा राँची

[53] वर्ष 2007-12 के दौरान पुनर्जीवित तथा विमुक्त: ₹ 8.14 करोड़, उपयोगित: ₹ 4.49 करोड़ (55.13 *प्रतिशत्*)।

तालिका 6: टीकाकरण, चिकित्सा, बन्ध्याकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान

(संख्या लाख में)

	टीकाकरण			चिकित्सा			बन्ध्याकरण			कृत्रिम गर्भाधान		
वर्ष	राज्य स्तरीय लक्ष्य	राज्य स्तरीय उपलब्धि	आठ नमूना जाँचित जिलों में उपलब्धि	राज्य स्तरीय लक्ष्य	राज्य स्तरीय उपलब्धि	आठ नमूना जाँचित जिलों में उपलब्धि	राज्य स्तरीय लक्ष्य	राज्य स्तरीय उपलब्धि	आठ नमूना जाँचित जिलों में उपलब्धि	राज्य स्तरीय लक्ष्य	राज्य स्तरीय उपलब्धि	आठ नमूना जाँचित जिलों में उपलब्धि
2007-08	अप्रस्तुत	अनुपलब्ध	2.69	अप्रस्तुत	अनुपलब्ध	4.56	अप्रस्तुत	अनुपलब्ध	0.36	1.51	0.57 (38)	0.26
2008-09	8.81	10.81 (123)	4.14	6.65	10.59 (159)	4.56	0.45	0.87 (193)	0.42	1.51	0.51(34)	0.25
2009-10	30.00	15.38 (51)	3.40	12.00	15.26 (127)	6.09	0.55	1.03 (187)	0.39	1.56	00	0.01
2010-11	30.00	20.22 (67)	7.00	15.00	15.32 (102)	6.87	0.90	1.12 (124)	0.45	1.56	0.42 (28)	0.22
2011-12	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	7.20	20.00	14.14 (71)	6.94	0.90	0.76 (84)	0.36	1.56	0.84 (54)	0.41

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग.। कोष्टक में दिये गए अंक प्रतिशत् को इंगित करता है।

तालिका-6 से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-12 के दौरान राज्य में टीकाकरण की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 51 और 123 *प्रतिशत्* के बीच था। सिवाय 2009-10 के, वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कृत्रिम गर्भाधान की उपलब्धि 28 से 54 *प्रतिशत्* के बीच रही।

वर्ष 2008-11 के दौरान टीकाकरण लक्ष्य के 51 से 123 *प्रतिशत्* रही

फ्रोजेन सीमेन बैंक, होटवार, राँची द्वारा तरल नाइट्रोजन तथा स्ट्रॉ की आपूर्ति सरकारी अस्पतालों में नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2009-10 में उपलब्धि नगण्य रही। सरकारी अस्पतालों के निकट क्षेत्र में भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फेडरेशन (बायफ) द्वारा डेयरी कैटल डेवलपमेंट सेन्टर (डी.सी.डी.सी.) का खुलना, जि.प.पदा. द्वारा कृत्रिम गर्भाधान में कम निस्तारण का कारण बताया गया। एम ओ यू के अनुसार दोहरीकरण से बचने के लिए डी.सी.डी.सी. को सरकारी अस्पतालों से कम से कम पाँच किलोमीटर की दूरी पर खोला जाना था। यह दोनों निदेशालयों के बीच समन्वय के अभाव को इंगित करता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को अंकित किया (जनवरी 2013)

गव्य निदेशालय

4.1.9.6 दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम

दूधारू पशु वितरण कार्यक्रम रा.कृ.वि.यो. के अन्तर्गत राज्य कार्यक्रम में 2008-09 से लिया गया था। ग्रामीण परिवारों को लाभपूर्ण स्वरोजगार प्रदान करने और राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च उत्पादन क्षमता वाले दुधारू पशु के वितरण हेतु अनुदान दिया जाना था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान और बैंक ऋण के माध्यम से प्रोटो टाईप,

योजनाएं[54] चलाई गई। इस उद्देश्य हेतु प्रस्तावित लाभुकों के लिए ऋण की स्वीकृति के लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार एवं उपायुक्त द्वारा अनुमोदित लाभुकों की सूची को विभिन्न बैंकों को भेजा जाना था। बैंकों से विमुक्त अनुदान लाभुकों के खातें में बैंक ऋण जमा होने के पश्चात स्थानान्तरित किए जाने थे। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परियोजना लागत ***परिशिष्ट 4.6*** में दिया गया है।

झारखण्ड सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रकार की डेयरी इकाई के लिए पशुओं का क्रय छः महिने के अंतराल पर दो चरणों[55] में किया जाना था, जिसका उद्देश्य पूरे वर्ष के दौरान दुग्ध की उपलब्धता कायम रखना था और जो किसानों के लिए बैंक ऋण के किस्तों का भुगतान करने में सहायक था।

2007-08 के दौरान योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित थी जबकि 2008-09 से रा.कृ.वि.यो. के अन्तर्गत पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित थी। 2007-12 के दौरान ₹ 56.45 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरूद्ध कुल ₹ 53.66 करोड़ का व्यय हुआ। आठ नमूना-जाँचित जिलों में कुल ₹ 29.08 करोड़ के आबंटन के विरूद्ध ₹ 27.81 करोड़ व्यय हुआ।

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुए:

दोनों चरणों में गायों की खरीद नहीं होने के कारण 3,670 इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 2,611 दुग्ध इकाईयाँ हीं स्थापित की गई

वर्ष 2007-11[56] के दौरान नमूना-जाँचित जिलों में कुल लक्षित 3,670 इकाईयों के विरूद्ध दूधारू पशु वितरण कार्यक्रम में प्रथम चरण में कुल 3,338 इकाईयों (91 प्रतिशत) के लिए गायों की आपूर्ति की गई थी। तथापि मात्र 2,611 इकाईयों (प्रथम चरण में क्रय की गई इकाईयों का 78 *प्रतिशत*) के लिए व्दितीय चरण की गायें आपूर्ति की गयी (***परिशिष्ट-4.7***)। प्रथम चरण में कम उपलब्धि (332 इकाई) के लिए जि.ग.वि.पदा. द्वारा बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति नहीं किया जाना और लाभुकों की ईच्छा में कमी बताया गया। लाभुकों द्वारा ऋण की खराब पुनर्भुगतान के कारण बैंकों द्वारा ऋण वितरित नहीं किया जाना द्वितीय चरण में कम उपलब्धि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

---

[54] दो गाय/भैंस, पाँच गाय/भैंस (मिनी डेयरी), दस गाय/भैंस (मिडी डेयरी), 20 गाय/भैंस (कामर्शियल डेयरी), 50 गाय/भैंस (मोडर्न डेयरी) और 100 गाय/भैंस (मोडर्न डेयरी)

[55] दो गाय इकाई - प्रत्येक चरण में एक गाय, पाँच गाय की मिनी डेयरी- पहले चरण में तीन गाय एवं दूसरे चरण में दो गाय, दस गाय की मिनी डेयरी- प्रत्येक चरण में पाँच गाय, बीस गाय की कामर्शियल डेयरी- प्रत्येक चरण में दस गाय, मोडर्न डेयरी (50 गायें) - प्रत्येक चरण में 25 गायें और मोडर्न डेयरी (100 गायें) - प्रत्येक चरण में 50 गायें।

[56] जुलाई 2012 तक 2011-12 के लिए गायों का क्रय नहीं किया गया था जबकि जि.ग.वि.प. दुमका और देवघर द्वारा 2007-08 के लिए सूचना नहीं दी गई।

विभाग द्वारा बताया गया कि लंबित क्रय में गति लाने के लिए जिलावार पशु मेला आयोजित किया जा रहा था एवं बैंकों द्वारा ऋण वितरण से संबंधित मामलों के निपटारा हेतु जि.ग.वि.पदा. को निर्देश निर्गत किये जा रहे थे।

- आगे, विभाग के कार्यकारी निर्देश के अनुसार सरकारी दुग्ध शीतक केन्द्र में दूध आपूर्ति हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाना था ताकि उन्हें दूध बिक्री हेतु पर्याप्त बाजार सुविधा से लाभान्वित किया जा सके। तथापि, आठ नमूना-जाँचित जिलों में से सिर्फ चार[57] जिलों में दुग्ध शीतक सयंत्र कार्यरत थे। इसके अलावे, ये दुग्ध शीतक संयंत्र मुख्यत: आधारभूत संरचना एवं कच्चे दूध की कमी के कारण अपनी क्षमता[58] के विरूद्ध आंशिक क्षमता[59] के साथ चल रहे थे। अत: दूध बिक्री हेतु किसानो को उचित बाजार सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा सका जिसके फलस्वरूप लोगों को गुणवतापूर्ण दूध आपूर्ति नहीं किया गया।

विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2012) कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त दूध की मूल्य संरचना की जाँच की जायेगी।

- कुल 3,338 में से 94 लाभुकों के साक्षात्कार में उद्घटित हुआ कि 35 लाभुकों (37 *प्रतिशत*) द्वारा अनुमानित वार्षिक औसत आय से ज्यादा अर्जित किया जा रहा था और 34 (36 *प्रतिशत*) लाभुकों द्वारा अनुमानित वार्षिक औसत आय[60] से कम अर्जित किया जा रहा था जबकि 15 लाभुकों (16 *प्रतिशत*) द्वारा कुछ भी अर्जित नहीं किया जा रहा था एवं दस लाभुकों ने कोई जवाब नहीं दिये।

विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2012) कि योजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए इच्छा अभिव्यक्ति हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

4.1.9.7 बछिया पालन कार्यक्रम

नस्ल सुधार एवं दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पैदा हुए बछियों को सहारा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था ताकि उन्हें जल्दी वयस्क बनाकर लम्बी

---

[57] धनबाद, देवघर, लातेहार एवं राँची।

[58] पूर्ण क्षमता- धनबाद- 5,000 लीटर प्रतिदिन, देवघर-10,000 लीटर प्रतिदिन, लातेहार- 2,000 लीटर प्रतिदिन और राँची - 20,000 लीटर प्रतिदिन।

[59] धनबाद- 1,600 लीटर प्रतिदिन, देवघर- 800 लीटर प्रतिदिन, लातेहार- 630 लीटर प्रतिदिन एवं राँची- सूचना उपलब्ध नहीं।

[60] दो गाय इकाई-₹ 35,830, मिनी डेयरी: ₹ 91,114, मिडी डेयरी- ₹ 1,62,850 एवं कामर्शियल डेयरी- ₹ 3,38,200।

दुधारू जीवन प्रदान किया जा सके। विभाग द्वारा रा.कृ.वि.यो. के अन्तर्गत 2008-09 से कार्यक्रम बैफ के माध्यम से चलाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत डी.सी.डी.सी. क्षेत्र में सभी बछियों को निबंधित, पट्टीकरण, कृमीमुक्त, टीकाकरण एवं बीमित करना था। इसके अलावे, काफ स्टार्टर पर 100 *प्रतिशत्* अनुदान एवं संतुलित आहार पर ₹ 5 प्रति किलोग्राम अनुदान किसानों को दिया जाना था।

2009-11 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 14.68 करोड़ स्वीकृत किया गया लेकिन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बैफ को ₹ 11.21 करोड़ विमुक्त किया गया। वर्ष 2011-12 में बैफ को कोई भी निधि विमुक्त नहीं किया गया। ₹ 11.21 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 3.22 करोड़ व्यय किया गया एवं 31 मार्च 2012 को बैफ के पास ₹ आठ करोड़ शेष था।

गव्य विकास निदेशालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के विश्लेषण से उद्घटित हुआ कि बछिया पालन कार्यक्रम में कम उपलब्धि प्राप्त किया गया था जैसा कि **तालिका-7** में दर्शाया गया है।

तालिका-7: बछिया पालन कार्यक्रम का लक्ष्य एवं उपलब्धि

मद	लक्ष्य (2009-12)	इकाई	उपलब्धि			
			2009-10	2010-11	2011-12	कुल
पंजीकरण	16000	संख्या	8144	14608	18715	41467
काफ स्टार्टर (खाद्य सामग्री)	320	टन	49.42	135.99	241.28	426.69
कृमि मुक्तिकरण	16000	संख्या	13839	13106	15868	42813
टीकाकरण	16000	संख्या	7000	14064	शून्य	21064
संतुलित आहार	21300	टन	1026.88	1461.32	2250.88	4739.08
बीमा	16000	संख्या	890	5165	3517	9572

स्रोत: गव्य विकास निदेशालय

- 2009-12 के दौरान 16,000 बछिया के लक्ष्य के विरूद्ध 41,467 बछिया निबंधित किये गये।
- कुल 41,467 निबंधित बछियों के विरूद्ध कृमि विमुक्त 42,813 बछिया की उपलब्धि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।
- 16,000 बछिया के लिए 21,300 टन संतुलित आहार के लक्ष्य के विरूद्ध 2009-12 के दौरान 4,739.08 टन संतुलित आहार उपयोग किया गया। यह मात्रा सिर्फ 3,560 बछिया के लिए पर्याप्त था।
- कुल लक्ष्य 16,000 बछिया एवं निबंधित 41,467 के विरूद्ध कुल 9,572 बछियों का बीमा किया गया था।

विभाग द्वारा बताया गया कि निबंधित संख्या यह इंगित नहीं करता था कि सभी बछियों को पूरे मात्रा का लाभ दिया जाना था। यह राशि की उपलब्धता के आधार पर अधकितम बछिया को दिया जाना था और बीमाकरण की प्रक्रिया जारी थी। जवाब सही नहीं था क्योंकि लक्ष्य के विरूद्ध भी उपलब्धि कम थी।

4.1.9.8 ग्रासलैण्ड विकास योजना (शत प्रतिशत् केंद्र प्रायोजित)

भूमि की अनुपलब्धता के कारण पाँच नमूना-जाँचित जिलों में ग्रासलैंड योजना कार्यान्वित नहीं की गयी

ग्रासलैण्ड विकास योजनान्तर्गत राज्य के 22 जिलों के 220 हेक्टेयर में 22 ग्रासलैण्ड विकास हेतु भारत सरकार ने ₹ 1.87 करोड़[61] (शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान) स्वीकृत किया (दिसम्बर 2008)। इसका उद्देश्य बंजर भूमि का विकास करके पूरे वर्ष पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना था जिससे मृदा कटाव भी रोका जाता। जि.ग.वि.पदा. द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से भूमि की व्यवस्था किया जाना था और बैफ द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाना था।

नमूना-जाँचित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि 2009-12 के दौरान ₹ 14.05 लाख व्यय करके तीन[62] जिलों में 30 हेक्टेयर में ग्रासलैण्ड स्थापित किये गये थे और अन्य पाँच[63] जिलों में भूमि की अनुपलब्धता/विवादित भूमि के कारण ग्रासलैण्ड का सृजन नही किया गया था यद्यपि बीज और खाद, पर्यवेक्षकों के मजदूरी इत्यादि पर ₹ 2.81 लाख[64] व्यय किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप नमूना-जाँचित जिलों में मवेशी प्रर्याप्त हरा चारा से वंचित रहे। पूर्व में आवंटित राशि के कम उपयोग के कारण विभाग ने शेष 50 *प्रतिशत्* राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं किया।

विभाग ने बताया कि भूमि की उपलब्धता की प्रगति को उपायुक्तों के स्तर पर अनुकरण हेतु जि.ग.वि.पदा. को निर्देशित किया गया था।

4.1.9.9 दूध प्रापण, संसाधन एवं विपणन

झारखण्ड डेयरी परियोजना (झा.डे.प.) की स्थापना दुग्ध सह शीतक संयंत्रों के वाणिज्यिक संचालन हेतु की गई थी। झा.डे.प. को चलाने के लिए झारखण्ड सरकार और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एन.डी.डी.बी.), आनन्द गुजरात के बीच एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षित (दिसम्बर 2007) हुआ था। झा.डे.प. का कार्यान्वयन एन.डी.डी.बी. एवं झा.स. द्वारा संयुक्त रूप से बनाये गये योजना एवं कार्यक्रम के आधार पर किया जाना था। झा.स. के आदेश (नवम्बर 2008)

---

[61] अनुमानित लागत:₹ 8.50 लाख प्रति।

[62] देवघर, दुमका और राँची ₹ 4.25 लाख के दर से (50 *प्रतिशत्*)।

[63] बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और लातेहार।

[64] बोकारो: ₹ 0.36 लाख एवं धनबाद ₹ 2.45 लाख।

के अनुसार एन.डी.डी.बी. को प्रथम चरण के पाँच वर्षों में 12 जिले आच्छादित किये जाने थे। तथापि, लक्ष्य प्राप्ति की विफलता में एन.डी.डी.बी. को दण्डित करने संबंधी कोई प्रावधान एम.ओ.यू. में नहीं था।

गव्य विकास निदेशालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के विशलेषण में उद्घटित हुआ कि 2008-12 के दौरान 2,212 दुग्ध उत्पादकों (सात *प्रतिशत*) को आच्छादित करते हुए एन.डी.डी.बी. द्वारा मात्र तीन जिलों[65](25 *प्रतिशत*) को ही आच्छादित किया जा सका। कुल दूध प्रापण 7,330 लीटर प्रतिदिन (11 *प्रतिशत*) था यद्यपि 2008-12 के दौरान एन.डी.डी.बी. द्वारा कुल आबंटित ₹ 26.80 करोड़ में से ₹ 11.10 करोड़ व्यय किये गये। लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण ***परिशिष्ट-4.8*** में दिया गया है। एम.ओ.यू. की अवधि 06 दिसम्बर 2012 को समाप्त हो गई और एन.डी.डी.बी. द्वारा परियोजना का आगे प्रबंधन हेतु असमर्थता व्यक्त की गई (06 दिसम्बर 2012)। अतः, वाणिज्यिक संचालन हेतु झा.डे.प. का प्रभार लेने संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिया गया (दिसम्बर 2012)।

निदेशक ने बताया कि (अगस्त 2012) दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा किसानों को राशि उपलब्ध कराने में अरूचि दिखायी गई जो झा.डे.प. के लक्ष्य की कम उपलब्धि का मुख्य कारण था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि एम.ओ.यू. करने के समय नयी व्यवस्था और उससे जुड़ी कठिनाइयों से विभाग अवगत था।

इस प्रकार, एन.डी.डी.बी. को तय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गतिशील बनाने में विभाग असफल हुआ। यद्यपि इनके द्वारा एन.डी.डी.बी. के साथ समय-समय पर कई बैठकें आयोजित की गई। एम.ओ.यू. में मुआवजा का प्रावधान नहीं होने के कारण विभाग एन.डी.डी.बी. को उसके खराब उपलब्धि के लिए दण्डित भी नहीं कर सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।

4.1.9.10 विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जाना

संदर्श योजना (2007-12) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न पशुपालन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन पेशेवर एवं प्रतिष्ठित संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में उद्घटित हुआ कि 2007-11 के दौरान इस हेतु कोई राशि उद्व्ययित नहीं की गई थी। 2011-12 में यद्यपि ₹ 14.32 लाख स्वीकृत किये गये थे। उसके विरूद्ध मात्र ₹ 3 लाख आवंटित किया गया जिसका भी इस्तेमाल

[65] लोहरदगा, रामगढ़ और रॉची।

नहीं हो सका। इस प्रकार, उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 136.55 करोड़ व्यय से संबंधित कार्यान्वित योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया। अत: विभाग कार्यान्वित योजनाओं के प्रभाव की जानकारी से वंचित रहा।

गव्य विकास प्रक्षेत्र में यद्यपि प्रभाव मूल्यांकन नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेस के द्वारा किया गया था जिसने राज्य में गव्य विकास हेतु विस्तृत रोड मैप प्रदान किया था।

4.1.10 अनुश्रवण

विभाग के आदेशानुसार (फरवरी 2005) गव्य विकास निदेशालय के सभी योजनाओं का भौतिक सत्यापन वर्ष में दो बार संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किया जाना था। विभाग ने आदेश दिया (नवम्बर 2009) कि केवल स्थापित कामर्शियल एवं मोडर्न डेयरी का शत् प्रतिशत् भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक द्वारा प्रत्येक छ: महीने में एक बार किया जाए।

पशुपालन निदेशालय द्वार अनुश्रवण से संबंधित कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ था। तथापि, सरकार के स्वीकृति आदेशों में विशेष योजनाओं के अनुश्रवण हेतु कुछ अनुदेश समाहित थे।

छ:[66] नमूना-जाँचित जि.ग.वि.प. के द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि 2007-12 के दौरान वांछित 60 निरीक्षणों में से क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक द्वारा मात्र सात निरीक्षण किये गये थे। निरीक्षणों के विवरण ***परिशिष्ट-4.9*** में दिये गये हैं। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर दो[67] जि.ग.वि.प. ने बताया (अप्रैल एवं मई 2012) कि यद्यपि निरीक्षण किये गये थे लेकिन इस संबंध में कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

स्वीकृति आदेशों (2011-12) में सम्मिलित अनुदेशों के अनुसार योजनाओं का अनुश्रवण निदेशक द्वारा छ: महीने में एक बार, जि.प.पदा. द्वारा तीन महीने में एक बार एवं बी.ए.एच.ओ. द्वारा महीने में एक बार किया जाना था। इस हेतु विहित अनुश्रवण-सह-निर्देशिका पुस्तक में प्रविष्टि किया जाना था। लेकिन इस अवधि में किये गये निरीक्षण से संबंधित कोई अभिलेख नमूना-जाँचित जिलों में उपलब्ध नहीं थे। वांछित निरीक्षण के अभाव में अनियमितता/कमियों से इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने बताया (जनवरी 2013) कि मुख्यालय स्तर पर 2011-12 में एक अनुश्रवण कोषांग की स्थापना चालू योजनाओं के अनुश्रवण हेतु की गई थी।

---

[66] बोकारो, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और लातेहार।

[67] देवघर और राँची

4.1.11 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई संगठन अपने को यह आश्वस्त करता है कि विहित व्यवस्था ठीक से कार्यरत है। आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अवयव है। वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण एवं मुख्य लेखा नियंत्रक के नेतृत्व में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग सहित सभी विभागों का आन्तरिक लेखापरीक्षा करता है। पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग का कोई अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है।

संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि वित्त विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 2007-12 के दौरान नमूना-जाँचित जिलों का लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग के क्रियाकलापों में विहित कमियों एवं अनियमितताओं का पता लगाया जाना शेष रह गया।

4.1.12 निष्कर्ष

पशुपालन एवं गव्य विकास निदेशालयों के योजना अनुश्रवण एवं परियोजना कार्यान्वयन में कमियाँ थी जैसा कि निम्नलिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्रतिबिम्बित हुई।

- राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) के प्रावधानों के अनुसार वांछित 1756 पशु अस्पतालों के विरूद्ध राज्य में मात्र 451 पशु अस्पताल थे। पशु अस्पतालों/औषधालयों में बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त थी। राज्य में विभाग के पास सिर्फ आठ कार्यरत दूध शीतक संयंत्र थे जो दुग्ध उत्पादकों के दूध की लाभकारी बिक्री सुविधा प्रदान करने जैसे उद्देश्य को बुरी तरह से प्रभावित किया। यहाँ तक कि मिल्क बूथें भी स्थल की कमी के कारण स्थापित नहीं किये गये थे। इसके अलावे, यहाँ पशु चिकित्सकों को कमी (32 *प्रतिशत*) थी।

- मुख्यत: निधियों के आबंटन में विलम्ब के कारण योजना राशि में अत्यधिक बचत थी एवं मार्च महीनें में व्यय का वेग था। अनुदान की बड़ी राशि विभिन्न बैंकों में पड़े हुए थे एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी (जि.प.पदा.) द्वारा लाभुकों के बैंक खाते में अनुदान जमा किये जाने का अनुश्रवण नहीं किया गया था।

- बकरा विकास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा बकरों की खरीद एवं बकरा आवास निर्माण को समक्रमित नहीं किया गया। बकरा क्रय हेतु उपलब्ध राशि को विचलित किया गया। अनुश्रवण की कमी के कारण योजना का

कार्यान्वयन बाधित हुआ। लाभुकों से साक्षात्कार में बकरियों की मृत्यु उद्घटित हुए थे जिसकी जानकारी जि.प.पदा. को नहीं थी।

- कुक्कुट विकास योजना के अन्तर्गत लाभुकों के चयन में विलम्ब के कारण तय लक्ष्य से कम उपलब्धि प्राप्त हुए। मुर्गियों की मृत्यु की जानकारी जि.प.पदा. को नहीं थी।
- नमूना-जाँचित जिलों में 38 लाभुकों के साक्षात्कार से उद्घाटित हुआ कि 2009-12 की अवधि में यद्यपि 17 लाभुकों के 46 सूकर मर गये थे लेकिन सूकरों के बीमित नहीं होने के कारण कोई दावा नहीं किया जा सका क्योंकि राशि की उपलब्धता के बावजूद लाभुकों के बीच जि.प.पदा. जागरूकता पैदा करने में असफल थे।
- पशु रोगों की रोकथाम हेतु राज्यों को सहायता (एस्काड) के अन्तर्गत, 2007-12 की अवधि के दौरान टीकाकरण लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी थी। यह कमी टीकाओं के विलम्बित/कम आपूर्ति के कारण एफ.एम.डी. में सात *प्रतिशत्*, पी.पी.आर. में 89 *प्रतिशत्*, बी.क्यू. और एच.एस. में 40 *प्रतिशत्* तथा रानीखेत में 88 *प्रतिशत्* थी।
- दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गायों के कम क्रय के कारण 2007-11 की अवधि के दौरान नमूना-जाँचित जिलों में 3,670 इकाइयों में से मात्र 2,611 इकाईयाँ (71 *प्रतिशत्*) ही स्थापित हो पायी।
- नेशनल डेयरी डेवेलपमेंट बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा प्रबंधित (एम.ओ.यू. के अन्तर्गत) झारखण्ड डेरी प्रोजेक्ट (जे.डी.पी.) 2008-12 की अवधि के दौरान ₹ 11.10 करोड़ व्यय के पश्चात् कुल 12 में से तीन जिला ही दूध प्रापण एवं संसाधन हेतु आच्छादित कर सका। विभाग द्वारा जे.डी.पी. का प्रबंधन प्रभार एम.ओ.यू. के समाप्त होने के बाद ही लिया गया (दिसम्बर 2012)।

4.1.13 अनुशंसाएं

- *पशु चिकित्सालयों, शीतक संयंत्रों, मिल्क बूथों एवं पशु चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *योजना राशि का अधिकतम उपयोग एवं मार्च में व्यय के वेग को कम करने के लिए ससमय राशि का आवंटन सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बैंकों में पड़े अनुदान की राशि का अनुश्रवण भी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *सरकार को बकरा क्रय एवं योजना का अनुश्रवण सुनिश्चित करना चाहिए।*

- *योजना का वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए मुर्गियों की स्वास्थ्य देख-भाल एवं नियमित अनुवर्तन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *लाभुकों को हानि से बचाने के लिए सूकरों की बीमा संबंधी जागरूकता विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *टीकाकरण द्वारा बीमारियों के नियंत्रण हेतु टीका-द्रव्यों का ससमय एवं पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *वांछित लाभों की प्राप्ति हेतु योजना में तय कुल गायों का क्रय सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2012)। उनसे प्राप्त (दिसम्बर 2012 एवं जनवरी 2013) उत्तर को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थान पर सम्मिलित किये गए।

अध्याय -5

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-5

अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्र निर्माण के अनुपालन लेखापरीक्षा में गबन, दुर्विनियोजन, संसाधनों के प्रबंधन में त्रुटियों और नियमन, औचित्य एवं मितव्ययिता के नियमों के पालन में हुई विफलता के बहुत से उदाहरण पाये गये। इनको अनुवर्त्ती कंडिकाओ के अन्तर्गत विस्तृत उद्देश्य शीर्ष में प्रस्तुत किया गया है।

5.1 नियमों का अनुपालन नहीं

सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, विनियमों और आदेशों के तहत् व्यय किया जाता हो। यह न तो केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग एवं धोखेबाजी को रोकता है वरन् अच्छे वित्तीय अनुशासन के संधारण में भी मदद करता है। नियमों की अवहेलना पर कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये है:-

पथ निर्माण विभाग

5.1.1 मूल्य समायोजन पर परिहार्य व्यय

सरकारी आदेश के खिलाफ सड़क निर्माण के लिए कार्य संपादन हेतु अतिरिक्त समय दिए जाने के कारण अनुबंध में मूल्य समायोजन का क्लॉज शामिल करना पड़ा जिसके फलस्वरूप ₹ 6.25 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सड़क कार्य के समापन अवधि निश्चित करने से सम्बन्धित, भारतीय रोड कांग्रेस के द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर झारखण्ड सरकार ने पथ निर्माण विभाग के संदर्भ में आदेश दिया (अगस्त 2007) कि एक से 15 कि.मी. तक की लम्बाई वाले सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को 10 माह के अंदर (1 वर्ष से कम) पूर्ण किया जायेगा तथा समय सीमा का विस्थापन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। नवम्बर 2007 में, पथ निमार्ण विभाग ने तय किया कि मूल्य समायोजन सीमेंट, बिटुमिन, स्टील और अन्य सामग्रियों पर उन परियोजनाओं के लिए देय होगा जिनका मूल्य ₹ 2.5 करोड़ से उपर हो तथा समय सीमा 1 वर्ष से ज्यादा हो। उस निर्णय को मानक बोली-प्रक्रिया (बिड़ींग) दस्तावेज के एक क्लॉज (खण्ड) के रूप में

शामिल किया गया। इस प्रकार 15 कि.मी. तक के पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में मूल्य समायोजन नहीं होना था।

लेखापरीक्षा जाँच (जून 2011 और फरवरी 2012) में यह पाया गया कि कार्यपालक अभियंतागण पथ निर्माण गोड्डा और राष्ट्रीय राजमार्ग डिविजन चाईबासा ने 4 पथों[1] (जिनकी लम्बाई 8 से 13 कि.मी. के मध्य था) के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य हेतू तीन निविदा आमंत्रित की (फरवरी और जून 2009 के मध्य) जिनका मूल्य ₹ 10.45 से ₹ 24.60 करोड़ के बीच था। जारी निविदाएं कार्य के परिमाण विपत्र की मात्रा पर आधारित थी जो अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अंचल, रांची द्वारा अनुमोदित थी (फरवरी 2009), निविदा में निर्धारित कार्य समय सीमा 13 से 15 माह के मध्य थी। हमने पाया कि चाईबासा के दोनों मामलों में प्रारंभ में कार्यपालक अभियंता ने जो निविदा आमंत्रित की (19 जनवरी 2009) उसमें कार्य संपादन का समय 12 माह था। बाद में, एक शुद्धिपत्र प्रकाशित हुआ (21 जनवरी 2009) जिसमें समय को 13 माह तक बिना किसी कारण के बढाया गया। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि अनुमान्य समय सीमा के विस्थापन को उचित ठहराये। विभागीय निविदा समिति[2] ने निविदा को मान्यता देते समय सरकार के अगस्त 2007 के आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया।

कार्यपालक अभियंताओं ने चार एस.बी.डी. अनुबंध जिसका मूल्य ₹ 68.56 करोड़[3] था, तीन ठेकेदारों[4] के साथ (अगस्त और अक्टूबर 2009 के मध्य) किये। चूंकि कार्य समापन की समय सीमा एक वर्ष से अधिक थी अत: मूल्य समायोजन की कंडिका अनुबंध में सम्मिलित की गई। ₹ 68.56 करोड़ के मान्य दर के विरूद्ध ठेकेदारों को ₹ 77.40 करोड़ (पथ विभाग गोड्डा: ₹ 21.05 करोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग चाईबासा ₹ 56.35 करोड) रूपये भुगतान किये गए (दिसम्बर 2010 और जनवरी 2012 के मध्य) जिनमें मूल्य

---

1 (1).गोड्डा-पिरपैति पथ 25 से 32 कि.मी तक (लम्बाई:8कि.मी., नियत समय 15 माह), और 33 से 42 कि.मी.-10 कि.मी., नियत समय 15 माह)। (2) चाईबासा-जैंतगड़ पथ 177 से 189 कि.मी. और 190 से 202 कि.मी. राज्य मार्ग, 75 ई का (प्रत्येक 13 कि.मी. लम्बाई के लिए नियत समय प्रत्येक पथ के लिए 13 माह)।

2 मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में।

3 आर सी डी. गोड्डा: ₹ 11.33 करोड़+₹ 8.97 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग चाईबासा: ₹ 25.82 करोड़+ ₹ 22.44 करोड

4 आर.सी.डी. गोड्डा: (1) कोलकाता इंडस्ट्रीयल सप्लाई कॉरपोरेशन, कोलकाता; राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमंडल चाईबासा (1) खोखर इनफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, टाटा रोड, चाईबासा (2) राम कृपाल सिंह कन्श्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, राँची।

समायोजन ₹ 6.25 करोड़ (पथ विभाग गोड्डा: ₹ 1.42 करोड़ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग चाईबासा: ₹ 4.83 करोड़) शामिल था। पथ कार्य सितम्बर 2010 और फरवरी 2011 के मध्य समाप्त हुए। हमने पाया कि चार में से एक पथ कार्य (चाईबासा-जैंतगड़ पथ: 13 कि.मी.) 11 माह 6 दिन में समाप्त हुए जिसके लिए प्रारंभ में 12 माह की समय सीमा निर्धारित थी जिसे बाद में बढ़ा कर 13 माह कर दिया गया। अन्य पथ कार्य (गोड्डा-पीरपैंती पथ 10 कि.मी.) जिसे 15 माह में समाप्त करना था वास्तव में 13 माह में समाप्त हुआ। इससे यह इंगित हुआ कि दी गई समय सीमा आवश्यकता से अधिक तथा गैर न्यायोचित थी।

इन बिन्दुओं को इंगित किये जाने (मई 2012) पर विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग ने अभियंता पथ निर्माण विभाग गोड्डा तथा मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग राँची का उत्तर प्रस्तुत किया (नवम्बर 2012)। पथ निर्माण विभाग गोड्डा के जवाब में बताया गया कि मानक बिड़िग दस्तावेज के अनुसार, कार्यस्थल पर दी जानेवाली संयंत्र एवं/मशीनरी की संख्या/कोड के मूल्य पर आधारित थे, जिसके कारण कम संयंत्र एवं मशीनरी का प्रयोग हुआ फलस्वरूप कार्य संपादन हेतु अधिक समय का प्रावधान आवश्यक था। इसके अलावा कार्य में (कवच) गार्ड दीवार, पुलिया एव नालियों के निर्माण संबंधी अतिरिक्त कार्य भी शामिल था।

एस.बी.डी. के तहत कम मात्रा में मशीनरी के उपयोग को पुन: मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग को संदर्भित किया (मार्च 2013) गया जिन्होने जवाब दिया कि एस.बी.डी. के तहत मशीनरी के आवश्यकता का प्रावधान सिर्फ एक दिशा निर्देश है, अनिवार्य आवश्यकता नहीं। मशीनरी प्रयोग का तदाद, कार्य विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाना है। अत: कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग गोड्डा द्वारा मशीनरी की जरूरत का आकलन आर.सी.डी. द्वारा निर्धारित (अगस्त 2009) समय सीमा को घ्यान में रखकर करना चाहिए था। आगे, अतिरिक्त कार्यों के लिए केवल 15 दिन निर्धारित थे (गार्ड वाल निर्माण, पुलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण जैसा जवाब में था) जिसके पूर्णता के लिए समय सीमा विस्तार उचित नहीं था।

राष्ट्रीय राजमार्ग चाईबासा के संदर्भ में यह बताया गया कि पथ निमार्ण विभाग के अगस्त 2007 के आदेश, झारखण्ड के राजमार्ग कार्य पर लागु नहीं थे चूँकि राजमार्ग का कार्य, सड़क परिवहन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्गत मार्ग दर्शिका के अधीन किया जाता है। अत: विभागीय प्राधिकारों द्वारा निविदा आमंत्रण के समय, अगस्त 2007 के सरकारी आदेश की

अवहेलना कर सड़क कार्यों के समापन समय सारणी का अनियमित निर्धारण से मूल्य समायोजन पर ₹ 6.25 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अगस्त 2007 के आदेश में मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को भी इस तरह के कार्य के तकनीकी स्वीकृति देते समय इसी कार्य समापन अनुसूचि का अनुसरण करने के लिए कहा गया था।

भवन निर्माण विभाग

5.1.2 एकरारनामा का अनाधिकृत कार्यान्वयन

संवेदक के निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त्तों के अधीन किए गए करार जिसमें मूल्यवृद्धि एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम अनुमान्य नहीं था के विरूद्ध विभाग ने ₹ 47.53 करोड़ मूल्य का कार्य जिसमें मूल्यवृद्धि एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम सन्निहित था का कार्य कराया। यह सभी निविदादाताओं को समान अवसर प्रदान करने का सरकार के आदेश का उल्लंघन था।

सितम्बर 2005 में निर्गत वित्त विभाग के आदेशानुसार, एन.आई.टी. के निर्गतोपरान्त निविदा के अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) के किसी भी शर्त को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि निविदादाताओं के लिए समान अवसर के अधिकार का खंडन नही हो।

समाहरणालय परिसर, फेज-II, राँची के निर्माण की तकनीकी अनुमोदन (मार्च 2007) और ₹ 41.65 करोड़ के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (सितम्बर 2007) भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रदान किया गया। कार्य में, एक पुराने भवन के विध्वंसोपरान्त तीन भवनों का निर्माण एवं एक नया भवन, जो फेज-I में निर्माणाधीन था, उसमें अभिलेखों को स्थानान्तरित करना, सम्मिलित था। प्रशासनिक स्वीकृति (ए.ए.) के शर्त के अनुसार, समाहरणालय भवन फेज-II के निर्माण के लिए निविदा इस प्रकार आमंत्रित किया जाना था कि फेज-I के निर्माणाधीन भवन के पूर्ण होने के ठीक पहले करार किया जा सके।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.) विशेष कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, राँची के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2011) से पता चला कि फेज-I भवन को जनवरी 2008 तक पूर्ण किया जाना था। का.अ. द्वारा दिसम्बर 2007 में फेज-II कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) निर्गत की गई। एन.आई.टी. के शर्तों के अनुसार, पी.डब्ल्यू.डी. प्रपत्र एफ-2[5] में डाला जाने

[5] एफ एफ 2 करार में निविदाकर्त्ता सभी मदों का दर अनुमनित लागत के ऊपर था नीचे प्रतिशतता उद्धत करता है और इसमें मूल्य समायोजन तथा चलंत अग्रिम का कोई प्रावधान नहीं होता।

वाला अनुमोदित परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) पर मुहरबंद निविदायें आमंत्रित किया गया और अचानक बदलाव और/या श्रम, सामग्री इत्यादि के दरों में वृद्धि की स्थिति में कोई दावा देय नहीं था। कोई मोबिलाईजेशन अग्रिम भी ठेकेदार को देय नही था। निविदा मूल्यांकण समिति (नि.मू.स.) ₹ 47.53 करोड़ (बी. ओ. क्यू. मूल्य से 8.5 *प्रतिशत्* अधिक) पर उसी ठेकेदार[6] को जिसे पहले से फेज-I का कार्य आवंटित था, के पक्ष में निविदा का निर्णय लिया (मार्च 2008)। अधीक्षण अभियन्ता, भवन निर्माण अंचल, राँची निविदा निर्णय के बारे मे का.अ. को सूचित किया (अप्रैल 2008)। यद्दापि, का.अ. ठेकेदार के साथ करार कार्यान्वित नही किया गया, क्योंकि फेज- II में भवन के निर्माण के लिए स्थल, अवरोध मुक्त नही था, चूंकि फेज-I का कार्य पूर्ण नही था। इसी बीच, सरकार ने ₹ 2.5 करोड़ से अधिक की लागत वाले कार्य के लिए स्टैंडर्ड बीडींग डोक्यूमेन्ट्स (एस.बी.डी.) लागू किया (नवम्बर 2008)। एस.बी.डी. के अंतर्गत मूल्य समायोजन और मोबिलाईजेशन अग्रिम/संयंत्र अग्रिम देय था। ठेकेदार ने का.अ. से एस.बी.डी. के अंतर्गत एकरारनामा कार्यान्वित करने का अनुरोध की (24 नवम्बर 2008) क्योंकि कार्य का मूल्य ₹ 47.53 करोड़ था। का.अ. ने एस.बी.डी. के अंतर्गत एकरारनामा के कार्यान्वयन के लिए विशेष सचिव, बी.सी.डी. से अनुमति मांगा (25 नवम्बर 2008)। विभाग ने अनुमोदित मूल्य लागत ₹ 47.53 करोड़, जो पहले ही 8.5 *प्रतिशत्* प्रीमियम में था, पर ठेकेदार के साथ एस.बी.डी. एकरारनामा के कार्यान्वयन की सहमति प्रदान की (12 दिसम्बर 2008)। का.अ., ठेकेदार के साथ एस.बी.डी. करार कार्यान्वित किया (दिसम्बर 2008) और ₹ 5.85 करोड़ की राशि का मार्च 2012 तक का मूल्य समायोजन और एस.बी.डी. के नियम और शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को ₹ 7.13 करोड़ का मोबिलाईजेशन/संयंत्र अग्रिम का भुगतान (मार्च 2012) किया।

चुँकि एस.बी.डी. एकरारनामा मूल्य समायोजन और मोबिलाईजेशन अग्रिम के भुगतान को आकर्षित करता है, यह दिसम्बर 2007 के एन.आई.टी. के शर्तों के विरूद्ध था, निविदा मूल्य पर एस.बी.डी. एकरारनामा को कार्यान्वित किया जाना, जो एन.आई.टी. के शर्तों के आधार पर निर्णय लिया गया था, तर्क संगत नही था। नई निविदा आमंत्रित किये बिना उसी ठेकेदार को कार्य दिया जाना समान अवसर के अधिकार को सुनिश्चित करने वाली वित्त विभाग के अनुदेश (सितम्बर 2005) का भी उल्लंघन था।

[6] श्री राम कृपाल सिह कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लि., राँची।

इस प्रकार, विभाग रूप से ₹ 47.53 करोड़ के कार्य के लिए मूल ठेकेदार के साथ एस.बी.डी. एकरारनामा के कार्यान्वयन की अनाधिकृत अनुमति प्रदान की, जिसमें मूल्य समायोजन और मोबिलाईजेशन/संयंत्र अग्रिम के भुगतान का भी प्रावधान था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2012)। विभाग ने कहा (अगस्त 2012) कि कार्यालय के स्थानांतरण, अतिक्रमण को हटाने और पुराने समाहरणालय भवन को विध्वंस करने में विलंब के कारण स्थल उपलब्ध नही था। इसके परिणामस्वरूप एफ-2 करार के स्थान पर एस.बी.डी. एकरारनामा पर हस्ताक्षर किया गया। उत्तर तर्कपूर्ण नही था क्योंकि एन.आई.टी. के मूल नियम एवं शर्तों, जिस पर निविदा निर्णय की गई थी, उसे परिवर्तित करना अनुमान्य नही था और नई निविदा आमंत्रित किये बिना एस.बी.डी. एकरारनामा के अंतर्गत कार्य दिया जाना अन्य निविदादाताओं के लिए समान अवसर के अधिकार को खंडित किया।

ग्रामीण कार्य एंव ग्रामीण विकास विभाग

5.1.3 अग्रिमों का वसूली न होना

अस्थाई-अग्रिम प्रदान करने एवं उनके समायोजन में संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरुप ₹ 48.34 लाख के सरकारी धन की वसूली न होना।

झारखण्ड लोक निर्माण लेखा संहिता के नियम 100 में यह प्रावधान है कि जब एक संवितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को मस्टर रौल या दूसरे प्रमाणकों पर छोटी-मोटी भुगतान हेतु राशि देता है तो इसे अस्थायी अग्रिम माना जाना चाहिए और प्रपत्र-2 (शिडियूल XLV-प्रपत्र सं. 113) में लेखापीत होना चाहिए। जितना जल्द संभव हो, कार्यपालक अभियंता द्वारा अग्रिमों की वसूली अथवा समायोजन के पश्चात अग्रिमों के लेखा को बंद कर देना चाहिए। सरकार के आदेशानुसार[7] (दिसम्बर 1983) इस तरह के अस्थायी अग्रिम का लेखा अग्रिम प्राप्ति की तिथि से एक माह के अंदर समर्पित कर दिया जाना चाहिए एवं अगला अग्रिम, कार्य की प्रगति के मूल्याकंन एवं पिछले अग्रिमों के समायोजन के उपरांत ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) ग्रामीण कार्य विभाग, गढवा के रोकड़-बही एवं बकाया अग्रिमों के विवरण की संवीक्षा (नवम्बर-2011) से उद्घटित हुआ कि

[7] तकनीकी निगरानी प्रकोष्ठ, कैबिनेट (निगरानी) विभाग के पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 1983

चार सहायक अभियंताओं को विभिन्न योजनाओं[8] के क्रियान्वयन तथा कार्यभारित भुगतान हेतु ₹ 56.46 लाख (फरवरी 2007 एवं मार्च 2011 के बीच) दिया गया जो बकाया रहा ***(परिशिष्ट-5.1)***। भुगतानों की जाँच में यह पाया गया कि प्रत्येक सहायक अभियंताओं को अग्रिमों का भुगतान, 2 से 29 बार किया गया जो कि 8 से 57 महीनों तक, असमायोजित रहा (नवम्बर 2011)। इन अग्रिमों का भुगतान पिछले भुगतानों के समायोजन के बिना किया गया जो कि संहिता के नियमों के विरूद्ध था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, गढवा ने बताया (12मार्च 2013) कि ₹ 56.46 लाख के अग्रिम के विरूद्व ₹ 39.30 लाख की वसूली (मई 2012 एवं नवम्बर 2012 के बीच) कर ली गई थी तथा शेष ₹ 17.16 लाख की राशि फरवरी 2013 तक असमायोजित वसूलनीय रहा।

इसी प्रकार, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला में यह देखा गया कि 10 कनीय अभियंताओं को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ₹ 37.10 लाख (जनवरी 2004 एवं फरवरी 2010 के बीच) का अग्रिम दिया गया जो कि 2 से 76 महीनों ***(परिशिष्ट-5.2)*** तक असमायोजित रहा (अप्रैल 2010)। इन अग्रिमों के भुगतान में यह पाया गया कि संहिता के नियंमों का उल्लंघन करते हुए 2 से 54 बार प्रत्येक कनीय अभियंताओं को अग्रिमों का भुगतान किया गया।

जब हमने यह इंगित किया तो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल,गुमला ने बताया (12 मार्च 2013) कि ₹ 5.92 लाख की राशि समायोजित किया गया तथा ₹ 31.18 लाख की राशि फरवरी 2013 तक असमायोजित/वसूलनीय रही।

आगे यह भी देखा गया कि चार वैसे कर्मचारियों[9] के विरूद्व ₹ 4.44 लाख (क्रम सं.1 और 4, ***परिशिष्ट-5.1*** तथा क्रम सं.8 और 9, ***परिशिष्ट-5.2***) का अग्रिम लंबित था जो कि या तो सेवानिवृत हो गए थे या अन्य मंडल कार्यालयों में स्थानान्तरित हो चुके थे जबकि ₹ 14.75 लाख का अग्रिम,

---

[8] जिला योजना, स्वास्थ्य, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा), विधायक (एम.एल.ए.) कोष, संसद (एम.पी.) कोष, मुख्यमंत्री विकास योजना (एम.एम.भी.वाई.), राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना (एन.एफ.एफ.डब्लू.पी.), सुनिश्चित स्वर्ण जयंती एवं सम विकास योजना (एस.एस.जे.एस.वी.वाई.)

[9] ग्रामीण कार्य विभाग, गढवा के दो कर्मचारियों (₹ 2.41 लाख) और ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला के दो कर्मचारियों (₹ 2.03 लाख)

ग्रामीण कार्य विभाग, गढवा (क्रम सं.-2) के वैसे कर्मचारी के विरूद्ध था जिनकी मृत्यु अगस्त 2010 में हो गयी थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2012)। उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2013)।

इस प्रकार कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अग्रिमों के दिये जाने एवं उनके समायोजन के संदर्भ में संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के कारण फरवरी 2013 तक ₹ 48.34 लाख असमायोजित/वसूलनीय रहा।

वित्त विभाग

5.1.4 मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता का अग्राह्य भुगतान

हकदार सीमा से अधिक मकान किराया भत्ता की स्वीकृति के कारण ₹ 23.18 लाख परिवहन भत्ता के साथ कुल ₹ 70.87 लाख रूपये का अग्राह्य भुगतान

बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) अधिनियम 1980 के नियम 4(बी) (II) जो कि झारखण्ड में लागू है, में उल्लेख है कि योग्य शहरों के लिए ग्राहय मकान किराया भत्ता निम्नलिखित शर्तो की संतुष्टि के पश्चात प्रशासनिक विभाग अपने सेवारत कर्मचारियों को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है।

1) योग्य शहर के नगरपालिका परिसीमा एवं कार्य स्थल के बीच की दूरी 8 कि.मी. से अधिक न हो और

2) कार्यस्थल के निकट मकान उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारी को आवश्यकता बस योग्य शहर में रहना पड़ता हो।

आगे नियम 4 (बी) (II) के नोट-2 के अनुसार यह नियम उन स्थापनाओं पर लागू नहीं होगा जो इस नियम के अन्य प्रावधान के अन्तर्गत किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के तहत, मकान किराया भत्ता, परियोजना भत्ता, दूरदराज इलाके का भत्ता, पहाडी क्षेत्रों के भत्ता के हकदार हैं।

वित्त विभाग वेतन पुनरीक्षण (फरवरी 1999) के दौरान अवर्गीकृत नगर/शहर के लिए मकान किराया भत्ता जो कि मूल वेतन के 5 *प्रतिशत्* की दर से 1 फरवरी 1999 से प्रभावी था, का निर्धारण किया गया। यह दर 1 सितंबर 2008 के प्रभाव से मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन का 10 *प्रतिशत्* की दर से बढाया गया था (फरवरी 2009)। इस प्रकार अवर्गीकृत नगरों/शहरों के लिए

निश्चित मकान किराया भत्ता के लागू हो जाने पर उस क्षेत्र के कर्मचारी नियम 4(बी) (II) के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ के हकदार नहीं थे।

पाँच कार्यालयों[10] जो कि राँची नगर निगम क्षेत्र से आठ कि.मी. की परिधि के अन्दर थे के कर्मचारियों के वेतन अभीश्रवों (मार्च 2007 एवं मई 2011 के बीच) के जाँच (अप्रैल 2011 एवं जूलाई 2012 के बीच) से यह उदघटित हुआ कि इन कार्यालयों के 192 कर्मचारियों को नियम 4(बी) (II) के प्रावधान के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता के रूप में ₹ 1.31 करोड का भुगतान, राँची की दर (15 *प्रतिशत्* और 20 *प्रतिशत्*) से किया गया था। वित्त विभाग के फरवरी 1999 एवं फरवरी 2009 के आदेशानुसार इन कार्यालयों के कर्मचारी मकान किराया भत्ता के लिए फरवरी 1999 से अगस्त 2008 के बीच 5 *प्रतिशत* की दर से एवं सितंबर 2008 से मई 2011 के बीच 10 *प्रतिशत्* की दर से ₹ 60.66 लाख के हकदार थे। जब कि इन 192 कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता के रूप में ₹ 131.47 लाख का भुगतान किया गया फलस्वरुप ₹ 70.87 लाख मकान किराया भत्ता का अग्राह्य भुगतान हुआ (मार्च 2007 से मई 2011 के बीच) (***परिशिष्ट 5.3)***। आगे वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 दिनांक 28 फरवरी 2009 के अनुसार परिवहन भत्ता सिर्फ राँची, जमशेदपुर और धनबाद नगर निगम की अधिसूचित क्षेत्र के अन्दर पदस्थापित कर्मचारियों के लिए ग्राह्य था।

जाँच से यह उदघटित हुआ कि इन कार्यालयो के 177 कर्मचारियों को परिवहन भत्ता (मार्च 2009 से मई 2011) के रूप में ₹ 23.18 लाख का भुगतान किया गया जो कि अग्राह्य था एवं वित्त विभाग के संकल्प के विरूद्ध था (***परिशिष्ट 5.4***)। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित (सितम्बर 2012) करने पर सरकार ने 2 फरवरी 2013 को एक स्पष्टीकरण संबंधित प्राधिकारियों को अग्रसारित किया जिसमें यह उल्लेखित था कि वैसे स्थापनाओं जो कि वर्गीकृत शहरों के सीमा की परिधि से 8 कि.मी. के भीतर अवस्थित है को अवर्गीकृत शहरों की दर से मकान किराया भत्ता भुगतेय होगा। सरकार ने मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता के अधिक भुगतान के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जबकि सरकार का स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के अनुरूप था।

[10] अंचल अधिकारी (सी.ओ.) नामकोम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नामकोम, प्राईमरी हेल्थ सेंटर (पी.एच.सी.) नामकोम, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) रातु और सी.डी.पी.ओ. नामकोम, राँची

5.2 औचित्य लेखापरीक्षा/औचित्य विरूद्ध व्यय

लोक निधि से होने वाले व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धांत से मार्गदर्शीत किया जाना है। प्राधिकारियों, जिनमें व्यय करने की शक्ति निहित है से आशा की जाती है कि व्यय करते समय वे वैसा ही सतर्कता बरतें जैसा कि सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति स्वयं के पैसे को खर्च करते समय बरतता है तथा उन्हें प्रत्येक कदम पर वित्तीय आदेश व सशक्त मितव्ययिता को लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अनौचित्य एवं अतिरिक्त व्यय के उदाहरणों का पता किया जिसमें से कुछ का वर्णन यहाँ नीचे किया जा रहा है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

5.2.1 ठेकेदार को अदेय भुगतान

संविदा के नियम एवं शर्तों में सरकार के निर्देशों को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 6.77 करोड़ की राशि का अदेय भुगतान द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया।

कैबिनेट, झारखण्ड सरकार (झा.स.), द्वारा अनुमोदन के आधार पर पथ निर्माण विभाग द्वारा एक संकल्प निर्गत (26 मार्च 2002) किया गया कि ₹ 10 लाख एवं अधिक के मूल्य वाले कार्य के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी सामग्री ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जाएगी न कि विभाग द्वारा। यह भी निर्णय लिया गया कि निविदित परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) 'अनुमोदित प्रतिशता दर' अर्थात् प्रीमियम दर, कार्य में आपूर्तित एवं उपयोग की गई सामग्री जैसे अलकतरा, सिमेंट, स्टील, छड़, पाईप और अन्य निर्माण सामग्री की लागत ठेकेदार का परिवहन और लाभ सहित पर ठेकेदार को भुगतेय नहीं होगा। आगे, दर अनुसूचि (एस.ओ.आर.), निर्धारण समिति द्वारा तैयार की गयी (2006-07) जिसमें सामग्री की लागत सहित प्रत्येक मदों के लिए ठेकेदार का लाभ 10 *प्रतिशत्* सम्मिलित था। संकल्प के अनुसार (मार्च 2002), सामग्री पर प्रीमियम दर का भुगतान नही किया जाना राज्य में सभी कार्य विभागों में लागू था।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सं. 1, धनबाद के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2010) से उद्घटित हुआ कि ई.ई. ने

धनबाद फेज-II जलापूर्ति योजना के पुनरूद्धार एवं संवर्धन[11] के लिए एक ठेकेदार (मेसर्स नागार्जुना कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुड़गाँव) के साथ ₹ 68.67 करोड़ का एकरारनामा कार्यान्वित किया (दिसम्बर 2007)। सरकार के मार्च 2002 के संकल्प के विरूद्ध पाईप, अलकतरा, स्टील, सिमेंट इत्यादि सहित सभी मदों पर बी.ओ.क्यू. से 15 *प्रतिशत्* अधिक पर करार कार्यान्वित किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्य मे उपयोग किए गये डक्टाईल आयरन (डी.आई.) पाईप की लागत पर ₹ 4.44 करोड़ (***परिशिष्ट 5.5** और **5.6***) के प्रीमीयम दर का अदेय भुगतान किया गया।

तदनन्तर, करार में डी.आई. पाईपों को ढोने के लिए 300 कि.मी. की दूरी का प्रावधान किया गया। जबकि, बीजकों की संवीक्षा मे पाया गया कि आपूर्तिकर्त्ता से जिस दर पर ठेकेदार ने डी. आई. पाईपों (के.-7 और के.-9) का क्रय किया उसमें सभी प्रकार के कर तथा धनबाद रेलवे स्टेशन तक का परिवहन लागत सम्मिलित था। इस प्रकार, विभाग द्वारा करार में कलकत्ता से स्थल तक का भाड़ा लागत अर्थात् 300 कि.मी. का भाड़ा वास्तव में आधिक्य भाड़ा का प्रावधान था जिसके परिणामस्वरूप डी.आई. पाईपों (के.-7 और के.-9) के भाड़ा लागत के लिए ठेकेदार को ₹ 2.33 करोड़ का भुगतान न्यायसंगत नही था (***परिशिष्ट 5.7** और **5.8***)।

इस प्रकार, सरकारी निर्देशों के अवहेलना किये जाने और विभाग द्वारा डी.आई. पाईपों के आपूर्ति के लिए अधिक दर की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 6.77 करोड़ का अदेय भुगतान और अन्यायसंगत व्यय किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2012)। विभाग ने कहा (अगस्त 2012) कि "पथ निर्माण विभाग (आर.सी.डी.) द्वारा सामग्री पर प्रीमीयम दर का भुगतान नही किये जाने का निर्गत आदेश (मार्च 2002), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डी.डब्ल्यू. एण्ड एस.डी.) के लिए लागू नही था।"

विभाग का उत्तर तर्क संगत नही था क्योंकि उपरोक्त संकल्प (मार्च 2002) डी.डब्ल्यू. एण्ड एस.डी. सहित सभी कार्य विभागों के लिए लागू था और इसकी प्रतिलिपि डी.डब्ल्यू. एण्ड एस.डी. सहित संबंधित विभागों को परिचालित किया गया था। विभाग द्वारा भाड़ा लागत के अधिक भुगतान पर कोई जवाब नहीं दिया गया।

---

[11] विस्तृत सर्वेक्षण, लेवेलींग, सभी संबंधित मदों के डिजायन और ड्राइंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, राइजिंग मेन डी.आई.के.-7 और वितरण मेन डी.आई.के.-9 पाईप इत्यादि सहित धनबाद फेज –II जलापूर्ति योजना के पुनरूद्धार और संवर्धन।

जल संसाधन विभाग

5.2.2 *ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ*

भैरवा और केसो जलाशय योजनाओं के बचे हुए कार्यों के संरचना और आलेख हेतु भुगतान में उच्चतर अधिकारी के आदेशों तथा अनुबंध के प्रावधानों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.08 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया।

हजारीबाग और बरही में 9073 हेक्टेयर (भैरवा: 4,858 हेक्टेयर तथा केसो: 4,215 हेक्टेयर) की सिंचाई क्षमता के निर्माण हेतु दो मध्यम सिंचाई परियोजनायें, भैरवा तथा केसो जलाशय योजनायें क्रमश: वर्ष 1987-88 और 1990-91 के दौरान प्रारंभ की गई। इन परियोजनाओं के घटकों (डैम, स्पीलवे, नहर आदि) के संरचना और आलेख मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा अगस्त 1986 और मार्च 1991 के मध्य स्वीकृत किए गए थे। बिहार सरकार द्वारा निधि मुक्त नहीं किये जाने के कारण इन परियोजनाओं के कार्य, रोक दिए गए 1991-92 (केसो) और 1993-94 (भैरवा)।

झारखण्ड राज्य के निर्माण के बाद, इन परियोजनाओं के बचे हुए कार्य टर्नकी आधार पर ₹ 122.67 करोड (भैरवा: ₹ 55.73 करोड़ और केसो: ₹ 66.94 करोड़) के मूल्य पर लिए गए (भैरवा: जुलाई 2005 एवं केसो: मार्च 2007) जिसे अनुबंध की तिथि[12] के 30 माह के अन्दर पुरा किया जाना था। अनुबंधों के अनुसार, कार्य को 1986/1991 के अनुमोदित संरचना और आलेखों के अनुसार किया जाना था क्योंकि ये कार्य, बचे हुए किस्म के थे। लेकिन, इन अनुबंधो के साथ भुगतान अनुसूचि में अलेख एवं सरंचना का ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाना एवं विभाग द्वारा उनका अनुमोदन भी एक मद था, जो अनियमित था।

अभिलेखों की संवीक्षा (मई एवं जून 2011) से पता चला कि ठेकेदारों ने स्वयं की आलेख और संरचना प्रस्तुत की और कार्यपालक अभियंताओं ने इन सरंचनाओं और अभिलेखों को प्रस्तुत करने एवं उनके अनुमोदन हेतु ठेकेदारों को ₹ 1.08 करोड़[13] का भुगतान (मई 2008 और अक्टूबर 2009) किया। यह अनुबंध की धाराओं के खिलाफ था। केसों परियोजना के संबंध में देखा गया कि अधीक्षण अभियंता (एस.ई.) जल संसाधन अंचल, हजारीबाग ने कार्यपालक

---

[12] भैरवा: 1F2/2005-06 कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग हजारीबाग द्वारा 2 जुलाई 2005 को किया गया और केसो: 15F2/2006-07 कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग बरही द्वारा 23 मार्च 2007 में किया गया।

[13] भैरवा: ₹ 57.95 लाख, मई 2008 तक और केसो: ₹ 49.58 लाख अक्टूबर 2009 तक

अभियंता, जल संसाधन प्रमण्डल बरही को निर्देश दिया (जनवरी 2008) कि पूर्व में अनुमोदित (1986-91) नक्शों पर कार्य के लिए अनुबंध हुआ था और अनुमोदित नक्शों तथा आलेखों में कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्य अभियंता (मु.अ.) जल संसाधन विभाग अधीक्षण अभियंता, हजारीबाग को निर्देश दिया (मार्च 2008) कि ठेकेदार से लिखित सहमति लिया जाए कि कार्य पूर्व में स्वीकृत आलेख और संरचना के अनुसार हो रहा था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह ज्ञात हो कि अधीक्षण अभियंता ने ठेकेदार से कोई उस आशय का पत्र लिया। अत: कार्यपालक अभियंताओं द्वारा आलेख और सरंचना मद में ₹ 1.08 करोड़ का राशि की भुगतान उच्च अभियंताओं के आदेशों के विरूद्ध था तथा इससे ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस बिंदु के उठाए जाने पर (मई 2011 और जून 2011) सरकार ने बनाया (सितम्बर 2012) कि केसो और भैरवा परियोजनाओं के संबंध में, भुगतान सूची जो अनुबंध के साथ संलग्न थी, विभिन्न अवयवों के मुल्य का एक *प्रतिशत्* का प्राकलन, आलेख और संरचना के निर्माण तथा अनुमति के लिए था (जुलाई 2005 एवं मार्च 2007)।

जवाब स्वीकार्य नही था क्योंकि संरचनाओं और आलेखों के लिए किए गए भुगतान अनुबंधों जिसमें यह उल्लेखित था कि कार्य को पूर्व में अनुमोदित आलेख और संरचना के अनुसार किया जाना था, के खिलाफ थे। आगे, अधीक्षण अभियंता, हजारीबाग ने कार्यपालक अभियंताओं को मूल आलेखों और संरचनाओं को ही लागू करने का निर्देश दिया था।

पथ निर्माण विभाग

5.2.3 बिना पहुँच पथ के पुल के निर्माण पर निष्फल व्यय

पहुँच पथ के लिए भूमि अधिग्रहण किए बिना कार्य प्रारंभ करने के कारण उच्च स्तरीय पुल के निर्माण पर ₹ 1.02 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत, के नियम 132 के अनुसार दरार की मरम्मत आदि आवश्यक निर्माण कार्य के सिवाय कोई भी निर्माण, ऐसी जमीन पर आरंभ न किया जाय जो जिम्मेदार असैनिक पदाधिकारी द्वारा यथावत सौंप न दी गई हो। पुन: बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के विधान[14] के अनुसार निविदा प्रारंभ की जानी चाहिए

[14] कैबिनेट सचिव और समन्वय विभाग (सतर्कता प्रकोष्ठ) के ज्ञापन सं. 948 दिनांक 16 जुलाई 1986 का कंडिका संख्या 4.5 तथा 7.5 बिहार लोक निर्माण विभाग सहिता में समाहित।

जब तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई हो, निधि का आवंटन सुनिश्चित कर लिया गया हो एवं भूमि का अर्जन यदि आवश्यक हो, कर लिया गया हो।

चौड़े पुल के साथ अच्छा पथ संचरण सुविधा प्रदान करने के लिए हजारीबाग-बरकागांव-टंडवा पथ पर 29वाँ कि.मी. में चमगधा नदी नाला पर अवस्थित पुराना संकीर्ण और सेवा के लिए अयोग्य पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल और पहुँच पथ का निर्माण आवश्यक था। पथ निर्माण विभाग द्वारा उच्च स्तरीय पुल और पहुँच पथ के निर्माण के लिए ₹ 1.26 करोड़ के लिए प्राशासनीक अनुमोदन (अगस्त 2007) प्रदान किया गया और मुख्य अभियंता, केन्द्रीय आलेखन संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची द्वारा ₹ 1.27 करोड़ के लिए तकनीकी स्वीकृति (जुलाई 2007) प्रदान की गई। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा ₹ 1.26 करोड़ के लिए ठेकेदार को कार्य प्रदान (नवम्बर 2007) किया गया और जनवरी 2008 में एकरारनामा कार्यन्वित किया गया। कार्य के एक वर्ष की अवधि में पूर्ण करना था अर्थात जनवरी 2009 तक।

कार्यपालक अभियंता के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी-2012) में पाया गया कि प्रस्तावित भूमि का अर्जन नहीं होने के कारण ठेकेदार ने पुल फर्नीचर[15] और पहुँच पथ को छोड़कर उच्च स्तरीय पुल का कार्य अप्रैल 2010 में पूर्ण कर लिया। ठेकेदार ने पहुँच पथ के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता को बार-बार अनुरोध[16] किया। अंततः ठेकेदार ने केवल पुल का कार्य समाप्त करने के बाद बीच में ही कार्य रोक (मई 2010) दिया, इसके एवज में अगस्त 2010 तक उसे ₹ 98.80 लाख का भुगतान किया गया।

पुनः विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों एवं सूचनाओं (जून-अक्टूबर 2010) की जाँच में पाया गया कि भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता को दिसम्बर-2011 में भू-स्वामित्व की लिखित सूचना दी गई थी, लेकिन लोक अवरोध के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया क्योंकि दो भू-स्वामियों ने क्षतिपूर्ति की राशि, निम्न दर पर मूल्यांकन के तर्क पर, स्वीकार करने से इनकार कर दिया (मई 2012)। मामले का समाधान भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा सका और भूमि के अभाव में अक्टूबर 2012 तक पहुँच पथ का निर्माण नहीं किया जा सका।

---

[15] डिवाइडर, परावर्तक, फर्श निर्देश, साइन बोर्ड आदि।

[16] ठेकेदार का पत्रांक शून्य, दिनांक-4 अप्रैल 2010, 24 मई 2010, 13 जनवरी 2011, 16 जुलाई 2011, 28 नवम्बर 2011, 21 जनवरी 2012 और 8 मई 2012।

पुल के निर्माण पर कुल ₹ 1.02 करोड़[17] का व्यय (जून 2012) किया गया जिसे पहुँच पथ के आभाव में उपयोग में नहीं लाया जा सका। इस प्रकार भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य की प्रक्रिया/निविदा और मुख्य अभियंता, केन्द्रीय आलेखन संगठन द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

विभाग द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2012) कि व्यय निष्फल नहीं था क्योंकि पैदल और साइकिल सवारों द्वारा पुल का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संकीर्ण और सेवा के अयोग्य पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण वाहनों को आसानी से चलने के प्रयोजन से बनाया गया था जो नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त पथ उपयोगकर्त्ताओं को पूरे वर्ष अच्छी पथ संचरण सुविधा प्राप्त कराने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

ग्रामीण कार्य विभाग एवं झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

5.2.4 निष्फल व्यय एवं परिनिर्धारित क्षति की वसूली न होना

कार्यपालक अभियंता द्वारा समय पर कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण ₹ 1.34 करोड का निष्फल व्यय के अलावे ₹ 25.50 लाख की परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं हुई।

इंडियन रोड कॉंग्रेस के मानक विनिर्देश की कंडिका 4.8.2 तथा डब्लू.बी.एम. के लिए व्यवहार के नियम के अनुसार बेस कोर्स के लिए कोलतार वाली सतह उपलब्ध करना है। यातायात शुरू करने के पहले कोलतार वाले सतह तभी बिछाना है जब डब्लू.बी.एम. कोर्स पुरी तरह सुख गया हो।

पुनः एस.बी.डी. के कंडिका 21 (बी) (सी) के साथ 44 और 52 के अनुसार यदि संवेदक निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है तो संवेदक से परिनिर्धारित क्षति के रुप में प्रारंभिक संविदा मूल्य[18] के एक *प्रतिशत्* की दर से जिसमें कि सम्पूर्ण कार्य का साप्ताहिक अभिरक्षण लागत शामिल हो से अधिकतम 10 *प्रतिशत्* निकटतम हजार रुपये के रुप में वसूली की जानी थी। पुनः जनवरी 1991 में जारी निर्देशो[19] के अनुसार संवेदक द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी की विशुद्धता का सत्यापन कार्यपालक अभियंता के द्वारा यथाशीघ्र बैंक से करा ली जानी चाहिए।

---

[17] ठेकेदार का भुगतान -₹ 98.80 लाख+आकस्मिकता, ₹ 0.42 लाख+ भूमि उपार्जन, ₹ 2. 89 लाख

[18] संविदा मूल्य (₹ 3.49 करोड) अभिरक्षण लागत सहित

[19] जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा जारी पत्रांक 34/90-2 दिनांक 15 जनवरी 1991

मुख्य अभियंता झारखण्ड राज्य ग्रामीण सडक प्राधिकरण द्वारा (दिसम्बर 2007) प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना (पैकेज न. जे.एच.-0202) के तहत चतरा जिले में कोलकोले खुर्द से बनवार तक 10 कि.मी. कोलतार वाली सडक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति ₹ 3.49 करोड के लागत पर प्रदान की गई।

यह कार्य निविदा अप्रैल 2008 में मेसर्स लवली ट्रांसपोर्ट राँची को ₹ 3.48 करोड की लागत पर आवंटित किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग चतरा एवं संवेदक के बीच एकरारनामा पर हस्ताक्षर किया गया (मई 2008)। इस कार्य को मई 2009 तक पूरा कर लिया जाना नियत था।

विभागों के अभिलेखों के संविदा से उद्घटित हुआ (जून 2011) कि संवेदक निर्धारित समयावधि में कार्य संपन्न करने में असफल रहा। यद्यपि समयावधि विस्तार नही दी गई थी फिर भी संवेदक द्वारा नियत अवधि के समाप्त हो जाने के 29 सप्ताह पश्चात भी कार्य किया जाता रहा एवं उसे ₹ 10.31 लाख एवं ₹ 15.49 लाख का भुगतान क्रमशः दिसम्बर 2009 तथा जनवरी 2010 में पूर्णता की नियत अवधि के बाद किया गया। बाद में, बिना कोई कारण बताए संवेदक ने कार्य को डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड[20] II एवं III जिसका मूल्य ₹ 1.34 करोड है, करने के पश्चात बीच में ही छोड़ दिया (जनवरी 2010)। कार्यपालक अभियंता द्वारा जून 2010 में एकरारनामा को अपखंडित कर दिया गया। पुनः संविदा में किसी भी संवेदक द्वारा भाग नहीं लेने के कारण बचा कार्य (₹ 2.14 करोड) फरवरी 2013 तक पुनरारंभ नहीं हो सका। डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड II एवं III के पूरा होने के पश्चात पुरी लम्बाई में कोलतार बिछाने का कार्य नहीं हुआ जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत इसे सभी मौसमों में उपयोग हेतु बनाना था। डब्ल्यू.बी.एम. कार्य पूरा होने के 3 साल से अधिक समय बीत जाने के कारण इसकी गुणवत्ता का ह्रास हुआ इस प्रकार कार्य बीच में रुक जाने के कारण ₹ 1.34 करोड का व्यय निष्फल हुआ।

पुनः संविदा के शर्तों के अनुसार नियत तिथि के अन्दर कार्य पूरा न होने पर कार्यपालक अभियंता संवेदक से परिनिर्धारित क्षति की पूरी राशि वसूल करने में असफल रहे। हमने पाया कि कार्य पालक अभियंता ने अनियमित रुप से परिनिर्धारित क्षति मद में ₹ 2.58 लाख[21] की कटौती की तथा ₹ 6.72 लाख

---

[20] ये सभी डब्ल्यू.बी.एम. के अंग है जिसमें उपयोग हुए पत्थर का आकार ग्रेड- II एवं ग्रेड- III के लिए क्रमशः 45 मि.मि.से 63 मि.मि.और 22.40 मि.मि से 53 मि.मि.है।

[21] 7वें एवं 8वें चालू खाता बिल से ₹ 1.03 लाख और ₹ 1.55 लाख (प्रारंभिक संविदा मूल्य का नहीं बल्कि बिल मूल्य का 10 *प्रतिशत*)।

की सुरक्षित जमा को जब्त कर लिया जबकि प्रारंभिक संविदा मूल्य जिसमें कि पूरे कार्य का अभिरक्षण शुल्क सम्मिलित था का अधिकतम 10 *प्रतिशत्* की दर से ₹ 34.80 लाख[22] वसूला जाना था क्योंकि कार्य में विलंब की अवधि 10 हफ्ते से अधिक की थी। प्रारंभिक संविदा मूल्य के बदले संवेदक द्वारा जमा किए गए विपत्रों के आधार पर परिनिर्धारित क्षति की गलत गणना किये जाने के कारण परिनिर्धारित क्षति की राशि कम वसूली गई। फलस्वरुप परिनिर्धारित क्षति की राशि की वसूली ₹ 25.50 लाख कम हुई।

पुन: यह पाया गया कि कार्यपालक अभियंता द्वारा सुरक्षित जमा के रुप में बैंक गारंटी को समय रहते जब्त कर नकद करने के बदले, एक नया बैंक गारंटी ₹ 17.50 लाख (फरवरी 2010) को व्ययगत बैंक गारंटी के बदले स्वीकार कर लिया गया। जनवरी 1991 के आदेश की अवहेलना कर कार्यपालक अभियंता द्वारा बैंक गारंटी की सत्यता की जाँच नहीं की गई। कार्यपालक अभियंता ने तीन माह बीत जाने के पश्चात, बैंक से बैंक गारंटी के सत्यापन का अनुरोध किया (मई 2010)। बैंक ने मई 2010 में सूचित किया कि बैंक गारंटी उस बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया था। जिस कारण विभाग द्वारा ₹ 17.50 लाख की बैंक गारंटी का नगदीकरण नहीं किया जा सका। कार्यपालक अभियंता द्वारा समय रहते बैंक गारंटी के नवीनीकरण करवा पाने में असफल रहने के कारण विभाग ₹ 17.50 लाख से वंचित हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2012) किया गया था। साथ ही जुलाई और अगस्त 2012 में स्मारित किया गया था। उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2013)।

इस प्रकार कार्यपालक अभियंता द्वारा समय रहते एकरारनामा की शर्तो के अनुसार संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने में असफल रहने के कारण अधूरी सड़क पर ₹ 1.34 करोड़ का व्यय निष्फल रहा जिससे ग्रामीण क्षेत्र के वासी वांछित लाभ से वंचित रहे। इसके अलावा परिनिर्धारित क्षति की राशि ₹ 25.50 लाख की वसूली नहीं हो पाई।

---

[22] कार्य पूरा करने का नियत समय मई 2009 था। अंतिम मापी तक (8वें चालू खाता बिल) कार्य पूरा नहीं हुआ था अर्थात-10 जनवरी 2010। कुल 29 सप्ताह x ₹ 3.48 करोड संविदा मुल्य का 1 *प्रतिशत* = ₹ 1.00 करोड, अधिकतम संविदा मूल्य का 10 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 34.80 लाख-₹ 2.85 लाख पूर्व ही काट ली गई परिनिर्धारित क्षति और पूर्व ही जब्त कर ली गई सुरक्षित जमा राशि ₹ 6.72 लाख=₹ 25.50 लाख।

5.3 दृष्टिचूक/शासन की विफलता

सरकार को लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का दायित्व है जिसके लिए यह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और बुनियादी संरचना के उन्नयन और जनसेवा आदि के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के तहत् कार्य करती है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में उदाहरण पाये गये, जहाँ सरकार द्वारा समुदायिक लाभ हेतु लोक संपदा की सृष्टि हेतु विमुक्त की गयी निधि विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में असमर्थता एवं योजनाबद्ध तरीके का आभाव, प्रशासनिक दृष्टिचूक का अभाव, के कारण अनुपयोगित/अवरोधित और/या निष्फलसिद्ध/अउत्पादक रही। कुछ वैसे मामलों को नीचे विमर्शित किया गया है:

पथ निर्माण विभाग

5.3.1 सरकारी राशि का अवरोध

लागत हिस्सेदारी के आधार पर प्रस्तावित पार पथ के प्राक्कलन के अनुमान्यता/ स्वीकार्यता के बिना संहिता प्रावधानों/सरकारी आदेश के विरोध में दक्षिण पूर्वी रेलवे को अग्रिम दिया गया, फलस्वरूप सरकारी राशि ₹ 7.37 करोड़ का अवरोध हुआ तथा ₹ 2.30 करोड़ के सूद की हानि हुई।

बिहार लोक कार्य लेखा संहिता (बी.पी.डब्ल्यू.ए.) जिसे झारखण्ड ने अंगीकृत किया है, में बतायी गई सरकारी निर्णय[23] के पारा 7.2 के अनुसार प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य नहीं लिया जाना है। आगे सरकार द्वारा निर्गत निधि आबंटन पत्र (फरवरी 2008)के पारा 11 के अनुसार, तकनीकी स्वीकृति की प्राप्ति के बाद खर्च किया जाना था। एक रिट याचिका[24] की सुनवाई करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय ने दक्षिण पूर्वी रेलवे को डिबडीह लेवल क्रासिंग के ऊपर Y-लेग रोड ओवरब्रिज निमार्ण का आदेश दिया (दिसम्बर 2005) जिससे की पथ के उपयोगकर्त्ता मेकन[25] कॉलोनी की तक की यात्रा कर सकें। इस कार्य को रेलवे तथा झारखण्ड सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी[26] के आधार पर किया जाना था।

---

23 निगरानी विभाग पत्रांक 948 दिनांक 16.07.1996

24 डब्लू.पी.(पी.आई.एल.) संख्या 6085/2002 का

25 मेटलर्जिकल इंजीनियरींग एण्ड कंसल्टेन्टस ऑफ इंडिया लिमिटेड

26 लागत हिस्सेदारी आधार-उपरी पथ/अन्दर पुल निर्माण कार्य रेलवे द्वारा समपार क्रासिंग के बदले में मूल्य बंटवारा आधार पर ली जाती है यदि यातायात घनत्व एक लाख या अधिक ट्रेन वेहिकल इकाई (टी.यू. भी.) हो। टी.यू.भी. एक ईकाई है जो 24 घंटे में किसी समपार क्रासिंग से गुजरनेवाली

कार्यापालक अभियंता (ई.ई.) पथ प्रमण्डल राँची के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2011) तथा प्राप्त सुचनाओं (मई 2012) से उद्घटित हुआ कि पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य के 50 *प्रतिशत्* हिस्से जो कि ₹ 7.37 करोड़ थी, ₹ 7.37 करोड़ के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी (दिसम्बर 2007)। आगे संवीक्षा से पता चला कि कार्यपालक अभियंता ने दक्षिण पूर्वी रेलवे गार्डन रीच कोलकाता के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (एफ.ए. एण्ड सी.ए.ओ.) का बिना कोई अनुबंध किए तथा बिना किसी तकनीकी स्वीकृति के ₹ 7.37 करोड़ का अग्रिम दिया (अप्रैल 2008) जो संहिता के प्रावधान तथा सरकारी आदेश के खिलाफ था।

आगे यह पाया गया कि दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा विस्तृत प्राक्कलन[27] बनाए गए तथा पथ निर्माण विभाग को दिये गए (फरवरी 2011) जिसका अनुमान्य मूल्य ₹ 22.24 करोड़ था जिसे रेलवे का भाग बढ़कर ₹ 11.22 करोड़ हुआ तथा राज्य सरकार का भी भाग ₹ 11.22 करोड़ हुआ, जिसका मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग ने अग्रिम देने के तीन साल से अधिक बीत जाने के बाद स्वीकृत किया (अप्रैल 2011) प्राक्कलन की स्वीकृति के बाद, पथ निर्माण विभाग तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे के अभियंताओं की टीम द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया (जून 2011) जिसके दौरान यह पाया गया कि मेकन की तरफ अतिरिक्त Y-लेग आर.ओ.बी. देने से एक मतभेद का बिन्दु[28] उभरेगा। अपने निरीक्षण नोट में मुख्य अभियंता (सी.ई.) पथ निर्माण विभाग ने वर्त्तमान फोर लेन आर.ओ.बी. में अतिरिक्त लेग नहीं जोडने की सलाह दी (जुलाई 2011)। लेखापरीक्षा द्वारा (अप्रैल 2012) दक्षिण पूर्वी रेलवे से की गई पूछताछ पर बताया गया (मई 2012) की आर.ओ.बी. का निर्माण नहीं किया जाएगा जैसा की मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग ने सलाह दिया था (जुलाई 2011) और यह कार्य रेलवे बजट से हटा दिया गया था। विभाग ने दक्षिण पूर्वी रेलवे से ₹ 7.37 करोड़ के अग्रिम (अप्रैल 2008) लौटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जबकि मुख्य अभियंता ने जुलाई 2011 में ही प्रस्तावित आर.ओ.बी. के नही बनाने की सलाह दी थी।

पथ गाड़ियों की संख्या को गुजरनेवाली रेलगाड़ियों की संख्या से गुणा करने से आती है। (रेलवे की पालिसी संख्या 2007/सीई I/एल एक्स/90)

27 एस्टीमेट संख्या 1478 डब्ल्यू/2010

28 मतभेद बिन्दु वह बिन्दु है जहाँ एक राजमार्ग उपयोगकर्त्ता, पार करते हुए, मिलते हुए या पथ से अलग होते हुए दुसरे राजमार्ग उपयोगकर्त्ता से उसी भाग के इस्तेमाल के क्रम में टकराता है। यह वह बिन्दु है जहाँ कोई भी सीधी जानेवाली या जुड़नेवाली गाड़ियों के पथ अलग होते हों, मिलते हों या क्रास करते हो।

सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि आर.ओ.बी. के मतभेद बिन्दु से यातायात संकीर्णता/दुर्घटना, होने की प्रबल संभावना थी, इसलिए प्रस्तावित आर.ओ.बी. के निर्माण का प्रस्ताव हटा दिया गया था। फलस्वरूप, दक्षिण पूर्वी रेलवे को सूद समेत अग्रिम वापसी का अनुरोध किया गया था (अक्टूबर 2012)। अनुवर्ती कार्रवाई प्रतिक्षित है (फरवरी 2013)।

इस प्रकार संहिता/सरकारी आदेश के प्रावधानों के उलघन कर प्राक्कलन की मंजूरी/स्वीकृति के बिना दक्षिण पूर्वी रेलवे को दी गई ₹ 7.37 करोड़ की अग्रिम राशि, जो कि प्रस्तावित आर.ओ.बी. पर खर्च होनी थी, तीन साल से अधिक समय के लिए अउपयोगित रही, जिसे अंत में निर्माण के योग्य नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के औसत उधार दर के बराबर दर पर ₹ 2.30 करोड़ के सूद[29] की हानि हुई।

5.3.2 बेली पुल के निर्माण में योजना का अभाव

आपदा की स्थिति में बेली पुल के अधिष्ठापन एवं संयोजन हेतु तैयारी एवं योजना के अभाव में विभाग ₹ 6.09 करोड़ व्यय करने के बावजूद बेली पुल के द्वारा यातायात सम्बद्धता उपलब्ध कराने में असफल रहा।

सचिव, पथ निर्माण ने आपत्तिकाल/आपदा के समय यातायात पुन: बहाल करने के लिए तीन बेली पुल[30] क्रय करने के लिए सलाहकार परिषद[31] को एक प्रस्ताव उपस्थापित किया (जून 2009)। तदनुसार पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राँची, हजारीबाग और दुमका पथ प्रमण्डल के लिए ₹ 6.89 करोड़ की लागत से तीन बेली पुल क्रय करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (जून 2009)।

पथ प्रमण्डल राँची, हजारीबाग तथा दुमका के कार्यपालक अभियंताओं के अभिलेखों (अप्रैल 2011 और अप्रैल 2012) की संवीक्षा में पाया गया कि पथ निर्माण विभाग ने मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकात्ता भारत सरकार के उपक्रम (अभिकर्त्ता) को बेली पुलों की आपूर्त्ति के लिए नामित किया (जून 2009) जिसके लिए कार्यपालक अभियंताओं ने अभिकर्त्ता को ₹ 6.09 करोड़ का भुगतान किया (जनवरी 2010 और मार्च 2011 के बीच)। अभिकर्त्ता ने इन तीन प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंताओं को मार्च और मई 2010 के बीच अवयवों की आपूर्ति की।

---

[29] ₹ 7.37 करोड़ पर 7.83 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से चार वर्षों के लिए।

[30] बेली पुल एक लघु लोहा (इस्पात) का पुल है, जिसे दो मुख्य धरन के बीच पथ सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जगह पर संयोजित किया जाता है।

[31] झारखण्ड सरकार के सलाहकारों का सम्मेलन।

हमने आगे पाया कि अभिकर्त्ता ने मूल्य एवं भुगतान शर्त्तों की जानकारी देते समय सुझाव दिया था (अक्टूबर 2009) कि पुल का निर्माण उनके सूचीबद्ध निर्माण कर्त्ताओं द्वारा कराया जा सकता था तथापि विभाग द्वारा सुझाव को अमल में नहीं लाया गया। हमने यह भी पाया कि अभियंता प्रमुख के तकनीकी सचिव पथ निर्माण विभाग ने मुख्य अभियंता (यातायात) को यान्त्रिक प्रमण्डलों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश (जून 2010) दिया ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक सप्ताह के अन्दर बेली पुल का संयोजन किया जा सके। तथापि मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख द्वारा इसका अनुसरण नहीं किया गया एवं कर्मचारी अप्रशिक्षित रहे।

पुन: अभिलखों में नहीं पाया गया कि बेली पुल की उपलब्धता की सूचना पथ-निर्माण विभाग के सभी प्रमण्डलों को दी थी ताकि आपदा के समय प्रमण्डलीय पदाधिकारियों द्वारा इस हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया जा सके।

हमने आगे यह भी पाया कि पथ प्रमण्डल, दुमका के अन्तर्गत दुमका-साहेबगंज रोड पर गुमरा पुल का एक विस्तार अगस्त 2010 में ध्वस्त हो गया। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल दुमका ने तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से सचिव, पथ निर्माण विभाग को बेली पुल के उपयोग के लिए संसूचित किया (अगस्त 2010)। तथापि बेली पुल के अधिष्ठापन के संबंध में निर्देश के अभाव में डायभर्सन का निर्माण कर यातायात पुन: स्थापित किया गया (मार्च 2011)।

देवघर पथ प्रमण्डल के अन्तर्गत जसीडीह- देवघर राज्य उच्चपथ पर धरवा नदी के ऊपर दूसरा पुल जून 2011 में ध्वस्त हो गया। अधीक्षण अभियंता, दुमका अंचल, दुमका ने यातायात व्यवस्था पुन: स्थापित करने के लिए अभियंता प्रमुख को दुमका और हजारीबाग पथ प्रमण्डलों से देवघर पथ प्रमण्डल को बेली पुल के अवयवों के स्थानांतरण हेतु आवश्यक आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया (जून 2011)। तथापि बेली पुल के स्थानांतरण के संबंध में कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया और जून- दिस्म्बर 2011 के दौरान कॉज वे बनाकर पथ सम्बद्धता कर यातायात को चालू किया गया।

जब हमने मुख्य अभियंता (यातायात) पथ निर्माण विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया (सितंबर 2012) तब उन्होंने स्वीकार किया (सितम्बर 2012) कि निर्माणकर्त्ता सूचीबद्ध नहीं किये गये थे और प्रमण्डलों के कर्मचारी बेली पुल के अवयवों के संयोजन के लिए अनुभवी नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि क्षतिग्रस्त गुमरा पुल के स्थान पर बेली पुल को स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि खंभें इतने मजबूत नहीं थे कि चलनेवाले वाहनों का भार सह सकें।

धरवा नदी पर पुल के संबंध मे मुख्य अभियंता ने कहा कि शुरूआत में बेली पुल की स्थापना पर विचार किया गया लेकिन खंभों और आधार के निर्माण जिसमे अधिक समय लगने की आवश्यकता के कारण फर्श पर रास्ता बनाकर यातायात को पुन: स्थापित किया गया। मुख्य अभियंता का उत्तर बेली पुल के आपूर्तिकर्त्ता मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बेली पुल के चित्रण/वर्णन के अनुसार नहीं था। बेली पुल का ढाँचा ऐसी थी कि इसे दरार पुल के एक किनारे बेलन पर पूर्णत: खडा किया जा सकता था और दरार में बिना किसी अस्थायी सहारा के आर-पार फेंका जा सकता था। इसके अलावे प्रमण्डलों ने दो क्षतिग्रस्त पुलों में सम्बद्धता की पु:स्थापना के लिए फर्श पर रास्ता बनाने/विपधन के निर्माण में एक से पाँच महीने का समय लिया जबकि आवश्यक परिस्थिति में यातायात व्यवस्था को पुन:स्थापित करने के लिए ₹ 6.09 करोड़ की लागत से क्रय किया गया बेली पुल जिसका संयोजन एक सप्ताह में किया जा सकता था अप्रयुक्त पडा रहा।

इस प्रकार बेली पुल की खरीद के 28 माह बाद भी विभाग द्वारा निर्माणकर्त्ता को सूचीबद्ध करने या कर्मचारियों को संयोजन हेतु प्रशिक्षित करने में असफलता के कारण पुलों के ध्वस्त होने पर बेली पुलों का उपयोंग नहीं किया जा सका। यह विपत्ति की अवस्था हेतु तैयारी की कमी तथा अकुशल योजना को दर्शाता है एवं परिणाम स्वरूप बेली पुल के क्रय पर ₹ 6.09 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी उसके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

मामला सरकार के पास भेजा गया (मई 2012)। उत्तर अप्राप्त था (फरवरी 2013)।

5.4 लगातार एवं बारंबार होने वाली अनियमिततायें

एक अनियमितता को लगातार कहा जाता है जब वह निरंतर प्रत्येक वर्ष होता है। यह बारंबार हो जाता है जब यह पूरे प्रणाली में व्याप्त हो जाता है। पूर्व के लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बावजूद अनियमितताओं का पुन: होना कार्यपालिका के पक्ष में न केवल अगंभीरता को दर्शाता है बल्कि प्रभावी अनुश्रवण की कमी को भी दर्शाता है। बदले में यह नियम/विनियम का जानबूझ कर अनदेखी करने को प्रोत्साहित करता है तथा प्रशासनिक ढॉचा को कमजोर करने के परिणाम के रूप में आता है। एक महत्वपूर्ण मामला पाया गया जो नीचे विमर्शित हैं:

वन एवं पर्यावरण विभाग

5.4.1 दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण एवं वर्तमान निवल मूल्य का कम वसूलीकरण

दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण एवं वर्तमान निवल मूल्य का कम निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 65.34 लाख क्षतिपूरक वनरोपण एवं ₹ 80 लाख वर्तमान निवल मूल्य का कम वसूली हुआ।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार, वनभूमि का गैर वनभूमि में परिवर्त्तन की अनुमति निर्धारित शर्त्तों के समाधान होने पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें वर्त्तमान निवल मूल्य[32] का भुगतान, अनिर्वाय क्षतिपूरक वनरोपण[33] की लागत और दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण[34], जहॉ लागू हो, शामिल है। इन सभी पर होने वाला व्यय उपयोग करने वाले अभिकर्ता द्वारा वहन किया जाना है। यदि कोई उपयोग अभिकर्ता वन भूमि को गैर वनभूमि में उपयोग करने का इरादा रखता है तो उन्हें करने वाले प्रधान मुख्य वन संरक्षक को आवेदन करने की आवश्यकता है, जो संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रक्रिया[35] को विभिन्न स्तरों से होते हुए अनुमोदन के लिए भारत सरकार के पास भेजता है। भारत सरकार से सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने के पश्चात शुद्ध वर्त्तमान मूल्य/ क्षतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की लागत की माँग की जाती है और उपयोग करने वाले अभिकर्ता को भूमि के विपधन से पूर्व माँग का भुगतान करना पड़ता है। तथापि वन संरक्षण अधिनियम एवं नियमों के मार्गदर्शिका एवं स्पष्टीकरण के कंडिका 3.2 (VIII) (घ) अनुसार खनन पट्टा के नवीकरण की स्थिति में क्षतिपूरक वनरोपण की लागत की वसूली नहीं किया जाना है। माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार (मई 2006), उपयोग

---

[32] नि.व.मू.(निवल वर्त्तमान मूल्य) का अर्थ पर्यावरणीय सेवाओं की मात्रा की गणना है जो वन क्षेत्र को गैर वन प्रयोग में उपयोजन हेतु दी जाती है जैसा केन्द्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

[33] क्षतिपूरक वनरोपण (सी. ए.) उपयोग करने वाले अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई समतुल्य भूमि पर या उपयोग करने वाले अभिकर्ता द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने के मामले में अवकृष्ट वन भूमि के दुगने क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण किया जाना है।

[34] दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का अर्थ वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत निर्धारित क्षतिपूरक वनरोपण के ऊपर वनरोपण कार्य से है जिस पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्व अनुमोदन के गैर वनरोपण कार्य किया गया हो जिस पर अवक्रमित वनभूमि के मूल्य का दुगुना दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण निर्धारित किया जाएगा।

[35] भारत सरकार वनभूमि को गैर वन प्रयोजन हेतु अपयोजन के लिए अनुमोदन दो चरणों में प्रदान करती है-जैसे सैद्धान्तिक अनुमोदन एवं अंतिम अनुमोदन।

करने वाले अभिकर्ता से प्राप्त निवल वर्त्तमान मूल्य/क्षतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण आदि की लागत राशि को क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकार (केम्पा) कोष में स्थानांतरित किया जाना है।

धालभूम वन प्रमण्डल, जमशेदपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2011) में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (उपयोग करने वाला अभिकर्ता) को केन्दाडीह ग्राम खनन पट्टा के 225.363 हे. वनभूमि के विपधन का सैद्धांतिक अनुमति प्रदान (जुलाई 2009) करते समय, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन[36] में सम्मिलित द्विगुणित अवक्रमित वन भूमि का दुगुना (48.69x2=97.38 हे.) दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वनरोपण की लागत वसूलने का निर्देश दिया। तथापि वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण की लागत की गणना (जून 2010) ₹ 1.31 करोड़ (97.38 हे. का दुगुना अर्थात 194.76 हे.) के स्थान पर 97.38 हे. पर ₹ 65.34 लाख निर्धारित किया। इसके परिणामस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण के रूप में ₹ 65.34 लाख का कम माँग निर्धारण किया गया।

पुन: 225.363 हे. वन भूमि में से जो सैद्धांतिक रूप से विपधन के लिए अनुमोदित था, भारत सरकार द्वारा विस्थापित भूमि का निवल वर्त्तमान मूल्य वसूली के लिए निर्देश दिया गया था (जुलाई 2009), जो ₹ 11 करोड़ आता है (48.69 हे. उपरी सतह खनन के लिए ₹ 8.03 लाख प्रति हे. की दर से तथा शेष 176.673 हे. भूमिगत खनन के लिए ₹ 8.03 प्रति हे. का 50 *प्रतिशत* की दर से) जबकि प्रमण्डल द्वारा केवल 205.473 हे. के लिए निवल वर्त्तमान मूल्य की माँग की गणना ₹ 10.20 करोड़ निर्धारित किया गया (48.69 हे. ऊपरी सतह खनन तथा 156.783 हे. भूमिगत खनन के लिए), परिणामस्वरूप ₹ 80 लाख का निवल वर्त्तमान मूल्य का कम निर्धारण किया गया।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धालभूम वन प्रमण्डल द्वारा उत्तर (सितम्बर 2012) में कहा गया कि भारत सरकार के निर्देश[37] (जुलाई 2009) के अनुसार स्पष्ट था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन में सम्मिलित द्विगुणित अवक्रमित वन भूमि का दुगुना दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का निर्धारण किया जाएगा और उपयोग करने वाला अभिकर्ता के लागत पर रखरखाव किया

---

[36] भारत सरकार के अनुमति के बिना उपयोग करने वाला अभिकर्ता द्वारा वनभूमि के क्षेत्र को खंडित किया गया है।

[37] भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एफ.सी.प्रमण्डल) के पत्र सं एफ ने. 8/26/1997 एफ सी. दिनांक 30 जुलाई 2009.

जाएगा, जिसकी गणना 48.69 x 2=97.38 हे. किया गया। तदानुसार 97.38 हे. का दावा निर्धारित किया गया था। तथापि वन प्रमण्डल पदाधिकारी ₹ 80 लाख के निवल वर्त्तमान मूल्य के कम निर्धारण के संबंध में चुप रहे।

उपर वर्णित पत्र जो दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वनरोपण का निर्धारण द्विगुणित अवक्रमित वन भूमि का दुगुना करने के संबंध में है, के अनुसार वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उत्तर सही नहीं था। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा अवक्रमित वन भूमि का केवल दुगुना माँग निर्धारित किया गया अर्थात 97.38 हे. के लिए जबकि 97.38 हे. का दुगुना माँग निर्धारित किया जाना चाहिए था अर्थात 97.38 हे. वनरोपण के लागत का दुगुना।

मामला सरकार के पास प्रतिवेदित (जून 2012) था, साथ ही अगस्त और नवम्बर 2012 के बीच स्मार पत्र दिया गया। इनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2013)।

मृदुला सप्रू

राँची, **(मृदुला सप्रू)**
दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली, **(विनोद राय)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

(संदर्भित कंडिका - 1.7 पृष्ठ - 13)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी

वर्ष	आर्थिक क्षेत्र (गैर -पी.एस.यू.)			सामाजिक क्षेत्र-I			सामाजिक क्षेत्र-II		
	नि.प्र	कंडिकाओं की संख्या		नि.प्र	कंडिकाओं की संख्या		नि.प्र	कंडिकाओं की संख्या	
		अनुभाग अ	अनुभाग ब		अनुभाग अ	अनुभाग ब		अनुभाग अ	अनुभाग ब
2002-03	07	18	24	--	--	--	--	--	--
2003-04	30	25	162	33	67	233	02	--	07
2004-05	123	130	483	24	14	112	98	300	681
2005-06	160	172	723	98	66	458	119	261	746
2006-07	206	253	956	63	83	282	130	360	425
2007-08	160	216	707	78	81	240	105	269	482
2008-09	161	281	653	86	64	372	108	131	667
2009-10	133	107	541	127	70	697	86	70	607
2010-11	155	279	838	146	61	703	69	169	500
2011-12	100	137	703	134	34	480	78	87	570
कुल	**1235**	**1618**	**5790**	**789**	**540**	**3577**	**795**	**1647**	**4685**

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भित कंडिका 2.1.6: पृष्ठ-23)

प्रोटोटाइप योजनाओं का अवलोकन एवं प्रति इकाई लागत

	जल संग्रहक, सिंचाई योजना एवं भूमि सुधार योजना	वर्षा जल संग्रहण कृषि पद्धति	बागवानी एवं ईमारती लकड़ीयों का वृक्षरोपण (बहुस्तरीय रोपण)	दूग्ध उत्पादन	गृहीत कुक्कुट पालन	बकरी पालन	तसर (प्री कोकून)	तसर (पोस्ट कोकून)	रंगीनी लाह पालन	शहतुत वृक्षरोपण एवं रेशम कीड़ा पालन
कलस्टर का निम्न आकार	10 गाँव	50 हेक्टेयर 2-5 गाँव में	25 हेक्टेयर 5-7 गाँव में	5 गाँव	10 गाँव	10 गाँव	6 गाँव, 100 एकड़	12 गाँव	10 गाँव	6 गाँव, 30 एकड़
प्रति कलस्टर लाभुकों की संख्या	500	250	60	50	60	60	112	360	100	60
कलस्टर में इकाईयों की संख्या	1	3	3	3	4	4	1	1	4	
सभी कलस्टरों में लाभुकों की संख्या	500	750	180	150	240	240	112	360	400	
संस्थागत व्यवस्था	अनौपचारिक उपयोगी समूह	अनौपचारिक उपयोगी समूह	अनौपचारिक उपयोगी समूह	पालक का सहकारी	पालक का सहकारी	पालक की समिति	पालक का सहकारी	पालक का सहकारी	अनौपचारिक उपयोगी समूह	पालक का सहकारी
इनटर प्राइज का आकार	0.2 से 0.4 हेक्टेयर	2 हेक्टेयर	0.4 हेक्टेयर	2 शंकर गाये	1 बैच में 300 पक्षियाँ	शुरू में पाँच बकरीयाँ जो बट कर 15 होगा बच्चों के साथ	1 हेक्टेयर में वृक्ष रोपण		12 वृक्षों पर 25 किलोग्राम ब्रुड लाह्	0.4 हेक्टेयर
प्रतिलाभुक शुद्ध वार्षिक प्राप्ती	₹ 10,000 से 20,000	₹ 16,000		₹ 12,000	₹ 13,000	₹ 9000	₹ 6000	₹ 9000	₹ 4000	₹ 26,375
परियोजना विनियोग (कार्यशील पूंजी एवं लागत निर्माण)	80,00,000	40,15,876	63,02,430	88,77,625	11,031,547	35,41,200	16,40,500	20,073,100	11,84,900	95,04,760
प्रोत्साहन लागत एवं क्षमता वर्धन लागत	9,89,850	13,99,108	10,53,938	12,67,033	20,00,015	9,87,310	57,65,585	11,91,654	11,23,710	10,52,436
कुल इकाई लागत	89,89,850	54,14,984	73,56,368	101,44,658	130,31,562	45,28,510	74,06,085	212,64,754	23,08,610	105,57,196

परिशिष्ट - 2.2

(संदर्भित कंडिका 2.1.7: पृष्ठ - 26)

बैच के अनुसार आ0 क0 आ0 द्वारा स0 ज0 वि0 अ0 एवं स0 ज0 वि0 अ0 द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्गत की गई राशि की विवरणी

(लाख रूपये में)

बैच्	विभाग द्वारा आ0 क0 आ0 के निर्गत राशि	पत्र संख्या एवं तिथि	प्रोटोटाइप की संख्या (इकाएयों) स्वीकृत	आ0 क0 आ0 द्वारा स0 ज0 वि0 अ0/एम0 ए0 डी0 ए0 को निर्गत राशि	राशि	अवधि	स0 ज0 वि0 अ0 द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को	अवधि
I (2005-08)	11122.41	139, दिनांक 22.8.06	146	**स0 ज0 वि0 अ0 एम0 ए0 डी0 ए0**	9608.80 1613.61	08/06 से 03/09	1. सिमडेगा 2. राँची 3. चक्रधरपुर 4. गुमला	03/06 से 07/11 11/06 से 10/07 04/06 से 08/08 01/06
II (2006-08)	5397.05	171, दिनांक 19.08.08	70	**स0 ज0 वि0 अ0 एम0 ए0 डी0 ए0 ओ0 एस0 एम0**	4752.34 255.44 389.22	09/2006 से 10/2008	1. सिमडेगा 2. राँची 3. चक्रधरपुर 4. गुमला	02/07 से 10/09 01/08 से 12/08 02/07 से 01/08 04/07
III (2007-10)	13310.39	174, दिनांक 19.08.09 396, दिनांक 05.03.09 161, दिनांक 29.07.10 245, दिनांक 23.10.10	183	**स0 ज0 वि0 अ0 एम0 ए0 डी0 ए0 ओ0 एस0 एम0 कलस्टर पी0 टी0 जी0**	9714.24 1756.02 1166.91 147.12 526.10	11/2008 से 11/ 2010	1. सिमडेगा 2. राँची 3. चक्रधरपुर 4. गुमला	03/10 से 03/12 02/09 से 12/10 05/10 से 04/11 08/10

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भित कंडिका 2.1.7.4: पृष्ठ - 28)

चाईबासा स.ज.वि.अ. में अपूर्ण योजनाओं की विवरणी

(राशि रूपये में)

क्रम संख्या	योजना क्रमांक	कार्य का नाम	अग्रिम भुगतान	जमा किये गये चल लेखा के अनुसार	कनीय अभियता के नाम
1	1/05-06	मंझारी प्रखण्ड के गितिलिपी में चेक डैम का निर्माण	635000	408160	सुखराम कुंकल
2	2/05-06	तंतनगर प्रखण्ड के रंगपोखरिया चेक डैम का निर्माण	580000	521419	दिनेश चंद्र नंदी
3	7/05-06	कुमारडुन्डी प्रखण्ड के देहरि कंदियातिरिया गाँव में चेक डैम का निर्माण	580000	202391	कनिश राउत
4	8/05-06	जगरनाथपुर प्रखण्ड के कुदाहातु में चेक डैम का निर्माण	600000	00	लाल सिंह लमेय
5	9/05-06	मंझारी प्रखण्ड के गितिलिपी गाँव में भवन निर्माण	1307012	822684	सुखराम कुंकल
6	1/06-07	जगरनाथपुर प्रखण्ड के कसिरा गाँव के जहिरा स्थाल पर निर्माण	300000	00	साकेत ठाकुर
7	4/06-07	तांतनगर प्रखण्ड के बड़ा कुम्ता में सरना स्थल का चारदिवारी	500000	168989	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
8	5/06-07	जगरनाथपुर प्रखण्ड के केदमासई में चेक डैम का निर्माण	600000	560451	साकेत ठाकुर
9	7/06-07	जनजातीय छात्रावास भवन का निर्माण (आदिम जनजाति), चाईबासा	550000	00	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
10	8/06-07	के0 बी0 छात्रावास का मरम्मत, चाईबासा	950000	00	साकेत ठाकुर
11	2/07-08	राजकीय् उच्च विद्यालय जनजातीय आवासीय् छात्रावास का निर्माण, कुमारडुंगी प्रखण्ड	4771574	1822364	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
12	1/08-09	मंझारी प्रखण्ड के तारपाई में चहारदिवारी का निर्माण	537300	481413	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
13	2/08-09	आवासीय विद्यालय (जनजातीय) में भण्डार घर , रासोई घर, भोजन घर का निर्माण, चाईबासा	691400	600000	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
14	3/08-09	जनजातीय बालिका आवासीय विद्यालय में विधुत कार्य, चाईबासा	600000	418793	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
15	8/08-09	राजकीय बालिका विद्यालय में 50 शैय्या वाला छात्रावास का निर्माण, चाईबासा	4856700	3090022	उपेन्द्र ठाकुर
16	9/08-09	राजकीय रसेल उच्च विद्यालय, जगरनाथपुर	5538270	5369604	उपेन्द्र ठाकुर
17	10/08-09	तांतनगर प्रखण्ड के बालिका उच्च विद्यालय, चितिमीटी में 50 शैय्या वाला छात्रावास का निर्माण	5490573	5123185	उपेन्द्र ठाकुर
18	1/07-08	बड़ाचिरू में 50 शैय्या वाले अस्पताल में कर्मचारियों के आवास का निर्माण	4307108	3254521	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
19	5/07-08	मझगाँव प्रखण्ड के डेप्रेबुआ में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	200000	87843	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
20	6/07-08	मझगाँव प्रखण्ड के सगरिफ में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	200000	110708	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
21	7/07-08	कुमारडुंगी प्रखण्ड के दिर्गो में आग्नबाड़ी केन्द्र का निर्माण	200000	54627	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
22	9/07-08	जगरनाथपुर प्रखण्ड के भैराभरसाई में आगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	198300	227904	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
23	10/07-08	जगरनाथपुर प्रखण्ड के देबुआ में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	220000	227904	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
24	11/07-08	टोंटो प्रखण्ड के लुईया में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	200000	00	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
25	2/08-09	कुमारडुंगी प्रखण्ड में दिकुना सकर में पक्का चेक डैम का निर्माण	1481300	1164091	प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम
26	7/08-09	चाईबासा में 50 शैय्या जनजातीय कन्या छात्रावास का निर्माण	4899784	4864649	उपेन्द्र ठाकुर
		कुल	**40994321**	**29581722**	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भित कंडिका 2.1.7.4 पृष्ठ - 28)

साहेबगंज स0 ज0 वि0 अ0 में अपूर्ण योजनाओं के असमायोजित अग्रिम की विवरणी

क्रम संख्या	योजना क्रमांक	नाम	स्थान	कार्यशील की तिथि	प्राक्कलित राशि (₹ लाख में)	अग्रिम राशि (₹ में)	अंतिम अग्रिम की तिथि
1	2/10-11	कन्या उच्च विद्यालय के लिए 100 शैय्या वाले छात्रावास	बान्दरकोला	8.11.10	94.28	1767172	20.9.11
2	3/10-11	उच्च विद्यालय के लिए 100 शैय्या वाले छात्रावास	तालझारि	8.11.10	94.28	8000000	29.3.12
3	4/10-11	छात्राओं के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	पतना	8.11.10	56.15	5300000	29.3.12
4	5/10-11	छात्राओं के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	तालझारि	8.11.10	56.15	5000000	28.7.11
5	6/10-11	मध्य विद्यालय के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	पतना	8.11.10	56.15	5000000	29.3.12
6	7/10-11	मध्य विद्यालय के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	बरहेट	8.11.10	56.15	2054403	20.9.11
7	8/10-11	छात्रों के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	बोआरिजोर	8.11.10	56.15	1521900	20.9.11
8	9/10-11	छात्रों के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	बोआरिजोर	8.11.10	56.15	1507075	20.9.11
9	10/10-11	छात्रों के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	बोआरिजोर	8.11.10	56.15	1399387	31.3.12
10	11/10-11	विद्यालय अनुरक्षण	बोआरिजोर	8.11.10	3.27	300000	31.3.11
11	12/10-11	अदिम जनजाति के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	बोआरिजोर	8.11.10	56.15	1899287	27.9.11
12	02/08-09	8 ए0 सी0 आर0, बांझी	बांझी	08-09	42.03	4203000	-
13	03/80-09	डॉक्टरों के लिए आवास्	पतना	08-09	13.14	1313403	-
14	08/05-06	50 शैय्या वाले छात्रावास	रतनपुर्	08-09	46.10	4530307	-
15	10/05-06	50 शैय्या वाले छात्रावास	कार्तिकभिठा	08-09	46.10	4366656	-
16	07/05-06	50 शैय्या वाले छात्रावास	कुर्तिका	08-09	46.10	3835134	-
कुल					**834.50**	**51997724**	

परिशिष्ट-2.5

(*संदर्भित कंडिका 2.1.12:* पृष्ठ - 49)

पाँच स.ज.वि.अ. में स्वीकृत एवं कार्य बल की स्थिति का व्योरा

पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
परियोजना निदेशक	5	5	शुन्य
अपर परियोजना निदेशक	10	शुन्य	10
सहायक परियोजना प्रबंधक	10	शुन्य	10
सहायक अभियंता	5	3	2
कार्यलय अधीक्षक	5	4	1
लेखापाल	5	3	2
लिपिक	10	9	1
निजी सहायक सह आशुलिपिक	5	3	2
आदेशपाल	20	15	5
चालक	15	3	12
कुल	**90**	**45**	**45**

परिशिष्ट-2.5 क्रमश:

(संदर्भित कंडिका 2.1.12: पृष्ठ - 49)

पाँच स.ज.वि.अ. में स्वीकृत एवं कार्य तल की स्थिति की विवरण

पद के नाम	चाईबासा		गुमला		राँची		साहेबगंज		सिमडेगा	
	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
परियोजना निदेशक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
अपर परियोजना निदेशक	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
सहायक परियोजना प्रबंधक	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
सहायक अभियंता	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
कार्यलय अधीक्षक	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
लेखापाल	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
लिपिक	2	0	2	0	2	0	2	0	1	1
निजी सहायक सह अशुलिपिक	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
आदेशपाल	2	2	4	0	3	1	4	0	2	2
चालक	1	2	1	2	0	3	1	2	0	3
कुल	**08**	**10**	**11**	**07**	**09**	**09**	**12**	**06**	**05**	**13**

परिशिष्ट -2.6

(संदर्भित कंडिका 2.2.5: पृष्ठ - 59)

जेएनएनयूआरएम के तहत झारखंड में मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं	परियोजनाओं के नाम	यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसी के नाम
1	शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं (बीएसयूपी)	रांची नगर निगम
2	शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं (बीएसयूपी)	धनबाद नगर निगम
3	शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं (बीएसयूपी)	जमशेदपुर शहरी संकुलन
4	यूआइजी शहरी परिवहन प्रणाली (यूटीएस)	रांची नगर निगम
5	युआइजी शहरी परिवहन प्रणाली (यूटीएस)	धनबाद नगर निगम
6	युआइजी शहरी परिवहन प्रणाली (यूटीएस)	जमशेदपुर शहरी संकुलन
7	युआइजी जल आपूर्ति (डब्लुएस)	रांची नगर निगम
8	युआइजी जल आपूर्ति (डब्लुएस)	धनबाद नगर निगम
9	युआइजी- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	रांची नगर निगम
10	युआइजी- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	धनबाद नगर निगम
11	युआइजी-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	जमशेदपुर शहरी संकुलन
12	यूआईडीएसएसएमटी- जल आपूर्ति (डब्लुएस)	देवघर नगर निगम
13	यूआईडीएसएसएमटी- जल आपूर्ति (डब्लुएस)	चाईबासा नगर पर्षद
14	यूआईडीएसएसएमटी- जल आपूर्ति (डब्लुएस)	चास नगर पर्षद
15	यूआईडीएसएसएमटी- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	चास नगर पर्षद
16	यूआईडीएसएसएमटी- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	लोहरदगा नगर पर्षद
17	यूआईडीएसएसएमटी- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	हजारीबाग नगर पर्षद
18	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	लोहरदगा नगर पर्षद
19	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	हजारीबाग नगर पर्षद
20	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	गुमला नगर पंचायत
21	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	चाईबासा नगर पर्षद
22	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	गिरिडीह नगर पर्षद
23	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	मेदिनिनगर नगर पर्षद
24	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	फुसरो नगर पर्षद
25	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	चतरा नगर पंचायत
26	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	सरायकेला नगर पंचायत
27	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	मिहिजाम नगर पंचायत

परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भित कंडिका 2.2.6.2 : पृष्ठ - 62)

सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति

राज्य स्तरीय सुधार

क्र.सं	ब्यौरे	कार्यान्वयन के लिए समय सीमा	31 मार्च 2012 को स्थिति	
1	74वां सीएए (12 वीं अनुसूची के तहत 18 कार्यों के स्थानांतरण)	31.03.10	सीएए की 12 वीं अनुसूची के 18 कार्यों को झारखंड नगरपालिका ऐक्ट 2011 में शामिल किया गया।	पूरी तरह से लागू।
2	नगर पालिकाओं में चुनाव	31.03.09	सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण जमशेदपुर, जुगसलाई और मानगो को छोड़कर सभी शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव आयोजित किया गया। यह जल्द ही गठित की जाएगी।	लागू।
3	एसएफसी की स्थिति	31.03.09	गठन किया गया है और प्रथम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है।	लागू।
4	74वां (जिला योजना समिति का गठन)	31.03.09	गठन किया गया है और अधिसूचना सं.563 दिनांक 02.08.11 द्वारा नियम बना लिया गया है।	लागू।
5	74वां (महानगर योजना समिति का संविधान)	31.03.09	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 384 में प्रावधान किए गए है।	लागू।
6	स्थानांतरण-शहरी योजना कार्य	31.03.10	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011में शामिल किया गया है जो झारखंड ऐक्ट सं 07/2012 दिनांक-30-01-12 द्वारा अधिनियमित किया गया है।	लागू।
7	स्थानांतरण-शहर जल आपूर्ति और स्वच्छत	31.03.10	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011में शामिल किया गया है जो झारखंड ऐक्ट सं 07/2012 दिनांक-30-01-12 द्वारा अधिनियमित किया गया है।	लागू।
8	स्थानांतरण-सार्वजनिक परिवह	31.03.10	रांची, धनबाद एवं जमशेदपुर (यू/ए) में बस सेवा शुरू की गई है और और यह एसपीवी द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की ओर से चलाया जाता है।	लागू।
9	किराया नियंत्रण में सुधार	31.03.09	झारखंड ऐक्ट सं .06/2012 दिनांक 30-01-12. द्वारा अधिनियमित किया गया है।	लागू।
10	5 *प्रतिशत* स्टाम्प ड्यूटी का युक्तिकरण	-	निबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 141 दिनांक 31.05.04 द्वारा लागू किया गया है।	
11	शहरी भूमि सीलिंग और विनियमन अधिनियम (यूएलसीआरए) का निरसन	31.03.11	अधिनियम सं 91 दिनांक 24.01.11 द्वारा निरसित।	लागू।
12	सामुदायिक भागीदारी कानून का अधिनियमन	31.03.10	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011के अध्याय 5 की धारा 52 में प्रावधान किया गया है।	लागू।
13	सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून के अधिनियमन	31.03.09	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011के अध्याय 6 की धारा 52 में प्रावधान किया गया है।	लागू।

यूएलबी स्तरीय सुधार

क्र.सं	ब्यौरे	कार्यान्वयन के लिए समय सीमा	31 मार्च, 2012 को स्थिति	
14	ई-शासन व्यवस्थ	31.03.09	एनएमएमपी के तहत धनबाद में ई-शासन पर पायलट परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। मुख्यालय में मुख्य एप्लिकेशन की स्थापना के बाद और धनबाद नगर निगम में पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, समय के साथ अन्य नगर पालिकाओं में लागू किया जाएगा	आंशिक रूप से लागू।
15	एक्रुअल आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणालिमें शिफ्ट	31.03.10	सलाहकार मैसर्स प्राइसवाटर हाउस एंड कूपर्स प्राइवेट. लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा परियोजना लागू किया जा रहा है. ड्राफ्ट झारखंड नगरपालिका लेखा मैनुअल तैयार किया गया है। एक्रुअल आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को व्यवहार में शीघ्र ही लाया जाएगा।	आंशिक रूप से लागू।
16	संपत्ति कर (85 *प्रतिशत* कवरेज)	31.03.12	शहरी स्थानीय निकायों को अपंजीकृत होल्डिंगस के पहचान के लिए निजी व्यक्तियों को शामिल कर संपत्ति कर कवरेज के विस्तार के लिए कदम उठाने हेतु निर्देश दिया गया है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (जीएसएसी), रांची रांची नगर निगम के लिए घरेलू संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग लागू कर रहा है। वर्तमान में झारखंड में होल्डिंगस की कुल अनुमानित संख्या के खिलाफ शहरी स्थानीय निकाय 60-80 *प्रतिशत* परिवारों को कवर कर पाये हैं। वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए बचे हुए होल्डिंगस को कवर करने की प्रक्रिया चल रही है।	आंशिक रूप से लागू।
17	संपत्ति कर 90 *प्रतिशत* संग्रह क्षमता	31.03.12	कुल दर्ज होल्डिंगस के खिलाफ करों का भुगतान करने वाले होल्डिंगस की संख्या लगभग 60-75 *प्रतिशत* है. सरकार.जीआईएस विधि का उपयोग कर आधार बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है.संपत्ति कर संग्रह क्षमता कम है, लेकिन और सभी होल्डिंगस के जीआईएस मैपिंग पंजीकरण के बाद काफी सुधार होगा। नगर विकास विभाग ने स्थानीय निकायों को संपत्ति कर संग्रह में धीरे-धीरे सुधार कर 90 *प्रतिशत* तक करने का अनुदेश दिया है।	आंशिक रूप से लागू
18	100 *प्रतिशत* लागत वसूली जल आपूर्त	31.03.11	जल कर लगाया जा रहा है। संशोधित दर पर जल कर जमा करने के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं।	लागू।
19	100 *प्रतिशत* लागत वसूली एसडब्लुएम	31.03.11	पीपीपी आधार पर रांची नगर निगम में कार्यान्वयन किया जा रहा है और इसमें 100 *प्रतिशत* लागत वसूली मेकानिज्म को शामिल किया गया है।	आंशिक रूप से लागू।
20	शहरी गरीबों के लिए सेवाओं के लिए धन का आंतरिक निर्धारण	31.03.09	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 105 में प्रावधान किया गया है	लागू।
21	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के प्रावधान	31.03.09	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 105 में प्रावधान किया गया है।	लागू।

वैकल्पिक सुधार

क्र.सं	ब्यौरे	कार्यान्वयन के लिए समयसीमा	31 मार्च 2012 को स्थिति	
22	संपत्ति शीर्षक प्रमाणन प्रणाली का शहरी स्थानीय निकायों में प्रारं	31.03.11	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।	आंशिक रूप से लागू
23	भवन उपनियम में संशोधन अनुमोदन	31.03.10	भवन उपनियम 2006 में संशोधित किया गया नया भवन उपनियम सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए संशोधनों के साथ तैयार किया	लागू नहीं।

	प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना		गया है और यह संबंधित विभाग द्वारा छानबीन की गई है जैसे, कानून, पंजीकरण, भवन। यह बहुत जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।	
24	वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए भवन उपनियम में संशोधन	31.03.09	भवन उपनियम 2006 में इसका प्रावधान किया गया है।	लागू।
25	ईडब्ल्यूएस/एलआइजी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं में विकसित भूमि के 25 प्रतिशत का निर्धारण	31.03.10	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 427(5) (क) में विकसित किए गए भूमि के 20 *प्रतिशत* का प्रावधान किया गया है	लागू।
26	गैर कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे का सरलीकरण	31.03.10	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करना है ताकि इस सुधार को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान किया जा सके। प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।	लागू नहीं
27	जमीन और संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया का प्रारंभ	31.03.09	जमीन और संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया पूरे राज्य में शुरू किया गया है।	लागू.
28	पुनर्चक्रित पानी का पुनःउपयोग हेतु उपनियम	31.03.11	यह पहले से ही मौजूदा भवन उपनियम 2006 के धारा 17.6.2 (ख) में अनिवार्य कर दिया है "अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किसी भी भवन के लिए अनिवार्य किया जा जाएगा जो प्रति दिन 12000 लीटर से अधिक की खपत करता हो या जिसमें 24 फ्लैट या अधिक हो, इनमें से जो भी कम है"	लागू।
29	प्रशासनिक सुधार	31.03.09	सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर 1190 नए पदों का सृजन किया है और राज्य मुख्यालय में एक तकनीकी सेल बनाया गया है। पदों को युक्तिसंगत बनाया गया है और इन सेवाओं के लिए सेवा नियम बनाने हेतु कार्रवाई जारी है।	आंशिक रूप से लागू।
30	संरचनात्मक सुधार	31.03.09	नगरीय शासन के प्रशासन के लिए विभाग ने राज्य स्तर पर अन्य लाइन संगठनों को बनाया है जैसे टीसीपीओ, सूडा, निदेशालय नगर प्रशासन।	लागू।
31	सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन	31.03.10	इस एजेंडे का कार्यान्वयन विशिष्ट परियोजनाओं पर आधारित है। पीपीपी आधार पर परियोजनाओं को लागू करने के लिए, परियोजना के क्षेत्र के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में, रांची में एसडब्लुएम परियोजना पीपीपी आधार पर कार्यान्वयन के अधीन है। एस्डब्लुएम धनबाद और जमशेदपुर के लिए परियोजनाएं (यूए) पीपीपी आधार पर चलाई जा रही हैं।	लागू।

स्रोत:एसएलएनए द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भित कंडिका 2.2.7.1 : पृष्ठ - 64)

झारखण्ड में जेएनएनयूआरएम के तहत परियोजनाओं के लिए निधि के आवंटन का स्वरूप

कार्यक्रम अवयव	**धनबाद और जमशेदपुर**	**रांची और अन्य[1]**
युआइजी	50 *प्रतिशत* केन्द्रीय शेयर 20 *प्रतिशत* राज्य के शेयर और 30 *प्रतिशत* पैरास्टेटल/यूएलबी/वित्तीय संस्था से ऋण	80 *प्रतिशत* केन्द्रीय शेयर, 10 *प्रतिशत* राज्य के शेयर और 10 *प्रतिशत* पैरास्टेटल/यूएलबी/ वित्तीय संस्था से ऋण।
बीएसयूपी	50 *प्रतिशत* केन्द्रीय शेयर और 50 *प्रतिशत* राज्य/यूएलबी/लाभार्थी योगदान सहित पैरास्टेटल शेयर।	80 *प्रतिशत* केन्द्रीय शेयर और 20 *प्रतिशत* राज्य/यूएलबी/लाभार्थी योगदान सहित पैरास्टेटल शेयर।
यूआईडीएसएसएमटी	लागू नहीं।	80 *प्रतिशत* केन्द्रीय शेयर, 10 *प्रतिशत* राज्य के शेयर और 10 *प्रतिशत* नोडल/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण या कार्यान्वयन एजेंसियों के आंतरिक संसाधनों से।
आईएचएसडीपी	लागू नहीं।	80 *प्रतिशत* केन्द्रीय 20 *प्रतिशत* राज्य/यूएलबी द्वारा स्वयं के स्रोतों से या लाभार्थी योगदान/वित्तीय संस्थाओं से।

स्रोत: जेएनएनयूआरएम के दिशानिर्देश

[1] गैर मिशन शहर-देवघर, चास, लोहरदगा, गुमला, मेदिनिनगर, फुसरो सरायकेला, गिरिडीह, चाईबासा, चतरा, मिहिजाम हजारीबाग

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भित कंडिका 2.2.7.2 : पृष्ठ - 66)

निधि के उपयोग का प्रतिशत दर्शाती विवरणी (चयनित परियोजनाएं)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	यूएलबी/परियोजना के नाम	परियोजना लागत	3/12 तक प्राप्ति	3/12 तक व्यय	*प्रतिशत* उपयोग
बीएसयूपी					
1	रांची/बीएसयूपी के द्वितीय चरण	67.47[2]	37.08	7.75[3]	20.90
2	धनबाद/बीएसयूपी के द्वितीय चरण	34.28	6.12	0.44[4]	7.19
कुल योग		**101.75**	**43.20**	**8.19**	**18.96**
युआइजी					
3	रांची जल आपूर्ति	288.39	96.92	96.92 [5]	100.00
4	धनबाद जल आपूर्ति	365.85	99.12	99.12	100.00
कुल योग		**654.24**	**196.04**	**196.04**	**100.00**
यूआईडीएसएसएमटी					
5	चास/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	5.68	3.21[6]	1.76	54.83
6	चास/जल की आपूर्ति	34.24	50.26[7]	30.64	60.96
7	लोहरदगा/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	4.48	2.08[8]	1.54	74.04
8	हजारीबाग/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	5.69	2.65[9]	2.11	79.62
9	देवघर जल आपूर्ति	47.38	48.07[10]	30.36	63.16
कुल योग		**97.47**	**106.27**	**66.41**	**62.49**
आईएचएसडीपी					
10	लोहरदगा आईएचएसडीपी	35.05	11.52	11.87[11]	103.04
11	गुमला आईएचएसडीपी	19.67	9.31	5.61	60.26
12	हजारीबाग आईएचएसडीप	19.83	9.02	8.14	90.24
कुल योग		**74.55**	**29.85**	**25.62**	**85.83**
महायोग		**928.01**	**375.36**	**296.26**	**78.93**

स्रोत: स्वीकृति पत्र, रोकड बही और त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

---

2 संशोधित तकनीकी स्वीकृत लागत=₹ 81.01 करोड़

3 सभी चरणों के लिए प्राप्त धन एक ही बैंक खाते में रखा गया और व्यय से खर्च किया गया. द्वितीय चरण के संबंध में विशेष रूप से व्यय पता लगाने योग्य नहीं था

4 सभी चरणों के लिए प्राप्त धन एक ही बैंक खाते में रखा गया और व्यय से खर्च किया गया . द्वितीय चरण के संबंध में विशेष रूप से व्यय पता लगाने योग्य नहीं

5 5 प्रमंडलों द्वारा वास्तविक व्यय=₹ 91.82 करोड़

6 डीपीआर तैयार करने के लिए₹ 0.09 करोड़ भी शामिल है

7 डीपीआर तैयार करने के लिए ₹ 0.50 करोड़ भी शामिल है

8 डीपीआर के लिए ₹ 0.07 करोड़ (₹ 6.72 लाख) भी शामिल है

9 डीपीआर तैयार करने के लिए ₹ 8.54 लाख रुपये भी शामिल है

10 डीपीआर तैयार करने के लिए ₹ 0.71 करोड़ भी शामिल है

11 प्राप्त आवंटन से अधिक व्यय जमाओं पर अर्जित ब्याज से किया.

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भित कंडिका 2.2.7.2: पृष्ठ - 66)

उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

शहर	परियोजना का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	2010-11 तक यूएलबी द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि (केन्द्रीय हिस्से+राज्य+यूएलबी) डीपीआर तैयार करने के लिए प्राप्त राशि को छोड़कर	व्यय के खिलाफ भारत सरकार को प्रस्तुत उपयागिता प्रमाणपत्र की 2010-11 तक स्थिति	2011-12 तक यूएलबी द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि (केन्द्रीय हिस्से+राज्य+यूएलबी) डीपीआर तैयार करने के लिए प्राप्त राशि को छोड़कर	2011-12 तक यूएलबी द्वारा खर्च की गई राशि	2011-12 तक व्यय के खिलाफ भारत सरकार को प्रस्तुत उपयागिता प्रमाणपत्र
रांची	बीएसयूपी (द्वितीय चरण)	67.47	20.84	शून्य	37.08	7.75	शून्य
	जल आपूर्ति	288.39	96.92	71.67	96.92	96.92	83.93
धनबाद	बीएसयूपी (द्वितीय चरण)	34.28	6.12	शून्य	6.12	0.44	शून्य
	जल आपूर्ति	365.85	99.12	शून्य	99.12	99.12	74.80
देवघर	पानी की आपूर्ति	47.38	29.65	29.06	47.36	30.36	29.06
हजारीबाग	एस्डब्लुएम	5.69	2.55	0.84	2.56	2.12	0.84
	आईएचएसडीप	19.83	5.69	शून्य	9.02	8.14	शून्य
लोहरदगा	आईएचएसडीपी	35.05	10.22	शून्य	11.52	11.87	10.22
	एस्डब्लुएम	4.48	2.01	1.52	2.01	1.54	1.52
गुमला	आईएचएसडीपी	19.67	9.31	शून्य	9.31	5.61	शून्य
चास	एस्डब्लुएम	5.68	2.55	1.71	3.12	1.76	1.71
	पानी की आपूर्ति	34.24	20.14	15.51	49.76	30.64	20.64
कुल योग		**928.01**	**305.12**	**120.31**	**373.90**	**296.27**	**222.72**

स्रोत: स्थानीय निकायों और एसएलएनए से संकलित आंकड़े

परिशिष्ट - 2.11

(संदर्भित कंडिका 2.2.7.3 : पृष्ठ - 67)

अर्जित ब्याज, उसकी निकासी और जीआरडीए लिमिटेड के प्रशासनिक खाते में हस्तांतरित राशिको दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	अर्जित ब्याज
1	2008-09	27,33,503.49
2	2009-10	2,53,68,944.52
3	2010-11 *	2,28,32,840.10
4	2011-12	2,91,00,741.62
	कुल योग	**8,00,36,029.73**

केवल जनवरी 2011 तक उपलब्ध आंकड़े

क्र सं	तारीख	चैक सं.	के खाते से स्थानांतरण	बैंक का नाम	खाता सं	₹ में राशि	निकासी के कारण
1	29/09/2008	232503	बीएसयूपी रांची	भारतीय स्टेट बैंक	30357050316	10,00,000.00	प्रशासन के खर्च के लिए
2	02/06/2009	232456	युआइडीएसएसएमटी-डब्लुएस/चास	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया	30357050815	8,00,000.00	तथैव
3	24/02/2009	232504	बीएसयूपी रांची	भारतीय स्टेट बैंक	30357050316	1,00,000.00	तथैव
4	19/02/2009	232457	युआइडीएसएसएमटी-डब्लुएस/चास	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया	30357050815	2,00,000.00	तथैव
5	19/02/2009	47973	बीएसयूपी धनबाद	इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा	50001409373	1,00,000.00	तथैव
6	13/06/2009	181329	आईएचएसडीपी गुमला	बैंक ऑफ इंडिया, विकास भवन शाखा	496610210000035	1,00,000.00	तथैव
7	13/06/2009	232509	बीएसयूपी रांची	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया	30357050316	1,50,000.00	तथैव
8	13/06/2009	47983	युआइडीएसएसएमटी-डब्लुएस/देवघर	इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा	50001410049	1,00,000.00	तथैव
9	27/08/2009	17230	युआइजी-डब्लुएस/रांची	बैंक ऑफ इंडिया	496610210000209	30,00,000.00	तथैव
10	16/02/2010	17231	युआइजी-डब्लुएस/रांची	बैंक ऑफ इंडिया	496610210000209	30,00,000.00	तथैव
11	24/10/2010	17234	युआइजी-डब्लुएस/रांची	बैंक ऑफ इंडिया	496610210000209	40,00,000.00	स्व मूल्यांकन कर (निर्धारण वर्ष2010-11)

12	14/03/2011	232512	बीएसयूपी रांची	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया	30357050316	1,00,00,000.00	अग्रिम कर (निर्धारण वर्ष 2011-12)
13	12.12.11	232513	बीएसयूपी रांची	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया	30357050316	80,00,000	अग्रिम कर (निर्धारण वर्ष 2012-13)
कुल योग						**3,05,50,000.00**	

स्रोत: एसएलएनए द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भित कंडिका 2.2.8.3 : पृष्ठ - 74)

मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान और वसूली का विवरण

क्र.सं	डिवीजन के नाम	मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान (₹)	तारीख	मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली(₹)	मार्च 2012 को वसूल किये जाने हेतु शेष (₹)
रांची					
1	हेडवर्क्स	68884300	26.04.10	68884300[12]	शून्य
2	वितरण	41422300	29.04.10	11586523	29835777
3	गोंडा	55814820	28.04.10	28070995	27743825
4	हटिया	45340000	07.05.10/21.02.11	10457603	34882397
5	यांत्रिक शहरी	23248000	03.05.10/19.02.11	शून्य	23248000
कुल योग		**234709420**		**118999421**	**115709999**
धनबाद					
1	डिवीजन-1	298000000	02.06.11	39537706	258462294
कुल योग		**298000000**		39537706	258462294
महायोग		**532709420**		**158537127**	**374172293**

स्रोत: मापी पुस्तकें

[12] सितंबर 2011 तक पूर्णतया वसूल.

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भित कंडिका 2.2.8.10 : पृष्ठ - 84)

बी.ओ.क्यु. के अनुमोदन के बिना निविदाकर्ताओं को आवंटित किये गये आधारभूत संरचनओं के कार्य

क्रम सं/समूह	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹)	जिन्हें काम दिया गया	कार्यादेश सं/तिथि	किया गया भुगतान (₹)
1	टुकु टोली और कदम टोली में बुनियादी सुविधाओं के विकास	47,98,475	मेसर्स सुरेश अग्रवाल	1212/22.10.08	47,96,175
2	दुन्दुरिया में बुनियादी ढांचे का विकास	26,00,276	नृपेन्द्र कुमार सिंह	1213/22.10.08	26,00,276
3	करंज टोली और दादू टोली में बुनियादी सुविधाओं के विकास	49,95,660	न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन	1215/22.10.08	41,95,521
4	चेतार और कुम्हार टोली में बुनियादी सुविधाओं के विकास	87,02,655	बालाजी कंस्ट्रक्शन	1216/22.10.08	76,22,305
5	आजाद बस्ती और हुसैन नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास	48,54,470	रामापति साहू	1217/22.10.08	48,37,021
6	अम्बेडकर नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास	24,20,745	मैसर्स वदूद खान कंस्ट्रक्शन	1218/22.10.08	22,72,570
7	खरिया पारा और भाटी मोहल्ला में बुनियादी सुविधाओं का विकास	45,73,665	मैसर्स उदय कंस्ट्रक्शन	1219/22.10.08	44,89,293
8	गौस नगर और डुम्बर टोली में बुनियादी सुविधाओं का विकास	23,23,115	मैसर्स विक्की कंस्ट्रक्शन	1220/22.10.08	23,00,139
9	शांति नगर और घाटो बगीचा में बुनियादी सुविधाओं का विकास	48,38,645	मैसर्स अम्बर कंस्ट्रक्शन	1222/22.10.08	41,51,247
10	वार्ड नं 10,11 और 12 में बुनियादी सुविधाओं का विकास	8,89,455	श्री रंजीत सिंह	1227/22.10.08	8,89,455
11	धोबी मोहल्ला और न्यू बस स्टैंड में बुनियादी सुविधाओं का विकास	9,21,000	श्री अजीत कुमार साहू	1223/22.10.08	9,15,827

12	करम टोली में बुनियादी सुविधाओं का विकास	77,04,385	मैसर्स डी.के. कंस्ट्रक्शन	1221/22.10.08	72,99,398
13	शास्त्री नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास	9,11,920	श्री अरविंद कुमार	1224/22.10.08	8,88,046
14	पंडित मोहल्ला में बुनियादी सुविधाओं का विकास	9,88,540	श्री रूपेश कुमार सिंह	1225/22.10.08	5,58,323
15	बराइक मोहल्ला में बुनियादी सुविधाओं का विकास	24,18,080	श्री अजीत कुमार साहू	1222/22.10.08	23,70,050
16	हरिजन टोली और सरना टोली में बुनियादी ढांचे का विकास	21,23,000	श्री अजय कुमार सिंह	96 (i)/ 27.01.09	19,03,306
17	दुन्दुरिया में पार्क का निर्माण	23,67,000	श्री अजीत कुमार साहू	98/28.01.09	23,25,716
18	टंगरा बाजार में इन्फोरमल सेक्टर मार्केट का निंमाण	38,29,000	मैसर्स पंजाब आरा मशीन	111/30.01.09	29,48,682
योग		**6,22,60,086**			**57363350**

स्रोत: योजना संचिकाएं

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भित कंडिका 2.2.8.15 : पृष्ठ - 93)

सफ़ाई उपकरणों और वाहनों की अनुमोदित दर से अधिक दर पर खरीद को दर्शाती विवरणी

क्र.सं	उपकरणों के नाम	मात्रा	खरीद दर प्रति इकाई (₹)	डीपीआर के अनुसार स्वीकृत दर (₹)	अधिक दर (*प्रतिशत* में)	अतिरिक्त/अनियमित व्यय (₹)
चास नगर परिषद						
1	कन्टेनराइज्ड रिक्शा ट्राली	75	11900	8000	48.75	292500
2	सीमलेस हैन्डकार्ट	10	4500	2500	80.00	20000
3	कम्युनिटि डस्टबिन	40	45000	40000	12.50	200000
4	ट्विन बिन	200	7491	5691	31.63	360000
5	डम्पर प्लेशर	3	1272000	900000	41.33	1116000
						1988500
लोहरदगा नगर परिषद						
1	कन्टेनराइज्ड हैन्डकार्ट	30	4625	3250	42.31	41250
2	कन्टेनराइज्ड रिक्शा ट्राली	25	13720	8000	71.50	143000
3	सीमलेस हैन्डकार्ट	5	4625	2500	85.00	10625
4	कम्युनिटिडस्टबिन	20	61900	40000	54.75	438000
5	ट्विन बिन	50	13600	10400	30.77	160000
6	हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रेलर	2	457900	250000	83.16	415800
7	डम्पर प्लेशर	2	945500	900000	5.06	91000
8	सीधे कचरा संग्रहण के लिए छोटे वाहन	2	474500	275000	72.54	399000
						1698675
हजारीबाग नगर परिषद						
1	कन्टेनराइज्ड हैन्डकार्ट	75	6500	3250	100.00	243750
2	कन्टेनराइज्ड रिक्शा ट्राली	100	16000	8000	100.00	800000
3	सीमलेस हैन्डकार्ट	40	7500	2500	200.00	200000
4	कम्युनिटिडस्टबिन	40	53500	40000	33.75	540000
5	हैजारडस वेस्ट कंटेनर	10	32200	20000	61.00	122000
6	हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रेलर	3	526000	250000	110.40	828000
7	डम्पर प्लेशर	4	995000	900000	10.56	380000
8	सीधे कचरा संग्रहण के लिए छोटे वाहन	3	305000	275000	10.91	90000
					कुल योग	**3203750**
					महायोग	**6890925**

स्रोत: डीपीआर और खरीद संबंधी दस्तावेज

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भित कंडिका 2.2.8.16 : पृष्ठ - 94)

सफ़ाई वाहनों के अपर्याप्त उपयोग को दर्शाती विवरणी

वाहन	मात्रा	खरीद की तारीख	माइलोमीटर के अनुसार तय की गयी कुल दूरी (कि.मी.)	औसत/माह (कि.मी. में)	लॉग बुक के अनुसार तय की गयी कुल दूरी (कि.मी.)	औसत/माह (कि.मी. में)
हजारीबाग नगर परिषद (29 मई 2012 की स्थिति)						
2		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
ट्रक टिपर	2	08.10.09	(i) 4123 (ii) 8723	(i) 128.84 (ii) 272.59	(i) 13,608 (ii) 15,485	(i) 425.25 (ii) 483.91
हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रेलर	3	03.11.09	(i) 1887[13] इएच (ii) 1178 इएच (iii) 1284 इएच	(i) 60.87 इएच (ii) 38 इएच (iii) 41.42 इएच	(i) 22,685 (ii) 25,121 (iii) 24,784	(i) 731.77 (ii) 810.35 (iii) 799.48
क्लोज्ड डम्पर प्लेशर	2 2	25.02.10 04.03.10	(i) 4925 (ii) 2122 (iii) 2673 (iv) 3228	(i) 182.41 (ii) 78.59 (iii) 99 (iv) 119.56	(i) 7506 (ii) 1405 (iii) 1505 (iv) 3410	(i) 278 (ii) 52.03 (iii) 55.74 (iv) 126.30
सीधे कचरा संग्रहण के लिए छोटे वाहन	3	02.09.09	(i) 5230 (ii) 1586 (iii) 180	(i) 158.48 (ii) 48.06 (iii) 5.45	(i) 2944 (ii) 1760 (iii) लौग बुक उपलब्ध नही	(i)89.21 (ii)53.33 (iii) -
लोहरदगा नगर परिषद (05 मई 2012 की स्थिति)						
ट्रक टिपर	2	23.06.08	(i) 1581 (ii)1797	34 38.64	लौग बुक उपलब्ध नही	-
हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रेलर	2	23.06.08	(i) 414 इएच (ii) 19 इएच	8.9 इएच 0.41 इएच	तथैव	-
क्लोज्ड डम्पर प्लेशर	2	23.06.08	(i) 6426 (ii) 4333	138.19 93.18	तथैव	-
सीधे कचरा संग्रहण के लिए छोटे वाहन	2	23.06.08	(i) 2754 (ii) 465	59.29 10	तथैव	-
चास नगर परिषद (27 अप्रैल 2012 की स्थिति)						

[13] इंजन घंटे

ट्रक टिपर	2	30.12.08	2858 3386	71.45 84.65	तथैव	-
क्लोज्ड डम्पर प्लेशर	3	15.11.08	6083 4296 12007	152.08 107.40 300.18	तथैव	-

स्रोत: वाहनों और लॉग बुक की* माइलोमीटर *के भौतिक सत्यापन से संकलित आंकड़े

परिशिष्ट – 2.16

(संदर्भित कंडिका 2.2.10: पृष्ठ - 100)

सभी परियोजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

क्र.सं	शहर के नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ ₹ में)	03/12 तक प्राप्त राशि (करोड़ ₹ में)	03/12 तक खर्च राशि (करोड़ ₹ में)	*प्रतिशत* विमुक्ति के विरूद्ध इस्तेमाल की	*प्रतिशत* परियोजना लागत के खिलाफ इस्तेमाल
बीएसयूपी							
1	रांची	बीएसयूपी	263.59	108.64	7.75	7.13	2.94
2	धनबाद	बीएसयूपी	91.99	21.34	0.44	2.06	0.48
3	जमशेदपुर	बीएसयूपी	148.86	3.59	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल योग	**504.44**	**133.57**	**8. 19**	**6.13**	**1.62**
युआइजी							
4	रांची	सिटी बस सेवा	17.50	10.50	6.43	61.24	36.74
		जल आपूर्ति परियोजना	288.39	96.92	96.92	100.00	33. 61
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	51.39	20.56	6.24	30.35	12.14
5	धनबाद	सिटी बस सेवा	14.30	9.29	6.69	72.01	46.78
		जल आपूर्ति परियोजना	365.85	99.12	99.12	100.00	27.09
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	55.86	30.34	0.44	1.45	0.79
6	जमशेदपुर	सिटी बस सेवा	5.50	4.13	4.13	100.00	75.09
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	33.36	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल योग	**832.15**	**270.86**	**219.97**	**81.21**	**26.43**
आईएचएसडीपी							
7	गिरिडीह	आईएचएसडीपी	25.32	9.18	0.15	1.63	0.59
8	गुमला	आईएचएसडीपी	19.67	9.31	5.61	60.26	28.52
9	लोहरदगा	आईएचएसडीपी	35.05	11.52	11.87	103.04	33.87
10	चायबासा	आईएचएसडीपी	12.99	5.77	3.45	59.79	26.56
11	मेदिनिनगर	आईएचएसडीपी	22.25	9.25	2.72	29.44	12.22
12	फुसरो	आईएचएसडीपी	15.94	7.31	शून्य	शून्य	शून्य
13	चतरा	आईएचएसडीपी	19.83	5.86	शून्य	शून्य	शून्य
14	सरायकेला	आईएचएसडीपी	27.69	11.28	शून्य	शून्य	शून्य
15	हजारीबाग	आईएचएसडीपी	19.83	9.02	8.14	90.24	41.05
16	मिहिजाम	आईएचएसडीपी	27.07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल योग	**225.64**	**78.50**	**31.94**	**40.69**	**14.16**

यूआईडीएसएसएमटी							
17	देवघर	जल आपूर्ति	47.38	48.07	30.36	63.16	64.08
18	चैस	जल आपूर्ति	34.24	50.26	30.64	60.96	89.49
19	चैस	एस्डब्लुएम	5.68	3.21	1.76	54.83	30.99
20	लोहरदगा	एस्डब्लुएम	4.48	2.08	1.54	74.04	34.38
21	हज़ारीबाग	एस्डब्लुएम	5.69	2.65	2.11	79.62	37. 08
22	चायबासा	जल आपूर्ति	32.18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल योग	**129.65**	**106.27**	**66.41**	**62.49**	**51.22**
		महायोग	**1691.88**	**589.20**	**326.51**	**55.42**	**19.30**

स्रोतः स्वीकृति पत्र, रोकड़ बही और एसएलएनए द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े

परिशिष्ट– 2.17

(संदर्भित कंडिका 2.3.1 एवं 2.3.3.1.: पृष्ठ– 101 और 105)

त्वरित सिंचाई लाभ योजना(त्व.सिं.ल.यो.) के अन्तर्गत ली गई परियोजनाओं के स्थिति मार्च 2012

सिंचित क्षमता (सि.क्ष.) हेक्टेयर

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम (वृहत मध्यम, लघु)	सृजित.क्षमताओं (सृ.क्ष.) का लक्ष्य	त्व.सिं;ल.यो. को सम्मिलित करने का वर्ष	परियोजनाओं की स्थिति	सृजित सृ.क्ष.
1	गुमानी बराज (वृहत)	16190	1997-98	अपूर्ण	शून्य
2	कंसजोर जलाशय[1] (मध्यम)	6260	1997-98	आंशिक पूर्ण (2006-07)	6260
3	सोनूआ जलाशय (मध्यम)	8008	1997-98	अपूर्ण	शून्य
4	सूरंगी रिर्जवार (मध्यम)	2601	1997-98	अपूर्ण	शून्य
5	अपरशंख रिर्जवार (मध्यम)	7070	2004-05	आंशिक पूर्ण	400
6	पंचखेरो जलाशय (मध्यम)	3085	2004-05	अपूर्ण	शून्य
7	तपकरा जलाशय (मध्यम)	1860	1997-98	पूर्ण (2002-03)	1840
8	तोरई जलाशय (मध्यम)	8000	1997-98	परित्यक्त	शून्य
9	लतरातू जलाशय (मध्यम)	9900	1997-98	पूर्ण (2002-03)	9900
10	सूकरी जलाशय (लघु)	440	2010-11	अपूर्ण	शून्य
11	284 श्रृंखलाबद्ध अवरोधक बॉधे (चेक डैम) (लघु)	56235	2010-11	148 पूर्ण	26944
योग		**119649**			**45344**
12	स्वर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना (वृहत)	265000	2011-12	अपूर्ण	शून्य
13	171 श्रृंखलाबद्ध अवरोधक बॉधे (चेक डैम) (लघु)	21898	2011-12	अपूर्ण	शून्य
योग		**286898**			शून्य
कुल योग		**406547**			**45344**

(स्रोतः जल संसाधन विभाग)

[1] फेज I पूर्ण.

परिशिष्ट- 2.18

(संदर्भित कंडिका 2.3.2.1 एवं 2.3.3.1 :पृष्ठ– 103 और 105)

प्रगतिशील सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की स्थिति मार्च 2012 तक केन्द्रीय ऋण/अनुदान सहित

(₹करोड़ में)

क्रसं.	परियोजनाओं का नाम	परियोजना के प्रारंभ का वर्ष	अनुमानित लागत		त्व.सिं.ल.यो. को सम्मिलित करने का वर्ष	त्व.सिं.ल.यो. के अन्तर्गत ऋण/अनुदान			ऋण/अनुदान से व्यय	कुल व्यय राज्य निधि सहित
			प्रारंभिक	वर्त्तमान		ऋण (1996-2005)	अनुदान (2005-12)	योग		
वृहत एवं मध्यम परियोजनाएँ										
1	गुमानी	1976	3.84	185.76	1997-98	25.94	5.46	31.40	31.40	150.27
2	कंसजोर	1987	8.66	52.97	1997-98	10.56	0.48	11.04	11.04	54.99
3	सोनुआ	1982	8.92	82.65	1997-98	17.64	1.61	19.25	19.25	75.71
4	सुरंगी	1987	4.60	41.17	1997-98	12.15	1.13	13.28	13.28	47.03
5	अपरशंख	1987	9.19	141.19	2004-05	8.27	18.08	26.35	17.73	136.16
6	पंचखेरो	1986	9.55	75.69	2004-05	4.49	3.75	8.24	8.24	69.08
योग			**44.76**	**579.43**		**79.05**	**30.51**	**109.56**	**100.94**	**533.24**
लघु परियोजनाएँ										
7	सुकरी	2008	9.35	9.35	2010-11	0.00	5.67	5.67	2.55	2.83
8	284 माइक्रो लिॅफ्ट (एमआई)	2010-11	440.53	440.53	2010-11	0.00	328.88	328.88	222.58	247.30
योग			**449.88**	**449.88**		**0.00**	**334.55**	**334.55**	**225.13**	**250.13**
कुल योग			**494.64**	**1029.31**		**79.05**	**365.06**	**444.11**	**326.07**	**783.37**

(स्रोत: जल संसाधन विभाग)

परिशिष्ट- 2.19

(संदर्भित कंडिका 2.3.4: पृष्ठ- 107)

चयनित परियोजनाओं के अपूर्ण कार्यों की विवरणी नवम्बर/दिसम्बर 2012 तक

(₹ लाख में)

क्र.सं	प्रमंडल के नाम	कार्यों के नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की तिथि/कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारित मूल्य	भुगतान की वर्त्तमान स्थिति	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
गुमानी परियोजना (नवम्बर 2012 की स्थिति)							
1	सिंचाई प्रमंडल (सिं.प्र) बरहेट (मुख्य कार्य)	बराज फाटक एवं स्टोप लॉग की स्थापना करना	24 एफ2/07-08	25.3.08/ 30.6.11	748.02	668.57	संरचना का अनुमोदन न होना
2	(सिं.प्र) बरहेट (गुमानी मुख्य नहर (जीएमसी)	चेन संख्या 216 से 253 तक तल की सफाई (बेड क्लीयरेन्श)	5 एफ2/11-12	28.12.11/ 25.2.12	20.48	15.41	धीमी गति से कार्य का होना
3	(सिं.प्र) बरहरवा (जीएमसी)	एकल पथ पुल चेन सं.584/585 पर	1 एफ 2/12-13	7.4.12/ 31.4.12	31.04	0	-वही-
4	(सिं.प्र) बरहरवा (बरहरवा शाखा नहर)	12 आउटलेट	3 एफ 2/08-09	18.8.08/ 31.1.09	4.47	0	ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जाना
5		अवशेष मिट्टी कार्य चेन सं. 606.50 से 618 तक	16 एफ 2/10-11	25.3.11/ 24.7.11	6.14	0.56	धीमी गति से कार्य का होना
6		अवशेष मिट्टी कार्य चेन सं.618.50 से 708	5 एफ 2/10-11	5.7.11/ 4.3.12	20.35	10.20	-वही-
7		एकल पथ पुल चेन सं. 233 पर	2 एफ 2/12-13	7.4.12/ 31.4.12	14.95	0	-वही-
8	(सिं.प्र) बरहेट (दरियापुर वितरणी)	सीडी चेन सं. 270 पर	5 एफ 2/09-10	19.12.09/ 18.6.10	10.97	4.21	-वही-
9	-तथैव- (पतना वितरणी)	12 आउटलेट	8 एफ 2/07-08	25.07.07/ 24.10.07	3.58	2.09	धीमी गति से कार्य का होना
10	(सिं.प्र) पाकुड़ (बरमसिया वितरणी)	चेन सं. 578 पर जलवाहा	14 एफ 2/07-08	18.03.08/ 31.3.08	4.22	3.86	-वही-
11	-तथैव-	चेन सं. 167 पर अवशेष मिट्टी कार्य	08 एफ 2/10-11	12.01.11/ 11.4.11	4.99	4.40	-वही-
12	-तथैव-	चेन सं.240 पर जलवाहा का अवशेष मिट्टी कार्य	09 एफ 2/10-11	17.02.11/ 16.5.11	4.75	3.34	-वही-
13	-तथैव-	चेन सं. 510 से 520 पर अवशेष मिट्टी कार्य	11 एफ 2/10-11	17.02.11/ 16.5.11	4.63	2.49	-वही-
	योग				**878.59**	**715.13**	
अपरशंख जलाशय योजना (नवम्बर 2012 की स्थिति)							
14	जल पथ प्रमंडल (ज.प.प्र.) II,	3.84 किमी पर सीडी	4 एफ2/09-10	6.3.10/ 5.4.11	18.73	17.53	धीमी गति से कार्य का होना

(₹ लाख में)

क्र.सं	प्रमंडल के नाम	कार्यों के नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की तिथि/कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारित मूल्य	भुगतान की वर्त्तमान स्थिति	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
15	चैनपुर, गुमला (बॉयी मुख्य नहर)	6.00/5.67 कि. मी. पर सीडी का अवशेष कार्य	2 एफ 2/09-10	29.7.09/ 29.8.09	7.70	7.13	जनाक्रोश
16		0.20, 11.07, 11.34, 11.72, 12.24, 13.50, 13.75 कि.मी. पर काजवे	12 एफ 2/10-11	1.11.10/ 31.1.11	161.83	138.97	धीमी गति से कार्य का होना
17		0.0 से 14.04 कि.मी. के बीच 9 सीधा आउटलेट और 11.72/11.70 कि.मी. पर स्केप रेगुलेटर का निर्माण	13 एफ 2/10-11	2.11.10/ 1.1.11	21.95	17.90	धीमी गति से कार्य का होना
18	जलपथ प्रमंडल I, चैनपुर, गुमला (दॉयी मुख्य नहर)	9926 से 10082 मी. पर मिट्टी कार्य	13 एफ 2/07-08	15.10.07/ 14.7.08	52.44	51.76	धीमी गति से कार्य का होना
19		9.303 कि.मी. पर सीडी	33 एफ 2/07-08	19.12.07/ 18.9.08	71.39	69.36	-वही-
20		11. कि.मी. पर सीडी	53 एफ 2/07-08	14.03.08/ 13.12.08	27.16	25.31	-वही-
21		12.15 कि.मी. पर सीडी	08 एफ 2/08-09	15.10.08/ 14.4.09	9.52	7.03	-वही-
22		7141 से 7765 मी. पर मिट्टी कार्य तथा 8080 से 8360 मी. पर बोल्डर पिचिंग	09 एफ 2/08-09	15.10.08/ 14.4.09	5.71	4.73	-वही-
23		3360 से 3420 मी. और 3660 मी. पर सुपर पैसेज का अवशेष कार्य	10 एफ 2/08-09	06.11.08/ 4.5.09	17.18	17.17	-वही-
24		13050 से 13110 मी. पर स्केप	14 एफ 2/08-09	30.01.09/ 29.4.09	4.78	4.20	
25		2.70 और 3.12 कि.मी. पर 2 आउटलेट का निर्माण	15 एफ 2/08-09	09.02.09/ 8.5.09	1.75	1.62	-वही-
26		0.72, 1.62 और 2.46 कि.मी. पर 5 आउटलेट का निर्माण	17 एफ 2/08-09	20.02.09/ 19.5.09	2.60	2.49	-वही-
27		2.79 कि.मी. पर मुख्य रेगुलेटर का निर्माण	28 एफ 2/08-09	13.03.09/ 12.5.09	2.68	2.05	-वही-
28		3.84 कि.मी.पर मुख्य रेगुलेटर का निर्माण	29 एफ 2/08-09	13.03.09/ 12.5.09	3.32	2.89	ठेकेदार द्वारा मिट्टी कार्य नहीं किया जाना
29		1.50 पर मुख्य रेगुलेटर का निर्माण	32 एफ 2/08-09	23.03.09/ 18.9.09	1.48	1.39	धीमी गति से कार्य का होना
30		3.6 से 3.9 कि.मी.पर सीडी पुल एवं मिट्टी कार्य	01 एफ 2/10-11	12.04.10/ 11.7.10	38.16	20.86	ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर देना
31		1.85 कि.मी.और 4.65 कि.मी पर सीडी एवं 90 मी. से 660 मी पर मिट्टी कार्य	02 एफ 2/10-11	12.04.10/ 11.7.10	168.21	111.83	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिए गए परामर्श को कार्यान्वित करने के लिए प्रारंभिक कार्य बंद किया गया
32		7.68 कि.मी.पर एच.आर.	03एफ2/10-11	12.04.10/ 11.7.10	8.27	7.73	धीमी गति से कार्य का होना

(₹ लाख में)

क्र.सं	प्रमंडल के नाम	कार्यों के नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की तिथि/कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारित मूल्य	भुगतान की वर्त्तमान स्थिति	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
33		110 मी से 140 तक पत्थर कटाव के साथ नाली(ड्रेन) का निर्माण	01 एफ 2/11-12	1.6.11/ 30.6.11	4.9	4.61	-वही-
34		6823 मी.से 7000 मी.तक मिट्टी स्थापना कार्य	03 एफ 2/11-12	16.06.11/ 16.7.11	13.71	2.90	-वही-
35		1330 मी.से 3550 मी.पर मिट्टी स्थापना कार्य	04 एफ 2/11-12	24.06..11/ 23.7.11	25.75	14.87	-वही-
36		690 से 1320 मी.पर मिट्टी स्थापना कार्य	05 एफ 2/11-12	27.06.11/ 26.7.11	21.89	7.41	-वही-
37		6540 से 6815 मी.पर मिट्टी स्थापना कार्य	06 एफ 2/11-12	27.06.11/ 26.7.11	15.82	3.40	-वही-
38		4020 से 6480 मी.पर मिट्टी स्थापना कार्य एवं तल की सफाई	07 एफ 2/11-12	27.06.11/ 26.7.11	11.14	4.23	-वही-
39		आकाशी वितरणी के लिए मिट्टी कार्य	20 एफ 2/08-09	21.02.09/ 18.8.09	9.78	8.55	बिना भूमि अधिग्रहण के एकरारनामा किया जाना
40		वितरणी सं.-5 का निर्माण	05 एफ 2/10-11	17.09.10/ 16.6.11	59.94	3.67	
41		वितरणी सं. 2 पर मिट्टी कार्य	41 एफ 2/07-08	03.03.08/ 2.7.08	15.73	7.00	-वही-
42	-वही- (वितरणी)	वितरणी सं. 1 पर मिट्टी कार्य	02 एफ 2/08-09	06.05.08/ 4.9.08	5.57	0	भूमि क्षतिपूर्ति दिया जाना बाकी
43		-वही-	04 एफ 2/08-09	15.10.08/ 14.2.09	5.62	1.93	-वही-
44		बॉयी मुख्य नहर 7 कि.मी.से लघु वितरणी	31 एफ 2/08-09	23.03.09/ 22.9.09	6.67	6.31	-वही-
45		पुतरंगी वितरणी पर मिट्टी कार्य	34 एफ 2/08-09	26.03.09/ 24.5.09	14.41	0.55	-वही-
	योग				**835.79**	**577.38**	
पंचखेरो जलाशय योजना (दिसम्बर **2012** तक की स्थिति)							
46	जलपथ प्रमंडल बरही (मुख्य कार्य)	स्पेल चैनल	1 एफ2/07-08	7.5.07/ 6.2.08	356.91	218.55	पुनर्रिक्षित अनुमान जनवरी 2013 में समर्पित
47		1200 से 1370 मी.पर नदी अवरोधन एवं कौफर बॉध	एस.बी.डी. 1/11-12	18.4.11/ 15.6.12	598.31	188.60	धीमी गति से कार्य
48	-वही- (बॉयी मुख्य नहर)	चेन सं.20 से 45.47 पर अवशेष मिट्टी कार्य	21 एफ 2/07-08	29.2.08/ 28.11.08	30.69	28.35	सीडी आवश्यक
49		चेन सं.137.77 से 172 पर अवशेष मिट्टी कार्य	9 एफ 2/07-08	12.1.08/ 11.10.08	19.77	16.58	क्षतिपुर्ति नहीं दिया गया
50		चेन सं. 172 से 185 पर अवशेष मिट्टी कार्य	11 एफ 2/07-08	18.1.08/ 17.7.08	6.60	2.55	धीमी गति से कार्य
51		चेन सं. 45.47 से 109.47 पर	1 एफ 2/09-10	16.7.09/	11.24	10.58	क्षतिपुर्ति नहीं दिया

(₹ *लाख में*)

क्र.सं	प्रमंडल के नाम	कार्यों के नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की तिथि/कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारित मूल्य	भुगतान की वर्त्तमान स्थिति	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
		अवशेष मिट्टी कार्य		15.10.09			गया
52	-वही-	चेन सं.0.50 से 20.50 पर अवशेष मिट्टी कार्य	13 एफ 2/07-08	6.2.08/ 5.8.08	3.90	1.58	पुनर्रिक्षित अनुमान की आवश्यकता
53	(दॉयी मुख्य नहर)	चेन सं. 45.10 से 106.50 पर मिट्टी कार्य	22 एफ2/07-08	29.2.08/ 28.8.08	15.93	13.66	-वही-
योग					**1043.35**	**480.45**	
कुल योग					**2757.73**	**1772.96**	

(स्रोत: सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा, बरहेट, पाकुड़, जलपथ प्रमंडल सं.-1 चैनपुर, सं.-2 चैनपुर एवं बरही)

परिशिष्ट- 2.20

(संदर्भित कंडिका 2.3.4: पृष्ठ- 107)

2007-08 तक एकरारित कार्यों जो कि अबतक अपूर्ण है, कि विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमंडलों का नाम	कार्यों का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारनामा की तिथि/कार्य संपन्न किए जाने की तिथि	एकरारित मूल्य	वर्त्तमान तक का भुगतान	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
गुमानी बराज परियोजना (नवम्बर 2012तक की स्थिति)							
1	सिंचाई प्रमंडल बरहरवा (चुटिया वितरणी)	चेन सं.80 पर एकल पथ पुल	22 एफ2/05-06	22.3.06/ 21.9.06	3.33	2.98	भूमि अधिग्रहण के बिना कार्य को कराये जाने के खिलाफ जनाक्रोश
2		चेन सं.167.50 पर एकल पथ पुल	24 एफ 2/05-06	28.3.06/ 27.9.06	4.00	0	
3		चेन सं. 58.50 पर एकल पथ पुल	1 एफ 2/06-07	8.4.06/ 7.10.06	3.47	2.99	
4		चेन सं 224 पर एकल पथ पुल	9 एफ 2/06-07	20.10.06/ 31.3.07	4.54	0	
5		चेन सं 258 पर एकल पथ पुल	12 एफ 2/06-07	7.11.06/ 31.3.07	4.05	0	
6		चेन सं 283 पर एकल पथ पुल	13 एफ 2/06-07	16.11.06/ 31.3.07	4.54	0	
7		चेन सं 363 पर एकल पथ पुल	3 एफ 2/06-07	20.5.06/ 19.11.06	2.02	0	
8		चेन सं 390 पर एकल पथ पुल	2 एफ 2/06-07	4.5.06/ 3.11.06	2.52	0	
9	सिंचाई प्रमंडल पाकुड़ (फतेहपुर वितरणी)	चेन सं 4 पर जलवाहा	4 एफ 2/04-05	29.11.04	5.40	0.33	संवेदक द्वारा प्रारंभिक कार्य करने के उपरांत कार्यों को लंबे अरसे तक छोड़ दिया गया
10		चेन सं 56 पर जलवाहा	9 एफ 2/04-05	13.12.04	8.05	4.95	
11		चेन सं 320 (दॉयी) पर जलवाहा	7 एफ 2/04-45	8.12.04	3.90	2.29	
12		चेन सं 31 पर जलवाहा	29 एफ 2/05-06	8.12.05	5.72	5.89	
13		चेन सं 76.50 पर जलवाहा	30 एफ 2/05-06	8.12.05	5.50	4.83	
14		चेन सं 275 (दॉयी) पर जलवाहा	46 एफ 2/05-06	19.3.06	1.24	0.97	
15		चेन सं 306 (बॉयी) पर	37 एफ 2/05-06	22.12.05	5.35	3.65	

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमंडलों का नाम	कार्यों का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारनामा की तिथि/कार्य संपन्न किए जाने की तिथि	एकरारित मूल्य	वर्त्तमान तक का भुगतान	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
		जलवाहा					
16		चेन सं.320 (बॉयी) पर जलवाहा	36 एफ 2/05-06	22.12.05	3.54	2.36	
17	-वही (बरमसिया वितरणी)	चेन सं.360 पर जलवाहा	12 एफ 2/04-05	15.12.04	6.37	4.85	-वही-
18		चेन सं.468.50 पर जलवाहा	14 एफ 2/04-05	15.12.04	6.63	4.76	
योग					**80.17**	**40.85**	
अपरशंख जलाशय योजना (नवम्बर- 2012 तक की स्थिति)							
19	जलपथ प्रमंडल स-II, चैनपुर गुमला (मुख्य कार्य)	180 से 400 मी.पर स्पील चैनल का अवशेष कार्य एवं 0.20 मी.पर सीफॉन	4 एफ 2/02-03	--/ 31.12.07	664.17	540.94	धीमी गति से कार्य
20	जलपथ प्रमंडल स-II, चैनपुर गुमला (बॉयी मुख्य नहर)	6.06 से 6.75 कि.मी. में मिट्टी कार्य एवं 6.65 कि.मी. पर सीडी	8 एफ 2/04-05	6.1.05/ 31.3.06	47.31	36.52	-वही-
21		12.81 से 13.17 कि.मी. में मिट्टी कार्य, 13.03 कि.मी.पर सीडी,13.09 कि.मी.पर एकल पथ	7 एफ 2/04-05	6.1.05/ 5.7.05	15.81	14.24	-वही-
22		13.17 से 13.77 कि.मी.में मिट्टी कार्य	9 एफ 2/04-05	6.1.05/ 5.7.05	7.96	5.58	-वही-
23		11.34 से 11.77 कि.मी.में मिट्टी कार्य, 11.72 कि.मी. पर सीडी, 11.52 कि.मी.पर एकल पथ	10 एफ 2/05-06	30.4.05/ 29.4.06	54.38	52.48	-वही-
24	जलपथ प्रमंडल स-I, चैनपुर गुमला (दॉयी मुख्य नहर)	3990 मी.पर पुल	49 एफ 2/05-06	17.01.06/ 16.7.06	31.95	24.19	जनाक्रोश
योग					**821.58**	**673.95**	
पंचखेरो जलाशय योजना (दिसम्बर- 2012 तक की स्थिति)							
25	जलपथ प्रमंडल	1370 से 2180 मी. मिट्टी बॉध	3 एफ 2/05-	7.7.05/ 6.6.06	158.80	102.03	जनाक्रोश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमंडलों का नाम	कार्यों का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारनामा की तिथि/कार्य संपन्न किए जाने की तिथि	एकरारित मूल्य	वर्त्तमान तक का भुगतान	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
	बरही (मुख्य कार्य)	पर अवशेष मिट्टी कार्य	06				क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया
26	-वही- (बॉयी मुख्य नहर)	सं. 0 से 20 पर मिट्टी कार्य	5 एफ 2/05-06	23.2.06/ 22.8.06	12.73	11.64	क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया
27	-वही- (दॉयी मुख्य नहर)	चेन सं.29.5 और 41 पर सीडी	14 एफ 2/02-03	15.1.03/ 14.5.03	21.07	17.57	ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जाना
योग					**192.60**	**131.24**	
कुल योग					**1094.35**	**846.04**	

(स्रोत: सिंचाई प्रमंडल बरहरवा और पाकुड़, जलपथ प्रमंडल नं. I और II, चैनपुर गुमला एवं बरही)

परिशिष्ट– 2.21

(संदर्भित कंडिका 2.3.4.2: पृष्ठ- 113)

अत्यधिक भुगतित राशि के नहीं वसूली की विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यों का नाम	एकरारनाम सं.	एकरारनामा की तिथि/कार्य पूर्ण करने की तिथि	एकरारित मूल्य	संवेदकों की भुगतान	अंतिम मापी के अनुसार कार्यों का मूल्य	अत्याधिक भुगमान	भारित दंड	सुरक्षित राशि के समांजस्य के उपरांत वसूलनीय राशि
1	6279 मी.से 6300 मी.में मिट्टी कार्य एवं पुल	51 एफ 2/05-06	11.2.06/ 10.01.07	25.02	21.60	16.89	4.71	2.50	6.13
2	5070 मी सं 6120 मी.में मिट्टी कार्य	38 एफ 2/03-04	29.1.04/ 28.07.04	20.60	20.18	17.67	2.51	2.06	4.01
3	6775 मी.से 6840 मी.में मिट्टी कार्य	01 एफ 2/05-06	19.4.05/ 18.10.05	22.96	24.83	17.09	7.74	2.30	7.57
4	1890 पर सीडी 2150 मी.पर पुल 2600 में कट पुल 3600 से 3900मी में मिट्टी कार्य	01 एफ 2/ 10-11	12.4.10/ 11.07.10	38.61	20.86	20.85	0.01	3.86	0.90
5	6660 से 6715 मी में मिट्टी कार्य	02 एफ 2/05-06	19.4.05/ 18.10.05	22.96	9.24	5.25	3.99	2.30	3.81
6	3600 मी.से 3990 में मिट्टी कार्य	61 एफ 2/03-04	19.2.04/ 18.08.04	33.12	22.09	22.09	0	3.31	0.37
7	6140 से 6240 में मिट्टी कार्य और सीडी सह बैरल	28 एफ 2/05-06	24.1.06/ 23.04.07	179.53	187.85	159.12	28.73	17.95	41.92
योग				**342.80**	**306.65**	**258.96**	**47.69**	**34.28**	**64.71**

(स्रोत: जलपथ प्रमंडल नं. I, चैनपुर, गुमला)

परिशिष्ट- 2.22

(संदर्भित कंडिका 2.3.4.4:पृष्ठ- 118)

चयनित लघु सिंचाई परियोजनाओं के दिसम्बर 2012 तक की स्थिति की विवरणी

फेज	चेक डैम (सीडी) सहित स्वीकृत योजनाएँ				पूर्ण योजनाओं एवं चेक डैम (सीडी)				अपूर्ण योजनाएँ		
	सं.	सीडी	लागत (त्व.सिं.ल. यो.)	सृजित.क्षमता (सृ.क्ष.) का लक्ष्य	सं.	सीडी	सृजित.क्षमता (सृ.क्ष.)	व्यय	सं.	सीडी	व्यय
कोडरमा											
I	4	11	469.21	619	3	8	373	196.11	0[2]	0	0.00
II	5	20	584.71	685	5	20	672	419.07	0	0	0.00
III	9	30	928.52	1000	5	19	519	304.20	4	11	79.16
योग	**18**	**61**	**1982.44**	**2304**	**13**	**47**	**1564**	**919.38**	**4**	**11**	**79.16**
हजारीबाग											
I	4	13	495.07	615	4	13	595	400.11	0	0	0.00
II	2	6	305.01	260	2	6	260	178.48	0	0	0.00
योग	**6**	**19**	**800.08**	**875**	**6**	**19**	**855**	**578.59**	**0**	**0**	**0.00**
पाकुड़											
I	2	10	419.20	495	2	10	495	305.72	0	0	0.00
II	2	7	242.70	410	2	7	410	178.01	0	0	0.00
योग	**4**	**17**	**661.90**	**905**	**4**	**17**	**905**	**483.73**	**0**	**0**	**0.00**
रामगढ											
I	5	19	602.50	1107	4	18	1002	405.37	1	1	0.00
II	2	5	131.79	170	2	5	170	102.47	0	0	0.00
III	7	28	891.45	1284	7	28	840	810.95	0	0	0.00
योग	**14**	**52**	**1625.74**	**2561**	**13**	**51**	**2012**	**1318.79**	**1**	**1**	**0.00**
गुमला											
I	4	10	544.19	684	4	10	551	417.18	0	0	0.00
II	5	13	979.12	914	4	12	741	668.39	1	1	12.83
III	17	56	3333.67	3556	1	3	150	86.97	16	53	557.70
योग	**26**	**79**	**4856.98**	**5154**	**9**	**25**	**1442**	**1172.54**	**17**	**54**	**570.53**
साहेबगंज											
I	5	18	541.98	585	3	13	359	235.63	2	5	76.13
II	3	9	251.84	520	3	9	275	251.39	0	0	0.00
योग	**8**	**27**	**793.82**	**1105**	**6**	**22**	**634**	**487.02**	**2**	**5**	**76.13**
पूर्वी सिंहभूम											
I	6	20	697.09	1590	6	20	1381	547.79	0.00	0	0.00
II	1	3	172.26	270	1	3	180	137.20	0.00	0	0.00
III	9	26	1473.60	2970	5	16	1680	585.61	4	10	152.51
योग	**16**	**49**	**2342.95**	**4830**	**12**	**39**	**3241**	**1270.60**	**4**	**10**	**152.51**
कुल योग	**92**	**304**	**13063.91**	**17734**	**63**	**220**	**10653**	**6230.65**	**28**	**81**	**878.33**

(स्रोत: संबंधित लघु सिंचाई प्रमंडलें)

[2] एक श्रृंखला (तीन सीडी चेक डैम सहित) कोडरमा जिला में स्थगित किया गया।

परिशिष्ट-2.23

(संदर्भित कंडिका 2.4.2: पृष्ठ - 125)

आठ चयनित जिलों में जाचॅ किये गए पंचायत भवनों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
1	लोहरदगा	लोहरदगा	रामपुर
2	लोहरदगा	लोहरदगा	आरकोसा
3	लोहरदगा	लोहरदगा	भटखिजरी
4	लोहरदगा	लोहरदगा	हेसल
5	लोहरदगा	लोहरदगा	जोरी
6	लोहरदगा	लोहरदगा	निगनी
7	लोहरदगा	लोहरदगा	जूरिया
8	लोहरदगा	लोहरदगा	बगहा
9	लोहरदगा	लोहरदगा	हिरही
10	लोहरदगा	लोहरदगा	मनहो
11	लोहरदगा	कुडू	जिंगी
12	लोहरदगा	कुडू	लावागांई
13	लोहरदगा	कुडू	सुंदरु
14	लोहरदगा	कुडू	कोलसिमरी
15	लोहरदगा	कुडू	टाटी
16	लोहरदगा	कुडू	पंडरा
17	लोहरदगा	कुडू	काकरगढ
18	लोहरदगा	कुडू	बडकीचापी
19	लोहरदगा	कुडू	चांदलासो
20	लोहरदगा	कुडू	सलगी
21	धनबाद	धनबाद	नावाडीह
22	धनबाद	धनबाद	दामोदरपुर
23	धनबाद	धनबाद	सियालगूदडडी.
24	धनबाद	धनबाद	पेटिया
25	धनबाद	धनबाद	अलगरिया
26	धनबाद	धनबाद	परसिया
27	धनबाद	धनबाद	बरडूबी
28	धनबाद	धनबाद	समशिखारा
29	धनबाद	धनबाद	डूबराजडीह
30	धनबाद	धनबाद	ढोकरा
31	धनबाद	गोविंदपुर	बरवा पूर्वी
32	धनबाद	गोविंदपुर	गोविंदपुर पूर्वी
33	धनबाद	गोविंदपुर	बिराजपूर
34	धनबाद	गोविंदपुर	खरनी
35	धनबाद	गोविंदपुर	तिलैया
36	धनबाद	गोविंदपुर	डमकारा बरवा
37	धनबाद	गोविंदपुर	नगर कियारी
38	धनबाद	गोविंदपुर	पथूरिया
39	धनबाद	गोविंदपुर	बारीयो

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
40	धनबाद	गोविंदपुर	कंचनपूर
41	देवघर	देवघर	सरसा
42	देवघर	देवघर	शांकरी
43	देवघर	देवघर	गिलूआचांदडीह
44	देवघर	देवघर	खोरापनन
45	देवघर	देवघर	महतोडीह उदयपुरा
46	देवघर	देवघर	संग्राम लोधिया
47	देवघर	देवघर	पिचरीबाद
48	देवघर	देवघर	केनमनकाठी
49	देवघर	देवघर	कोकरीबैंक
50	देवघर	देवघर	मासनजोर
51	देवघर	पालोजोरी	बाधडीह
52	देवघर	पालोजोरी	बिराजपुर
53	देवघर	पालोजोरी	भुरकुन्डी
54	देवघर	पालोजोरी	महुआडाबर
55	देवघर	पालोजोरी	बसहा
56	देवघर	पालोजोरी	रघुआडीह
57	देवघर	पालोजोरी	धावा
58	देवघर	पालोजोरी	जमुआ
59	देवघर	पालोजोरी	दुधानी
60	देवघर	पालोजोरी	कुन्जबोना
61	देवघर	मधुपुर	पहरूडीह
62	देवघर	मधुपुर	गोनिया
63	देवघर	मधुपुर	जमुनी
64	देवघर	मधुपुर	सिकटीया
65	देवघर	मधुपुर	डरवे
66	देवघर	मधुपुर	जामागुडी
67	देवघर	मधुपुर	सुग्गापहाडी-2
68	देवघर	मधुपुर	पसिया
69	देवघर	मधुपुर	डलहा
70	देवघर	मधुपुर	सपतार
71	देवघर	मधुपुर	बरा नारायणपुर
72	जामताडा	जामताडा	चन्द्रदीप
73	जामताडा	जामताडा	गोपालपुर
74	जामताडा	जामताडा	सोनबाद
75	जामताडा	जामताडा	शहरडाल
76	जामताडा	जामताडा	बरजोरा
77	जामताडा	जामताडा	दखीनबहल
78	जामताडा	जामताडा	सुखजोरा
79	जामताडा	जामताडा	पियासोला
80	जामताडा	जामताडा	दुलादी
81	जामताडा	जामताडा	नवाडीह
82	जामताडा	नारायणपुर	नारायणपुर

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
83	जामताडा	नारायणपुर	नयाडीह
84	जामताडा	नारायणपुर	ढावाकेन्द्र
85	जामताडा	नारायणपुर	बुढ़ूडीह
86	जामताडा	नारायणपुर	बांकुडीह
87	जामताडा	नारायणपुर	नवाडीह
88	जामताडा	नारायणपुर	पबिया
89	जामताडा	नारायणपुर	शहरपुरा
90	जामताडा	नारायणपुर	रुपडीह
91	जामताडा	नारायणपुर	टोपाटांड
92	जामताडा	नारायणपुर	दिघारी
93	जामताडा	करमाताङ	अलगचुंआ
94	जामताडा	करमाताङ	बरमुंडी
95	जामताडा	करमाताङ	तारकोजोरी
96	जामताडा	करमाताङ	करमाताङ
97	चतरा	चतरा	आरा
98	चतरा	चतरा	बरैनी
99	चतरा	चतरा	दाढा
100	चतरा	चतरा	देवरिया
101	चतरा	चतरा	गंधरिया
102	चतरा	चतरा	मोकतमा
103	चतरा	चतरा	पाराडीह
104	चतरा	चतरा	सिकीद
105	चतरा	चतरा	सीमा
106	चतरा	चतरा	टीकर
107	चतरा	ईटखोरी	धनकेरी
108	चतरा	ईटखोरी	धुना
109	चतरा	ईटखोरी	हलमता
110	चतरा	ईटखोरी	ईटखोरी
111	चतरा	ईटखोरी	करनी
112	चतरा	ईटखोरी	कोनी
113	चतरा	ईटखोरी	मलकपुर
114	चतरा	ईटखोरी	नवाडीह
115	चतरा	ईटखोरी	परसौनी
116	चतरा	ईटखोरी	टोनाटाड.
117	सिमडेगा	सिमडेगा	अरानी
118	सिमडेगा	सिमडेगा	बंगरु
119	सिमडेगा	सिमडेगा	बडापरपानी
120	सिमडेगा	सिमडेगा	बीरु
121	सिमडेगा	सिमडेगा	गरजा
122	सिमडेगा	सिमडेगा	जोकबहार
123	सिमडेगा	सिमडेगा	कोचेडेगा
124	सिमडेगा	सिमडेगा	कुळलुकेरा
125	सिमडेगा	सिमडेगा	पिथरा

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
126	सिमडेगा	सिमडेगा	तमरा
127	सिमडेगा	कोलेबिरा	एगेडा
128	सिमडेगा	कोलेबिरा	अघरमा
129	सिमडेगा	कोलेबिरा	बंदरचुंआ
130	सिमडेगा	कोलेबिरा	बरसलोआ
131	सिमडेगा	कोलेबिरा	डोमटोली
132	सिमडेगा	कोलेबिरा	कोलेबिरा
133	सिमडेगा	कोलेबिरा	लचरागढ
134	सिमडेगा	कोलेबिरा	नावाटोली
135	सिमडेगा	कोलेबिरा	रैसिया
136	सिमडेगा	कोलेबिरा	शाहपुर
137	लातेहार	लातेहार	अरागुंडी
138	लातेहार	लातेहार	बेंदी
139	लातेहार	लातेहार	डेमु
140	लातेहार	लातेहार	धनकारा
141	लातेहार	लातेहार	हेथपोचरा
142	लातेहार	लातेहार	ईचाक
143	लातेहार	लातेहार	नावागढ
144	लातेहार	लातेहार	पेसरार
145	लातेहार	लातेहार	सांसग
146	लातेहार	लातेहार	शिशि
147	लातेहार	चंदवा	अलौदीया
148	लातेहार	चंदवा	बोदा
149	लातेहार	चंदवा	चकला
150	लातेहार	चंदवा	चंदवा पूर्वी
151	लातेहार	चंदवा	डुमारो
152	लातेहार	चंदवा	जमीरा
153	लातेहार	चंदवा	लाधुप
154	लातेहार	चंदवा	मलहान
155	लातेहार	चंदवा	सेरक
156	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बगबेरा पश्चिमी
157	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बयांगबील
158	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बेको
159	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	छोटा गोविन्दपुर उत्तर
160	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	छोटा गोविन्दपुर दक्षिण
161	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	घाघीडीह पूर्वी
162	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	हलुदबनी मध्य
163	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	हुरलुंग
164	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	केरूवाडुंगरी
165	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	किताडीह उत्तर
166	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	मऊभंडार उत्तर
167	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	कालचिती
168	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बरजुरी

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
169	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बघुरिया
170	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	महुलिया
171	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	उलदा
172	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	काराडुबा
173	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बनकारी
174	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	झांटीझरना
175	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	पाबरा

परिशिष्ट-2.24

(संदर्भित कंडिका 2.4.3: पृष्ठ - 127)

पंचायत भवनों के निर्माण एवं व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड	पंचायत भवनों के नाम	पूर्ण होने की देय तिथि	पूर्ण होने की तिथि	किया गया व्यय	विलम्ब महीनों मे
1	लोहरदगा	लोहरदगा	जोरी	30.09.08	25.11.09	1350000	14
2	लोहरदगा	कुडू	चांदलासो	31.12.10	05.05.11	2008846	04
3	लोहरदगा	कुडू	लावागांई	31.10.10	04/2011	1975800	06
4	लोहरदगा	कुडू	बडकीचापी	30.11.07	28.01.10	1620239	26
5	धनबाद	धनबाद	परसिया	31.03.09	08.10.10	1990700	18
6	धनबाद	धनबाद	बरडूबी	31.03.09	10.12.10	1990700	20
7	धनबाद	धनबाद	समशिखारा	30.03.09	10.12.10	1990700	20
8	धनबाद	धनबाद	डूबराजडीह	31.03.09	07.09.10	1990700	17
9	धनबाद	गोविंदपुर	नगर कियारी	31.08.10	25.03.12	1900000	18
10	धनबाद	गोविंदपुर	बारीयो	31.03.09	30.12.10	1990700	21
11	धनबाद	गोविंदपुर	कंचनपूर	31.03.09	25.01.10	1990700	10
12	देवघर	देवघर	शांकरी	27.09.10	06/2011	2096580	09
13	देवघर	देवघर	गिलूआचांदडीह	01/2010	07.08.10	2097273	06
14	देवघर	देवघर	खोरापनन	13.04.09	06.09.10	2090024	16
15	देवघर	देवघर	महतोडीह उदयपुरा	27.10.10	04.06.11	2065161	07
16	देवघर	देवघर	संग्राम लोधिया	21.03.11	08.08.11	1718971	05
17	देवघर	देवघर	पिचरीबाद	13.04.09	14.09.10	2087453	18
18	देवघर	पालोजोरी	बाधडीह	02.11.09	28.12.10	2097470	14
19	देवघर	पालोजोरी	बिराजपुर	31.10.08	07.01.09	1624000	02
20	देवघर	पालोजोरी	भुरकुन्डी	04/2009	11.01.10	2097500	08
21	देवघर	पालोजोरी	पहरूडीह	11.04.09	28.12.10	2097450	19
22	देवघर	मधुपुर	गोनिया	27.06.10	15.02.11	1883013	07
23	देवघर	मधुपुर	जमुनी	27.07.08	15.03.10	1623966	19
24	देवघर	मधुपुर	सिकटीया	13.04.09	15.02.10	2097500	09
25	देवघर	मधुपुर	डरवे	04/2009	10.10.09	2096716	05
26	देवघर	मधुपुर	जामागुडी	31.10.10	08.08.11	2180572	09
27	देवघर	मधुपुर	सुग्गापहाडी-2	31.12.10	05.03.12	2043168	14
28	देवघर	मधुपुर	पसिया	31.12.10	02.08.11	2177516	07
29	देवघर	मधुपुर	डलहा	19.03.11	07.02.12	2182200	11
30	देवघर	मधुपुर	सपतार	31.10.10	07.08.11	2178853	09
31	देवघर	मधुपुर	बरा नारायणपुर	31.12.10	31.07.11	2179185	07
32	जामताडा	जामताडा	गोपालपुर	24.03.10	20.10.10	2070100	10
33	जामताडा	जामताडा	सोनबाद	15.03.10	26.08.10	2066100	05
34	जामताडा	जामताडा	शहरडाल	07.08,10	12.08.11	2070100	12
35	जामताडा	जामताडा	बरजोरा	06.11.10	11.07.11	2070100	07
36	जामताडा	जामताडा	दखीनबहल	06.11.10	10.07.11	2070100	07

37	जामताडा	जामताडा	सुखजोरा	08.07.09	14.06.10	2059990	11
38	जामताडा	जामताडा	दुलादी	07.07.09	16.10.10	2070100	15
39	जामताडा	जामताडा	नवाडीह	10.08.09	26.03.10	2066730	07
40	जामताडा	जामताडा	पियासोला	06.11.10	05.11.11	2070100	19
41	जामताडा	नारायणपुर	बांकुडीह	08.04.09	09.03.10	2065161	10
42	जामताडा	नारायणपुर	पबिया	07.07.09	09.03.10	2065372	06
43	जामताडा	नारायणपुर	शहरपुरा	23.03.09	20.06.10	2070100	15
44	जामताडा	नारायणपुर	रुपडीह	10.08.09	20.06.10	1990700	10
45	जामताडा	नारायणपुर	टोपाटांड	20.08.10	20.05.11	2070100	09
46	जामताडा	नारायणपुर	दिघारी	08.07.09	06/2010	2070100	10
47	जामताडा	करमाताड	अलगचुंआ	20.09.10	10.02.11	2070100	05
48	जामताडा	करमाताड	बरमुंडी	30.06.10	10.01.11	2070100	06
49	सिमडेगा	सिमडेगा	अरानी	22.01.10	12.10.10	2003400	08
50	सिमडेगा	सिमडेगा	बंगरु	19.06.08	16.10.11	1624000	40
51	सिमडेगा	सिमडेगा	बडापरपानी	01.05.09	18.11.11	2003400	30
52	सिमडेगा	सिमडेगा	बीरु	31.12.09	02.09.10	2003400	08
53	सिमडेगा	सिमडेगा	गरजा	31.03.08	05.10.08	1624000	04
54	सिमडेगा	सिमडेगा	जोकबहार	20.04.11	29.10.11.	2066000	07
55	सिमडेगा	सिमडेगा	कोचेडेगा	10.06.08	28.08.11	1624000	38
56	सिमडेगा	सिमडेगा	कुळलुकेरा	02.10.10	15.04.11	2066000	06
57	सिमडेगा	सिमडेगा	पिथरा	31.03.08	05.10.08	1624000	06
58	सिमडेगा	सिमडेगा	तमरा	20.04.11	10.12.11	2048072	07
59	सिमडेगा	कोलेबिरा	एगेडा	30.04.09	05.03.11	1987918	22
60	लातेहार	लातेहार	अरागुंडी	11.02.09	10.09.11	1990700	31
61	लातेहार	लातेहार	हेथपोचरा	11.02.09	11.10.11	1990700	32
योग						**121254399**	

परिशिष्ट-2.25

(संदर्भित कंडिका 2.4.3: पृष्ठ - 127)

आठ चयनित जिलों में अपूर्ण पंचायत भवनों पर किये गए व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम.सं	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	व्यय 30 जून 2012 तक	पूर्ण होने की देय तिथि	विलम्ब महीनों मे जून 2012 तक
1	लोहरदगा	लोहरदगा	रामपुर	1060000	31.12.10	18
2	लोहरदगा	लोहरदगा	आरकोसा	1526175	31.11.10	19
3	लोहरदगा	लोहरदगा	भटखिजरी	1286000	30.12.10	18
4	लोहरदगा	लोहरदगा	हेसल	1646276	30.11.10	19
5	लोहरदगा	लोहरदगा	निगनी	1393515	31.12.10	18
6	लोहरदगा	लोहरदगा	जूरिया	1376064	31.12.10	18
7	लोहरदगा	लोहरदगा	बगहा	1707244	30.11.10	19
8	लोहरदगा	लोहरदगा	हिरही	1513786	30.11.10	19
9	लोहरदगा	लोहरदगा	मनहो	1595763	31.08.07	58
योग				**13104823**		
1	लोहरदगा	कुडू	जिंगी	1450772	31.10.10	18
2	लोहरदगा	कुडू	सुंदरु	1958425	30.11.10	19
3	लोहरदगा	कुडू	कोलसिमरी	1751209	30.11.10	19
4	लोहरदगा	कुडू	टाटी	1951630	20.11.10	17
5	लोहरदगा	कुडू	पंडरा	1282357	31.12.10	17
6	लोहरदगा	कुडू	काकरगढ	1917409	31.12.10	18
7	लोहरदगा	कुडू	सलगी	1068030	30.03.08	51
योग				**11379832**		
1	धनबाद	धनबाद	नावाडीह	998918	02.10.11	09
2	धनबाद	धनबाद	दामोदरपुर	850438	02.10.11	09
3	धनबाद	धनबाद	सियालगूदडडी.	582405	02.10.11	09
4	धनबाद	धनबाद	पेटिया	407268	02.10.11	09
5	धनबाद	धनबाद	अलगरिया	634443	02.10.11	09
6	धनबाद	धनबाद	ढोकरा	1398857	31.03.09	39
योग				**4872329**		
1	धनबाद	गोविंदपुर	बरवा पूर्वी	1527991	31.03.10	27
2	धनबाद	गोविंदपुर	गोविंदपुर पूर्वी	1204285	31.03.10	27
3	धनबाद	गोविंदपुर	बिराजपूर	1557609	09/2010	20
4	धनबाद	गोविंदपुर	खरनी	995705	31.03.10	27
5	धनबाद	गोविंदपुर	तिलैया	1624532	31.03.10	27
6	धनबाद	गोविंदपुर	डमकारा बरवा	796000	30.07.10	23
7	धनबाद	गोविंदपुर	पथूरिया	1600000	31.05.10	25

क्रम.सं	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	व्यय 30 जून 2012 तक	पूर्ण होने की देय तिथि	विलम्ब महीनों मे जून 2012 तक
योग				**9306122**		
1	देवघर	देवघर	सरसा	453456	05/2011	13
2	देवघर	देवघर	केनमनकाठी	477583	21.01.11	17
3	देवघर	देवघर	कोकरीबैंक	450764	05/2011	13
4	देवघर	देवघर	मासनजोर	988882	26.06.11	12
योग				**2370685**		
1	देवघर	पालोजोरी	महुआडाबर	656399	31.07.11	11
2	देवघर	पालोजोरी	बसहा	684925	31.07.11	11
3	देवघर	पालोजोरी	रघुआडीह	1867720	10/2010	19
4	देवघर	पालोजोरी	धावा	761935	31.07.11	11
5	देवघर	पालोजोरी	जमुआ	355000	31.05.11	13
6	देवघर	पालोजोरी	दुधानी	681641	31.05.11	13
7	देवघर	पालोजोरी	कुन्जबोना	435684	31.05.11	13
योग				**5443304**		
1	जामताडा	जामताडा	चन्द्रदीप	606571	25.05.11	13
योग				**606571**		
1	जामताडा	नारायणपुर	नारायणपुर	1132560	11.12.07	54
2	जामताडा	नारायणपुर	नयाडीह	644746	30.06.08	48
3	जामताडा	नारायणपुर	ढावाकेन्द्र	1337554	04.04.11	14
4	जामताडा	नारायणपुर	बुढूडीह	762445	12.06.08	54
5	जामताडा	नारायणपुर	नवाडीह	2069800	30.07.11	11
योग				**5947105**		
1	जामताडा	करमाताड	तारकोजोरी	518147	31.12.11	06
2	जामताडा	करमाताड	करमाताड	564947	21.12.11	06
योग				**1083094**		
1	सिमडेगा	कोलेबिरा	अघरमा	1449600	8.2.08	52
2	सिमडेगा	कोलेबिरा	बंदरचुंआ	1412375	3.8.08	46
3	सिमडेगा	कोलेबिरा	बरसलोआ	1176650	10.2.08	52
4	सिमडेगा	कोलेबिरा	डोमटोली	1190954	25.2.08	52
5	सिमडेगा	कोलेबिरा	कोलेबिरा	1353909	30.7.07	55
6	सिमडेगा	कोलेबिरा	लचरागढ	1161000	10.3.08	51
7	सिमडेगा	कोलेबिरा	नावाटोली	825995	31.3.08	51
8	सिमडेगा	कोलेबिरा	रैसिया	1308875	30.9.07	53
9	सिमडेगा	कोलेबिरा	शाहपुर	1184046	10.2.08	52
योग				**11063404**		
1	लातेहार	लातेहार	बेंदी	648124	16.6.10	24
2	लातेहार	लातेहार	डेमु	1318147	16.6.10	24

क्रम.सं	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	व्यय 30 जून 2012 तक	पूर्ण होने की देय तिथि	विलम्ब महीनों मे जून 2012 तक
3	लातेहार	लातेहार	धनकारा	1034113	16.6.10	24
4	लातेहार	लातेहार	पेसरार	00		
5	लातेहार	लातेहार	ईचाक	1485840	16.6.10	24
6	लातेहार	लातेहार	नावागढ	967031	16.6.10	24
7	लातेहार	लातेहार	सांसग	1487462	16.6.10	24
8	लातेहार	लातेहार	शिशि	452563	15.3.11	15
योग				**7393280**		
1	लातेहार	चंदवा	अलौदीया	899469	21.12.07	50
2	लातेहार	चंदवा	बोदा	1803484	11.2.09	40
3	लातेहार	चंदवा	चकला	1721925	11.2.09	40
4	लातेहार	चंदवा	चंदवा पूर्वी	869468	14.11.07	51
5	लातेहार	चंदवा	डुमारो	409925	16.6.10	24
6	लातेहार	चंदवा	जमीरा	505768	16.6.10	24
7	लातेहार	चंदवा	लाधुप	858533	21.12.07	50
8	लातेहार	चंदवा	मलहान	482212	15.3.11	15
9	लातेहार	चंदवा	सेरक	15000	12.7.10	23
योग				**7565784**		
1	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बगबेरा पश्चिमी	658034	15.1.11	17
2	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बयांगबील	1101209	30.6.11	12
3	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बेको	2179452	15.1.11	17
4	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	घाघीडीह पूर्वी	500000	31.3.12	03
5	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	हुरलुंग	540890	15.1.11	17
6	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	केरूवाडुंगरी	1454426	13.1.11	17
योग				**6434011**		
1	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	मऊभंडार उत्तर	1645240	31.10.09	30
2	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	कालचिती	1707944	30.11.10	19
3	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बरजुरी	1345352	30.6.11	12
4	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	काराडुबा	1000000	28.6.08	48
5	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बनकारी	200000	30.6.11	12
6	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	झांटीझरना	639100		
7	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बघुरिया	1471818	30.6.11	12
8	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	महुलिया	1017830	23.11.11	07
9	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	उलदा	1685715	5.1.11	18
योग				**10712999**		
1	चतरा	चतरा	आरा	1010000	6.1.11	18
2	चतरा	चतरा	बरैनी	965000	6.1.11	18

क्रम.सं	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	व्यय 30 जून 2012 तक	पूर्ण होने की देय तिथि	विलम्ब महीनों मे जून 2012 तक
3	चतरा	चतरा	दाढा	1472762	6.1.11	18
4	चतरा	चतरा	देवरिया	755000	6.1.11	18
5	चतरा	चतरा	गंधरिया	1330000	6.1.11	18
6	चतरा	चतरा	पाराडीह	00	6.1.11	18
7	चतरा	चतरा	मोकतमा	637000	6.1.11	18
8	चतरा	चतरा	सिकीद	914662	1.7.08	48
9	चतरा	चतरा	सीमा	938000	6.1.11	18
10	चतरा	चतरा	टीकर	593824	1.8.08	47
योग				**8616248**		
1	चतरा	ईटखोरी	धनकेरी	1312200	30.4.08	43
2	चतरा	ईटखोरी	हलमता	1053457	6.1.11	18
3	चतरा	ईटखोरी	ईटखोरी	1245291	31.1.08	53
4	चतरा	ईटखोरी	करनी	452464	7.10.10	32
5	चतरा	ईटखोरी	धुना	00	6.1.11	18
6	चतरा	ईटखोरी	कोनी	1832914	10.3.11	16
7	चतरा	ईटखोरी	मलकपुर	1724409	6.1.11	18
8	चतरा	ईटखोरी	परसौनी	1813662	6.6.11	13
9	चतरा	ईटखोरी	टोनाटाड.	1000000	6.1.11	18
योग				**10434397**		
कुल योग				**116333988**		

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भित कंडिका 3.1.5: पृष्ठ - 146)

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों का विवरण

क्रम संख्या	योजना	व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी / एजेंसी
1	एस.एस.ए.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
2	मध्याह्न भोजन	जिला शिक्षा अधीक्षक
3	रा.ग्रा.स्वा.मि.	जिला स्वास्थ्य समिति
4	समेंकित बाल विकास सेवाएं	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
5	एस.जी.एस.वाई.	जिला ग्रामिण विकास एजेंसी
6	इंदिरा आवास योजना	जिला ग्रामिण विकास एजेंसी
7	आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	अपर समहर्ता
8	एन.आर.डी.डब्लू.पी.	ई.ई, पेय जल एवं स्वच्छता प्रमण्डल
9	राज्य सड़क	ई.ई, सड़क निर्माण प्रमण्डल
10	प्रा.मं.ग्रा.सं.यो.	ई.ई, ग्रामीण कार्य प्रमंडल
11	रा.गॉ.ग्रा.वि.यो.	ई.ई, झा.रा.वि.बो.

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भित कंडिका 3.1.7.1: पृष्ठ - 149)

महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं / कार्यक्रमों के संबंध में निधि प्रवाह व्यवस्था

प्रक्षेत्र	योजना	निधि प्रवाह
सामाजिक	मनरेगा	भारत सरकार और झारखंड सरकार जिले में बनाए एक अलग बैंक खाता में मनरेगा निधि के अपने संबंधित शेयरों के हस्तांतरण करते है।. राज्य रोजगार गारंटी निधि (रा0रो0गां0नि0) वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक राज्य स्तर पर सेटअप नहीं हुए थे। आयुक्त, मनरेगा राज्य स्तर पर समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन और प्रतिवेदन के लिए जिम्मेदार है। जिला स्तर पर डीसी, जो पदेन जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) है ब्लॉक, पंचायतों और लाइन विभागों के बीच धन का आवंटन करते हैं ।
सामाजिक	एसएसए	भारत सरकार और झारखंड सरकार राज्य के खातों के बाहर राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी (एसआईएस) के बैंक खाते में सर्व शिक्षा अभियान के धन हस्तांतरण करते है।. एसआईएस एक राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) के नेतृत्व में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए झारखंड सरकार द्वारा गठित एक समाज है,. सर्व शिक्षा अभियान के वित्त नियंत्रक और वरिष्ठ वित्त अधिकारी राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के बैंक खाते में धनराशि की संयुक्त संरक्षक हैं. एसपीडी एस0आई0एस0 के भीतर प्रत्येक जिले के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्थापित सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम अधिकारी को हस्तांतरित निधियों का प्रशासक है. जिला स्तर पर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालयों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखा अधिकारी संयुक्त रूप से जिला में बैंक खाते के संरक्षक के रूप में कार्य करते है।
सामाजिक	एनआरएचएम	भारत सरकार और झारखंड सरकार राज्य सरकार के खाते के बाहर,राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी (एसएचएस) के बैंक खाते में एनआरएचएम के धन से अपने शेयर हस्तांतरण करते है। मिशन निदेशक और राज्य लेखा प्रबंधक, एनआरएचएम एसएचएस के बैंक खाते के संचालन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं. मिशन निदेशक निधि का व्यवस्थापक है. वे जिला स्वास्थ्य समिति के बैंक खाते में धन स्थानान्तरण करते है. सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी सचिव होते है, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और जिला लेखा प्रबंधक संयुक्त रूप से बैंक खाते का संचालन करते है।.
सामाजिक	एमडीएम	मध्याह्न भोजन योजना के भुगतान में चार घटक . (i) खाद्यान्न, (ii) खाद्यान का परिवहन (iii) खाद्यानों का भोजन में रूपांतरित लागत (iv)योजना का प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन शामिल है। भारत सरकार द्वारा निधि का हस्तांतरण खाद्यान्न–भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2010 तक के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सीधे खाद्यान्न की लागत प्रतिपूर्ति और अब यह सीधे झारखण्ड सरकार के बजट के माध्यम से किया जाता है. खाद्यान की परिवहन लागत: जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) झाखण्ड सरकार के बजट के माध्यम से ट्रांसपोर्टरों को सीधे प्रतिपूर्ति करती है।. रूपांतरित लागत और प्रबंधन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन: भारत सरकार झारखंड सरकार के बजट माध्यम से डी0एस0ई0 के लिए इन फंडों का हस्तान्तरण करते है। झारखंड सरकार की व्यवस्था: उपर्युक्त सभी चार घटकों की निकासी जिला स्तर पर झारखंड सरकार के बजट के माध्यम से डीएसई करते हैं।
सामाजिक	आईएवाई	भारत सरकार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को सीधे अपने शेयर हस्तान्तरण करता है।. झारखण्ड सरकार का हिस्सा राजकोष से डीआरडीए द्वारा निकासी की जाती है। दोनों एक ही बैंक खाते में रखा जाता है. डीडीसी,डीआरडीए बैंक खाता संचालित करते है और निधि के व्यवस्थापक है. वे योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के माध्यम से लाभार्थी के खातों में निधि स्थानान्तरण करते है।
सामाजिक	टीएससी	भारत सरकार प्रत्येक जिले में, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के बैंक खाते में सीधे अपने हिस्से हस्तान्तरण करते है . मिशन के पदेन सचिव जो मिशन के निदेशक है, झारखंड सरकार से प्राप्त आवंटन के आधार पर जिला कोषागार से निकासी करते है और मिशन के बैंक खाते में रखते है।
आर्थिक	पीएमजीएसवाई	एक स्वायत एजेंसी के रूप में स्थापित (2004) झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से फण्ड प्राप्त कर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों को फण्ड उपलब्ध कराती है।

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भित कंडिका 3.1.8.2: पृष्ठ - 151)

मार्च2012 में डीआईएसई के आंकड़ों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात

क्रम सं	प्रखण्ड का नाम	नामांकन	शिक्षक	अनुपात
1	विश्रामपुर	21343	402	53
2	चैनपुर	52115	889	58.62
3	छतरपुर	39483	809	48.80
4	**मेदिनीनगर**	**25575**	**680**	**37.61 (38)**
5	हैदरनगर	16980	330	51.45
6	हरिहरगंज	18681	319	58.56
7	**हुसैनाबाद**	**36022**	**632**	**60**
8	लेस्लीगंज	23807	465	51.19
9	मनातु	13281	242	55
10	मूहम्मदगंज	9852	169	58.29
11	नवा बजार	12138	207	58.64
12	नवाडीह बजार	26019	539	48.27
13	पांडु	15047	262	57.43
14	पांडवा	10763	226	47.62
15	**पांकी**	**43395**	**722**	**60.10**
16	पाटन	31329	537	58.34
17	**पीपरा**	**11396**	**190**	**59.98 (60)**
18	सतबरवा	18519	328	56.46
19	तरहसी	19025	355	53.59
20	उँटारी रोड	7927	137	57.86

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भित कंडिका 3.1.8.4: पृष्ठ - 153)

विद्यालयों में मौलिक सुविधाओं का विवरण

क्रम संख्या	प्रखण्ड	विद्यालयों की कुल संख्या	बिना पेयजल सुविधा के विद्यालय	बिना शौचालय सुविधा के विद्यालय	बिना बालिका शौचालय सुविधा के विद्यालय	बिना रैम्प सुविधा के विद्यालय	बिना चारदिवारी के विद्यालय	बिना विद्युत सुविधा के विद्यालय
1	सदर (यू)	175	28 (16)	148 (85)	122(70)	120(69)	121(69)	165(94)
2	चैनपुर(आर)	303	35(12)	245 (81)	202(67)	213(70)	272(90)	295(97)
3	सतबरवा (आर)	135	17(15)	105(78)	79(59)	94(70)	111(82)	132(98)
4	लेस्लीगंज(आर)	166	10(6)	136(82)	103(62)	142(86)	144(87)	166(100)
5	पांकी(आर)	289	20(7)	260(90)	156(54)	272(94)	261(90)	285(99)
6	मनातु(आर)	92	06(7)	81(88)	51(55)	57(62)	83(90)	92(100)
7	पाटन(आर)	194	15(8)	166(86)	119(61)	103(53)	175(90)	190(98)
8	विश्रामपुर(आर)	118	03(3)	90(76)	67(57)	106(90)	95(81)	113(96)
9	पांडु(आर)	73	10(14)	63(86)	48(66)	58(79)	70(96)	71(97)
10	छतरपुर(आर)	241	23(10)	199(83)	176(73)	229(95)	191(79)	238(99)
11	हरिहरगंज(आर)	86	01(1)	80(93)	41(48)	51(59)	73(85)	84(98)
12	हुसैनाबाद(यू)	168	13(8)	154(92)	130(77)	95(57)	144(86)	161(96)
13	हैदरनगर(आर)	63	08(13)	48(76)	33(52)	36(57)	55(87)	63(100)
14	मोहम्मदगंज(आर)	40	07(18)	31(78)	24(60)	26(65)	34(85)	40(100)
15	पीपरा(आर)	61	04(7)	46(75)	46(75)	42(69)	56(92)	61(100)
16	नवा बाजार(आर)	69	09(13)	56(81)	37(54)	57(83)	59(86)	66(96)
17	पांडवा (आर)	56	01(2)	47(84)	23(41)	38(68)	47(84)	55(98)
18	नवाडीह बाजार (आर)	170	15(9)	149(88)	106(62)	168(99)	143(84)	168(99)
19	उँटारी रोड (आर)	40	03(8)	32(80)	33(83)	35(88)	32(80)	37(93)
20	तरहसी (आर)	117	09(8)	100(85)	63(54)	77(66)	104(89)	117(100)
मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं (प्रतिशत)		**2656**	**237** *(9)*	**2236** *(84)*	**1659** *(62)*	**2019** *(70)*	**2270** *(85)*	**2599** *(98)*
मौलिक सुविधाएं उपलब्ध (प्रतिशत)			**2419** *(91)*	**420** *(16)*	**997** *(38)*	**637** *(30)*	**386** *(15)*	**56** *(02)*

स्रोत: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एसएसए पलामू - कोष्टक में दर्शाई गई संख्या प्रतिशत में।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भित कंडिका 3.1.10.3: पृष्ठ - 160)

मूलभूत उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा सुविधा की विवरणी

विविध	सीएच सी	पीएच सी	एचएस सी	अनुमंडल अस्पताल	सदर अस्पताल
कुल स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या	10	21	171	02	01
रक्त संग्रह की सुविधा	02	0	0	02	01
नवजात शिशु देखभाल की सुविधा	08	0	0	02	01
24 X 7 सेवा की सुविधा	08	10	35	02	01
अंत:रोगी सेवा की सुविधा	08	10	0	02	01
एक्स-रे की सुविधा	02	0	0	01	01
अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा	0	0	0	0	01
ईसीजी की सुविधा	0	0	0	0	01
प्रसव देखभाल की सुविधा	0	0	0	01	01
24 घंटे आकस्मिक सेवा की सुविधा	08	10	0	02	01
परिवार नियोजन की सुविधा (ट्यूबकटोमि एवं भासेकटोमि)	01	0	0	02	01
गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की देखभाल की सुविधा	01	0	0	0	01
शिशुरोग विशेषज्ञों की सुविधा	01	0	0	01	01
शल्य कक्ष की सुविधा	08	0	0	02	01
प्रसवगृह की सुविधा	08	10	35	02	01
मुफ्त दवाई की सुविधा	08	0	0	02	01
बाधा रहित विद्यत प्रवाह की सुविधा	08	0	0	02	01
किराये की भवन में चल रहे केंद्रों की संख्या	0	0	99	0	0
स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की संख्या	06	02	01	06	100
24 घंटे जलापूर्ति की सुविधा	08	10	0	0	0

नोट :- उपरोक्त वर्णित सुविधाएँ आईपीएचएस के अनुसार सभी सीएचसी में रहना अनिवार्य।

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भित कंडिका 3.1.10.4: पृष्ठ - 161)

एन0आर0एच0एम0 के अंतर्गत जिला में स्वीकृत बल (स) पदस्थापन (प) की स्थिति की विवरणी

	नियमित चिकित्सक			एएनएम			लैब तकनिशियन			एक्स-रे तकनिशियन			स्टाफ नर्स			फॉर्माशिस्ट			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता		
	स	प	र	स	प	र	स	प	र	स	प	र	स	प	र	स	प	र	स	प	र
जिलास्तर	26	20	06	6	4	2	3	1	2	2	2	0	8	8	0	2	2	0	0	0	0
सीएचसी स्तर	41	30	11	45	23	22	10	0	10	0	0	0	2	0	2*	10	1	9	20	7	13
पीएचसी स्तर	42	22	20	42	16	26	4	0	4	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0	0	0
एचएससी स्तर	0	0	0	146	78	68*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**109**	**72**	**37(34)**	**239**	**121**	**118(49)**	**17**	**1**	**16(94)**	**2**	**2**	**0**	**10**	**8**	**2(20)**	**33**	**3**	**30(91)**	**20**	**7**	**13(65)**

कुल स्वीकृत पद- 430

कार्यरत -214

रिक्ति -216 (50 प्रतिशत)

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भित कंडिका 3.1.13: पृष्ठ - 171)

आईएवाई आवास निर्माण की भौतिक उपलब्धि

श्रेणी	वर्ष	विगत वर्षों की अपूर्ण आवास	निमार्ण के लिए ली गई योजना	कुल आवास	अपूर्ण आवास (प्रतिशत)
सामान्य	2009-10	2622	5550	8172	6462 *(79)*
	2010-11	6462	10433	16895	10597 *(63)*
	2011-12	10597	3817	14414	4780 *(33)*
उत्क्रमित	2009-10	1448	1266	2714	1431 *(53)*
	2010-11	1431	शून्य	1431	शून्य
	2011-12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नक्सल प्रभावित सामान्य	2009-10	शून्य	7553	7553	7054 *(93)*
	2010-11	7054	शून्य	7054	377 *(5)*
	2011-12	377	शून्य	377	377 *(100)*
नक्सल प्रभावित उत्क्रमित	2009-10	शून्य	4406	4406	4302 *(98)*
	2010-11	4302	शून्य	4302	154 *(4)*
	2011-12	154	शून्य	154	154 *(100)*

स्रोत: डीआरडीए पलामू का अभिलेख

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भित कंडिका 3.1.14: पृष्ठ - 172)

अन्नपूर्णा,बीपीएल,एएवाई एवं अतिरिक्त बीपीएल योजना के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) द्वारा कम दर्शाए गये खाद्यान की विवरणी

(क्विंटल में)

योजना का नाम	वर्ष	खाद्यान के नाम	एफपीएस को एसएफसी द्वारा वास्तविक रूप से जारी की गई अनाज	एमओ द्वारा संधारित एफपीएस को वास्तविक प्राप्त अनाज	एफपीएस द्वारा कम प्राप्ति	न्यून्तम मूल्य	राशि ``₹ में
अन्नपूर्णा	2009-10	चावल	12416.64	10402.50	2014.14	2088	4205524
	2011-12	चावल	5752.55	4184.40	1568.15	2088	3274297
बीपीएल	2009-10	चावल	199037.85	173791.99	25245.86	2088	52713356
	2010-11	चावल	246590.57	219918.72	26671.85	2088	55690822
	2011-12	चावल	273690.23	264521.98	9168.25	2088	19143306
	2009-10	गेंहू	73020.25	66889.83	6130.42	1526	9355020
	2010-11	गेंहू	25574.50	23137.20	2437.30	1526	3719320
एएवाई	2009-10	चावल	121102.87	106461.74	14641.13	2088	30570679
	2009-10	गेंहू	76782.19	69881.04	6901.15	1526	10531155
	2010-11	गेंहू	30411.20	25766.80	4644.22	1526	7087080
	2010-11	चावल	187320.85	162460.73	24860.12	2088	51907930
अतिरिक्त बीपीएल	2010-11	चावल	57687.72	57110.40	577.32	2088	1205444
	2011-12	चावल	309827.18	213926.00	95901.18	2088	200241664
कुल							**44.96 करोड़**

(क्विंटल में)

अनाज	एसएफसी द्वारा वास्तविक रूप से एफपीएस को जारी	एमओ द्वारा संधारित एफपीएस को वास्तविक प्राप्त अनाज	एफपीएस द्वारा कम प्राप्ति
चावल	**1413426.46**	**1212778.46**	**200648.00**
गेंहू	**205788.14**	**185674.87**	**20113.27**

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भित कंडिका 3.1.18.1: पृष्ठ - 179)

पीएमजीएसवाई सड़क के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत सड़क			पूर्ण सड़क			अपूर्ण सड़क			ग्रामीण बस्तियॉ जिन्हें जोड़ना था	
	सड़क की संख्या	लम्बाई (किमी)	करार मूल्य	सड़क की संख्या	लम्बाई (किमी)	व्यय	सड़क की संख्या	लम्बाई (किमी)	व्यय	1000 से उपर	1000 से नीचे
2000-09	86	385.66	90.21	63	264.38	63.78	23	114.38	15.69	210	12
2009-10	90	279.15	77.14	27	87.30	22.25	63	191.85	31.21	0	177
2010-11	35	160.46	43.39	12	44.50	10.10	23	115.96	11.38	92	0
2011-12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**125**	**439.61**	**120.53**	**39**	**131.80**	**32.35**	**86**	**307.81**	**42.59**	**92**	**177**

स्रोत: आरडब्लूडी डिविजन, मेदिनीनगर एवं जेएसआरआरडीए

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भित कंडिका 3.1.20.7: पृष्ठ - 187)

31 मार्च 2012 को स्वीकृत एवं कार्यरत बल की स्थिति की विवरणी

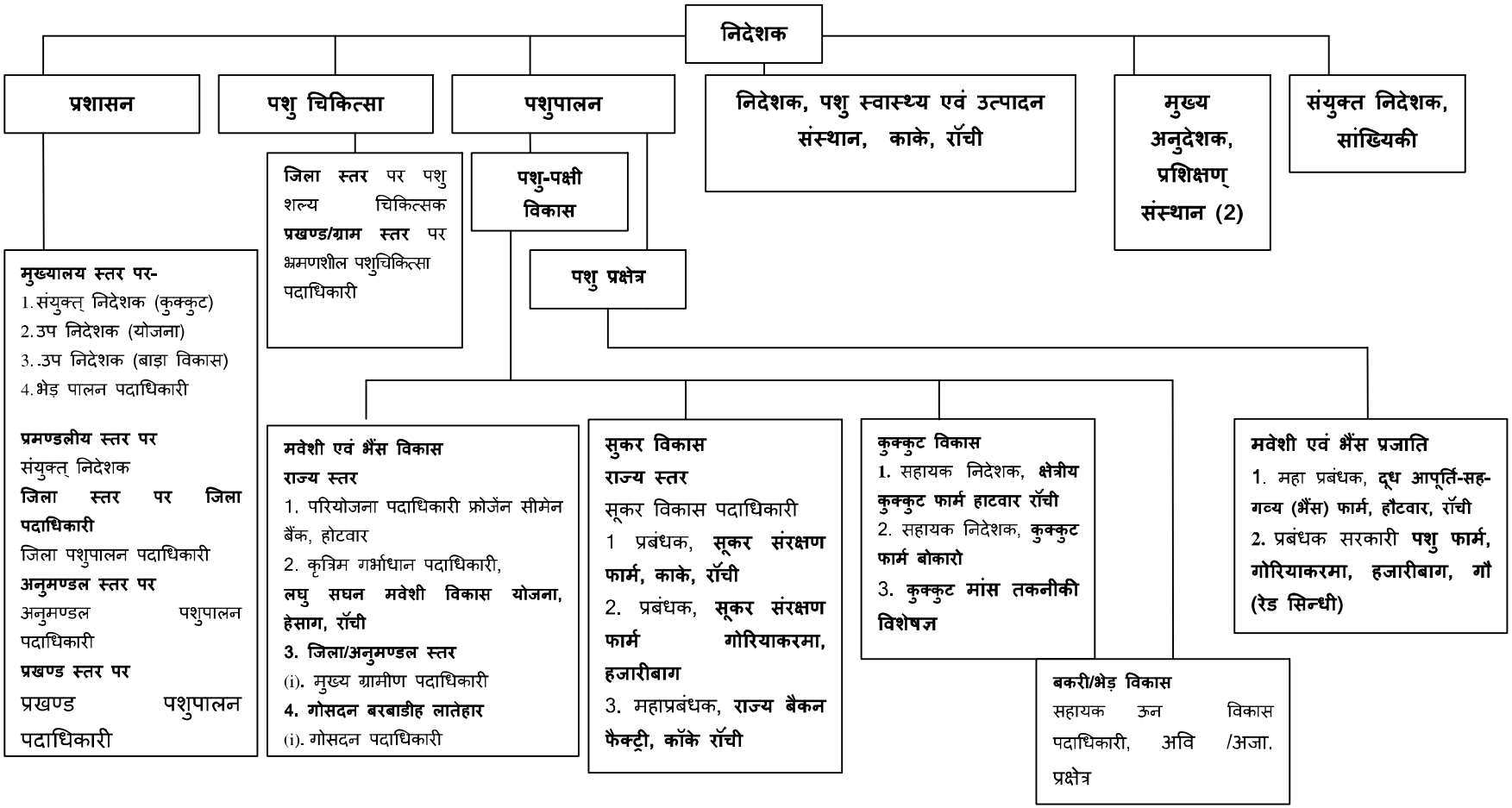
		अप्रैल 2009 की स्थिति			31 मार्च 2012 की स्थिति			
पदाधिकारी संवर्ग								
कैडर	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी प्रतिशत में	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी प्रतिशत में
पुलिस अधीक्षक	1	1	00	00	1	1	00	00
पुलिस उपाधीक्षक	4	4	00	00	4	02	02	50
निरीक्षक	6	5	01	17	7	7	00	00
उपनिरीक्षक	98	62	36	37	142	79	63	44
सहायक उपनिरीक्षक	141	98	43	30	195	176	19	10
प्रवर परिचारी	1	1	00	00	1	1	00	00
परिचारी	2	1	01	50	2	0	02	100
आरक्षी संवर्ग								
हवलदार	366	216	150	41	426	241	185	43
सिपाही	1652	1357	295	18	1892	1710	182	10
चालक	90	44	46	51	150	88	62	41

स्रोत: कार्यालय पुलिस अधीक्षक , पलामू

परिशिष्ट -4.1

(संदर्भित कंडिका 4.1.2: पृष्ठ - 193)

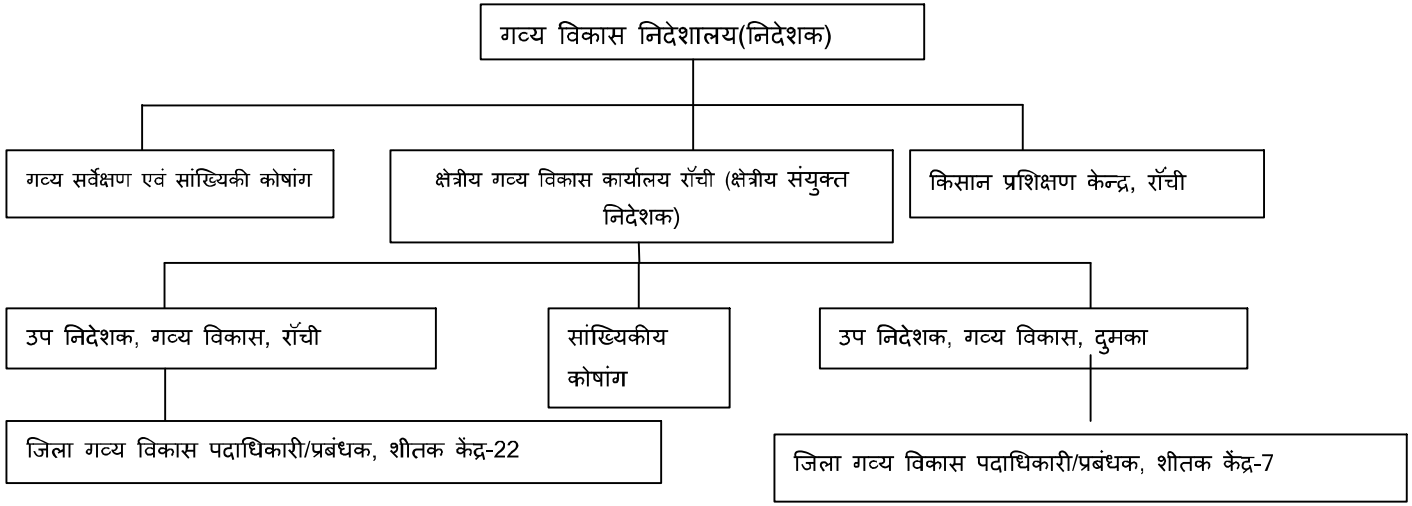
पशुपालन निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ाँचा



परिशिष्ट 4.2

(संदर्भित कंडिका 4.1.2: पृष्ठ - 193)

गव्य विकास निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ाँचा



परिशिष्ट 4.3

(संदर्भित कंडिका 4.1.7.1: पृष्ठ - 196)

(अ) प. स्वा. एवं उ. सं., कांके रॉची द्वारा विभिन्न टीकाओं के उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य (लाख डोज)						उपलब्धि (लाख डोज)						
	एचएस	बी क्यू	एन्थ्रैक्स	आर डी	एस एफ	कुल	एचएस	बी क्यू	एन्थ्रैक्स	आर डी	एस एफ	कुल	प्रतिशत
2007-08	16	11	2	25	0.1	54.10	3.199	4.665	शून्य	शून्य	शून्य	7.86	14.53
2008-09	16	11	2	25	0.1	54.10	1.84	1.14	शून्य	शून्य	शून्य	2.98	5.51
2009-20	16	11	2	25	0.1	54.10	4.951	2.27	शून्य	शून्य	शून्य	7.22	13.35
2010-11	16	11	2	25	0.1	54.10	6.04	5.17	2.00	शून्य	शून्य	13.21	24.42
2011-12	16	11	2	5	0.5	34.50	6.516	6.59	2.50	शून्य	शून्य	15.60	45.22

(स्रोत: प. स्वा. एवं उ. संस्थान कांके)

(ब) टीकाकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

वर्ष	लक्ष्य (लाख डोज)						उपलब्धि (लाख डोज)					
	एचएस	बी क्यू	एन्थ्रैक्स	आर डी	एस एफ	कुल	एचएस	बी क्यू	एन्थ्रैक्स	आर डी	एस एफ	कुल
2007-08	10	10	शून्य	5	0.5	25.5	4.37	3.19	शून्य	शून्य	0.05	7.61
2008-09	10	10	शून्य	5	0.5	25.5	9.21	8.79	शून्य	शून्य	0.05	18.05
2009-10	10	10	शून्य	5	0.5	25.5	5.09	6.54	0.99	1.39	0.01	14.02
2010-11	10	10	शून्य	5	0.5	25.5	7.64	4.64	0.98	0.54	शून्य	13.80
2011-12	15	10	2	5	0.5	32.5	6.51	6.59	2.50	1.00	शून्य	16.60

(स्रोत:पशुपालन निदेशालय)

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भित कंडिका 4.1.7.2: पृष्ठ - 201)

स्वीकृत एवं कार्यरत बल की विवरणी

(अ) पशुपालन निदेशालय

वर्गीकृत पद	राज्य स्तर			नमना जॉचित जिले		
	स्वीकृत	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत्)	स्वीकृत	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत्)
राजपत्रित (वर्ग- II) पशु चिकित्सक	773	524	249(32)	296	218	78 (26)
अराजपत्रित (वर्ग- III)	1362	590	772(57)	525	206	319(61)
अराजपत्रित (वर्ग- IV)	1453	1197	256(18)	484	418	66(14)
कुल	**3588**	**2311**	**1277(36)**	**1305**	**842**	**463(35)**

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग

(ब) गव्य विकास निदेशालय

वर्गीकृत पद	राज्य स्तर			नमूना- जॉचित जिले		
	स्वीकृत	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत्)	स्वीकृत	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत्)
तकनीकी पदाधिकारी एवं कर्मचारी	160	84	76 (48)	49	23	26 (53)
गैर तकनीकी पदाधिकारी एवं कर्मचारी	136	98	38 (28)	38	21	17 (45)
कुल	**296**	**182**	**114 (39)**	**87**	**44**	**43(49)**

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग, झारखण्ड सरकार

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भित कंडिका 4.1.9: पृष्ठ - 205)

पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत योजनाओं का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	योजना	इकाई लागत ₹	आवंटन (करोड़ ₹ में)	व्यय (₹ करोड़ में)	उद्देश्य
बकरा विकास योजना						
2007-08	बकरी पालको के स्वयं सहायता समूहों के संरचना का सृजन	राज्य योजना	27,130	1.02	0.89	दुमका एवम् रॉची जिलों के बकरी पालकों के स्वयं सहायता समूह को आधारभूत संरचना (375इकाई) की उपलब्धता
2008-09	10 ब्लैक बंगाल बकरियों एवं एक उन्नत नस्ल का बकरा	रा.कृ.वि.यो.	60000	3.65	3.63	बकरा विकास हेतु राज्य में उन्नत नस्ल के बकरा इकाईयों (687) का वितरण
2009-10	10 स्थानीय बकरियॉ एवं एक ब्लैक बंगाल बकरा	रा.कृ.वि.यो.	18000 और 1100 प्रशिक्षाण एवं अनुश्रवण के लिए	0.42	0.33	उन्नत नस्ल के बकरों का पुन: उत्पादन जिससे लाभुकों को ₹ 18,600 प्रतिवर्ष की कमाई हो
2011-12	पॉच ब्लेक बंगाल बकरियों एवं एक ब्लेक बंगाल बकरा राज्य योजना के अंतर्गत	राज्य योजना	22500 और प्रचार प्रसार हेतु 800	4.40	3.83	उन्नत नस्ल की बकरियों का उत्पादन (`₹ 11,694 प्रथम वर्ष और ₹ 40,929 दूसरे वर्ष)
कुक्कुट विकास योजना						
2008-09	बैकयार्ड पौल्ट्री योजना (60 मुर्गी की इकाई)	रा.कृ.वि.यो.	8,000	3.40	3.38	गॉव में अण्डों एवं कुक्कुट मांस के उत्पादन में वृद्धि के साथ कमजोर वर्ग के प्रत्येक लाभुकों को (4793 ईकाई) वार्षिक अनुमानित ₹ 0.17 लाख की आमदनी
2010-11	400 ब्रायलर मुर्गियों की इकाई का अनियोजित ग्रामीण महिलाओं में वितरण	रा.कृ.वि.यो.	86,000	1.61	1.03	प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता एवं ग्रामीणों के आर्थिक हालत में सुधार के साथ 250 इकाईयों की स्थापना द्वारा ₹ 0.43 लाख प्रतिवर्ष की आमदनी
2011-12	-वही-	रा.कृ.वि.यो.	86,000	3.27	3.04	प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता एवं ग्रामीणों के आर्थिक हालत में सुधार के साथ 760 पालटरी इकाई इकाईयों की स्थापना द्वारा ₹ 0.43 लाख प्रतिवर्ष की आमदनी

सूकर विकास योजना						
2009-10	सूकर विकास योजना उन्नत नस्ल के पुन: उत्पादित सूकर इकाईयों का वितरण	रा.कृ.वि.यो.	30,000 (2नर + 4 मादा)	1.50	1.09	सूकर पालकों एवं सूकर पालन हेतु प्रशिक्षित लाभुकों के बीच टी एण्ड डी नस्ल की सूकर इकाईयों (1006) का वितरण जिसका अनुमानित लाभ ₹ 0.23 लाख प्रतिवर्ष
2010-11	-वही-	रा.कृ.वि.यो.	40,000 (2 नर + 4 मादा) 71,000 (5 नर + 8 मादा) 40,000 (तीन सूकर शेड)	1.80	1.64	-वही- (2नर + 4मादा इकाई के लिए 317, 5नर +8मादा इकाई के लिए 122 और सूकर शेड के लिए 115) लाभ (2 नर + 4 मादा इकाई से ₹ 0.27 लाख, 5 नर + 8 मादा इकाई से ₹ 0.66 लाख और शेड निर्माण इकाई से लाभ आकलित नहीं किया गया)
2011-12	-वही-	रा.कृ.वि.यो.	27,500 (2 नर + 4 मादा)	3.16	2.13	सूकर पालकों या सूकर पालन हेतु प्रशिक्षित लाभुकों के बीच टी एण्ड डी नस्ल की सूकर इकाईयों(1294) का वितरण- अनुमानित 25,880 सूकर बच्चों का प्रथम वर्ष के अंत में उत्पादन

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.6 : पृष्ठ - 218)

दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम के प्राक्कलित राशि का विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	दो गाय योजना				मिनी डेयरी (पॉच गाय)				मिनी डेयरी (दस गाय)			
	इकाई लागत	अनुदान			इकाई लागत	अनुदान			इकाई लागत	अनुदान		
		कुल	फेज I	फेज II		कुल	फेज I	फेज II		कुल	फेज I	फेज II
2007-08	48910	24460	13530	10930	140825	35225	24475	10750				
2008-09	72000	36000	22750	13250	184000	92000	62000	30000				
2009-10	67000	33500	20250	13250	174000	69600	48100	21500	350000	115500	70950	44550
2010-12	80760	40380	23690	16690	208400	104200	70520	33680	418800	167520	99760	67760

(राशि ₹ में)

वर्ष	कामर्शियल डेयरी (20 गाय)				मॉडर्न डेयरी (50 गाय)				मॉडर्न डेयरी (100 गाय)			
	इकाई लागत	अनुदान			इकाई लागत	अनुदान			इकाई लागत फेज I	अनुदान		
		कुल	फेज I	फेज II		कुल	फेज I	फेज II		कुल	फेज I	फेज II
2007-08	561340	112268	69344	42924								
2008-09	715000	178750	111250	67500					5450000	1090000	820000	270000
2009-10	700000	175000	107500	67500					5450000	1090000	820000	270000
2010-12	837600	209400	124700	84700	2269000	453800	284400	169400				

स्रोत: गव्य विकास निदेशालय

परिशिष्ट 4.7

***(संदर्भित कंडिका 4.1.9.6: पृष्ठ* - 218)**

पशु वितरण योजना की स्थिति का विवरण

(संख्या इकाई में)

वर्ष	दो गाय			मिनी डेयरी			मिनी डेयरी			कामर्शियल डेयरी			मॉर्डन डेयरी (50 गाय)			मॉर्डन डेयरी (100 गाय)		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
		फेज I	फेज II		फेज I	फेज II		फेज I	फेज II		फेज I	फेज II		फेज I	फेज II		फेज I	फेज II
2007-08	1067	973	850	96	88	74	-	-	-	28	28	25	-	-	-	-	-	-
2008-09	859	724	486	100	99	85	-	-	-	58	53	41	-	-	-	9	8	7
2009-10	192	192	192	275	261	214	59	56	40	25	23	19	-	-	-	-	-	-
2010-11	575	538	346	229	208	163	72	64	54	24	21	14	2	2	1	-	-	-
कुल	**2693**	**2427**	**1874**	**700**	**656**	**536**	**131**	**120**	**94**	**135**	**125**	**99**	**2**	**2**	**1**	**9**	**8**	**7**

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		कमी	
	फेज I	फेज II	फेज I	फेज II	फेज I	फेज II
2007-08	1191	1191	1089	949	102	242
2008-09	1026	1026	884	619	142	407
2009-10	551	551	532	465	19	86
2010-11	902	902	833	578	69	324
कुल	**3670**	**3670**	**3338**	**2611**	**332**	**1059**

स्रोत: नमूना -जॉचित जिले

परिशिष्ट 4.8

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.9: पृष्ठ -222)

झारखण्ड डेयरी परियोजना के प्रगामी लक्ष्य एवं उपलब्धि

विवरण	इकाई	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
आच्छादित होने वाले गॉव	संख्या	130	00	360	111	580	242	850	292
आच्छादित होने वाले दुग्ध उत्पादक	संख्या.	4600	00	11800	715	20850	1368	32450	2212
आच्छादित होने वाले गॉवों में कुल दुग्ध संग्रहण	एलपीडी	8000	00	21000	2500	40000	4230	65000	7330
दूध की बिक्री	एलपीडी	8000	00	21000	1450	36000	2260	58000	5020
दही की बिक्री	एलपीडी	0	00	00	00	4000	00	7000	30
घी की बिक्री	एमटी	11	00	40	00	74	00	129	00

स्रोत: गव्य विकास निदेशालय टिप्पणी :एलपीडी लीटर प्रतिदिन।

परिशिष्ट 4.9

(संदर्भित कंडिका 4.1.10 पृष्ठ - 223)

संयुक्त क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा निरीक्षण का विवरण

जिला	स्थापित डेयरी इकाईयों की संख्या			कॉमर्शियल एवं मार्डन डायरी इकाई की संख्या		योजनाओं का आर. जे. डी द्वारा निरीक्षण		टिप्पणी
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	आवश्यक	किया गया	
बोकारो	06	61	27	02	शून्य	10	2	2009-10 में एक बार और 2011-12 में एक बार.
धनबाद	173	104	50	04	03	10	1	2009-10 में कॉमर्शियल डेयरी का एक बार
दुमका	उपलब्ध नहीं	145	20	01	शून्य	10	1	2008-09 के कामर्शियल डेयरी 2009-10 में एक बार
गुमला	04	46	12	01	शून्य	10	1	2008-11 के सभी कॉमर्शियल डेयरी 2010-11 में एक बार
पूर्वी सिंहभूम	227	182	29	02	01	10	1	कॉमर्शियल एवं मोर्डन डेयरी के लिए 2008-09 में एक बार
लातेहार	164	35	16	शून्य	शून्य	10	1	2008-09 में एक बार
रॉची	515	182	317	09	07	10	उपलब्ध नहीं	निरिक्षण किया गया लेकिन कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं किया गया।
देवघर	129	129	55	04	शून्य	10	उपलब्ध नहीं	

स्रोत: नमूना-जाँचित जिले।

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भित कंडिका: 5.1.3; पृष्ठ - 233)

ग्रामीण कार्य प्रमंडल गढवा के लम्बित अस्थाई अग्रिमों की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रमांक	नाम/सुत्री/त्री	पदनाम	लम्बित अग्रिम राशि	अग्रिमो के अनुमोदन की तिथि/समयावधि (अग्रिमों की संख्या)	अनुमोदित अग्रिम का उद्देश्य	अधिकारियों की वर्तमान स्थिति	अप्रैल 2011 को लंबित अग्रिम की समयावधि	मार्च 2013 तक शेष प्राप्य
1	सुखराम प्रसाद	स. अ.	1054391	जुन 2010 से मार्च 2011 (11 अदद)	मनरेगा, सांसद कोष	31 जूलाई 2011 को सेवा निवृत	8 से 17 माह	95319
2	स्व एस एन सिहं	स. अ.	2611407	फरवरी 2008 से मार्च 2010 (23 अदद)	मनरेगा, स्वास्थ्य सांसद कोष, एस.एस.जे.एस.भी.वाई, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना,	अगस्त 2010 को देहांत	20 से 45 माह	1474810
3	डीबी शर्मा	स. अ.	1834352	फरवरी 2007 से मार्च 2010 (29 अदद)	मनरेगा, जिला योजना, विधायक कोष, सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना, एस.एस.जे.एस.भी.वाई, मुख्यमंत्री वि. योजना सांसद कोष	जुलाई 2010 मे स्थानांतरण	20 से 57 माह	0
4	कमलेश कुमार	स. अ.	145858	जुन 2009 से अगस्त 2009 (02 अदद)	कार्य आरोपित भुगतान	अगस्त 2009 में स्थानांतरण	27 से 29 माह	145858
कुल			**5646008**					**1715807**

स अ-सहायक अभियंता, **एम. जी. एन. आर. ई. जी. एस.**-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, **एम.एल.ए. कोष**-विधायक कोष, **एम.पी.कोष**- सांसद कोष, **एम. एम. वी. वाई.**- मुख्यमंत्री विकास योजना, **एन. एफ. एफ. डब्लु. पी.**- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना **एस.एस.जे.एस.भी.वाई.** सुनिश्चित स्वर्ण जयंती एवं समविकास योजना

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भित कंडिका: 5.1.3; पृष्ठ - 233)

ग्रामीण विशेष कार्य प्रमंडल (आर.डी.एस.) गुमला के लम्बित अस्थाई अग्रिमों का ब्यौरा

(राशि ₹ में)

क्रमांक	नाम/सुत्री/त्री	पदनाम	लम्बित अग्रिम राशि (₹ लाख में)	अग्रिमो के अनुमोदन की तिथि/समयावधि (अग्रिमों की संख्या)	अनुमोदित अग्रिम का उद्देश्य	अधिकारियों की वर्तमान स्थिति	अप्रैल 2010 को लंबित अग्रिम की समयावधि	मार्च 2013 तक शेष प्राप्य
1	उमेश प्र. सिन्हा	क.अ.	908182	अप्रैल 2005 से जुन 2007 (32 अदद)	एन एफ एफ डब्ल्यू पी, एम एम वाई, एम एल ए, एस.एस.जे.एस.भी.वाई, मनरेगा	आर डी एस डी हजारीबाग में प्रतिनियुक्त	34 से 60 माह	908182
2	श्रध्दानंद सिहं	क.अ.	383770	फरवरी 2008 से मई 2009 (10 अदद)	मनरेगा	आर ई ओ गुमला	11 से 26 माह	0
3	रामेश्वर सिंह	क.अ.	73312	अप्रैल 2005 से फरवरी 2010 (34अदद)	आर एस वी वाई, एन एफ एफ डब्लू पी मनरेगा	वर्तमान	2 से 60 माह	0
4	बनारसी प्र. सिहं	क.अ.	145691	मई 2005 से जुलाई 2008 (24 अदद)	आर एस वी वाई, विधायक कोष, एन एफ एफ डब्लू पी,	सेवानिवृत	21 से 59 माह	145691
5	अजय कुमार जायसवाल	क.अ.	83485	2007 से नवंबर 2009(42 1 अदद)	आर एस वी वाई, विधायक कोष,	वर्तमान	5 से 40 माह	83485
6	सावना उराँव	क.अ.	560264	फरवरी 2004 से नवंबर 2006 (05 अदद)	आर एस वी वाई, विधायक कोष, एन एम वाई	एन आर ई पी गुमला	41 से 74 माह	560264
7	महेन्द्र कुमार सिन्हा	क.अ	1363201	अप्रैल 2005 से जुन 2007 (54 अदद)	आर एस वी वाई, विधायक कोष, एन एफ एफ डब्लू पी, एस.एस.जे.एस.भी.वाई, मनरेगा	वर्तमान	36 से 60 माह	1363201
8	रामानुज सिहं	क.अ	3589	जनवरी 2004 से मार्च 2009 (07 अदद)	विधायक कोष, डब्लू एफ,	वर्तमान	13 से 75 माह	0
9	सिध्देश्वर	क.अ	176167	2004 से	विधायक कोष, डब्लू	बिहार मे	68 से	56915

	प्रसाद			अगस्त 2004 (02 अदद)	एफ,	स्थानांतरण	76 माह	
10	अरविंद कुमार सिहं	क.अ	12704	2006 से दिसंबर 2008 (28 अदद)	आर एस वी वाई, पुलिस	वर्तमान	16 से 52 माह	0
कुल			**3710365**					**3117738**

स्रोतः- प्रमंडल द्वारा प्रस्तुत आँकडे

क.अ.-कनीय अभियंता, **मनरेगा-** म. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, **एम. एल. ए. फंड** - विधायक कोष, **एम. एम. वी. वाई.**-मुख्यमंत्री विकास योजना, **एन. एफ. एफ. डब्लु. पी.-** राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, **एस.एस.जे.एस.भी.वाई.** सुनिश्चित स्वर्ण जयंती एवं समविकास योजना

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भित पैराग्राफः 5.1.4: पृष्ठ - 235)

मार्च 2007 से मई 2011 के दौरान लिया गया अधिक मकान किराया भत्ता की विवरणी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	कर्मचारियों की संख्या	देय मकान किराया भत्ता (*प्रतिशत*)	देय मकान किराया भत्ता	मकान किराया भत्ता देय एवं आहरित (*प्रतिशत*)	मकान किराया भत्ता देय एवं आहरित	अतिरिक्त मकान किराया भत्ता आहरित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रखण्ड विकास कार्यालय नामकुम	65	5	2,26,699	15	6,80,102	4,53,403
			10	9,87,906	20	19,75,812	9,87,906
कुल		**65**		**12,14,605**		**26,55,914**	**14,41,309**
2	अंचल कार्यालय, नामकुम	33	5	1,83,940	15	5,51,819,	3,67,879
			10	6,78,967	20	13,57,930	6,78,963
कुल		**33**		**8,62,907**		**19,09,749**	**10,46,842**
3	बाल विकास परियोजना कर्यालय, नामकुम	16	5	1,00,933	15	3,02,,799	2,01,866
			10	5,66,111	20	11,32,222	5,66,111
कुल		**16**		**6,67,044**		**14,35,021**	**7,67,977**
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नामकुम	67	5	5,15,614	15	15,46,841	10,31,227
			10	23,40,981	20	46,81,962	23,40,981
कुल		**67**		**28,56,595**		**62,28,803**	**33,72,208**
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रातु	11	10	4,58,906		9,17,812	4,58,906
कुल		**11**		**4,58,906**	**20**	**9,17,812**	**4,58,906**
कुल योग		**192**		**60,60,057**		**1,31,47,299**	**70,87,242**

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.4:; पृष्ठ - 235)

मार्च 2009 से मई 2011 के दौरान भुगतान किए गये अग्राहय परिवहन भत्ता का विवरणी

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	कर्मचारियों की संख्या	भुगतान किया गया परिवहन भत्ता
1	प्रखण्ड विकास कार्यालय, नामकुम	65	6,25,538
कुल		**65**	**6,25,538**
2	अंचल कार्यालय, नामकुम	24	3,52,378
कुल		**24**	**3,52,378**
3	बाल विकास परियोजना कार्यालय, नामकुम	10	2,95,425
कुल		**10**	**2,95,425**
4	प्राथमिक स्वास्थ केन्द्द, नामकुम	67	8,21,801
कुल		**67**	**8,21,801**
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रातु	11	2,22,876
कुल		**11**	**2,22,876**
कुल योग		**177**	**23,18,018**

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भित कंडिका: 5.2.1; पृष्ठ - 237)

डी0आई0 पाईपों (के-9) के गलत दर विश्लेषण के कारण अधिकाई भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

डी0आई0 पाईपों का व्यास	कर और भाड़ा लागत सहित वास्तविक लागत (बीजक)	(बी) पर 10 प्रतिशत अनुमव्य ठेकेदार के लाभ का दर	बी0 ओ0 क्यू0/ एस्टीमेट के अनुसार दर	समायोजन(डी0 पर 15 प्रतिशत अधिक)के अनुसार दर/भुगतान किया गया	10 प्रतिशत ठेकेदार के काम पर उपबंधित अधिकाई दर (ई0 सी0)
(ए)	*(बी)*	*(सी)*	*(डी)*	*(ई)*	*(एफ)*
200मी0मी0व्यास	1145.00	1259.50	1365.59	1570.00	310.50
250मी0मी0व्यास	1513.00	1664.30	1794.95	2064.00	399.70
300मी0मी0व्यास	1930.00	2123.00	2272.98	2614.00	491.00
350मी0मी0व्यास	2420.00	2662.00	2834.03	3259.00	597.00
400मी0मी0व्यास	2905.00	3195.50	3419.12	3932.00	736.50
450मी0मी0व्यास	3475.00	3822.50	4086.99	4700.00	877.50
600मी0मी0व्यास	5356.00	5891.60	6276.09	7218.00	1326.40
700मी0मी0व्यास	6927.00	7619.70	8128.44	9348.00	1728.30

एस्टीमेट/एग्रीमेंट मे उपबंधित डी0 आई0 पाईपों के उच्च दर के कारण अधिकाई भुगतान किया गया

(राशि ₹ में)

डी0आई0 पाईपों का व्यास	एम0बी0 के अनुसार डी0आई0 पाईपों की लम्बाई	अधिकाई दर	अधिकाई भुगतान
200मी0मी0व्यास	995.50	310.50	309103.00
250मी0मी0व्यास	1496.00	399.70	597951.00
300मी0मी0व्यास	6283.50	491.00	3085199.00
350मी0मी0व्यास	6171.00	597.00	3684087.00
400मी0मी0व्यास	2579.00	736.50	1899434.00
450मी0मी0व्यास	7621.50	877.50	6687866.00
600मी0मी0व्यास	4994.50	1326.40	6624705.00
700मी0मी0व्यास	1550.00	1728.30	2678865.00
कुल योग	**31691.00**	**6466.90**	**25567210.00**

परिशिष्ट 5.6

(संदर्भित कंडिका: 5.2.1; पृष्ठ - 237)

डी0आई0 पाईपों के गलत दर विश्लेषण के कारण अधिकाई भगतान को दर्शाने वाली विवरणी (के-7)

डी0आई0 पाईपों का व्यास	कर और भाड़ा लागत सहित वास्तविक लागत (बीजक)	(बी) पर 10 प्रतिशत अनुमव्य ठेकेदार के लाभ का दर	बी0 ओ0 क्यू0/ एस्टीमेट के अनुसार दर	समायोजन(डी0 पर 15 प्रतिशत अधिक)के अनुसार दर/भुगतान किया गया	10 प्रतिशत ठेकेदार के काम पर उपबंधित अधिकाई दर (ई0 सी0)	अभ्युक्ति
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
100 मी0मी0व्यास	604.00	664.40	616.44	709.00	44.60	यद्यपि ठेकेदार ने डी0आई0 पाईप जिस दर पर खारीदा उसमें भाड़ा लागत सम्मिलित था लेकिन ₹ 13449791 की राशि ठेकेदार को भुगतान किया गया, वह एग्रीमेंट में सम्मिलित था।
150 मी0मी0व्यास	875.00	962.50	893.08	1027.00	64.50	
250 मी0मी0 व्यास	1803.00	1983.30	1736.99	1998.00	14.70	
300 मी0मी0 व्यास	1652.00	1817.20	2223.82	2557.00	739.80	
350 मी0मी0 व्यास	2079.00	2286.90	2799.92	3220.00	933.10	
400 मी0मी0 व्यास	2492.00	2741.20	3402.58	3913.00	1171.80	
450 मी0मी0 व्यास	2954.00	3249.40	4098.82	4714.00	1464.60	
500 मी0मी0 व्यास	3470.00	3817.00	4889.18	5623.00	1806.00	
600 मी0मी0 व्यास	4570.00	5027.00	6507.88	7484.00	2457.00	

एस्टीमेट मे उपबंधित डी0 आई0 पाईपों के उच्च दर के कारण किया गया अधिकाई भुगतान

राशि ₹ मे

डी0आई0 पाईपों का व्यास	एम0बी0 के अनुसार डी0आई0 पाईपों की लम्बाई	अधिकाई दर	अधिकाई भुगतान
100 मी0मी0व्यास	133155.00	44.60	5938713.00
150 मी0मी0व्यास	48380.00	64.50	3120510.00
250 मी0मी0व्यास	16860.00	14.70	247842.00
300 मी0मी0व्यास	7012.50	739.80	5187848.00
350 मी0मी0व्यास	3729.00	933.10	3479530.00
400 मी0मी0व्यास	181.50	1171.80	212682.00
450 मी0मी0व्यास	352.00	1464.60	515539.00
500 मी0मी0व्यास	27.50	1806.00	49665.00
600 मी0मी0व्यास	49.50	2457.00	121622.00
कुल योग	**209747.00**		**18873951.00**

परिशिष्ट 5.7

(संदर्भित कंडिका :5.2.1; पृष्ठ - 237)

डी.आई. पाईपों (के-9) की भाड़ा लागत के अन्याय-संगत व्यय को दर्शानेवाली विवरणी

(राशि ₹ में)

डी.आई. पाईपों का व्यास	एम.बी. के अनुसार डी.आई. पाईपों की लम्बाई	एम.बी. के अनुसार राशि	एम.बी. के अनुसार 15 प्रतिशत प्रीमियम	एम.बी. के अनुसार भाड़ा लागत पर अधिकाई भुगतान (कॉलम 3+ कॉलम 4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
200 मी0मी0व्यास	995.50	77391.00	11608.00	89000.00
250 मी0मी0व्यास	1496.00	158696.00	23804.00	182500.00
300 मी0मी0व्यास	6283.50	862285.00	129343.00	991628.00
350 मी0मी0व्यास	6171.00	1199766.00	179965.00	1379731.00
400 मी0मी0व्यास	2579.00	668580.00	100287.00	768867.00
450 मी0मी0व्यास	7621.50	2262518.00	339378.00	2601896.00
600 मी0मी0व्यास	4994.50	2329335.00	349400.00	2678735.00
700 मी0मी0व्यास	1550.00	983243.00	147486.00	1130729.00
कुल योग	**31691.00**			**9823086.00**

परिशिष्ट 5.8

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.2.1; पृष्ठ - 237)

डी.आई. पाईपों (के-7) की भाड़ा लागत के अन्याय-संगत व्यय को दर्शानेवाली विवरणी

(राशि ₹ में)

डी.आई. पाईपों का व्यास	एम.बी. के अनुसार डी.आई. पाईपों की लम्बाई	एम.बी. के अनुसार राशि	एम.बी. के अनुसार 15 प्रतिशत प्रीमियम	एम.बी. के अनुसार भाड़ा लागत पर अधिकाई भुगतान (कॉलम 3+ कॉलम 4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
100 मी0मी0व्यास	133155.00	3881468.00	582220.00	4463688.00
150 मी0मी0व्यास	48380.00	2257894.00	338684.00	2596579.00
200 मी0मी0व्यास	24655.00	1917665.00	287649.00	2205316.00
250 मी0मी0व्यास	16860.00	1767292.00	265094.00	2032387.00
300 मी0मी0व्यास	7012.50	962325.00	144349.00	1106674.00
350 मी0मी0व्यास	3729.00	724992.00	108749.00	833741.00
400 मी0मी0व्यास	181.50	47052.00	7058.00	54110.00
450 मी0मी0व्यास	352.00	104495.00	15674.00	120169.00
500 मी0मी0व्यास	27.50	9199.00	1379.00	10578.00
600 मी0मी0व्यास	49.50	23086.00	3463.00	26549.00
कुल योग	**234402.00**			**13449791.00**

परिशिष्ट 5.7 एवं परिशिष्ट 5.8 का कुल योग= ₹ 98,23,086 + ₹ 1,34,49,791= ₹ 2,32,72,877